VIDYA UNIVERSITY PRESS

TOUCH n PASS

सर्वश्रेष्ठ परीक्षा पथ-प्रदर्शक

B.A.
तृतीय वर्ष
(डिग्री कोर्स)
सेमेस्टर-V

अर्थशास्त्र

आर्थिक वृद्धि और विकास

SYLLABUS

UNIT-I Meaning and Measurement of Economic Growth and Development-Measuring Development and Development Gap, GDP, GNP, Per Capita Income, Factors affecting Economic growth and Development.

UNIT-II Concept of Poverty and Inequality, Vicious cycle of poverty, Lorenz Curve, Gini Coefficient Concept of Human Development, Human Development Index, Physical Quality of Life Index, Quality of Life Indices. Hunger Index, Happiness Index, Development and Sustainability. Concept of Sustainable Development. Millennium Development goals.

UNIT-III Lewis model of labour surplus economy, Rosentein Rodan's theory of Big Push, Nelson's Level equilibrium trap, balanced vs Un-balanced growth, Rostor's stages of growth, Harrod and Domar Growth models.

UNIT-IV Theory of Demographic Transition, Population as I imits to Growth. The Concept of Inclusive Growth-with Reference to India. Market Failure and Government Failure, Food Security, Education, Health and Nutrition, Gender and Development.

UNIT-V Development & Underdevelopment : an Overview; The Characteristics and Explanations of Underdevelopment-Vicious Circle of Poverty, Circular Causation, Dualism-Social, Technological, Financial, Organizational, Model of Dual Economy, Ranis-Fei, Jorgenson, Dependency Theories of Underdevelopment.

UNIT-VI Models of Technical Progress, Embodied and Disembodied Technical Progress, Neutral Technical Progress- Hicks, harrod, Solow, Kaldor, Mirrless Technical Progress Function, Arrow's Learning by Doing Approach to Economic Growth.

UNIT-VII Accumulation Endogenous growth, Intellectual capital, Role of Learning, Education and Research, Explanatons of Cross country Differentials in Economic Growth, Information Paradigm-Stigliz.

UNIT-VIII International Trade, Aid and Finance in the Development of Developing Countries-with special reference to India. FDI & FII, Role of Technology Transfer and Multinational Corporations in promoting development in development of developing countries-with Special Reference to India.

TOUCH n PASS

VIDYA®
UNIVERSITY PRESS

पंजीकृत कार्यालय
विद्या एम्पायर, बागपत रोड,
मेरठ, उत्तर प्रदेश (NCR) 250 002
www.vidyauniversitypress.com

© प्रकाशक

लेखन एवं सम्पादन
शोध एवं अनुसन्धान प्रकोष्ठ

मुद्रक
विद्या यूनिवर्सिटी प्रेस

TOUCH 'n' PASS

विषय-सूची

UNIT-I : आर्थिक वृद्धि का अर्थ एवं मापन ...3
UNIT-II : गरीबी एवं असमानता की अवधारणा ...17
UNIT-III : विभिन्न वृद्धि मॉडल ...36
UNIT-IV : जनसंख्या एवं आर्थिक विकास ...57
UNIT-V : विकास एवं अल्प-विकास ...85
UNIT-VI : प्रौद्योगिकीय विकास ...109
UNIT-VII : आर्थिक विकास में शिक्षा एवं शोध की भूमिका ...133
UNIT-VIII : अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ...150

UNIT-I

आर्थिक वृद्धि का अर्थ एवं मापन
Meaning and Measurement of Economic Growth

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. आर्थिक विकास को परिभाषित कीजिए।
Define the economic development.

उत्तर आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है।

प्र.2. स्थैतिक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं?
What is the static economics?

उत्तर जिसमें कार्य निरन्तर रूप से दिन प्रतिदिन हो रहा है परन्तु उसमें वृद्धि अथवा कमी न हो रही हो। इस सक्रिय अपरिवर्तनीय प्रक्रिया को ही स्थैतिक अर्थशास्त्र कहते है।

प्र.3. प्रति व्यक्ति आय क्या है?
What is per capita income?

उत्तर किसी देश की राष्ट्रीय आय को वहाँ की जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं।

प्र.4. वास्तविक आय क्या हैं?
What is real income?

उत्तर मौद्रिक आय की क्रय शक्ति को वास्तविक आय कहते हैं।

प्र.5. राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं?
What is national income?

उत्तर किसी देश के श्रम व पूँजी उसके प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रतिवर्ष जिन भौतिक वस्तुओं एवं सेवाओं का शुद्ध वास्तविक उत्पादन करते हैं। उनका मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है।

प्र.6. सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं?
What do you mean by GNP?

उत्तर एक अर्थव्यवस्था में अन्तिम रूप से उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के समस्त मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) कहा जाता है।

प्र.7. आर्थिक कल्याण क्या हैं?
What is economic welfare?

उत्तर आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जिसे मुद्रा के मापदण्ड से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सम्बन्धित किया जा सकता है।

प्र.8. GDP को समझाइए।
Explain GDP.

उत्तर एक वर्ष की अवधि में जितनी वस्तुओं एवं सेवाओं का किसी देश में उत्पादन होता है उसका बाजार कीमतों पर मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद (GDP) कहलाता हैं।

TOUCH 'n' PASS

प्र.9. मानवीय पूँजी निर्माण का क्या उद्देश्य है?
What is object of human capital formation.

उत्तर भारतीय पूँजी निर्माण का सम्बन्ध उस विनियोग से है जो धन के उत्पादकों के रूप में लोगों की योग्यताओं एवं क्षमताओं में सुधार करने के उद्देश्य से किया जाता है।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. आर्थिक वृद्धि एवं विकास का विश्लेषण कीजिए।
Analise the economic growth and development.

उत्तर

आर्थिक वृद्धि एवं विकास का विश्लेषण
(Analysis of Economic Growth and Development)

विकास का अर्थशास्त्र अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास की समस्याओं से सम्बन्ध रखता है। यद्यपि आर्थिक विकास के अध्ययन ने वाणिज्यवादियों तथा एड्म स्मिथ से लेकर मार्क्स और केन्ज तक सभी अर्थशास्त्रियों का ध्यान आकर्षित किया था, फिर भी, उनकी दिलचस्पी प्रमुख रूप से ऐसी समस्याओं में रही जिनकी प्रकृति विशेषतया स्थैतिक थी और जो अधिकतर सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के पश्चिम यूरोपीय ढाँचे से सम्बन्ध रखती थी। वर्तमान शताब्दी के पाँचवे दशक में और विशेष रूप से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही अर्थशास्त्रियों ने अल्पविकसित देशों की समस्याओं के विश्लेषण की ओर ध्यान देना शुरू किया। विकास के अर्थशास्त्र में उनकी दिलचस्पी राजनैतिक पुनरूत्थान की उस लहर के द्वारा और भी बढ़ी, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया तथा अफ्रीका के राष्ट्रो में फैल गई थी। इन देशों के नेता शीघ्रता से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहते थे। और साथ ही विकसित राष्ट्र भी यह महसूस करने लगे थे कि "किसी एक स्थान की दरिद्रता प्रत्येक सम्पन्न स्थानों की समृद्धि के लिए खतरा है।" इन दोनों बातों से अर्थशास्त्रियों की रुचि इस विषय में और सजग हुई। इस सन्दर्भ में मायर तथा बाल्डविन ने कहा है कि 'राष्ट्रों के धन के अध्ययन की अपेक्षा राष्ट्रों की दरिद्रता के अध्ययन की अधिक आवश्यकता है।' इस क्रम में अल्पविकसित देशों की विशाल दरिद्रता को दूर करने में धनी राष्ट्रों की रुचि किसी मनावहितवादी उद्देश्य को लेकर नहीं जागृत हुई है बल्कि धनी विकसित देशों द्वारा इन गरीब राष्ट्रों को अन्य गरीब देशों के मुकाबले में अधिक सहायता देने का वचन देकर प्रत्येक देशा में अल्पविकसित देशों का समर्थन और वफादारी प्राप्त करने का प्रयत्न करता है आज के इस प्रगतिशील युग की मुख्य समस्या आर्थिक विकास की समस्या है। वर्तमान आर्थिक जगत में, आर्थिक विकास का विचार एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है तथा अधिकांश अर्थशास्त्रियों द्वारा किये जाने वाले चिन्तन का यह एक केन्द्र बिन्दु बना हुआ है। आर्थिक विकास जैसा कि इस शब्द से स्पष्ट होता है, का अर्थ है—अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता के स्तर को बढ़ाना।' विस्तृत अर्थ में, आर्थिक विकास से अभिप्राय राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके, निर्धनता को दूर करना तथा सामान्य जीवन स्तर में सुधार करना है।

प्र.2. आर्थिक कल्याण एवं आर्थिक विकास का उल्लेख कीजिए।
Mention the economic welfare and economic development.

उत्तर

आर्थिक कल्याण एवं आर्थिक विकास
(Economic Welfare and Economic Development)

विभिन्न देशों में यह प्रवृत्ति भी होती है कि आर्थिक कल्याण के दृष्टिकोण से आर्थिक विकास की परिभाषा दी जाये। ऐसी प्रक्रिया को आर्थिक विकास माना जाये जिससे प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होती हैं और उसके साथ-साथ असमानताओं का अन्तर कम होता है तथा समस्त जनसाधारण के अधिमान सन्तुष्ट होते हैं। इसके अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों के वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग में वृद्धि होती है। **ओकन** और **रिचर्डसन** के शब्दों में "आर्थिक विकास, भौतिक समृद्धि में ऐसा अनवरत दीर्घकालीन सुधार है जो कि वस्तुओं और सेवाओं के बढ़ते हुए प्रवाह में प्रतिबिम्बित समझा जा सकता है।"

सीमाएँ—यह परिभाषा भी सीमाओं से मुक्त नहीं है। **प्रथम**, यह आवश्यक नहीं है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि का अर्थ "आर्थिक कल्याण" में सुधार ही हो। ऐसा सम्भव है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने से अमीर अधिक अमीर हो रहे हों या गरीब और अधिक गरीब। इस प्रकार केवल आर्थिक कल्याण में वृद्धि से ही आर्थिक विकास नहीं होता, जब

TOUCH 'n' PASS

कि राष्ट्रीय आय का वितरण न्यायपूर्ण न माना जाये। **दूसरे**, आर्थिक कारण को मापते समय कुल उत्पादन की संरचना का ध्यान रखना पड़ता है जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, और यह उत्पादन कैसे मूल्यांकित हो रहा है? बढ़ा हुआ कुल उत्पादन पूँजी पदार्थों से मिलकर बना हो सकता है और यह भी उपभोक्ता वस्तुओं के कम उत्पादन के कारण। **तीसरे**, वास्तविक कठिनाई इस उत्पादन के मूल्यांकन में होती है। उत्पादन तो मार्केट कीमतों पर मूल्यांकित होता है, जबकि आर्थिक कल्याण वास्तविक राष्ट्रीय उत्पादन या आय में वृद्धि में मापा जा सकता है। वास्तव में, आय के विभिन्न वितरण से कीमतें भिन्न होंगी और राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्य तथा संरचना भी भिन्न होंगे। **चौथे**, कल्याण के दृष्टिकोण से हमें केवल यह नहीं देखना चाहिए कि क्या उत्पादित किया जाता है। बल्कि यह भी कि उसका उत्पादन कैसे होता है? वास्तविक राष्ट्रीय उत्पादन के बढ़ने से सम्भव है कि अर्थव्यवस्था में वास्तविक लागतों तथा पीड़ा और त्याग जैसी सामाजिक लागतों में वृद्धि हुई हो। उदाहरणार्थ, उत्पादन में वृद्धि अधिक घण्टे तथा श्रम-शक्ति की कार्यकारी अवस्थाओं में गिरावट के कारण हुई हो। **पाँचवें**, हम प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि को भी आर्थिक कल्याण में वृद्धि के बराबर नहीं मान सकते।

विकास की इष्टतम दर निश्चित करने के लिए हमें आय-वितरण, उत्पादन की संरचना, रुचियों, वास्तविक लागतों तथा ऐसे अन्य सभी विशिष्ट प्रयत्नों के सम्बन्ध में मूल्य-निर्णय करने पड़ेंगे, जो कि वास्तविक आय में कुल वृद्धि से सम्बन्ध रखते हैं'' इसलिए मूल्य निर्णयों से बचने और सरलता के लिए अर्थशास्त्री प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का माप बनाकर प्रयोग करते हैं।

अन्तिम, सबसे बड़ी कठिनाई व्यक्तियों के उपभोग को भार देने की है। वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग व्यक्तियों की रुचियों और अधिमानों पर निर्भर करता है जो भिन्न-भिन्न होते हैं। इसलिए व्यक्तियों का कल्याण सूचक बनाने में समान भार लेना सही नहीं हैं।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. आर्थिक विकास की विभिन्न परिभाषाएँ दीजिए एवं आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अन्तर बताइए।
Give the various definitions of economic development and state the difference between economic development and economic growth.

उत्तर

आर्थिक विकास की परिभाषाएँ
(Definitions of Economic Development)

विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास की परिभाषा के लिए भिन्न-भिन्न आधारों को अपनाया है। अर्थशास्त्रियों के एक समूह ने आर्थिक विकास का अर्थ, कुल राष्ट्रीय वास्तविक आय में वृद्धि करना बताया है, तो दूसरी विचारधारा के लोगों ने प्रति-व्यक्ति वास्तविक आय में की जाने वाली वृद्धि को आर्थिक विकास की संज्ञा दी है।

प्रथम सम्प्रदाय में **प्रो० साइमन कुजनेट्स, मायर** एवं **बाल्डविन** तथा **ए०जे० यंगसन**, आदि को सम्मिलित किया जाता है।

द्वितीय सम्प्रदाय में प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि को, आर्थिक विकास मानने वाले अर्थशास्त्रियों में **डॉ० बैंजमीन, हिगीन्स हार्वे लिवेस्टीन, डब्लू. आर्थर लुईस, प्रो० विलियमसन** तथा **जैकब बॉइनर** आदि प्रमुख रूप से है।

आर्थिक विकास की प्रचलित परिभाषाएँ निम्नवत हैं—

मायर एवं वाल्डविन के मतानुसार—''आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है।''

प्रो० लुईस के शब्दों में—''आर्थिक विकास का अर्थ, प्रति-व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि से लगाया जाता है।''

प्रो० यंगसन के विचारानुसार—''आर्थिक प्रगति से आशय किसी समाज से सम्बन्धित आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की शक्ति में वृद्धि करना है।''

प्रो० विलियमसन के अनुसार—''आर्थिक विकास अथवा वृद्धि से उस प्रक्रिया का बोध होता है जिसके द्वारा किसी देश अथवा प्रदेश के निवासी प्रदेश के निवासी उपलब्ध साधनों का उपयोग, प्रति व्यक्ति वस्तुओं के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि के लिए करते हैं।'

प्रो० डी० ब्राइट सिंह की दृष्टि में—''आर्थिक वृद्धि से अभिप्राय, एक देश के समाज में होने वाले उस परिवर्तन से लगाया जाता है जो अल्प-विकसित स्तर से उच्च आर्थिक उपलब्धियों की ओर अग्रसर होता है।''

उपरोक्त परिभाषाओं के विवेचन से स्पष्ट है कि जहाँ **मायर** एवं **वाल्डविन** ने आर्थिक विकास में वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने की बात कही है वहीं विलियमसन तथा लुईस द्वारा प्रति व्यक्ति उत्पादन अथवा आय में वृद्धि का समर्थन किया गया है लेकिन ऊपर वर्णित सभी परिभाषाओं में तीन महत्त्वपूर्ण बातें समान रूप से परिलक्षित होती हैं—

1. **विकास की सतत प्रक्रिया**— आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है। जिसका अर्थ, कुछ विशेष प्रकार की शक्तियों के कार्यशील रहने के रूप में, लगाया जाता है। इन शक्तियों के एक अवधि तक निरन्तर रहने के कारण आर्थिक घटकों में सदैव परिवर्तन होते रहते हैं। यद्यपि इस प्रक्रिया के फलस्वरूप किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन तो होता है किन्तु इस प्रक्रिया का सामान्य परिणाम, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना है।
2. **वास्तविक राष्ट्रीय आय**—आर्थिक विकास का सम्बन्ध वास्तविक राष्ट्रीय आय की वृद्धि से है। ध्यान रहे, वास्तविक राष्ट्रीय आय की वृद्धि से अभिप्राय किसी राष्ट्र द्वारा एक निश्चित काल में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के विशुद्ध मूल्य में होने वाली वृद्धि से लगाया जाता है। न कि मौद्रिक आय की वृद्धि से। चूँकि आर्थिक विकास को मापने के लिए राष्ट्रीय आय को ही आधार माना जाता है इसलिए किसी देश का आर्थिक विकास तभी माना जाएगा जब उस देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन निरन्तर बढ़ता रहे। कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से मूल्य ह्रास अथवा मूल्य स्तर में हुए परिवर्तनों को समायोजित करने पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त हो जाता है।
3. **दीर्घकालीन अथवा निरन्तर वृद्धि**—आर्थिक विकास का सम्बन्ध अल्पकाल से न होकर दीर्घकाल से होता है। दूसरे शब्दों में, विकास की यह प्रक्रिया एक या दो वर्षों में होने वाले अल्पकालीन परिवर्तनों से सम्बन्धित नहीं होती बल्कि 15 से 20 वर्षों के बीच दीर्घकालीन परिवर्तनों से सम्बन्धित होती है। इसलिए अगर किसी अर्थव्यवस्था में किन्हीं अस्थायी कारणों से देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाता है, जैसे अच्छी फसल अथवा अप्रत्याशित निर्यात होना, तो इसे आर्थिक विकास नहीं समझना चाहिए, क्योंकि विकास विशेष घटकों से प्रभावित होने वाला विकास है।

आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अन्तर
(Difference in Economic Development and Economic Growth)

"अल्पविकसित देशों की समस्याएँ उपयोग में न लाये गये साधनों के विकास से सम्बन्ध रखती है, भले ही उनके उपभोग भली-भाँति ज्ञात न हों, जबकि उन्नत देशों की समस्याएँ वृद्धि से सम्बन्धित रहती है, जिनके बहुत सारे साधन पहले से ज्ञात और किसी सीमा तक विकसित रहते हैं। प्राय: आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में कोई अन्तर नहीं किया जाता है किन्तु प्रो० शुम्पीटर तथा श्रीमती उर्सला हिक्स ने इन दोनों शब्दों में भेद करने का प्रयास किया है। आर्थिक वृद्धि एक स्वाभाविक एवं सामान्य प्रक्रिया है जिसके लिए समाज को कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, इसके विपरीत आर्थिक विकास के लिए विशेष प्रयत्नों का किया जाना जरूरी है अर्थात् आर्थिक विकास की प्रक्रिया के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों का होना आवश्यक है ताकि विद्यमान आर्थिक व्यवस्था के पूरे स्वरूप को परिवर्तित किया जा सके। प्रो० शुम्पीटर के अनुसार विकास स्थिर व्यवस्था में होने वाला एक ऐसा असतत एवं स्वत: परिवर्तन है जो पहले से स्थापित सन्तुलन की अवस्था (अर्थात् विद्यमान स्थिति) को हमेशा के लिए बदल देता है, जबकि इसके विपरीत वृद्धि दीर्घकाल में घटित होने वाला एक क्रमिक तथा स्थिर गति वाला परिवर्तन है जो बचत और जनसंख्या की दर में होने वाली सामान्य वृद्धि का परिणाम होता हैं।"

इस प्रकार जो उन्नति धीरे-धीरे आर्थिक व सामाजिक तत्त्वों में होने वाले परिवर्तनों के कारण होती है। उसे आर्थिक वृद्धि कहते हैं, परन्तु जब अर्थव्यवस्था में उन्नति की प्रबल इच्छा के तदन्तर, कुछ विशेष प्रयत्नों व क्रियाओं द्वारा क्रान्तिकारी परिवर्तन लाये जाते हैं। तो उसके फलस्वरूप होने वाली उन्नति को, आर्थिक विकास कहा जाता है। इस सन्दर्भ में यह बात ध्यान देने योग्य है कि उन्नति के यह दोनों स्वरूप दीर्घकालीन तथ्य है। प्रो० शुम्पीटर ने आर्थिक विकास को आर्थिक वृद्धि की अपेक्षा अधिक उपर्युक्त माना है।

इस सम्बन्ध में श्रीमती उर्सला हिक्स का कहना है कि आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है क्योंकि इन देशों में उत्पादन के साधन पहले से ही ज्ञात एवं विकसित होते हैं। इसके विपरीत 'विकास' का सम्बन्ध अल्प-विकसित देशों से है जहाँ अशोषित व अर्द्ध शोषित साधनों के पूर्ण उपयोग व विकास की सम्भावनाएँ विद्यमान होती हैं। इसी प्रकार **प्रो० बोन** ने भी आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अन्तर स्थापित किया है। उनके मतानुसार विकास के लिए विशेष निर्देशन, नियन्त्रण, प्रयास व मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और यह बात अल्प विकसित देशों के सम्बन्ध में ही ठीक बैठती है।

TOUCH 'n PASS

क्र०सं०	आर्थिक वृद्धि	आर्थिक विकास
1.	स्वाभाविक क्रमिक व स्थिर गति वाला परिवर्तन	प्रेरित एवं असंगत प्रकृति का परिवर्तन
2.	केवल उत्पादन में वृद्धि का होना	उत्पादन–वृद्धि + प्राविधिक एवं संस्थागत परिवर्तनों का होना।
3.	आर्थिक व संस्थागत घटकों में परिवर्तन होने पर स्वत: ही घटित होती रहती है।	विकास के लिए संरचनात्मक परिवर्तनों का किया जाना आवश्यक है।
4.	वर्तमान साम्य की अवस्था में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं होता।	नई शक्तियों से नये मूल्यों का निर्माण किया जाता है तथा प्रचलित साम्य में सुधार लाये जाते हैं।
5.	आर्थिक उन्नति नियमित घटनाओं का परिणाम है।	आर्थिक विकास उन्नति इच्छा, विशेष निर्देशन व सृजनात्मक शक्तियों का परिणाम है।
6.	यह उन्नत देशों की समस्याओं का समाधान है।	यह अल्प विकसित देशों की समस्याओं को हल करने का एक नारा हैं
7.	आर्थिक वृद्धि स्थैतिक साम्य की स्थिति हैं।	आर्थिक विकास गतिशील साम्य का एक रूप है।

इसके विपरीत आर्थिक वृद्धि का स्वभाव स्वेच्छानुसार होता है जो कि एक उन्नत स्वतन्त्र उपक्रम वाली अर्थव्यवस्था का लक्षण है। प्रो० किण्डले बर्जर के मतानुसार 'आर्थिक वृद्धि का अर्थ केवल उत्पादन वृद्धि से है जबकि आर्थिक विकास का अर्थ है उत्पादन वृद्धि के साथ प्राविधिक एवं संस्थागत परिवर्तन का होना है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आर्थिक वृद्धि की दशा में आर्थिक जीवन प्रत्येक वर्ष उन्हीं आर्थिक धाराओं से होकर इस प्रकार बहता चला जाता है जिस प्रकार एक प्राणी की धमनियों में रक्त का संचालन होता है। दूसरे शब्दों में, आर्थिक वृद्धि के अन्तर्गत ज्यादा नवीनता का सृजन नहीं होता है बल्कि जो कुछ भी उन्नति होती है वह परम्परागत एवं नियमित घटनाओं का परिणाम होती है। इसके विपरीत आर्थिक विकास में नई शक्तियों को जन्म दिया जाता है और प्रचलित सन्तुलन में निरन्तर सुधार लाने के प्रयत्न किये जाते हैं। आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास में पाये जाने वाले प्रमुख अन्तरों की विवेचना निम्नवत हैं—

प्रो० एलन बरेरी ने आर्थिक वृद्धि तथा प्रगति में अन्तर करने का प्रयत्न किया है। उनके मतानुसार 'प्रगति' से अभिप्राय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से हैं। जबकि 'आर्थिक वृद्धि' का अर्थ, जनसंख्या एवं कुल वास्तविक आय (राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय) दोनों में होने वाली बढ़ोतरी से लगाया जाता है। आर्थिक प्रगति, आर्थिक वृद्धि के बिना भी सम्भव हो सकती है, अर्थात् जब (i) कुल आय के स्थिर रहने पर जनसंख्या में कमी हो जाये अथवा (ii) कुल आय में कमी होने पर जनसंख्या में अपेक्षाकृत और अधिक कमी हो जाये तो यह प्रगति बिना वृद्धि के मानी जायेगी। ठीक प्रकार आर्थिक वृद्धि आर्थिक प्रगति के बिना भी सम्भव हो सकती है।

प्रो० बरेरी महोदय द्वारा आर्थिक वृद्धि के निम्न स्वरूप बताए गए हैं—

प्रगतिशील वृद्धि—जल कुल आय में वृद्धि जनसंख्या में होने वाली वृद्धि से अधिक हो।

अधोगामी वृद्धि—जब कुल आय में वृद्धि की अपेक्षा जनसंख्या में होने वाली वृद्धि अधिक हो।

स्थिर उन्नति—जब कुल आय में वृद्धि व जनसंख्या में होने वाली वृद्धि दोनों समान दर से बढ़ रही हों।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यद्यपि आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास में भेद करना सम्भव है किन्तु इस प्रकार का भेद व्यावहारिक दृष्टि से अधिक उपयोगी नहीं कहा जा सकता। अत: 'विकास' एवं वृद्धि शब्द को पर्यायवाची मानते हुए इन्हें एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है। **प्रो० पॉल ए० बरन** का भी यह मत है।

प्र.2. आर्थिक विकास के विभिन्न मापों की विवेचना कीजिए।

Discuss the different measurement of economic development.

उत्तर

आर्थिक विकास का मापन
(Measurement of Economic Development)

'आर्थिक विकास' आज के इस प्रगतिशील युग का एक बहुचर्चित विषय है और प्रत्येक राष्ट्र विकास की इस दौड़ में दूसरों से आगे निकलने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है। आर्थिक विकास की माप हेतु विकासवादी अर्थशास्त्रियों द्वारा निम्नलिखित मापदण्ड प्रस्तुत किए गए हैं।

TOUCH 'n PASS

सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं आर्थिक विकास
(Gross National Product and Economic Development)

कुछ अर्थशास्त्री सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि को ही आर्थिक विकास का सूचक मानते हैं। उनके अनुसार, 'आर्थिक विकास को समय की किसी दीर्घावधि में एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि के रूप में मापा जाए।' इस कथन को नीचे चित्र से स्पष्ट किया गया है क्षैतिक अक्ष पर समय को लिया गया है जबकि अनुलम्ब अक्ष पर राष्ट्रीय आय में परिवर्तन समय के साथ दिखाया गया हैं। रेखा Ya देश A में राष्ट्रीय आय के स्तर को और Yb देश B में राष्ट्रीय आय के स्तर को दर्शाती है। समय T तक देश A में राष्ट्रीय आय में वृद्धि देश B में विकास परियोजनाएँ शुरू होने से राष्ट्रीय आय की तीव्रता से वृद्धि होती है। जैसा कि चित्र में E बिन्दु के बाद $Yb > Ya$ से स्पष्ट हो रहा है। इस सन्दर्भ में प्रोफेसर मॉयर एवं बाल्डबिन ने ठीक ही कहा है कि "आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल में वृद्धि होती है।"

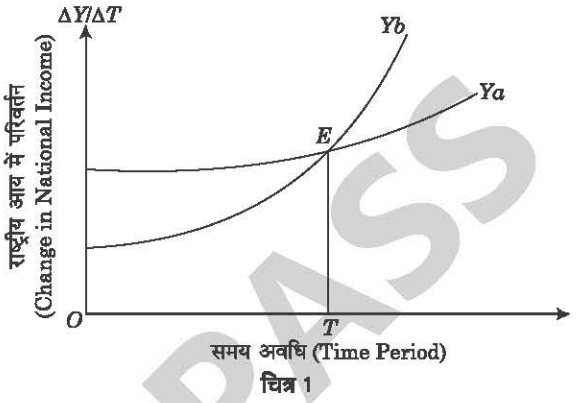

चित्र 1

सकल राष्ट्रीय उत्पाद के माप में कठिनाईयाँ (Difficulties in the Measurement of GNP)

किसी भी देश की राष्ट्रीय आय का आकलन करना एक जटिल समस्या है जिसमें निम्नलिखित कठिनाइयाँ पाई जाती हैं—

1. **राष्ट्र की परिभाषा**—प्रथम कठिनाई 'राष्ट्र' की परिभाषा है। हर राष्ट्र की अपनी राजनीतिक सीमाएँ होती है परन्तु राष्ट्रीय आय में राष्ट्र की सीमाओं से बाहर विदेशों में कमाई गई देशवासियों की आय भी सम्मिलित होती हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय आय के दृष्टिकोण से 'राष्ट्र' की परिभाषा राजनैतिक सीमाओं को पार कर जाती है। इस समस्या को सुलझाना कठिन है।
2. **कुछ सेवाएँ**— राष्ट्रीय आय सदैव मुद्रा में ही मापी जाती है परन्तु बहुत सी वस्तुएँ और सेवाएँ ऐसी होती हैं जिनका मुद्रा में मूल्यांकन करना मुश्किल होता है, जैसे किसी व्यक्ति द्वारा अपने शौक के लिए चित्र बनाना, माँ का अपने बच्चों को पालना आदि। इसी प्रकार जब एक फर्म का मालिक अपनी महिला सेक्रेटरी से विवाह कर लेता है तो उसकी सेवाएँ राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती जबकि विवाह से पहले वह राष्ट्रीय आय का भाग होती है। ऐसी सेवाएँ राष्ट्रीय आय में सम्मिलित न होने से राष्ट्रीय आय कम हो जाती हैं।
3. **दोहरी गणना**—राष्ट्रीय आय की परिगणना करते समय सबसे बड़ी कठिनाई दोहरी गणना की होती है। इसमें एक वस्तु या सेवा को कई बार गिनने की आशंका बनी रहती है। यदि ऐसा हो तो राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ जाती है। इस कठिनाई से बचने के लिए केवल अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं को ही लिया जाता है जो आसान काम नहीं है।
4. **अवैध क्रियाएँ**—राष्ट्रीय आय में अवैध क्रियाओं से प्राप्त आय सम्मिलित नहीं की जाती जैसे, जुए या चोरी से बनाई गई शराब से आय। ऐसी सेवाओं में वस्तुओं का मूल्य होता है और वे उपभोक्ता की आवश्यकताओं को भी पूरा करती है परन्तु इनको राष्ट्रीय आय में शामिल न करने से राष्ट्रीय आय कम रह जाती है।
5. **अन्तरण भुगतान**—राष्ट्रीय आय में अन्तरण भुगतानों को सम्मिलित करने की कठिनाई उत्पन्न होती हैं। पेन्शन, बेरोजगारी भत्ता तथा सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं पर इन्हें राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाए या न किया जाये, एक कठिन समस्या है एक ओर तो ये प्राप्तियाँ व्यक्तिगत आय का भाग हैं दूसरी ओर ये सरकारी व्यय हैं। यदि इन्हें दोनों ओर सम्मिलित किया जाए तो राष्ट्रीय आय में बहुत वृद्धि हो जाएगी। इस कठिनाई से बचने के लिए इन्हें राष्ट्रीय आय में से घटा दिया जाता है।
6. **वास्तविक आय**—मुद्रा के रूप में राष्ट्रीय आय की परिगणना वास्तविक आय का न्यून आकलन करती है। इसमें किसी वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया में किए गए अवकाश का त्याग शामिल नहीं होता। दो व्यक्तियों द्वारा अर्जित की गई आय समान हो सकती है परन्तु उसमें से यदि एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा अधिक घण्टे काम करता है तो यह कहना कुछ ठीक ही होगा कि पहले की वास्तविक आय कम बताई गई है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय वस्तु के उत्पादन की वास्तविक लागत को नहीं लेती।

TOUCH 'n' PASS

7. **सार्वजनिक सेवाएँ**—राष्ट्रीय आय की परिगणना में बहुत सी सार्वजनिक सेवाएँ भी ली जाती हैं, जिनका ठीक-ठीक हिसाब लगाना कठिन होता है। पुलिस तथा सैनिक सेवाओं का आकलन कैसे किया जाए? युद्ध के दिनों में तो सेना क्रियाशील होती है जबकि शान्ति में छावनियाँ में ही विश्राम करती है। इसी प्रकार सिंचाई तथा शक्ति परियोजनाओं से प्राप्त लाभों का मुद्रा के रूप में राष्ट्रीय आय में योगदान का हिसाब लगाना भी एक कठिन समस्या है।
8. **पूँजीगत लाभ या हानियाँ**—जो सम्पत्ति मालिकों को उनकी पूँजी परिसम्पत्तियों के बाजार मूल्य में वृद्धि, कमी या माँग में परिवर्तनों से होती है वे सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी०एन०पी०) में शामिल नहीं की जाती है। क्योंकि ऐसे परिवर्तन चालू आर्थिक क्रियाओं के कारण नहीं होते हैं। जब पूँजी या हानिया चालू प्रवाह या उत्पादकीय क्रियाओं के अप्रवाह के कारण होते हैं तो उन्हें जी०एन०पी० में सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार पूँजी लाभों या हानियों की राष्ट्रीय आय में आकलन करने में बहुत कठिनाई होती हैं।
9. **माल सूची परिवर्तन**—सभी माल सूची परिवर्तन चाहे ऋणात्मक हों या धनात्मक जी०एन०पी० में शामिल किये जाते हैं। परन्तु समस्या यह है कि फर्में अपनी माल सूचियों को उनकी मूल्य लागतों के हिसाब से दर्ज करती है न कि उनकी प्रतिस्थापन लागत के हिसाब से। जब कीमतें बढ़ती है तो मूल्य सूचियों के अंकित मूल्य में लाभ होता है इसके विपरीत कीमतें गिरने पर हानि होती है। अत: जी०एन०पी० का सही हिसाब लगाने के लिए माल सूची समायोजन की आवश्यकता होती है जो कि बहुत कठिन काम है।
10. **मूल्य ह्रास**—जब पूँजी मूल्य ह्रास को जी०एन०पी० में से घटा दिया जाता है तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (एन०एन०पी०) प्राप्त होती है। परन्तु मूल्य ह्रास की गणना की समस्या बहुत मुश्किल है। उदाहरणार्थ यदि कोई ऐसी पूँजी परिसम्पत्ति है जिसकी प्रत्याशित आयु बहुत अधिक जैसे 50 वर्ष है। तो उसकी चालू मूल्य ह्रास दर का हिसाब लगा सकना बहुत कठिन होगा और यदि परिसम्पत्तियों की कीमतों में प्रत्येक वर्ष परिवर्तन होता जाए, तो यह कठिनाई और बढ़ जाती है। माल सूचियों के विपरीत मूल्य ह्रास मूल्यांकन कर पाना बहुत कठिन और जटिल तरीका होता है।
11. **हस्तान्तरण भुगतान**—राष्ट्रीय आय के माप में हस्तान्तरण भुगतानों की समस्या भी पाई जाती है। व्यक्तियों को पेंशन, बेकारी भत्ता और सार्वजनिक ऋण पर ब्याज प्राप्त होता है। परन्तु इन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल करने की कठिनाई उत्पन्न होती है। एक ओर तो यह अर्जन व्यक्तिगत आय का भाग है और दूसरी ओर यह सरकारी व्यय है।

प्र.3. प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि कहाँ तक आर्थिक विकास का सन्तोषजनक माप प्रस्तुत करती हैं? वर्णन कीजिए।

Explain to what extent the increase in per capita real income represents a satisfactory measure of economic development?

उत्तर

मूलभूत आवश्यकताएँ एवं आर्थिक वृद्धि
(Basic Needs and Economic Growth)

आर्थिक विकास के माप के रूप में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की कीमत से असन्तुष्ट होकर, कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास को सामाजिक अथवा मूलभूत (आधारभूत) आवश्यकता सूचक के रूप में मापना प्रारम्भ किया है। जिसके अनेक कारण निम्नवत हैं।

1950 तथा 1960 के दशकों में GNP में वृद्धि एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को आर्थिक विकास का सूचक माना जाता रहा। 1960 के विकास दशक के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव द्वारा अल्पविकसित देशों के लिए 5 प्रतिशत की वृद्धि दर का लक्ष्य निश्चित किया। इस लक्ष्य दर को प्राप्त करने के लिए अर्थशास्त्रियों ने शहरीकरण के साथ तीव्र औद्योगिकरण का सुझाव दिया। उनका यह मत था कि वृद्धि से प्राप्त लाभ अपने आप रोजगार और आय के सुअवसरों में वृद्धि के रूप में गरीबों तक धीरे-धीरे पहुँच जाएगे। इस प्रकार, विकास के इस माप के अनुसार गरीबी, बेरोजगारी और आय असमानताओं की समस्याओं को गौण महत्त्व दिया गया।

रोस्टोव द्वारा प्रतिपादित विकास के इस एक रेखीय वृद्धि की अवस्थाओं के पथ को नर्क्से के कम बचतों, छोटी मार्केटों तथा जनसंख्या दबावों के कुचक्रों ने और शक्ति प्रदान की। यह समझा गया कि इन कुचक्रों को दूर करने के लिए प्राकृतिक शक्तियाँ मुक्त हो जायेगी। जो अर्थव्यवस्था में ऊँची वृद्धि लायेंगी। इसके लिए रोडान ने बड़ा धक्का नर्क्से ने सन्तुलित विकास, हर्षमैन ने असन्तुलित विकास, तथा लीबन्स्टीन ने क्रान्तिक न्यूनतम प्रयत्न सिद्धान्त का सुझाव दिया। परन्तु अल्पविकसित देशों में विकास के

TOUCH 'n' PASS

लिए पूँजी, तकनीकी ज्ञान विदेशी विनिमय आदि के रूप में ''लुप्त अंशों'' को प्रदान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहायता पर अधिक बल दिया गया। विदेशी सहायता के तर्क के पीछे ''दोहरा अन्तराल मॉडल'' तथा आयत स्थानापन्नता द्वारा औद्योगिकीकरण था ताकि अल्पविकसित देश धीरे-धीरे विदेशी सहायता का परित्याग कर दें।

डेविड मोरवैट्ज के अनुमान यह बताते हैं कि इस विकास कूटनीति के अपनाने से विकासशील देशों में 1950-75 के बीच GNP एवं प्रति व्यक्ति आय में 3.4 प्रतिशत प्रति वर्ष औसत दर से वृद्धि हुई। परन्तु यह वृद्धि दर ऐसे देशों की गरीबी, बेरोजगारी तथा असमानताओं को दूर करने में असफल रही।

आर्थिक विकास के सूचक के रूप में GNP के विरुद्ध अर्थशास्त्रियों के बीच आलोचनाएँ 1960 की दशाब्दी से बढ़ती जा रही थी। परन्तु सार्वजनिक तौर से प्रथम प्रहार प्रो० सिराज ने 1969 में नई दिल्ली में आयोजित Eleventh World Conference of the Society for International Development के अध्यक्षीय भाषण में किया। उसने समस्या को इस प्रकार प्रस्तुत किया, ''एक देश के विकास के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं—गरीबी का क्या हो रहा हैं? बेरोजगारी का क्या हो रहा है? असमानता का क्या हो रहा है? यदि यह तीनों ऊँचे स्तरों से कम हुए हैं तो बिना संशय के उस देश के लिए विकास की अवधि रही है। यदि इन मुख्य समस्याओं में से एक या दो अधिक बुरी अवस्था में हो जा रही हों, या तीनों ही निम्नता में हों तो परिणाम को विकास कहना आश्चर्यजनक होगा चाहे प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई हों।'' उस समय के विश्व बैंक के गर्वनर **रार्बट मैक्कनमारा** ने भी फरवरी 1970 में विकासशील देशों में GNP वृद्धि दर को आर्थिक विकास के सूचक की विफलता को इन शब्दों में स्वीकार किया—

''प्रथम विकास दशाब्दी में, GNP में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के विकास उद्देश्य को प्राप्त किया गया था। यह मुख्य उपलब्धि थी। परन्तु GNP में सापेक्षतया ऊँची वृद्धि दर विकास में सन्तोष जनक उन्नति न लाई। विकासशील विश्व में, दशाब्दी के अन्त में, कुपोषण सामान्य है, शिशु मृत्यु दर ऊँची है। अशिक्षा विस्तृत है, बेरोजगारी स्थानिक रोग है जो और बढ़ जाता है, धन और आय का पुनर्वितरण अत्यन्त विषम है।'' विकास की GNP प्रति व्यक्ति मापों से असन्तुष्ट होकर, 1970 की दशाब्दी से आर्थिक विचारकों ने विकास प्रक्रिया की गुणवत्ता की ओर ध्यान देना प्रारम्भ किया है। जिसके अनुसार वे तीन महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं रोजगार को बढ़ाने, गरीबी को दूर करने तथा आय और धन की असमानताओं को कम करने के लिए मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं की कूटनीति पर बल देते हैं। इसके अनुसार, जनसाधारण को स्वस्थ्य शिक्षा, जल, खुराक, कपड़े, आवास, काम आदि के रूप में मूलभूत भौतिक आवश्यकताएँ और साथ ही सांस्कृतिक पहचान तथा जीवन और कार्य में उद्देश्य एवं सक्रिय भाग की भावना जैसी अभौतिक आवश्यकताएँ प्रदान करना है। मुख्य उद्देश्य गरीबों को मूलभूत मानवीय आवश्यकताएँ प्रदान करके उनकी उत्पादकता बढ़ाना और गरीबी दूर करना है। यह तर्क दिया जाता है कि मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं का प्रत्यक्ष प्रबन्ध करने से गरीबी पर थोड़े संसाधनों द्वारा और थोड़े समय में प्रभाव पड़ता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं के रूप में मानव संसाधन विकास के उत्पादकता के उच्च स्तर प्राप्त होते हैं। ऐसा विशेषतौर से वहाँ होता है जहाँ ग्रामीण भूमिहीन अथवा शहरी गरीब पाये जाते हैं तथा जिनके पास दो हाथ और काम करने की इच्छा के सिवाय कोई भौतिक परिसम्पत्तियाँ नहीं होती हैं। इस कूटनीति के अन्तर्गत मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं के अलावा, रोजगार के सुअवसरों, पिछड़े वर्गों के उत्थान तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर बल देना और उचित कीमतों एवं दक्ष वितरण प्रणाली द्वारा आवश्यक वस्तुओं को गरीब वर्गों के लिए जुटाना है।

सामाजिक सूचक
(Social Index)

सामाजिक आर्थिक विकास के सूचकों का विस्तृत अध्ययन निम्नवत है—

अर्थशास्त्री सामाजिक सूचकों में तरह-तरह की मदों को शामिल कर लेते हैं। इसमें से कुछ आगतें है जैसे पौष्टिकता मापदण्ड या अस्पताल के बिस्तरों की संख्या या जनसंख्या के प्रतिव्यक्ति डॉक्टर, जबकि दूसरी कुछ मदें इन्हीं के अनुरूप निर्गतें हो सकती हैं, जैसे—नवजात शिशुओं की मृत्यु दर के अनुसार स्वास्थ्य में सुधार रोग दर, आदि। सामाजिक सूचकों को प्राय: विकास के लिए मूल आवश्यकताओं के सन्दर्भ में लिया जाता है। मूल आवश्यकताएँ, गरीबों की मूल मानवीय आवश्यकताओं को उपलब्ध करा कर गरीबी उन्मूलन पर केन्द्रित होती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य, जल, स्वच्छता तथा आवास जैसी प्रत्यक्ष सुविधाएँ थोड़े से मौद्रिक संसाधनों तथा अल्पावधि में ही गरीबी पर प्रभाव डालती है। जबकि GNP प्रति व्यक्ति आय की कूटनीति उत्पादकता बढ़ाने तथा गरीबों की आय बढ़ाने के लिए दीर्घावधि में स्वत: ही कार्य करती है। मूल आवश्यकताओं की पूर्ति उच्च स्तर पर उत्पादकता तथा आय बढ़ाती है, जिन्हें शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं जैसे मानव विकास के साथ साधनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

TOUCH 'n PASS

प्रो० हिक्स और स्ट्रीटन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए छः सामाजिक सूचकों पर विचार करते हैं—

	मूल आवश्यकता	सूचक
1.	स्वास्थ्य	जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा
2.	शिक्षा	प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों में जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार दाखिले द्वारा साक्षरता की दर।
3.	खाद्य	प्रति व्यक्ति कैलोरी आपूर्ति
4.	जल आपूर्ति	शिशु मृत्यु दर तथा पीने योग्य पानी तक कितने प्रतिशत जनसंख्या की पहुँच
5.	स्वच्छता	शिशु मृत्यु दर तथा स्वच्छता प्राप्त जनसंख्या का प्रतिशत
6.	आवास	कोई नहीं

सामाजिक सूचकों की विशेषता यह है कि वे लक्ष्यों से जुड़े और वे लक्ष्य हैं मानव विकास। आर्थिक विकास इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। सामाजिक सूचकों से पता चलता है कि कैसे विभिन्न देश वैकल्पिक उपयोगों के बीच अपने आवंटन करते हैं। कुछ शिक्षा पर अधिक तथा अस्पतालों पर कम खर्च करना पसन्द करते हैं। इसके साथ-साथ इनसे बहुत सी मूल आवश्यकताओं की उपस्थिति, अनुपस्थिति अथवा कमी के बारे में जानकारी मिलती है।

उपर्युक्त सूचकों में प्रतिव्यक्ति कैलोरी आपूर्ति को छोड़कर शेष सूचक निर्गत सूचक है। निःसन्देह नवजात शिशुओं की मृत्युदर, स्वच्छता तथा साफ पेय जल सुविधाओं दोनों की सूचक है क्योंकि नवजात शिशु पानी से होने वाले रोगों का शीघ्र शिकार हो सकते हैं। नवजात शिशु मृत्युदर भोजन की पोष्टिकता से भी सम्बन्धित है। इस प्रकार शिशुओं की मृत्युदर 6 में से 4 मूल आवश्यकताओं को मापती हैं।

कुछ सामाजिक सूचकों से सम्बन्धित विकास का एक सामान्य सूचक बनाने में कुछ समस्याएँ उत्पन्न होती है जो कि निम्नवत हैं—

प्रथम, ऐसे सूचक में शामिल किए जाने वाली मदों की संख्या और किस्मों के बारे में अर्थशास्त्रियों में एक मत नहीं है। उदाहरणार्थ, हेगन और संयुक्त राष्ट्र की सामाजिक विकास के लिए अन्वेषण संस्था 11 से 18 मदों का प्रयोग करते हैं। जिनमें से बहुत कम समान हैं। दूसरी ओर डी० मौरिस तुलनात्मक अध्ययन के लिए विश्व के 23 विकसित और विकासशील देशों से सम्बन्धित "जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचक" बनाने के लिए केवल तीन मदों अर्थात् जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्युदर और साक्षरता दर को लेता है।

दूसरे, विभिन्न मदों को भार देने की समस्या उत्पन्न होती है जो देश के सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक ढाँचे पर निर्भर करती है। यह व्यक्तिपरक बन जाती है मौरिस तीनों सूचकों को समान भार प्रदान करता है जो विभिन्न देशों के तुलनात्मक विश्लेषण के लिए सूचक का महत्त्व कम कर देता है। यदि प्रत्येक देश अपने सामाजिक सूचकों की सूची का चुनाव करता है और उनका भार प्रदान करता है तो उनकी अन्तर्राष्ट्रीय तुलनाएँ उतनी ही गलत होंगी जितने की GNP के आँकड़े होते हैं।

तीसरे, सामाजिक सूचक वर्तमान कल्याण से सम्बन्धित होते हैं न कि भविष्य के कल्याण से।

चौथे, अधिकतर सूचक आगत हैं न कि निर्गत जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य आदि।

अन्तिम उनमें मूल्य-निर्णय पाए जाते हैं। अतः मूल निर्णयों से बचने और सुगमता के लिए अर्थशास्त्री तथा यू०एन० के संगठन GNP एवं प्रति व्यक्ति आय को आर्थिक विकास के माप के रूप में प्रयोग करते हैं।

मूलभूत आवश्यकताएँ बनाम आर्थिक वृद्धि (Basic Needs vs Economic Growth)

क्या आर्थिक वृद्धि और मूलभूत आवश्यकताओं की कूटनीति के बीच कोई विवाद है? जैसा कि पहले कहा गया है, मूलभूत आवश्यकताएँ लक्ष्यों से सम्बन्धित हैं और आर्थिक वृद्धि इन लक्ष्यों को पाने का साधन। अतः आर्थिक वृद्धि तथा मूलभूत आवश्यकताओं में कोई विरोध नहीं है। गोल्डस्टीन ने शिशु मृत्युदर के माध्यम से आर्थिक वृद्धि तथा मूलभूत आवश्यकताओं के बीच गहरा सम्बन्ध पाया हैं। वह आर्थिक विकास को कुशलता का नाम देता है। उसके अनुसार, शिशुओं की मृत्यु दर को 5 प्रतिशत से कम रखने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए GDP का स्तर आवश्यक है। जो देश अपने GDP का एक बड़ा हिस्सा अथवा कुछ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करते हैं, वे अधिक कुशल हैं, क्योंकि इस प्रकार वे शिशु मृत्युदर को घटाने में सफल हो जाते हैं। गोल्डस्टीन ने पाया कि कुछ विकासशील देशों ने अपने थोड़े से संसाधनों को शिक्षा तथा स्वास्थ्य की मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने में लगाया। अपने विभिन्न वर्गों के अध्ययन में उसने स्कूलों में दाखिले तथा महिलाओं में स्वास्थ्य के

साथ-साथ शिक्षा की प्राप्ति को लिया। उसने पाया कि कुछ विकासशील देशों ने बहुत थोड़े संसाधनों को शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगाया। वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि जो विकासशील देश प्राथमिक स्कूली शिक्षा तथा महिला शिक्षा पर अधिक ध्यान देते हैं, वे इन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम खर्च करके भी अधिक विकास कर सकते हैं।

फाई, रैनिस तथा **स्टूअर्ट** के अनुसार विकासशील देशों में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर खर्च करने से उत्पादक निवेश में कमी नहीं होती। उन्होंने नौ देशों का सैम्पल लिया। उनके अध्ययन से पता चलता है कि ताईवान, दक्षिण कोरिया, फिलीपीन्स, उरूग्वे तथा थाईलैण्ड ने मूलभूत आवश्यकताओं का अच्छा प्रबन्ध किया तथा उनके निवेश अनुपात भी औसत से अधिक थे। जबकि फोलम्बिया, क्यूबा, जर्मेका तथा श्रीलंका ने अच्छी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ-साथ औसत निवेश अनुपात रखें। उन्होंने नौ विभिन्न देशों के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में किए गए कार्य को औसत से अधिक तथा औसत से कम आर्थिक वृद्धि के साथ भी सम्बद्ध किया। इनमें से ताइवान, दक्षिण-कोरिया तथा इण्डोनेशिया ऐसे हैं जिन्होंने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ औसत से अधिक आर्थिक वृद्धि की। ब्राजील ने मात्र न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया तथा औसत से अधिक आर्थिक वृद्धि भी की। जबकि दूसरी ओर सोमालिया, श्रीलंका, क्यूबा तथा मिस्र की आर्थिक वृद्धि दर औसत से कम रही। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मूलभूत आवश्यकताओं के अधिक प्रावधान करने से आर्थिक वृद्धि भी होती है। नॉरमन हिक्स ने भी अपने अध्ययन में यह दर्शाया है कि कई विकासशील देशों की आर्थिक वृद्धि की दर मूलभूत आवश्यकताओं की कूटनीति द्वारा बढ़ी है।

दीर्घकाल में GNP प्रति व्यक्ति GNP मूलभूत आवश्यकताओं तथा कल्याण धारणाओं के आर्थिक विकास पर प्रभावों की तुलना करने पर। चित्र में तीन पर्थ A_1, A_2 तथा A_3 दिखाएँ गए हैं। इसमें समय को क्षैतिज अक्ष पर रखा गया है तथा विकास की दर को अनुलम्ब अक्ष पर गरीबों में प्रति व्यक्ति उपभोग द्वारा मापा गया हैं। पथ A_1 का सम्बन्ध GNP/प्रति व्यक्ति GNP कूटनीति से है। स्पष्ट है कि आरम्भ में गरीबों में प्रति व्यक्ति उपभोग समय T_1 तक घटता है क्योंकि तेजी से उद्योगीकरण तथा शहरीकरण से गरीबी, बेरोजगारी तथा असमानता में वृद्धि होती है। लेकिन जब GNP प्रति व्यक्ति GNP में वृद्धि के लाभ गरीबों तक 'रिस कर' पहुँचते हैं। तो उनके रोजगार तथा आय में वृद्धि होती है तथा समय T_1 के बाद प्रति व्यक्ति उपभोग में भी वृद्धि होनी आरम्भ हो जाती हैं।

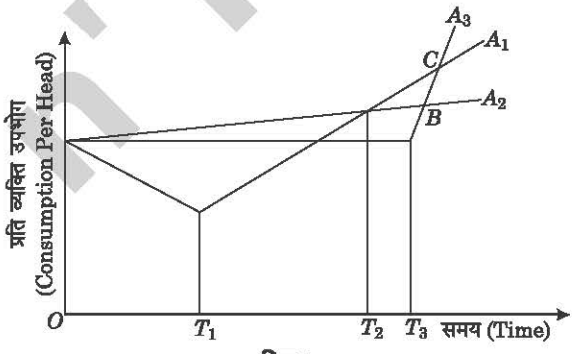

चित्र 1

पथ A_2 का सम्बन्ध कल्याण धारणा से है जो गरीबों में प्रति व्यक्ति उपभोग की धीमी वृद्धि को दर्शाता है यह पथ समय T_2 से पथ A_1 से पीछे रहता है।

पथ A_3 मूलभूत आवश्यकताओं की कूटनीति से सम्बन्धित है। आरम्भ में गरीबों में उपभोग के मूल न्यूनतम वर्तमान स्तर को प्राप्त करने को उच्च प्राथमिकता दी जाती है जो समय T_3 तक कल्याण तथा GNP के उपभोग स्तरों से कम हो सकता है। जब एक दीर्घ अवधि में गरीबों की मूलभूत आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं तथा उनकी उत्पादकता तथा आय के स्तरों में वृद्धि हो जाती है तो समय T_3 से आगे आर्थिक वृद्धि तेजी से होने लगती है। पथ A_3 पहले पथ A_2 को B बिन्दु पर पीछे छोड़ देता है तथा बाद में C बिन्दु पर पथ A_1 को। इस प्रकार मूलभूत आवश्यकताओं की कूटनीति GNP प्रति व्यक्ति GNP और कल्याण की आर्थिक विकास की कूटनीति से बेहतर है।

प्र.4. आर्थिक वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले तत्त्वों का वर्णन कीजिए।
Describe the elements affecting economic growth and development.

उत्तर

आर्थिक वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले तत्त्व
(Factors Affecting Economic Growth and Development)

आर्थिक वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले तत्त्वों का वर्णन निम्नलिखित हैं—

1. **प्राकृतिक साधन** (Natural Resources)—किसी भी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करने हेतु प्राकृतिक साधनों का महत्त्वपूर्ण योगदान है। अर्थशास्त्र में प्राकृतिक साधन का अर्थ भूमि से है। इसकी उपजाऊ शक्ति, क्षेत्र,

बनावट, वन-सम्पदा, खनिज पदार्थ, जन साधन आदि सम्मिलित होते हैं। अल्पविकसित देशों में प्राकृतिक साधनों का सही प्रकार से प्रयोग नहीं हो पाता है इसलिए देश के विकास में इसका पूर्ण योगदान नहीं होता। प्राकृतिक साधनों के सदुपयोग से रोजगार खाद्यान्न और आर्थिक सुधार की रफ्तार में तेजी नहीं आ पाती। अल्पविकसित देश में तकनीकी ज्ञान के अभाव की वजह से या तो इनका उपयोग नहीं होता है या अल्प-उपयोग या दुरूपयोग होता है। इस तरह यह कहा जाता है कि प्राकृतिक साधनों की कमी से विकास सम्भव तो हो सकता है। लेकिन प्राकृतिक साधन किसी देश की वृद्धि और विकास को किसी न किसी तरीके से जरूर प्रभावित करते हैं।

किसी भी अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक साधनों का अहम स्थान है। इनका यदि सदुपयोग किया जाए तो भारत जैसे देश जो प्राकृतिक साधनों से लबालब भरे पड़े हैं। इनके सदुपयोग से विकसित देशों की कतार में खड़े हो सकते हैं। अल्पविकसित (Under-developed) देशों में औद्योगिक विकास का आधार प्राकृतिक साधन ही है। क्योंकि जनसंख्या का अधिकतर भाग कृषि पर आधारित है। और कृषि पर आधारित अनेक उद्योग धन्धे रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं।

2. **पूँजी** (Capital)—आर्थिक विकास की दूसरी रूकावट (Hindrance) पूँजी है। अल्पविकसित देशों में पूँजी की कमी से उद्योगों का विकास नहीं हो पाता। नकर्से ने कहा है जिस देश में पूँजी की कमी महसूस नहीं होती उस देश के लोग अपनी उत्पादन क्रियाओं का अधिकतर भाग उपभोग पर खर्च नहीं करते। वरन उसके हिस्से को पूँजीगत वस्तुओं, मशीनों, परिवहन निर्माण तथा यन्त्र निर्माण में लगा देते हैं। इसलिए पूँजी निर्माण का अभिप्राय पूँजी को पूँजीगत वस्तुओं में लगाना है। जिससे उत्पादकता और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती हैं।

   अल्पविकसित देशों मे पूँजी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ता (Consumer) को बचत हेतु प्रोत्साहित करना, वास्तविक बचतों में वृद्धि करना बचतों को इकट्ठा तथा बचतों को एकत्रित करने से हैं। क्योंकि पूँजी आर्थिक वृद्धि की पूँजी है। पूँजी निर्माण का अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में बहुत महत्त्व हैं। यह बढ़ी हुई जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने और रोजगार के अवसर जुटाने में सहायक हैं। अल्पविकसित देशों में पूँजी (Capital) की कमी (Scarcity) के कारण उत्पादन क्षमता कम होती हैं। इसलिए जो देश गरीबी के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। उनके लिए पूँजी निर्माण अत्यन्त जरूरी हैं।

3. **श्रम** (Labour)—उत्पादन में दो तत्त्वों का महत्त्वपूर्ण स्थान है पूँजी एवं श्रम। श्रमिक की दक्षता (Efficiency) से उत्पादन क्षमता (Capacity) में वृद्धि होती हैं। **लुइस** ने कहा है कि श्रम की उपलब्धि किसी देश के लिए वरदान (Boon) का कार्य करती है। यदि उसका सही ढंग से प्रयोग किया जाए। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में पूँजी की कमी से सामाजिक विकास पर कम ध्यान केन्द्रित (Focus) रहता है। जिससे श्रम में अज्ञानता और अकुशलता तत्त्वों का समागम अधिक है। जिससे प्रति व्यक्ति उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। यदि श्रम का विशिष्टीकरण किया जाए तो उत्पादकता में बढ़ोत्तरी होती है। आर्थिक वृद्धि में श्रम के विशिष्टीकरण को अधिक महत्त्व दिया गया है। हर श्रमिक कुशल होगा तो वह समय की बचत करता है वह नई मशीनों की खोज करने में भी सक्षम होता है। जिससे उत्पादन में कई गुणा वृद्धि होती है।

4. **तकनीक** (Technology)—आर्थिक विकास में तकनीकी पिछड़ेपन (Technological Backwardness) के कारण से रूकावट आती है। अल्पविकसित देशों में उत्पादन तकनीक विकसित नहीं होती है जिसकी वजह से उत्पादन क्षमता प्रभावित (affect) होती है। शोध और विकास, उद्योग और शोध संस्थाओं के बीच मन्द आदान प्रदान एवं श्रम की अधिकता और पूँजी की कमी नवप्रवर्त्तन तकनीक को प्रयोग लाने में रूकावट हैं। अल्पविकसित देशों में प्रभावित संस्थाओं की कमी है जो उस देश के लिए उपर्युक्त तकनीक का आविष्कार (Invention) कर सकें। ऐसी अवस्था में अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में इस तरह की तकनीक को आयात करने का प्रयास नहीं किया गया जो उस अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से समाहित हों। अधिकतर उत्पादन क्षेत्रों में उत्पादक (Producer) आधुनिक तकनीक को प्रयोग करना चाहते हैं। लेकिन आदान-प्रदान की और कुछ जगह गरीबी की वजह से प्रयोग करने में रूकावट हैं। उदाहरण के तौर पर भारत कृषक को आधुनिक तकनीक जैसे नए खाद-बीज मशीनरी के बारे में ज्ञान है परन्तु गरीबी की वजह से वह परम्परागत तकनीक (Traditional Technique) का ही प्रयोग करता है यह भी सही है कि आधुनिक तकनीक को प्रयोग करने से कुछ मजदूरों की नौकरी चली जाएगी लेकिन यह स्थिति केवल कुछ समय के लिए हो सकती हैं।

5. **मानव संसाधन विकास** (Human Resource Development)—अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास में अविकसित मानव संसाधन एक बड़ी बाधा है। ऐसे देशों में देश के विकास के लिए आवश्यक कुशलताएँ और ज्ञान वाले व्यक्तियों की कमी होती है। अविकसित मानव संसाधन की वजह से उत्पादन में अधिकतर परम्परागत तकनीक का प्रयोग

TOPPER'S PASS

किया जाता है जिससे कार्यकुशलता की कमी से उत्पादकता कम हो जाती है। यदि कुछ क्षेत्रों में आयातित नई तकनीक का प्रयोग भी किया जाता है तो उस तकनीक अथवा मशीनों का ठीक ढंग से प्रयोग न करने पर टूट फूट, की सम्भावना ज्यादा होती है और इसका सही ढंग से उत्पादकीय उपयोग नहीं हो पाता अतएव अविकसित मानव संसाधन से नीची उत्पादकता, कार्यकुशलता की कमी, विशिष्टीकरण का अभाव, सीमित व्यवसाय और परम्परागत रीतिरिवाजों आदि जैसी स्थिति अर्थव्यवस्था में बनी रहती है जो आर्थिक विकास के लिए रूकावट है और किसी भी देश को आगे बढ़ने से रोकती है।

6. **आधारभूत** (Infrastructure)—अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में मूलभूत सुविधाओं (Fundamental Fecilities) की कमी रहती है जो उत्पादन के क्षेत्र (कृषि तथा उद्योग) को प्रभावित करती है। इन देशों में यातायात एवं संचार के साधन अपर्याप्त, बाजार के छोटे आकार की वजह से इन साधनों का कुशलतम प्रयोग नहीं हो पाता। व्यापार के प्रमुख केन्द्र बड़े-बड़े शहरों में स्थित होने से ग्रामीण क्षेत्र प्रभावित हैं। इससे 70 से 80% जनसंख्या जो ग्रामीण क्षेत्र में विद्यमान रहती है उसकी गतिशीलता (Movability) में मन्दी रहती है। अल्पविकसित देशों में उन्नत एवं पिछड़ी तकनीकों का साथ-साथ प्रयोग करने से एक क्षेत्र (कृषि) दूसरें क्षेत्र से पिछड़ जाता है। साधनों का पर्याप्त विकास न होने पर उत्पादन लागतें ऊँची रहती है। साथ-साथ देश में व्यापार का क्षेत्रीय असन्तुलन (Regional Imbalance) बना रहता है। जबकि विकसित देशों की उन्नति का प्रमुख कारण (Infrastructure) का विकसित होना है।

अल्पविकसित देशों में उद्यमी योग्यता (Entrepreneurial Ability) का भी अभाव पाया जाता है। प्रशिक्षित श्रम एवं प्रबन्ध की कमी, बाजार का आकार, पूँजी की कमी, निजी सम्पत्ति का अभाव, कच्चे माल एवं आर्थिक उपरिसुविधाएँ न मिलने पर भी कुशल उद्यमी नवप्रवर्तन की क्षमता पर निर्भर रहता है। हालाँकि ये आर्थिक विकास में बहुत रुकावट है। उद्यमी को पनपने से भी रोकती है। इसलिए आर्थिक विकास के क्षेत्र में दूसरे तत्त्वों के साथ-साथ (यातायात, संचार के साधन, मशीनीकरण) उद्यमी का भी अहम् स्थान है जो आर्थिक विकास में एक बहुत महत्त्वपूर्ण कड़ी है।

इस प्रकार ये सभी तत्त्व आर्थिक विकास की प्रक्रिया को प्रोत्साहित (Encourage) करते हैं। वे एक दूसरे पर भी निर्भर करते हैं। आर्थिक विकास अतिरेक द्वारा भी प्रभावित होता है क्योंकि अतिरेक निवेश को और निवेश पूँजी निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं। इनके साथ-साथ दूसरे व्यापार से सम्बन्धित तत्त्व जैसे सामाजिक तथा राजनैतिक प्रशासन क्योंकि यदि सामाजिक और राजनैतिक प्रशासन ढीला होगा तो उद्यमी में असुरक्षा की भावना पैदा होगी। जिससे आर्थिक विकास प्रभावित होगा। क्योंकि स्वच्छ, शक्तिशाली और न्यायपूर्ण शासन आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा। लुइस ने कहा है—योग्य सरकार के बिना आर्थिक प्रगति नहीं की जा सकती।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. आर्थिक विकास से सन्दर्भ है—

(क) आर्थिक वृद्धि (ख) आर्थिक स्वतन्त्रता

(ग) सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सतत वृद्धि (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (क) आर्थिक वृद्धि

प्र.2. आर्थिक विकास है—

(क) अनवरत प्रक्रिया (ख) प्रतिबन्धित प्रक्रिया

(ग) (क) और (ख) दोनों (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (ग) (क) और (ख) दोनों

प्र.3. भारतीय अर्थव्यवस्था है—

(क) सामाजिक अर्थव्यवस्था (ख) मिश्रित अर्थव्यवस्था

(ग) स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (ख) मिश्रित अर्थव्यवस्था

प्र.4. निम्न में से कौन आर्थिक विकास का सहगामी है—

(क) मुद्रास्फीति (ख) रिफ्लेशन (ग) मुद्रा अवस्फीति (घ) स्टैगफ्लेशन

उत्तर (क) मुद्रास्फीति

TOUCH 'n' PASS

प्र.5. किसी देश की आर्थिक संवृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदण्ड क्या हैं?
(क) सकल घरेलू उत्पाद (ख) सकल राष्ट्रीय उत्पाद
(ग) प्रति व्यक्ति आय (घ) बेरोजगारी की दर
उत्तर (ग) प्रति व्यक्ति आय

प्र.6. किसी भी देश की औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है?
(क) देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर
(ख) सरकार द्वारा प्राप्त कुल कर की राशि को कुल जनसंख्या से भाग देकर
(ग) गरीबी रेखा के ऊपर के लोगों की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर
(घ) जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए है। उनकी कुल आय को कुल जनसंख्या से गुणा करके।
उत्तर (क) देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर

प्र.7. मानव विकास सूचकांक (HDI) किसने बनाया था?
(क) UNCTAD (ख) ASEAN (ग) UNDP (घ) IBRD
उत्तर (ग) UNDP

प्र.8. मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन हैं?
(क) एडम स्मिथ (ख) अमर्त्य सेन (ग) कीन्स (घ) महबूब-उल-हल
उत्तर (घ) महबूब-उल-हल

प्र.9. आर्थिक विकास के अन्तर्गत सम्मिलित लक्ष्य हैं—
(क) नियमित रोजगार (ख) स्वतन्त्रता
(ग) निर्मित व बेहतर मजदूरी (घ) ये सभी
उत्तर (घ) ये सभी

प्र.10. विकास को मापने हेतु कौन-सा मापदण्ड है?
(क) स्वास्थ्य (ख) प्रति व्यक्ति आय (ग) साक्षरता दर (घ) ये सभी
उत्तर (घ) ये सभी

प्र.11. जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है—
(क) अविकसित (ख) विकसित (ग) अर्द्ध-विकसित (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (ख) विकसित

प्र.12. किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है?
(क) सेवा (ख) कृषि (ग) उद्योग (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (ग) उद्योग

प्र.13. अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति—
(क) तीव्र हो जाती है (ख) सामान्य रहती है (ग) मन्द हो जाती है (घ) कुछ भी नहीं होता
उत्तर (ग) मन्द हो जाती है

प्र.14. स्थायी लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) है—
(क) राष्ट्रीय आय के बराबर (ख) हमेशा सकल घरेलू उत्पाद से अधिक
(ग) राष्ट्रीय आय से अधिक (घ) राष्ट्रीय आय से कम
उत्तर (क) राष्ट्रीय आय के बराबर

प्र.15. निम्नलिखित में से कौन-सा संगठन भारत में सकल घेरलू उत्पाद (GDP) की गणना करता है?
(क) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (ख) वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय
(ग) भारतीय सांख्यिकी संस्थान (घ) भारतीय रिजर्व बैंक
उत्तर (क) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

TOUCH 'n PASS

प्र.16. निम्न में से कौन-सी विधि सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने की नहीं है—
(क) उत्पाद विधि (ख) आय विधि (ग) व्यय विधि (घ) ह्रासमान लागत विधि
उत्तर (घ) ह्रासमान लागत विधि

प्र.17. निम्न में कौन-सा कथन सही है—
(क) साधन लागत पर GDP = शुद्ध मूल्य बढ़ाव + मूल्यह्रास
(ख) साधन लागत पर GDP = शुद्ध मूल्य बढ़ाव – मूल्यह्रास
(ग) साधन लागत पर GDP = शुद्ध मूल्य बढ़ाव + अप्रत्यक्ष कर
(घ) साधन लागत पर GDP = शुद्ध मूल्य बढ़ाव + अप्रत्यक्ष कर
उत्तर (क) साधन लागत पर GDP = शुद्ध मूल्य बढ़ाव + मूल्यह्रास

प्र.18. आर्थिक वृद्धि का मुख्य तत्त्व है—
(क) पूँजी निर्माण (ख) जनसंख्या (ग) प्रौद्योगिकी प्रगति (घ) ये सभी
उत्तर (घ) ये सभी

प्र.19. आर्थिक वृद्धि की आधुनिक अवधारणा किसके द्वारा दी गई?
(क) मोरीस एलिस (ख) लिमोनटीफ (ग) स्टोन (घ) साइमन कुजनेट्स
उत्तर (घ) साइमन कुजनेट्स

प्र.20. आर्थिक विकास का तात्पर्य हैं—
(क) वृद्धि (ख) विकास (ग) वृद्धि एवं परिवर्तन (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (ग) वृद्धि एवं परिवर्तन

प्र.21. आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि से—
(क) संकीर्ण विचार है (ख) व्यापक विचार है
(ग) दोनों समान है (घ) दोनों में बिल्कुल समानता नहीं है
उत्तर (ख) व्यापक विचार है

प्र.22. "विकास मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है" ये शब्द है—
(क) मेयर एवं बाल्डबिन (ख) डब्ल्यू०ए० लुइस (ग) शुम्पीटर (घ) जे०आर० हिक्स
उत्तर (ख) डब्ल्यू०ए० लुइस

प्र.23. निर्माणकारी उद्योग तथा कृषि का सन्तुलित विकास करना सन्तुलित विकास कहलाता है?
(क) किण्डलबर्जर (ख) हर्षमैन (ग) मायर (घ) वाल्डविन
उत्तर (क) किण्डलबर्जर

प्र.24. क्रय शक्ति समता पर आधारित प्रति व्यक्ति ..... द्वारा मापा जाता है?
(क) WDI (ख) GDP (ग) GDI (घ) HPI
उत्तर (ख) GDP

प्र.25. आर्थिक संवृद्धि को प्रभावित करने वाले आर्थिक घटक है—
(क) प्राकृतिक संसाधन (ख) मानवीय संसाधन या श्रम
(ग) पूँजी निर्माण (घ) ये सभी
उत्तर (घ) ये सभी

TOUCH 'n' PASS

UNIT-II

गरीबी एवं असमानता की अवधारणा
Concept of Poverty and Inequality

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. गरीबी की अवधारणा क्या है?

What is concept of poverty?

उत्तर गरीबी का अर्थ भोजन, वस्त्र और आवास सहित बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन न होना है। हालाँकि, पर्याप्त धन न होने से गरीबी कहीं अधिक है। विश्व बैंक संगठन गरीबी का वर्णन इस प्रकार करता है: "गरीबी भूख हैं। गरीबी आश्रय की कमी है।

प्र.2. गरीबी की क्या विशेषताएँ हैं?

What are the Characteristics of poverty?

उत्तर भुखमरी और भुखमरी गरीबी से प्रभावित परिवारों की प्रमुख विशेषताएँ हैं। गरीबों के पास बुनियादी साक्षरता और नौकरियाँ नहीं होती हैं और इसलिए उनकी आर्थिक सम्भावनाएँ कमजोर होती हैं।

प्र.3. गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा क्या हैं?

What is teh concept of vicious circle of poverty?

उत्तर गरीबी का दुष्चक्र प्रोफेसर राग्नार नर्कसे द्वारा दिया गया था। यह कहता है कि आय का निम्न स्तर बचत और निवेश के निम्न स्तर की ओर ले जाएगा। इसलिए कम निवेश से कम उत्पादकता होगी जिससे फिर से कम आय होगी।

प्र.4. गरीबी के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं?

What are the two main types of poverty?

उत्तर पूर्ण गरीबी एक निर्धारित आय स्तर के आधार पर परिवारों की तुलना करती है। और यह स्तर अलग-अलग देशों में इसकी समग्र आर्थिक स्थितियों के आधार पर भिन्न होता है। सापेक्ष गरीबी तब होती है जब परिवारों को औसत घरेलू आय से 50% कम प्राप्त होता है।

प्र.5. वैश्विक भूख सूचकांक कौन जारी करता है?

Who releases the global hunger index?

उत्तर ग्लोबल हंगर हंडेक्स क्या होता है? दुनियाभर के देशों में भुखमरी के हालात को लेकर हर साल रिपोर्ट जारी की जाती है। इसे ग्लोबल हंगर इण्डेक्स नाम दिया गया है। ये रिपोर्ट जर्मनी का गैर-सरकारी संगठन 'वेल्ट हंगर हिल्फ' और आयरलैण्ड का गैर-सरकारी संगठन 'कंसर्न वर्ल्डवाइड' मिलकर जारी करते हैं।

प्र.6. जीवन की गुणवत्ता से क्या तात्पर्य है?

What is the meaning of quality of life?

उत्तर जीवन की गुणवत्ता (अंग्रेज: Quality of Life) (QOL) व्यक्तियों और समाज की सामान्य भलाई हैं। जो जीवन के नकारात्मक और सकारात्मक विशेषताओं को दर्शाती हैं। इसमें जीवन की सन्तुष्टि देखने को मिलती हैं। जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य, परिवार, शिक्षा रोजगार, धन, धार्मिक विश्वास, वित्त और पर्यावरण से लेकर सब शामिल हैं। खुशी सूचकांक क्या निर्धारित करता हैं। वे पोल में पूछे गए मुख्य जीवन मूल्यांकन प्रश्न के उत्तर पर आधारित है। इस कैंट्रिल लैडर कहा जाता है। यह उत्तरदाताओं को एक सीढ़ी के बारे में सोचने के लिए कहता है, जिसमें उनके लिए सबसे अच्छा सम्भव जीवन 10 और सबसे खराब सम्भव जीवन 0 है। फिर उन्हें उस 0 से 10 पर अपने स्वयं के वर्तमान जीवन को रेट करने के लिए कहा जाता है।

TOUCH 'n' PASS

प्र.7. हैप्पीनेस इण्डेक्स से आप क्या समझते हैं?
What do you mean happiness index?

उत्तर हैप्पीनेस इण्डेक्स जीवन सन्तुष्टि, खुशी की भावना और अन्य खुशी को मापता है। डोमेन: मनोवैज्ञानिक कल्याण, स्वास्थ्य, समय सन्तुलन, समुदाय, सामाजिक समर्थन, शिक्षा, कला।

प्र.8. स्थायी विकास का अर्थ क्या हैं?
What is meaning of sustainable development?

उत्तर स्थायी विकास ऐसा विकास है जो भावी पीढ़ियों की अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति की योग्यता से बिना किसी तरह का समझौता किए बिना अपनी मौजूदा आवश्यकताओं की पूर्ति करता हैं।

प्र.9. विकास और सतत विकास क्या हैं?
What is the development and sustainable development?

उत्तर स्थिरता समान आर्थिक विकास पर ध्यान केन्द्रित करती है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएँ बिना सभी के लिए धन उत्पन्न करती है। निवेश और आर्थिक संसाधनों का समान वितरण सम्पूर्ण विकास के लिए स्थिरता के अन्य स्तम्भों को मजबूत करेगा।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. मानव गरीबी पर टिप्पणी कीजिए।
Write a note on human poverty.

उत्तर

मानव गरीबी
(Human Poverty)

अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने गरीबी को आय (Income) के साथ जोड़ा है। लेकिन यह मानव जीवन की अधूरी तस्वीर है। Human Development Report, 1997 में कहा गया है। अच्छा स्वास्थ्य तथा अच्छा जीवन कोई भी बिता सकता है, लेकिन अनपढ़ (Illiterate) होने से कोई भी मनुष्य संचार या दूसरों से विचार विमर्श से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। दूसरा उदाहरण एक आदमी पूर्ण रूप से शिक्षित हैं। लेकिन स्वास्थ्य खराब या किसी बीमारी से पहले मृत्यु हो जाती है। तीसरा प्रकार जो गरीबी को प्रभावित करता है उसको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। इन लोगों की कठिनाइयों को आय पूर्ण रूप से नहीं पकड़ सकती। इससे साफ है कि गरीबी के बारे में पूर्ण विचार प्राप्त करके उसकी मुश्किलें इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करके पूर्ण रूप से गरीबी के बारे में अध्ययन करना चाहिए न कि केवल आय के बारे में कि यही केवल गरीबी का कारण है। मानव गरीब का यही तत्त्व हैं। इसका आशय मानव विकास के लिए अथवा मानव विकास का जो आधार है। उसको नकार दिया गया है। क्योंकि मानव विकास का आधार है— लम्बा जीवन, स्वस्थ, क्रियात्मक जीवन और स्वतन्त्रता आत्म सम्मान, दूसरों का सम्मान।

मानव गरीबी सूचकांक (Human Poverty Index)—1997 में Human Development Report ने गरीबी सूचकांक आरम्भ किया ताकि कम्पोजिट इण्डेक्स जिसमें समुदाय में उपस्थित परेशानियाँ, आदि को Human Development Index के साथ मिला लिया जाए। यह रिपोर्ट बताती है कि गरीबी की माप में (Human Development Index), मानव गरीबी सूचकांक से भी बड़ी है। यह बहुत चीजों को शामिल करती है जैसे—स्वतन्त्रता की कमी, फैसलों में शामिल होने की अयोग्यता, निजी सुरक्षा की कमी, सामुदायिक सेवाओं में शामिल होने की अयोग्यता आदि जिसको माप नहीं सकते। यद्यपि अल्पविकसित देशों में भूख (Hunger), असाक्षरता, अकाल, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी या साफ पानी को शामिल किया गया है। लेकिन Human Development Report में Human Life (मानव) के चार तत्त्व लिए गए हैं। लम्बी आयु, ज्ञान स्वास्थ्य, अच्छा (उच्च) जीवन स्तर।

मानव गरीबी सूचकांक में शामिल होने वाले तत्त्व हैं—

1. मानव गरीबी दरिद्रता/सूचकांक (Human Poverty Index) में उनको लोगों का प्रतिशत जो 40 साल की आयु पहले मरते हैं।
2. असाक्षरता की प्रतिशत दर
3. उच्च जीवन स्तर (High Life Standard) जिसमें साफ पीने का पानी बगैर स्वास्थ्य सेवाओं के लोगों का प्रतिशत, सेनीटेशन सुविधाओं के बिना लोगों का प्रतिशत।

प्र.2. भारत में मानव दरिद्रता व ग्रामीण दरिद्रता का उल्लेख कीजिए।
Explain the human and rural poverty in india.

उत्तर

भारत में मानव दरिद्रता
(Human Poverty in India)

भारत में मानव दरिद्रता बहुत ज्यादा है। मानव गरीबी का सबसे बड़ा तत्त्व हैं। छोटा जीवन, अधिकतर लोगों की 40 साल से पहले मृत्यु हो जाती हैं। भारत में लोगों का 1/ 5 भाग इस आयु से पहले मर जाते हैं। यह औद्योगिक क्षेत्रों की बजाय चार गुणा है। चीन, श्रीलंका, मलेशिया, अर्जेनटीना, क्यूबा, चीन 8 प्रतिशत लोग 40 से पहले मर जाते हैं। तथा भारत में 16 प्रतिशत हैं। 1997 में भारत में 15 साल से ऊपर असाक्षरता 46.5 प्रतिशत यह अल्पविकसित (Under-developed) देशों से 28.4 प्रतिशत ज्यादा है। वियतनाम श्रीलंका, थाईलैण्ड यह 10 प्रतिशत है। 1997 में भारत में 15 वर्ष से ऊपर महिला असाक्षरता 60.4 प्रति औरत तथा आदमी असाक्षरता 30.3 प्रतिशत थी।

ऊपर वर्णित गरीबी के माप के बारे में हमने तीन माप को लिया है। (1) Head Count Approach (2) Squared Gap Poverty Index और Human Poverty Index. यदि हम दरिद्रता के विषय में आकलन करें तो अलग-अलग अर्थशास्त्रियों, नियोजन कमीशन आदि ने अलग-अलग मैथोडोलोजी ली है यद्यपि प्रभाव डालने वाले तत्त्व एक जैसे है। अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने इसको अलग से परिभाषित (Define) नहीं किया है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में दरिद्रता बढ़ने पर ही यह शहर में स्थान्तरित (Transfer) होती है। इसलिए शहरी दरिद्रता और उनकी समस्याओं को अलग से परिभाषित करना कठिन है।

ग्रामीण दरिद्रता
(Rural Poverty)

ग्रामीण दरिद्रता का महत्त्वपूर्ण कारण जनसंख्या वृद्धि है। रोजगार के सिमटते साधनों ने इसको और बढ़ा दिया है। कृषि पर निर्भरता भी इसका कारण है। अधिकतर कृषि मजदूर, छोटे व सीमान्त (Marginal) किसान सभी गरीब है। भारत का सामाजिक राजनीतिक ढाँचा (Structure) भी इसमें सुधार नहीं ला सका। जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि पर दबाव बढ़ने से प्रति व्यक्ति श्रम आय (Per Capita Labour Income) में कमी आयी है। इसके साथ कृषि में लागत कम करने वाली तकनीक के प्रयोग से ग्रामीण (Rural) दरिद्रता में कमी आई है। नई तकनीक के प्रयोग करने पर खाद्यान्न उत्पादन की लागत में कमी से श्रम रोजगार में वृद्धि हुई हैं। आय के प्रभाव को देखते हुए यह गरीबों के हक में है। इसका अर्थ है नई तकनीक को कृषि क्षेत्र में प्रयोग करने पर रोजगार के साथ आय में वृद्धि हुई जो एक महत्त्वपूर्ण साधन है।

ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने एक कार्यक्रम अथवा माप शुरू किया है। जो इसको कम करने में मदद करेगा। इसे Poverty Trickle Down का नाम दिया है।

प्र.3. ग्रामीण क्षेत्र में दरिद्रता व ट्रीकल डाउन का उल्लेख कीजिए।
Explain the poverty and trickle down in the rural poverty.

उत्तर

ग्रामीण क्षेत्र में दरिद्रता व ट्रीकल डाउन
(Poverty and Trickle Down in the Rural Sector)

इस सिद्धान्त के अन्तर्गत गरीबी हटाने के लिए प्रति व्यक्ति आय में तेज वृद्धि की जरूरत है। भारत में एक कृषि विकास (Cultural Development) के सन्दर्भ में इस सिद्धान्त का प्रयोग किया गया। इस सिद्धान्त में माना गया है कि कृषि उत्पादक में बगैर संस्थागत परिवर्तन के वृद्धि इस गरीबी तत्त्व को कम करेगी। Prof. S. Ahluwalia ने माना कृषि क्षेत्र में ट्रीकल डाउन सिद्धान्त मौजूद है। अतएव इसके द्वारा कृषि उत्पादन से प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर गरीबी में कमी आएगी। उनके अनुसार कृषि क्षेत्र में आय वितरण स्थिर रहता है इसलिए इस सिद्धान्त को प्रयोग कर हम उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं और स्थिर आय वितरण, उत्पादन पर विपरीत (Adverse) प्रभाव नहीं डालता है। उनका यह भी मत है कि इच्छा के अनुसार उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती है, अतएव सम्पूर्ण दरिद्रता को समाप्त नहीं किया जा सकता। घरेलू उत्पादन में कृषि आय 2 प्रतिशत बढ़कर है। परन्तु यह गरीबी को खत्म करने के लिए पूर्ण नहीं है।

फिर भी इस सिद्धान्त के साथ हम गरीबी पर काबू कर सकते हैं। प्रो० वरदान ने 60 के दशक में इस सिद्धान्त के रोकने के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए है। उनका मानना है कि नई तकनीक कृषि पर तथा कृषि श्रम पर विपरीत प्रभाव डालती है उनका कहना

है कि श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग कर आय और रोजगार को बढ़ा सकते हैं जोतकर जो कि 1990 में अपनाया गया था। उनके विचार हैं—

1. श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग
2. काश्तकार (Tenent) को बाहर कर जमींदारों को खुद खेती जोतकर आय में वृद्धि
3. कुछ क्षेत्रों में तेजी से कृषि विकास जिससे श्रम का हस्तान्तरण रूके।

इन सब बातों से श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग कर कृषि क्षेत्र में आय के स्रोत बढ़ा सकते है। जिसमें व्यक्ति आय में वृद्धि से गरीबी का स्तर (Level) गिरेगा और यह सिद्धान्त अपने आप लागू होगा। इसके साथ सरकार गरीबी हटाने के लिए काफी कार्यक्रम आरम्भ किए हैं। जैसे Integrated Rural Development Programme (1980), National Rural Employment Programme, Employment Guarantee Programme, etc. जो गाँव में सामुदायिक (Community) सेवाएँ प्रदान करने के साथ ग्रामीण लोगों को रोजगार जुटाने में भी सहायता करेगें। इससे यदि पिछले आँकड़ों (Datas) को देखा जाए तो गरीबी में कुछ गिरावट आई है।

प्र.4. निर्धनता के दुष्चक्र का उल्लेख कीजिए।
(Explain the vicious circle of poverty)

उत्तर

निर्धनता का दुष्चक्र
(Vicious Circle of Poverty)

निर्धनता का दुष्चक्र विभिन्न तत्त्वों के वृत्तीय सम्बन्ध का द्योतक (Indicator) है जो एक-दूसरे से मिलकर इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं कि देश गरीबी की स्थिति में जकड़ा रहता है।

पूर्ति पक्ष की ओर निर्धनता के दुष्चक्र के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण बचत (saving) की अपर्याप्ता है तथा माँग पक्ष की ओर निर्धनता के दुष्चक्र के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण माँग (Demand) की कमी या बाजार का सीमित आकार है।

1. **प्रौद्योगिकीय-द्वैतवाद** (Technology Dualism)—इसका अर्थ है एक अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्था में उत्पादन की उन्नति और पिछड़ी हुई तकनीकों को साथ-साथ प्रयोग किया जाना।
2. **व्यापार की शर्तें** (Terms of Trade)—व्यापार की शर्तें (Stipulation) उस दर से सम्बन्धित है जिस पर किसी देश के निर्यात और आयात में विनिमय (Exchange) होता है।
3. **प्रदर्शन प्रभाव** (Demonstration Effect)—समाज में रहने वाले अन्य व्यक्तियों के श्रेष्ठ उपभोग व्यवहार की नकल करने को प्रदर्शन (Demonstration) प्रभाव कहते है। इसे एक सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय **जेम्स एस० ड्यूजनबरी** (James S. Dussenberry) को है।
4. **संकुचन प्रभाव व विस्तारक प्रभाव** (Backwash Effect and Spread Effect)—संकुचन प्रभाव आर्थिक विकास के प्रतिकूल (Adverse) होते हैं, जबकि विस्तार प्रभाव आर्थिक विकास के अनुकूल होता है। **मिर्डल** के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय असमानताओं का मुख्य कारण प्रबल संकुचन प्रभाव व दुर्बल विस्तारक प्रभाव है।

   प्रश्न यह उठता है कि अर्द्ध-विकसित देश किन कारणों से आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इनके विकास के रास्ते में क्या मुख्य बाधाएँ हैं जिनके कारण इनका विकास नहीं हो पा रहा है। यद्यपि अर्द्ध-विकसित देशों की सामान्य विशेषताएँ ही उनके पिछड़े हुए आर्थिक विकास की कहानी कहती हैं फिर भी इन देशों के आर्थिक पिछड़ेपन (Economic Backwardness) के विभिन्न कारणों का ऐसा सामान्य तत्वों का समूह नहीं है जिसे सभी अर्द्ध-विकसित देशों के पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी कहा जा सके।

प्र.5. दुष्चक्र को तोड़ने के तरीकों का उल्लेख कीजिए।
Explain the methods of breaking the vicious circle.

उत्तर

दुष्चक्र को तोड़ने के तरीके
(Methods of Breaking the Vicious Circle)

प्रो० नर्क्स का कथन है, "हम जानते हैं कि विश्व के कुछ भागों में आर्थिक विकास हुआ है। इसलिए स्पष्ट है कि इन देशों ने किसी न किसी प्रकार इस दुष्चक्र को तोड़ा होगा। इसलिए गतिहीनता के सिद्धान्त के बाद अब विकास-सिद्धान्त का प्रतिपादन

TOUCH 'n PASS

किया जाना चाहिए जिसमें यह विवेचन किया जाना चाहिए कि अर्थव्यवस्था के इस स्थिर पिछड़ेपन से मुक्ति पाने में कौन-सी शक्तियाँ सहायक रही हैं या हैं।''

अर्थात् आर्थिक विकास को प्राप्त करने हेतु दुष्चक्र को तोड़ना अर्द्ध-विकसित (Half-developed) देशों का प्राथमिक (Primary) कार्य होता है परन्तु इस दरिद्रता के दुष्चक्र को समाप्त करना सहज कार्य नहीं है। इसके समाधान के लिए एक प्रभावशाली आन्दोलन की जरूरत है।

सर्वप्रथम पूँजी के पूर्ति पक्ष में दूषित चक्र को तोड़ना होगा, ताकि पूँजी के अभाव की समस्या से मुक्ति पायी जा सकें। इसके लिए हमें—(अ) बचत तथा विनियोग के प्रत्येक सम्भव उपाय का प्रयास करना होगा। (ब) समारोहों, उत्सवों, वैभवपूर्ण उपभोग, आभूषणों आदि अनुत्पादक कार्यों (Unproductive Works) किये जाने वाले व्यय को कम कर, इसे उत्पादक कार्यों में लगाना होगा। (स) जनता के आर्थिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था में उपभोग में कटौती करनी होगी। (द) अर्द्ध-विकसित देशों में व्याप्त अदृश्य (Disguised) बेरोजगारी के रूप में छिपी हुई बचत सम्भावनाओं का प्रयोग किया जा सकता है। (य) अन्त में, पूँजी की जरूरत का कुछ भाग विदेशी सहायता से भी पूरा किया जा सकता है। इन सभी आन्तरिक एवं बाह्य उपायों के द्वारा पूँजी (Capital) के पूर्ति पक्ष के दुष्चक्र को तोड़कर बचत एवं विनियोग को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

इसी प्रकार माँग पक्षीय दुष्चक्र को भी तोड़ा जा सकता है। इसके लिए पूँजी की माँग-वृद्धि एवं बाजार के आकार में वृद्धि करनी होगी। बाजार के विस्तार के लिए सन्तुलित और असन्तुलित विकास के मार्ग अपनाये जा सकते है। सन्तुलित विकास की स्थिति में एक साथ कई प्रकार के विभिन्न उद्योगों में पूँजी का विनियोग (Investment) किया जाता है। जिनके कारण माँग (Demand) में वृद्धि होती है और बाजार का विस्तार होता है। असन्तुलित विकास (Inbance Development) की स्थिति में उद्योगों की स्थापना का भार निजी उद्योगपतियों को सौंपा जाता है।

प्र.7. मानव विकास सूचकांक पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए।
Write a short note on human development index.

उत्तर

मानव विकास सूचकांक
(Human Development Index)

अर्थशास्त्रियों ने एक, दो अथवा अधिक संकेतकों को लेकर मानव विकास के सम्मिश्र सूचकों के निर्माण के लिए मूल आवश्यकताओं के सामाजिक सूचकों को मापने का प्रयास किया है। अब मौरिस द्वारा विकसित जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक (Physical Quality of Life Index) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा विकसित मानव विकास सूचकांक (HDI) का अध्ययन करेंगे।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme, UNDP) के साथ जुड़े हुए अर्थशास्त्री महबूबउल हक ने विकास के एक सर्वमान्य सूचकांक को विकसित करने की दिशा में सबसे पहले प्रयास शुरू किया। उनके कहने पर नोबल पुरस्कार से सम्मानित **प्रो० ए०के० सेन** तथा **प्रो० सिंगर हंस** के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों के एक समूह ने मानव विकास सूचकांक को विकसित किया। HDI की पूरी धारणा इस मान्यता पर अवलम्बित है कि ''किसी राष्ट्र में रहने वाले लोग ही उस राष्ट्र की सम्पत्ति है।'' आर्थिक विकास का मूल उद्देश्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना है। जिससे लोग लम्बे, स्वस्थ और सृजनात्मक जीवन का आनन्द उठा सकें। मानव विकास प्रतिवेदन के अनुसार, ''मानव विकास लोगों की पसन्दगियों के विस्तृत करने की एक प्रक्रिया है।'' ये पसन्दगियाँ अनेक हो सकती हैं और इन पसन्दगियों में समय के साथ परिवर्तन हो सकता है लेकिन विकास के प्रत्येक स्तर पर तीन जरूरी पसन्दगियाँ हैं। और ये हैं—लम्बी और स्वस्थ जिन्दगी जीने की इच्छा, ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा और एक खूबसूरत जिन्दगी व्यतीत करने के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुँचने की इच्छा। यदि ये तीनों पसन्दगियाँ उपलब्ध नहीं है तो व्यक्ति को अनेक अवसरों से वंचित (Deprive) होना पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति को एक खूबसूरत जिन्दगी व्यतीत करने के लिए (i) आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने के लिए आय (ii) शिक्षा और (iii) स्वास्थ्य जरूरी हैं।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. भारत में गरीबी का विचार इसके घटकों व सीमाओं का वर्णन कीजिए।
Describe the concept, factors and limitations of poverty in India.

उत्तर अधिकांश सभी अल्पविकसित देश (Under-developed Countries) जहाँ प्रति व्यक्ति आय कम, आय असमानता (Disparity) ने कई बुराईयों को जन्म दिया है। जिनमें से गरीबी एक है। भारत में पाँच दशकों में विकास होने के बावजूद 24.8

प्रतिशत लोग गरीब है। वर्तमान आय के समान वितरण करने के बाद क्या हर एक अमीर होगा, लेकिन इसमें शक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति न्यूनतम उपभोग करेगा।

गरीबी की अवधारणा
(The Concept of Poverty)

प्राय: यह माना जाता है कि जो एक निश्चित न्यूनतम उपभोग (Minimum Consumption) स्तर प्राप्त नहीं करता है वो गरीब (Poor) कहलाएगा। लेकिन अर्थशास्त्रियों ने यह पता लगाने में असमर्थता जाहिर कि क्या आय कीमत एक समय पर न्यूनतम उपभोग स्तर को प्राप्त करने के लिए गारण्टी देती हैं। 1962 में भारत सरकार ने निरीक्षण किया कि राष्ट्रीय स्तर पर उपभोग का स्तर क्या होना चाहिए। इस ग्रुप ने निजी उपभोग का खर्च ₹ 20 (1960-60 कीमत पर) प्रति व्यक्ति प्रति माह ग्रामीण और शहरी रहन-सहन पर कोई अन्तर नहीं किया। यद्यपि यह साफ नहीं था कि किस आधार पर यह न्यूनतम स्तर बनाया लेकिन काफी लोगों ने इस पर प्रश्न चिह्न लगाया क्योंकि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने की लागत अलग-अलग हैं।

नियोजन कमीशन ने (Task Force) द्वारा दी गई परिभाषा से गरीबी को परिभाषित करने हेतु विकल्प माना है। इनका पावर्टी मैथड को प्रयोग करते हुए गरीबी प्रति व्यक्ति खर्च जिसमें कैलोरी की मात्रा गाँव में 2400 कैलोरी प्रतिदिन और 2100 शहरी क्षेत्र में इसके पूरा करने के लिए ₹ 49 ग्रामीण क्षेत्र में तथा ₹ 57 शहरी क्षेत्र के लिए (1973-74 की कीमतों पर) G. Dutt, B Ozler, M. Ravallion, S.D. Tendulkar और L.R. Jain ने भी रीबीर रेखा का प्रयोग किया हैं।

गरीबी के घटक (Factors of Poverty)

भारत में गरीबी पर सही रूप से आँकड़े (Datas) उपलब्ध नहीं हैं। इस देश ने इस तरह के आँकड़ें इकट्ठे करने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किया। NSS के उपभोग आँकड़े (गरीबी) इस तरह की सूचना प्रदान करते हैं जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी के घटक को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो निम्नलिखित हैं—

1. **Head Count Approach**—भारत में गरीबी के अंदाज के बारे में दांडेकर और रथ, वरदान और अहलूवालिया ने आँकड़े प्रस्तुत किए हैं लेकिन वे काफी पुराने और गरीब घटक है और गरीबी के घटक जो उपलब्ध है, उनके बारे में सही स्थिति प्रदान नहीं करते। **प्रो० मिन्साह** के अनुसार, 1967-68 में गरीबी रेखा से नीचे 37.1 प्रतिशत थे और अहलूवालिया 56.5 प्रतिशत व वरदान ने 54 प्रतिशत उसी वर्ष और 1968-69 के लिए दांडेकर व रूप ने 40 प्रतिशत बनाया हैं। प्रो० वरदान दांडेकर व रथ ने मिहास से गरीबी रेखा थोड़ी सी नीचे दिखाई हैं। इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इन अर्थशास्त्रियों ने एक जैसे आँकड़े प्रयोग कर मैथोडोलौजी अलग-अलग प्रयोग की है। इन सब बातों से यही पता चलता है कि 1960 में गरीबी की संख्या काफी थी वरन इस देश की कुल जनसंख्या का बड़ा हिस्सा गरीबी में था।

   नियोजन कमीशन ने भी आँकड़ों के घटक के अंदाज लगाए हैं जो ग्रामीण जनसंख्या के लिए ₹ 49 (1973-74 कीमतों पर) प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा शहरी क्षेत्र (शहरी जनसंख्या) ₹ 57 (1973-74 की कीमतों पर)। इन घटकों से 1978-79 में 51.2 प्रतिशत गरीब ग्रामीण क्षेत्र में और 38.22 शहरी क्षेत्र में। ये आँकड़ें 1978-79 में उपलब्ध थे। नियोजन कमीशन द्वारा प्रयोग की गई मैथोडोलॉजी की आलोचना की गई और यह महसूस किया गया कि गरीब से सम्बन्धी सारे तत्त्वों को दोबारा निरक्षित किया जाए। नियोजन कमीशन ने एक्सपर्ट ग्रुप बनाया। जो प्रयोग की गई मैथोडलॉजी का निरीक्षण करें। एक्सपर्ट ग्रुप ने टास्क फोर्स द्वारा लिया गया अथवा उसके द्वारा दिया गया सुझाव को मान लिया गया। इनका यह मानना था कि कीमत रेखा को भी ध्यान में रखा जाए।

सूची-1
गरीबी से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत
(नियोजन कमीशन के अंदाज एक्सपर्ट ग्रुप की मैथोडोलॉजी)

क्षेत्र	1983-84	1987-88	1993-94
ग्रामीण	46.6	39.1	37.3
शहरी	42.2	40.1	32.4
दोनों	44.8	39.3	36.4

TOUCH 'n' PASS

स्त्रोत : भारत सरकार, एक्सपर्ट ग्रुप की रिपोर्ट के आधार पर, गरीबों की संख्या 1993, भारत सरकार, नियोजन कमीशन, नवीं पंचवर्षीय 1997-2002 Vol I.

वर्तमान समय में नियोजन कमीशन ने गरीबी को मापने के लिए दो विभिन्न अंदाज अपनाए हैं। यह सब 1978 के बाद स्थिति दर्शाते हैं। इन अंदाजों के आधार पर (वही प्रश्न चिन्ह लगी मैथोडोलॉजी का प्रयोग) बताया है कि भारत में गरीबी रेखा में तेजी से गिरावट आई है जो घटकर 29.8 प्रतिशत (987-88) से 1994-95 में रह गई है। यद्यपि इन आँकड़ों की उपयोगिता (Utility) सही न होने पर इनका प्रयोग नहीं किया गया हैं। एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा सुझाव दी गई मैथोडोलॉजी को प्रयोग करने के पश्चात् नियोजन कमीशन के खुद के आँकड़ें इससे ज्यादा जो सूची-1 में दर्शाये गए हैं। वर्तमान समय में वर्ल्ड बैंक के पावर्टी और ह्यूमन रिसार्स डिविजन द्वारा भी आँकड़े दर्शाए गए हैं। जिनमें काफी लम्बा समय प्रयोग किया गया हैं। (1950-1951 से 1973-74) इसके बाद 1989-90 तक गरीबी में कमी आई है उसके बाद यह उल्टी हो गई है। 1993-94 में ग्रामीण क्षेत्रों में 38.7 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र 30 प्रतिशत गरीब जनसंख्या (Population) थी।

2. **हैड कांउट गैर-भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण की सीमाएँ** (Limitations of the Head-Count Non-Discriminatory Approach)—ऊपर जो गरीबी के घटक लिए गए है। वे सब इस सीमा के द्वारा मापे गए हैं। इसके द्वारा जो माप दिए गए हैं। कि ₹ 77 या इससे कम या ज्यादा रुपये गरीबी को निर्धारित करते हैं। क्योंकि यदि वह आदमी ₹ 77 कमा रहा है तो ठीक है यदि ₹ 25 कमा रहा है तो उसे किसी सूची में रखा जाए।

अमर्त्य सेन ने कहा है गरीब एक आर्थिक वर्ग नहीं है यदि हमने गरीबी को मापना है तो उसे प्रभावित करने वाले पहलू (Aspects) सामाजिक या अन्य कोई उसको देखना चाहिए। गरीबी सर्वेक्षण को दोबारा लिया गया है। (1) बराबर आय प्रयोग कर किसको कितना मिला है और कुछ आय के तत्त्व प्रयोग कर गरीबी को रेखांकित किया (2) वास्तव में स्थिति कितनी खराब है और एक की स्थिति दूसरे की स्थिति से खराब है। इस सन्दर्भ में "अमर्त्य सेन ने कहा है यह सम्पूर्ण तथ्य नहीं है कि कितने लोग गरीब हैं, बल्कि किस हद तक वे गरीब हैं। "प्रो. सेन के मत से सब गरीबी की समस्या को टेकल करते हैं। वर्तमान समय में प्रो० आजलर, दत्त व रेवेलन ने वर्ल्ड बैंक के लिए किए गए अध्ययन में गरीबी अन्तर अनुपात और प्रभावित अन्तर अनुपात 1951-94 समय के लिए प्रयोग किया है। ये गरीबी के घटक के साथ-साथ गरीबी की गहराई को भी मापते हैं।

उनके बीच और गरीबी की रेखा के बीच का अन्तर है। पावर्टी गेप आय के हस्तान्तरण को मापता है जो गरीब को गरीबी रेखा तक पहुँचने के लिए है। ऐसी हालत में यह सिद्धान्त गरीबी की गहराई के साथ इसके घटक को भी मापता है। यद्यपि यह सिद्धान्त गरीबों की आय के बीच असमानता है। उसका व्याख्यान नहीं करता। यदि एक गरीब की आय को दूसरे गरीब के पास हस्तान्तरित किया जाए तो कौन ज्यादा गरीब है। क्योंकि गरीबी सूचकांक में इससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यह सीमा ज्यों कि त्यों खड़ी हुई है वरना तो गरीबी अन्तर माप सामान्य (Head-Count) से उच्च होने चाहिए।

पावर्टी गेप इण्डेक्स से शहरी क्षेत्र में भी गरीबी मापी गई है। ओजलर, दत्त व रेवेलियन वर्ल्ड बैंक के पावर्टी एण्ड ह्यूमन डिविजन डैवल्पमैट के लिए प्रयोग किया है। ये आँकड़े भी बताते है। कि 1950-51 से 1973-74 तक कोई ज्यादा अन्तर दिखाई नहीं देता लेकिन उसके बाद 1989-90 तक गरीबी सूचकांक कम हुआ है। नब्बे के प्रारम्भ में यह स्तर उल्टा था और 1993-94 में पावर्टी गेप इण्डेक्स ग्रामीण जनसंख्या के लिए 9.1 और शहरी जनसंख्या के लिए 7.62 था।

3. **स्केयेरड पावर्टी गेप इण्डेक्स** (The Squared Poverty Gap Index)—यह माप गरीबों के बीच आय असमानता को दर्शाती है। इसको हम आय गरीबी को मापने का सही तरीका कह सकते हैं।

इस स्केयेरड पावर्टी गेप इण्डेक्स को प्रो० ओजलर, दत्त और रेवेलियन ने साफ तौर पर बताया है कि 1950-51 से 1973-74 तक गरीबी में कोई अन्तर नहीं आया है। यद्यपि 1974 के बाद स्केयेरड पावर्टी इण्डेक्स ग्रामीण और शहरी जनसंख्या दोनों की कम हुई हैं। 1993-94 में ग्रामीण जनसंख्या के लिए 3.27 और शहरी के लिए 2.76 स्केयेरड पावर्टी इण्डेक्स था। 1973-74 में ग्रामीण में 7.13 और शहरी में 5.22 था। इसका मतलब इस सूचकांक में कमी हुई है।

अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में गरीबी हटाने के लिए महत्त्वता दी गई है लेकिन सरकार को नीतियाँ बनाने से पहले यह निर्धारित करना चाहिए कि गरीब है कौन? सरकार ने इस बारे में कोई विशेष प्रयास नहीं किए हैं। NSS आँकड़ों को प्रयोग करते हुए, मिंहास, रथ दांडेकर और कुछ दूसरे अर्थशास्त्रियों ने इसको परिभाषित किया है।

TOUCH 'n PASS

1. घरेलू कृषि मजदूर जो भूमिहीन हैं, घरेलू श्रमिक मजदूर का 60 प्रतिशत हैं।
2. कृषि मजदूर घर जिसके पास थोड़ी जमीन हैं वे कृषि मजदूर का 40 प्रतिशत है।
3. गैर कृषि मजदूर घर जिसमें गाँव के कारीगर भी शामिल है और जो भूमिहीन हैं।
4. कम भूमि मालिकाना जो 2 एकड़ जमीन से कम को जोतते हैं वरन् 1 एकड़ से कम है।

शहरी गरीबों दांडेकर और रथ ने अलग से परिभाषित नहीं किया है वरन् शहरी गरीबों को उन्होंने ग्रामीण गरीबों की ज्यादा माँगों से जोड़ा है। जो ग्रामीण गरीब गाँव में रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते हैं और शहरों में चले जाते हैं। वे शहरी गरीबी में निवास करते हैं। बढ़ते हुए शहरों से उनकी श्रम और जीवन के बारे में कम पता चलता है।

प्र.2. जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का वर्णन कीजिए।

Describe the physical quality of life index.

उत्तर

जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचक
(Physical Quality of Life Index)

मौरिस डी० मौरिस (Morris D. Morris) ने 1979 में 23 विकसित और विकासशील देशों के जीवन की सम्मिश्र भौतिक गुणवत्ता (Composite physical quality of life) का तुलनात्मक (Comparative) अध्ययन किया। उसने शिशु मृत्युदर, एक वर्ष की आयु में जीवन सम्भाव्यता तथा 15 वर्ष की आयु में मूल शिक्षा जैसे तीन सूचक घटकों को, लोगों की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के कार्य के मूल्यांकन (Evaluation) जोड़ा। इस सूचक से बहुत से सूचकों, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पोषण और स्वच्छता आदि का पता चलता है। प्रत्येक सूचक के तीनों घटकों को शून्य से 100 तक के पैमाने पर रखा गया है जिसमें शून्य को मन्दत्तम और 100 को सर्वोतम प्रदर्शन के रूप में परिभाषित किया गया है। PQLI सूचक की गणना तीनों घटकों को समान भार (Weight) देते हुए औसत निकालकर की जाती है और सूचक को भी शून्य से 100 के पैमाने पर रखा गया है।

मौरिस के अनुसार, तीनों सूचकों में से प्रत्येक सूचक परिणाम को मापता है न कि आगतों को, जैसे आय। प्रत्येक सूचक आवंटन प्रभावों के प्रति संवेदनशील है अर्थात् इन सूचकों में वृद्धि अथवा सुधार से लोगों को उसी अनुपात में मिलने वाले लाभ का पता चलता है लेकिन कोई भी सूचक विकास के किसी स्तर विशेष पर निर्भर नहीं है। प्रत्येक सूचक की अन्तर्राष्ट्रीय तुलना (Comparison) की जा सकती हैं। सन् 1950 में गेबन की शिशु मृत्युदर 229 प्रति हजार को मन्दत्तम मानते हुए मौरिस ने इसे शून्य पर स्थिर कर दिया, और इसकी उच्चतम सीमा को सन् 2000 तक 7 प्रति हजार का लक्ष्य बनाया गया। इसी तरह, वियतनाम में एक वर्ष की आयु पर जीवन संभाव्यता सन् 1950 में 38 वर्ष ली। इसे मौरिस ने जीवन संभाव्यता (Life Expectancy) सूचक पर शून्य का स्थान दिया। इसकी उच्चतम सीमा पुरुषों में और महिलाओं को मिलाकर सन् 2000 तक 77 वर्ष रखी गई। अन्त में, 15 वर्ष की आयु में शिक्षा की दर को शिक्षा सूचक बनाया गया। मौरिस ने इसके सहसम्बन्ध निम्न अनुसार प्रस्तुत किए हैं—

(N = 150)	शिशु मृत्युदर	जीवन संभाव्यता
एक वर्ष की आयु में जीवन संभाव्यता	– 0.919	–
शिक्षा	– 0.919	0.897

एक वर्ष की आयु में जीवन संभाव्यता और शिशु मृत्युदर के बीच सहसम्बन्ध (Correlation) का गुणांक उच्च डिग्री और ऋणात्मक (negative) हैं। इस प्रकार का सहसम्बन्ध शिक्षा तथा शिशु मृत्युदर के बीच है अर्थात् शिक्षा के साथ शिशु–मृत्युदर में गिरावट आती हैं। शिक्षा और जीवन संभाव्यता के बीच गुणांक ऊँची डिग्री का धनात्मक (Positive) सह–सम्बन्ध दर्शाता है। अर्थात् शिक्षा के साथ–साथ जीवन संभाव्यता में भी वृद्धि होती है। मौरिस के अनुसार, एक वर्ष की आयु में जीवन संभाव्यता और शिशु मृत्युता जीवन की भौतिक गुणवत्ता के अच्छे सूचक हैं और यही बात शिक्षा एवं जीवन संभाव्यता के बारे में कही गई हैं। वास्तव में शिक्षा सूचक विकास की संभावना को व्यक्त करता है।

नीचे तालिका में दो विकसित एवं दो विकासशील देशों की GNP प्रतिव्यक्ति वृद्धि दर और PQLI से सम्बन्धित आँकड़ें प्रस्तुत हैं—

TOUCH 'n PASS

तालिका : जीवन केा भौतिक गुणवत्ता निष्पादन तथा GNP प्रतिव्यक्ति वृद्धि दर

देश	1950	(PQLI) 1960	1970	औसत वार्षिक GNP प्रति व्यक्ति वृद्धि दर %
भारत	14	30	40	1.8
श्रीलंका	65	75	80	1.9
इटली	80	87	92	5.0
संयुक्त राज्य अमेरिका	89	91	93	2.4

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि भारत जिसे मौरिस "बास्केट केस" (Basket Case) कहता है, अपनी GNP प्रति व्यक्ति 1.8% की धीमी वृद्धि दर के बावजूद, 1950 से 1970 तक की दो दशकों की अवधि में इसके PQLI में 14 से 40 तक की धीमी, लेकिन कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। उसी अवधि के दौरान श्रीलंका का PQLI भारत से कहीं अधिक था, यद्यपि इसकी औसत GNP प्रति व्यक्ति दर (1.9%) लगभग भारत के बराबर रही। अमेरिका और इटली दोनों विकसित देशों का PQLI काफी ऊँचा था यद्यपि इटली की प्रति व्यक्ति GNP दर (5%) अमेरिका (2.4%) से लगभग दोगुनी थी। इस सन्दर्भ में मौरिस ने देखा की प्रतिव्यक्ति GNP दर और PQLI के बीच कोई स्वत: तालमेल (Coordination) नहीं हैं। वास्तव में, सामाजिक सम्बन्धों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति, पोषण सम्बन्धी दर्जा, लोगों का स्वास्थ्य, शिक्षा और पारिवारिक वातावरण, किसी समाज के PQLI को निर्धारित करते हैं। इसके अतिरिक्त, उच्च PQLI को बनाने और बनाए रखने में सहायक संस्थागत प्रबन्ध के निर्माण में बहुत समय लग जाता है।

इसकी सीमाएँ (Its Limitations)

मौरिस ने यह स्वीकार किया है कि PQLI मूल आवश्यकताओं को केवल एक सीमा (Limit) तक ही माप सकता है। यह GNP का परिपूरक हैं न कि विस्थापक। यह आर्थिक वृद्धि को मापने का काम भी नहीं करता है। इसके अलावा यह सामाजिक और आर्थिक संगठन के बदलते हुए ढाँचे को भी नहीं दिखाता। इसलिए यह आर्थिक विकास को नहीं मापता। इसी तरह, यह कुल कल्याण को भी नहीं मापता है। फिर भी, यह जीवन की गुणवत्ताओं को मापता है जो गरीबों के लिए बहुत जरूरी है।
मौरिस द्वारा PQLI के प्रयुक्त तीन चरों को मनगढ़ंत भार देने के कारण मौरिस की आलोचना हुई। **प्रो० मायर** के अनुसार, "PQLI द्वारा लिए गए गैर-आय वाले घटक महत्त्वपूर्ण हैं, परन्तु उतने ही महत्त्वपूर्ण समग्र गरीबी सूचकांक को प्राप्त करने के लिए समूहन (Aggregation) के वितरण संवेदनशील (Sensitive) तरीके और आय तथा उपभोग आँकड़ें होते हैं।
निष्कर्ष (Conclusion)—इन सीमाओं (Limitations) के बावजूद, PQLI विशेषकर अल्पविकास के विशेष क्षेत्रों का पता लगाने और सामाजिक नीतियों की असफलता अथवा उपेक्षा के शिकार समाज के विभिन्न वर्गों की जानकारी प्राप्त करने में काम आ सकता है। यह उस सूचक की ओर इंगित करता है जहाँ तुरन्त कार्रवाई की जरूरत है। सरकार ऐसी नीतियाँ अपना सकती है। जिनसे PQLI में भी शीघ्र वृद्धि हो तथा आर्थिक विकास भी बढ़े।

प्र.3. जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता का वर्णन कीजिए।
Descuss the physical quality of life index.

उत्तर

जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता
(Physical Quality of Life Index)

मॉरिस डेविड मॉरिस ने 1970 के दशक के मध्य में ओवरसीज डेवलपमेण्ट काउंसिल के लिए फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इण्डेक्स (PQLI) बनाया। विकास संकेतक के रूप में जीएनपी के उपयोग से अप्रसन्नता के जवाब में इसका गठन किया गया था। PQLI एक कदम आगे हैं, लेकिन यह अभी भी उन्हीं मुद्दों से ग्रस्त है, जो जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करने के अन्य प्रयासों में हैं। शिशु मृत्यु-दर और जीवन प्रत्याशा के इतने निकट से सम्बन्धित होने के कारण इसे भी दण्डित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक, खुशी का एक अधिक सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला मीट्रिक हैं।
फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इण्डेक्स (PQLI) किसी देश के समग्र जीवन स्तर या यहाँ तक कि अच्छी तरह से मापने का एक प्रयास है। संख्या की गणना तीन तथ्यों और आँकड़ों का औसत लेकर की जाती है। बुनियादी साक्षरता दर, नवजात मृत्यु दर और एक वर्ष में उनका जीवन काल, जिनमें से सभी को 0 से 100 के पैमाने पर समान रूप से आंका जाता है। यह 1970 के मध्य में मॉरिस डेविड मॉरिस द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी समिति के लिए आर्थिक विकास के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में जीएनपी के उपयोग के माध्यम से असन्तोष के जवाब में उत्पादित कई मेट्रिक्स में से एक के रूप में खोजा गया था।

TOUCH 'n' PASS

जबकि जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता को एक सुधार माना जा सकता है, यह जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करने से जुड़ी बुनियादी कठिनाइयों को साझा करता है। इसके अतिरिक्त, नवजात मृत्यु-दर के बीच पर्याप्त अतिव्याप्ति के कारण इस पर सवाल उठाया गया है। जीवन प्रत्याशा दर उन वर्षों की औसत संख्या का प्रतिनिधित्व करती है जो एक व्यक्ति के जीने की भविष्यवाणी की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में औसत आयु 66.8 वर्ष है।

शिशु मृत्यु-दर नवजात शिशुओं की संख्या है जो प्रत्येक 1000 जन्मों के लिए शैशवावस्था के पहले वर्ष के दौरान मर जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, यह प्रति 1000 लोगों पर 47 है।

बुनियादी साक्षरता दर : सात वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो कम से कम एक भाषा पढ़ और समझ सकता है, शिक्षित माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार, यह भारत में 74.04 प्रतिशत है।

उपरोक्त मानदण्डों में से प्रत्येक को 1 से 100 के पैमाने पर स्कोर किया जाता है, जिसमें 1 सबसे खराब प्रदर्शन है और 100 उच्चतम प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। इन तीन मापदण्डों की तुलना करके और प्रत्येक को समान योग्यता आवंटित करके जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता की गणना की जाती है।

PQLI के लाभ (Advantages of POLI)

PQLI के लाभ यह है कि यह अर्थव्यवस्था की समग्र भलाई और इसके कल्याणकारी उपायों को क्रियान्वित करने वाली प्रभावशीलता को समझने में सहायता करता है। यह उपचारात्मक उपायों को लागू करने में सरकार की सहायता करता है। जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत है। अत: इसका उपयोग राष्ट्रों की तुलना करने के लिए किया जा सकता है, जो तुलनात्मक रूप से गरीब देशों को उपचारात्मक कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है जो पीक्यूएलआई के फायदों में से एक हैं।

तीन मेट्रिक्स, अर्थात् जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु-दर और साक्षरता, सभी देश की जनसंख्या की भलाई को सटीक रूप से दर्शाते हैं। एक राष्ट्र जो तीनों मापदण्डों पर अच्छा स्कोर करता है, उसे एक सफल अर्थव्यवस्था माना जाता है। यह PQLI का एक और फायदा हैं।

जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता देश की आय के बँटवारे का मूल्यांकन करती है। किसी राष्ट्र की उच्च जीवन प्रत्याशा, लम्बी जीवन प्रत्याशा या निम्न नवजात मृत्यु-दर तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उसके निवासियों का एक महत्त्वपूर्ण अनुपात आर्थिक प्रगति से लाभान्वित न हो।

PQLI की कमियाँ (Disadvantages of POLI)

जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता विभिन्न प्रकार के तत्त्वों की अनदेखी करती है जो नौकरी, आवास, न्याय, जीवन प्रत्याशा दर और राज्य पेंशन सहित किसी के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।

जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा दर का एक अंकगणितीय माध्य है, जिसमें प्रत्येक तत्त्व को समान महत्त्व दिया जाता है। हालाँकि, यह देखना कठिन है कि सभी तत्त्वों को समान भार क्यों दिया जाना चाहिए।

जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता किसी देश की अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक रूप से बदलने के लिए जिम्मेदार नहीं है।

निष्कर्ष (Conclusion)—जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता देशों के लिए एक आवश्यक घटक है। जैसा कि, इसका उपयोग राष्ट्रों की तुलना करने के लिए किया जा सकता है, जो तुलनात्मक रूप से गरीब देशों को उपचारात्मक कार्रवाई करने में सहायता करता है। तीन संकेतक, अर्थात् जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु-दर और साक्षरता दर, देश के नागरिकों की भलाई को सटीक रूप से दर्शाते हैं।

प्र.4. **सतत विकास प्राप्त करने में शिक्षा की भूमिका एवं परिकल्पना का वर्णन कीजिए।**
Describe the role of education in achieving sustainable development.

उत्तर

सतत विकास प्राप्त करने में शिक्षा की भूमिका
(Role of Education in Achieving Sustainable Development)

सतत विकास, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया था, औपचारिक रूप से वर्ष 1992 से विश्व समुदाय के लिए आरम्भ किया गया था। इसमें शिक्षा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह पर्यावरणीय विषयों से जुड़ा हुआ है। कोविड–19 महामारी से उत्पन्न त्रासदी

TOUCH 'n PASS

विश्व को बेहतर निर्माण का एक अविश्वसनीय अवसर भी प्रदान करती है। शैक्षणिक संस्थान, चाहे वे कॉलेज, स्कूल या विश्वविद्यालय हों, उनको यह सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करना चाहिए कि विश्व के नीति निर्माताओं और नेताओं को विश्व की तेजी से जटिल विकास समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएँ।
इस तरह, सतत विकास के लिए शिक्षा अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है और मानव निर्मित निर्णयों से उत्पन्न होने वाली सतत विकास सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करती है। मानव संसाधनों में निवेश के रूप में शिक्षा कारकों के बीच महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो सतत विकास में योगदान करती हैं।

ई एस डी सतत समाज को प्रोत्साहित करती है (ESD promotes and encourages Sustainable Society)—एक से अधिक सतत समाज को प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण कुँजी और उपकरण है। 2002 में जोहान्सबर्ग (Johannesburg) में संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में इस महत्त्व पर जोर दिया गया था, जहाँ वर्तमान शिक्षा प्रणालियों की पुन: संरचना को एस डी० (सतत विकास) की कुँजी के रूप में रेखांकित किया गया था। यह ध्यान दिया जा सकता है कि एस डी के लिए शिक्षा एक सतत समाज बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल, मूल्यों और कार्यों के विकास को प्रोत्साहित करती है, जो पर्यावरण संरक्षण और रक्षण सुनिश्चित करती है, सामाजिक समदृष्टि को प्रोत्साहित करती है, और आर्थिक कल्याण को उत्साहित करती हैं। परम्परागत रूप से, भारत एक सतत समाज रहा है। शिक्षा में सतत विकास के मूल्य को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने अपने विभिन्न शिक्षा विभागों को पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में पर्यावरण शिक्षा (Environment Education-E E) घटक पर सक्रिय रूप से काम करने का निर्देश दिया।

सतत विकास के लिए शिक्षा (ई०एस०डी०) का उद्देश्य पर्यावरण के बारे में ज्ञान का विकास करना है (ESD aims to develop knowledge about environment)—ई०एस०डी० की अवधारणा मूल रूप से पर्यावरण शिक्षा से विकसित हुई, जिसने पर्यावरण के संरक्षण पर अधिक ध्यान देने के लिए लोगों में ज्ञान, कौशल, मूल्यों और व्यवहार को विकसित करने की माँग की है। ई०एस०डी० का उद्देश्य लोगों को पृथ्वी ग्रह से समझौता किए बिना निर्णय-निर्माण और कार्यों को करने में सक्षम बनाना है। कोविड—19 (COVID-19) महामारी ने वैश्विक संकट को जन्म दिया है, जो अभूतपूर्व चुनौतियों को पूरा करने की हमारी क्षमता को गम्भीर रूप से प्रतिबन्धित कर रहा है। कॉलेजों, स्कूल और विश्वविद्यालय के बन्द होने से विश्व भर में 90 प्रतिशत छात्रों को शिक्षा संस्थानों से बाहर रखा गया हैं। परिवारों पर दबाव तीव्र हैं। नौकरियाँ समाप्त हो रही है और आय में कटौती हो रही है। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध घरेलू हिंसा बढ़ रही है।
जलवायु परिवर्तन और जीवित विश्व का पतन अपेक्षाकृत बहुत तेजी से हो रहा है। इसके परिणाम विश्व भर में अनुभव किए जा रहे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और साइबेरिया में बड़ी तेजी से जंगल की आग ने अपनी भयंकरता के रिकॉर्ड तोड़ दिए है। हाल के महीनों में, दक्षिण-एशिया में बाढ़ ने 25 मिलियन से अधिक लोगों को अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर किया है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ई०एस०डी० का उद्देश्य मानव निर्मित समस्याओं के बारे में लोगों के ज्ञान और व्यवहार को व्यापक बनाना है। ई एस डी का उद्देश्य पृथ्वी के संसाधनों से समझौता किए बिना लोगों को निर्णय लेने और कार्यवाई करने में योग्य बनाना हैं।

ई०एस०डी० की रूपरेखा सतत विकास के सिद्धान्तों और कार्यों के एकीकरण को प्रस्तुत करती है। (ESD outlines integration of principles and practices of Sustainable Development)—यूनेस्को (UNESCO) द्वारा उल्लिखित दशक (दस वर्षों का समय) (2005-2014) का लक्ष्य सतत विकास के सिद्धान्तों, मूल्यों, और कार्यों को शिक्षा के सभी पहलुओं और आयामों में एकीकृत करना है। इस प्रकार, इसका उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन को प्रोत्साहित करना है, जो अधिक सतत भविष्य का निर्माण करेगा। डी०ई०एस०डी० (Decade of Education for Sustainable Development–DESD) के सबसे महत्त्वपूर्ण पहलुओं में से एक मान्यता यह है कि ई एस डी को हितधारकों-सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समाज और आम जनता की व्यापक श्रेणी को संलग्न करना चाहिए।
ई०एस०डी० को प्रोत्साहित करने के लिए, सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र की दशक शिक्षा को (DESD) 2005-2014 संयुक्त राष्ट्र के साथ अपनाया गया था, शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) को पूरे दशक में पदोन्नति के लिए प्रमुख एजेन्सी के रूप में नामित किया गया था। दशक एक वैश्विक दृष्टि का अनुसरण करता है'' एक ऐसा विश्व, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से लाभ उठाने और सतत भविष्य के लिए और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक मूल्यों, व्यवहार और जीवनशैली को सीखने का अवसर मिलता है।

डी ई एस डी (DESD) के लिए अपनी अन्तर्राष्ट्रीय कार्यान्वयन योजना में, यूनेस्कों का कथन है कि ई०एस०डी० मूल रूप से व्यवहारों और मूल्यों के विषय में है, विशेष रूप से दूसरों के लिए सम्मान, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों सहित, पर्यावरण और पृथ्वी संसाधनों के विषय में (यूनेस्को, 2006)। शिक्षा हमें अपने आप को और दूसरों को और व्यापक प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के साथ हमारे सम्बन्धों को समझने के योग्य बनाती हैं। यह समझ सम्मान के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार के रूप में सहायता करती है। न्याय, जिम्मेदारी, अन्वेषण और संवाद की भावना के साथ, ई एस डी का उद्देश्य हमें व्यवहारों और प्रथाओं को अपनाने में योग्य बनाना है। जो हमे मौलिक मानवीय आवश्यकताओं और माँगों से वंचित किए बिना पूर्ण जीवन जीने के लिए हमारा मार्गदर्शन करेगा।

ई०एस०डी० पर्यावरण विषयों और मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करता है (ESD focuses on environmental themes and concerns)—ई०एस०डी० भविष्य के लिए एक सुन्दर दृष्टि प्रदान करता है, और उसका प्रमुख ध्यान पर्यावरण सम्बन्धी चिन्ताओं पर है। यह गरीबी उन्मूलन, नागरिकता शान्ति, नैतिकता, शासन, न्याय, मानव अधिकार, जेन्डर, समानता, निगमित जिम्मेदारी, प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन और जैविक विविधता जैसे विषयों को भी सम्बोधित करता है। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि ई०एस०डी० के सफल कार्यान्वयन के लिए कुछ विशेषताओं को महत्त्व दिया जाता है, जो सीखने की प्रक्रिया और शिक्षा प्रक्रिया के परिणामों के समान महत्त्व को दर्शाती है (सतत विकास के संयुक्त राष्ट्र दशक—UN Decade of Sustainable Development से अनुकूलित, 2005-2014)।

ई०एस०डी० का ध्यान प्रारम्भिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए निर्धारित होने वाले पाठ्यक्रम पर है। पाठ्यक्रम अधिकतर अन्त: विषय में नीति-निर्माण में एक सम्पूर्ण संस्थागत दृष्टिगत के लिए अनुमति देता है। ई एस डी उन मूल्यों और सिद्धान्तों को साझा करता है जो सतत विकास को रेखांकित करते हैं। वास्तव में, महत्त्वपूर्ण सोच, समस्या का समाधान करने और कार्यवाई अभिविन्यास को प्रोत्साहित करता है, जो सभी सतत विकास से सम्बन्धित चुनौतियों को सामना करते हुए आत्मविश्वास का विकास करते है। यह शिक्षार्थियों को शैक्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा और सामग्री पर निर्णय-निर्माण में भाग लेने की अनुमति देता है।

प्र.5. सतत विकास की अवधारणा और उद्भव का वर्णन कीजिए।
Describe the concept and evolution of sustainable development.

उत्तर

सतत विकास की अवधारणा और उद्भव
(Concept and Evolution of Sustainable Development)

सतत विकास आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों को एकीकृत करने की एक प्रक्रिया है। सतत विकास शब्द की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा 1987 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (United Nations Commission on Environment and Development) द्वारा निर्मित की गई थी। आयोग की रिपोर्ट, हमारा सामूहिक भविष्य में सतत विकास को इस प्रकार परिभाषित किया है, "विकास वह है जो भावी पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की योग्यता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करता है।"

यह सतत विकास की सबसे बहुधा उद्धृत परिभाषा है। यह दो आन्तरिक विचारों पर जोर देती है—

(i) **आवश्यकताओं की अवधारणा** (Concepts of Needs)—विशेष रूप से, विश्व के गरीबों की आवश्यक जरूरतें।

(ii) **सीमाओं का विचार** (Idea of Limitations)—वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरण की क्षमता पर प्रौद्योगिकी और सामाजिक संगठन की स्थिति लगाए गए सीमाओं पर विचार।

ये विचार विकासशील देशों में रहने वाले दुनिया के गरीबों की तत्काल विकास की जरूरतों को पूरा करने और पर्यावरणीय सीमाओं की विफलता के परिणामस्वरूप निरन्तर प्रगति के लिए खतरा होने के कारण इसकी नैतिक अनिवार्यता हैं। साथ ही सतत विकास की यह प्रसिद्ध परिभाषा मूल तत्त्वों के रूप में तीन नए नियमों को प्रस्तुत करती है—

पारस्परिकता (Mutuality)—सतत विकास पहचानने वाले मानव पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, और इससे प्रभावित होते हैं।

पारस्परिकता (Sustainability)—सतत विकास स्वीकार करता है कि पर्यावरण के साथ मानव सम्बन्धों को दीर्घकालिक समय में सतत होना चाहिए।

TOUCH 'n' PASS

एकीकरण (Integration)—सतत विकास नि:सन्देह रूप से यह स्वीकार करता है कि पर्यावरण, सामाजिक विकास और आर्थिक विकास एक-दूसरे को परस्पर प्रभावित करते हैं।

सतत विकास का उद्भव (Evolution of Sustainable Development)—1990 के दशक से, संयुक्त राष्ट्र की सरकारों और एजेन्सियों द्वारा सतत विकास की अवधारणा का अधिक से अधिक समर्थन किया गया है। यह धीरे-धीरे एक नए अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्ड के रूप में उभरा है, जो एक प्रकार से परिवर्तन का विशेषक है। जिसे विश्वसनीय विकास माना जाता है। सतत विकास की अवधारणा चार मुख्य घटनाओं के माध्यम से अपने वर्तमान स्वरूप में विकसित हुई।

मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference on Human Environment, 1972)—1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का सतत विकास के उद्भव में बहुत महत्त्व हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन (Stockholm Conference) के नाम से प्रसिद्ध यह कार्यक्रम पर्यावरण की रक्षा की आवश्यकता और महत्त्व पर दुनिया भर में बढ़ती जागरूकता पर राजनीतिक स्वीकार्यता का एक प्रमुख प्रतीक बन गया। यद्यपि इस सम्मेलन ने राज्य नीति के तरीके से बहुत कम उत्पादित किया, फिर भी यह पर्यावरण और विकास के बीच सम्बन्धों पर जागरूकता पैदा करने में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण था।

पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग (World Commission on Environment and Development, 1983)—सतत विकास की उन्नति में एक और महत्त्वपूर्ण घटना 1987 में पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की स्थापना थी, जिसे ब्रंटलैण्ड आयोग (Brundtland Commission) के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की प्राकृतिक प्रणालियों की स्थितियों का पता लगाने और वैश्विक पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। इस ब्रंटलैण्ड आयोग ने अपनी रिपोर्ट 'हमारा सामूहिक भविष्य' में सतत विकास के परिभाषिक शब्द को केवल लोकप्रिय ही नहीं बनाया, बल्कि पहले से बिना पहचान की अवधारणा को सुलभ और सहज पहचान योग्य परिभाषा प्रदान की। सार्थक रूप से, इस आयोग ने वैश्विक राजनीतिक स्तर पर सतत विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया। रिपोर्ट ने गम्भीर चिन्ता भी व्यक्त की, कि विश्व की जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों की पुन: पूर्ति करने के लिए ग्रह के साधनों से परे अच्छे तरीके से निर्वाह कर रही थी।

पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
(United Nations Conference on Environment and Development, 1992)

पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCED), जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन (Earth Summit) के रूप में भी जाना जाता है, ने 1992 में सतत विकास में दुनिया की अभिरुचि को नवीनीकृत किया। इस शिखर सम्मेलन को वैश्विक पर्यावरण शासन में एक मील के पत्थर के रूप में देखा गया। इस शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं द्वारा सतत विकास की अवधारणा का समर्थन किया गया।

सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन (World Summit on Sustainable Development, 2002)—सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन सतत विकास के व्यावहारिक कार्यान्वयन के महत्त्व को उजागर करने के लिए सबसे आधुनिक घटना है। शिखर सम्मेलन ने सतत विकास और उल्लिखित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के सिद्धान्तों को लागू करने के लिए राष्ट्रों के प्रति कई प्रतिबद्धताओं को निर्दिष्ट किया।

प्र.6. वैश्विक भुखमरी सूचकांक का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।
Discuss the global hunger index in detail.

उत्तर

वैश्विक भुखमरी सूचकांक
(Global Hunger Index)

वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) वैश्विक, क्षेत्रीय और देश के स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने एवं ट्रैक करने का एक साधन है।

गणना—इसकी गणना चार संकेतकों के आधार पर की जाती है—

(i) अल्पपोषण, (ii) चाइल्ड वेस्टिंग, (iii) चाइल्ड स्टंटिग, (iv) बाल मृत्यु-दर

GHI 100-बिन्दु पैमाने पर भूख की गम्भीरता का निर्धारण करता है। जहाँ 0 सबसे अच्छा सम्भव स्कोर है। (शून्य भूख) और 100 को सबसे खराब माना जाता है।

TOUCH 'n PASS

वार्षिक रिपोर्ट—कंसर्न वर्ल्डवाइड और वेल्थुंगरहिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित।

GHI एक वार्षिक रिपोर्ट है और GHI स्कोर का प्रत्येक सेट 5 वर्ष की अवधि के डेटा का उपयोग करता है। वर्ष 2022 GHI स्कोर की गणना वर्ष 2017 से वर्ष 2021 के डेटा का उपयोग करके की जाती है।

वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में देशों का प्रदर्शन—वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान को छोड़कर दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सभी देशों की तुलना में खराब प्रदर्शन किया है। यह 121 देशों में से 107 वें स्थान पर है।

वैश्विक भुखमरी सूचकांक, 2021 में भारत 116 देशों में 101वे स्थान पर था।

वैश्विक विकास—विश्व स्तर पर हाल के वर्षों में भुखमरी के खिलाफ प्रगति काफी हद तक स्थिर हो गई है; वर्ष 2022 में 18.2 का वैश्विक स्कोर वर्ष 2014 में 19.1 की तुलना में थोड़ा बेहतर हुआ है। हालाँकि, 2022 का GHI स्कोर अभी भी ''मध्यम'' है।

इस प्रगति में ठहराव के प्रमुख कारण देशों के मध्य संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 महामारी के आर्थिक नतीजों के साथ-साथ रूस यूक्रेन युद्ध जैसे अतिव्यापी संकट हैं, जिसके कारण वैश्विक स्तर पर खाद्य ईंधन और उर्वरक की कीमतों में वृद्धि हुई है तथा यह आशंका व्यक्त की गई है कि ''वर्ष 2023 व उसके बाद भी भुखमरी और बढ़ेगी।''

सूचकांक के अनुसार, 44 ऐसे देश है, जिनमें वर्तमान में 'गम्भीर' या 'खतरनांक' भूखमरी का स्तर है और न तो वैश्विक स्तर पर तथा न ही लगभग 46 देशों में जहाँ वर्ष 2030 तक GHI द्वारा भुखमरी की आशंका व्यक्त की गई है, बिना किसी बड़े बदलाव के इसका समाधान निकाला जा सकता है।

शीर्ष और सबसे खराब प्रदर्शनकर्त्ता—GHI 2022 में बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन तथा क्रोएशिया शीर्ष पाँच देश हैं।

चाड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगों, मेडागास्कर, सेन्ट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और यमन सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश हैं।

भारत और पड़ोसी देश—दक्षिण एशियाई देशों में भारत (107), श्रीलंका (64), नेपाल (81), बांग्लादेश (84) तथा पाकिस्तान (99) भी अच्छी स्थिति में नहीं हैं। भारत का स्कोर 29.1 है, जो इसे 'गम्भीर' श्रेणी में रखता है। अफगानिस्तान (109) दक्षिण एशिया का एकमात्र देश है, जिसका प्रदर्शन सूचकांक में भारत से भी खराब है। 5 से कम अंक के साथ चीन 16 अन्य देशों के साथ सूचकांक में शीर्ष देश में शामिल है।

चार संकेतकों में भारत का प्रदर्शन—चाइल्ड वेस्टिंग—3% के साथ भारत में चाइल्ड वेस्टिंग दर (लम्बाई के अनुपात में कम वजन) वर्ष 2014 (15.1%) और यहाँ तक कि वर्ष 2000 (17.15%) की अपेक्षा दर्ज स्तरों से भी खराब है। यह विश्व के किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक है तथा भारत की विशाल जनसंख्या के कारण इसका औसत और बढ़ जाता है।

अल्पपोषण—देश में अल्पपोषण की व्यापकता भी वर्ष 2018-2020 के 14.6% से बढ़कर वर्ष 2019-2021 में 16.3% हो गई है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत में 224.3 मिलियन लोग (वैश्विक स्तर पर 828 मिलियन में से) कुपोषित माने जाते हैं।

संकेतक आहार ऊर्जा सेवन की चिरकालिक कमी का सामना करने वाली आबादी के अनुपात को मापता है।

चाइल्ड स्टंटिंग और मृत्यु दर—भारत के चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु-दर में सुधार हुआ है।

वर्ष 2014 से वर्ष 2022 के बीच बाल स्टंटिंग (उम्र के अनुसार कम ऊँचाई) 38.7% से घटकर 35.5% हो गई है।

इसी तुलनात्मक अवधि में बाल मृत्यु-दर (पाँच वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर) 4.6% से घटकर 3.3% हो गई है।

सम्बन्धित अन्य सूचकांक/रिपोर्ट—विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति : खाद्य और कृषि संगठन, कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कोष, यूनिसेफ विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रस्तुत किया गया।

वैश्विक पोषण रिपोर्ट, 2021—इसकी परिकल्पना वर्ष 2013 में पहले न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव समिट (N4G) के बाद की गई थी।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)—सर्वेक्षण में भारत की राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रजनन क्षमता, शिशु एवं बाल मृत्यु-दर, परिवार नियोजन की प्रथा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य पोषण, एनीमिया, स्वास्थ्य व परिवार नियोजन सेवाओं का उपयोग तथा गुणवत्ता आदि से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की गई हैं।

TOUCH 'n' PASS

भूख/कुपोषण उन्मूलन हेतु भारत की पहल
(India's Initiative for Eradication of Hunger/Malnutrition)

'ईट राइट इण्डिया मूवमेण्ट'—भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा नागरिकों के सही तरीके से भोजन ग्रहण करने हेतु आयोजित एक आउटरीच गतिविधि।

पोषण (Poshan) **अभियान**—महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किया गया। यह अभियान स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया (छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर बालिकाओं में) को कम करने का लक्ष्य रखता है।

प्रधानमन्त्री मातृ वन्दना योजना—महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय द्वारा क्रियान्वित यह केन्द्र प्रायोजित योजना एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है, जो 1 जनवरी, 2017 से देश के सभी जिलों में लागू है।

फूड फोर्टिफिकेशन—फूड फोर्टिफिकेशन या फूड एनरिचमेन्ट का आशय चावल, दूध और नमक जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों में प्रमुख विटामिनों व खनिजों (जैसे आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन A तथा D) को संलग्न करने की प्रक्रिया है। ताकि पोषण सामग्री में सुधार लाया जा सके।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013—यह कानूनी रूप से ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System) के तहत रियायती खाद्यान प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।

मिशन इन्द्रधनुष—यह 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 12 वैक्सीन-निवारक रोगों (VPD) के विरुद्ध टीकाकरण के लिए लक्षित करता है।

एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना—वर्ष 1975 में शुरू की गई योजना 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए छह सेवाओं का पैकेज प्रदान करती है।

भारत ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय आर्थिक विकास किया है और यह दुनिया की सबसे तेजी से विकास करती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हालाँकि कई प्रगतियों के बावजूद भूख और कुपोषण अभी भी देश के लिए प्रमुख चिन्ता का विषय बना हुआ है। जबकि खाद्य सुरक्षा की स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है, गरीब आबादी के लिए पोषण और सन्तुलित आहार तक पहुँच अभी भी समस्याग्रस्त हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक, 2022 (Global Hunger Index-GHI, 2022) में भारत 121 देशों की श्रेणी में 6 स्थान और फिसलकर 107वें स्थान पर आ गया है। इस पर पहली प्रतिक्रिया में भारत सरकार ने सूचकांक की कार्यविधि को ही प्रश्नगत किया है। इस परिदृश्य में GHI, 2022 से सम्बन्धित मुद्दों और भारत में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के दायरे पर एक विचार करना प्रासंगिक होगा। सामान्य दृष्टिकोण में भुखमरी या 'हंगर' (Hunger) भोजन की कमी से होने वाली परेशानी को संदर्भित करती है। हालाँकि GHI महज इसी आधार पर भुखमरी का मापन नहीं करता बल्कि यह भुखमरी की बहुआयामी प्रकृति पर विचार करता है।

इसके लिए GHI चार आधारों पर विचार करता है—

अल्पपोषण (Undernourishment)—जनसंख्या का वह हिस्सा जिसका कैलोरी सेवन अपर्याप्त हैं। यह GHI स्कोर के 1/ 3 भाग का निर्माण करता है।

चाइल्ड स्टंटिंग (Child Stunting)—5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वह हिस्सा जिनका कद उनकी आयु के अनुरूप कम हैं, जो गम्भीर अल्पपोषण (Chronic undernutrition) को दर्शाता है। यह GHI स्कोर के 1/6 भाग का निर्माण करता है।

चाइल्ड वेस्टिंग (Child Wasting)—5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वह हिस्सा जिनका वजन उनके कद के अनुरूप कम है, जो तीव्र अल्पपोषण (acute undernutrition) को दर्शाता है। यह GHI स्कोर के 1/6 भाग का निर्माण करता है।

बाल मृत्यु दर (Child Mortality)—पाँच वर्ष की आयु से पूर्व मृत्यु का शिकार हो जाने वाले बच्चों का हिस्सा, जो अपर्याप्त पोषण और अस्वास्थ्यकर वातावरण के घातक मिश्रण को प्रकट करता है। यह GHI स्कोर के 1/3 भाग का निर्माण करता है।

कुल स्कोर को 100—पॉइन्ट स्केल पर रखा गया है और कम स्कोर बेहतर प्रदर्शन को परिलक्षित करता है।

20 से 34.9 के बीच के स्कोर को 'गम्भीर (Serious) श्रेणी में आँका जाता है। और GHI 2022 में 29.1 के कुल स्कोर के साथ भारत को इसी श्रेणी में रखा गया है।

TOUCH 'n PASS

भारत सरकार ने GHI 2022 की आलोचना (Criticism of GHI 2022 by Indian Government)

भारत सरकार ने GHI की कार्यविधि (Methodology) पर सवाल उठाया है। सरकार के तर्क के दो प्रमुख उप-भाग हैं—
पहला, GHI भुखमरी के एक भ्रामक मापन का उपयोग करता है, कि इसमें उपयोग किये गए 4 चरों में से 3 बच्चों से सम्बन्धित हैं और ये पूरी आबादी के प्रतिनिधि नहीं हो सकते हैं।
दूसरा GHI का चौथा संकेतक, यानी अल्पपोषित आबादी का अनुपात 3000 लोगों के एक बहुत छोटे नमूने के जनमत सर्वेक्षण पर आधारित हैं, जो वैश्विक आबादी के पाँचवें हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत जैसे देश के आकलन के लिए उपर्युक्त नहीं हैं।

भुखमरी से निपटने के लिए सरकार की प्रमुख पहलें—

- पोषण अभियान (Poshan)
- प्रधानमन्त्री मातृ वन्दना योजना
- फूड़ फोर्टिफिकेशन (Food Fortification)
- मिशन इन्द्रधनुष
- 'ईट राइट इण्डिया मूवमेन्ट (Eat Right India Movement)

भारत में भुखमरी और कुपोषण के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक (Factors Responsible for Hunger and Malnutriton in India)

गरीबी समर्थित भुखमरी : बदतर जीवन स्थिति बच्चों के लिए भोजन की उपलब्धता को सीमित करती है, जबकि आहार तक सीमित पहुँच के साथ अत्यधिक जनसंख्या की समस्या विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों में कुपोषण जैसे परिणाम उत्पन्न करती है।

दोषपूर्ण सार्वजनिक वितरण—शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य के वितरण में व्यापक भिन्नता की स्थिति रही है, जहाँ अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में ले जाया जाता है। जबकि राशन की दुकानों में खराब गुणवत्ता वाले अनाज की बिक्री की जाती है। इसके साथ ही, इन राशन दुकानों को खोले जाने में भी अनियमितता की स्थिति रही है।

अनभिज्ञात भुखमरी (Unidentified Hunger)—किसी परिवार की गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line–BPL) की स्थिति को निर्धारित करने के लिए उपयोग किये जाने वाले मानदण्ड मनमानी प्रकृति के हैं और ये मानदण्ड प्राय: अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होते हैं। गरीबी रेखा से ऊपर (Above Poverty Line-APL) और नीचे (BPL) के गलत वर्गीकरण के कारण खाद्य उपभोग में व्यापक गिरावट आयी है।
इसके अलावा, अनाज की खराब गुणवत्ता ने समस्या को और बढ़ा दिया है।

प्रच्छन्न भुखमरी (Hidden Hunger)—भारत सूक्ष्म पोषक तत्त्व की गम्भीर कमी (जिसे प्रच्छन्न भुखमरी के रूप में भी जाना जाता है) का सामना कर रहा है। गुणवत्ताहीन आहार, रोग और महिलाओं में गर्भावस्था एवं स्तनपान के दौरान सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की आवश्यकताओं की पूर्ति में विफलता जैसे कई कारण इस समस्या के लिए उत्तरदायी है।
माताओं के बीच पोषण, स्तनपान और पालन-पोषण के सम्बन्ध में पर्याप्त ज्ञान का अभाव चिन्ता का एक अन्य क्षेत्र है।

लिंग असमानता—पितृसत्तात्मक मानसिकता के कारण, लिंग असमानता बालिकाओं को बालकों की तुलना में अलाभ की स्थिति में रखती है और उन्हें अधिक पीड़ित बनाती है। क्योंकि वे घर में सबसे बाद में आहार पाती हैं और कम महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। बालकों के विपरीत बालिकाएँ विद्यालय तक कम अभिगम्यता के कारण 'मध्याह्न भोजन' (mid-day meals) से वंचित रहती है।

टीकाकरण की कमी—जागरूकता की कमी के कारण निवारक देखभाल (विशेष रूप से टीकाकरण) के मामले में भी बच्चों की अनदेखी की जाती है और सामर्थ्य समस्याओं के कारण रोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल तक उनकी पहुँच नहीं हो पाती है।

पोषण सम्बन्धी कार्यक्रमों की लेखापरीक्षा का अभाव—यद्यपि देश में पोषण में सुधार के मुख्य लक्ष्य के साथ कई कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय शासन स्तर पर कोई विशिष्ट पोषण लेखापरीक्षा तन्त्र मौजूद नहीं है।

प्र.7. विश्व खुशहाली सूचकांक का वर्णन कीजिए।
Discuss the world happiness index.

उत्तर हाल ही में यूएन सस्टेनेबेल डेवलपमेण्ट सॉल्यूशंस नेटवर्क (सतत विकास समाधान नेटवर्क) ने वर्ल्ड खुशहाली रिपोर्ट 2023 जारी की, जो देशों को खुशहाली के आधार पर रैंक प्रदान करती है।

TOUCH 'n' PASS

विश्व खुशहाली रिपोर्ट—विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ष 2012 के बाद से प्रत्येक वर्ष 20 मार्च के आसपास इन्टरनेशनल डे ऑफ खुशहाली सेलिब्रेशन के हिस्से के रूप में प्रकाशित की जाती है। यह रिपोर्ट 150 से अधिक देशों में लोगों के सर्वेक्षण डेटा के आधार पर वैश्विक स्तर पर खुशहाली हेतु रैंक प्रदान करती है। इस वर्ष रिपोर्ट में 136 देशों को शामिल किया गया है। रैंकिंग खुशहाली को मापने हेतु छह प्रमुख कारकों का उपयोग करती है—सामाजिक सहयोग, आय, स्वास्थ्य, स्वतन्त्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति। देशों की रैंकिंग करने के अलावा रिपोर्ट 2023 में दुनिया की स्थिति का मूल्यांकन भी करती है।

विभिन्न देशों का प्रदर्शन

शीर्ष प्रदर्शनकर्त्ता—फिनलैण्ड, लगातार छठी बार शीर्ष पर है। डेनमार्क दूसरे स्थान पर रहा, इसके बाद तीसरे स्थान पर आइसलैण्ड है। पिछले वर्ष की भाँति ही इस वर्ष भी शीर्ष 20 प्रदर्शनकर्त्ताओं के आँकड़ों में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुए हैं, एक छोटा सा परिवर्तन यह है कि लिथुआनिया ने 20वें स्थान के रूप में शीर्ष 20 में अपनी जगह बना ली है।

सबसे खराब प्रदर्शनकर्त्ता—अफगानिस्तान सबसे खराब प्रदर्शनकर्त्ता रहा, उसके बाद क्रमशः लेबनान, सिएरा लियोन, जिम्बाब्वे का स्थान है।

भारत का प्रदर्शन—136 देशों में भारत 125वें स्थान पर है, जो इसे विश्व के सबसे कम खुशहाल देशों में से एक के रूप में प्रदर्शित करता है। वर्ष 2022 में भारत 146 देशों में 136वें स्थान पर था। यह नेपाल, चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे है।

सतत विकास समाधान नेटवर्क (SDSN)—वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क (UN-SDSN) को संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्त्वाधानान में शुरू किया गया था। SDSN शिक्षा, अनुसंधान नीति विश्लेषण और वैश्विक सहयोग के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (SDG) एवं जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को कार्यान्वित करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।

विश्व खुशहाली सूचकांक—विश्व खुशहाली सूचकांक (वर्ल्ड हैप्पीनेस इण्डेक्स) 2023 रिपोर्ट इस साल के ग्लोब हैप्पीनेस रिफ्लेक्ट के साथ अपनी दसवीं वर्षगांठ को चिन्हित करेगी, जो यह दिखाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के डेटा का उपयोग करती है। कि लोग 150 से अधिक देशों में अपने जीवन को कैसे रैंक करते हैं। वर्तमान समय में, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 द्वारा प्रकट आशावाद की एक झलक है। महामारी न केवल पीड़ा और पीड़ा का कारण बना, बल्कि इससे सामाजिक सहायता और धर्मार्थ दान में भी वृद्धि हुई।

विश्व खुशहाली सूचकांक की मुख्य विशेषताएँ—विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार, फिनलैण्ड को लगातार पाँचवें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश नामित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास का समाधान नेटवर्क ने एक नई रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसे वार्षिक अन्तर्राष्ट्रीय खुशी दिवस से दो दिन पहले सार्वजनिक किया गया था। यह जीडीपी, जीवन प्रत्याशा और जीवन की गुणवत्ता के अन्य संकेतकों जैसे कारकों के आधार पर 150 देशों (2023 में 146) को रेट करता है। रैंकिंग, अब अपने ग्यारहवें वर्ष में, तीन वर्षों में एकत्र किए गए डेटा के औसत और गणितीय सूत्र के आधार पर 0 और 10 के बीच स्कोर प्रदान करती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, रूस के लिए यह वर्ष सुखद नहीं है क्योंकि यह इस साल फिर से वैश्विक खुशहाली रैंकिंग में गिर गया है। खुशहाली में योगदान करने वाले कारकों के अनुसार, जैसे कि प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, सामाजिक स्वतन्त्रता, दान और भ्रष्टाचार की कमी, विश्व खुशी रिपोर्ट 156 देशों को रैंक करती है।

विश्व खुशहाली सूचकांक के अनुसार, विश्व खुशहाली रिपोर्ट समग्र खुशहाली का एक पैमाना है। रैंकिंग उत्तरदाताओं के अपने व्यक्तिगत जीवन के मूल्यांकन की रिपोर्ट पर आधारित है और वे राष्ट्रीय खुशहाली पर लेखों को भी ध्यान में रखते हैं। अध्ययन अतिरिक्त कारकों के साथ विरोधाभास करता है जो जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2023 तक फिनलैण्ड को लगातार पाँच बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बताया गया था। सबसे हालिया गणना का अभी तक खुलासा नहीं किया गया है।

विश्व खुशहाली सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया—सतत विकास समाधान नेटवर्क विश्व खुशी सूचकांक 2023 नामक एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यह अध्ययन 150 से अधिक देशों में विश्व स्तर पर खुशी के स्तर का आकलन करता है। गैलप वर्ल्ड पोल ने इस अध्ययन के लिए मुख्य स्रोत के रूप में कार्य किया। प्रत्येक विश्व खुशहाली रिपोर्ट में एक वीडियो होता है जिसे वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। अन्य कैम्ब्रिज प्रोफेसरों में, जॉन एफ हेलीवेल, रिचर्ड लायार्ड, जेफरी डी सैक्स और जान-इमैनुएल डी नेव ने 2020 के शोध का सम्पादन किया। लारा अकनिन, शुन वांग और हैफांग हुआंग इस खण्ड के सहयोगी सम्पादकों के रूप में सहयोग कर रहे हैं।

TOUCH 'n PASS

विश्व खुशहाली सूचकांक निर्धारित करने के लिए कारक—दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची संकलित करने और ग्रह पर हर देश को रेट करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क कुल छह तत्त्वों को ध्यान में रखता है। पैरामीटर निम्नलिखित है—

(i) डायस्टोपिया अन्याय से पीड़ित होने, अधिनायकवाद के हमले के तहत, या सर्वनाश के बाद की दुनिया में होने के अनुभव को दर्शाता हैं।

(ii) नागरिकों की धारणा कि भ्रष्टाचार को उन्होंने किस तरह महसूस किया हैं, भ्रष्टाचार की उनकी धारणा कहा जाता है। उदारता सहानुभूति की भावना के साथ व्यक्तियों के बीच मौलिक मानवीय सम्बन्ध है।

(iii) जीवन के निर्णय लेने की स्वतन्त्रता। यह पहलू उस स्थिति को संदर्भित करता है। जिसमें कोई सामाजिक नतीजों के कारण समझौता किए बिना जीवन में निर्णय और विकल्प बनाने के लिए पर्याप्त रूप से मुक्त या स्वतन्त्र होता है।

(iv) घातक रोगों या पीड़ाओं से मुक्त एक स्वस्थ जीवन की अपेक्षा को "स्वस्थ जीवन प्रत्याशा" के रूप में जाना जाता है।

(v) सामाजिक समर्थन इस बात का संकेतक है कि किसी देश के निवासी एक-दूसरे से कितना समर्थन प्रदान करते हैं और प्राप्त करते हैं।

(vi) अपनी आबादी द्वारा विभाजित राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का भी गरीबी और वित्तीय सुरक्षा निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

भारत का विश्व खुशहाली सूचकांक—वैश्विक खुशहाली रैंकिंग में भारत अब 136वें स्थान पर है। 2021 में दुनिया की खुशी की 9वीं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की रैंकिंग में भारत 139वें स्थान पर आया था। यह मार्च 2021 में उपलब्ध होगा। भारत 2020 में 144वें स्थान पर रहा। विश्व खुशी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के लिए सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित की जाती है। अध्ययन का सबसे हालिया संस्करण 20 मार्च, 2021 को जारी किया गया था, जो विश्व खुशी दिवस था।

विश्व खुशहाली सूचकांक रूस रैंक—खुशहाली में योगदान करने वाले कारकों के अनुसार, जैसे कि प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, सामाजिक स्वतन्त्रता, दान और भ्रष्टाचार की कमी, विश्व खुशी रिपोर्ट 146 देशों को रैंक करती हैं।

यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेण्ट सॉल्यूशंस नेटवर्क (एसडीएसएन) द्वारा जारी शोध के अनुसार, रूस विश्व सूचकांक में 74वें स्थान पर फिसल गया हैं। रूस को पहले पाकिस्तान और फिलीपींस के बीच रखा गया था और यह ग्रह पर 68 वाँ सबसे खुश देश हैं। 2018 में यह 58वें स्थान पर था, जो 2017 में 49वें स्थान पर था।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. स्वतन्त्रता से पहले भारत में निर्धनता रेखा की अवधारणा पर विचार करने वाले प्रथम व्यक्ति थे—
(क) आर०सी० देसाई (ख) महात्मा गाँधी (ग) जवाहरलाल नेहरू (घ) दादाभाई नौरोजी

उत्तर (घ) दादाभाई नौरोजी

प्र.2. निम्नलिखित में से निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं हैं—
(क) अपर्याप्त संवृद्धि (ख) जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर
(ग) बेरोजगारी (घ) बढ़ता निवेश

उत्तर (घ) बढ़ता निवेश

प्र.3. भारत में निर्धनता को परिभाषित किया गया हैं—
(क) परिवार के सदस्यों की संख्या से (ख) मासिक प्रतिव्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE) से
(ग) लोगों के जीवन स्तर से (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (ख) मासिक प्रतिव्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE) से

प्र.4. "गरीबी के दुष्चक्र" की अवधारणा किससे सम्बन्धित हैं?
(क) कार्ल मार्क्स (ख) नर्कसे (ग) एडम स्मिथ (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (ख) नर्कसे

TOUCH 'n PASS

प्र.5. देश में गरीबों के भोजन और पोषण स्तर में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था?

(क) मध्याह्न भोजन योजना (ख) समेकित बाल विकास योजना
(ग) सार्वजनिक वितरण योजना (घ) ये सभी

उत्तर (घ) ये सभी

प्र.6. निम्नलिखित में से कौन-सा कारक गरीबी का कारण बनता हैं?

(क) सामाजिक बहिष्कार (ख) धन का असमान वितरण
(ग) भूमि की चयनात्मक उर्वरता (घ) ये सभी

उत्तर (घ) ये सभी

प्र.7. भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता हैं?

(क) नीति आयोग की टास्क फोर्स (ख) CSO
(ग) NSSO (घ) भारतीय रिजर्व बैंक

उत्तर (ख) CSO

प्र.8. 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में गरीबी रेखा (BPL) के नीचे का प्रतिशत क्या हैं?

(क) 32% (ख) 22.% (ग) 42% (घ) 35%

उत्तर (ग) 42%

प्र.9. निम्नलिखित में से लॉरेन वक्र द्वारा मापा जाता हैं—

(क) निरक्षरता (ख) बेरोजगारी (ग) जनसंख्या वृद्धि दर (घ) आय की असमानता

उत्तर (घ) आय की असमानता

प्र.10. निर्धनता रेखा ''निर्धारण की कितनी विधियाँ हैं?

(क) 4 (ख) 5 (ग) 3 (घ) 2

उत्तर (घ) 2

प्र.11. निम्न में से किस राज्य में मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया हैं?

(क) मध्यप्रदेश (ख) केरल (ग) महाराष्ट्र (घ) गुजरात

उत्तर (ख) केरल

प्र.12. मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता हैं?

(क) यू०एन०डी०पी० (ख) संयुक्त राष्ट्र (ग) विश्व बैंक (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (क) यू०एन०डी०पी०

प्र.13. 2023 में मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन-सा स्थान है?

(क) 131 (ख) 132 (ग) 133 (घ) 134

उत्तर (ख) 132

प्र.14. मानव विकास सूचकांक की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस संकेतक का उपयोग नहीं किया जाता हैं?

(क) जीवन प्रत्याशा (ख) शिक्षा (ग) प्रति पूँजी आय (घ) सामाजिक असमानता

उत्तर (ग) प्रति पूँजी आय

प्र.15. दशक को भारत में जनसंख्या रिपोर्ट विस्फोट की अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता हैं—

(क) 1981 से 2001 तक (ख) 1921 से 1951 तक
(ग) 1901 से 1921 तक (घ) 1951 से 1981 तक

उत्तर (घ) 1951 से 1981 तक

TOUCH 'n PASS

UNIT-III

विभिन्न वृद्धि मॉडल
Various Growth Models

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. बड़े धक्के के सिद्धान्त की पाँच मान्यताएँ लिखिए।
Write five assumptions of big push theory.

उत्तर बड़े धक्के के सिद्धान्त की पाँच मान्यताएँ निम्नलिखित हैं—

1. स्थिर अर्थव्यवस्था की प्रारम्भिक जड़ता तोड़ने के लिए न्यूनतम प्रयास का बड़ा धक्का जरूरी है।
2. निर्धन या अर्द्ध-विकसित देशों में एक सुनिश्चित न्यूनतम स्तर विद्यमान रहता है।
3. विकास को आवश्यक प्रबल गति देने के लिए न्यूनतम आवश्यक विनियोग (Capital) जरूरी है।
4. बड़े धक्के से बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं।
5. सरकार को आर्थिक संरचना का निर्माण करने हेतु पर्याप्त मात्रा में एक बार पूँजी (Capital) विनियोग कर देना चाहिए।

प्र.2. सन्तुलित विकास की विशेषताएँ लिखिए।
Write the characteristics of balanced growth.

उत्तर सन्तुलित विकास की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. सन्तुलित विकास (Balance Development) का अर्थ एक-साथ सभी उद्योगों में विनियोग करना है।
2. यह सिद्धान्त बहुमुखी विकास के सिद्धान्त की धारणा पर अवलम्बित है।
3. सन्तुलित विकास में कृषि एवं उद्योगों में सन्तुलन बिठाने हेतु दोनों का विकास एक समन्वित योजना के तहत किया जाता है।
4. सन्तुलित विकासपूरक उद्योगों का विकास करके बाजार को विस्तृत करता है।
5. इसके तहत निजी उपक्रम प्रणाली पर जोर दिया जाता है।
6. सन्तुलित विकास में पूँजी का सुव्यवस्थित उपयोग जरूरी है।

प्र.3. हैरोड तथा डोमर आर्थिक वृद्धि मॉडल क्या हैं?
What is the economic growth model of harrod and domar?

उत्तर हैरोड तथा डोमर (Harrod and Domar) के आर्थिक वृद्धि के मॉडल औद्योगिक दृष्टि से विकसित अर्थव्यवस्थाओं के अनुभव और उनकी समस्याओं पर आधारित हैं। यह मॉडल मुख्यत: विकसित पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के लिए हैं। हैरोड़ और डोमर ने इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं की सतत और एकरूप वृद्धि की जरूरतों का विश्लेषण (Analysis) करने का प्रयास किया है।

प्र.4. हैरोड और डोमर ग्रोथ मॉडल में क्या अन्तर है?
What is difference in harrad and Domar grwoth model.

उत्तर डोमर निवेश की माँग और आपूर्ति के बीच एक कड़ी बनाता है। जबकि हैरोड बचत की माँग और आपूर्ति के बीच समानता रखता है। डोमर मॉडल एक विकास दर पर आधारित है। लेकिन हैरोड विकास की तीन अलग-अलग दरों का उपयोग करता है। वास्तविक दर (G), वारंटेड दर (Gw) और प्राकृतिक दर (G)।

TOUCH 'n' PASS

प्र.5. हैरोड डोमर मॉडल कब विकसित हुआ था?

उत्तर मॉडल को 1939 में आरएफ हैरोड और 1946 में एवेसी डोमर द्वारा स्वतन्त्र रूप से विकसित किया गया था, हालाँकि 1924 में गुस्ताव कैसल द्वारा एक समान मॉडल प्रस्तावित किया गया था। हैरोड-डोमर मॉडल को बहिर्जात विकास मॉडल के अग्रदूत के रूप में माना जा सकता है।

प्र.6. कौन-सी पंचवर्षीय योजना हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित हैं?

उत्तर पहली पंचवर्षीय योजना हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। हैरोड-डोमर मॉडल आर्थिक विकास का एक शास्त्रीय कीनेसियन मॉडल है और इसका उपयोग अर्थव्यवस्था की विकास दर को समझाने हेतु अर्थशास्त्र के विकास में किया जाता है।

प्र.7. किस विकास मॉडल ने विकास नियोजन के लिए पूँजी उत्पादन अनुपात के उपयोग को प्रेरित किया?

उत्तर हैरोड-डोमर मॉडल अनिवार्य रूप से पूँजी-उत्पादन अनुपात के माध्यम से रोजगार, उत्पादन और निवेश समुच्चय से सम्बन्धित है, जिसे स्थिर माना जाता है। विकास का हैरोड-डोमर सिद्धान्त मानता है कि निवेश क्षमता-निर्माण और आय-सृजन दोनों है।

प्र.8. सन्तुलित और असन्तुलित विकास में क्या अन्तर हैं?

उत्तर असन्तुलित विकास एक ऐसी रणनीति को दर्शाता है जो अकेले कृषि या उद्योग पर केन्द्रित है। "सन्तुलित विकास का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को एक साथ बढ़ाना चाहिए ताकि उद्योग और कृषि के बीच और घरेलू खपत के लिए उत्पादन और निर्यात के लिए उत्पादन के बीच उचित सन्तुलन बना रहे।

प्र.9. असन्तुलित विकास का अर्थ क्या हैं?

उत्तर असन्तुलित विकास से तात्पर्य उस स्थिति से होता है, जिसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्र एक-दूसरे के साथ समान गति से विकास नहीं कर पाते हैं। किसी क्षेत्र में विकास तेजी से होता है तो किसी क्षेत्र में विकास की दर बेहद धीमी होती है। इस तरह के विकास को असन्तुलित विकास कहा जाता है।

प्र.10. सन्तुलित विकास के समर्थक कौन हैं?

उत्तर सन्तुलित विकास सिद्धान्त के प्रवर्तक के रूप में एडम स्मिथ और फ्रेडरिक लिस्ट का नाम लिया जा सकता है वर्तमान समय में रोजोन्स्टीन रोहान रागनर नक्सें, आर्थर लुईस, सीटोवस्की, रोस्टोव और हार्वे लीबिन्स्टीन इस विकास नीति के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. बड़े धक्के के सिद्धान्त का उल्लेख कीजिए।
Explain the big push theory.

उत्तर

बड़े धक्के का सिद्धान्त
(The Big Push Theory)

'बड़ा धक्का अथवा प्रयास'' सिद्धान्त प्रो० पाल एन० रोजोन्स्टीन रोडन के नाम से सम्बद्ध है। अवधारणा यह है कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में विकास की बाधाओं को पार करने और उसे प्रगति के पथ पर चलाने के लिए "बड़ा धक्का'' बड़ा व्यापक प्रोग्राम आवश्यक है जो न्यूनतम किन्तु उच्च मात्रा के निवेश के रूप में हो।

प्रो० पाल एन० रोजोन्स्टीन रोडान ने 'बड़े धक्के का सिद्धान्त' का प्रतिपादन सन्तुलित विकास पद्धति की मान्यता पर किया है। इस सिद्धान्त के अनुसार आर्थिक विकास का सूत्रपात करने के लिए अविभाज्यताओं को कम करना और बाहरी बचतों को प्राप्त करना जरूरी है। जिसके लिए विनियोग की निश्चित न्यूनतम मात्रा का होना आवश्यक है।

TOUCH 'n' PASS

रोडन ने सन्तुलित विकास के तीन सन्तुलनों की चर्चा की है। इस दृष्टि से–

(i) विभिन्न उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में उनकी सापेक्षिक माँग के अनुसार समतल सन्तुलन (Horizontal Equilibrium) होना चाहिए।

(ii) पूँजी उद्योगों, मध्यम उद्योगों और उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में लम्बवत् सन्तुलन (Vertical Equilibrium) होना चाहिए।

(iii) पूँजीगत उद्योगों, उपभोक्ता उद्योगों तथा सामाजिक उपरिव्यय पूँजी (Social Overhead Capital) तथा प्रत्यक्ष उत्पादक प्रक्रियाओं (Directly Productive Activities) के बीच सामान्य सन्तुलन (General Equilibrium) बना रहना चाहिए।

अन्त में, रोडन ने अर्द्ध-विकसित देशों के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बहुत बड़े पैमाने पर विनियोग के लिए राज्य की भूमिका को महत्त्वपूर्ण माना है।

प्रो० पाल०एन० रोजोन्स्टीन रोडन ने 'बड़े धक्के' या 'प्रबल प्रयास का सिद्धान्त' का प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार अर्द्ध-विकसित देशों में धीरे-धीरे नीति के आधार पर विकासात्मक कार्यों को क्रियान्वित करने पर कोई विशेष लाभ नहीं होता, यहाँ जरूरत बड़े पैमाने पर विनियोग की है। उसने M.I.T अध्ययन से अपने तर्क पर बल देने के लिए एक सादृश्य (Analogy) प्रस्तुत किया है। "यदि विकास प्रोग्राम को थोड़ा भी सफल बनाना है तो संसाधनों का एक न्यूनतम स्तर पर उस प्रोग्राम में लगाना ही पड़ेगा। किसी देश को वृद्धि की आत्मनिर्भरता की अवस्था में लाना ठीक वैसा ही है, जैसा हवाई जहाज को धरती से हवा में उड़ाना। भूमि पर एक ऐसी कांतिक गति होती है, जिसे विमान को वायुवाहित बनने के लिए धरती पर ही पार करना पड़ता है।" यह सिद्धान्त कहता है कि धीरे-धीरे चलने से अर्थव्यवस्था को सफलतापूर्वक विकास पथ पर नहीं लाया जा सकता वरन इसके लिए जरूरी स्थिति यह है कि एक न्यूनतम मात्रा में निवेश किया जाए। इसके लिए उन बाह्य मितव्ययिताओं को प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है, जो तकनीकी रूप में स्वतन्त्र उद्योगों की एक-साथ स्थापना से उत्पन्न होती है। इस प्रकार निवेश की न्यूनतम मात्रा से प्रवाहित होने वाली अविभाज्यताएँ और बाह्य मितव्ययिताएँ आर्थिक विकास का सफलतापूर्वक सूत्रपात करने के लिए जरूरी है। रोडान का सिद्धान्त सन्तुलित विकास पद्धति की मान्यता पर आधारित है।

प्र.2. बड़े धक्के सिद्धान्त का आधार संक्षेप में बताइए।
State the base of theory or logical justification.

उत्तर

सिद्धान्त का आधार या तार्किक औचित्य
(Base of Theory or Logical Justification)

बाह्य बचतों को प्राप्त करने की सम्भावना विनियोग के बड़े धक्के सिद्धान्त का प्रमुख आधार है। **रोजोन्स्टीन रोडन** के अनुसार, "बाह्य बचतों पर जोर देना ही विकास सिद्धान्त को स्थैतिक सिद्धान्त से अलग करता है। स्थैतिक सिद्धान्त में बाह्य बचतें अपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण होती हैं किन्तु आर्थिक विकास के सिद्धान्त में वे विशेष महत्त्व रखती है। 'बड़े धक्के' के सिद्धान्त के अनुसार 'एक विकास कार्यक्रम' कम से कम एक जरूरी न्यूनतम आकार का होना चाहिए जिससे कि अर्थव्यवस्था में अविभाज्यताओं और असमानताओं को कम किया जा सके, पैमाने की अबचतों को निष्प्रभावित किया जा सके और कुछ अन्य ऐसी शक्तियों का मुकाबला किया जा सके जो एक बार विकास प्रारम्भ हो जाने पर उसे दबाने के लिए प्रारम्भ होती है।" अतएव आर्थिक विकास का सूत्रपात करने के लिए अविभाज्यताओं को कम करना और बाह्य विनियोग को प्राप्त करना जरूरी है। जिसके लिए विनियोग की निश्चित न्यूनतम मात्रा का होना जरूरी हैं।

प्र.3. नैल्सन के निम्न स्तरीय सन्तुलन अवरोध सिद्धान्त का उल्लेख कीजिए।
Explain the Nelson's theory of low-level equilibrium.

उत्तर

नैल्सन का निम्न स्तरीय सन्तुलन अवरोध का सिद्धान्त
(Nelson's Theory of Low-Level Equilibrium)

नैल्सन का सिद्धान्त लीबन्स्टीन के सिद्धान्त की ही भाँति माल्थस की इस परिकल्पना पर आधारित है कि एक देश में न्यूनतम जीवनयापन स्तर पर प्रति व्यक्ति आय के अधिक हो जाने पर जनसंख्या (Population) में वृद्धि होती है। जो प्रति व्यक्ति आय (pcg) को दो बार पीछे ढकेल कर उसे आरम्भिक स्थिर सन्तुलन स्तर पर पहुँचा देती है और इस तरह अल्प-विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएँ निम्न सन्तुलन पाश के भँवर जाल में फँसकर रह जाती है। नैल्सन ने यह प्रतिपादित किया है कि "इस निम्न सन्तुलन पाश से बाहर निकलने के लिए यह आवश्यक है कि इतनी अधिक मात्रा में विनियोग किया जाए कि प्रति व्यक्ति आय की

वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि दर को पीछे छोड़ दें क्योंकि प्रारम्भ में जब प्रति व्यक्ति आय जीवन निर्वाह स्तर से ऊपर उठती है तो उसके साथ जनसंख्या भी बढ़ती है, पद एक सीमा के बाद प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर जनसंख्या की वृद्धि दर (Growth Rate) में गिरावट होने लगती है।

आर०आर० नेल्सन ने अपना निम्न स्तरीय सन्तुलन अवरोध सिद्धान्त 1856 में अमेरिकन एकोनामिक रिब्यू में प्रकाशित अपने एक लेख *'A Theory of Life Low-level EquilibriumTrap'* में प्रस्तुत किया। उन्होंने अर्द्ध-विकसित देशों के लिए निम्नस्तरीय सन्तुलन अवरोध सिद्धान्त विकसित किया। लीबन्स्टीन के आवश्यक न्यूनतम प्रयत्न सिद्धान्त की भाँति, नैल्सन का सिद्धान्त भी माल्थस की इस मान्यता पर अवलम्बित है।

अर्द्ध-विकसित देशों (half-developed Countries) की समस्याओं पर विचार करते हुए नैल्सन ने यह प्रतिपादित किया कि ये देश निम्न (Low) प्रति व्यक्ति आय (pcg) के सन्तुलन पाश या जाल में जकड़े हुए हैं। ये देश अत्यन्त ही अल्प प्रति व्यक्ति आय पर, जो जीवन निर्वाह की आवश्यकता की पूर्ति के बराबर है या लगभग बराबर है, स्थिर साम्य या गतिहीनता की स्थिति में है। स्थिर साम्य से हमारा आशय यह है कि यदि किसी प्रयास के कारण ये देश इस निम्न स्तरीय साम्य (Low-Level Equilibrium) से बाहर निकलते हैं तो इसी स्तर पर साम्य के पुन: स्थापित होने की प्रवृत्ति पायी जाती है। इस निम्न स्तरीय साम्य की स्थिति में बचत और विनियोग (Investment) की दर अत्यन्त ही कम होती है। यदि प्रति व्यक्ति आय को न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर से ऊपर उठाया भी जाता है तो इससे जनसंख्या में वृद्धि (Growth in Population) प्रेरित होती है। जनसंख्या में इस वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय में कमी आयेगी और अर्थव्यवस्था दौबारा उसी न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर पर स्थापित हो जायेगी और इस तरह अर्थव्यवस्था निरन्तर रूप से निम्न प्रति व्यक्ति आय सन्तुलन जाल में फँसी रहती है।

नैल्सन ने यह प्रतिपादित किया है कि "इस निम्न सन्तुलन पाश (अवरोध) से बाहर निकलने के लिए यह आवश्यक है कि इतनी अधिक मात्रा में विनियोग किया जाए कि प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि दर को पीछे छोड़ दें क्योंकि प्रारम्भ में जब प्रति व्यक्ति आय जीवन निर्वाह स्तर से ऊपर उठती है तो उसके साथ जनसंख्या भी बढ़ती है, पर एक सीमा के बाद प्रति व्यक्ति आय में और वृद्धि होने पर जनसंख्या की वृद्धि दर में गिरावट होने लगती है।"

प्र.4. निम्न स्तरीय सन्तुलन अवरोध में सहायक तत्वों को लिखिए।
Write the Auxiliary elements of low-level equilibrium barrier.

उत्तर

निम्न स्तरीय सन्तुलन अवरोध में सहायक तत्त्व
(Auxiliary Elements in Low-level Equilibrium barrier)

नैल्सन ने निम्नलिखित सामाजिक प्रौद्योगिक स्थितियों का उल्लेख किया है, जो निम्न स्तरीय सन्तुलन अवरोध में सहायक होती है—

(i) **ऊँचा सह-सम्बन्ध** (High Co-relation)—नैल्सन का मत है कि अर्द्ध-विकसित देशों के पिछड़ेपन (Backwardness) का कारण या इसके जाल में फँसे रहने का कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के कारण जनसंख्या में वृद्धि होना है। इस प्रकार इन दोनों में ऊँचा-सम्बन्ध होता है।

(ii) **विनियोग की नीची प्रवृत्ति (Low Propensity to Investment)**—अर्द्ध-विकसित देशों के पिछड़ेपन (Backwardness) का कारण यह भी है कि यहाँ प्रति व्यक्ति आय में तो वृद्धि हो जाती है परन्तु वहाँ के लोग अपने जीवन निर्वाह को पूरा करने में ही समस्त आय को व्यय कर देते हैं। इसके कारण बचत होती ही नहीं। यदि थोड़ी-बहुत बचत होती भी है तो वहाँ के निवासियों में विनियोग करने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है।

(iii) **भूमि की कमी** (Lack of Land)—अर्द्ध-विकसित देशों में आय का प्रमुख साधन कृषि (Agriculture) ही होता है। अतएव देश में उपलब्ध समस्त कृषि योग्य भूमि पर खेती कर ली जाती है। इसलिए देश का आर्थिक विकास करने के लिए और उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि भूमि की कमी रहती है।

(iv) **उत्पादन के पुराने तरीके** (Old Technical of Production)— अर्द्ध-विकसित देश निम्न सन्तुलन जाल में इसलिए भी फँसे रहते हैं क्योंकि वहाँ उत्पादन की पुरानी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। जिससे वस्तुओं की उत्पादन लागत अधिक आती है।

(v) **अन्य कारण** (Other Factors)—अर्द्ध-विकसित देश का निम्न सन्तुलन जाल में रहने का कारण आर्थिक और सांस्कृतिक निष्क्रियताएँ भी हैं। सांस्कृतिक निष्क्रियता से आर्थिक निष्क्रियता और आर्थिक निष्क्रियता से सांस्कृतिक

TOUCH 'n' PASS

निष्क्रियता (Inactivity) आती है। अर्द्ध-विकसित देश के आर्थिक विकास के अध्ययन से पता चलता है कि ऊपर बतायी गयी स्थितियों की उपस्थिति के कारण अधिकांश अर्द्ध-विकसित देश निम्नस्तरीय सन्तुलन अवरोध (Barricode) में जकड़े हुए है।

प्र.5. सन्तुलित विकास पर टिप्पणी कीजिए।
Write a short note on balanced growth.

उत्तर

सन्तुलित विकास
(Balanced Growth)

अर्थ (Meaning)—सन्तुलित विकास का अर्थ यह है कि एक विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था (Developing Economy) के विभिन्न अंगों को एक साथ विकसित करना चाहिए, जिससे विकास प्रक्रिया में कठिनाइयाँ उत्पन्न न हों। उदाहरण के लिए, कृषि, उद्योग, परिवहन आदि सभी का, एक ही समान विकास होना चाहिए।

स्पष्ट व्याख्या करने की दृष्टि से नीचे कुछ 'परिभाषाएँ' दी जा रही हैं—

1. **नर्क्से**—"सन्तुलित विकास अन्त में सन्तुलित भोजन की आवश्यकता पर निर्भर करता है।"
2. **लेविस**—"विकास कार्यक्रमों में अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों को एक साथ विकसित करना चाहिए जिससे कि उद्योग एवं कृषि तथा घरेलू उत्पादन तथा निर्यात के लिए उत्पादन में उचित सन्तुलन स्थापित किया जा सके।"
3. **ए० घोष**—"सन्तुलित विकास के साथ नियोजन इंगित करता है कि अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्र एक ही अनुपात में विकास करेंगे जिससे कि उपभोग, विनियोग एवं आय समान दर से बढ़ सके।"
4. **रेडावे**—"सन्तुलित विकास से अर्थ अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों में सन्तुलन स्थापित करने से है। इसमें उत्पादन एवं उपभोग के मध्य, उपभोग व पूँजी के मध्य तथा उत्पादन प्रणाली में समन्वय स्थापित किया जाता है। जिससे कि कच्ची सामग्री अर्द्ध-निर्मित सामग्री एवं औद्योगिक आवश्यकताओं में सन्तुलन स्थापित किया जा सके।"

सरल शब्दों में, "सन्तुलित विकास से आशय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का एक साथ तथा एक-सा विकास करना है, ताकि सभी क्षेत्र समानता लिए हुए विकसित हों।"

सन्तुलित विकास के समर्थकों में एडम स्मिथ, नर्क्से, आर्थर लुइस, फ्रैडरिक लिस्ट, रोजोन्स्टीन रोडान, हार्वे लीबिन्स्टीन आदि अर्थशास्त्रियों के नाम प्रमुख रूप से शामिल किया जाते हैं।

सन्तुलित विकास का आशय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक साथ तथा एक-सा विकास करना है, जिससे राशि क्षेत्र समानता लिए हुए विकसित हो।

असन्तुलित वृद्धि का सिद्धान्त सन्तुलित वृद्धि की धारणा के बिल्कुल विपरीत है। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश न करके कुछ के क्षेत्रों में सर्वप्रथम निवेश करना चाहिए। किसी भी अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के पास साधन और पूँजी इतने नहीं होते कि समस्त क्षेत्रों में निवेश एक साथ किया जा सके। इस कारण ऐसे देशों में कुछ चुने हुए प्रमुख क्षेत्रों या उद्योगों में निवेश करके उनमें विकास की गति तीव्र की जाती है और उनसे उत्पन्न होने वाली मितव्ययिताओं (Frugalities) में वृद्धि होने से अन्य क्षेत्रों का भी विकास होता है। इस प्रकार धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था असन्तुलित वृद्धि से सन्तुलित वृद्धि (Balanced Growth) की ओर बढ़ती है।

प्र.6. सन्तुलित विकास के लाभ अथवा सन्तुलित विकास के प्रभावों का उल्लेख कीजिए।
Explain the advantages and effects of balanced growth.

उत्तर

सन्तुलित विकास के लाभ अथवा सन्तुलित विकास के प्रभाव
(Advantages of Balanced Growth or Effects of Balanced Growth)

यदि किसी देश में सन्तुलित ढंग से आर्थिक विकास होता है तो इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है और देश में सन्तुलित विकास के निम्नलिखित लाभ या प्रभाव होते हैं—

1. **मितव्ययिताओं की प्राप्ति** (Achievement of Economies)—सन्तुलित विकास नीति के फलस्वरूप बाजार का विस्तार होता है और उद्योगों में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है जिससे उत्पादन के साधनों का अनुकूलतम प्रयोग सम्भव हो जाता है। और बाह्य मितव्ययिताओं की प्राप्ति होती है।

TOUCH 'n' PASS

2. **कुशल श्रम-विभाजन** (Efficient Division of Labour)—बाजार के आकार में विस्तार पैमाने में वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। पैमाने में वृद्धि के परिणामस्वरूप श्रम-विभाजन के अनेक लाभ और मितव्ययिताएँ प्राप्त हो सकती हैं।
3. **उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि** (Increase in Production and Productivity)—सन्तुलित विकास नीति को अपनाये जाने पर जब श्रम-शक्ति, तकनीक और प्राकृतिक साधनों पर बड़ी मात्रा में विनियोजन किया जाता है तो उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है।
4. **कृषि और उद्योग का सन्तुलित विकास** (Balanced Growth of Agriculture and Industry)—सन्तुलित विकास की नीति के कारण देश में कृषि एवं उद्योग का सन्तुलित विकास सम्भव होता है यह दोनों एक-दूसरे की वस्तुओं की माँग उत्पन्न करते हैं जिससे देश का तेजी से विकास होता हैं।
5. **रोजगार के अवसरों में वृद्धि** (Increase in Employment Opportunities)—जब विविध उद्योगों में एक साथ विनियोग किया जाता है, तब रोजगार के अवसरों में वृद्धि होना स्वाभाविक हैं। नर्क्स के अनुसार, सन्तुलित विकास के कारण ही कृषि-क्षेत्र की अतिरिक्त जनसंख्या को उद्योगों में रोजगार की प्राप्ति होती है।
6. **सन्तुलित विदेशी व्यापार** (Balanced Foreign Trade)—प्रो. नर्क्स का कहना है कि सन्तुलित विकास अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की सुदृढ़ आधारशिला है। इसके कारण देश के विदेशी व्यापार में सन्तुलन (Balance) बना रहता है।
7. **विनियोग प्रेरणाओं में वृद्धि** (Increase in Investment Incentives)—सन्तुलित विकास नीति को अपनाने पर बाजार सम्बन्धी अपूर्णताएँ समाप्त हो जाती हैं। माँग की कमी की कोई समस्या नहीं रहती है इसलिए पूँजीपति विनियोग करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।
8. **मूल्य स्थिरता** (Price Stability)—सन्तुलित विकास नीति को अपनाये जाने से अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ता है अर्थात् वस्तुओं की पूर्ति बढ़ती है जिससे मूल्यों में स्थिरता (Stability) की प्रवृत्ति होती है।
9. **सामाजिक लाभों में वृद्धि** (Increase in Social Benefits)—सन्तुलित विकास नीति को अपनाते समय सामाजिक लाभ की भावना को ध्यान में रखकर ही विनियोजन (Investment) किया जाता है। इसलिए समाज के लाभों में वृद्धि होना स्वाभाविक होता है।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. लुइस के विकास का सिद्धान्त पर विस्तृत विवेचना कीजिए।
Discuss the Lewis model of Development in details.

उत्तर

लुइस के विकास का सिद्धान्त
(Lewis Model of Development)

लुइस ने आर्थिक विकास के विचार को श्रम की असीमित पूर्ति (Unlimited Supply) के साथ जोड़ा है। लुइस के इस सिद्धान्त को श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धान्त भी कहते हैं। लुइस ने अर्थव्यवस्था (Economy) को दो भागों में बाँटा है—1. **पूँजीवादी क्षेत्र** 2. **निर्वाह क्षेत्र।**

पूँजीवादी क्षेत्र वह क्षेत्र है, जो दोबारा उत्पादित होने वाली पूँजी का प्रयोग करता है और उसके प्रयोग की एवज में पूँजीवादी को इसका प्रयोग का भुगतान करता है। पूँजीवादी क्षेत्र में श्रमिकों को खानों एवं बागानों में लगाता है। इसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। पूँजीवादी क्षेत्र निजी एवं सरकारी दोनों हो सकते हैं। इस क्षेत्र में निर्वाह क्षेत्र की बजाय मजदूरी का स्तर ऊँचा होता है। दूसरा क्षेत्र निर्वाह क्षेत्र है जिसमें दोबारा उत्पादित होने वाली पूँजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इसमें प्रतिव्यक्ति उत्पादन की मात्रा पूँजीवादी क्षेत्र की बजाय कम होती है। निर्वाह क्षेत्र में उपलब्ध तकनीक पर कृषि में श्रम की सीमान्त उत्पादकता (Marginal Production) जीरों (शून्य) भी हो सकती है जहाँ छिपी बेरोजगारी की स्थिति हो।

दोनों क्षेत्रों के बीच सम्बन्ध

इन दोनों क्षेत्रों के बीच आपसी सम्बन्धी है जब पूँजीवादी (Capitalist) क्षेत्र का फैलाव होता है तो श्रमिक निर्वाह क्षेत्र से पूँजीवादी क्षेत्र में चले जाते हैं। लेकिन यह निर्वाह के न्यूनतम आवश्यक इकाई पर निर्भर करता है। इसका आशय निर्वाह क्षेत्र में

TOUCH n PASS

मजदूरी स्तर श्रमिक के औसत उत्पादन से कम नहीं हो सकता। यह स्पष्ट है कि अकुशल (Unskilled) श्रमिकों की पूर्ति पूँजीवादी क्षेत्र में असीमित है। ऐसी स्थिति में नए उद्योगों की स्थापना होगी तथा पुराने क्षेत्र मजदूरी की वर्तमान सीमा पर फैलेंगे। नए रोजगार के साधनों के पनपने से श्रम की कमी महसूस नहीं होगी क्योंकि कृषि में पहले ही छुपी हुई बेरोजगारी समाहित है। इस असीमित पूर्ति क्षेत्र में वही आएँगे जो कृषि और दूसरे क्षेत्रों जैसे घरेलू नौकर, छोटे मोटे व्यापारी, घरेलू काम-काज करने वाली औरतें और जनसंख्या वृद्धि।

विस्तृत पूँजीवादी क्षेत्र में मजदूरी का निर्धारण निर्वाह क्षेत्र में कमाने वाली मजदूरी से निर्धारित होगा। यदि कृषि में श्रम की सीमान्त उत्पादकता (Marginal Production) शून्य है और परिवार का एक व्यक्ति कुल उत्पादन में से हिस्सा प्राप्त करता है तो यह लगभग औसत उत्पादन (Average Production) होगा।

यदि पूँजीवादी क्षेत्र में मजदूरी औसत उत्पादन से कम होगी तो वह निर्वाह क्षेत्र से पूँजीवादी क्षेत्र में स्थानान्तरित नहीं होगा। अतएव पूँजीवादी क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई मजदूरी निर्वाह क्षेत्र से ज्यादा होनी चाहिए। तभी श्रमिक अपना परम्परागत (Traditional) व्यवसाय छोड़कर पूँजीवादी क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इसको निम्नलिखित चित्र द्वारा समझाया गया है—

OS = निर्वाह मजदूरी

OW = पूँजीवाद क्षेत्र में वास्तविक मजदूरी

WK = श्रम की पूर्ण लोच पूर्ति

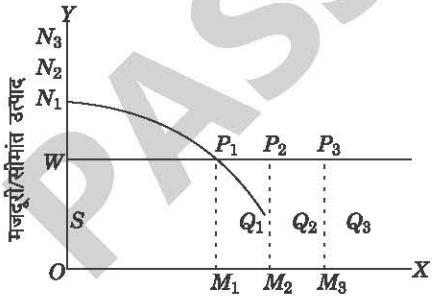

चित्र 1

पूँजीवादी क्षेत्र में श्रम की सीमान्त उत्पादक शुरू में OM_1 श्रम के लिए N_1Q_1 है। इस अवस्था में Surplus (अतिरेक) WN_1P_1 हैं। जब अतिरिक्त निवेश दोबारा किया जाता है तो सीमान्त उत्पादकता वक्र ऊपर की तरफ चला जाता है जो N_2Q_2 है। इस पूँजीवादी क्षेत्र में रोजगार (Employment) अधिक है जो WN_2P_2 तथा OM_2 हैं। और अधिक पुन: निवेश से सीमान्त उत्पादकता वक्र को रोजगार के स्तर को बढ़ाकर N_3Q_3 तथा M_3 पर ले जाते हैं। जब श्रम का कोई अतिरेक न बचे। आर्थिक फैलाव की प्रक्रिया चलती रहती है। जो पूँजीवादी का अतिरेक का एक हिस्सा का विनिवेश किया गया है। जिससे स्थिर पूँजी और श्रम की सीमान्त उत्पादकता (Marginal Productivity) बढ़कर N_2Q_2 हो जाती है। कुल उत्पादन $ON_2P_2M_2$ बढ़ जाता है। परिणाम के तौर पर मजदूरी का हिस्सा बढ़कर OWP_2M_2 और लाभ या पूँजीपति का अतिरेक बढ़कर WN_2P_2 हो जाता है। प्रत्येक स्तर पर पूँजीपति का लाभ एवं रोजगार का स्तर बढ़कर OM_1 से OM_2 से OM_3 इत्यादि हो जाता है। यह ऊपर लिखित वर्णन आर्थिक विकास में लाभ ओर उसके विनिवेश महत्त्वता के बारे में बताता है। जिससे पूँजीपति का लाभ, उत्पादन का स्तर, रोजगार और मजदूरी (Wage) का स्तर भी बढ़ता है।

बचत की भूमिका (Role of Saving)

यह सही है कि आर्थिक विकास में बचत का अहम योगदान हैं यदि पूँजीपति लाभ का बड़ा हिस्सा का विनिवेश (Invest) नहीं करेंगे तो न तो उत्पादन बढ़ेगा न ही रोजगार में वृद्धि होगी। लुइस का मत है कि बचत उन्हीं लोगों द्वारा की जाती है। जो लाभ या कर प्राप्त करते हैं कारण यह है कि मजदूरों की बचत की मात्रा कम होती है। मध्यवर्ग एवं वेतन भोगी वर्ग भी कम बचत कर पाता है। इसलिए जब विनिवेश की बात आती है तो यह लाभ और कर पर अटक जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऊपरी 10 प्रतिशत लोग क्यों ज्यादा बचत (Saving) करते हैं। इसका कारण विनिवेश (Disinvestment) की प्रक्रिया। एक बार यदि पूँजीवादी क्षेत्र का विकास होता है तो वह धीरे-धीरे बढ़ता रहता है। लेकिन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में गरीबी का कारण पूँजीवादी क्षेत्र का छोटा होना है। यदि पूँजीवादी क्षेत्र में फैलाव (Extension) होगा तो आय की असमानता की समस्या उत्पन्न होती है। लुइस का मत है कि अविकसित क्षेत्रों में बचत करने की क्षमता कम नहीं होती बल्कि आय का अधिक भाग 10 प्रतिशत लोगों के हाथ में होने पर यह स्थिति उत्पन्न होती है।

पूँजी निर्माण में साख की भूमिका (Role of Credit in Capital Formation)

पूँजी का निर्माण केवल लाभों से नहीं होता वरन वह साख से भी निर्मित होता है। अल्पविकसित देशों में पूँजी की कमी होती है वहाँ पूँजी निर्माण पर बैंक साख का वही प्रभाव पड़ता है जो लाभों का। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में बैंक साख के कारण उत्पादन एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। लेकिन जो पूँजी निर्माण साख होगा उसमें आरम्भ में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होगी

क्योंकि श्रम की खपत (Consumption) से मजदूरी बढ़ने की माँग बढ़ती है और कीमतों में वृद्धि होती है। लेकिन यह स्थिति तब तक है जब तक एक नया उत्पादन बाजार में नहीं आता। उसके उपरान्त कीमतें अपने आप कम होनी शुरू हो जाती है। इसलिए बैंक साख से पूँजी निर्माण में वृद्धि होती है लाभ और मजदूरी भी बढ़ती है। अधिक लाभों से अधिक बचत (Surplus) होती है और एक ऐसा समय आएगा जब बचते इतनी बढ़ जाएगी कि साख के बिना ही वित्त की व्यवस्था की जा सकेगी।

क्या पूँजी प्रक्रिया रूकती है (Does Capital Accumulation Stop)

लुइस के मॉडल में विकास एवं पूँजीपति के लाभ में सम्बन्ध है। जैसे-जैसे पूँजीपति का अतिरेक बढ़ता है। राष्ट्रीय आय में निवेश का स्तर बढ़ता है जो अर्थव्यवस्था में विकास को बढ़ाता है। पूँजीपति अतिरेक का सम्बन्ध श्रम की अतिरेक मात्रा से सम्बन्धित है। यह पूँजीपति अतिरेक बढ़ेगा तो श्रम की अतिरेक मात्रा (Surplus Quantity) में भी वृद्धि होगी। यह प्रक्रिया (Process) तब रूकेगी जब मजदूरों की वास्तविक आय (Real Income) पूँजीपति के लाभ से अधिक हो जाए इस अवस्था में सारे लाभों का उपभोग करने से निवेश की प्रक्रिया रूक जाती है या अथवा कोई निवेश न हो दूसरी और लुईस ने बताया कि यदि पूँजी निर्माण से कोई अतिरेक श्रम न बचे, या पूँजी क्षेत्र में विकास इतनी तेजी से हो कि निर्वाह क्षेत्र में जनसंख्या बिल्कुल घट जाए और निर्वाह क्षेत्र में श्रम की उत्पादकता बढ़ जाए क्योंकि उत्पादन को बाँटने वाले लोग कम रह जाते हैं। यदि पूँजीवादी क्षेत्र नई तकनीक (New Technology) प्रयोग करना आरम्भ कर दे। ऐसी अवस्था में पूँजीवादी क्षेत्र में मजदूरी बढ़ जाएगी। इन सभी अवस्थाओं में पूँजीपति का अतिरेक कम होगा। ऐसी अवस्था में पूँजी की प्रक्रिया पर नकारात्मक (Negative) प्रभाव पड़ेगा।

खुली अर्थव्यवस्था (Open Economy)

लुइस का मॉडल बन्द अर्थव्यवस्था में वर्जित किया गया है। जब इन सब साधनों से वृद्धि की प्रक्रिया पर प्रतिकूल (Adverse) प्रभाव पड़ता है। तो दूसरे देश से अतिरेक श्रम की पूर्ति (Supply) की जा सकती है। यह आप्रवास को प्रोत्साहन देकर या उन देशों में पूँजी का निर्यात करके जहाँ निर्वाह दर पर मजदूरी प्राप्त होती है। पूँजी संचय जारी रख सकते हैं। लेकिन लुइस ने इस सिद्धान्त को रद्द कर दिया है। क्योंकि अकुशल श्रमिकों का अप्रवास सम्भव नहीं, पूँजी निर्यात से आयात-निर्यात का अन्तर अधिक होने पर भुगतान सन्तुलन (Balance of Payment) की समस्या उत्पन्न होगी। ऐसी अवस्था के लिए लुइस ने विनिमय नियन्त्रण (Exchange Control) की सलाह दी है।

प्र.2. बड़े धक्के सिद्धान्त के प्रमुख तत्त्वों का वर्णन कीजिए।
Describe the main elements of the big push theory.

उत्तर

सिद्धान्त के प्रमुख तत्त्व
(Main Elements of the Theory)

1. **बड़े धक्के से बाह्य मितव्ययिताओं का विकास** (Big Push to Creation of External Economies)— अर्द्ध-विकसित देशों में सहायक आर्थिक एवं सामाजिक संरचना का अभाव रहता है। अतएव निजी विनियोग (Investment) प्रेरणाहीन और प्रभावविहीन होते हैं। चूँकि आर्थिक व सामाजिक संरचना के निर्माण में विनियोग अनुत्पादक और लाभरहित होता है अतएव निजी व्यक्तियों की रुचि इस ढाँचे के विस्तार में नहीं रहती है। जरूरी आर्थिक संरचना (Economic Structure) के अभाव में सन्तुलित विकास सम्भव नहीं हो पाता।
   आर्थिक एवं सामाजिक संरचना के निर्माण अर्थात् बाह्य मितव्ययिताओं (Frugalities) के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में पूँजी विनियोग की जरूरत होती है इसलिए सरकार को स्वयं ही इस ओर ध्यान देना चाहिए।
   यदि अर्थव्यवस्था में बाह्य मितव्ययिताएँ विद्यमान हों तो—(i) नये साहसी उपक्रम लगाना शुरू कर देंगे। (ii) कई नये स्थानों पर साहसी अपने उपक्रमों का विस्तार करेंगे। (iii) लाभ की मात्रा अधिक होने से विदेशी एवं घरेलू विनियोगकर्त्ता पूँजी लगाना प्रारम्भ कर देंगे। यदि कुछ उद्योग समानान्तर स्थापित होंगे तो एक-दूसरे पर तकनीकी निर्भरता भी बढ़ सकेगी। इस अनुपूरकता के आधार पर दुष्चक्रों को तोड़ा जा सकेगा।
2. **बाजार विस्तार एवं प्रबल प्रयास (बड़े धक्के)** (Big Push and Enlagring the Market) —विनियोग के बड़े धक्के के कारण पूर्ति पक्ष में विस्तार होगा। पूर्ति को आवश्यक स्तर पर बनाये रखने के लिए उत्पादित वस्तुओं एवं सेवा के लिए माँग में विस्तार एवं वृद्धि जरूरी हैं। इसके लिए कई सहायक एवं पूरक उद्योगों की स्थापना होने से अन्तर उद्योग माँग का भी विस्तार होगा और प्रत्येक उद्योग एक-दूसरे के लिए माँगकर्त्ता होंगे। इसके फलस्वरूप विकास पक्ष में गति उत्पन्न होगी।

सहायक एवं पूरक उद्योगों की बड़े पैमाने पर स्थापना होने से

(i) आय-प्रभाव का सृजन होता है।

(ii) आय में वृद्धि से माँग में वृद्धि होती है।

(iii) उद्योगों की उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग होने लगता है।

(iv) लागत न्यूनतम बिन्दु पर आ जाती है।

3. **अविभाज्यताओं और बाह्य बचतों के रूप** (Forms of Indivisibility and External Saving)—रोडन ने चार प्रकार की अविभाज्यताओं और बाह्य बचतों का उल्लेख किया है—

(i) **उत्पादन फलन में अविभाज्यता** (Indivisibility of Production Function)—अर्द्ध-विकसित देशों में उत्पादन फलन में बहुत-सी अविभाज्यताएँ पाई जा सकती है। किन्तु सामाजिक उपरि पूँजी की अविभाज्यता उनमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। अपनी अविभाज्यता के कारण इस तरह का विनियोग बाह्य बचतों और बढ़ते हुए प्रतिफल (Return) का एक बड़ा स्रोत हो सकता है। अविभाज्यता का प्रमुख कारण सामाजिक उपरिव्यय पूँजी है। सामाजिक उपरिव्यय से सम्बन्धित सेवाएँ, जैसे—जल व्यवस्था, संवादवाहन, शक्ति व्यवस्था, यातायात का प्रबन्ध आदि ऐसी सेवाएँ हैं। जो अप्रत्यक्ष (Indirect) रूप से अत्यधिक उत्पादक (Very Productive) होती हैं और इनकी आयु भी अधिक होती है। इनका आयात भी प्राय: सम्भव नहीं होता। इन सामाजिक उपरिव्यय सेवाओं के विकास के लिए काफी बड़ी मात्रा में विनियोजन की जरूरत पड़ती है। यह हो सकता है कि अर्द्ध-विकसित देशों में उनकी पूरी क्षमताओं (Capability) का प्रयोग कुछ समय तक न हो सके। लेकिन अन्य उद्योगों के विकास के लिए इनका समुचित प्रबन्ध जरूरी होता है। इस प्रकार के विनियोग से प्रतिफल (Return) काफी लम्बे समय के बाद मिलता है।

प्रो० रोजोन्स्टीन रोडन के अनुसार सामाजिक उपरिव्यय पूँजी के साथ निम्नलिखित अविभाज्यताओं को सम्बन्धित किया जा सकता है—

(a) इस व्यय का ऐतिहासिक (Historical) क्रम नहीं बदला जा सकता है अर्थात् इस व्यय का सबसे पहले ही किया जाना जरूरी होता है।

(b) एक न्यूनतम मात्रा आर्थिक और सामाजिक उपरिव्यय पर व्यय किये बिना मनोवांछित प्रगति (Progress) अथवा विकास प्राप्त नहीं किया जा सकता।

(c) यह विनियोग बड़ी मात्रा में ही करना पड़ता है। अन्यथा इसे 'तकनीकी लाभ' प्राप्त नहीं हो सकते।

(d) इन विकास सेवाओं का आयात (Import) नहीं किया जा सकता। इसलिए उनका निर्माण देश के अन्दर ही करना पड़ता है।

(e) आदान-प्रदान प्रक्रियाओं के कारण सामाजिक उपरिव्यय मदों पर किया गया प्रत्येक विनियोग अन्य उद्योगों में विनियोग (Investment) की सम्भावना (Posibility) को बढ़ा देता है।

(ii) **माँग की अविभाज्यता** (Indivisibility of Demand)—'बड़े धक्के' के सिद्धान्त के पक्ष में दूसरा महत्त्वपूर्ण तर्क माँग अथवा पूरक माँग की अविभाज्यता है। माँग की अविभाज्यता के कारण ही परस्पर निर्भर उद्योगों का एक साथ विकास करने की जरूरत होती है। व्यक्तिगत अथवा एकाकी विनियोजनों के साथ यहाँ अधिक मात्रा में जोखिम इसलिए पाया जाता है कि इस बात की सम्भावना नहीं होती कि सीमान्त माँग के कारण उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएँ बिक भी सकेंगी अथवा नहीं। अतएव यह अत्यन्त जरूरी हो जाता है कि पारस्परिक निर्भरता वाले अनेक उद्योग-धन्धों में एक साथ विनियोजन किया जाए, जिससे माँग की कमी के कारण किसी समस्या (Problem) का सामना न करना पड़े। एक साथ अनेक उद्योग-धन्धों में विनियोजन किये जाने से माँग बढ़ेगी, रोजगार के स्तरों में भी वृद्धि होगी या अधिक वस्तुओं के उत्पादन के साथ-साथ उनकी खपत (Consumption) भी बढ़ेगी। **प्रो० रोड़न** ने स्वयं लिखा है।, "जब तक इस बात का निश्चय न हो कि विनियोजन पूरक होगा, तब तक विनियोजन एकांकी कार्यक्रम अत्यधिक जोखिमपूर्ण ही समझा जायेगा। किन्तु एक बड़ा विनियोजन कार्यक्रम जो एक इकाई के रूप में हो, राष्ट्रीय आय में काफी वृद्धि प्राप्त कर सकता है।"

TOUCH 'n PASS

उदाहरण (Example)—रोजोन्स्टीन रोडन ने अपनी बात स्पष्ट करने के लिए जूता कारखाने का प्रसिद्ध उदाहरण दिया हैं। प्रारम्भ में बन्द अर्थव्यवस्था लेकर, मान लीजिए कि एक जूता कारखाने में सौ प्रच्छन्न बेरोजगार श्रमिक काम पर लगाये जाते हैं। जिनकी मजदूरी अतिरिक्त आय का निर्माण करती है। यदि ये श्रमिक अपनी समस्त आय उन जूतों पर व्यय करें। जिनका वे निर्माण करते हैं तो जूता-बाजार में निरन्तर माँग रहेगी और इस तरह उद्योग सफल हो जायेगा लेकिन वे समस्त अतिरिक्त आय जूतों पर व्यय नहीं करेंगे। क्योंकि मानवीय आवश्यकताएँ अनेक प्रकार की होती हैं।

कारखाने के बाहर के लोग भी इन अतिरिक्त जूतों को नहीं खरीदेंगे क्योंकि वे दरिद्र हैं और उनके पास इतना धन नहीं है कि वे अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकें। इस प्रकार बाजार के अभाव के कारण नया कारखाना बन्द हो जायेगा।

रोडन की जूता फैक्टरी का उदाहरण चित्र की सहायता से स्पष्ट किया गया है—

(a) मान लीजिए, जूता फैक्टरी जिस प्लाण्ट पर कार्य कर रही है, उसका औसत लागत वक्र AC और सीमान्त लागत (Marginal Cost) वक्र MC हैं। यह प्लाण्ट अनुकूलतम प्रकार के प्लाण्ट से कुछ छोटा है।

(b) चित्र में AR_1 या D_1 जूता फैक्टरी की माँग और MR_1 उसकी सीमान्त आय प्रदर्शित करती है, जबकि अर्थव्यवस्था में विनियोग केवल जूता की फैक्टरी द्वारा किया जाता है।

(c) इस स्थिति में MC और MR_1 के कटान के आधार पर सन्तुलन उत्पादन OQ_1 (या 10,000) जूते हैं। जिन्हें वह OP कीमत पर बेचती है।

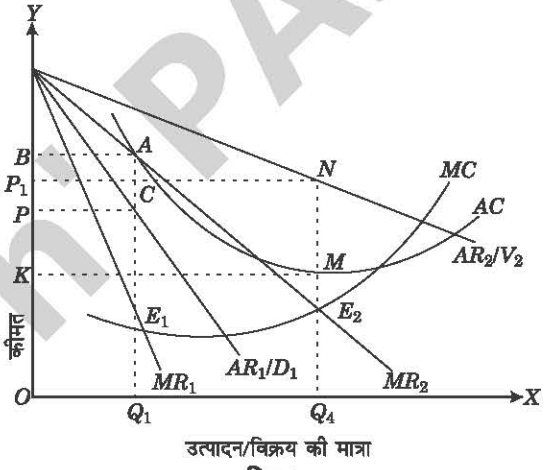

चित्र 1

(d) OP कीमत पर माँग की कमी के कारण फैक्टरी अपनी औसत लागत (AC) नहीं निकाल पा रही है और उसे $PCAB$ की हानि उठानी पड़ रही है।

(e) अब मान लीजिए, एक साथ अनेक विभिन्न उद्योगों में विनियोग (Investment) किया जाता है तो जूतों के बाजार का विस्तार होता है जिससे जूतों की माँग वक्र (चार गुना) बढ़कर D_2 हो जाती है और उससे सम्बन्धित सीमान्त आय MR_2 हो जाती है।

(f) इस स्थिति में अब MR_2 और MC वक्रो के आधार पर निर्धारित उत्पादन OQ_1 (या 40,000 उत्पादन में चार गुना वृद्धि) OP_1 कीमत पर होगी। इसके परिणामस्वरूप फैक्टरी अपनी लागत पूरी कर लेगी और P_1NMK लाभ भी अर्जित करेगी।

उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि माँग की परिपूरकता के कारण सीमित माँग (Demand) की समस्या विभिन्न उद्योगों में एक साथ विनियोजन करने के पश्चात दूर हो जाती है और विनियोजन के क्षेत्र में पाया जाने वाला जोखिम भी काफी कम हो जाता है। इस प्रकार की अविभाज्यता के कारण भी यह जरूरी हो जाता है कि बड़ी मात्रा में अनेक उद्योग धन्धों में एक साथ विनियोजन किया जाये।

(iii) **बचत की पूर्ति में अविभाज्यता** (Invisibility in Supply of Savings)—अर्द्ध-विकसित देशों में 'बड़े धक्के' के पक्ष में बचतों की पूर्ति की अविभाज्यता का तर्क भी दिया जाता है। यह अविभाज्यता इसलिए पैदा होती है क्योंकि आय के एक निश्चित स्तर पर पहुँच जाने के पश्चात ही बचतों में सार्थक वृद्धि करना सम्भव होता है। विशेष रूप से अर्द्ध-विकसित देशों में निम्न आय स्तर (Low Income Level) के कारण बचतों का स्तर भी अत्यन्त निम्न रहता है। फलत: यह और भी जरूरी हो जाता है कि जब विनियोग वृद्धि के फलस्वरूप आय में

TOUCH 'n PASS

वृद्धि हो तो बचत की औसत दर की अपेक्षा बचत की सीमान्त दर अधिक तीव्र गति से बढ़नी चाहिए अन्यथा विनियोग निष्क्रिय सिद्ध होगा और पुनर्विनियोग अत्यन्त कम होगा।

रोजोन्स्टीन के शब्दों में "एक न्यूनतम ऊँची मात्रा के विनियोग के लिए ऊँची मात्रा में बचत की आवश्यकता होती है जिसे निम्न आय वाले अर्द्ध-विकसित राष्ट्र में प्राप्त करना कठिन हैं। इस दुष्चक्र से बाहर आने का रास्ता है कि सर्वप्रथम आय में वृद्धि की जाये और ऐसी तान्त्रिकता का प्रबन्ध किया जाये तो यह आश्वासन दे कि द्वितीय अवस्था में बचत की सीमान्त दर औसत बचत दर से बहुत ऊँची होगी।" अन्य शब्दों में, प्रो० रोडन का मत है कि आय के नीचे स्तर वाली अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बचत की ऊँची दरों को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका विनियोगों (Investments) में वृद्धि हैं। जिसे इन देशों में यहाँ अविकसित एवं अप्रयुक्त मानवीय संसाधन और अन्य साधनों को गतिशील (Movable) कर प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) **मनोवैज्ञानिक अविभाज्यता** (Psychological Indivisibility)—मनोवैज्ञानिक आधार पर भी प्रो० रोडन ने भारी मात्रा में विनियोजन का सुझाव प्रस्तुत किया है। उन्हीं के शब्दों में, छोटे-छोटे प्रयास विकास पर पर्याप्त प्रभाव नहीं डालते। विकास के लिए अनुकूल वातावरण उतना ही जरूरी है जितना कि एक न्यूनतम गति अथवा मात्रा। सफल आर्थिक विकास नीति में बल एवं प्रेरणा की अविभाज्यता का विशेष महत्त्व हैं।

तीन सन्तुलन (Three Balance)—रोडन ने सन्तुलित विकास के तीन सन्तुलनों के समूह की चर्चा की है—

(a) उपभोक्ताओं द्वारा माँग में वृद्धि के क्रमानुसार विभिन्न उपभोग पदार्थ उद्योगों में क्षैतिज सन्तुलन (Horizontal Balance) लाना, जिससे माँग में वृद्धि के साथ-साथ इन वस्तुओं की पूर्ति अबाध गति से होती रहे।

(b) सभी औद्योगिक क्षेत्रों में सामाजिक उपरिव्यय पूँजी (Social Overhead Capital) और प्रत्यक्ष उत्पादक प्रक्रियाओं (Directly Productive Activities) के बीच सन्तुलन बनाये रखना, जिससे एक-दूसरे के अभाव में विकास का कार्यक्रम ढीला न पड़ सके।

(c) पूँजीगत उद्योगों व उपभोक्ता पदार्थ उद्योगों के बीच उनकी तकनीकी निर्भरता के अनुसार उदग्रीय सन्तुलन (Vertical Balance) बनाये रखना जिससे बड़े पैमाने पर बाह्य बचतें प्राप्त हो सके।

इस सिद्धान्त के अनुसार आर्थिक गतिविधि में इस तरह का व्यापक सन्तुलन बनाये बिना अर्द्ध-विकसित देशों में आर्थिक विकास करना लगभग असम्भव है।

राज्य की भूमिका (Role of the State)—रोड़न ने अर्द्ध-विकसित देशों के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बहुत बड़े पैमाने पर प्रयास तथा विनियोग के लिए राज्य की भूमिका को महत्त्वपूर्ण माना है। इसलिए रोडन ने व्यक्तिगत निर्णयों के स्थान पर केन्द्रीकृत विनियोग नियोजन (Centralised Investment Planning) या निर्णय पर जोर दिया है। जिससे एक साथ अर्थव्यवस्था में अनेक पूरक उद्योगों में विनियोग हो और बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था को बाह्य बचतों का लाभ मिल सके।

इसी कारण प्रथम योजना में स्पष्ट किया गया कि "चूँकि नियोजन का उद्देश्य वस्तुतः द्रुत विकास को प्रोत्साहित करना हैं, इसलिए समस्या विनियोग दर की निश्चित अवस्थाओं में बढ़ाने की है, ताकि आरम्भिक काल में स्पष्ट कम किया जा सके परन्तु साथ ही साथ यह भी ध्यान रखा जाये कि समाज अपेक्षित दृष्टि से अल्पकाल में वांछित महान प्रयास अवश्य जुटाएँ।"

प्र.3. रोडन के सिद्धान्त के गुण व आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
Critical merits and appraisal of Rodan's theory.

उत्तर

रोडन के सिद्धान्त के गुण
(Merits of Rodan Theory)

इस सिद्धान्त के निम्नलिखित गुण हैं—

(i) प्रो० रोजोन्स्टीन रोडन का सिद्धान्त अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक मान्यताओं पर अवलम्बित है। उन्होंने 'अविभाज्यताओं' और 'सम्भावनाओं एवं असम्भावनाओं' का एक अच्छा उल्लेख प्रस्तुत किया है।

(ii) उनका सिद्धान्त सन्तुलन की दशाओं मात्र का ही उल्लेख प्रस्तुत नहीं करता वरन सन्तुलन के मार्ग का भी विश्लेषण (Analysis) प्रस्तुत करता है।

TOUCH 'n PASS

(iii) यह सिद्धान्त कुछ बातों में स्थैतिक सन्तुलन (Static balance) के परम्परागत सिद्धान्त से भी श्रेष्ठ है। रोडन का यह कहना है कि यह विकास प्रक्रिया अनेक असतत छलाँगों का परिणाम है जो पूर्णतया सत्य जान पड़ता है। उनकी उत्पादन फलन की अविभाज्यताओं की मान्यता भी आर्थिक जगत की एक वास्तविकता है।

(iv) यह सिद्धान्त अर्द्ध-विकसित देशों में पायी जाने वाली बाजार अपूर्णताओं से सम्बन्धित विनियोग का एक मार्गदर्शक सिद्धान्त है जो हमें यह बताता है कि ऐसे देशों में कीमत यन्त्र की अपेक्षा विनियोग की एक जरूरी न्यूनतम मात्रा ही आर्थिक विकास को गति दे सकती है।

रोडन के सिद्धान्त का आलोचनात्मक विश्लेषण
(Critical Appraisal of Rohan's Theory)

आर्थिक विकास के बड़े धक्कें की कई अर्थशास्त्रियों ने कटु आलोचना की है जिनमें जेकाब, विनार, एलिस, हावर्ड और एडलर प्रमुख हैं। कुछ आलोचनाएँ हैं—

1. **नगण्य मितव्ययिताएँ** (Negligible Economies)—बड़े धक्के के सिद्धान्त के प्रतिपादन का मुख्य आधार यह है कि इससे बाह्य मितव्ययिताएँ प्राप्त होती है। परन्तु (i) बाह्य मितव्ययिताएँ तो विदेशी व्यापार से उपलब्ध की जा सकती है। जिसके लिए इतनी अधिक मात्रा में विनियोग की आवश्यकता न होगी। (ii) चूँकि बाह्य मितव्ययिताएँ लागत (Frugalities) अधिक घटाती है और तदनुरूप उत्पादन नहीं बढ़ातीं, अतएव यह नीति अर्द्ध-विकसित देशों में अधिक उपर्युक्त न होगी। इसका कारण यह है कि अर्द्ध-विकसित देशों में प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादनकर्त्ता ही अधिक होते हैं। इसलिए बाह्य मितव्ययिताएँ बढ़ने से इन वस्तुओं के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा।
2. **कृषि-क्षेत्र की उपेक्षा** (Neglect of Agriculture Sector)—यह सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि आर्थिक विकास औद्योगिक उन्नति के द्वारा ही हो सकता है। कृषि की उन्नति से नहीं लेकिन अर्द्ध-विकसित देशों में राष्ट्रीय आय का लगभग 75% कृषि से ही प्राप्त होता है, अतएव कृषि के विकास से कुल अर्थव्यवस्था का विकास सम्भव है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में कृषि क्षेत्र की उपेक्षा विकास को तीव्र करने के बजाय मन्द कर देगी।
3. **ऐतिहासिक तथ्य नहीं है** (Not a Historical Fact)—अगर हम विकसित देशों के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो हमे विदित होगा कि उन देशों का विकास किसी बड़े धक्के के कारण नहीं हुआ था। प्रो० हेगन के अनुसार, "ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े धक्के की उपस्थिति या अनुपस्थिति कहीं भी विकास की प्रमुख विशेषता नहीं रही है।"
4. **पूँजी-निर्माण का अभाव** (Lack of Capital Formation)—अर्द्ध-विकसित देशों में इस बड़े धक्के के सिद्धान्त के कार्यक्रमों में पर्याप्त मात्रा में बचतों एवं पूँजी निर्माण का अभाव रहता है। जिसका इस सिद्धान्त में ध्यान नहीं दिया गया है।
5. **कम विनियोजन से अधिक उत्पादन** (More Production With Less Investment)—प्रो० जान एडलर ने भारत, पाकिस्तान व अन्य एशियाई व दक्षिणी अमेरिका के देशों में निम्न पूँजी उत्पाद अनुपातों के अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि "विनियोजन का सापेक्षतम निम्न स्तर अतिरिक्त उत्पादन के रूप में अच्छी तरह हिसाब चुकता कर देता है।" इसलिए इस बात का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि अर्द्ध-विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए विनियोजन के बड़े धक्के की जरूरत है।
6. **प्रशासकीय कठिनाइयाँ** (Administrative Difficulties)—रोड़न का सिद्धान्त इस मान्यता (Opinion) पर आधारित है कि राज्य द्वारा बड़े पैमाने पर विनियोजन (Investment) किया जाता है। चूँकि अर्द्ध-विकसित देशों में प्रशासकीय मशीनरी दुर्बल एवं अदक्ष होती है। अतएव राज्य विनियोजन पर निर्भरता स्वयं अनेक समस्याएँ उत्पन्न कर देती है। सांख्यिकीय सूचना, तकनीकी ज्ञान, प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी के कारण न केवल विविध परियोजनाओं की योजना बनाने में मुश्किल होती है। वरन इनके क्रियान्वयन (Implimentation) में भी कठिनाई होती है।
7. **स्फीतिकारी दबाव** (Inflationary Pressure)—जब सरकार आर्थिक संरचना के निर्माण के लिए भारी मात्रा में विनियोजन करती है तो उपभोक्ता वस्तुओं की कमी से स्फीतिकारी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जो आर्थिक विकास में गतिरोध (Hindrance) उत्पन्न कर सकती हैं।
8. **सामाजिक उपरि पूँजी की अविभाज्यता का अतार्किक दृष्टिकोण** (Unlogical Approach towards Indivisibility of Social Overheads)—सामाजिक उपरि पूँजी की अविभाज्यताएँ रोडन के सिद्धान्त का सबसे

TOUCH 'n PASS

प्रबल तर्क है। लेकिन अर्द्ध-विकसित देशों के सम्बन्ध में यह तर्क ठीक नहीं बैठता। बहुत से अर्द्ध-विकसित देशों में पहले से ही सामाजिक उपरि सुविधाओं का नये सिरे से विकास करने की समस्या नहीं हैं वरन वर्तमान सुविधाओं का विस्तार और उनमें सुधार करने की समस्या हैं। अतएव यह सम्भव हो सकता है कि सामाजिक उपरि पूँजी के निर्माण में बहुत अधिक विनियोग करना इन देशों के लिए बहुत अधिक उपर्युक्त न हो।

9. **मिश्रित अर्थव्यवस्था** (Mixed Economy)—अधिकांश अर्द्ध-विकसित देश मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) को अपनाये हुए हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक निजी क्षेत्रों में सहयोग एवं सामंजस्य के स्थान पर प्रतियोगिता और संघर्ष ही दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में बड़े धक्के के सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप देने पर यह प्रतियोगिता और संघर्ष और अधिक बढ़ जाता है।
10. **प्रो० इलिस की आलोचनाएँ** (Criticisms of Prof. Ellis)—प्रो० इलिस ने रोडन के सिद्धान्त की आलोचना करते हुए यह कहा है कि इस सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप में अपनाने में निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा—
    (i) अर्द्ध-विकसित देश प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले देश है। इन देशों में बाह्य मितव्ययिताओं के बढ़ने के बाद भी इन वस्तुओं के उत्पादन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आयेगा।
    (ii) प्रो० रोड़न के सिद्धान्त में अर्द्ध-विकसित देशों में बचत समस्या पर समुचित रूप से बल नहीं दिया गया है।
    (iii) विकसित देशों का आर्थिक विकास यह स्पष्ट कर देता है कि इनका आर्थिक विकास 'बड़े धक्के' के सिद्धान्त को अपनाने के बाद नहीं हुआ है।
    (iv) इस सिद्धान्त की यह मान्यता भी सही नहीं है कि आर्थिक विकास कृषि उन्नति के बजाय औद्योगीकरण की सहायता से हो सकता है। अर्द्ध-विकसित देश अपनी राष्ट्रीय आय या विदेशी व्यापार आय का लगभग दो-तिहाई भाग कृषि से ही प्राप्त करते हैं। इसलिए कृषि के विकास को इन देशों में अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व देना होगा।

प्र.4. नैल्सन मॉडल की व्याख्या विस्तार से कीजिए।
Explanation of Nelson's model in detail.

उत्तर

नैल्सन का मॉडल
(Nelson's Model)

नैल्सन मॉडल इस मान्यता पर आधारित है कि जनसंख्या की वृद्धि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की वृद्धि परस्पर आश्रित और सम्बन्धित है। आय के निम्न स्तर पर किसी अर्थव्यवस्था का निम्न स्तरीय सन्तुलन अवरोध (Obstacles) समझाने के लिए नैल्सन के सम्बन्धों के तीन समुच्चय (Sets) प्रयोग किये हैं—

1. **जनसंख्या वृद्धि समीकरण** (Population Growth Equation)—जनसंख्या वृद्धि का समीकरण वह समीकरण है जो स्पष्ट करता है कि नीची प्रति व्यक्ति आय वाले क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि की दर dP/P में परिवर्तन मृत्यु-दर में परिवर्तनों के कारण होते हैं और मृत्यु-दर में परिवर्तन प्रति व्यक्ति आय के स्तर में परिवर्तनों के कारण होते हैं लेकिन जब प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर से ऊपर पहुँच जाती हैं। तो प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि मृत्यु-दर को प्रभावित नहीं करती।

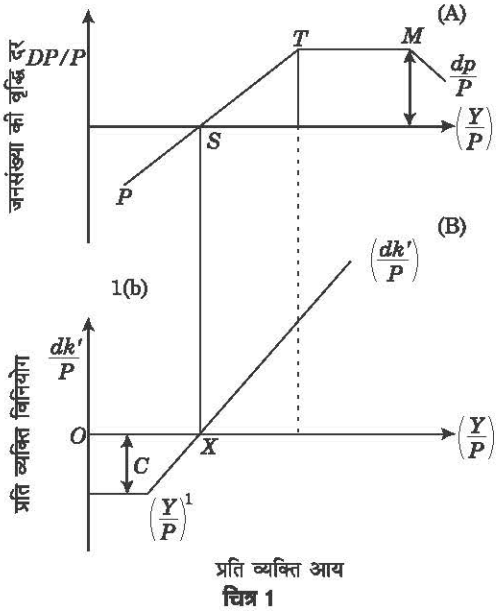

चित्र 1

इस तथ्य को रेखाचित्र की सहायता से दर्शाया गया है। चित्र में भाग (A) में—
(i) Y/P प्रति व्यक्ति आय के स्तर से सम्बन्ध रखता है जो कि क्षैतिज अक्ष पर मापी गई और dP/P जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशत दर है जो अनुलम्ब अक्ष पर मापी गई है।

TOUCH 'n' PASS

(ii) क्षैतिज अक्ष S बिन्दु प्रति व्यक्ति आय का न्यूनतम जीवन निर्वाह-स्तर है जहाँ पर कि जनसंख्या (Population) का वृद्धि वक्र (dP/P) प्रति व्यक्ति आय के स्तर के बराबर है। इस स्तर पर जनसंख्या स्थिर है।

(iii) S बिन्दु के बायीं ओर जनसंख्या घट रही है यदि हम जनसंख्या के वृद्धि वक्र के साथ-साथ S से ऊपर की ओर चलें तो

न्यूनतम निर्वाह-स्तर से ऊपर प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर, जनसंख्या की वृद्धि-दर "एक उच्च भौतिक सीमा" T तक बढ़ती चलती है। कुछ समय तक, इस स्तर पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ-साथ जनसंख्या बढ़ेगी और फिर बिन्दु M से गिरना शुरू हो जायेगी अर्थात् उच्च प्रति व्यक्ति आय पर जनसंख्या की वृद्धि दर (Growth Rate) गिरेगी।

2. **पूँजी-निर्माण से सम्बन्धित समीकरण** (Capital Formation Equation)—अर्थव्यवस्था में पूँजी निर्माण अथवा शुद्ध विनियोग (dK) बराबर होता है—

(i) बचत से निर्मित पूँजी (dK)

(ii) कृषि के तहत नयी भूमि की मात्रा (dr) अर्थात् $dk = dk' + dr$।

चूँकि जैसे-जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है, नई भूमि जोत में आती है पर एक सीमा के बाद नई भूमि में वृद्धि दुर्लभ हो जायेगी, अतएव यह मान लिया गया है कि नयी भूमि-पूँजी निर्माण का स्रोत नहीं है। पूँजी स्टॉक में वृद्धि बचत (Saving) द्वारा ही होगी। यह भी मान लिया गया है कि सभी बचत विनियोजित हो जायेगी। इस प्रकार—

पूँजी निर्माण में वृद्धि = बचत में वृद्धि = औद्योगिक क्षेत्र में विनियोग में वृद्धि।

जब तक आय जीवन निर्वाह स्तर से ऊपर नहीं हो जाती, विनियोग में कोई वृद्धि सम्भव नहीं होगी, इस बिन्दु के बाद विनियोग में वृद्धि प्रति व्यक्ति आय के साथ होती है। नैल्सन ने यह भी माना है कि अविनियोग (Disinvestment) की भी एक निचली सीमा है क्योंकि कोई कितना भी भूखा क्यों न हो, वह रेल या सड़क तोड़कर नहीं खायेगा।

इसी तथ्य को चित्र के भाग (B) में दर्शाया गया है। चित्र में—

(i) dK/P बचतों में से विनियोग की प्रति व्यक्ति दर है जो अनुलम्ब अक्ष पर मापी गयी है।

(ii) वक्र dK/P विनियोग का वृद्धि वक्र है जो विनियोग की प्रति व्यक्ति दर को प्रति व्यक्ति आय के विभिन्न स्तरों से जोड़ता है। यह वक्र क्षैतिज अक्ष को X बिन्दु पर काटता है जो कि शून्य बचत का स्तर है।

(iii) X बिन्दु के बायीं ओर विनियोग ऋणात्मक है X शून्य बचत वाले आय स्तर को बतलाता है। जैसे—जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। विनियोग स्तर भी बढ़ता है जिसकी कोई उच्चतम (Highest) सीमा नहीं है।

3. **आय-निर्धारण समीकरण** (Income Determination Equation)—नैल्सन मॉडल का आय-निर्धारण समीकरण उत्पादन फलन की भाँति है। जो इस मान्यता पर आधारित है कि आय या उत्पादन साधनों के रूप में आगतों का रैखिक सजातीय फलन है। अर्थात् आय (Y) या उत्पादन (O) फलन है—पूँजी (K), श्रम (L) व प्रौद्योगिकी स्तर (T) का। इस प्रकार : Y or $O\ f\ (K\ L\ T)$ मॉडल की उपर्युक्त मान्यताओं (Opinion) के आधार पर 'आय-वृद्धि-वक्र' (Income Growth Curve) का निर्माण किया जा सकता है। जिसका प्रदर्शन रेखाचित्र में dY/Y वक्र के द्वारा किया गया है। $S=X$ रेखाचित्र से लिया गया हैं। इस स्थिति में जनसंख्या स्थिर है, बचत के द्वारा निर्मित प्रति व्यक्ति पूँजी शून्य है। फलस्वरूप आय की वृद्धि दर शून्य ($dY/Y = O$) हैं। स्थिर साम्य के स्तर के ऊपर प्रति व्यक्ति आय के वृद्धि के साथ प्रति व्यक्ति पूँजी की उपलब्धता तथा श्रम शक्ति की वृद्धि के कारण आर्थिक विकास की दर में वृद्धि होती है। परन्तु प्रौद्योगिकी प्रगति के अभाव में 'परिवर्तनीय अनुपात नियम' की क्रियाशीलता के कारण आर्थिक विकास की वृद्धि दर में गिरावट आयेगी।

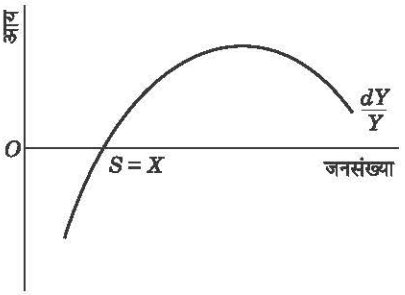

चित्र 2

नैल्सन-मॉडल की व्याख्या (Explanation of Nelson's Model)

उपर्युक्त तीनों समीकरणों और रेखा चित्र व से प्राप्त तीन वक्रों (अ) जनसंख्या वृद्धि वक्र (dP/P) (ब) प्रति व्यक्ति विनियोग वृद्धि दर (dK/P) (स) आय वृद्धि दर (dY/Y) की सहायता से अपने मॉडल की व्याख्या

TOUCH 'n' PASS

रेखाचित्र 3 की सहायता से किया है। चित्र 3 में—

(i) (dY/Y) आय वृद्धि दर वक्र है जिसे रेखाचित्र 3 से लिया गया है। तथा (dP/P) वक्र जनसंख्या वृद्धि दर वक्र है। जिसे रेखाचित्र 1(a) से लिया गया है।

(ii) रेखाचित्र 1(b) से X का स्तर लिया गया हैं। जो सुविधा के लिए S के बराबर मान लिया गया है।

(iii) रेखाचित्र 3 में $S = X$ एक ऐसा बिन्दु है जिस पर प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर के बराबर है जिस पर जनसंख्या की वृद्धि दर स्थिर है और दूसरी ओर, यह प्रदर्शित करता है कि इस बिन्दु पर प्रति व्यक्ति बचत तीन विनियोग शून्य हैं।

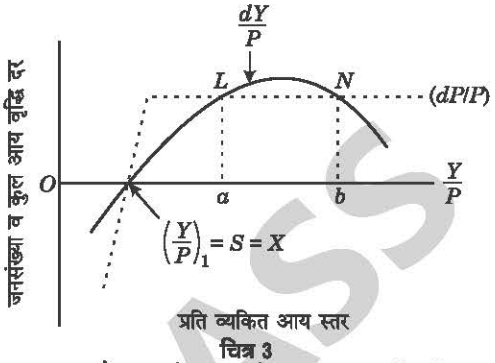

चित्र 3

(iv) प्रति व्यक्ति आय के प्रत्येक स्तर पर जो जीवन-निर्वाह स्तर बिन्दु ($S=X$) और Oa के बीच हो, जनसंख्या की वृद्धि दर (Growth Rate) आय की वृद्धि दर की अपेक्षा अधिक होगी इसके कारण प्रति व्यक्ति आय में स्थायी रूप से गिरावट होगी और यह जीवन-निर्वाह स्तर पर पहुँच जायेगी। इस बिन्दु को 'अल्प सन्तुलन पाश बिन्दु' या 'निम्न स्तरीय सन्तुलन में जकड़ा बिन्दु' कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय (Percapita Income) का कोई भी स्तर जो Oa से कम हो, प्रति व्यक्ति आय को जरूरी रूप से जीवन निर्वाह स्तर पर पहुँचा देगा।

(v) आय के वितरण में परिवर्तन लाने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए, जिससे विनियोजक धन संचय कर सकें।

(vi) एक मापक सरकारी विनियोग कार्यक्रम होना चाहिए।

(vii) विदेशों से कोष प्राप्त करके आय और पूँजी बढ़ानी चाहिए।

अर्द्ध-विकसित देशों में निम्न स्तरीय सन्तुलन अवरोध से बचने और यह जरूरी है कि उपर्युक्त वर्णित उपायों को एक साथ अपनाया जाए, जिससे जनसंख्या की वृद्धि दर की तुलना में आय की वृद्धि दर अधिक हो सके। जब किसी निश्चित न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय स्तर से ऊपर एक बार यह स्थिति उपलब्ध हो जायेगी तो सरकारी प्रयास के बिना भी तब तक सतत विकास होता चला जायेगा जब तक कि प्रति व्यक्ति आय (Percapita Income) का एक नया उच्च स्तर नहीं आ जाता।

आलोचनाएँ (Criticisms)

1. **समय तत्त्व की अवहेलना** (Time Element Ignored)—नैल्सन के सिद्धान्त की आलोचना करते हुए प्रो० मिण्ट ने यह आपत्ति उठायी कि प्रति व्यक्ति आय स्तर में थोड़ी-सी वृद्धि, जैसे—S से C, S बिन्दु पर पुनः स्थिर साम्य की स्थिति कायम तभी करेगी जबकि 'समय' को वक्र खींचते समय नहीं लिया गया हो, पर यदि 'समय' को लिया गया तो S से C पर बदलाव के साथ पूँजी स्टॉक में स्थायी वृद्धि हो जायेगी, ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था फिर C से खिसककर S पर नहीं आयेगी।
2. **फलनात्मक सम्बन्ध नहीं** (No Functional Relations)—प्रति व्यक्ति आय स्तर जनसंख्या की वृद्धि दर और कुल आय के वृद्धि दर के बीच नैल्सन ने फलनात्मक सम्बन्ध की बात की, पर मिण्ट के अनुसार इसके बीच इस तरह के निश्चित और कठोर फलनात्मक सम्बन्ध को खींचा नहीं जा सकता है।
3. **अन्य आलोचनाएँ** (Other Criticisms)
   (i) यह सिद्धान्त जन्म-दर कम करने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे जनसंख्या नियन्त्रण प्रयासों की अवहेलना करता है।
   (ii) यह सिद्धान्त अर्द्ध-विकसित देशों में बचत एवं विनियोग के स्तर पर विदेशी पूँजी के प्रभाव का विश्लेषण (Analysis) प्रस्तुत नहीं करता है।

TOUCH 'n' PASS

प्र.5. डोमर के मॉडल एवं हैरोड-डोमर मॉडल की अल्प-विकसित देशों की दृष्टि से सीमाओं का विवरण दीजिए। (Describe the Domar Model and limitations of Harrod-Domar models from the stand-point of underdevelopment countries.

उत्तर

डोमर का मॉडल
(The Domar Model)

डोमर ने 1947 में अपने मॉडल का विकास किया जिसका प्रकाशन मार्च, 1947 में 'American Economic Review' में हुआ। यह मॉडल मूलत: कीन्स की विचारधारा पर आधारित है। डोमर के मतानुसार कीन्स के मॉडल में अनेक कमियाँ (Demerits) हैं। जैसे—(i) कीन्स के मतानुसार बेरोजगारी का प्रमुख कारण जमाखोरी (Hoarding) हैं। किन्तु डोमर का मत है कि यदि जमाखोरी समाप्त भी हो जाए (अर्थात् विनियोग करने से), तब भी पूर्ण रोजगार (Full Employment) की स्थिति को प्राप्त कर सकना सम्भव नहीं होगा। (ii) कीन्स ने अपने सिद्धान्त से माँग वृद्धि को अधिक महत्त्व प्रदान किया हैं किन्तु विनियोग की मात्रा और दर की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। डोमर के मॉडल की मुख्य विषय-वस्तु यह है कि विनियोग से एक ओर तो आय का सृजन होता है और दूसरी ओर उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, इसलिए पूर्ण रोजगार को बनाये रखने के लिए विनियोग में किस दर से वृद्धि हो जिससे कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि आय वृद्धि के बराबर हो। डोमर इस प्रश्न का उत्तर विनियोग के माध्यम से कुल पूर्ति और कुल माँग के बीच सम्बन्ध स्थापित करके प्रस्तुत करते हैं।

निरपेक्ष वृद्धि के बराबर होगी, यथा—

$$150 \times \frac{\frac{12}{100} \times \frac{25}{100}}{150} = \frac{12}{100} \times \frac{25}{100} = \propto \sigma = 3\%$$

इस तरह पूर्ण रोजगार स्तर को बनाये रखने के लिए आय में 3% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि जरूरी है। इस सुनहरी मार्ग से विचलन (Divergence) के परिणामस्वरूप चक्रीय परिवर्तन (Cyclical Fluctuations) होंगे।

जब $\propto \sigma$ की अपेक्षा $\frac{\Delta I}{I}$ अधिक होगा, तब अर्थव्यवस्था में तेजी (Boom) होगी और जब $\propto \sigma$ से $\frac{\Delta I}{I}$ कम होगा, तब अर्थव्यवस्था में मन्दी होगी।

हैरोड-डोमर मॉडल की अल्प-विकसित देशों की दृष्टि से सीमाएँ
(Limitations of Harrod-Domar Models from the Stand point of Underdeveloped Countries)

हैरोड-डोमर मॉडल औद्योगिक दृष्टि से विकसित अर्थव्यवस्थाओं की समस्याओं पर आधारित हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं की प्रमुख समस्या दीर्घकालीन स्थिरता और उच्चावचनों की है। यह मॉडल उस आय वृद्धि की दर को निर्धारित करने का प्रयास करता है। जिससे कि अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन स्थिरता बनी रहे और साथ ही साथ उसमें उच्चावचन भी न हो। किन्तु अर्द्ध-विकसित देशों की समस्या उच्चावचनों की नहीं वरन आर्थिक विकास की है। हैरोड-डोमर मॉडल अर्द्धविकसित अर्थव्यवस्थाओं में अनेक कारणों से लागू नहीं होता हैं। जिनमें से निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण हैं—

1. **परिस्थितियों में भिन्नता** (Different Conditions)—हैरोड-डोमर मॉडल का विकास विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस मॉडल के विकास का उद्देश्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं को दीर्घकालीन गतिहीनता के सम्भावित प्रभावों से बचाना है। इस मॉडल का यह उद्देश्य नहीं हैं। कि अर्द्धविकसित अर्थव्यवस्था में विकास के कार्यक्रमों के लिए दिशा-निर्देश प्रदान किये जायें।
2. **सरकारी हस्तक्षेप** (Government Intervention)—यह मॉडल इस मान्यता पर आधारित है कि सरकार आर्थिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। किन्तु अर्द्धविकसित देशों में आर्थिक गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप (Interfere) के बिना वांछित गति से आर्थिक विकास सम्भव नहीं है। इन देशों में सरकार को पथ-प्रदर्शक की भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है।
3. **बेरोजगारी की समस्या के स्वरूप की विभिन्नता** (Difference in the form of Unemployment)—**प्रो० कुरिहारा** (Kurihara) के अनुसार इस मॉडल द्वारा प्रस्तावित विनियोग की वृद्धि दर अल्प-विकसित देशों में पायी जाने

TOUCH 'n' PASS

वाली बेरोजगारी की समस्या का निदान-प्रदान कर सकने में असमर्थ है। यह मॉडल विकसित देशों की बेरोजगारी (Unemployment) की समस्या को हल करने में भले ही सफल हो किन्तु अर्द्ध-विकसित (Under-developed) देशों की बेरोजगारी न्यूर छिपी हुई बेरोजगारी को दूर कर सकने में सफल नहीं होगा।

4. **निम्न बचत-अनुपात** (Low-Saving Ratio)—इस मॉडल की विशेषता ऊँचा बचत अनुपात (High Saving Ratio) और ऊँची पूँजी-उत्पादन अनुपात (High Capital-Output Ratio) है। अर्द्ध-विकसित देशों में जनसंख्या का अधिकांश भाग जीवन-निर्वाह स्तर (Subsistence Level) पर रहता है। जिनके बचत करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस तरह इन देशों में बचत करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का बहुत ही कम प्रतिशत है। इन देशों में बचत और विनियोग का निर्णय प्राय: एक ही वर्ग लेता है।

डोमर के मतानुसार पूँजीवादी अर्थव्यवस्था से पूर्ण रोजगार स्तर बनाये रखने के लिए आय में निरन्तर वृद्धि (Consistent Growth) जरूरी होती है। डोमर के सिद्धान्त में विनियोग की दोहरी भूमिका है—प्रथम, इससे व्यक्तियों की आय में वृद्धि होती है एवं द्वितीय, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है और वस्तुओं की पूर्ति भी बढ़ती है। किसी अर्थव्यवस्था में जब उत्पादन क्षमता के बराबर वास्तविक आय में वृद्धि होगी, वहीं पूर्ण रोजगार की स्थिति कायम होगी। विनियोग के उत्पादन क्षमता को पूर्ति पक्ष (Supply Side) और वास्तविक आय-वर्धक क्षमता को माँग पक्ष (Demand Side) कहा जाता है।

उत्पादक क्षमता में वृद्धि (Increase in Productive Capacity)—डोमर ने पूर्ति पक्ष को निम्नानुसार प्रस्तुत किया—मान लीजिए कि—

(i) विनियोग की वार्षिक दर I है; तथा

(ii) नव-निर्मित पूँजी की प्रति डॉलर प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता औसतन s है। (यह उत्पादन में वृद्धि के पूँजी में वृद्धि के अनुपात अथवा वास्तविक आय अथवा सीमान्त पूँजी-उत्पादन अनुपात (Capital-output Ratio) और त्वरक (Accelerator) के व्युत्क्रम (Reciprocal) को व्यक्त करता है।

इसलिए यदि I डालर विनियोग किया जाये, तब उसकी उत्पादन क्षमता I-s डॉलर प्रति वर्ष होगी।

किन्तु नया विनियोग कुछ पुराने को खोकर ही सम्भव होगा। इस तरह श्रम, बाजार और उत्पादन के अन्य साधनों के लिए पुराने विनियोग से इसकी प्रतियोगिता होगी जिससे कि पुराने संयन्त्रों के उत्पादन में कुछ कमी होगी और अर्थव्यवस्था के वार्षिक उत्पादन (उत्पादन क्षमता) में I-s से थोड़ी कम ही वृद्धि होगी जिसे $I\sigma$ के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ σ से आशय विनियोग की औसत उत्पादकता (Average Productivity and Investment) अथवा सामाजिक क्षमता (Social Potential) है। सूत्र रूप में इसे निम्नानुसार व्यक्त किया जा सकता है—

$$\sigma = \frac{\Delta Y}{I}$$

इस प्रकार, $1\sigma < I - s$

$I\sigma$ अर्थव्यवस्था का उत्पादन में समग्र विशुद्ध सम्भावित वृद्धि (Total Net Potential Increase in Output) है। इसे सिग्मा प्रभाव (Sigma Effect) कहा जाता है।

कुल माँग में अपेक्षित वृद्धि (Required Increase in Aggregate Demand)—डोमर ने माँग का विश्लेषण कीन्स के गुणक के द्वारा किया है—

मान लीजिए कि—

ΔY = आय में वार्षिक वृद्धि

ΔI = विनियोग में वृद्धि

तथा

$$\propto = \frac{\Delta s}{\Delta Y} = \text{सीमान्त बचत प्रवृत्ति}$$

तब आय में वृद्धि = विनियोग में वृद्धि के गुणक के $\left(\frac{1}{\propto}\right)$ गुणा होगी।

आय में वृद्धि के विनियोग में वृद्धि के गुणक के $\left(\frac{1}{\alpha}\right)$ गुणा वृद्धि का कारण यह है कि α = सीमान्त बचत प्रवृत्ति

तथा $$\frac{1}{\alpha} = \frac{1}{(1 - \text{MPC})}$$

अत: $$\Delta Y = \Delta I \frac{1}{\alpha}$$

साम्यावस्था (Equilibrium)

आय का पूर्ण रोजगार सन्तुलन स्तर पर बने रहने के लिए यह आवश्यक है कि कुल माँग, कुल पूर्ति के बराबर हो। डोमर का आधारभूत समीकरण निम्नानुसार है—

$$\Delta I = \frac{1}{\alpha} = 1\sigma$$

दोनों पक्षों को I से विभाजित किया जाये तथा α से गुणा, तब—

$$\Delta I \times \frac{1}{\alpha} \times \frac{1}{I} \times \alpha = I\sigma \times \frac{1}{I} \times \alpha$$

अथवा $$\frac{\Delta \text{I}}{\text{I}} = \alpha\,\sigma$$

यदि दोनों पक्षों को $\frac{I}{\alpha}$ से गुणा किया जाये, तब

$$\frac{\Delta I}{I} \times \frac{I}{\alpha} = \alpha\,\sigma \times \frac{I}{\alpha} \quad \text{अथवा} \quad \Delta \frac{1}{\alpha} = I\sigma$$

किन्तु $$1\sigma = \Delta I \frac{I}{\alpha} \quad \text{तथा} \quad \Delta I \frac{I}{\alpha} = \Delta Y$$

अत: $$1\sigma = \Delta Y$$

उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि पूर्ण रोजगार स्तर को बनाये रखने के लिए यह जरूरी है कि—

$$\frac{\Delta I}{I} = \alpha\,\sigma$$

जबकि $\frac{\Delta I}{I}$ विशुद्ध स्वतन्त्र (Autonomous) विनियोग की दर है और $\alpha\,\sigma$ सीमान्त बचत प्रवृत्ति (α) और विनियोग की उत्पादक (σ) का गुणनफल है। अत: पूर्ण रोजगार स्तर सभी कायम रह सकता है। जबकि $\frac{\Delta I}{I}$ (शुद्ध स्वतन्त्र विनियोग की दर) $\alpha\,\sigma$ के बराबर हो। $\alpha\,\sigma$ सीमान्त बचत प्रवृत्ति (α) तथा विनियोग की उत्पादकता (σ) का गुणनफल है। डोमर ने अपने मॉडल को निम्न संख्यात्मक उदाहरण द्वारा व्यक्त किया है।

मान लीजिए कि,

उत्पादन क्षमता (σ) = 25% प्रति वर्ष

सीमान्त बचत प्रवृत्ति (α) = 25% प्रति वर्ष

आय (Y) = 150 बिलियन प्रति वर्ष।

पूर्ण रोजगार स्तर को बनाये रखने के लिए आवश्यक विनियोग = $\frac{150 \times 12}{100}$ = 18 बिलियन डॉलर विनियोग आवश्यक है।

परिणामस्वरूप इससे उत्पादन क्षमता में विनियोजित मात्रा की σ गुना वृद्धि होगी अर्थात् $150 \times \frac{12}{100} \times \frac{12}{100} = 4.5$ बिलियन डॉलर।

TOUCH 'n' PASS

5. **संरचनात्मक बेरोजगारी** (Structural Unemployment)—**प्रो० कुरिहारा** के मतानुसार, यह मॉडल पूँजी के पूर्ण उपयोग (Use) का तो दावा करता है किन्तु श्रम के पूर्ण रोजगार (Full Employmnt of Labour) का नहीं। हैरोड—डोमर द्वारा समझायी गयी विकास की दर प्रभावपूर्ण माँग की कमी से उत्पन्न होने वाली माँग की समस्या का ही निदान प्रस्तुत कर सकती है। अर्द्धविकसित देशों की संरचनात्मक बेरोजगारी (Structural Unemployment) की समस्या का निदान केवल प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि करने मात्र से ही कर सकना सम्भव नहीं है। वास्तव में, संरचनात्मक बेरोजगारी की समस्या के उदय का प्रमुख कारण यह है कि जिस दर से जनसंख्या में वृद्धि होती है, उस दर से पूँजी संचय में वृद्धि नहीं होती है।
6. **निम्न पूँजी उत्पादन अनुपात** (Low Capital-Output Ratio)—अर्द्धविकसित देशों में दुर्लभताओं और अड़चनों के कारण सामान्य उत्पादकता आमतौर पर अवरुद्ध हो जाती है जिससे पूँजी उत्पादन अनुपात का सही-सही अनुमान लगा सकना सम्भव नहीं होता है। यदि इन अवरोधों को दूर कर दिया जाता है, तब पूर्व में विनियोजित पूँजी की उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती हैं। जिससे पूँजी उत्पादन अनुपात निम्न होता है इस कारण से इस तरह की अर्थव्यवस्थाओं को अपनी उत्पादन विधियों में सुधार कर और विनियोग की विभिन्न बाधाओं को दूर कर अपने बचत अनुपात को बढ़ाना पड़ेगा। अथवा पूँजी-उत्पादन अनुपात को बढ़ाना जरूरी होगा। **प्रो० हर्षमैन** के मतानुसार, बचत-प्रवृत्ति तथा पूँजी-उत्पादन अनुपात पर आधारित मॉडल का "पूर्वसूचक तथा व्यवहार-योग्य मूल्य (Predictive and Operational Value) बहुत ही कम होता है। क्या विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अर्द्धविकसित अर्थव्यवस्थाओं में उपयोगिता भी कम होती है।
7. **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** (Foreign Trade)—यह मॉडल बन्द अर्थव्यवस्था की मान्यता पर आधारित है। किन्तु अर्द्धविकसित अर्थव्यवस्थाएँ बन्द अर्थव्यवस्थाएँ नहीं वरन खुली अर्थव्यवस्थाएँ हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी सहायता का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है।
8. **संस्थागत परिवर्तन** (Institutional Changes)—इन विकास मॉडलों में संस्थागत तत्त्वों को स्थिर मान लिया जाता है लेकिन संस्थागत परिवर्तनों के अभाव में अर्द्धविकसित देशों का विकास सम्भव ही नहीं है।
9. **मूल्यों में परिवर्तन** (Price Changes)—इसमें मान लिया जाता है कि मूल्यों में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है लेकिन अर्द्धविकसित देशों में आर्थिक विकास के साथ मूल्यों में बदलाव हो जाता है।

एच. डब्ल्यू. सिंगर (H.W. Singer) के अनुसार हैरोड-डोमर का मॉडल विकसित देशों के लिए "आशावादी-मॉडल' है किन्तु अर्द्धविकसित देशों के लिए इस मॉडल में निराशावादी विचार ही सामने आते हैं। इस तरह अर्द्धविकसित देशों के लिए इस मॉडल की व्यवहारिकता नहीं के बराबर है। क्योंकि यह अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. लेविस के अनुसार, अल्पविकसित देशों में विकास की कुँजी हैं—

(क) प्रचलित मजदूरी की दर में वृद्धि (ख) पूँजी निर्माण की दर में वृद्धि
(ग) अवसंरचना का विकास (घ) ये सभी

उत्तर (ख) पूँजी निर्माण की दर में वृद्धि

प्र.2. रोजोन्स्टीन रोडन के अनुसार अर्थव्यवस्था के विकास की सर्वोत्तम विधि है—

(क) अर्थव्यवस्था को जान-बूझकर असन्तुलित करना।
(ख) व्यापक सामाजिक विकास
(ग) निवेश का एक वृहद एवं सन्तुलित कार्यक्रम
(घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर (ख) व्यापक सामाजिक विकास

TOUCH 'n PASS

प्र.3. प्रबल प्रयास के सिद्धान्त का औचित्य किसके विचार पर निर्भर करता हैं?
(क) आन्तरिक मितव्ययिता (ख) बाह्य मितव्ययिता
(ग) जनसंख्या का आकार (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (ख) बाह्य मितव्ययिता

प्र.4. अर्थशास्त्रियों और उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा सही सुमेलित हैं?
(क) ए०डब्ल्यू० लिविस — बिग पुश सिद्धान्त
(ख) ए०आर० हर्शमैन — असन्तुलित संवृद्धि की रणनीति
(ग) रोजोन्स्टीन रोडन — आर्थिक संवृद्धि की अवस्थाएँ
(घ) डब्ल्यू० डब्ल्यू० रोस्टेव — श्रम की असीमित पूर्ति के साथ विकास
उत्तर (ख) ए०आर० हर्शमैन — असन्तुलित संवृद्धि की रणनीति

प्र.5. प्रबल-प्रयास का सिद्धान्त निम्न विकास में से किस धारणा पर आधारित हैं?
(क) जनसंख्या (ख) ब्राह्य बचतें (ग) आन्तरिक बचतें (घ) पूँजी निर्माण
उत्तर (घ) पूँजी निर्माण

प्र.6. वित्तीय द्वैतवाद सिद्धान्त के प्रतिपादक हैं–
(क) बैन्जामिन हिंगिन्स (ख) प्रो० मिण्ट (ग) प्रो० बाल्डविन (घ) प्रो० शुम्पीटर
उत्तर (ख) प्रो० मिण्ट

प्र.7. औद्योगिक द्वैतवाद के सिद्धान्त की मान्यताएँ हैं–
(क) दो वस्तु है (ख) दो उत्पादन साधन है
(ग) दो क्षेत्र है (घ) ये सभी
उत्तर (घ) ये सभी

प्र.8. द्वैत अर्थव्यवस्था का मॉडल दिया–
(क) आर०एफ० हैरोड ने (ख) आर०एम० सोलो ने
(ग) ए०के०सेन ने (घ) डब्ल्यू०ए० लेविस ने
उत्तर (घ) डब्ल्यू०ए० लेविस ने

प्र.9. बिग पुश सिद्धान्त के अनुसार, छोटे-छोटे विकास के कार्यक्रम एक बड़े विकास का रूप नहीं ले सकते—
(क) सही (ख) गलत (ग) अनिश्चित (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (क) सही

प्र.10. किस अर्थशास्त्री का सम्बन्ध बड़े धक्के की विचारधारा से है?
(क) नेल्सन (ख) रोजोन्स्टीन रोडन (ग) होर्व लीबिस्टीन (घ) नर्क्से
उत्तर (ख) रोजोन्स्टीन रोडन

प्र.11. क्रान्तिक न्यूनतम प्रयास सिद्धान्त किसने दिया था?
(क) एच० लीस्टीन (ख) रोजोन्स्टीन रोडन (ग) डब्ल्यू०ए० लेविस (घ) जे०एच० बोएक
उत्तर (क) एच० लीस्टीन

प्र.12. प्रति व्यक्ति आय के निम्न साम्य स्तर पर—
(क) बचत एवं शुद्ध निवेश की दर निम्न स्तर पर बनी रहती है।
(ख) उद्यमिता क्षमता में वृद्धि होती है।
(ग) औद्योगिक विकास की दर तीव्र होती है।
(घ) उपरोक्त सभी सत्य है।
उत्तर (क) बचत एवं शुद्ध निवेश की दर निम्न स्तर पर बनी रहती है।

TOUCH 'n PASS

प्र.13. नेल्सन के अनुसार आयन फलन है—
(क) पूँजी स्टॉक का (ख) तकनीकी स्तर का
(ग) जनसंख्या के आकार का (घ) इन सभी का
उत्तर (घ) इन सभी का

प्र.14. नेल्सन के अनुसार एक बार प्रति व्यक्ति आय के जीवन निर्वाह स्तर से उच्च हो जाने पर–
(क) मृत्यु दर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा (ख) मृत्युदर पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा
(ग) मृत्युदर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा (घ) सभी सत्य है।
उत्तर (ख) मृत्युदर पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा

प्र.15. लीबीन्स्टीन के ही समान विचार निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दिये?
(क) हर्षमैन (ख) रोजोन्स्टीन (ग) रोस्टोव (घ) नेल्सन
उत्तर (क) हर्षमैन

प्र.16. *इकॉनामिक वैकवर्डमैन एण्ड इकॉनामिक ग्रोथ* के लेखक हैं?
(क) एच० लीबीन्स्टीन (ख) नैल्सन (ग) मायर (घ) हिगिन्स
उत्तर (ख) नैल्सन

प्र.17. सन्तुलित विकास सिद्धान्त के अनुसार कम विकास का मुख्य कारण हैं—
(क) बाजार का लघु आकार (ख) तकनीकी का निम्न स्तर
(ग) बचत की कमी (घ) विदेशी प्रभुत्व
उत्तर (क) बाजार का लघु आकार

प्र.18. असन्तुलित विकास की रणनीति का परामर्श दिया–
(क) रेग्नर नर्क्स ने (ख) ए०ओ० हिर्षमैन ने (ग) रोजोन्स्टीन रोडन ने (घ) एन० काल्डार ने
उत्तर (ख) ए०ओ० हिर्षमैन ने

प्र.19. असन्तुलित विकास प्राक्कथन इस मान्यता पर बनाया गया है कि—
(क) विस्तार विभिन्न दिशाओं में एक साथ होता है।
(ख) पूँजी और श्रम की पूर्ति स्थिर है।
(ग) श्रम और पूँजी की पूर्ति असीमित है।
(घ) विकासशील देश विकास दर की उच्चतम सीमा रखते है।
उत्तर (घ) विकासशील देश विकास दर की उच्चतम सीमा रखते है।

प्र.20. लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था के विकास की सर्वोत्तम विधि है—
(क) अर्थव्यवस्था को जान-बूझकर असंतुलित करना (ख) व्यापक सामाजिक विकास
(ग) निवेश का एक वृहद एवं संतुलित कार्यक्रम (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (ख) व्यापक सामाजिक विकास

प्र.21. नेल्सन के अनुसार आय फलन है—
(क) पूँजी स्टॉक का (ख) तकनीकी स्तर का
(ग) जनसंख्या के आकार का (घ) इन सभी का
उत्तर (घ) इन सभी का

TOUCH 'n' PASS

UNIT-IV

जनसंख्या एवं आर्थिक विकास
Population and Economic Growth

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. समावेशी विकास का क्या अर्थ है?

What is meaning of inclusive development?

उत्तर समावेशी विकास का अर्थ ऐसे विकास से लिया जाता है जिसमें रोजगार के अवसर पैदा हों और जो गरीबी को कम करने में मददगार साबित हो। इसमें अवसर की समानता प्रदान करना तथा शिक्षा व कौशल के लिए लोगों को सशक्त करना शामिल है, अर्थात् अवसरों की समानता के साथ विकास को बढ़ावा देना।

प्र.2. समावेशन की अवधारणा क्या है?

What is the concept of inclusive?

उत्तर समावेशन एक छत्र शब्द है जो सभी छात्रों को उनकी सामाजिक पहचान के बावजूद, उनकी भिन्नताओं और अक्षमताओं की परवाह किए बिना, शैक्षिक प्रणाली में प्रत्येक श्रेणी के बच्चों को शामिल करने के लिए संदर्भित करता है यह विविधता को महत्त्व देता है और सभी को सीखने और बढ़ने के समान अवसर प्रदान करता है।

प्र.3. समावेशी विकास के प्रमुख सिद्धान्त क्या हैं?

What are teh main principles of inclusive development?

उत्तर (i) अन्तर्निहित गरिमा, व्यक्तिगत स्वायत्तता के लिए सम्मान, जिसमें अपनी पसन्द बनाने का अधिकार और व्यक्तियों की स्वतन्त्रता शामिल है। (ii) गैर-भेदभाव, (iii) समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी तथा समावेशन।

प्र.4. जनसांख्यिकीय सिद्धान्त क्या है?

What is the demographic theory?

उत्तर जनसांख्यिकी सिद्धान्त आबादी को विश्लेषणात्मक गतिशील प्रणालियों के रूप में वर्णित करने से सम्बन्धित है। कैसे और क्यों आबादी बदलती है में अनुभवजन्य पैटर्न खोजने के लिए।

प्र.5. जनांकिकीय संक्रमण की तीन अवस्थाओं की विवेचना कीजिए।

Discuss the three stages of demographic transition?

उत्तर यह किसी भी क्षेत्र की भविष्य की जनसंख्या कैसी और कितनी होगी, इसका वर्णन और भविष्यवाणी करता है। यह हमें बताता है कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या समय के साथ उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में बदल जाती है।

प्र.6. जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धान्त किसने दिया था?

Who gave the transition theory of demography?

उत्तर 1944-45 में, फ्रैंक नोटस्टीन और किंग्सले डेविस ने जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धान्त को उस रूप में प्रस्तुत किया जो लगभग सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत हो गया। यह माना जाता था कि सभी समाज, पूर्व औद्योगिक से उत्तर-औद्योगिक जनसांख्यिकीय सन्तुलन तक, तीन चरणों से गुजरेंगे।

TOUCH 'n' PASS

प्र.7. जनांकिकी की विशेषता क्या है?
What is the characteristics of demography?

उत्तर भारत की प्रमुख जनांकिकीय विशेषताएँ निम्न हैं—
(i) इस समय भारत से अधिक जनसंख्या केवल चीन में है। (ii) भारतीय जनसंख्या में विभिन्न धर्मों और सम्प्रदायों से सम्बन्धित लोगों का समावेश है। अनेक जनजातियों के लोग परिवार नियोजन में विश्वास नहीं करते। (iii) भारत में आज भी लगभग 72 प्रतिशत लोग गाँवों में निवास करते हैं।

प्र.8. जनसांख्यिकीय का उद्देश्य क्या है?
What is the purpose of demography?

उत्तर जनसांख्यिकीय जानकारी आपको दर्शकों की कुछ पृष्ठभूमि विशेषताओं को बेहतर ढंग से समझने की अनुमति देती है, चाहे वह उनकी उम्र, जाति, जातीयता, आय, कार्य की स्थिति, वैवाहित स्थिति आदि हो।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक है?
How is population Growth helpful in economic development?

उत्तर

जनसंख्या वृद्धि : आर्थिक विकास में सहायक
(Population Growth : Helpful in Economic Development)

जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है। इस सम्बन्ध में निम्न तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं—

1. **श्रमशक्ति आपूर्ति का स्रोत**—आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधनों, पूँजी की मात्रा, तकनीकी ज्ञान और श्रमशक्ति (Labour Power) पर निर्भर करता है। आर्थिक विकास के निर्धारक घटकों में श्रमशक्ति सबसे महत्त्वपूर्ण एवं सक्रिय घटक हैं। इस सम्बन्ध में **साइमन कुजनेट्स** का कथन है कि, "अन्य बातों के यथावत रहने पर जनसंख्या की प्रत्येक वृद्धि श्रमशक्ति को बढ़ाती है।
   हाँ, इसका श्रमशक्ति हेतु निश्चित योगदान इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या जनसंख्या वृद्धि मृत्यु दर गिरने के कारण अथवा शुद्ध देशान्तरण के कारण या जन्म दर में वृद्धि के फलस्वरूप हुई है। इस प्रकार, कार्यकारी श्रमशक्ति की पूर्ति के स्रोत के रूप में जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास की उत्प्रेरक है और अन्ततः इसका प्रभाव उत्पादन की मात्रा को बढ़ावा देने वाला होता है।
2. **विस्तृत बाजार**—जनसंख्या वृद्धि उपभोक्ताओं के रूप में वस्तुओं के लिए माँग (Demand) पैदा करती है जिससे बाजारों का विस्तार होता है। इससे उत्पादन के स्वरूप में विविधता (Variation) आती है। उत्पादन बढ़ने से रोजगार (Employment) के अवसर एवं आय में वृद्धि होती है। इस तरह, जनसंख्या वृद्धि बाजार का विस्तार कर आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है।
3. **उत्पादन में वृद्धि**—जनसंख्या बढ़ने से श्रम शक्ति एवं विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलता है जिससे श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होती है जो अन्ततः उत्पादन को बढ़ाती है। **डॉ० ब्राइट सिंह** का मत है कि, "जनसंख्या वृद्धि गहन श्रम विभाजन तथा व्यापक विशिष्टीकरण को जन्म देती है, पैमाने की बचतों को सम्भव बनाती है, जिससे तकनीकी प्रगति तथा संगठनात्मक सुधारों को बढ़ावा मिलता है।" लेकिन जनसंख्या वृद्धि से उत्पादन मात्रा में तभी वृद्धि सम्भव है जब जनसंख्या को आकार देश में उपलब्ध पूँजी और भूमि की तुलना में छोटा रहता है।
4. **दक्षता एवं निपुणता को बढ़ावा**—नए ज्ञान की खोज एवं उसका विकास कर दक्षता एवं निपुणता को बढ़ावा देना मानव का स्वभाव है, जो स्वयं जनसंख्या का परिणाम है। इस प्रकार, वृद्धिशील जनसंख्या सृजनात्मक मस्तिष्कों का सृजन करती है, जिससे कौशल को बढ़ावा मिलता है। नए ज्ञान का भण्डार बढ़ता है, जिससे राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होने लगती है।
5. **मानव पूँजी निर्माण में सहायक**—जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप उपलब्ध अतिरिक्त श्रमशक्ति पूँजी निर्माण का एक सुलभ साधन माना जाता है। **रैगनर नर्क्स** का मत है कि अतिरिक्त श्रम शक्ति एक तरह की अदृश्य बचत है और अर्द्ध-बेरोजगारी के रूप में इन अदृश्य सम्भाव्य बचतों के पूँजी-निर्माण के लिए प्रयोग की जा सकती हैं।

TOUCH 'n' PASS

जब देश में उपलब्ध जनशक्ति के ज्ञान में वृद्धि करके उसकी कार्यकुशलता एवं योग्यता में सुधार किया जाता है जब मानव पूँजी का निर्माण होता है जिसका अन्तिम प्रभाव यह होता है कि देश में प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ता है और देश का आर्थिक विकास होता है। **डॉ० कैन्ड्रिक** का कथन है कि, "श्रम उत्पादकता में वृद्धि, औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक विकास की एक पूर्व शर्त रही है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण अमेरिका तथा जापान का द्रुतगामी विकास है जो पूरी तरह से श्रम की उत्पादकता में वृद्धि के कारण ही हो सका है।"

प्र.2. आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावों का उल्लेख कीजिए।
Explain the effects of economic development on population growth.

उत्तर

आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव
(Effect of Economic Development on Population Growth)

किसी देश के आर्थिक विकास का उस देश की जनसंख्या वृद्धि पर जो प्रभाव पड़ता है उसे जनांकिकीय संक्रमण सिद्धान्त द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धान्त के अनुसार आर्थिक विकास के दौरान किसी देश की जनसंख्या को निम्नलिखित पाँच अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है—

1. **प्रथम अवस्था** (First Stage)—इस अवस्था में लोगों का सामाजिक व आर्थिक दृष्टिकोण संकुचित होता है। सन्तुलित भोजन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव होता है। अतएव मृत्यु दर, विशेषकर शिशु मृत्यु दर ऊँची रहती है। व्यापक निरक्षरता, परिवार नियोजन के ज्ञान का अभाव, छोटी आयु में विवाह, बच्चों के प्रति लगाव, आदि के जन्म दर ऊँची होती है। इस अवस्था में आय का प्रमुख स्रोत कृषि क्षेत्र होता है बच्चों के पालन-पोषण पर व्यय बहुत कम होता है। वे बहुत कम आयु में ही परिवार की आय का स्त्रोत हो जाते हैं जिससे बच्चे दायित्व न होकर सम्पत्ति समझे जाते हैं। ऐसे आदिमकालीन समाज में जनसंख्या वृद्धि दर, वास्तव में ऊँची नहीं होती क्योंकि उच्च जन्म दर को उच्च मृत्यु दर सन्तुलित कर देती है। यह अवस्था 'ऊँची जन-वृद्धि की सम्भाव्य अवस्था' (High Population Growth Potential Stage) हैं, अर्थात् इसमें वास्तविक वृद्धि तो कम होती हैं किन्तु जन-वृद्धि की पर्याप्त क्षमता पायी जाती है।
2. **द्वितीय अवस्था** (Second Stage)—इस अवस्था में आर्थिक क्रियाओं का विस्तार होता है आय में वृद्धि होने लगती है। बैंक, बीमा, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं का क्षेत्र व्यापक हो जाता है। फलस्वरूप मृत्युदर में गिरावट आ जाती है और जन्मदर या तो स्थिर रहती है अथवा उसमें मामूली गिरावट आ पाती है। जन्मदर को प्रभावित करने वाली धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में बदलाव नहीं होता। इस तरह, द्वितीय अवस्था में जन्म दर ऊँची और मृत्यु दर नीची रहती हैं, जिससे जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होती है। इसे जनसंख्या विस्फोट की अवस्था भी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से यह स्थिति घातक होती है। मृत्यु दर में कमी और जन्मदर में वृद्धि के कारण देश में जनाधिक्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिससे जीवन स्तर को उन्नत बनाने के सभी प्रयास निरर्थक सिद्ध होने लगते हैं और आर्थिक विकास के बावजूद, आर्थिक स्थिरता की दशा उत्पन्न हो जाती है।
3. **तृतीय अवस्था** (Third Stage)—इस अवस्था में आर्थिक विकास की गति और अधिक तीव्र हो जाती है। शिक्षा और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं में और अधिक सुधार होता है, जिसके परिणामस्वरूप मृत्युदर में और अधिक गिरावट आती है। शिक्षा के प्रसार एवं आर्थिक विकास के फलस्वरूप सामाजिक दृष्टिकोण (Outlook) बदलते हैं। छोटे परिवार को वरीयता दी जाने लगती है, परिवार नियोजन ऐच्छिक रूप ले लेता है, जिसके कारण जन्मदर गिरने लगती है। परन्तु इस अवस्था में भी जन्मदर एवं मृत्युदर में अन्तर बहुत अधिक होता है जिससे जनसंख्या की शुद्ध वृद्धि दर अधिक होती है। यह अवस्था भी जनसंख्या विस्फोट (Population Expoltion) की ही अवस्था है।

प्र.3. जनांकिकीय संक्रमण सिद्धान्त एवं जनसंख्या की अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए।
Mention the demographic transition theory and stages of population.

उत्तर

जनांकिकीय संक्रमण सिद्धान्त : जनसंख्या की अवस्थाएँ
(Demographic Transition Theory : State of Population)

यह जनसंख्या के विकास का आधुनिकतम सिद्धान्त है जिसे विश्व के अधिकांश अर्थशास्त्रियों व जनसंख्या शास्त्रियों का समर्थन मिला है। यह सिद्धान्त यूरोप के अनेक देशों के आँकड़ों पर अवलम्बित है। यह सरल है, तर्कसंगत है और सभी सिद्धान्तों में

TOUCH 'n' PASS

सर्वाधिक वैज्ञानिक प्रतीत होता है। वर्तमान जनसंख्या शास्त्रियों का मत है कि प्रत्येक समाज की जनसंख्या को अनेक अवस्थाओं से गुजरना होता है। प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएँ होती हैं। विश्व का कोई देश प्रथम अवस्था में है तो कोई द्वितीय, और कोई तृतीय अवस्था में। इन तीनों अवस्थाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न है—

प्रथम अवस्था यह अवस्था पिछड़े देशों में होती है। जहाँ जन्मदर भी ऊँची है तथा मृत्यु-दर भी ऊँची है। कृषि, आय का प्रमुख स्रोत है—ग्रामीण अर्थव्यवस्था। द्वितीयक उद्योग या तो हैं ही नहीं, यदि हैं तो बहुत छोटे पैमाने पर। तृतीयक उद्योग (Tertiary Sector) जैसे—बीमा, बैंक आदि नहीं होते हैं। प्रति व्यक्ति आय कम है अत: बच्चे आय बढ़ाने के स्रोत होने के कारण दायित्व नहीं वरन् पूँजी है। कृषि में प्रत्येक उम्र के बच्चे के लिए काम निकल आता है। इसलिए छोटा बच्चा भी आय का स्रोत होता है। बच्चों के विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की कोई महत्त्वकांक्षा ही नहीं होती, अतएव उनमें व्यय नहीं होता है। संयुक्त परिवार-व्यवस्था होती है, अत: लालन-पालन की कोई समस्या नहीं होती है। इन्हीं सब कारणों से प्रथम अवस्था में जन्मदर ऊँची होती है तथा मृत्युदर भी ऊँची होती है।

प्रथम चरण में बड़े परिवार के अनेक आर्थिक लाभ भी होते हैं **ए०जे० कोल** एवं **इ०एम० हूवर** ने लिखा है—

"Children contribute at an early age.....And are traditional source of security in the old age of parents. The prevalent high death rates especially in infancy imply that such security can be attained only when many children are born."

द्वितीय अवस्था द्वितीय चरण में अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होती है। कृषि के साथ उद्योग भी बढ़ने लगते हैं। परिवहन एवं शहरीकरण होने से गतिशीलता (Movability) बढ़ती है। शिक्षा का विस्तार, आय में वृद्धि, भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा में सुधार होने से मृत्यु-दर घटती है। किन्तु धर्मान्धता (Bigotry), रीति-रिवाज व रूढ़िवादिता (Conservatism) के बन्धन ढीले नहीं होते हैं। अतएव जन्म-दर नहीं घटती है और जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आ जाती है।

तृतीय अवस्था में जीवन-स्तर सुधार, मानसिक विकास, नारी-शिक्षा, नारी रोजगार में वृद्धि तथा महिलाओं में जागृति आती हैं। परिणामस्वरूप महिलाएँ कम बच्चे पसन्द करने लगती हैं, सारे जीवन भर बच्चे खिलाने की अपेक्षा वे अन्य क्षेत्रों में सहयोग करना चाहती हैं, बच्चों की शिक्षा-दीक्षा अच्छी तरह करने की होड़ होने लगती है। शहरीकरण से आर्थिक कशमकश बढ़ती है, साधन कम पड़ने लगते हैं। परिवार नियोजन की विधियाँ विकसित होती हैं। विवाह की आयु बढ़ने लगती है इसलिए प्रजनन आयु-वर्ग का विस्तार घटने लगता है अतएव दिखावा प्रभाव (Demonstration effect) अत्यन्त प्रभावशील होता है। अत: जन्मदर घटने लगती है। प्रो० ए०जे० कोल ने निम्न वाक्यों में स्पष्ट किया है कि आर्थिक विकास किस प्रकार छोटे परिवार के प्रति लोगों को प्रेरित करता है—

"With the development of economic roles for women outside the home, tends to increase the possibility of economic mobility that can better be achieved with small families, and tends to decrease the economic advantages of a large family. One of the features of economic development is typically increase urbanisation and children are usually more of a burden and less of an assetin an urban setting than in a rural."

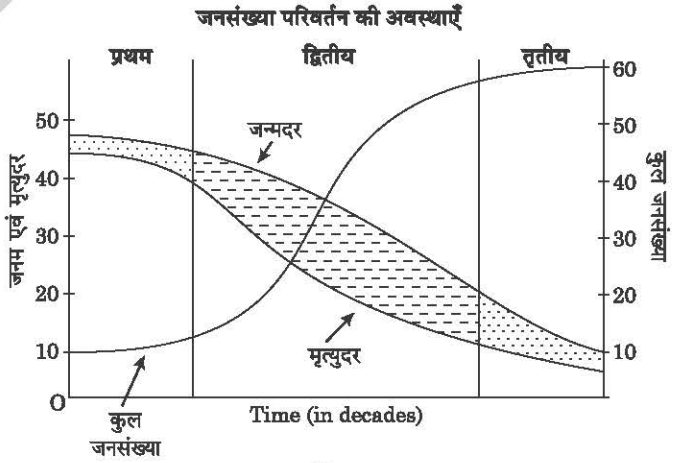

चित्र 1

विश्व के सभी देश इन्हीं तीन प्रमुख अवस्थाओं से गुजर रहे हैं अथवा गुजर चुके हैं। अफ्रीका के कुछ देश प्रथमावस्था में हैं, एशिया शिया से कुछ द्वितीय अवस्था में हैं, और यूरोपीय देश तृतीय अवस्था में हैं। निम्न चित्र में इन तीनों अवस्थाओं का निरूपण किया गया है—

उपर्युक्त चित्र में ऐसी तीनों अवस्थाओं को प्रदर्शित किया गया है। प्रथम अवस्था में जन्मदर करीब 46 या 48 प्रति हजार है। किन्तु मृत्युदर भी इसके करीब-करीब बराबर होती है। अत: जनसंख्या बहुत धीरे-धीरे बढ़ती है।

TOUCH 'n' PASS

प्र.4. जनांकिकी संक्रमण सिद्धान्त की आलोचनाएँ लिखिए।
Write the criticism of theory.

उत्तर

जनांकिकी संक्रमण सिद्धान्त की आलोचनाएँ
(Criticism of Demographic Transition Theory)

जनांकिकी संक्रमण सिद्धान्त की आलोचना निम्नलिखित हैं—

1. यह सिद्धान्त जनसंख्या परिवर्तन के विभिन्न चरणों में कितना समय लगता है, इस बात पर कोई प्रकाश नहीं डालता है।
2. प्रथम अवस्था में जन्मदर तो ऊँचे स्तर पर स्थिर होती है। किन्तु मृत्युदर में प्राकृतिक प्रकोपों के कारण उच्चावचन होते रहते हैं। इसलिए जनसंख्या वृद्धि प्रथम अवस्था में भी परिवर्तनशील रहती हैं।
3. यह सिद्धान्त आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों एवं जनांकिकी संक्रमण के चरणों के बीच किसी सम्बन्ध की चर्चा नहीं करता है। जबकि प्रो० लाइबेन्स्टिन की धारणा है कि आर्थिक विकास के चरण और जनांकिकी संक्रमण की अवस्था साथ-साथ चलती है।
4. यह सिद्धान्त प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण की व्याख्या (Explanation) तो करता है किन्तु चतुर्थ चरण के विषय में विद्वानों में मतभेद हैं, कुछ विद्वानों की धारणा है कि जनसंख्या चतुर्थ चरण में बढ़ती है तथा कुछ की धारणा है कि यह स्थिर रहती है।
5. आर्थिक विकास एवं जनांकिकी संक्रमण दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। केवल विकास के कारण संक्रमण नहीं होता है। वरन् संक्रमण के कारण भी विकास होता है।
6. इस सिद्धान्त की पुष्टि आँकड़ों के आधार पर नहीं की जा सकती है। इसलिए यह सांख्यिकी विश्लेषण के लिए अयोग्य हैं।

प्र.5. संजनांकिकी क्रमण सिद्धान्त का मूल्यांकन कीजिए।
State the evaluation of transition theory.

उत्तर

संक्रमण सिद्धान्त का मूल्यांकन
(Evaluation of Analysis Transition Theory)

जनसंख्या के संक्रमण सिद्धान्त की विवेचना एवं विश्लेषण (Analysis) से यह स्पष्ट होता है कि यह सिद्धान्त जनसंख्या वृद्धि का एक सर्वमान्य, व्यावहारिक, यथार्थवादी एवं वैज्ञानिक सिद्धान्त है। यह सिद्धान्त उन सब साधनों जैसे सामाजिक, आर्थिक, संस्थागत एवं जैविकीय पर विचार करता है जो जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावित करते हैं। यह सिद्धान्त माल्थस के सिद्धान्त से श्रेष्ठ है क्योंकि यह खाद्यपूर्ति पर जोर नहीं देता और न ही निराशावादी दृष्टिकोण अपनाता है। यह अनुकूलतम सिद्धान्त से भी श्रेष्ठ हैं जो जनसंख्या वृद्धि के लिए एकमात्र प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पर बल देता है और जनसंख्या को प्रभावित करने वाले अन्य साधनों की उपेक्षा कर जाता है। जैविकीय सिद्धान्त भी एकांगी है। जनसंख्या सिद्धान्तों में जनांकिकीय संक्रमण सिद्धान्त इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि यह यूरोप के विकसित देशों की जनसंख्या वृद्धि की वास्तविक प्रवृत्तियों पर आधारित है। यह सिद्धान्त देशों के साथ-साथ विकासशील देशों पर समान रूप से लागू होता है। अफ्रीका महाद्वीप के कुछ बहुत पिछड़े देश अभी भी प्रथम अवस्था में हैं और विश्व के अन्य विकासशील देश दूसरी अवस्था में हैं। यूरोप के लगभग सभी देश प्रथम दो अवस्थाओं से गुजरकर तीसरी अवस्था एवं चौथी अवस्था में पहुँच चुके हैं। इस तरह यह सिद्धान्त व्यावहारिक रूप से पूरी दुनिया में लागू होता हैं। इसी सिद्धान्त के आधार पर अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक जनांकिकीय मॉडलों (Economic Demographic Models) का विकास किया है, जिससे विकासशील देश अन्तिम अवस्था में पहुँचे और आत्मनिर्भर बन सकें। इसी तरह का एक मॉडल कोल-हूवर मॉडल (Coole-Hoover Model) भारत के लिए बनाया गया है, जो दूसरे विकासशील देशों पर भी लागू किया जा रहा है।

जनांकिकीय संक्रमण सिद्धान्त की विकासशील देशों के लिए सार्थकता पर कुछ विद्वानों ने प्रश्न चिन्ह भी लगाए हैं और यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है, कि जिन सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों से विकसित देश गुजर चुके हैं वे आज के विकासशील देशों की परिस्थितियों से भिन्न हैं।

फिर भी यह कहा जा सकता है कि जनसंख्या विकास के इस सिद्धान्त को अर्थशास्त्रियों एवं जनसंख्याशास्त्रियों का व्यापक समर्थन प्राप्त है। यह सरल, तर्कसंगत एवं जनसंख्या सिद्धान्तों में सर्वाधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला है।

TOUCH 'n PASS

प्र.6. भारत में समावेशी विकास की क्या आवश्यकता है? बताइए?
What is the need of inclusive development in India?

उत्तर

भारत में समावेशी विकास की आवश्यकता
(Need of Inclusive Development in India)

समावेशी विकास सतत् विकास, धन और समृद्धि के समान वितरण के लिए आवश्यक है। समावेशी विकास हासिल करना भारत जैसे देश में सबसे बड़ी चुनौती है। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 7वाँ और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। फिर भी, भारत अपने पड़ोसी चीन के विकास से बहुत दूर है। इसी तरह, पूरे देश के लिए 8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि की उपलब्धि एक प्रमुख कारक है, जो भारत में समावेशी विकास को महत्त्व देता है। इसी तरह, कम कृषि विकास, कम गुणवत्ता वाले रोजगार विकास, कम मानव विकास, ग्रामीण–शहरी विभाजन, लिंग और सामाजिक असमानता, और क्षेत्रीय असमानता आदि के मामले में बहिष्कार राष्ट्र के लिए समस्याएँ हैं। समावेशी विकास के लिए गरीबी और अन्य विषमताओं को कम करना और आर्थिक विकास को बढ़ाना देश का सबसे प्रमुख उद्देश्य हैं। भारत में बाल श्रम को कानून द्वारा प्रतिबन्धित किया गया है और इस अमानवीय प्रथा को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। आज भी भारत में कई बच्चे शिक्षा से वंचित हैं क्योंकि उनको जीवन–यापन के लिए श्रम करना पहली प्राथमिकता है। इसके अलावा, साक्षरता के स्तर को उच्च विकास के लिए आवश्यक कुशल कार्यबल प्रदान करने के लिए भारत में समावेशी विकास सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है क्योंकि देश में आर्थिक सुधार पुरानी दार्शनिकता और राजनेताओं और विपक्षी दलों के आरोप–प्रत्यारोपों से अभिभूत हैं। साथ ही, आय, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं और बाल विकास, बुनियादी ढाँचे और पर्यावरण से सम्बन्धित निगरानी योग्य लक्ष्यों की उपलब्धि के खिलाफ समावेशी दृष्टिकोण अपनाना जरूरी हैं। इसके अलावा, भारत में राजनीतिक नेतृत्व देश के समग्र विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन अध्ययनों में पाया गया है कि इस देश के अधिकांश राजनेताओं में वैज्ञानिक साक्षरता का स्तर बहुत निम्न है। विभिन्न अन्य अध्ययनों ने अनुमान लगाया कि भारत में भ्रष्टाचार की लागत जीडीपी के 10 प्रतिशत से अधिक है। भ्रष्टाचार उन बीमारियों में से एक है जो समावेशी विकास को बाधित करता है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, असमानताओं को लेकर चिन्ता व्यक्त की जा रही है और विकास के लिए समावेशी दृष्टिकोण के बारे में भी बात कर रहे हैं। भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश में ग्रामीण भारत में रहने वाले एक–चौथाई लोगों को मुख्यधारा में लाना सबसे बड़ी चिन्ता है। विकास को समाज के सभी वर्गों और देश के सभी हिस्सों में पहुँचाने की चुनौती है। समावेशी विकास प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका विकासशील लोगों को कौशल के माध्यम से प्रशिक्षित करना है। अतएव निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत को वृद्धि और विकास में समावेशी दृष्टिकोण अपनाने की बहुत आवश्यकता है।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. आर्थिक विकास में मानव संसाधन अथवा जनसंख्या के योगदान एवं एल्विन हैन्सेल के विचारों की विवेचना कीजिए।
Discuss the view of Alvin Hansen and role of human resources or population in economic development.

उत्तर

आर्थिक विकास में मानव संसाधन अथवा जनसंख्या का योगदान
(Role of Human Resources or Population in Economic Development)

किसी देश के आर्थिक विकास में मानव संसाधनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ विद्वानों की धारणा है कि आर्थिक विकास के लिए मानव संसाधन प्राकृतिक संसाधनों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित विद्वानों के विचार उल्लेखनीय हैं—

हार्बिन्सन एवं **मायर्स** के अनुसार, "आधुनिक राष्ट्रों का निर्माण मनुष्यों के विकास और मानवीय क्रियाओं के संगठन पर निर्भर करता है। निःसन्देह पूँजी, प्राकृतिक संसाधन, विदेशी सहायता और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं परन्तु इनमें से कोई इतना महत्त्वपूर्ण नहीं जितना मानव शक्ति।"

प्रो० रिचर्ड टी० गिल (R.T. Gill) के अनुसार, "आर्थिक विकास एक यन्त्रीकृत प्रक्रिया नहीं है। यह एक मानव उपक्रम है तथा अन्य समस्त मानवीय उपक्रमों की तरह इसका परिणाम उन व्यक्तियों की योग्यता, गुण एवं दृष्टिकोण पर निर्भर करता है जो इसे अपने हाथों में लेते हैं।"

प्रो० ह्विपल (Whipple) के अनुसार, "एक राष्ट्र की वास्तविक सम्पत्ति उसकी भूमि, जल वनों, खानों, पशु-पक्षियों अथवा डालरों में निहित होती है, बल्कि उस राष्ट्र के समृद्ध तथा प्रसन्नचित पुरुषों, स्त्रियों एवं बच्चों में निहित हैं।"

इस तरह, मानव संसाधन आर्थिक विकास के अन्य संसाधनों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है। आज आर्थिक विकास के नए-नए संसाधनों की खोज, गगनचुम्बी इमारतों और विशालकाय फैक्ट्रियों का निर्माण, पर्वतों का वक्ष छेदन, सागर एवं अन्तरिक्ष विजय, वेगवती नदियों के जल को नियन्त्रित करने वाले, बाँध, पृथ्वी के गर्भ से निकाली गई विशाल खनिज सम्पदा आदि सब मानवीय प्रयासों एवं संकल्प शक्ति की देन हैं।

स्पष्टतया, जनसंख्या आर्थिक विकास को गतिशील (Dynamic) बनाने में सहायक है। जनसंख्या वृद्धि प्रारम्भ में आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव डालती है। इससे श्रमशक्ति में बढ़ोत्तरी होती है जिससे प्राकृतिक संसाधन का उचित विदोहन (Exploration) होने लगता है। देश के कुल उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और देश आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर होता है। जनसंख्या आर्थिक विकास में सहायक है। इस मत को व्यक्त करने वालों में प्रमुख हैं—(प्रो० हेन्सन, आर्थर लुइस, कोलिन क्लार्क तथा ई०एफ० पेनरोज आदि) **प्रो० हेन्सन** के अनुसार, "जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास की एक पूर्व शर्त है।" **प्रो० हर्ष मेन** के अनुसार, "जनसंख्या का दबाव आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है।"

किसी देश की समृद्धि (Prosperity) में वहाँ की जनसंख्या सहायक होती है परन्तु इस तस्वीर का दूसरा रुख भी है। यदि जनसंख्या आर्थिक विकास का एक प्रभावी स्रोत है तो कुछ दशाओं में वह आर्थिक विकास के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधा भी है। जब जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने लगती है तो अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के आदर्श अनुपात से दूर हट जाती है जिससे देश में नई समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है और पूर्व की छोटी-छोटी समस्याएँ वृहद् तथा जटिल हो जाती हैं। इस प्रकार जनसंख्या आर्थिक विकास में सहायक तत्त्व के रूप में होने के स्थान पर बाधक तत्त्व बन जाती हैं। **रिचर्ड गिल** के अनुसार, "जनसंख्या वृद्धि का राष्ट्रीय उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय पर अन्तिम प्रभाव धनात्मक, ऋणात्मक अथवा तटस्थ होगा, यह बात पर निर्भर करेगा कि जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप क्या है और वह किन दशाओं में हो रही है।" यदि उच्च प्रजनन-दर (High Birth Rate) के कारण जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, जिसके कारण देश में आश्रितों की संख्या बढ़ रही है तो इससे उत्पादक जनसंख्या के बजाय देश में उपभोक्ताओं (Consumers) की संख्या अधिक होगी और कुल मिलाकर प्रति व्यक्ति उत्पादन पर, ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके विपरीत, यदि जनसंख्या की आयु संरचना अनुकूल है तो इसका आर्थिक विकास पर धनात्मक प्रभाव पड़ेगा। पुनः जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि देश में प्रौद्योगिकी स्तर, विकास की अवस्था, पूँजी निर्माण की दर, जनशक्ति का स्वरूप, नवप्रवर्तन के लिए प्रेरणा और बाजार का स्वरूप क्या है। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास के मार्ग में एक प्रबल बाधा (Hindrance) के रूप में खड़ी हो जाती है। **प्रो० सिंगर** (Singer) के अनुसार, "जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, बचत की दर को कम करती है और विनियोजन की उत्पादकता को कम करती है।" **प्रो० सिंगर** यह मत व्यक्त करते हैं कि आर्थिक विकास तभी हो सकता है जबकि उत्पादन में वृद्धि की दर जनसंख्या विकास की दर से अधिक हो। उन्होंने आर्थिक विकास की दर, बचतों की दर, विनियोग की उत्पादकता (Productivity) और जनसंख्या वृद्धि की दर के बीच के सम्बन्ध को व्यक्त करने के लिए निम्न समीकरण को प्रस्तुत किया है—

$$D = S.P - r$$

उपरोक्त समीकरण में,

D = आर्थिक विकास की दर
S = शुद्ध बचतों की दर (अथवा बचत-आय अनुपात)
P = नए विनियोग की उत्पादकता
r = जनसंख्या वृद्धि की दर

इस प्रकार, आर्थिक विकास के लिए यह जरूरी है कि बचतें बढ़ें विनियोग बढ़े, उत्पादन बढ़े और जनसंख्या में वृद्धि की दर घटे। इसी तरह **प्रो० मायर** कहते हैं कि, "अल्प विकसित देशों में तीव्र से बढ़ती जनसंख्या, पूँजी को बढ़ाने वाले निवेशों और नव प्रवर्तनों को हतोत्साहित करती है, पूँजी संचय की दर को कम करती है, निस्सारक उद्योगों (Extractive Industries) में लागतों को बढ़ाती है, अर्द्ध बेरोजगारी के आकार में वृद्धि करती है और बहुत हद तक पूँजी को शिशुओं के भरण-पोषण की ओर ले जाती है जो उत्पादक आयु तक पहुँचने से पहले ही मर जाते हैं।" इसी तरह, राष्ट्रीय संसाधन पूँजी निर्माण में न जाकर जनसंख्या निर्माण में स्वाहा हो जाते हैं। इस तरह जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक है।

इस प्रकार, जनसंख्या की वृद्धि एवं आर्थिक विकास के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों ने परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए हैं। कुछ अर्थशास्त्री बढ़ती हुई जनसंख्या को आर्थिक विकास में सहायक मानते हैं तो कुछ इसे आर्थिक विकास में बाधक बताते हैं। इस सम्बन्ध में कुछ प्रमुख विद्वानों के विचार निम्नलिखित हैं—

ऐल्विन हैन्सेन के विचार (Views of Alvin Hansen)

जनसंख्या एवं आर्थिक विकास के सम्बन्ध में नवकेन्सवादी अर्थशास्त्री एल्विन हैन्सेन ने एडम स्मिथ के इस विचार का समर्थन किया कि बढ़ती हुई जनसंख्या ही विकसित देशों के लिए उपयुक्त है। एडम स्मिथ की धारणा थी कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास को प्रभावित करती है और स्वयं आर्थिक विकास से प्रभावित भी होती है। उनके अनुसार बढ़ती जनसंख्या से श्रम विभाजन में वृद्धि होती है, उत्पादन व उत्पादकता बढ़ती है। आविष्कार करने की योग्यता बढ़ती है। देश में मजदूरी कोष में वृद्धि होती है और बाजार का विस्तार होता है। इस तरह एडम स्मिथ के विचार पूर्ण आशावादी (Optimist) थे। ऐल्विन हैन्सेन ने एडम स्मिथ की विचारधारा का समर्थन करते हुए माल्थस एवं रिकार्डों द्वारा जनसंख्या एवं आर्थिक विकास के सम्बन्ध में व्यक्त की गई निराशावादी धारणा की आलोचना की और इनकी विचारधारा को आधारहीन बताया। हैन्सेन का कथन है कि बढ़ती हुई जनसंख्या से माँग (Demand) में वृद्धि होती है, श्रमपूर्ति में कमी नहीं आ पाती, विशिष्टता एवं कार्यक्षमता बढ़ती और विनियोजन एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। हैन्सेन ने अपने विचार को केन्द्रीय विचारधारा के आधार पर आगे बढ़ाया। कीन्स का तर्क था कि जनसंख्या के घट जाने से प्रभावपूर्ण माँग कम हो जाती है। इससे विनियोजकों को विनियोजन के अवसर कम मिलते हैं। विनियोजन (Investment) में कमी आने से निराशा का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। बेरोजगारी बढ़ती है जिससे लोगों की आय कम हो जाती है। आय कम होने से मांग घट जाती है और मन्दी का चक्र प्रारम्भ हो जाता है। यही विचार व्यक्त करते हुए हैन्सेन कहते हैं, "यह मेरा बढ़ता हुआ विश्वास है कि जनसंख्या के घटने का तथा साथ ही साथ नव प्रवर्तन न होने का सम्मिलित प्रभाव यह होता है कि मन्दी की स्थिति पूर्णतया समाप्त होकर, पूर्ण रोजगार की स्थिति तक नहीं पहुँच पाती है ..... आज विकसित देशों में घटती हुई विनियोजन की सम्भावनाओं का मुख्य कारण घटती हुई जनसंख्या एवं बसने के लिए नए क्षेत्रों का पता लगाने की सम्भावनाओं की समाप्ति है।" हैन्सेन की धारणा है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका में 60 प्रतिशत पूँजी निर्माण जनसंख्या वृद्धि के ही कारण हुआ। इसी तरह यूरोप में भी 40 प्रतिशत पूँजी निर्माण जनसंख्या वृद्धि के कारण हुआ। इस कारण पर हैन्सेन इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि विकास के लिए जनसंख्या में वृद्धि होना जरूरी है।

हैन्सेन ने बताया कि अमेरिका में 1930 की महान आर्थिक मन्दी घटती हुई जनसंख्या के फलस्वरूप ही आयी थी। घटती हुई जनसंख्या से ही मन्दी की तीव्रता बढ़ गई थी तथा तेजी आने में देर हुई थी।

हैन्सेन का विचार था कि घटती हुई जनसंख्या से नए-नए आविष्कार करने तथा विनियोजन करने की प्रेरणा कम हो जाती है। इसके फलस्वरूप रोजगार के अवसर और आय कम हो जाती है। अथवा धीमी गति से बढ़ती है। इस तरह, बेरोजगारी स्थायी रूप से बनी रहती है। आय कम होने से माँग दोबारा कम हो जाती है। इस तरह का चक्र चल पड़ता है जिसके कारण आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसे *"Acceleration-decelaration Principle"* कहा जाता है। **हैन्सेन** और उनके अन्य समर्थकों का तर्क है कि नए मकानों का निर्माण भी प्रत्यक्षत: जनसंख्या वृद्धि पर निर्भर करता है। इसके विपरीत, जनसंख्या के घटने से इस कार्य में विनियोजन कम हो जाता है। जनसंख्या के कम होने पर न केवल मकानों का निर्माण अवरुद्ध हो जाता है बल्कि अन्य सार्वजनिक निर्माण के कार्यों पर भी विनियोजन कम होने लगता है। जनसंख्या कम होने पर आवश्यक उपभोग्य वस्तुओं का उत्पादन भी घट जाता है। इसके अलावा, स्कूलों, कारखानों, अस्पताओं, आदि पर भी विनियोजन कम होने लगता है सबसे गम्भीर बात यह होती है कि घटती जनसंख्या से माँग में कमी हो जाने के कारण लोगों में निराशा और अवसाद की भावना उत्पन्न हो जाती है। जनसंख्या घटने से अथवा जनसंख्या पर नियन्त्रण लगाने से समाज में जवानों की संख्या कम एवं बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ने लगती है। इस तरह, बूढ़े आश्रितों की संख्या बढ़ने से देश की कार्यक्षमता घट जाती हैं। जिससे पूँजी निर्माण की प्रक्रिया बाधित होती है।

प्र.2. भारत की जनसंख्या का आकार और संवृद्धि का विवरण कीजिए।
Describe the size and Enhancement of India's population.

उत्तर

भारत की जनसंख्या का आकार और संवृद्धि
(Size and Enhancement of India's Population)

भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, सन् 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी कुल जनसंख्या 121 करोड़ (यानी 1.21 अरब) हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2023 में भारत की जनसंख्या 1,428,627,663 है।

भारत 2023 में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश माना जा रहा है। जैसा कि सारणी में देखा जा सकता है भारत की जनसंख्या संवृद्धि दर हमेशा बहुत ऊँची नहीं रही। वर्ष 1901-1951 के बीच औसत वार्षिक संवृद्धि दर 1.33% से अधिक नहीं हुई जो कि एक साधारण संवृद्धि दर कही जा सकती है। सच तो यह है कि 1911 से 1921 के बीच संवृद्धि की दर नकारात्मक यानी ऋणात्मक रूप से –0.03% रही। इसका कारण 1918–19 के दौरान इंफ्लूएंजा महामारी का भीषण ताण्डव था। जिसने लगभग 1.25 करोड़ लोगों यानी देश की कुल जनसंख्या के 5% अंश को मौत के कुँए में ढकेल दिया था। (विसारिया और विसारिया 2003 : 191)। ब्रिटिश राज से स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जनसंख्या संवृद्धि दर में काफी बढ़ोतरी हुई और वह 1961-1981 के दौरान 2.2% पर पहुँच गई। तब से, यद्यपि वार्षिक संवृद्धि दर में गिरावट तो आयी है फिर भी वह विकासशील दुनिया में सबसे ऊँची बनी हुई हैं। चार्ट 1 में स्थूल जन्म एवं मृत्यु दरों की तुलनात्मक घट बढ़ दिखाई गई हैं। जनांसाख्यिकीय संक्रमण की अवस्था का प्रभाव स्पष्ट रूप से आरेख में दिखाया गया है। जिससे यह प्रकट होता है कि ये दरें 1921 से 1931 तक के दशक के बाद एक दूसरे से भिन्न दिशा में जाने लगी थीं।

सारणी : भारत की जनसंख्या और 20वीं एवं 21वीं शताब्दी में इसकी संवृद्धि

वर्ष	कुल जनसंख्या (लाखों में)	औसत वार्षिक संवृद्धि दर (%)	दशकीय संवृद्धि दर (%)
1901	238	–	–
1911	252	0.56	5.8
1921	251	– 0.03	– 0.3
1931	279	1.04	11.0
1941	319	1.33	14.2
1951	361	1.25	13.3
1961	439	1.96	21.6
1971	548	2.22	24.8
1981	683	2.20	24.7
1991	846	2.14	23.9
2001	1028	1.95	21.5
2011	1210	1.63	17.7

चार्ट 1 : भारत में जन्म एवं मृत्यु दरें 1901-2017

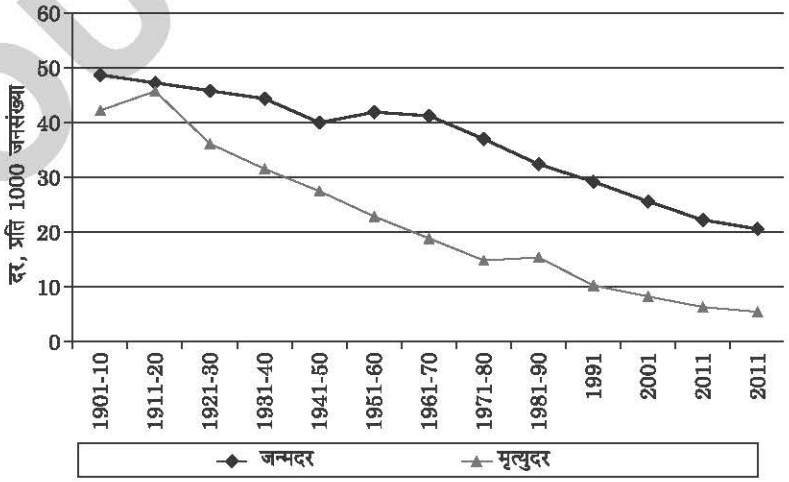

स्रोत : राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, भारत सरकार

TOUCH 'n' PASS

1931 से पहले, मृत्यु दरें और जन्म दरें दोनों ही ऊँची रही हैं। इस संक्रमण वर्ष के बाद मृत्यु दरों में तेज़ी से गिरावट आयी है जबकि जन्म दर थोड़ी-सी गिरी है। 1921 के बाद मृत्यु दर में गिरावट आने का प्रमुख कारण यह था कि अकालों और महामारियों पर नियन्त्रण बढ़ गया। इनमें महामारियों की रोकथाम सम्भवत: अधिक महत्त्वपूर्ण साबित हुई। पहले अनेक प्रकार की महामारियाँ थीं जिनमें विभिन्न प्रकार के ज्वर, प्लेग, चेचक और हैजा अधिक विनाशकारी थे। लेकिन 1918-19 की इंफ्लूएंजा नामक महामारी ने तो अकेले ही देशभर में तबाही मचा दी जिसमें 125 लाख यानी सवा करोड़ लोगों को अर्थात् तत्कालीन भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 5% भाग को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। (इस महामारी में हुई मृत्यु के बारे में अलग-अलग अनुमान लगाए गए जिनमें से कुछ के आँकड़े बहुत ऊँचे थे। स्पैनिश फ्लू नामक महामारी अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके सम्पूर्ण भूमण्डल में फैल गई। अंग्रेजी में ''पैंडेमिक' शब्द एक ऐसी महामारी के लिए उपयोग किया जाता है जो बहुत व्यापक भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित करती है। वहीं 'एपिडेमिक' शब्द को सीमित क्षेत्र में फैली महामारी के लिए उपयोग किया जाता है।

ऐसी बीमारियों के उपचार में किए गए सुधारों, बड़े पैमाने पर चलाए गए टीकाकरण कार्यक्रमों और व्यापक रूप से संचालित स्वच्छता अभियानों ने महामारियों को नियन्त्रित करने में सहायता की। किन्तु मलेरिया, क्षय रोग और पेचिश व दस्त की बीमारियाँ आज भी लोगों के लिए जानलेवा बनी हुई हैं हालाँकि, अब उनसे मरने वालों की संख्या उतनी अधिक नहीं होती जितनी पहले महामारी के रूप में उनके प्रकोप के कारण हुआ करती थीं। सूरत नगर सितम्बर, 1994 में कुछ हद तक प्लेग महामारी की चपेट में आ गया था और 2006 में देश के अनेक भागों में डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारी के व्यापक रूप से फैलने की खबरें पढ़ने-सुनने को मिलीं।

अकाल भी बढ़ती हुई मृत्यु दर के एक प्रमुख एवं पुनरावर्तक स्रोत थे। एक जमाना था जब अकाल व्यापक रूप से और बार-बार पड़ते थे उन दिनों अकाल पड़ने के कई कारण होते थे जिनमें से एक यह था कि जिन इलाकों में खेती वर्षा पर निर्भर रहती थी। वहाँ वर्षा की कमी के कारण खेती की उपज कम होती थी जिससे लोग घोर गरीबी और कुपोषण की हालत में जीवन बिताने को मजबूर हो जाते थे। इसके अलावा, परिवहन और संचार के साधनों की समुचित व्यवस्था न होने के कारण और राज्य की ओर से इस दिशा में पर्याप्त प्रयत्न न किए जाने के कारण भी अकाल पड़ते थे। किन्तु, जैसाकि अमर्त्य सेन एवं अनेक विद्वानों ने दर्शाया है कि अकाल अनाज के उत्पादन में गिरावट आने के कारण हीं नहीं पड़े वरन 'हकदारी की पूर्ति का अभाव' (Failure of entitlements) अथवा भोजन खरीदने या और किसी तरह से प्राप्त करने की लोगों की अक्षमता के कारण भी अकाल पड़ते रहे हैं। लेकिन अब भारतीय कृषि की उत्पादकता में (विशेष रूप से सिंचाई के विस्तार के कारण) पर्याप्त वृद्धि हो जाने, संचार के साधनों में सुधार हो जाने और सरकार द्वारा अधिक तेजी से राहत और निरोधक उपाय किए जाने से अकाल से कारण होने वाली मौतो की संख्या में बहुत तेजी से कमी आयी है। किन्तु आज भी देश के कुछ पिछड़े क्षेत्रों में भुखमरी के कारण लोगों के मरने के समाचार मिलते रहते हैं। सरकार ने अभी कुछ समय पहले ही ग्रामीण इलाकों में भूख और भुखमरी की समस्या के समाधान के लिए महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Rural Empolyment Guarantee Act) नामक एक कानून बनाया है।

हालाँकि मृत्यु दर की तरह जन्म दर में उतनी तेजी से गिरावट नहीं आयी। इसका कारण यह है कि जन्म दर ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटना है जिसमें परिवर्तन अपेक्षाकृत धीमी गति से आता है। सामान्यत: समृद्धि का बढ़ता स्तर जन्म दर को मजबूती से नीचे खींचता है। जब एक बार शिशु मृत्यु दरों में गिरावट आ जाती है और शिक्षा और जागरूकता के स्तरों में भी कुल मिलाकर वृद्धि हो जाती है। तो फिर परिवार का आकार छोटा होने लगता है। जैसा कि नक्शा 1 में देखा जा सकता है भारत के राज्यों के बीच प्रजनन दरों के मामलें में अत्यधिक भिन्नताएँ पायी जाती हैं। आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्य कुल प्रजनन दर 1.7 (2016) तक नीचे लाने में सफल हुए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इन राज्यों में औसत स्त्री 1-7 बच्चे ही पैदा करती है जो कि प्रतिस्थापन स्तर से नीचे हैं। केरल की कुल प्रजनन दर भी प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है जिसका तात्पर्य यह होगा कि भविष्य में जनसंख्या में गिरावट आ जाएगी। लेकिन कुछ राज्य, खासतौर पर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहाँ 2009 में प्रजनन दरें 3 या उससे भी ऊपर है। वर्ष 2009 के टी० एफ० आर० के अनुसार इन राज्यों की प्रजनन दर क्रमश: 3.3, 2.8, 2.7 और 3.1 था। वर्ष 2015 के आँकड़ों के अनुसार भारत में जन्म दर कुल 20.2% है। इसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर 22.4% और नगरीय क्षेत्रों में 17.3% था। भारत में सबसे अधिक जन्मदर उत्तर प्रदेश और बिहार में है। यह है 25.9% और 26.4% है और ये राज्य मिलकर 2026 तक भारत की कुल जनसंख्या का (50%) लगभग

आधा भाग तक बढ़ा सकते हैं। अकेला उत्तर प्रदेश ही अनुमानत: एक-चौथाई तक (22%) बढ़ा सकता है। विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय समूह के रूप में उनकी जनसंख्या बढ़ोतरी दर्शाई गई हैं।

वर्ष 2041 तक प्रक्षेपित जनसंख्या के क्षेत्रवार हिस्से

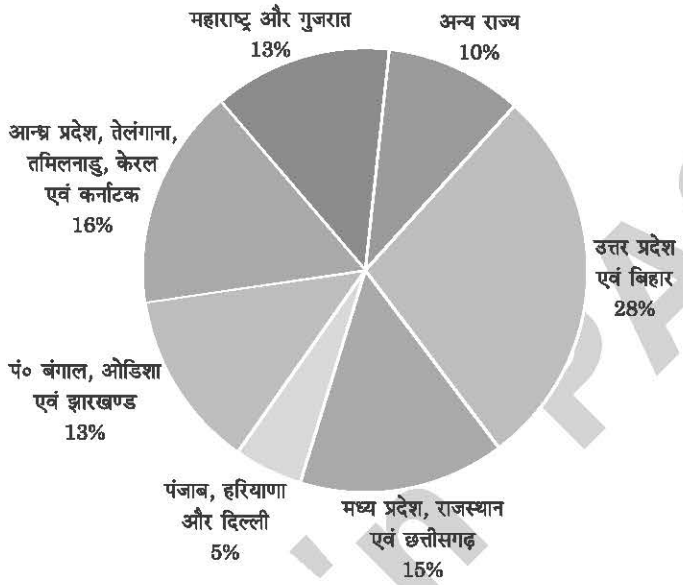

स्त्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण, 2018-19 खण्ड 1, पृष्ठ 137, वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार।

प्र.3. भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना का चित्र सहित वर्णन कीजिए।
Describe the age structure of India population with pictorial.

उत्तर

भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना
(Age Structure of India Population)

भारत की जनसंख्या बहुत जवान है यानी अधिकांश भारतीय युवावस्था में हैं और यहाँ की आयु का औसत भी अधिकांश अन्य देशों की तुलना में कम है। सारणी दर्शाती है कि देश की सम्पूर्ण जनसंख्या में 15 वर्ष से कम आयु वाले वर्ग का हिस्सा जो 1971 में 42% के सर्वोच्च स्तर पर था घटकर 2011 में 29% के स्तर पर आ गया है। 15–59 के आयु वर्ग का हिस्सा 53% से कुछ बढ़कर 63% हो गया है। जबकि 60 वर्ष से ऊपर की आयु वाले वर्ग का हिस्सा बहुत छोटा है लेकिन वह उसी अवधि के दौरान (5% से 7% तक) बढ़ना शुरू हो गया है। लेकिन अगले दो दशकों में भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना में काफी परिवर्तन आने की उम्मीद है और यह परिवर्तन अधिकांशत: आयु क्रम के दोनों सिरों पर आएगा। जैसाकि सारणी में दिखाया गया है। 0-14 आयु वर्ग का हिस्सा लगभग 11% घट जाएगा (यह 2001 में 34% था जो 2026 में घटकर 23% हो जाएगा) जबकि 60 वर्ष से अधिक के आयु वर्ग में लगभग 5% की वृद्धि होगी (यह 2001 के 7% से बढ़कर 2026 में 12% हो जाएगा) चार्ट 1 में 'जनसंख्या पिरामिड' का 1961 से लेकर 2026 तक का प्रक्षेपित स्वरूप दिखाया गया है।

सारणी : भारत की जनसंख्या की आयु संरचना, 1961-2026

वर्ष	आयु वर्ग			जोड़
	0-14 वर्ष	15-59 वर्ष	60 वर्ष से अधिक	
1961	41	53	6	100
1971	42	53	5	100
1981	40	54	6	100

1991	38	56	7	100
2001	34	59	7	100
2011	29	63	8	100
2026	23	64	12	100

चार्ट 1 : आयु समूह पिरामिड, 1961, 1981, 2001 एवं 2026

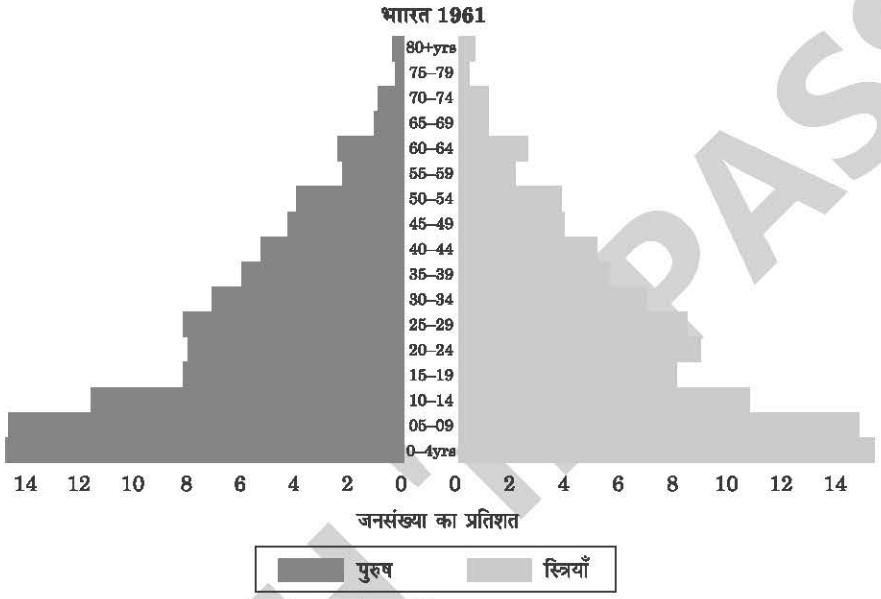

चित्र 1

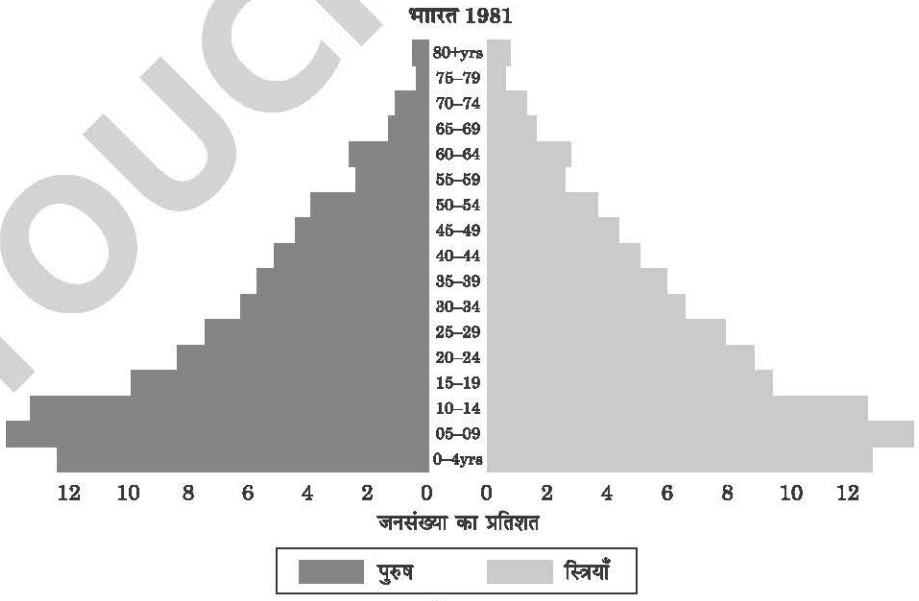

चित्र 2

TOUCH 'n PASS

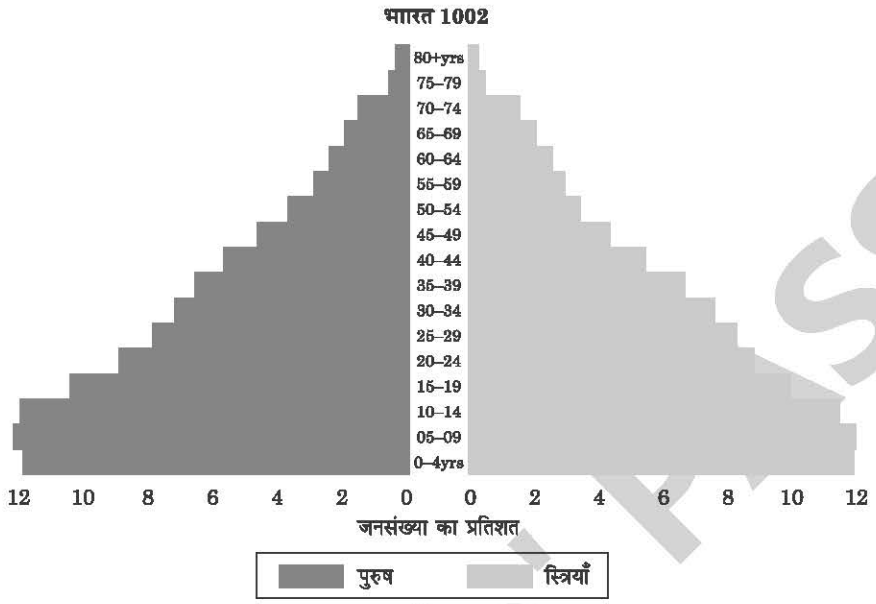

चित्र 3

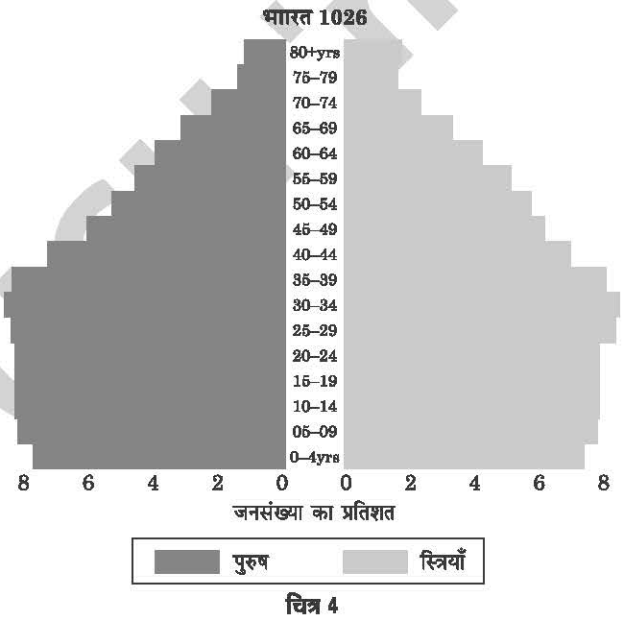

चित्र 4

जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रजनन दरें अलग-अलग होती हैं उसी प्रकार आयु संरचना में भी बहुत अधिक क्षेत्रीय अन्तर पाए जाते हैं। एक ओर तो स्थिति यह है कि केरल जैसा राज्य आयु संरचना के मामले में विकसित देशों की स्थिति को प्राप्त करने लगा है वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की स्थिति बिल्कुल भिन्न है जहाँ अपेक्षाकृत छोटे आयु समूहों में जनसंख्या के अनुपात काफी अधिक हैं और वृद्धजनों के अनुपात अपेक्षाकृत कम है। कुल मिलाकर भारत की स्थिति लगभग बीच की है क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी हैं और केरल जैसे राज्य भी, जिनकी संख्या ज्यादा है। चार्ट में उत्तर प्रदेश और केरल से सम्बन्धित वर्ष 2026 की अनुमानित जनसंख्या के पिरामिड़ दिखाए गए हैं। केरल और उत्तर प्रदेश के पिरामिड़ों में सबसे चौड़े भागों की स्थिति के अन्तर को ध्यान से देखिए।

TOUCH 'n PASS

चार्ट 2 : आयु संरचना पिरामिड, केरल और उत्तर प्रदेश 2026

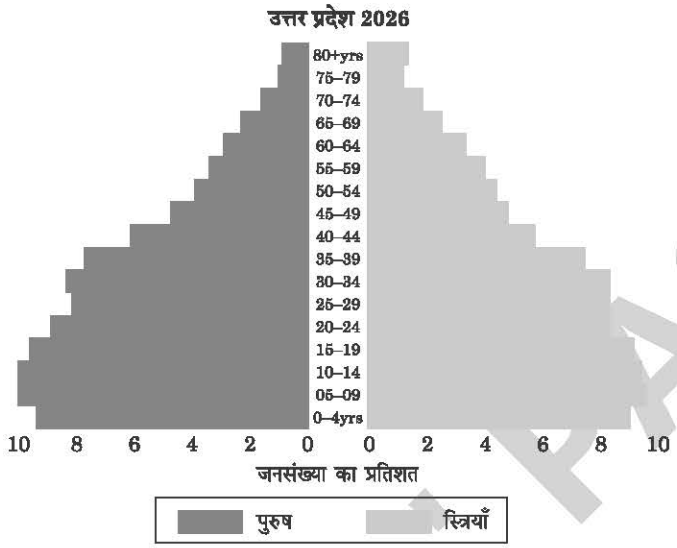

चित्र 5

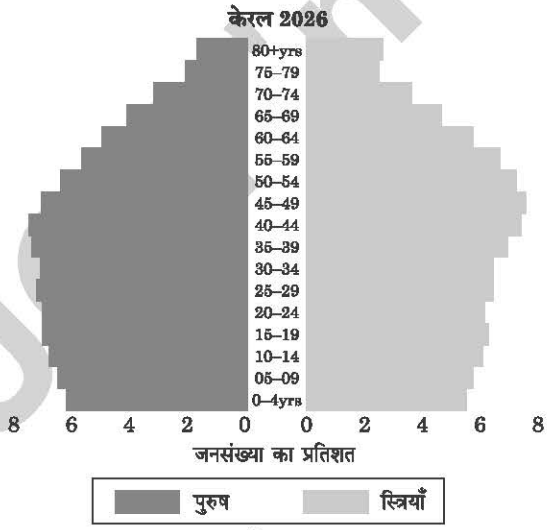

चित्र 6

आयु संरचना में अपेक्षाकृत छोटी आयु के वर्गों की ओर जो झुकाव पाया जाता है। उसे भारत के लिए लाभकारी माना जाता है। पिछले दशक में पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की तरह और आज के आयरलैण्ड की तरह यह समझा जाता है। कि भारत को भी 'जनसांख्यिकीय लाभांश' का फायदा मिल रहा है यह लाभांश इस तथ्य के कारण मिल रहा है कि कार्यशील लोगों की वर्तमान पीढ़ी अपेक्षाकृत बड़ी है एवं उसे वृद्ध लोगों की अपेक्षाकृत छोटी पीढ़ी का भरणपोषण करना पड़ रहा है। लेकिन यह लाभ अपने आप मिलने वाल नहीं हैं। बल्कि इसके लिए उपर्युक्त नीतियों का सोच-समझकर पालन करना होगा जैसाकि बॉक्स 2.3 में वर्णन किया गया है।

भारत में गिरता हुआ स्त्री-पुरुष अनुपात (Decline male-Female Ratio in India)

स्त्री-पुरुष अनुपात जनसंख्या में लैंगिक या लिंग सन्तुलन का एक महत्त्वपूर्ण सूचक है। जैसाकि ऊपर संकल्पनाओं सम्बन्धी अनुभाग में कहा गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से, स्त्री-पुरुष अनुपात स्त्रियों के पक्ष में रहा है। यानी प्रति 1,000 पुरुषों के पीछे

स्त्रियों की संख्या आमतौर पर 1,000 से कुछ ऊपर ही रहती आयी है। लेकिन जैसाकि सारणी 3 से स्पष्ट होता है। भारत में स्त्री-पुरुष अनुपात पिछली एक शताब्दी से कुछ अधिक समय से गिरता जा रहा है। 20वीं शताब्दी के शुरू में भारत में प्रति 1,000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 972 थी लेकिन 21वीं शताब्दी के शुरू में स्त्री-पुरुष अनुपात घटकर 933 हो गया हैं।

सारणी : भारत में गिरता हुआ स्त्री-पुरुष, 1901-2011

वर्ष	स्त्री-पुरुष अनुपात (सभी आयु वर्गो में)	पिछले दशक की तुलना में अन्तर	बाल स्त्री-पुरुष अनुपात (0-6 वर्ष)	पिछले दशक की तुलना में अंतर
1901	972	–	–	–
1911	964	–8	–	–
1921	955	–9	–	–
1931	950	–5	–	–
1941	945	–5	–	–
1951	946	+1	–	–
1961	941	–5	976	–
1971	930	–11	964	–12
1981	934	+4	962	–2
1991	927	–7	945	–17
2001	933	+6	927	–18
2011	943	+10	919	–8

टिप्पणी : स्त्री-पुरुष अनुपात को प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है।
स्त्रोत : 2011 की जनगणना के आधार पर

पिछले चार दशकों की प्रवृत्ति खासतौर पर चिन्ताजनक रही है, 1961 में स्त्री-पुरुष अनुपात 941 था जो घटते हुए अब तक के सबसे नीचे स्तर 927 पर आ गया हालाँकि 2001 में उसमें फिर मामूली सी बढ़ोतरी हुई हैं। अगर हम 2011 की जनगणना का अनुमानित स्त्री-पुरुष अनुपात को देखें तो प्रति 1,000 पुरुषों के पीछे 943 स्त्रियाँ हैं।

लेकिन जनसांख्यिकीविदों, नीति-निर्माताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और इस विषय से जुड़े नागरिकों को वास्तव में जिस तथ्य ने डरा दिया है। वह है बच्चों ने लैंगिक यानी बाल स्त्री-पुरुष अनुपात में एकाएक आयी भारी गिरावट। आयु विशेष स्त्री-पुरुष अनुपात का लेखा जोखा रखने का काम 1961 में शुरू हुआ था। जैसाकि सारणी 3 में दर्शाया गया है 0.6 आयु वर्ग का स्त्री-पुरुष अनुपात (जिसे बाल स्त्री-पुरुष अनुपात कहा जाता है) आमतौर पर सभी आयु वर्गों के समग्र स्त्री-पुरुष अनुपात से काफी ऊँचा रहता आया है लेकिन अब उसमें बड़ी तेजी से गिरावट आ रही है। वस्तुत: 1991 से 2001 तक के दशक के आँकड़ों में यह असामान्यतया दिखाई देती है कि समग्र स्त्री पुरुष अनुपात में जहाँ अब तक की सबसे अधिक 6 अंकों की बढ़ोतरी (निम्नतम 927 से 933) दर्ज हुई है। लेकिन बाल स्त्री-पुरुष अनुपात, 18 अंकों का गोला लगाकर 945 से घटकर 927 के स्तर पर आ गया है और इस प्रकार वह पहली बार समग्र स्त्री-पुरुष अनुपात से नीचे चला गया है। सन् 2011 की जनगणना के अनुमानित आँकड़ों के अनुसार स्थिति और खराब हो गई और बाल स्त्री-पुरुष अनुपात मात्र 914 रह गया है।

राज्य स्तरीय बाल स्त्री-पुरुष अनुपात तो चिन्ता का और भी बड़ा कारण प्रस्तुत करते हैं। कम-से-कम 9 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का बाल स्त्री-पुरुष अनुपात प्रति 1,000 पुरुष के पीछे 900 स्त्रियों से भी कम है। इस सम्बन्ध में हरियाणा राज्य की स्थिति सबसे खराब है क्योंकि वहाँ का बाल स्त्री-पुरुष अनुपात अविश्वसनीय रूप से 793 (एकमात्र ऐसा राज्य जो 800 से नीचे है।) पंजाब के बाद जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, चण्ड़ीगढ़ और उत्तराखण्ड आते हैं। उत्तर प्रदेश, दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और मध्य प्रदेश सभी में यह अनुपात 925 से नीचे हैं जबकि बड़े राज्य जैसे कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक में यह अनुपात 927 के राष्ट्रीय औसत से तो ऊपर है पर 970 के स्तर से नीचे है। यहाँ तक कि केरल भी जहाँ का समग्र स्त्री-पुरुष अनुपात सर्वोत्तम रहा है बाल स्त्री-पुरुष अनुपात के मामले में 964 के स्तर पर कोई बेहतर स्थिति में नहीं हैं जबकि 972 का उच्चतम बाल स्त्री-पुरुष अनुपात अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है।

TOUCH 'n' PASS

जनसांख्यिकीविदों और समाजशास्त्रियों ने भारत में स्त्री-पुरुष अनुपात में गिरावट आने के कई कारण बताए हैं। स्वास्थ्य सम्बन्धी मुख्य कारक जो पुरुषों की बजाय केवल स्त्रियों को ही प्रभावित करता है वह है स्त्रियों का गर्भधारण करना और फिर बच्चा पैदा करना इसलिए यह प्रश्न उठना प्रासंगिक है। कि क्या स्त्री-पुरुष अनुपात में गिरावट का एक कारण यह हो सकता है कि केवल स्त्रियों को ही बच्चा पैदा करने में मौत का जोखिम उठाना पड़ता हैं। किन्तु, यह माना जाता है कि विकास के साथ मातृ-मृत्यु दर में गिरावट आती है क्योंकि विकास की बदौलत पोषण, सामान्य शिक्षा और जागरूकता के स्तर बढ़ते जाते हैं और साथ ही चिकित्सा और संचार की सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार होता जाता है। निस्सन्देह, भारत में भी मातृ-मृत्यु दरें घटती जा रही हैं। भले ही वे अन्तर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में अब भी ऊँची बनी हुई हैं। इसलिए यह मुश्किल दिखाई देता है कि मातृ-मृत्यु दरों के कारण स्त्री-पुरुष अनुपात की हालत बिगड़ती गई हैं। एक अन्य तथ्य यह भी है कि बाल स्त्री-पुरुष अनुपात में गिरावट समग्र अनुपातों के मुकाबले अधिक तेजी से आयी है। इसलिए समाजविज्ञानियों का विश्वास है कि इस गिरावट के कारण को बालिका शिशुओं यानी बच्चियों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार में खोजना होगा।

बाल स्त्री-पुरुष अनुपात में गिरावट आने के अनेक कारण है जैसे, शैशवावस्था में बच्चियों की देखभाल की घोर उपेक्षा, जिससे उनकी मृत्यु दरें ऊँची हो जाती है, लिंग-विशेष के गर्भपात जिससे बच्चियों को पैदा ही होने नहीं दिया जाता और बालिका शिशुओं की हत्या (अथवा धार्मिक या सांस्कृतिक अन्धविश्वासों के कारण शैशवावस्था में ही बच्चियों की हत्या)। इनमें से प्रत्येक कारण एक गम्भीर सामाजिक समस्या की ओर इशारा करता है और इस बात के कुछ प्रमाण भी मिलते हैं कि ये सब कारण भारत में कार्य करते रहे हैं। अनेक क्षेत्रों में बालिका हत्या की प्रथाएँ प्रचलित बताई जाती हैं जबकि ऐसी आधुनिक चिकित्सा तकनीकों को अधिक महत्त्व दिया जा रहा है। जिनकी सहायता से गर्भावस्था की प्रारम्भिक स्थितियों में की यह पता लगाया जा सकता है कि गर्भस्थ शिशु लड़का होगा या लड़की। सोनोग्राम (यानी अल्ट्रासाउण्ड, प्रौद्योगिकी पर आधारित एक्सरे जैसा नैदानिक उपाय) जो मूल रूप में भ्रूण में जननिक या अन्य विकारों का पता लगाने के लिए विकसित किया गया था अब भ्रूण के लिंग का पता लगाने और चयनात्मक आधार पर बालिका भ्रूण को गर्भ में ही नष्ट कर देने के लिए उसका दुरुपयोग किया जाने लगा है।

कुछ क्षेत्रों में बाल स्त्री-पुरुष अनुपातों का नीचा स्तर इस तर्क का समर्थन करता प्रतीत होता है। आश्चर्यजनक तथ्य तो यह है कि निम्नतम बाल स्त्री-पुरुष अनुपात भारत के सबसे अधिक समृद्ध क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हाल ही भारत की आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, इसी तरह पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़ और दिल्ली में भी प्रति व्यक्ति आय बहुत उच्च है लेकिन इन्हीं राज्यों में बाल-पुरुष अनुपात बहुत निम्न है (तदर्थ)। इसलिए चयनात्मक गर्भपातों की समस्या गरीबी या अज्ञान अथवा संसाधनों के अभाव के कारण उत्पन्न नहीं हुई है।

कभी-कभी आर्थिक दृष्टि से समृद्ध परिवार अपेक्षाकृत कम-अक्सर एक या दो-बच्चे उत्पन्न करना चाहते हैं इसलिए कि वे अपनी पसन्द के अनुसार ही लड़का या लड़की पैदा करना चाहेंगे। अल्ट्रासाउण्ड प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के कारण ऐसा करना सम्भव हो गया है हालाँकि, सरकार ने कठोर कानून बनाकर इस पद्धति पर प्रतिबन्ध लगा दिया है और इस कानून का उल्लंघन करने वाले को भारी जुर्माने और कारावास के दण्ड़ का भागी बना दिया है। प्रसवपूर्व नैदानिक प्रविधियाँ (दुरुपयोग का विनियमन और निवारण) अधिनियम नामक यह कानून 1999 से लागू है और इसे 2003 में और अधिक प्रबल बना दिया गया है तथापि, बालिका बच्चों के विरुद्ध पूर्वाग्रह जैसी समस्याओं का दीर्घकालीन समाधान समाज में उत्पन्न होने वाली अभिवृत्तियों पर अत्यधिक निर्भर करता है। नियम एवं कानून भी इसमें मदद कर सकते हैं। अपने देश में 'बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम का सूत्रपात हाल ही में भारत सरकार ने किया है। यह बाल स्त्री-पुरुष अनुपात को बढ़ाने के लिए कारगर नीति साबित हो सकती है।

प्र.4. भारत की जनसंख्या नीति की विवेचना कीजिए।

Discuss the population policy of India.

उत्तर

भारत की जनसंख्या नीति
(Population Policy of India)

जनसंख्या की गतिशीलता एक महत्त्वपूर्ण विषय है और यह एक राष्ट्र के विकास की सम्भावनाओं को और वहाँ की जनता के स्वास्थ्य और कल्याण को निर्णायक रूप से प्रभावित करती है। यह विशेष रूप से उन विकासशील देशों के मामले में अधिक सही है। जिन्हें इस सम्बन्ध में विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि भारत पिछले पचास साल से भी अधिक समय से एक अधिकारिक जनसंख्या नीति का पालन करता रहा है। वास्तव में, भारत ही सम्भवत: ऐसा पहला देश था जिसने 1952 में अपनी जनसंख्या नीति का स्पष्ट घोषणा कर दी थी।

हमारी जनसंख्या नीति ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के रूप में एक ठोस रूप धारण किया। इस कार्यक्रम के उद्देश्य मोटे तौर पर समान रहे हैं—जनसंख्या संवृद्धि की दर और स्वरूप को प्रभावित करके सामाजिक दृष्टि से वांछनीय दिशा की ओर ले जाने का प्रयत्न करना। प्रारम्भिक दिनों में, इस कार्यक्रम का सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य था। जन्म नियन्त्रण के विभिन्न उपायों के माध्यम से जनसंख्या संवृद्धि की दर को धीमा करना, जन-स्वास्थ्य के मानक स्तरों में सुधार करना और जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दों के बारे में आम लोगों की जागरूकता बढ़ाना।

राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि (1975-76) में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को गहरा धक्का लगा। इस आपातकालीन स्थिति में, सामान्य संसदीय और वैध प्रक्रियाएँ निलम्बित रहीं और विशेष कानून और अध्यादेश (संसद में पारित करवाए बिना ही) सीधे सरकार द्वारा लागू कर दिए गए। इस आपातकालीन में सरकार ने बड़े पैमाने पर जोर-जबरदस्ती से वंध्यकरण (Sterilisation) का एक कार्यक्रम लागू करके आबादी नियंत्रण पर ध्यान दिया गया।

पिछले लगभग पचास वर्षों में भारत ने जनसंख्या के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की है जिनका संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है।

I. भारत में जनसांख्यिकी संक्रमण

भारत की जनगणना के आँकड़ों (भारतीय जनसम्पर्क महासंघ) से पता चलता है कि 1991 के बाद से भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आयी है। 1990 में एक महिला उसके जीवन के दौरान औसतन 3.8 बच्चों को जन्म देती थी, वहीं 2023 में यह कम होकर 2.7 बच्चे प्रति महिला हो गए हैं। (ब्लूम, 2011)। हालाँकि प्रजनन क्षमता और जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आ रही है, लेकिन भारत की जनसंख्या वृद्धि की तीव्र गति के कारण 2050 तक इसके 1.6 अरब तक पहुँचने का अनुमान है। जनसंख्या की गति ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जहाँ प्रजनन की उम्र में महिलाओं की बड़ी संख्या अगली पीढ़ी के दौरान जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देगी।

भले ही यह पिछली पीढ़ियों से एक बच्चे की कम संख्या के रूप में हो। इसके अतिरिक्त पिछले चार दशकों से क्रूड मृत्यु दर (सी०डी०आर०) और क्रूड जन्म दर (बी०सी०आर०) गिरावट दर्शाती है कि भारत एक संक्रमणकालीन चरण के आगे प्रगति कर रहा है। 1950 से 1990 तक बी०सी०आर० की गिरावट सी०डी०आर० में आयी गिरावट की तुलना में कम तीव्र थी। हालाँकि, 1990 के दौरान सी०डी०आर० में आयी गिरावट सी०डी०आर० में आयी गिरावट की तुलना में तेज रही है, जिसकी परिणति आज 1.6% की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर के रूप में हुई हैं।

II. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के महत्त्वपूर्ण लक्ष्य

1. नीति में जनस्वास्थ्य व्यय को समयबद्ध ढंग से जी०डी०पी० के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान में यह जी०डी०पी० का 1.04 प्रतिशत हैं।
2. जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को 67.5 वर्ष से बढ़कर वर्ष 2025 तक 70 वर्ष करना।
3. वर्ष 2022 तक प्रमुख वर्गों में रोगों की व्यापतता और इसके रुझान को मापने के लिए विकलांगता समायोजित आयु वर्ष (DALY) सूचकांक की नियमित निगरानी करना।
4. वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate : TFR) को घटाकर 2.1 पर लाना।
5. वर्ष 2025 तक पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर को कम करके 23 करना तथा एम०एम०आर० के वर्तमान स्तर को वर्ष 2020 तक घटाकर 100 करना।
6. नवजात शिशु मृत्यु दर को घटाकर 16 करना तथा मृत जन्म लेने वाले बच्चों की दर को वर्ष 2025 तक घटाकर एक अंक में लाना।
7. वर्ष 2020 के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करना जिसे एच०आई०वी०/एड्स के लिए 90 : 90 : 90 के लक्ष्य के रूप में परिभाषित किया गया है। अर्थात् एच०आई०वी० पीड़ित सभी 90 प्रतिशत लोग अपनी एच०आई०वी० स्थिति के बारे में जानते हैं। सभी 90 प्रतिशत एच०आई०वी० संक्रमण से पीड़ित लोग स्थायी एंटीरोट्रोवाइरल चिकित्सा प्राप्त करते हैं तथा एंटीरोट्रोवाइरल चिकित्सा प्राप्त करने वाले सभी 90 प्रतिशत लोगों में वॉयरल रोकथाम होगा।
8. क्षयरोग के नए स्पुटम पॉजिटिव रोगियों में 85 प्रतिशत से अधिक की इलाजदर को प्राप्त करना और उसे बनाए रखना तथा नए मामलों में कमी लाना ताकि वर्ष 2025 तक इसे समाप्त किया जा सके।

TOUCH 'n' PASS

9. वर्ष 2025 तक दृष्टिहीनता की व्याप्तता को घटाकर 0.25/1000 करना तथा रोगियों की संख्या को वर्तमान स्तर से घटाकर एक-तिहाई करना।
10. हृदयवाहिका रोग, कैंसर, मधुमेह या सांस के पुराने रोगों से होने वाली अकाल मृत्यु को वर्ष 2025 तक घटाकर 25 प्रतिशत करना।
11. 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग मौजूदा स्तरों से 50 प्रतिशत बढाएँ।
12. प्रसवपूर्व देखभाल कवरेज 90 प्रतिशत से ऊपर और जन्म के समय कुशल उपस्थिति 2025 तक 90 प्रतिशत से अधिक हो।
13. 2025 तक एक वर्ष की आयु के नवजात शिशु 90 प्रतिशत से अधिक पूरी तरह से प्रतिरक्षित हो।
14. 2025 तक राष्ट्रीय और उप राष्ट्रीय स्तर पर 90 प्रतिशत से ऊपर परिवार नियोजन की आवश्यकता को पूरा करना।
15. घरेलू स्तर पर ज्ञात उच्च रक्तचाप और मधुमेह से ग्रस्त लोगों को 2025 तक 80 प्रतिशत नियन्त्रित रोग की स्थिति में लाना।
16. वर्तमान तम्बाकू के उपयोग को 2020 तक 15 प्रतिशत और 2025 तक 30 प्रतिशत तक घटाना।
17. 2025 तक पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में स्टंट करने के प्रचलन में 40 प्रतिशत की कमी लाना।
18. 2020 तक सभी के लिए सुरक्षित पानी और स्वच्छता तक पहुँच की सुविधा उपलब्ध करवाना।
19. 2020 तक 334 प्रति लाख कृषि श्रमिकों की व्यवसाय सम्बन्धी चोटों को वर्तमान स्तर से आधा करना।
20. 2025 तक भयावह स्वास्थ्य व्यय का सामना करने वाले परिवारों के अनुपात में वर्तमान स्तरों से 25 प्रतिशत तक कमी लाना।
21. 2020 तक उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में इण्ड़ियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड (IPHS) के मानकों के अनुसार पैरामेडिक्स और डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
22. 2025 तक उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की आई०पी०एच०एस० मानदण्ड के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित करना।
23. 2025 तक उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में मानदण्डों के अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल सुविधा उपलब्ध करना।
24. 2020 तक स्वास्थ्य प्रणाली के घटकों पर सूचना के जिला-स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस को सुनिश्चित करना।
25. 2020 तक राज्य के स्वास्थ्य व्यय को राज्य बजट में > 8 प्रतिशत तक बढ़ाना।

जनसंख्या की संवृद्धि दर को नीचे लाने का प्रयत्न किया। यहाँ वंध्यकरण का अर्थ ऐसी चिकित्सा पद्धतियों से हैं जिनके द्वारा गर्भाधान और शिशुजन्म को रोका जा सकता है। पुरुषों के मामलें में उपयोग में लायी जाने वाली शल्य पद्धति को नसबन्दी (Vasectomy) और स्त्रियों के लिए काम में लायी जाने वाली शल्य पद्धति को नलिकाबन्दी (Tubectomy) कहा जाता है। अधिकतर गरीब और शक्तिहीन लोगों का भारी संख्या में जोर-जबरदस्ती से वंध्यकरण किया गया और सरकारी कर्मचारियों (जैसे स्कूली अध्यापकों या दफ्तरी बाबुओं) पर भारी दबाव डाला गया कि वे लोगों को वंध्यकरण के लिए आयोजित शिविरों में लाएँ। इस कार्यक्रम का जनता में व्यापक रूप से विरोध हुआ और आपातकाल के बाद निर्वाचित होकर आयी सरकार ने इसे छोड़ दिया।

आपातकाल के बाद राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर उसे राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कहा जाने लगा और वंध्यकरण के लिए अपनाए जाने वाले दबावकारी तरीकों को छोड़ दिया गया। अब इस कार्यक्रम के व्यापक आधार वाले सामाजिक-जनसांख्यिकीय उद्देश्य हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 के अन्तर्गत कुछ नए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। 2017 में भारत सरकार ने इन सभी लक्ष्यों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में नए लक्ष्यों के साथ निगमित कर लिया। इन नीति लक्ष्यों को पढ़ें और इनके पहलुओं पर विचार विमर्श करें।

भारत का राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम हमें यह शिक्षा देता है कि हालाँकि राज्य जनसांख्यिकीय परिवर्तन के उद्देश्य से उपर्युक्त परिस्थितियाँ बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। फिर भी अधिकांश जनसांख्यिकीय परिवर्तनशील दरों में (विशेष रूप से मनुष्य की प्रजनन दर के मामले में) अन्ततः आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

TOUCH 'n PASS

प्र.5. समावेशी विकास का विस्तृत वर्णन कीजिए।
Describe the inclusive developmetn in detail.

उत्तर

समावेशी विकास
(Inclusive Development)

समावेशी विकास वह विकास है जो न केवल नए आर्थिक अवसरों का सृजन करता है, बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए, विशेष रूप से गरीबों के लिए, बनाए गए अवसरों तक समान पहुँच सुनिश्चित करता है। ओईसीडी समावेशी विकास को आर्थिक विकास के रूप में परिभाषित करता है जो आबादी के सभी वर्गों के लिए अवसर पैदा करता है और समाज में मौद्रिक व गैर-मौद्रिक, दोनों तरह के संवर्धित समृद्धि के लाभांश को पूरे समाज में न्यायसंगत ढंग से वितरित करता है। इस प्रकार, समावेशी विकास वह प्रक्रिया है। जो तेजी से अवसरों को बनाने और वंचितों सहित सभी के लिए इन्हें सुलभ बनाने पर केन्द्रित है।

पारम्परिक दृष्टिकोण बताता है कि विकास की प्रक्रिया में असमानता अन्तर्निहित है। विकास प्रक्रिया के संरचनात्मक परिवर्तन के दौरान कुछ क्षेत्र अन्य क्षेत्रों, जो पिछड़ जाते हैं, की तुलना में अधिक लाभान्वित होते हैं। इसलिए शुरूआती अवधि में वृद्धि असमानता को जन्म देती है। लेकिन बाद में, विकास का लाभ पिछड़े क्षेत्रों को भी मिला जाता है जिससे अधिक न्यायसंगत विकास परिणाम सामने आता है। यह प्रक्रिया 'कुजनेट वक्र' में दिखाई देती है जहाँ असमानता पहले बढ़ती है और फिर कम होती है। हालाँकि, भारत में यह प्रक्रिया सही नहीं पायी गयी क्योंकि विकास दर में वृद्धि के परिणामस्वरूप असमानता में कमी नहीं हुई हैं। 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों के बाद से देश 1993-94 और 2009-10 के दौरान लगभग 7 प्रतिशत और 2010 से 2016 की अवधि के दौरान 6.7 प्रतिशत की औसत विकास दर के साथ मजबूती से बढ़ा है। विकास के समान स्तर वाले अन्य देशों की तुलना में भारत में असमानता न केवल बहुत अधिक है, बल्कि समय के साथ इसने, विशेष रूप से 1990 के दशक की शुरूआत से, बढ़ती प्रवृत्ति को भी दिखाया हैं। हालाँकि असमानता में वृद्धि की दर 2004-05 के बाद धीमी हो गई लगती है, यह लगातार बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। भारत में असमानता उतनी ही शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और अवसरों के बारे में है जितनी कि बढ़ती आय असमानता के बारे में है। जीडीपी में तेजी से विकास, उदार और विस्तारवादी राजकोषीय नीति, बड़े सार्वजनिक ऋण, प्रौद्योगिकी में तेजी से सुधार और अधिक पूँजी का उपयोग करके उत्पादन की प्रकृति में बदलाव, जीडीपी में सेवाओं की बढ़ती हिस्सेदारी और अनुकूल नीतियाँ व संस्थान, आदि कुछ प्रशंसनीय कारण हो सकते हैं। इसके अलावा, देश में जाति, वर्ग, धर्म, नस्ल, लिंग और स्थान के आधार पर उच्च स्तर की क्षैतिज असमानताएँ हैं। असमानता का एक सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला सूचक गिनी सूचकांक है, जो शून्य (पूर्ण समानता के सन्दर्भ में) से एक (पूर्ण असमानता) तक भिन्न होता है। इस मापक के अनुसार 1983 और 1993-94 के बीच असमानता में गिरावट आयी लेकिन अगले दशक में 1991 में सुधारों की शुरुआत के बाद यह काफी बढ़ी।

बढ़ती आय असमानता, अवसरों में असमानता (शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाओं/समावेशन तक पहुँच सहित), बेरोजगारी, गरीबी और सामाजिक वंचन के अन्य रूपों में व्यापक असमानताओं को देखते हुए समावेशी विकास की ओर लक्षित नीतियाँ अनिवार्य हो जाती हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच, वित्तीय सेवाओं तक पहुँच, नई प्रौद्योगिकी, लैंगिक समानता और संसाधनों के अधिक समान वितरण, ये सभी समावेशी आर्थिक विकास का समर्थन कर सकते हैं। भारत में विभिन्न योजना अवधियों में समावेशी विकास को व्यापक रूप से परिलक्षित किया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास को इस प्रकार परिभाषित करती है 'एक संवृद्धि प्रक्रिया जो विस्तृत वयापक लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है'। इसी तरह, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य 'तेज, अधिक समावेशी और सतत धारणीय संवृद्धि था। हमने समावेशन पर प्रगति देखी हैं। कृषि विकास, गरीबी में कमी, शिक्षा, स्वास्थ्य, एससी/एसटी का उत्थान आदि। हालाँकि, समावेशन पर प्रगति अपेक्षा से कम है। इसे विभिन्न पहलुओं से समझा जा सकता है। भारत सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) के कई संकेतक हासिल करने से चूक गया। साक्षरता मोर्चे पर पिछड़े वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों के बीच साक्षरता बढ़ाने के लक्ष्य को हासिल नहीं किया गया है। कृषि विकास, अभी भी कमजोर स्थिति में है। मनरेगा जैसी रोजगार योजनाएँ स्तरीय नहीं हैं। कई योजनाएँ, नीतियाँ, योजनाएँ हैं लेकिन उनका कार्यान्वयन उनके अपेक्षित स्तर के अनुसार नहीं हुआ है।

TOUCH 'n' PASS

समावेशी विकास : नीतिगत निहितार्थ
(Inclusive Development : Policy Implications)

कृषि का विकास (Development of Agriculture)

कृषि के विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हालिया रुझानों से पता चलता है कि कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि क्षेत्र का योगदान वर्ष 1958-59 में 44.6 प्रतिशत से घटकर 2008-09 में 17.2 प्रतिशत, 2019-20 में 16.5 प्रतिशत हो गया है। इसी अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या बहुत कम नहीं हुई है। यह दर्शाता है कि कृषि क्षेत्र में कार्यबल में कमी की गति की तुलना में कृषि क्षेत्र द्वारा जीडीपी में योगदान में कमी की गति बहुत अधिक है। इसलिए, कृषि क्षेत्र को सिंचाई और जल प्रबन्धन, ऋण, अनुसन्धान और विस्तार, विपणन आदि के माध्यम से विकसित करने की आवश्यकता है। कृषि के विकास के लिए भूमि और जल प्रबन्धन (वाटरशेड विकास सहित) महत्त्वपूर्ण हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों के विकास ने न केवल रोजगार के दायरे का विस्तार किया है, बल्कि कृषि क्षेत्र पर बड़ी निर्भरता को भी कम किया है।

ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार के अवसर
(Rural Non-agriculture Imployment Opportunities)

ग्रामीण गैर-कृषिगत क्षेत्र (आरएनएफएस) सभी गैर-कृषि गतिविधियों को शामिल करता है खनन और उत्खनन, घरेलू, और गैर-घरेलू विनिर्माण, प्रसंस्करण, आदि। ग्रामीण गैर-कृषि अर्थव्यवस्था को ग्रामीण भारत में आर्थिक गतिविधियों के विकेन्द्रीकरण के लिए एक प्रभावी रणनीति के रूप में माना जाता है ताकि अनियमित प्रवासन (Migration) को रोका जा सके, ग्रामीण-शहरी विभाजन को पाटा जा सके, रोजगार पैदा किया जा सके, असमानताओं को कम किया जा सके आदि। भारत के श्रम बाजार पर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययनों के अनुसार 2011 से 2015 के बीच कृषि नौकरियों की संख्या में 26 मिलियन की गिरावट आयी जबकि गैर कृषिगत क्षेत्र में 33 मिलियन की वृद्धि हुई। हालाँकि, यह क्षेत्र अपर्याप्त ग्रामीण बुनियादी ढाँचा, विशेष रूप से सड़कें, बिजली और संचार सुविधाएँ, पर्याप्त कुशल श्रम की कमी और ऋण, सूचना एवं प्रशिक्षण सुविधाओं तक पर्याप्त पहुँच आदि जैसे कई कारकों से जूझ रहा है। इस प्रकार, सही शासन प्रणाली के साथ समावेशी, टिकाऊ और विविध ग्रामीण विकास के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है।

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion)

वित्तीय समावेशन वंचित और कम आय वाले समूहों को सस्ती लागत पर वित्तीय सेवाओं और समय पर पर्याप्त ऋण की उपलब्धता है। वित्तीय समावेशन गरीबी उन्मूलन, आय समानता, खाद्य सुरक्षा और स्थायी कृषि, बुनियादी ढाँचे और उद्योगों का समर्थन, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, बढ़ते उपभोग और बचत को प्रोत्साहित करना, बेरोजगारी में कमी और धारणीय आर्थिक संवृद्धि जैसे विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। सरकार और केन्द्रीय बैंक द्वारा निम्न के माध्यम से वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किया गया है—कम आय वाले समूहों के लिए ऐसे खातों तक पहुँच का विस्तार करने के लिए कम या शून्य न्यूनतम शेष और न्यूनतम शुल्क वाले खाते, आसान साख सुविधाएँ, सरल केवाईसी मानदण्ड, सरल उपयोग सूचना और प्रौद्योगिकी का प्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक लाभ अन्तरण प्रणाली का विस्तार, व्यापार पत्राचार मॉडल, बैंक शाखा और एटीएम विस्तार, वित्तीय साक्षरता और साख परामर्श, आदि। फिर भी, भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र से बाहर है। तेजी से शहरीकरण शहरी गरीबों की दर को बढ़ा रहा है। जो सबसे बुनियादी बैंकिंग सुविधाओं से वंचित हैं। इसके अलावा, अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग अभी भी औपचारिक वित्तीय प्रणाली के दायरे के बाहर हैं। इस प्रकार, समावेशी संवृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है।

सार्वजनिक निवेश (Public Investment)

समावेशी संवृद्धि के लिए बुनियादी ढाँचे में उच्च निवेश महत्त्वपूर्ण हैं। कई विकासशील देशों में यह दिखाई देता है। कि जीडीपी के प्रतिशत के रूपे में सार्वजनिक व्यय कम है और घट रहा है। ग्रामीण विकास में सार्वजनिक निवेश में तेजी से गिरावट आयी है। नतीजतन, भारत में कृषि विकास धीमा हो गया। भौतिक (सिंचाई, सड़क, संचार, परिवहन, बिजली, आदि) और मानव अवसंरचना (स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि) में सार्वजनिक निवेश की प्राथमिकता को महत्त्वपूर्ण कारकों में से एक माना जाता है। जिसके परिणामस्वरूप समावेशी संवृद्धि होती है।

TOUCH 'n' PASS

सार्वजनिक वित्त और कर नीतियाँ (Public Finance and Tax Policies)

कर सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार सृजन और समग्र सामाजिक क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय के लिए वित्तपोषण का प्राथमिक स्रोत प्रदान करते हैं। कर सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क और बुनियादी क्षेत्र के लिए भी वित्तीय आधार हैं, जो अप्रत्याशित जोखिमों के खिलाफ गरीब लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं और कठिन समय में उन्हें गरीबी में वापस आने से रोकते हैं। इसलिए प्रगतिशील कर नीतियाँ आय और धन के उचित वितरण को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख हैं।

संस्थाओं का विकास (Development of Organisation)

नई संस्थाओं का विकास और सेवा वितरण की मौजूदा संस्थाओं को मजबूत करना महत्त्वपूर्ण है। ऐसा लगता है कि कई संस्थाएँ विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, स्वास्थ्य और शिक्षा में बेहतर सेवाएँ देने में विफल रही हैं। जब महिलाएँ सशक्त होती हैं तो संस्थाएँ उत्तरदायी प्रतीत होती हैं। बेहतर वितरण प्रणाली के लिए पीआरआई को मजबूत करने के सन्दर्भ में विकेन्द्रीकरण में सुधार किया जाना है।

सामाजिक संरक्षण (Social Conservation)

सामाजिक संरक्षण प्रणाली पुनर्वितरण के माध्यम से गरीबी और असमानता को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इससे समाज के बहिष्कृत रह गए वर्ग को भी मंच देने में मदद मिलती है। भारत ने गरीबी और असमानता के मुद्दों को दूर करने के लिए अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को लागू किया है। सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (प्रत्यक्ष खाद्य सब्सिडी) इन्दिरा आवास योजना (गरीबों के लिए आवास) और वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, आदि जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्यक्ष नकद अन्तरण आदि हैं। कुछ अन्य प्रोत्साहन आधारित कार्यक्रम भी हैं, उदाहरण के लिए, संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहन, परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहन आदि। कुछ शैक्षिक विकास कार्यक्रमों जैसे छात्रवृत्ति, पुस्तकों, साइकिल, कपड़ों का नि:शुल्क वितरण, दोपहर का भोजन, आदि को लागू किया गया है।

समय-समय पर केन्द्र और राज्य सरकारें विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों को लागू करती हैं जो ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए न्यूनतम आजीविका प्रदान करते हैं। अगस्त 2005 में भारत सरकार द्वारा पारित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा) 2005, केन्द्र सरकार द्वारा लागू किया गया एक अनूठा कार्यक्रम हैं इससे प्रत्येक ग्रामीण भारतीय को कानून द्वारा प्रदत्त गारण्टीकृत रोजगार प्रदान करके सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रति वर्ष एक सौ दिनों के अकुशल कार्य की गारण्टी देता हैं।

प्र.6. भारत में समावेशी विकास का सविस्तार वर्णन कीजिए।

Explain in detail inclusive development in India.

उत्तर

भारत में समावेशी विकास
(Inclusive Development in India)

भारत में सर्वप्रथम समावेशी विकास की अवधारणा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में पेश की गई थी जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और समान अवसर उपलब्ध करने की बात कही गई थी। इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में इसको और व्यापक बनाया गया जिसमें गरीबी को कम करने, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं में सुधार और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने जैसी बातों पर खास जोर दिया गया। इसके लिए सरकार ने कई योजनाएँ चलाई हैं जिनमें दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, मनरेगा, समेकित बाल विकास योजना, मिड डे मील, स्कूली शिक्षा और साक्षरता, सर्व शिक्षा अभियान, जेएनएनयूआरएम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शामिल हैं।

व्यापारिक स्तर पर समावेशन (Business Level Inclusion)

विश्व बैंक द्वारा जारी होने वाले इज ऑफ डूइंग बिजनेस इण्डेक्स में 2018 में भारत 190 देशों में 77वें रैंक पर रहा। सरकार ने इस दिशा में बेहतर प्रदर्शन करते हुए चार सालों में भारत को 57रैंक ऊपर पहुँचाया है। इस सूचकांक के जरिये विभिन्न देशों में व्यापार करने की सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। इससे व्यापार के प्रति सरकारी अधिकारियों, वकीलों, बिजनेस कंसल्टेंट्स इत्यादि का भी रुख पता चलता है। कारोबार शुरू करना, निर्माण अनुमति, बिजली सप्लाई, सम्पत्ति का रजिस्ट्रेशन, कर्ज की उपलब्धता, निवेशकों की सुरक्षा, टैक्स अदायगी, सीमा पर व्यापार, कॉन्ट्रैक्ट्स का पालन, दिवालियेपन से उबरने की क्षमता जैसे आधारों पर इस सूचकांक में किसी देश की रैंकिंग निर्भर करती है।

TOUCH 'n PASS

हालाँकि इस सूचकांक को लेकर कुछ विवाद भी होता रहता है क्योंकि यह व्यापार सुगमता के लिए केवल सरकारी प्रयासों को ही आधार बनाता है, जबकि इसके अलावा कई कारक हैं जिन पर कारोबार की सुगमता निर्भर करती है, मसलन उत्पादकों को मिलने वाली सेवाएँ, बिजली के साथ पानी की उपलब्धता और कचरा प्रबन्धन।

मानव संसाधन विकास में समावेशन
(Inclusion Development in Human Resource)

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा जारी किये जाने वाले मानव विकास सूचकांक यानी HDI में भारत कोई खास प्रगति नहीं कर पाया है। साल 2014 में भारत का रैंक 130 था और साल 2018 में भी यह 130 ही था जो 2023 में 132वें स्थान पर है। जबकि भारत हालिया वर्षों में सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है। इससे एक बात तो साफ है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था मानव संसाधनों के मामले में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त किये बिना भी तेजी से विकास कर सकती है। आपको बता दें कि HDI को पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक एवं भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने मिलकर विकसित किया है। इसमें पर कैपिटा इनकम, स्वास्थ्य एवं स्कूली शिक्षा के आधार पर विभिन्न देशों को रैंकिंग दी जाती है। लैकिन इस इंडेक्स की एक खामी यह है कि इसमें विकास की जानकारी तो मिलती है, लेकिन उस विकास की गुणवत्ता के बारे में इसमें कुछ नहीं बताया जाता। मसलन केवल यह देखा जाना कि स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, काफी नहीं है, इसके साथ यह भी जरूरी है कि उन्हें मिलने वाली शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर कैसा है।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के स्तर पर समावेशन

पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में भारत को 180 देशों में 177वाँ रैंक मिला जबकि 2014 में भारत 180 देशों में 155वें पायदान पर था। अब 2023 में 180 देशों में से 180वाँ रैक मिला है। यानी पर्यावरण के मामले में भारत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है।

यह इंडेक्स वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, येल यूनिवर्सिटी और कोलम्बिया यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। इस सूचकांक में 24 संकेतकों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है जिसमें पर्यावरण स्वास्थ्य, पारिस्थितिक तन्त्रों की विविधता, हवा की गुणवत्ता, पेयजल और स्वच्छता, कृषि, जैवविविधता और बायो-हैबिटाट, जलवायु एवं ऊर्जा प्रमुख हैं।

विचार करने योग्य बात यह है कि साल 2018 में कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन के जरिये तटीय आर्थिक क्षेत्र में उन स्थानों को भी निर्माण एवं पर्यटन के लिए खोल दिया गया है। जिन्हें पहले पवित्र और इको सेंसिटिव माना जाता था।

भारत में भ्रष्टाचार और समावेशी विकास
(Inclusive Development and Corruption in india)

भ्रष्टाचार समावेशी विकास की राह में एक बड़ा रोड़ा है। भ्रष्टाचार वो बीमारी है जो समावेशी विकास के बजाय अमीरों को और अमीर बनाने और गरीबों को गरीब बनाए रखने का काम करती है।

अन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इन्टरनेशनल ने भृष्टाचार धारणाणा सूचकांक 2018 जारी किया था। अन्तर्राष्ट्रीय पारदर्शिता इन्टरनेशनल द्वारा जारी इस सूचकांक के अनुसार, भारत भ्रष्टाचार के मामले में 180 देशों की सूची में 78वें स्थान पर था। विचार करने योग्य बात यह है कि साल 2017 में भारत इस सूचकांक में 81वें पायदान पर था। जबकि 2022 में भारत इस सूचकांक में 85वें स्थान पर आ गया। इस सूचकांक के अनुसार, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी काफी कुछ किया जाना शेष है।

वित्तीय समावेशन (Finance inclusion)

वित्तीय समावेशन लोगों और अर्थव्यवस्था से जुड़ी वित्तीय मुख्यधारा के बीच कड़ी मुहैया कराकर वित्तीय अभाव को दूर करता है। इसके अलावा, यह निम्न आय वर्ग वाले लोगों को संगठित बैंकिंग क्षेत्र के दायरे में लाकर उनकी सम्पत्तियों और अन्य संसाधनों की जरूरी परिस्थितियों में सुरक्षा करता है। वित्तीय समावेशन सरकारी सिस्टम में कर्ज की उपलब्धता को आसान बनाकर कमजोर समूहों को शोषण से भी बचाता है। वित्तीय समावेशन की दिशा में सरकार द्वारा कई कदम उठाये गए हैं। जिनमें मोबाइल बैंकिग का विस्तार, बैंकिग कॉरस्पॉन्डेट योजना, प्रधानमन्त्री जन धन योजना, प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना और वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना अहम् हैं।

TOUCH 'n' PASS

किसी भी देश में वित्तीय समावेशन का न होना वहाँ के समाज और व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक होता है। जहाँ तक व्यक्ति का सवाल है, वित्तीय समावेशन के अभाव में, बैंकिंग सुविधा से वंचित लोग इनफॉर्मल बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जहाँ ब्याज दरें मनमानी और अधिक होती है और प्राप्त होने वाली राशि काफी कम होती है।

समाज के कई तबके विकास की दौड़ में पीछे छूट सकते हैं और इससे अराजकता, अपराध या बीमारी जैसी कई अन्य समस्याएँ भी पैदा हो सकती हैं। इससे समूचे राष्ट्र के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो सकता है। नक्सलवाद इसका एक ज्वलन्त उदाहरण है। साथ ही नैतिक और तार्किक आधार पर भी वित्तीय समावेशन जरूरी है।

चूँकि इनफॉर्मल बैंकिंग ढाँचा कानून के दायरे से बाहर होता है, ऐसे में, उधार देने वालों और उधार लेने वालों के बीच किसी भी विवाद की दशा में इसका कानूनन निपटान करना मुश्किल होता है।

वित्तीय समावेशन और महिलाएँ (Women and Finance Invlusion)

गौरतलब है कि विश्व की कुल जनसंख्या में आधी जनसंख्या महिलाओं की हैं। वे कार्यकारी घण्टों में दो-तिहाई का योगदान करती है, लेकिन उन्हें विश्व सम्पत्ति में सौवें से भी कम हिस्सा प्राप्त है। विश्व भर में लगभग 76 करोड़ व्यक्ति प्रतिदिन 1-9 अमेरिकी डॉलर या इससे कम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनमें एक बड़ा हिस्सा महिलाओं का भी है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि गरीबी का महिलाकरण हो गया है।

वर्ष 2011-17 के दौरान 15 साल के ऊपर की 77फीसदी महिलाओं के पास बैंक खाता था। ग्लोबल फिन्डेक्श 2017 के सर्वेक्षण के अनुसार इन आँकड़ों में 2011 के पश्चात 51 फीसदी बढ़ोत्तरी हुई। इस बढ़ोत्तरी की मुख्य वजह मौजूदा सरकार द्वारा शुरू की गई देशव्यापी योजना प्रधानमन्त्री जनधन योजना है, जिसका उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को बैंकिग सुविधाओं से जोड़ना है। यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे सेवाओं को जरूरी बनाता है और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा तथा बीमा योजनाओं से भी जुड़ा है।

सरकार ने स्टार्ट-अप इण्डिया, स्टैंड-अप इण्ड़िया, महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय द्वारा संचालित Support to Training and Employment Programme for Women यानी STEP, ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टैंस एण्ड डेवलपमेण्ट स्कीम फॉर वीमेन यानी TREAD योजना, प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना और महिला उद्यमिता मंच जैसे कदम उठाये हैं। इसके बावजूद ग्लोबल फिन्डेक्श रिपोर्ट में महिलाओं के वित्तीय समावेशन के भागीदारी पर चिन्ता व्यक्त की गई है। दरअसल इन चिन्ताओं के मूल में महिलाओं के वित्तीय समावेशन को लेकर आ रही चुनौतियाँ हैं।

वित्तीय समावेशन और दिव्यांग (Handicap and Finance inclusion)

निःशक्तता या विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2(N), के अनुसार किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी विकलांगता से न्यूनतम 40 प्रतिशत पीड़ित व्यक्ति को विकलांग व्यक्ति माना जाता है।

भारतीय सामाजिक विकास रिपोर्ट तथा जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 26.8 मिलियन व्यक्ति दिव्यांग हैं जो भारत की कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत है, जबकि विश्व बैंक के अनुसार, भारत में लगभग 4.8 प्रतिशत लोग दिव्यांग हैं। भारत में कुल दिव्यांगों में से 56 प्रतिशत पुरुष हैं। 70 प्रतिशत दिव्यांग ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं। जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सबसे अधिक दिव्यांग सिक्किम, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर तथा लक्षद्वीप में पाए गए जबकि जनसंख्या के दिव्यांगों का सबसे कम अनुपात तमिलनाडु, असम व दिल्ली में पाया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 45 प्रतिशत दिव्यांग निरक्षर है। आश्चर्य की बात यह है कि केरल जो कि शत-प्रतिशत साक्षर राज्य है, वहाँ पर भी 33.1 प्रतिशत दिव्यांग निरक्षर पाए गए।

दिव्यांगता से निपटने के लिए और उनके समावेशन के लिए सरकार ने अनेक महत्त्वपूर्ण कदम उठाये हैं— जैसे निःशक्तता या विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा), सुगम्य भारत अभियान, यूडीआईडी कार्ड, छात्रवृत्ति योजना, स्वावलम्ब योजना, दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तिकरण हेतु विभाग, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017।

TOUCH 'n' PASS

वित्तीय समावेशन और किसान (Farmer and Finance inclusion)

भारत में लगभग आधी आबादी, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अभी भी कृषि पर निर्भर है और विडम्बना यह है कि कृषि लम्बे समय से घाटे का सौदा रहा है, जिससे किसानों की आय काफी कम है। बड़े पैमाने पर कर्ज में दबे किसानों की आत्महत्या की घटना भी देखने को मिलती है। जो यह इशारा करता है कि किसान भी वंचित वर्ग में है और उसका भी समावेशन जरूरी है। सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करके 100 डॉलर प्रतिमाह करने का वादा किया था किन्तु वर्तमान में किसानों की आय लगभग 50 डॉलर प्रतिमाह ही है।

किसानों की स्थिति बेहतर बनाने के लिए और उनके वित्तीय समावेशन के लिए सरकार ने कई अहम् कदम उठाये हैं। जिनमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना (ई-एनएएम), प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, तिलहन एवं तेल ताड़ पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शामिल है। इसके अलावा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वृक्षारोपण (हर मेड़ पर पेड़), मधुमक्खी पालन, डेयरी और मत्स्य पालन से सम्बन्धित योजनाएँ भी लागू की जाती हैं।

समावेशी विकास, आर्थिक असमानता और बेरोजगारी (Unemployment and Economical Unequality, Inclusive Development)

भारत के विकास को लेकर अमेरिकी अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल क्रुगमैन का कहना है कि आर्थिक मोर्चे पर भारत ने तेजी से प्रगति की है, लेकिन देश में कायम आर्थिक असमानता एक बड़ा मुद्दा है। एक विश्लेषण से पता चलता है कि 2013 से 2016 के दौरान गिन्नी गुणांक में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

गिनी गुणांक के जरिये समाज में व्याप्त आय एवं सम्पत्ति के असमान वितरण का मापन किया जाता है। यदि गिनी गुणांक का मान 'शून्य' है, तो समाज में आय वितरण समान माना जाता है और यदि गिनी गुणांक का मान 1 है, तो इसका मतलब है कि समाज में आय वितरण में काफी असमानता व्याप्त है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी इण्डिया वेज रिपोर्ट : वेज पॉलिसीज फॉर डिसेंट वर्क एण्ड इंक्लूसिव ग्रोथ में बताया गया है कि भारत में पिछले दो दशकों में सालाना 7% की औसत जीडीपी दर होने के बावजूद वेतन में कमी और असमानता की स्थिति बनी हुई हैं।

इसके अलावा लगातार बढ़ रही बेरोजगारी भारत के विकास की राह में बाधक बन सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल तकरीबन सवा करोड़ शिक्षित युवा तैयार होते हैं। ये नौजवान रोजगार के लिए सरकारी और निजी क्षेत्रों में राह तलाशते हैं, लेकिन रोजगार के पर्याप्त अवसर के अभाव में एक बड़ा वर्ग बेरोजगारी का जीवन जी रहा है या अपनी योग्यता के अनुसार उपयुक्त नौकरी नहीं पाता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

उक्त के अलावा समाज के कई अन्य संवेदनशील वर्ग जैसे कि वरिष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, श्रमिक वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए किये जा रहे तमाम प्रयासों के बावजूद काफी कुछ किये जाने की जरूरत हैं।

अगर कुछ आँकड़ों पर नजर डाले तो हम पाते हैं कि भारत साल 2018 में वैश्विक भूख सूचकांक यानि ग्लोबल हंगर इण्डेक्स में 119 देशों की सूची में 103वें नम्बर पर आया था, वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में भारत 195 देशों की सूची में 145वें पायदान पर है। इन सब आँकड़ों से देश के लोगों का औसत जीवन स्तर जाहिर होता है, और शायद इसलिए समावेशी विकास की दिशा में और काम किये जाने की जरूरत है।

प्र.7. खाद्य सुरक्षा का अर्थ, अवधारणा और आयामों का वर्णन कीजिए।
Describe the meaning, concept and dimensions of food security.

उत्तर

खाद्य सुरक्षा का अर्थ और अवधारणा (Meaning and Concept of Food Security)

खाद्य सुरक्षा की अवधारणा जटिल बहु-तथ्यात्मक परिणामों के साथ एक अगोचर (Unobservable) चर है। इसका उपयोग कई शैक्षणिक और नीतिगत प्रवचनों में लगभग 200 भिन्न-भिन्न तरीकों से किया गया है और इसमें 450 संकेतक हैं। खाद्य

TOUCH 'n' PASS

सुरक्षा की परिभाषा समय के साथ विकसित हुई है। 1974 में, खाद्य सुरक्षा को विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन (World Food Summit-WFS) द्वारा परिभाषित किया गया, "खाद्य सेवन के पर्याप्त विश्व खाद्य आपूर्ति की उपलब्धता कराना और उत्पादन और कीमतों की अस्थिरता में समायोजन करना।" खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 1983 में इसका विस्तार किया गया, जिसमें उपलब्ध आपूर्ति के लिए कमजोर लोगों द्वारा पहुँच को सुरक्षित करना शामिल था।

1990 के दशक के मध्य तक, खाद्य सुरक्षा वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख चिन्ता का विषय बन गई थी और अब खाद्य तक पहुँच में पर्याप्त भोजन शामिल था, जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के लिए चिन्ता का संकेत था। बाद में, इस परिभाषा में खाद्य सुरक्षा, पोषण सन्तुलन, और खाद्य अभिरूचियों को सम्मिलित करके इसका और अधिक विस्तार किया गया। 1994 में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme-UNDP) ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट में मानव सुरक्षा की अवधारणा में खाद्य सुरक्षा को शामिल किया।

यह विश्व खाद्य सुरक्षा 1996 की नई परिभाषा में परिलक्षित होती है, जिसने खाद्य सुरक्षा को एक स्थिति के रूप में पुन: परिभाषित किया है 'जब सभी लोग, हर समय, अपनी आहार आवश्यकताओं और भोजन की प्राथमिकताओं को पूरा करने और सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए भौतिक और आर्थिक पहुँच रखते हैं। 2001 में, खाद्य सुरक्षा की इस परिभाषा को भी संशोधित किया गया व 'सामाजिक शब्द को सम्मिलित किया गया, "जब सभी लोग, हर समय, अपनी आहार आवश्यकताओं और भोजन की प्राथमिकताओं को पूरा करने और सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए भौतिक, आर्थिक और सामाजिक पहुँच रखते हैं।"

आज खाद्य सुरक्षा का अर्थ और मूल अवधारणा महत्त्वपूर्ण रूप से घरेलू और व्यक्तिगत स्तरों पर अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर मूल खाद्य आपूर्ति की उपलब्धता और सततता पर ध्यान केन्द्रित करने से बदल गई है। यदि भोजन उपलब्ध नहीं है, तो खाद्य सुरक्षा को सीमित रूप से परिभाषित नहीं किया जाता है, बल्कि यह देखना जरूरी है कि क्या पर्याप्त आहार या खाद्य के संचय और गुणवत्ता तक पहुँचने के लिए जनसंख्या के निपटान पर मौद्रिक और गैर-मौद्रिक संसाधन उपलब्ध हैं।

खाद्य असुरक्षा (Food Insecurity)

आर्थिक बाधाओं के कारण खाद्य असुरक्षा भोजन की अनैच्छिक कमी है। जब यह खाद्य की कमी इस बिन्दु तक पहुँचती है। शारीरिक लक्षण महसूस होते हैं व भूख लगती है। खाद्य असुरक्षा की वैचारिक समझ राष्ट्रीय स्तर पर अपर्याप्त खाद्य आपूर्ति की न केवल अस्थायी समस्याओं को शामिल करने के लिए धीरे-धीरे विकसित हुई है। बल्कि इसमें अपर्याप्त पहुँच, घरेलू और व्यक्तिगत स्तर पर असमान वितरण की पुरानी समस्याएँ भी शामिल हैं।

चिरकालिक खाद्य असुरक्षा (Chronic Food Insecurity)

यह आम तौर पर एक दीर्घकालिक घटना है। यह तब होती है, जब लोग समय की निरन्तर अवधि में अपनी न्यूनतम खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। कम आय और निरन्तर गरीबी इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं।

अनित्य खाद्य असुरक्षा (Transitory Food Insecurity)

यह खाद्य असुरक्षा की अल्पावधि (Shor-term) और अस्थायी स्थित हैं। ऐसा प्राकृतिक आपदाओं, द्वन्द्व या आर्थिक पतन के कारण उत्पादन में अचानक गिरावट या पर्याप्त भोजन तक पहुँच की कमी के कारण होता है।

सामयिक खाद्य असुरक्षा (Seasonal Food Insecurity)

सामयिक खाद्य असुरक्षा स्थायी खाद्य असुरक्षा की तरह है। इसकी सीमित अवधि होती है और इसे आवर्ती अस्थायी खाद्य असुरक्षा के रूप में देखा जा सकता है। यह भविष्यवाणी करना अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि यह ज्ञान घटनाओं के अनुक्रम का अनुसरण करता है। यह मौसम, जलवायु, फसलों के स्वरूप और निश्चित समय में बीमारियों के कारण मौसमी उतार-चढ़ाव के कारण होता है।

खाद्य सुरक्षा के आयाम (Dimensions of Food Security)

खाद्य सुरक्षा के चार मुख्य आयाम है, उपलब्धता सततता, पहुँच और उपयोग। ये आयाम खाद्य की भौतिक और आर्थिक पहुँच को दर्शाते हैं, जो लोगों की आहार सम्बन्धी जरूरतों और प्राथमिकताओं का पूरा करते हैं।

TOUCH 'n PASS

खाद्य उत्पादन और उपलब्धता (क्या भोजन उत्पादन पर्याप्त है।)

खाद्य उत्पादन (Food Production)—यह लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन का उत्पादन करने के लिए खाद्य उत्पादन प्रणाली की क्षमता से सम्बन्धित है। यह आयाम खाद्य सुरक्षा के आपूर्ति पक्ष को सम्बोधित करता है और गुणवत्ता वाले भोजन की पर्याप्त मात्रा की अपेक्षा करता है। अच्छा उत्पादन वर्षा की विशेषताओं पर निर्भर है, जोकि कृषि, आदानों, मूल्य निर्धारण और बाजार तक पहुँचने की क्षमता से सम्बन्धित सरकारी नीतियों सहित अन्य कारकों के साथ संयुक्त है। खाद्य उपलब्धता का अर्थ है कि हर समय पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध है। इसकी उपलब्धता खाद्य सुरक्षा के "आपूर्ति पक्ष" को सम्बोधित करती है और खाद्य उत्पादन भण्डार स्तर और शुद्ध व्यापार के स्तर से निर्धारित होता है।

भोजन तक पहुँच (क्या लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं, और इसे खरीदने की क्षमता रखते हैं)

राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भोजन की पर्याप्त आपूर्ति अपने आप में घरेलू स्तर की खाद्य सुरक्षा की गारण्टी नहीं देती है। भोजन की सुरक्षा खाद्य सुरक्षा का एक और आयाम है, जिसमें घरों या व्यक्तियों की आय, व्यय और खरीदने की क्षमता शामिल हैं। खाद्य तक पहुँच (Food Access) लोगों को पौष्टिक आहार के लिए आवश्यक खाद्य की मात्रा प्राप्त करने के लिए अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता से सम्बन्धित हैं। खाद्य तक पहुँच सम्बोधित करती है कि क्या घरों या व्यक्तियों के पास उचित मात्रा में गुणवत्ता वाला भोजन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। यह भी एक स्थिति से सम्बन्धित है, जिससे बाजार और गैर-बाजार वितरण तन्त्र के माध्यम से भोजन तक पहुँच अधिकतर न केवल मूलभूत ढाँचे जैसे भौतिक मानदण्डों पर निर्भर करती हैं, बल्कि वित्तीय कारकों पर भी निर्भर करती हैं।

खाद्य उपयोग (स्थानीय स्थितियाँ भोजन से लोगों के पोषण पर कैसे प्रभाव डालती हैं।)

खाद्य उपयोग (Food Utilisation) के सन्दर्भ में आम तौर पर समझा जाता है कि शरीर भोजन में विभिन्न पोषक तत्त्वों का सबसे अधिक उपयोग करता है। दूसरे शब्दों में, यह मूलभूत पोषण और देखभाल के ज्ञान के आधार पर विभिन्न खाद्य पदार्थों का उचित उपयोग है। खाद्य पदार्थों के अच्छे जैविक उपयोग के साथ संयुक्त, भोजन का उपयोग व्यक्तियों की पोषण स्थिति को निर्धारित करता है। यह केवल सम्बोधित नहीं करता कि लोग कितना खाते हैं, बल्कि यह भी दर्शाता है कि वे क्या और कैसे खाते हैं। वास्तव में, व्यक्तियों द्वारा पर्याप्त ऊर्जा और पोषक तत्त्वों का सेवन अच्छी देखभाल और भोजन प्रथाओं, भोजन की तैयारी, आहार की विविधता, भोजन, पानी और स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल प्रथाओं के आन्तर-घरेलू (Intra-household) वितरण का परिणाम है।

खाद्य आपूर्ति की सततता (क्या खाद्य आपूर्ति और उस तक पहुँच सुनिश्चित है)

प्रतिकूल मौसम की स्थिति, राजनीतिक अस्थिरता या आर्थिक कारक (बेरोजगारी, बढ़ती खाद्य कीमतें) व्यक्तियों की खाद्य सुरक्षा की स्थिति पर प्रभाव डाल सकते हैं। खाद्य सुरक्षा का यह आयाम समय के साथ अन्य तीन आयामों की स्थिरता (Stability) को सम्बोधित करता है। भोजन की उपलब्धता और खाद्य की पहुँच में परिवर्तन में खाद्य आपूर्ति की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। लोग तब तक खाद्य सुरक्षा पर विचार नहीं कर सकते, जब तक वे ऐसा महसूस नहीं करते और जब तक उपलब्धता, पहुँच और उचित उपयोग की खाद्य स्थिति की स्थिरता न हो।

इसके अतिरिक्त फसल की पैदावार और खाद्य आपूर्ति की स्थिरता परिवर्तनीय (Variable) मौसम की स्थिति से नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. सी०पी० ब्लैकर के अनुसार जनसंख्या परिवर्तन की कितनी अवस्थाएँ हैं?

(क) 5 (ख) 7 (ग) 8 (घ) 4

उत्तर (क) 5

प्र.2. द्वितीय अवस्था—

(क) कृषि में यन्त्रीकरण की शुरुआत होने लगी।

(ख) उद्योगों का विकास होना प्रारम्भ हो गया।

(ग) उपभोक्ता वस्तुएँ विदेशों से आयात की जाती थी वह देशों में बनने लगी।

(घ) उपरोक्त सभी।

उत्तर (घ) उपरोक्त सभी।

प्र.3. जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावित करने वाले साधन हैं—
(क) सामाजिक (ख) आर्थिक
(ग) संस्थागत एवं जैविकीय (घ) ये सभी
उत्तर (घ) ये सभी

प्र.4. तृतीय अवस्था में हुआ परिवर्तन
(क) आधुनिक प्रकार से कृषि होने लगी। (ख) लोगों का जीवन स्तर बढ़ने लगा।
(ग) महिलाओं की स्थिति में सुधार। (घ) ये सभी
उत्तर (घ) ये सभी

प्र.5. ऊँची जन-वृद्धि की सम्भावय अवस्था कौन-सी अवस्था में आती है?
(क) द्वितीय (ख) प्रथम (ग) पंचम (घ) चतुर्थ
उत्तर (घ) चतुर्थ

प्र.6. श्रमशक्ति आपूर्ति का स्त्रोत हैं—
(क) प्राकृतिक संसाधन (ख) पूँजी की मात्रा (ग) तकनीकी ज्ञान (घ) ये सभी
उत्तर (घ) ये सभी

प्र.7. आर्थिक विकास की दर बचतों की दर विनियोग की उत्पादकता और जनसंख्या विकास की वृद्धि दर के बीच सम्बन्ध को व्यक्त करने वाली समीकरण है—
(क) $D = S.P - r$ (ख) $S.P = D + r$
(ग) $r = S.P - D$ (घ) $D = r + S.P$
उत्तर (क) $D = S.P - r$

प्र.8. ''जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। बचत की दर को कम करती है तथा विनियोजन की उत्पादकता को कम करती है'' किसकी परिभाषा है?
(क) प्रो० मायर (ख) प्रो० हेंसन (ग) प्रो० रिजर्ट टी० गिल (घ) प्रो० सिंगर
उत्तर (घ) प्रो० सिंगर

प्र.9. जनसंख्या वृद्धि में विस्तृत बाजार किस तरह से सहायक है?
(क) उपभोक्ता के रूप में (ख) माँग पैदा करना
(ग) उत्पादन के स्वरूप में विविधता (घ) ये सभी।
उत्तर (घ) ये सभी।

प्र.10. जनसंख्या के सिद्धान्त पर एक निबन्ध पुस्तक का लेखक हैं—
(क) माल्थस (ख) जेम्स प्रिंसप (ग) कीन्स (घ) फ्रैंक नोटेनस्टीन
उत्तर (क) माल्थस

प्र.11. सिद्धान्त जो कहता है कि जनसंख्या का स्तर जिस पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हैं?
(क) माल्थस द्वारा जनसंख्या का सिद्धान्त (ख) इष्टम द्वारा जनसंख्या का सिद्धान्त
(ग) जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धान्त (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (क) माल्थस द्वारा जनसंख्या का सिद्धान्त

प्र.12. जनसंख्या एवं आर्थिक विकास के स्तर में कैसा सम्बन्ध होता है?
(क) अप्रत्यक्ष (ख) प्रत्यक्ष
(ग) परस्पर घनिष्ठ (घ) 'ख' और 'ग' दोनों
उत्तर (घ) 'ख' और 'ग' दोनों

TOUCH 'n' PASS

प्र.13. जनसंख्या राष्ट्र की किस प्रकार एक सम्पत्ति है?

(क) श्रम-विभाजन के लाभ (ख) राष्ट्र की रक्षा

(ग) प्राकृतिक संसाधनों का दोहन या उपयोग (घ) ये सभी

उत्तर (घ) ये सभी

प्र.14. जनसंख्या राष्ट्र के लिए सम्पत्ति और दायित्व

(क) दोनों है (ख) केवल सम्पत्ति है

(ग) केवल दायित्व (घ) ना सम्पत्ति ना दायित्व

उत्तर (क) दोनों है

प्र.15. मनुष्य या जनसंख्या की तीन मूलभूत आवश्यकता क्या है?

(क) भोजन, घूमना, रहना (ख) भोजन, कपड़ा व मकान

(ग) रहना, खाना व पीना (घ) सोना, भोजन, घूमना

उत्तर (ख) भोजन, कपड़ा व मकान

प्र.16. तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के आर्थिक विकास में सबसे अधिक है।

(क) सहायक (ख) लाभदायक (ग) बाधाक (घ) कोई नहीं

उत्तर (ग) बाधाक

प्र.17. भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या है?

(क) भुगतान सन्तुलन में (ख) खाद्यान्नों की पूर्ति में

(ग) बेरोजगारी, पूँजी निर्माण की गति में (घ) सभी

उत्तर (घ) सभी

प्र.18. बाजार विफलता किन क्षेत्रों में देखी जाती है?

(क) सड़कों (ख) रेलों (ग) टेली (घ) ये सभी

उत्तर (घ) ये सभी

प्र.19. राज्य तथा सार्वजनिक क्षेत्र की विफलताएँ है—

(क) स्टॉफ की अत्यधिक मात्रा

(ख) कार्यनिष्ठा में अभाव के परिणामस्वरूप क्षमता, उपयोग का निम्न स्तर

(ग) समय और लागत वृद्धि के कारण अधिपूँजीकरण

(घ) सभी

उत्तर (घ) सभी

❑

TOUCH 'n' PASS

UNIT-V

विकास एवं अल्प-विकास
Development and Under Development

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. विकसित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by developed economy?

उत्तर जो आर्थिक सामाजिक दृष्टि से उन्नत है जिनका कुल उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति आय, उपभोग, बचत व विनियोग का स्तर ऊँचा है तथा जनसंख्या वृद्धि निम्न स्तर की है, विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है।

प्र.2. अल्पविकसित अर्थव्यवस्था क्या है?
What is the underdeveloped economy?

उत्तर अल्पविकसित अर्थव्यवस्था वह है जिनमें मानवीय शक्ति का अल्प उपयोग या अनुपयोग एक ओर से प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग न होने की स्थिति दूसरी ओर साथ-साथ पायी जाती है।

प्र.3. निर्भरता का क्या सिद्धान्त है?
What is the dependency theory?

उत्तर निर्भरता को राज्य के आर्थिक विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, कुछ बाहरी प्रभावों, राष्ट्रीय विकास नीतियों के आधार पर, यथा—राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक निर्भरता है एक ऐतिहासिक अवस्थिति जो विश्व अर्थव्यवस्था (Economy) की संरचना (Structures) को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। जो कि अन्य को हानि पहुँचाने हेतु कुछ देशों का समर्थन करती है और अधीनस्थ अर्थव्यवस्थाओं की विकास सम्भावनाओं को कम करती है। एक ऐसी स्थिति जिसमें कुछ संगठित देशों की आर्थिक व्यवस्था अपने लाभ के लिए अन्य दूसरी अर्थव्यवस्थाओं का विकास एवं विस्तार करती है।

प्र.4. विकास और अल्प विकास में क्या अन्तर है?
What is difference between development and under-development?

उत्तर विकसित देशों में उत्पादन के सभी साधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है जबकि विकासशील देशों में कम तकनीकी विकास के कारण उत्पादन के सभी साधनों का अल्पतम उपयोग होता है। जिसके कारण संसाधनों की बर्बादी होती है।

प्र.5. विकासशील देशों में अल्प विकास का क्या कारण है?
What is the reason for underdevelopment in developing countries?

उत्तर इस असमानता के मूल में गरीबी, विकासदर का कम होना, कर चोरी, उत्पादन के साधनों का असमान वितरण, बेरोजगारी और अर्द्धबेरोजगारी, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, मुद्रा स्फीति और श्रम की निम्न उत्पादकता जैसे कारण निहित रहते हैं, जबकि 80 प्रतिशत योगदान विकसित देशों की ओर से प्राप्त होता है।

प्र.6. अल्प विकसित देश और विकासशील देश में क्या अन्तर है?
What is the difference between underdeveloped country and developing country?

उत्तर जो देश स्वतन्त्र और समृद्ध हैं, उन्हें विकसित देश के रूप में जाना जाता है। जो देश औद्योगीकरण की शुरुआत का सामना कर रहे हैं, उन्हें विकासशील देश कहा जाता है। विकसित देशों में साक्षरता दर अधिक है, लेकिन विकासशील देशों में निरक्षरता दर ज्यादा है।

TOUCH 'n' PASS

प्र.7. द्वैतवाद की विशेषताएँ क्या हैं?
What are the characteristics of dualism?

उत्तर धर्म में, द्वैतवाद का अर्थ दो सर्वोच्च विरोधी शक्तियों या देवताओं, या दैवीय या राक्षसी प्राणियों के समूह में विश्वास है, जिसके कारण दुनिया अस्तित्व में आई।

प्र.8. द्वैतवाद का विकास कैसे हुआ?
How did dualism develop?

उत्तर सर्वप्रथम यूनानी विद्वानों ने द्वैतवाद की नींव डाली जब हैकेटियस ने भौतिक भूगोल पर तथा हैरोडोटस एवं स्ट्रेबो ने मानवीय पक्ष पर अधिक बल दिया। द्वैतवाद का वास्तविक विकास सत्रहवीं शताब्दी में आरम्भ हुआ जब वारेनियस (1622-1650) ने अपनी पुस्तक "सामान्य-भूगोल' में सर्वप्रथम भौतिक एवं मानव भूगोल के मध्य अन्तर स्पष्ट किया।

प्र.9. द्वैतवाद और अद्वैतवाद में क्या अन्तर है?
What is the difference in dualism and non-dualism?

उत्तर जैसे-आदि शंकराचार्य का मानना था जीव (आत्मा) और ब्रह्म दोनों अलग-अलग नहीं बल्कि एक ही है। इसलिए उनके दर्शन को 'अद्वैतवाद' (Non-Dualism) कहा जाता है। जबकि माध्वाचार्य का मानना था कि आत्मा और परमात्मा अलग-अलग हैं। इसलिए इनके मत को द्वैतवाद (Dualism) कहा जाता है।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. अल्पविकसित तथा विकासशील अर्थव्यवस्था की विभिन्न परिभाषाएँ दीजिए।
Give the various definitions of underdeveloped and developing economy.

उत्तर

अल्पविकसित तथा विकासशील अर्थव्यवस्था
(Underdeveloped and Developing Economy)

अल्प विकास या अल्प विकसित देश को परिभाषित करना काफी कठिन है। प्रो० सिंगर का भी मत है कि 'एक अल्प विकसित देश 'जिराफ' की भाँति है। जिसका वर्णन करना कठिन है। लेकिन जब हम इसे देखते हैं तो समझ जाते हैं।'' वैसे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अनेक मापदण्ड प्रस्तुत किये गए हैं जैसे—निर्धनता, अज्ञानता, निम्न प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय का असमान वितरण, जनसंख्या भूमि अनुपात, प्रशासनिक अयोग्यता, सामाजिक बाधाएँ इत्यादि।

प्रो० डब्ल्यू०डब्ल्यू० सिंगर का मत है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को परिभाषित करने का कोई भी प्रयास, समय का बर्बाद करना है। फिर भी किसी एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए यह आवश्यक होगा कि कुछ प्रचलित परिभाषाओं का अध्ययन कर लिया जाए।

संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विज्ञप्ति के अनुसार "अल्प विकसित देश वह है जिसकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा पश्चिम यूरोपीय देशों की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की तुलना में कम है।''

प्रो० मेकलियोड के मतानुसार, "एक अल्प विकसित देश अथवा क्षेत्र वह है जिसमें उत्पत्ति के अन्य साधनों की तुलना में उद्यम एवं पूँजी का अपेक्षाकृत कम अनुपात है परन्तु जहाँ विकास सम्भाव्यताएँ विद्यमान हैं और अतिरिक्त पूँजी को लाभजनक कार्यों में विनियोजित किया जा सकता है।

प्रो० जे० आर० हिक्स—के शब्दों में "एक अल्प विकसित देश वह देश है जिसमें प्रौद्योगिकीय और मौद्रिक साधनों की मात्रा, उत्पादन एवं बचत की वास्तविक मात्रा की भाँति कम होती है। जिसके फलस्वरूप प्रति श्रमिक को औसत पुरस्कार उस राशि से बहुत कम मिलता है। जो प्राविधिक विकास की अवस्था में उसे प्राप्त हो पाता है।''

यह परिभाषा केवल प्राविधिक घटक पर ध्यान देने के कारण एकांगी मानी जाती है। प्राविधिक घटक के अलावा कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण आर्थिक, प्राकृतिक, सामाजिक घटकों को दृष्टि में नहीं रखा गया है।

प्रो० ऑस्कर लैंज—की दृष्टि में 'एक अल्प-विकसित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है। जिसमें पूँजीगत वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा देश की कुल श्रम शक्ति को आधुनिक तकनीक के आधार पर उपयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

ऑस्कर लैंज एवं नर्कसे के विचार मेकलियोड की भाँति ही त्रुटिपूर्ण हैं। आर्थिक विकास के लिए पूँजी एक आवश्यक शर्त है। परन्तु एक मात्र नहीं। परिभाषा में अन्य आवश्यक तत्त्वों की ओर संकेत नहीं किया गया है।

TOUCH n PASS

जैकब वाइनर—के अनुसार 'अल्प विकसित देश वह देश है जिसमें अधिक पूँजी अथवा अधिक श्रम-शक्ति अथवा अधिक उपलब्ध साधनों अथवा इन सबकों उपयोग करने की पर्याप्त सम्भावनाएँ हों, जिससे कि वर्तमान जनसंख्या के रहन सहन के स्तर को ऊँचा उठाया जा सके, और यदि प्रति व्यक्ति आय पहले से ही काफी अधिक है। तो रहन सहन के स्तर को कम किये बिना, अधिक जनसंख्या का निर्वाह किया जा सके।

प्र.2. विकसित तथा अल्प विकसित देश में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

Differentiate between developed and underdeveloped country.

उत्तर

विकसित तथा अल्पविकसित देश में अन्तर

()

डॉ० स्टीफैन ने इस दृष्टि से एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को 'अनार्थिक संस्कृति' का नाम दिया है। उनका मत है कि 'परम्परागत सामाजिक मनोवृत्ति मानवी साधनों के पूर्ण उपयोग को कुंठित करती है जिसके फलस्वरूप एक रूढ़िवादी मानव समाज भौतिक पर्यावरण में बदलाव लाने और उपभोग में अतिरिक्त वृद्धि के प्रति उदासीन हो जाता है।

क्र०सं०	विकास के अंग	विकसित देश	अल्प-विकसित देश
1.	आर्थिक स्थिति	उच्च प्रति व्यक्ति GNP, औसत 25000 डॉलर	निम्न प्रति व्यक्ति GNP, औसतन 1100 डॉलर
2.	कृषि	जनसंख्या का लगभग 25 प्रतिशत कृषि कार्य में संलग्न।	जनसंख्या का औसतन 50-65 प्रतिशत कृषि में लगा होना।
3.	उद्योग	बृहत स्तरीय उत्पादन व्यवस्था	लघु-स्तरीय उत्पादन ढाँचा।
4.	प्राविधिक स्तर	उन्नत प्राविधिक स्तर विशेष कर पूँजी प्रधान तकनीकी का प्रयोग किया जाना।	तकनीकी द्वैतवाद, मुख्यतया श्रम प्रधान तकनीकी का प्रयोग किया जाना।
5.	जनसंख्या	सन्तुलित जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या का अधिक प्रतिशत	जन्म-दर ऊँची व मृत्युदर का कम होना अकार्यशील जनसंख्या का अधिक प्रतिशत।
6.	रोजगार	लगभग पूर्ण रोजगार	व्यापक बेरोजगारी संरचनात्मक एवं अदृश्य बेरोजगारी।
7.	बचत निवेश	राष्ट्रीय आय के अनुपात में बचत तथा निवेश का उच्च स्तर।	राष्ट्रीय आय के अनुपात में बचत तथा निवेश का नीचा स्तर
8.	प्राकृतिक साधन	पर्याप्त प्राकृतिक साधन और उनका पूर्ण शोषण किया जाना।	पर्याप्त प्राकृतिक साधन, परन्तु पूर्ण विदोहन सम्भव न होना।
9.	निर्यात	निर्यात पर कम निर्भरता	निर्यात पर अधिक निर्भरता
10.	पूँजीनिर्माण	प्रति व्यक्ति ऊँचा पूँजी अनुपात	प्रति व्यक्ति कम पूँजी अनुपात

यद्यपि उपरोक्त विवरण से विकसित और अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था में अन्तर स्वत: स्पष्ट तथा विद्यार्थियों की सुविधा हेतु हमने विभिन्न विकास अंगों के रूप में इन दोनों प्रकार की अर्थ व्यवस्थाओं में अन्तर का एक संक्षिप्त सार प्रस्तुत किया है।

प्र.3. आर्थिक विकास में तकनीक की भूमिका बताइए।

State the role of technology in economic development.

उत्तर

आर्थिक विकास में तकनीक की भूमिका

(Role of Technology in Economic Development)

आधुनिक तकनीक का इतिहास पश्चिमी देशों में औद्योगिक क्रान्ति रेवुलेशन के साथ आरम्भ हुआ। नए वैज्ञानिक आविष्कारों का आरम्भ होने पर, उद्यमियों ने नए अविष्कार शुरू किये और जल्दी ही बाजार में नई वस्तुओं का आना शुरू हुआ। औद्योगिक रेवुलेशन आरम्भ होने के बाद नए-नए आविष्कारों का आरम्भ हुआ और प्रतियोगिता के दौर में उत्पादकों के बीच विकसित तकनीक अपनाने में होड़ लग गई और उपभोक्ताओं के लिए अच्छी किस्म के उत्पाद मिलने शुरू हो गए। धीरे-धीरे यह

TOUCH n PASS

प्रतियोगिता राष्ट्रीय चार दीवारी से बाहर निकलकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में प्रवेश हुई और अधिक विकसित तकनीक से बने उत्पाद का एक देश से दूसरे देश के बीच व्यापार शुरू हुआ। पश्चिमी देशों में समूचे उत्पादन में तकनीक प्रभाव देखने को मिला और अधिक तकनीक का विकास हुआ। विकास एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जो नई तकनीक के लगातार प्रयोग पर निर्भर करती है। पश्चिमी देशों के अभ्यास इस तर्क की सच्चाई का एक उदाहरण है। पश्चिमी संसार में आविष्कार दो तरह का काम करते हैं लागत कम करना व माँग बढ़ाना। प्रारम्भिक समय में आविष्कार व खोज उत्पादन की लागत कम कर वस्तुओं, उपभोक्ता को बाजार में लाते हैं। जैसे उपभोक्ता नई वस्तुओं की माँग बढ़ाते हैं। इससे माँग दबाव बढ़ जाता है और यह उद्यमी को नए तथा उत्तम उत्पादन बढ़ाने में उत्साहित करता है। पश्चिमी देशों में उपभोक्ताओं की बढ़ी माँग आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। जिससे औद्योगिक वस्तुओं का बाजार लगातार बढ़ता है।

आर्थिक विकास से तकनीक की भूमिका के बारे में जापान का उदाहरण दे सकते हैं। Cairn Cross ने महसूस किया है कि इस देश में आर्थिक वृद्धि शुरू होने से पहले, यह दूसरे देशों की तरह कृषि पर निर्भर करता था। जापान की 75 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती थी। यद्यपि यह दूसरे अल्पविकसित देशों की अपेक्षा आर्थिक पिछड़ापन में अलग था। अधिकतर जापानी विकसित देशों से तकनीकी ज्ञान दिखाने के लिए गए, विदेशी यन्त्र व तरीके अपनाकर नए उद्योगों का आरम्भ हुआ। इस सन्दर्भ में तकनीक के महत्त्व को आसानी से महसूस कर सकते हैं।

तकनीक के धनात्मक (Positive) प्रभाव के साथ विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। तकनीकी आविष्कार का सबसे नकारात्मक प्रभाव है यह श्रम को बाहर करना तथा इससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। यद्यपि अधिकतर अर्थशास्त्री इस सम्भावना को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार तकनीक परिवर्तन से श्रम लागत कम होगी, लागत कम होने पर उपभोक्ता उत्पादन की तरफ आकर्षित होंगे। यदि उत्पादन की माँग लोच है तो माँग बढ़ने पर रोजगार भी बढ़ेगा। अब वस्तु कम कीमत पर उपलब्ध है, इसकी वजह से उपभोक्ता दूसरी वस्तुओं पर खर्च करने के लिए रुपए बचा लेंगे। लेकिन माँग अलोच है तो मजदूर रोजगार से बाहर होंगे लेकिन अब कम कीमत पर वस्तु उपलब्ध है तो दूसरे उद्योगों की वस्तुओं की माँग बढ़ेगी व रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा दूसरे उद्योगों में रोजगार बढ़ेगा। यह तर्क दिया गया है कि दीर्घकालीन तकनीक बेरोजगार सम्भव नहीं। यद्यपि यह तर्क व्यापार संघों ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि उन्हें चिन्ता है कि अल्पकाल में श्रम बेरोजगार होगा। उनका मानना है तकनीक का भार मजदूरों को ही सहन करना पड़ता है चाहे यह अल्पकाल के लिए ही क्यों न हो।

तकनीक परिवर्तन की वकालत करने वाले लागों का मत है तकनीक से कुछ श्रमिकों पर प्रभाव पड़ता है लेकिन यह पूरी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए लाभदायक है। दूसरे जोखिम की तरह, तकनीक परिवर्तन भी एक जोखिम है जो बदलती या बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। यद्यपि तकनीक परिवर्तन का यह तर्क उद्यमी व श्रमिक पर पड़ने वाले प्रभाव को वर्णित नहीं करता। उद्यमी के पास फालतू पैसा है वह नुकसान को सहन करने की क्षमता नहीं होती। इसलिए तकनीक परिवर्तन उद्यमी के लाभ व हानि का निर्णय करता है। लेकिन मजदूरी प्रभावित होने पर यह श्रमिक के जन्म मरण का सवाल है। इसलिए दोनों को एक तराजू पर नहीं तोल सकते। मजदूरों को उद्यमी की बजाय ज्यादा सहन पड़ता है।

तकनीक उन्नति व आविष्कार सामाजिक आर्थिक माहौल में परिवर्तन लाती है। बढ़ते हुए शहरी व औद्योगिकरण की वजह से जीवन स्तर बढ़ता है और उन्नति के लिए चारों तरफ दरवाजें खुलते हैं। यद्यपि साथ-साथ वातावरण दूषित तथा पर्यावरण की समस्या असुरक्षा बढ़ना तथा पुरानी कारीगरी खत्म होती है। आदमी मशीन की तरह बन जाता है और तेज बदलती जिन्दगी में अपना अस्तित्व खो देता है। विकसित देशों में औद्योगिकरण तथा तकनीक विकास को देखते हुए अल्प विकसित देश भी इसको अपनाने में पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि तकनीक में ही उन्हें आर्थिक विकास की आशा दिखाई देती है। उनका मानना है कि जब तक तकनीक परिवर्तन स्थिर रहते हैं। अर्थव्यवस्था में पिछड़ापन, जनसंख्या का अधिक भाग का जीवन स्तर नीचा, अकाल इत्यादि से छुटकारा नहीं मिलता।

प्र.4. गरीबी अथवा निर्धनता का अर्थ अथवा अवधारणा लिखिए।
Write the meaning or concept of poverty.

उत्तर

गरीबी अथवा निर्धनता का अर्थ अथवा अवधारणा
(Meaning or Concept of Poverty)

आज सरकार, राजनीतिज्ञ, समाज-सुधारक, आदि सभी गरीबी के बारे में बात करते हैं। लेकिन सभी को गरीबी के सही अर्थ का बोध नहीं होता है। प्राय: गरीबी का आशय लोगों के निम्न जीवन-स्तर से लगाया जाता है। जीवन-स्तर सापेक्ष अथवा निरपेक्ष दृष्टि से देखा जा सकता है। इसलिए गरीबी की धारणा को दो रूपों में व्यक्त किया जा सकता है।

1. निरपेक्ष गरीबी 2. सापेक्ष गरीबी

1. **निरपेक्ष गरीबी** (Absolute Poverty)—"एक व्यक्ति की निरपेक्ष गरीबी से अर्थ है कि उसकी आय या उपभोग व्यय इतना कम है कि वह न्यूनतम भरण-पोषण स्तर के नीचे स्तर पर रह रहा है।" इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि "गरीबी से अर्थ मानव की आधारभूत आवश्यकताओं—खाना, कपड़ा, स्वास्थ्य सहायता, आदि की पूर्ति हेतु पर्याप्त वस्तुओं व सेवाओं को जुटा पाने में असमर्थता से है।"
इस तरह यह कहा जा सकता है कि "गरीबी से अर्थ उस न्यूनतम आय से है जिसकी एक परिवार के लिए आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यकता होती है तथा जिसे वह परिवार जुटा पाने में असमर्थ होता है।" इस गरीबी को निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। जो परिवार उस न्यूनतम आय को जुटा पाने में असमर्थ होता है। तब कहा जाता है कि वह परिवार गरीबी रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत कर रहा है।
2. **सापेक्ष गरीबी** (Relative Poverty)—सापेक्ष गरीबी आय की असमानताओं के आधार पर परिभाषित की जाती है। इस सम्बन्ध में विभिन्न वर्गों या देशों के निर्वाह-स्तर अथवा प्रति व्यक्ति आय की तुलना करके गरीबी का पता लगाया जाता है। जिस वर्ग या देश के लोगों का जीवन-स्तर या प्रति व्यक्ति आय का स्तर नीचा रहता है। वे उच्च निर्वाह स्तर या प्रति व्यक्ति आय वाले लोगों की तुलना में गरीब माने जाते हैं। निर्वाह-स्तर को आय एवं उपभोग-व्यय के आधार पर मापा जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए भारत में 2020 में प्रति व्यक्ति आय जापान की तुलना में 75 गुना और अमेरिका की तुलना में 68 गुना कम थी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जापान या अमेरिका के औसत नागरिक की अपेक्षा भारतीय उतने गुना गरीब हैं।

प्र.5. गरीबी के कारणों का उल्लेख कीजिए।
Explain the causes of poverty.

उत्तर

गरीबी के कारण
(Causes of Poverty)

गरीबी के लिए उत्तरदायी कारणों में से प्रमुख निम्नलिखित हैं।

1. **रोजगार के अवसरों में धीमी वृद्धि**—श्रमिकों की संख्या में तेजी से होती वृद्धि रोजगार अवसरों में कमी उत्पन्न करती हैं। ऐसा होने के दो कारण रहे। एक अपर्याप्त पूँजी निर्माण के फलस्वरूप अपेक्षित मात्रा में उत्पादक रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो सकें। तथा दूसरे, देश में पूँजी-प्रधान उत्पादन तकनीक अपनाए जाने से श्रम-प्रधान कार्यकलापों का अधिक तेजी से विस्तार नहीं हो सका। फलस्वरूप बेरोजगारी बढ़ी और अल्प रोजगार में लगे व्यक्तियों की संख्या में भी वृद्धि हुई। ऐसी स्थिति में गरीबी का फैलना स्वाभाविक हैं।
2. **निम्न आय अर्जक परिसम्पत्तियाँ**—रोजगार की कमी के कारण जहाँ मजदूरी नहीं बढ़ सकी, वहाँ आय-अर्जक परिसम्पत्तियों के अभाव में मजदूरी के अलावा आय का अन्य स्रोत भी नगण्य रहा। देश में आय वितरण की असमानता के फलस्वरूप गरीब व्यक्तियों के पास परिसम्पत्तियाँ न के बराबर हैं।
3. **कमाई या अर्जन का स्तर निम्न**—सामान्यतया जिन कार्यों में निर्धन व्यक्ति कार्यरत होते हैं। वहाँ अक्सर मजदूरों का शोषण होता है और उन्हें मजदूरी कम प्राप्त होती है। ऐसा विशेष रूप से अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में होता है, जैसे खेती, लघु उद्योग आदि। इन क्षेत्रों में श्रमिक संघ के रूप में संगठित नहीं हैं। इस कारण मालिक मजदूरों का शोषण करने और कम मजदूरी देने में सफल हो जाते हैं।
4. **जनसंख्या में भारी वृद्धि**—जनसंख्या में होने वाली भारी वृद्धि भी गरीबी की स्थिति को गम्भीर बनाने में सहायक है। जनसंख्या वृद्धि से गरीबों के उपभोग स्तर पर प्रतिकूल (Adverse) प्रभाव पड़ता है तथा उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती है। इनकी आय का लगभग सम्पूर्ण भाग परिवार के पालन पोषण पर व्यय हो जाता है और इस तरह बचत और निवेश के लिए इनके पास कुछ नहीं बचता। इससे पूँजी निर्माण और आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ जाती है। परिणामस्वरूप गरीबी की समस्या और उलझ जाती हैं।
5. **दोषपूर्ण विकास-रणनीति**—देश में गरीबी और आय-विषमताओं के लिए विकास की रणनीति भी बहुत हद तक उत्तरदायी है। उदाहरणार्थ, देश में पूँजीगत वस्तुओं के निर्माण पर अधिक बल दिया गया जिसके कारण पूँजी-गहन परियोजनाओं में निवेश अधिक हुआ और रोजगार के अवसर कम सृजित हुए। उपभोग वस्तुओं के उत्पादन पर ध्यान कम

TOUCH 'n' PASS

दिए जाने से उपभोग वस्तुओं का अभाव हो गया। उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि से आय एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सकती थी। इन सबका सम्मिलित प्रभाव यह हुआ कि देश में बेरोजगारी बढ़ी और आय कम होने से गरीबी की समस्या में वृद्धि हो गयी।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. अल्पविकसित तथा विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
Describe the characteristic of underdeveloped and development economy.

उत्तर

अल्पविकसित तथा विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ
(Characteristics of Underdeveloped and Developed Economy)

एक विकासशील या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश में कौन-सी आधारभूत विशेषताएँ पायी जाती है। इस सम्बन्ध में सर्वमान्य विशेषताएँ (Features) बताना कठिन है। इसका कारण यह है कि भिन्न-भिन्न विकासशील या अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में भिन्न-भिन्न विशेषताएँ पाई जाती हैं। मानर एवं बाल्डबिन ने अपनी पुस्तक *"Economic Development"* में अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के छः आधारभूत लक्षण बताये हैं—

1. प्राथमिक उत्पादन की प्रधानता
2. जनसंख्या दबाव
3. अल्प विकसित प्राकृतिक साधन
4. जनसंख्या का आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा होना।
5. पूँजी का अभाव (Scarcity of Capital)
6. विदेशी व्यापार की उन्मुखता।

हार्वे लिबिन्सटीन ने अल्प विकसित देशों की चार विशेषताएँ बताई हैं—

1. आर्थिक
2. जनसंख्या सम्बन्धी
3. प्राविधिक
4. सांस्कृतिक एवं राजनीतिक।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमने एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को छः भागों में बाँटा हैं—

1. आर्थिक विशेषताएँ
2. जनसंख्या सम्बन्धी विशेषताएँ
3. तकनीकी विशेषताएँ
4. सामाजिक विशेषताएँ
5. राजनीतिक विशेषताएँ
6. अन्य विशेषताएँ

I. आर्थिक विशेषताएँ (Economic Characteristics)

1. **कृषि की प्रधानता**—अल्प विकसित देशों की सबसे प्रमुख विशेषता अधिकांश जनता का कृषि में लगे रहना है। यहाँ कृषि से अर्थ कृषि, बागवानी, जंगल कटाई, पशुपालन व मछली पालन आदि से है। भारत, इण्ड्रोनेशिया, पाकिस्तान, आदि देशों को अल्प विकसित माना जाता है, क्योंकि भारत की 51.2 प्रतिशत जनसंख्या, इण्ड्रोनेशिया की 57 प्रतिशत जनसंख्या और पाकिस्तान की 56 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी है, जबकि विकसित देश फ्रांस, कनाडा, अमेरिका एवं ब्रिटेन की कुल जनसंख्या का प्रतिशत बहुत कम है। जैसे फ्रांस की 5 प्रतिशत, कनाड़ा की 3 प्रतिशत, अमेरिका की 1 प्रतिशत व ब्रिटेन की 2 प्रतिशत। यही कारण है कि अल्प विकसित देशों की राष्ट्रीय आय, निर्यात व्यापार व उद्योग कृषि पर आधारित होते हैं।
2. **प्राकृतिक साधनों का अल्प उपयोग**—अल्प विकसित देशों में प्राकृतिक साधनों के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के बाद भी उनका उपयोग या तो होता ही नहीं है और यदि होता भी है तो बहुत ही कम मात्रा में। कभी-कभी तो अल्प विकसित देशों को इस बात का पता ही नहीं होता कि उनके देश में प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं।
3. **प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर**—इन देशों में प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न होता है। 2022 में, भारत की प्रति व्यक्ति आय 2389 यूएस डॉलर है, जबकि भारत की तुलना में प्रति व्यक्ति आय अमेरिका में 2023 में 64187 यूएस डॉलर और जापान में 2022 में 33,853.8 यूएस डॉलर यूएस है।
4. **पूँजी निर्माण का निम्न स्तर**—यहाँ पूँजी निर्माण का स्तर निम्न है। अल्प विकसित देशों में घरेलू निवेश की दर राष्ट्रीय आय की 5 से 10 प्रतिशत तक होती है, जबकि विकसित देशों में यह 20 से 25 प्रतिशत तक की होती है। वर्तमान में भारत में पूँजी निर्माण की दर 39.1 प्रतिशत है।

TOUCH 'n PASS

5. **सम्पत्ति एवं आय वितरण में असमानता**—अल्प विकसित देशों में राष्ट्रीय सम्पत्ति एवं आय का बहुत बड़ा भाग कुछ ही व्यक्तियों के अधिकार में होता है, जबकि जनसंख्या के बड़े भाग को सम्पत्ति एवं आय का छोटा-सा हिस्सा मिल पाता है।
6. **औद्योगिक पिछड़ापन**—अल्प विकसित देश औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं। इसका अर्थ यह है कि यहाँ आधारभूत उद्योगों का अभाव होता है। यहाँ कुछ उद्योग जो उपभोक्ता वस्तु या कृषि वस्तु बनाते हैं उनका ही विकास हो पाता है। औद्योगिक पिछड़ेपन की पुष्टि इस अनुमान से हो जाती है कि 74 प्रतिशत जनसंख्या वाले देश विश्व औद्योगिक उत्पादन में केवल 20 प्रतिशत का ही योगदान देते हैं शेष 80 प्रतिशत उत्पादन विकसित देशों में ही होता है।
7. **अल्प रोजगार व बेरोजगारी**—इन अल्प विकसित देशों में अल्प रोजगार के साथ-साथ बेरोजगारी भी होती है जिन लोगों को काम मिला हुआ होता भी है उनको भी पूरे समय के लिए काम नहीं मिलता है। इन देशों में कुछ लोग सदा ही बेरोजगार बने रहते हैं। उनके लिए समाज के पास कोई कार्य नहीं होता है। इसका मुख्य कारण औद्योगीकरण की कमी एवं पूँजी निवेश का अभाव है।
8. **बैंकिंग सुविधाओं का अभाव**—अल्प विकसित देशों में बैंकिंग सुविधाओं का अभाव रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बैंकिग सुविधाएँ ही कम होती हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अल्प विकसित देशों में यह प्रतिशत 60 तक होता है।
9. **आर्थिक दुष्चक्र**—अल्पविकसित देशों में आर्थिक दुष्चक्रों की प्रधानता रहती है। वहाँ पूँजी की कमी से उत्पादन कम होता है। इससे वास्तविक आय कम होती है। अत: वस्तुओं की माँग कम रहती है। इन सबका परिणाम यह होता है कि साधनों का उचित विकास नहीं हो पाता है इस प्रकार यह कुचक्र चलता रहता है और इससे अर्थव्यवस्था निरन्तर प्रभावित होती रहती है।
10. **विदेशी व्यापार में अस्थिरता**—अल्प विकसित देशों के कच्चे माल का निर्यात व पक्के माल का आयात किया जाता है। कच्चे माल की वस्तुओं के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिर नहीं रहते हैं। इससे विदेशी मुद्रा अर्जन में घटा-बढ़ी होती रहती है जिससे देश की अर्थव्यवस्था भी स्थिर नहीं रहती है।
11. **ऊँची जन्म व मृत्यु दरें**—अल्प विकसित देशों में जन्म दर व मृत्यु दर अपेक्षाकृत ऊँची रहती है। एक अनुमान के अनुसार विकसित देशों में जन्म दर व मृत्यु दर क्रमश: 15 से 20 प्रति हजार व 9 से 10 प्रति हजार होती है, जबकि अल्प विकसित देशों में यह दरें क्रमश: 30 से 40 प्रति हजार व 15 से 30 प्रति हजार तक होती हैं। अल्प विकसित देशों में ऊँची जन्म दर के कारण हैं—सामाजिक धारणा एवं विश्वास, पारिवारिक मान्यता बाल विवाह, विवाह की अनिवार्यता, भाग्यवादिता, मनोरंजन सुविधाओं का अभाव, निम्न आय व निम्न जीवन-स्तर, निरोधक सुविधाओं का अभाव आदि। इसी प्रकार यहाँ ऊँची मृत्युदर के कारण हैं—अकाल व महामारी, लोक स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, स्त्री शिक्षा का अभाव, पौष्टिक आहार का अभाव आदि। भारत में वर्तमान में जन्म दर 23.1 व मृत्युदर 7.4 प्रति हजार है।
12. **ग्रामीण जनसंख्या की अधिकता**—अल्प विकसित देशों में अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। भारत की 65 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में व शेष शहरों में रहती है।
13. **जनसंख्या का आधिक्य**—अल्प विकसित देशों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। जबकि विकसित देशों में उतना नहीं होता है। साथ ही अल्प विकसित देशों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। अत: यहाँ जनसंख्या का आकार व घनत्व अधिक होता है।
14. **आश्रितों की अधिकता**—अल्प विकसित देशों में एक परिवार में आश्रितों की मात्रा अधिक होती है। इसका अर्थ यह है कि इन देशों में कमाने वाले कम होते हैं, जबकि खाने वाले अधिक। इसका कारण यह है कि यहाँ बच्चों व बूढ़ों की संख्या विकसित देशों की तुलना में अधिक होती है।
15. **अकुशल जनशक्ति की अधिकता**—अल्प विकसित देशों में अकुशल जनशक्ति की अधिकता रहती है। इसके कारण शिक्षा व प्रशिक्षण का अभाव, प्रति व्यक्ति निम्न आय, संयुक्त परिवार प्रणाली, रूढ़िवादिता, भाग्यवादिता, आत्मसन्तोष की भावना आदि हैं।

TOUCH 'n PASS

II. सामाजिक विशेषताएँ (Social Characteristics)

16. **साक्षरता की कमी**—अल्प विकसित देशों में साक्षरता की कमी पायी जाती है। दूसरे शब्दों में, इन देशों में व्यापक निरक्षरता होती है। जिसका प्रतिशत 70 या इससे भी ऊपर होता है। विकसित देशों में निरक्षरता का प्रतिशत 5 से भी कम होता है। इस निरक्षरता के कारण ही यहाँ के निवासी रूढ़िवादी, अन्धविश्वासी एवं भाग्यवादी होते हैं। जो नवीन परिवर्तनों का धर्म के नाम पर विरोध करते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की दर 64.3 प्रतिशत है।
17. **जातिवाद**—इन देशों में वर्ग भेद व जातिवाद की भावना व्याप्त होती है। जिसके परिणामस्वरूप यहाँ के व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति भिन्न-भिन्न होती है तथा प्रत्येक जाति की अपनी परम्पराएँ एवं रीति रिवाज होते हैं।
18. **रीति रिवाज की प्रधानता**—अल्प विकसित देशों में रीति-रिवाज की प्रधानता होती है जिनको प्रत्येक व्यक्ति आँखे मूँदकर मानता है और समय-समय पर उन्हीं रिवाजों के अनुसार कार्य करता है। जिसका परिणाम यह होता है कि फिजूलखर्ची को बढ़ावा मिलता है जिससे निवासी निर्धन व ऋणग्रस्त बने रहते हैं।
19. **स्त्रियों को निम्न स्थान**—अल्प विकसित देशों में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं होती है, उनका समाज में कोई महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं होता है। उन्हें कार्य करने की स्वतन्त्रता नहीं होती है। उनमें साक्षरता भी कम होती है। वे अपना पेट भरने के लिए पुरुषों पर निर्भर रहती हैं।

III. राजनीतिक विशेषताएँ (Political Characteristics)

20. **अधिकारों के प्रति ज्ञान न होना**—अल्प विकसित देशों में जनता अपने अधिकारों के प्रति ज्ञानवान नहीं होती है। अत: उसमें अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं पायी जाती है। इसका कारण यह है कि यहाँ के लोग अपनी दरिद्रता को ईश्वरीय देन मानते हैं।
21. **दुर्बल राष्ट्र**—अल्प विकसित देश विकसित देशों के मुकाबले दुर्बल होते हैं। और ऐसे देशों पर सदा ही विदेशी राष्ट्रों का आधिपत्य किसी न किसी रूप में बना रहता है।
22. **आधुनिक सेना का अभाव**—ऐसे देशों के पास आधुनिक अस्त्रों से लैस सेना का अभाव होता है।
23. **प्रशासनिक अकुशलता**—इन राष्ट्रों में प्रशासनिक कुशलता एवं ईमानदारी का अभाव होता है। राजनीतिक नेता भी इस सम्बन्ध में कोई अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते हैं। अत: यहाँ कालाबाजारी, भ्रष्टाचार व बेइमानी विस्तृत रूप में पायी जाती है।

IV. अन्य विशेषताएँ (other Characteristics)

24. **दोषपूर्ण वित्तीय संगठन**—अल्प विकसित देशों में वित्तीय संगठन दोषपूर्ण होता है। इन देशों में परोक्ष कर अधिक लगाये जाते हैं। मुद्रा बाजार असंगठित होता है। बैंकिंग व्यवस्था प्रभावशाली नहीं होती है। सरकारी आय के साधन भी सीमित होते हैं।
25. **स्थिर व्यावसायिक ढाँचा**—इन देशों में व्यावसायिक ढाँचा स्थिर रहता है। इसका अर्थ यह है कि इन देशों ने व्यवसायिक ढाँचा एक जैसा रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है।

प्र.2. फाई-रेनिस के आर्थिक विकास के सिद्धान्त की विवेचना कीजिए।
Discuss the fei-Ranis model of economic development.

उत्तर फाई के अनुसार एक विकासशील अर्थव्यवस्था गतिहीन की स्थिति से सेल्फ सस्टेंड विकास की ओर जाने की आशा रखती है। फाई ने अपने सिद्धान्त में दो क्षेत्रों कृषि व उद्योग को लिया है।

कृषि क्षेत्र
(Agricultural Sector)

कृषि क्षेत्र में जनसंख्या दबाव से प्राकृतिक साधनों की कमी (भूमि का दोहन होना) हो जाती हैं। तकनीक स्थिरता के कारण कृषि पर भूमि पर घटते प्रतिफल के नियम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिसको निम्नलिखित चित्र से वर्णित किया गया है। भूमि को Y-अक्ष पर तथा श्रम को X-अक्ष पर लिया गया है। कृषि की प्रक्रिया में श्रम तथा भूमि द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया गया है। उत्पादन रेखा M, M^1, M^{11} द्वारा दर्शाई गई है। OV और OU रेखा क्षेत्र में उत्पादन के साधनों में बदलाव (Substitution)

TOUCH 'n PASS

को दर्शाती है। जो इस क्षेत्र के भीतर ही बदल सकते हैं। बाहर नहीं। उत्पाद वक्र OV रेखा के नीचे पूर्ण रूप से अनुलम्ब (Horizontal) हैं। जो बताता है कि भूमि सीमित है। इसलिए श्रम की मात्रा बढ़ने पर लम्बे समय तक उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती है। चित्र में जब भूमि की मात्रा ot पर स्थिर है। जो ts तक रम को बढ़ाया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में कुल रम te दी गई है इसलिए कृषि क्षेत्र में रम की मात्रा es इकाई के बराबर है जो redunt है और श्रम की मात्रा जो st के बराबर है। वो non-redundant है। (चित्र 1 में दर्शाया गया है।)

"Labour Utilization Ratio" $R = ts/ot$

(श्रम प्रयोग करने की दर)

जो रिज रेखा (ov) से नीचे है।

हम यह मानते है कि श्रम की कुल पूर्ति (te) इकाई के बराबर है। जिसकी (ts) श्रम की इकाई non redundant है तथा se इकाई redundant है ts/te के अनुपात को non-redundancy coefficient जो T के बराबर है।

$$\therefore \quad T = st/te$$

R = श्रम प्रयोग का अनुपात

S = जनसंख्या घनत्व

T का सम्बन्ध R से सीधा है। तथा S से विपरीत है।

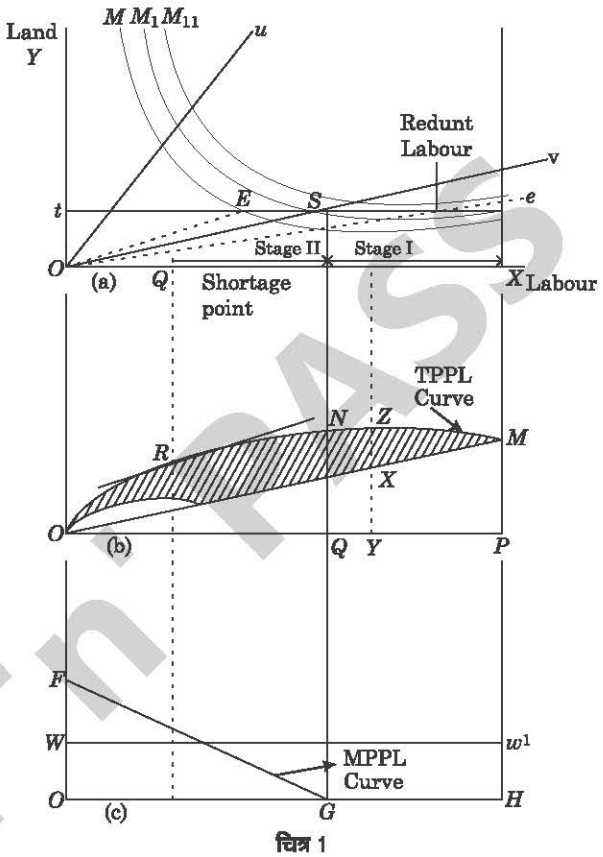

चित्र 1

चित्र (b) तथा (c) में श्रम की कुल भौतिक उत्पादकता (TPPL) श्रम की सीमान्त भौतिक उत्पादकता (MPPL) हैं। चित्र (b) दिखाता है कि (TPPL) घटती दर से बढ़ता है जब भूमि के निश्चित भाग पर अधिक से अधिक श्रम लगाई जाए। N बिन्दु पर वक्र अनुलम्ब (horizontal) हो जाता है। तथा चित्र (c) में g तक पहुँचता है। और G पर MPPL शून्य हो जाती है। G व N रेखा बिन्दु पर क्षैतिज (vertically) है जो ov रिज लाइन पर है।

उद्योग क्षेत्र
(Industrial Sector)

कृषि क्षेत्र में भूमि तथा श्रम को प्रयोग किया गया है। तथा उद्योग क्षेत्र में पूँजी तथा श्रम का प्रयोग किया है। निम्नलिखित चित्र द्वारा उद्योग क्षेत्र में पूँजी, श्रम उत्पादन को दर्शाया है। श्रम का माप अनुलम्ब अक्ष तथा पूँजी का माप तथा पूँजी को क्षैतिज अक्ष पर दिखाया है। Q_0, Q_1 तथा Q_2 उत्पादन को दर्शाती है। रेनिस फाई कृषि तथा औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में स्थिर प्रतिफल की दर मान कर चलता है। उद्योग क्षेत्र में विस्तार (Expansion path) को सीधा रेखा OA_0, A_1, A_2 तथा पूँजी विस्तार K_0 से K_1 से K_2 है। श्रम का विस्तार L_0 से L_1 से L_2 है। जो उद्योग में उत्पादन को Q_0 से Q_1 से Q_2 बढ़ाती हैं।

रेनिस का मानना है कि उद्योग क्षेत्र की उपलब्धता कृषि क्षेत्र से होती है।

चित्र (b) में उद्योग क्षेत्र में श्रम के पूर्ति वक्र को $PP_0P_1P_2S$ दिखाया गया है। जो चित्र (a) में क्षैतिज है। चित्र (b) में उद्योग में श्रम की पूर्ति को अनुलम्ब अक्ष पर मापा है जबकि वास्तविक मजदूरी (उद्योग सामान में) क्षैतिज अक्ष पर मापी गई है। श्रम का पूर्ति अनुलम्ब वक्र कृषि क्षेत्र से उद्योग क्षेत्र में श्रम की मात्रा दर्शाता है। इसकी वजह से उद्योग क्षेत्र की वास्तविक मजदूरी OP पर स्थिर रहती है P_2 बिन्दु पर वक्र ऊपर की तरफ से उठता है। जिससे इस बिन्दु के पश्चात श्रम की पूर्ति वास्तविक मजदूरी बढ़ाने पर ही बढ़ाई जा सकती है।

TOUCH 'n PASS

पूँजी संचय K_0, K_1, K_2 के द्वारा श्रम की सीमान्त भौतिक उत्पादकता वक्र (MPPL) खिंचा गया है। KO पूँजी संचय पर (MPPL) श्रम की सीमान्त भौतिक उत्पादकता वक्र MO है। जब पूँजी संचय Ko से K_1 बढ़ता है। तो MPPL, M_1 हो जाता है सन्तुलन कि स्थिति में MPPL वक्र उद्योग पूर्ति वक्र को P_0, P_1, P_2 पर काटता हैं। जब पूँजी संचय Ko हैं तो सन्तुलन की स्थिति Po है। रेनिस का मानना है कि आय स्तर के कम होने की वजह से उद्योग में काम करने वाले मजदूर कुछ नहीं बचा पाते। इसलिए निवेश का अधिक भाग उद्योगों के लाभ से किया जाता है।

नए पूँजी संचय की वजह से नया MPPL वक्र बनाया है। जो P_1 पर नया सन्तुलन स्थापित करता है। जिससे उद्योग क्षेत्र में रोजगार बढ़कर L_0, से L_1 हो जाता है जिससे निवेश तथा रोजगार की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है।

कृषि तथा उद्योग के अतिरेक की प्रक्रिया भी वर्णन करती है। रेनिस के मॉडल में कृषि की भूमिका मूल है। पूँजी संचय में वृद्धि होने पर श्रम की मात्रा कृषि से उद्योग क्षेत्र में स्थानान्तरित हो जाती है। इसलिए श्रम शक्ति, भोजन तथा कच्चा माल उद्योग क्षेत्र के लिए आग का काम करती है। रेनिस फाई दोहरी अर्थव्यवस्था की भी बात करता है जिसमें दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं और सन्तुलित विकास के लिए दोनों में एक साथ निवेश आवश्यक है।

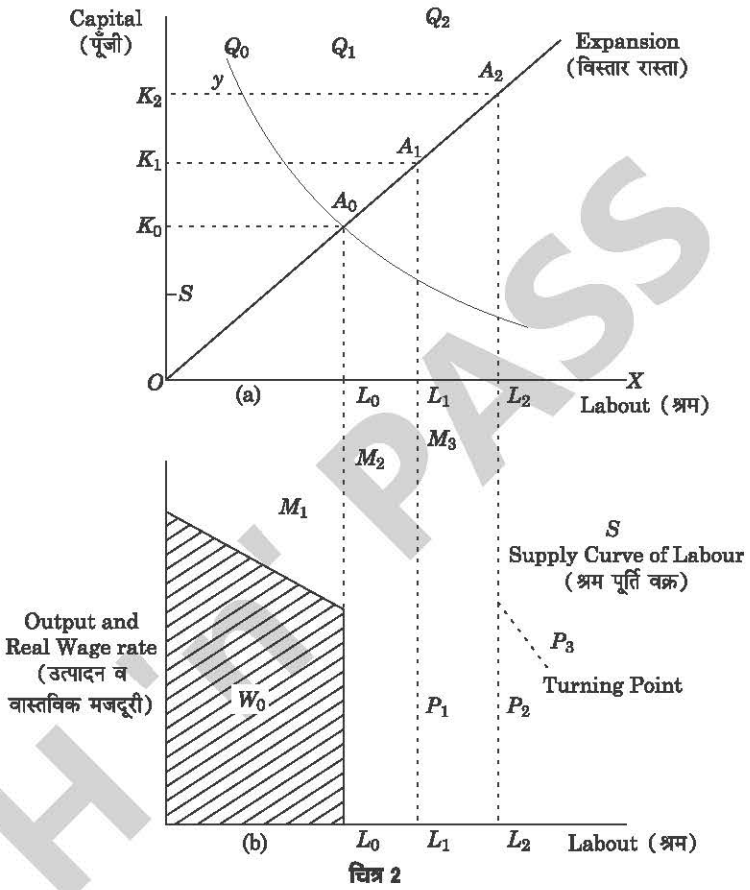

चित्र 2

रेनिस के सिद्धान्त की सीमाएँ
(Limitations of the Fei Ranis Model)

1. रेनिस मानता है कि प्रारम्भिक अवस्था में कृषि की सीमान्त भौतिक उत्पादकता शून्य है। इससे जनसंख्या का अधिक हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में स्थानान्तरित हो जाता है। यह अवस्था अल्पकालीन अवस्था है जो दीर्घकाल में सम्भव नहीं।
2. रेनिस मानते है कि भूमि की पूर्ति स्थिर है लेकिन जनसंख्या बढ़ने पर घटिया भूमि का भी प्रयोग किया जाता है इसलिए यह स्थिर नहीं रहती।
3. रेनिस श्रम मजदूरी तथा घरेलू मजदूरी में अन्तर नहीं करते। लेकिन अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में कीमत के बगैर दोहरी अर्थव्यवस्था के बारे में पूर्ण जानकारी सम्भव नहीं। यह भी तर्क दिया गया है कि भौतिक पूँजी के लिए मुद्रा का स्थानापन्न ठीक नहीं है। इसलिए कि एक स्तर पर मुद्रा तथा भौतिक पूँजी एक-दूसरे के समरूपक हैं।
4. रेनिस का विश्लेषण बन्द अर्थव्यवस्था की धारणा पर आधारित है। लेकिन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था बन्द न होकर खुली अर्थव्यवस्था है जहाँ कमी होने पर कृषि वस्तुओं को आयातित किया जाता है।
5. रेनिस मानते है कि कृषि उत्पादकता में वद्धि होने के बावजूद पहली दो अवस्थाओं में संस्थानिक मजदूरी स्थिर रहती है। लेकिन यह तर्क ठीक नहीं है क्योंकि कृषि उत्पादन में सामान्य वृद्धि होने पर मजदूरी अवश्य बढ़ेगी। उदाहरण के तौर पर

TOUCH 'n' PASS

हरियाणा तथा पंजाब में हरित क्रान्ति लागू हुई थी। सर्वेक्षण से पता चलता है इसके लागू करने के बाद कृषि वर्ग के लिए श्रमिक मजदूरों की दैनिक वास्तविक मजदूरी में सुधार हुआ है।

6. कृषि का व्यापारीकरण होने पर स्फीतिकारी दबाव शुरू हो जाते हैं। जब श्रमिक वर्ग कृषि क्षेत्र से उद्योग क्षेत्र में स्थानान्तरित हो जाता है जो कृषि क्षेत्र में श्रम की कमी महसूस होती है। इसी प्रकार स्थानान्तरित मजदूरी श्रमिकों की सीमान्त उत्पादकता के बराबर होती है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र में वस्तुओं की कमी से स्फीतीकारक दबाव पैदा होते हैं।

प्र.3. प्रौद्योगिकीय द्वैतवाद की विस्तृत व्याख्या कीजिए।
Write a long note on technological dualism.

उत्तर

प्रौद्योगिकीय द्वैतवाद
(Technological Dualism)

बूके के सामाजिक द्वैतवाद के विकल्प के रूप में प्रोफेसर हिग्गिन्ज ने प्रौद्योगिकीय द्वैतवाद का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। प्रौद्योगिकीय द्वैतवाद का आशय है। एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के विकसित तथा परम्परागत क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादन फलनों का प्रयोग। इस तरह के द्वैतवाद ने औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक प्रौद्योगिकीय बेरोजगारी और देहाती क्षेत्र में अल्प-रोजगार की समस्या को बढ़ाया है। हिग्गिन्ज का प्रौद्योगिकीय द्वैतवाद का सिद्धान्त ऐकॉस (R. S. Eckaus) द्वारा विवेचित साधन अनुपातों की समस्या को शामिल करता है और उन सीमित उत्पादकीय रोजगार सुविधाओं से सम्बन्ध रखता है। जो मार्किट अपूर्णताओं, विभिन्न साधन-सम्पन्नताओं और उत्पादन फलनों के कारण अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं के दो क्षेत्रों में पाई जाती हैं।

वास्तव में, अल्पविकसित देशों की एक विशिष्टता साधन स्तर पर संरचनात्मक असन्तुलन (Imbalance) है। साधन स्तर पर असन्तुलन या तो इस कारण उत्पन्न होता है कि एक एकल साधन विभिन्न प्रयोगों में विभिन्न प्रतिफल (Return) प्राप्त करता है या इसलिए कि साधनों के बीच कीमत सम्बन्ध साधन प्राप्यताओं से मेल नहीं खाते। डॉ० ऐकॉस के अनुसार, ऐसे असन्तुलन से अल्पविकसित देशों में दो प्रकार से बेरोजगारी या अल्पबेरोजगारी होती है। एक कीमत प्रणाली में अपूर्णताओं या कु-कार्यकरण से। दो, वर्तमान प्रौद्योगिकी या माँग की संरचना में रुकावटें, जो अति जनसंख्या वाले पिछड़े हुए देशों में अतिरेक श्रम का कारण बनती हैं। इसलिए एक अल्पविकसित देश में संरचनात्मक बेरोजगारी का सम्बन्ध अतिरेक श्रम से होता है, जो साधनों के कुवितरण, माँग की संरचना और प्रौद्योगिकीय रुकावटों से उत्पन्न होता है।

हिग्गिन्ज ने दो वस्तुओं, उत्पादन के दो साधनों और दो क्षेत्रों के गिर्द उनके साधन सम्पन्नता और उत्पादन-फलनों से अपने सिद्धान्त का निर्माण किया है। दो क्षेत्रों में से, औद्योगिक क्षेत्र बागानों, खानों, तेल-क्षेत्रों, रिफाइनरियों या बड़े पैमाने के उद्योगों में प्रवृत्त रहता है यह पूँजी गहन होता है और तकनीकी गुणांक इसे विशिष्टता प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, साधनों की तकनीकी स्थानापन्नता नहीं होती और उन्हें स्थिर अनुपातों में मिलाया जाता है। देहाती क्षेत्र खाद्य वस्तुओं के उत्पादन, दस्तकारी या बहुत छोटे उद्योगों में प्रवृत्त रहता है। इसके उत्पादन के तकनीकी गुणक परिवर्ती होते हैं जिससे यह तकनीकों के विस्तृत क्षेत्र और श्रम और पूँजी (जिसमें सुधारी हुई भूमि भी शामिल है।) के वैकल्पिक संयोगों से एक ही वस्तु का उत्पादन कर सके।

चित्र 1 में औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन फलन व्यक्त किया गया है। श्रम की इकाइयाँ क्षैतिज अक्ष पर मापी गई हैं और पूँजी इकाइयाँ अनुलम्ब अक्ष पर। वक्र Q_1 सममात्रा वक्र हैं, जो पूँजी की OK एवं श्रम की OL मात्राओं के संयोगों को प्रकट करता है। जोकि उत्पादन के एक निश्चित स्तर का उत्पादन करते हैं वक्र $Q_2Q_3Q_4$ उत्पादन के अधिक ऊँचे स्तरों को प्रकट करते हैं जो तभी सम्भव होंगे जब उन्हीं अनुपातों में पूँजी और श्रम की इकाइयाँ बढ़ाई जाएगी।

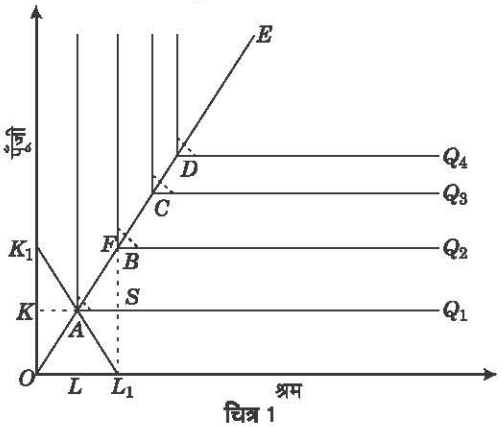

चित्र 1

इस तरह, बिन्दु A, B, C, D पूँजी और श्रम के उन स्थिर संयोगों को प्रकट करते हैं। जिनका उत्पादन के विभिन्न स्तरों $Q_1Q_2Q_3Q_4$ का उत्पादन करने के लिए प्रयोग होता है। इन बिन्दुओं को मिलाने वाली OE रेखा औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार मार्ग है। इसकी ढलान दो साधनों के स्थिर अनुपातों को व्यक्त करती है। K_1L_1 रेखा यह स्पष्ट करती है कि उत्पादन क्रिया पूँजी-गहन दिए हुए उत्पादन को उत्पादित करने के लिए श्रम की सापेक्षता में अधिक पूँजी की जरूरत है।

उत्पादन Q_1 के लिए पूँजी की OK इकाइयाँ और श्रम की OL इकाइयाँ प्रयोग होती हैं। पर, यदि वास्तविक साधन सम्पन्नता A की अपेक्षा S पर हो, इसका अर्थ होगा कि उसी Q_1 उत्पादन हेतु अधिक श्रम इकाइयाँ (OL_1) उपलब्ध हैं जबकि उपलब्ध पूँजी की इकाइयाँ उतनी (OK) ही रहती है। क्योंकि तकनीकी गुणक स्थिर हैं, इसलिए अतिरिक्त श्रम-पूर्ति का उत्पादन तकनीकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और श्रम की LL_1 इकाइयाँ बेरोजगार रहेंगी। इस अतिरिक्त श्रम-पूर्ति को इस क्षेत्र में खपाना केवल तभी सम्भव होगा, जब पूँजी-स्टॉक बढ़कर SF हो जायेगा। अन्यथा इसे देहाती क्षेत्र में रोजगार (Employment) खोजना पड़ेगा।

पर वास्तविकता में, तकनीकी गुणक इतनी कठोरता से स्थिर नहीं होते वरन कुछ-कुछ लचीले होते हैं सममात्रा वक्रों की बिन्दुकित वक्रता साधन-अनुपातों में थोड़े लचीलेपन की सम्भावनाओं को प्रकट करती हैं। यह साधन सम्पन्नताओं में बहुत थोड़े परिवर्तनों को प्रकट करती हैं जिनके लिए उद्यमी उत्पादन की तकनीकों में प्रचण्ड परिवर्तन नहीं करना चाहेंगे। इस तरह वे स्थिर तकनीकी गुणांक रखने को ही अधिमान देंगे।

कृषि क्षेत्र के लिए उत्पादन फलन चित्र 2 में दर्शाया गया है। सममात्रा वक्र $Q_1Q_2Q_3Q_4$ उत्पादन के परिवर्ती गुणांकों को व्यक्त करते हैं। अधिक उत्पादन करने के लिए पूँजी (सुधारी हुई भूमि) की सापेक्षता में अधिक श्रम लगाया गया है। अन्ततः अच्छी भूमि दुर्लभ हो जाती है और समस्त उपलब्ध भूमि अत्यधिक श्रम-गहन तकनीकों द्वारा बिन्दु E पर काश्त की जाती है। जहाँ उत्पादन का अधिकतम स्तर Q_n प्राप्त हो जाता है।

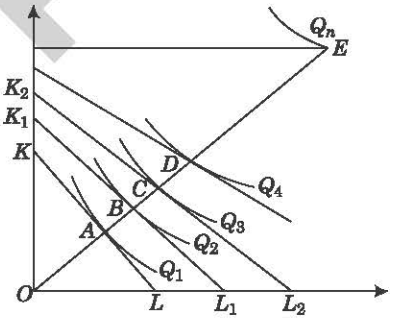

दो क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादन फलनों के दिए होने पर प्रोफेसर हिग्गिन्ज उस प्रक्रिया का विश्लेषण करता है जिसके परिणामस्वरूप प्रौद्योगिकीय द्वैतवाद ने द्वैतीय अर्थव्यवस्थाओं में बेरोगजारी और अदृश्य बेरोजगारी बढ़ाई है। दो क्षेत्रों में से, औद्योगिक क्षेत्र विदेशी पूँजी की सहायता से विकास एवं विस्तार करता है। इस तरह, औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप पूँजी संचय की दर से बहुत अधिक जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है। क्योंकि यह क्षेत्र पूँजी-गहन तकनीकों और स्थिर तकनीकी गुणकों का प्रयोग करता है, इसलिए यह उसी दर से रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं कर सकता जिससे जनसंख्या बढ़ती है। बल्कि यह भी हो सकता है कि औद्योगीकरण "उस क्षेत्र में कुछ रोजगार के अनुपात में सापेक्ष कमी ला दें।" इस प्रकार, अतिरेक श्रम के पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं कि वह देहाती क्षेत्र में रोजगार ढूँढ़े।

विकास प्रक्रिया के प्रारम्भ होने से पहले, देहाती क्षेत्र में उत्पादन के साधनों की न तो प्रचुरता होती है और न ही दुर्लभता। शुरू में तो यह सम्भव है कि अधिक भूमि को काश्त में लाकर अतिरिक्त श्रम-शक्ति को खपा लिया जाए। इसके परिणामस्वरूप श्रम और पूँजी (सुधारी हुई भूमि) के अनुकूलतम संयोग बनते हैं क्योंकि उत्पादन बढ़ता है। उस क्षेत्र में श्रम का उपलब्ध पूँजी से अनुपात धीरे-धीरे बढ़ता जाता है और क्योंकि तकनीक गुणांक उपलब्ध है, इसलिए इस क्षेत्र में तकनीकें उत्तरोत्तर परिवर्ती बनती जाती हैं। उदाहरणार्थ, कई एशियाई देशों में परिवर्ती शुष्क धान खेती के स्थान पर जलयुक्त धान खेती स्थानापन्न कर दी गई है। अन्ततः बहुत ही अधिक श्रम-गहन तकनीकों द्वारा समस्त भूमि काश्त हो जाती है और श्रम की सीमान्त उत्पादकता गिरकर शून्य या शून्य से भी कम हो जाती है। इस तरह जनसंख्या की निरन्तर वृद्धि होने पर, अदृश्य बेरोजगारी प्रकट होने लगती है। इन परिस्थितियों के तहत, कृषकों के लिए कोई प्रेरणा नहीं होती कि वे अधिक पूँजी लगाए अथवा श्रम-बचत तकनीकें अपनाएँ। इसके अलावा न तो प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ाने की कोई तकनीक (Technique) उपलब्ध है और न ही श्रम की ओर से अपने आप उत्पादन बढ़ाने का कोई प्रोत्साहन होता है। इसके कारण देहाती क्षेत्र में उत्पादन की तकनीकें, श्रम-घण्टा उत्पादकता (Productivity) और सामाजार्थिक कल्याण एक निम्न स्तर पर रहते हैं।

दीर्घकाल में प्रौद्योगिकीय प्रगति अदृश्य बेरोजगारी को दूर करने में सहायक नहीं होती वरन उसे बढ़ाती है। प्रोफेसर हिग्गिन्ज का कथन है कि पिछली दो शताब्दियों में देहाती क्षेत्र में बहुत थोड़ी या नहीं के बराबर प्रौद्योगिकीय प्रगति हुई है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में बहुत तीव्र प्रौद्योगिकीय प्रगति हुई है। इससे अदृश्य बेरोजगारी की संख्या बढ़ी है। ट्रेड यूनियन क्रियाओं या सरकार की नीति के कारण मजदूरी की कृत्रिम ऊँची दरों ने इस स्थिति को और भी गम्भीर बना दिया है। क्योंकि उत्पादकता की सापेक्षता में ऊँची औद्योगिक मजदूरी दरें उद्यमियों को इस बात के लिए प्रेरित करती हैं कि वे श्रम बचत तकनीकें अपनाएँ, जिसका परिणाम यह

TOUCH 'n' PASS

होता है कि अतिरेक (Surplus) श्रम को खपा सकने की औद्योगिक क्षेत्र की क्षमता और भी कम हो जाती है। अतएव ये साधन अल्पविकसित देशों में औद्योगिकीय द्वैतवाद की प्रवृत्ति बनाए रखते हैं।

समीक्षात्मक मूल्यांकन (Critical Appraisal)

प्रोफेसर हिग्गिन्ज़ ने आधुनिक और परम्परागत (Traditional) क्षेत्रों का ऐतिहासिक क्रम-विकास प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। जिसके कारण पहले क्षेत्र में धीरे-धीरे बेरोजगारी बढ़ती जाती है। प्रौद्योगिकीय द्वैतवाद बूके के सामाजिक द्वैतवाद से श्रेष्ठ प्रतीत होता है। यह यथार्थिक है क्योंकि इस बात पर विचार करता है कि द्वैतीय समाजों के देहाती क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी (Unemployment) धीरे-धीरे कैसे बढ़ती जाती है।

इसकी त्रुटियाँ (Its Defects)—फिर भी, इसमें कुछ त्रुटियाँ पाई जाती हैं—

1. **औद्योगिक क्षेत्र में गुणांक स्थिर नहीं** (Coefficients not fixed in industrial sector)—जहाँ देहाती क्षेत्र (Village Area) में परिवर्ती तकनीकी गुणांकों से उत्पादन हुआ है। वहाँ यह सन्देहास्पद है कि औद्योगिकीय क्षेत्र में उत्पादन वास्तव में स्थिर गुणांकों से होता रहा है। बिना किसी प्रमाण के यह मानना सही नहीं कि औद्योगिक क्षेत्र में स्थिर तकनीकी गुणांक पाए जाते हैं।
2. **श्रम खपाने वाली तकनीकों की अवहेलना** (Neglects the use of labour absorbing techniques)—हिग्गिन्ज का यह कथन, कि औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग के लिए अत्यन्त पूँजी-गहन प्रक्रियाएँ (Process) आयात की जाती हैं, श्रम खपाने वाली अन्य तकनीकों के प्रयोग की पूर्णरूप से अवहेलना (Ignorance) करता है। सब आयातित तकनीकें श्रम की बचत करने वाली नहीं होतीं। उदाहरणार्थ, जापान का कृषि विकास पूँजी-गहन तकनीकों के कारण नहीं हुआ है वरन अच्छे बीजों सुधारी हुई खेती के ढँगों, उर्वरकों के अधिक प्रयोग आदि के कारण हुआ है।
3. **अदृश्य बेरोजगारी की प्रकृति एवं आकार को स्पष्ट नहीं किया** (Nature and size of desguised unemployment not clarified)—हिग्गिन्ज़ देहाती क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी की और औद्योगिक क्षेत्र में अतिरिक्त श्रम-पूर्ति की प्रकृति स्पष्ट नहीं करता और न ही वह प्रौद्योगिक द्वैतवाद से उत्पन्न होने वाली अदृश्य बेरोजगारी की वास्तविक सीमा की बात करती है।
4. **साधन कीमतें साधन सम्पन्नताओं पर निर्भर नहीं करती** (Factor prices do not depend upon factor endowments)—यह सिद्धान्त इस ओर संकेत करता है कि किस कारण साधन सम्पन्नताओं एवं विभिन्न उत्पादन फलनों ने देहाती क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी को जन्म दिया है। यह साधन कीमतों के ढँग से महत्त्वपूर्ण तौर से सम्बद्ध है लेकिन साधन कीमतें बिल्कुल साधन सम्पन्नताओं पर ही निर्भर नहीं करतीं।
5. **संस्थानिक साधनों की उपेक्षा** (Neglect of institutional factors)—फिर, हिग्गिन्ज़ बहुत से संस्थानिक और मनोवैज्ञानिक तत्त्वों की अपेक्षा करता है, जो साधन अनुपातों को भी प्रभावित करते हैं।

प्र.4. निर्धनता या गरीबी के दुष्चक्र का वर्णन विस्तारपूर्वक कीजिए।
Describe the vicious circle of poverty in detail.

उत्तर

निर्धनता या गरीबी का दुश्चक्र
(Vicious Circle of Poverty)

अल्प-विकसित या अर्ध-विकसित देशों में एक विशेषता पायी जाती है कि उनके यहाँ गरीबी का दुश्चक्र चलता रहता है। इसलिए रैगनर नर्कसे (Ragner Nurkse) ने अपनी पुस्तक 'Problem of Capital Formation in Under-developed Countries' में लिखा है। कि इन देशों में शक्तियों का ऐसा चक्राकार नक्षत्रमण्डल होता है। कि वह एक-दूसरे पर क्रिया और प्रतिक्रिया (action and reaction) करता रहा है। जिससे एक निर्धन देश निर्धनता (Poverty) की स्थिति में बना रहता है। अल्पविकसित देशों में आधारभूत विषमचक्र का आरम्भिक बिन्दु पूँजी (Capital) की कमी है। जो इन देशों के अल्प विकास का कारण एवं परिणाम दोनों हैं।

रैगनर नर्कसे ने गरीबी के दुश्चक्र को पूँजी के माँग पक्ष एवं पूर्ति पक्ष दोनों के सन्दर्भ में परिभाषित किया है।

TOUCH 'n PASS

(A) माँग पक्ष

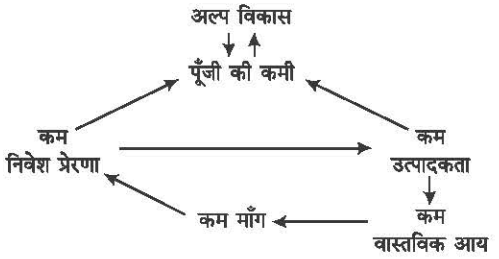

(B) पूर्ति पक्ष

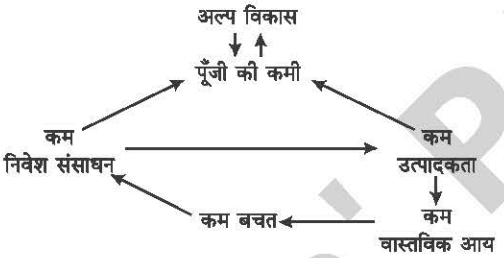

मांग पक्ष एवं पूर्ति पक्ष : संयुक्त क्रियाशीलता

रेगनर नर्कसे ने अल्प-विकसित देशों में प्रचलित गरीबी के दुश्चक्र का कारण माँग एवं पूर्ति पक्ष की संयुक्त क्रियाशीलता को माना है। उनकी दृष्टि में वास्तविक आय का निम्न स्तर वस्तुओं की माँग और पूर्ति के निम्न स्तर का कारण और परिणाम दोनों हैं। क्योंकि वास्तविक आय की कमी न केवल माँग पक्ष को कमजोर बनाती है वरन दूसरी ओर लोगों द्वारा आय में से की जाने वाली बचतों के आकार को भी संकुचित करती है। सीमित माँग एवं सीमित बचत संयुक्त रूप से अल्प-विकसित देशों में विनियोग के आकार को घटाते हैं। जिसके फलस्वरूप क्रमशः कम उत्पादकता एवं कम पूँजी-निर्माण के स्तर प्राप्त होते हैं। और गरीबी का दुश्चक्र पूरा हो जाता है।

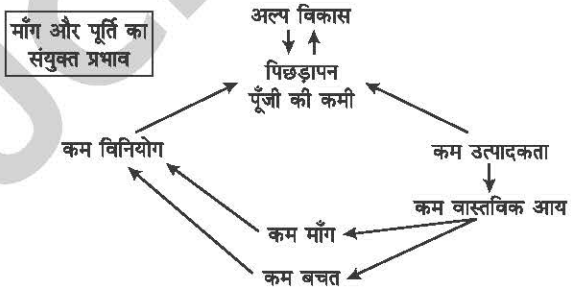

गरीबी के दुश्चक्र को तोड़ने के उपाय
(Solution of the Vicious Circle of Poverty)

गरीबी का दुश्चक्र अल्प-विकसित देशों की स्थिति की वास्तविकता को बतलाता है लेकिन यह चक्र अभेद्य नहीं है। विषम चक्र को तोड़ने की सम्भावनाएँ हमेशा उपस्थित रहती हैं। रेगनर नर्कसे के अनुसार, "एक स्थिर व्यवस्था में शक्तियों का चक्रीय रूप से काम करना एक वास्तविकता है, किन्तु सौभाग्य से यह चक्र अटूट नहीं है और यदि इसे एक बार किसी बिन्दु पर तोड़ दिया जाता है तो यही वास्तविकता कि सम्बन्ध चक्रीय है विकास को संचयी बना देती हैं। अतएव हमें इस चक्र को विषम कहने में संकोच करना चाहिए, क्योंकि वह लाभ पूर्ण बन सकता है।

गरीबी के दुश्चक्र का समाधान निम्न तीन प्रकार से किया जा सकता है।

1. बचत में वृद्धि एवं उसका उत्पादन कार्यों में निवेश

TOUCH 'n' PASS

2. बाजार का विस्तार करके
3. पिछड़ेपन में सुधार करके।

1. **बचत में वृद्धि और उसका उत्पादन कार्यों में निवेश करके**—गरीबी के दुश्चक्र से निकलने के लिए यह जरूरी है कि बचतों (Savings) को बढ़ाया जाए और उसको उत्पादन कार्यों में लगाया जाए। बचत बढ़ाने के लिए आवश्यक व्ययों को कम किया जाना चाहिए। जैसे शादी-विवाह रीति-रिवाज (Customs) पर होने वाले व्ययों में कमी की जानी चाहिए। शान एवं शौकत पर व्यय नहीं करना चाहिए या कम-से-कम करना चाहिए। सरकार को ऐच्छिक बचतों पर जोर देना चाहिए। यदि ऐच्छिक बचतें कम हों तो राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) में परिवर्तन कर बचतों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए अनिवार्य बचत योजनाओं को अपनाया जा सकता है।
   गरीबी के दुश्चक्र को तोड़ने के लिए बचत करना ही जरूरी नहीं है वरन बचत का निवेश (Investment) भी जरूरी है। जिसके लिए अल्पकालीन व दीर्घकालीन योजनाएँ बनायी जानी चाहिए और उनमें समन्वय इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उनसे अधिकाधिक लाभ हो।
   अतएव, गरीबी के दुश्चक्र को तोड़ने के लिए बचत की दर बढ़ानी चाहिए एवं उसका उचित निवेश होना चाहिए।
2. **बाजार का विस्तार करके**—गरीबी के दुश्चक्र को तोड़ने के लिए (Markets) बाजारों का विस्तार किया जाना चाहिए जिससे कि वस्तु की माँग बढ़े एवं निवेश करने वाले को प्रेरणा मिले। इसके लिए योजनात्मक विकास की नीति अपनायी जानी चाहिए एवं सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश बढ़ाया जाना चाहिए। जिससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ सके और मौद्रिक आय व बाजारों का विस्तार हो सके।
   माँग बढ़ाने के लिए एक दूसरा उपाय भी काम में लाया जा सकता है, जिसके तहत सन्तुलित विकास की नीति अपनाकर निवेश इस तरह किया जाना चाहिए कि एक उद्योग में निवेश होने से दूसरे उद्योग में माँग बढ़ सके।
3. **पिछड़ेपन में सुधार करके**—गरीबी के दुश्चक्र को तोड़ने हेतु अल्प-विकसित देशों को अपने पिछड़ेपन में सुधार करना चाहिए। इसके लिए शिक्षा का प्रसार, तकनीकी ज्ञान में वृद्धि एवं प्रबन्धकीय प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिए। साथ ही समाज में स्वास्थ्य में भी सुधार किया जाना चाहिए। जिसके लिए चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए। गाँव एवं शहरों को जोड़ने के लिए सड़कों, परिवहन व संचार साधनों का विकास किया जाना चाहिए। इन सभी के विकास से मानव शक्ति की कुशलता बढ़ेगी और वह अधिक आय अर्जित करने योग्य बन सकेगी। जिससे उसके जीवन-स्तर में सुधार होगा।

उपर्युक्त बिन्दुओं के अलावा अल्प-विकसित देशों में गरीबी के दुश्चक्र को तोड़ने की रणनीति में निम्नांकित उपायों का समावेश किया जाना आवश्यक है—

1. **बचत व विदेशी पूँजी को प्रोत्साहन**—पूँजी की कमी के लिए जनसाधारण में बचत करने एवं इनको उद्योगों, आदि में लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा यदि विदेशी पूँजी भी बिना शर्त या अनुकूल शर्तों पर मिले तो उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।
2. **बाजारों का विस्तार**—यदि देश में क्रय-शक्ति कम होने के कारण बाजारों का विस्तार करने की सम्भावनाएँ न हों तो निर्यात को प्रोत्साहित कर विदेशी मुद्रा अर्जित करनी चाहिए। जिससे कि नये-नये उद्योगों के लिए जरूरी मशीनें एवं पूँजीगत माल आयात (Import) किया जा सके।
3. **उपयुक्त संरचना की स्थापना**—देश में उपयुक्त संरचना (Structure) न होने से भी उत्पादनों को देश के गाँवो तक पहुँचाने में कठिनाई होती है। सड़क एवं अन्य परिवहन साधनों का विकास किया जाना चाहिए।
4. **सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं में परिवर्तन**—आर्थिक विकास हेतु सामाजिक वातावरण में परिवर्तन लाने व धार्मिक मान्यताओं में फेर-बदल करने के लिए उपयुक्त साधनों से प्रचार किया जाना चाहिए। जिससे कि इन मान्यताओं में धीरे-धीरे परिवर्तन लाया जा सके।
5. **जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण**—बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास की गति को कम कर देती है। इसलिए जनसंख्या को नियन्त्रित करने के लिए उपाय काम में लाये जाने चाहिए।
6. **राजनीतिक स्थिरता**—देश में राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए जिससे कि आन्तरिक झगड़ों का अन्त हो सके और शान्ति व्यवस्था कायम की जा सके। इससे नियोजन या विकास कार्यक्रम को निर्धारित गति से चलाया जा सकता है।

TOUCH 'n' PASS

प्र.5. मिर्डल के सन्तुलित क्षेत्रीय विकास मॉडल पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए।
Write a long note on Myrdal's model of balanced regional development.

उत्तर

सन्तुलित क्षेत्रीय विकास का अर्थ
(Meaning of Balanced Regional Development)

विश्व के कुछ ही राष्ट्र ऐसे हैं जिसकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अत्यधिक है और जो विकास की उच्चस्तरीय अवस्थाओं में प्रविष्ट हो चुके हैं। दूसरी ओर देशों का बहुत बड़ा समूह ऐसा है जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बहुत कम है और जो विकास की निम्नस्तरीय अवस्थाओं को भी पार नहीं कर पा रहे हैं। अतिविकसित देशों एवं अल्प-विकसित देशों में यह अन्तर निरन्तर विद्यमान ही नहीं है, वरन इस अन्तर में वृद्धि भी होती जा रही है। यही क्षेत्रीय असन्तुलन है। क्षेत्रीय विकास दो रूपों में मिलता है। (i) विभिन्न देशों का सन्तुलित विकास करना, (ii) एक ही राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों का सन्तुलित विकास करना।

विभिन्न देशों का सन्तुलित विकास
(Balanced Development of Different Countries)

आधुनिक युग में विकास के स्तर में विभिन्न राष्ट्रों में अत्यधिक विभिन्नता विद्यमान है। यह विभिन्नता प्रति व्यक्ति आय (PCg) से दृष्टिगोचर होती है। प्रति व्यक्ति औसत आय देश के उत्पादन एवं जनसंख्या से संदर्भित होती है।

1. **निर्धनता का दुश्चक्र** (Vicious Circle of Poverty)—अल्प-विकसित राष्ट्रों की व्यापक निर्धनता (Poverty) एक ऐसा ऋणात्मक घटक है जो विभिन्न अन्य ऋणात्मक घटकों को जन्म देता है। दूसरी ओर विकसित राष्ट्रों में सम्पन्नता का चक्र ऊर्ध्वमुखी होता है जिससे विकास में सहायता पहुँचाने वाले बहुत-से घटक (Factor) उदय एवं सुदृढ़ होते रहते हैं।
2. **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रतिकूल शर्तें** (Unfavourable terms of International Trade)—अल्प-विकसित राष्ट्रों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अपना निर्यात मूल्य नहीं मिलता है, और उन्हें अपने आयात के लिए अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। इनके निर्यात में विभिन्नता की कमी, पूर्ति एवं माँग (Demand) का बेलोच होना आदि प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत, आयात सशर्त होते हैं जिनका लाभ सहायता देने वाले देशों को होता है।
3. **प्राकृतिक साधनों का उपयुक्त अवशोषण न किया जाना** (Unexploitation of Available Natural Resources)—अल्प-विकसित राष्ट्रों में प्राकृतिक साधनों का पर्याप्त विदोहन नहीं किया जा सका है और जिन साधनों का विदोहन किया भी गया है उन पर विदेशियों का प्रभुत्व है। जिससे देश की अर्थव्यवस्था इससे लाभान्वित (Bonafide) नहीं होती है।
4. **औद्योगीकरण की मन्द गति** (Slow Growth of Industrialisation)—असन्तुलित विकास का एक प्रमुख कारण औद्योगीकरण की गति का अन्तर भी है। अल्पविकसित राष्ट्र कृषि प्रधान होते हैं। कृषि व्यवसाय में विकास की गति मन्द रहती है क्योंकि यह प्रकृति पर निर्भर करती है दूसरी ओर, औद्योगीकरण की प्रगति की दर मानवीय प्रयासों द्वारा उत्पादक साधनों पर निर्भर करती हैं। इसलिए औद्योगिक राष्ट्रों में विकास (Development) की गति कृषि प्रधान राष्ट्रों की तुलना में अधिक रहती हैं।
5. **आय का वितरण विकास में सहायक नहीं** (Distribution of Income is not helpful in Development)—अल्पविकसित राष्ट्रों में आय का वितरण विकसित राष्ट्रों की तुलना में अधिक विषम होता है। इन राष्ट्रों में आय का बहुत बड़ा भाग जमींदारों, साहूकारों एवं व्यापारियों को प्राप्त होता है। जो जोखिम नहीं उठाते हैं। दूसरी ओर विकसित राष्ट्रों में आय का वितरण साहसियों के पक्ष में होता है जिससे उत्पादक विनियोजन में निरन्तर वृद्धि होती रहती है।
6. **जनसंख्या का परिमाण, संरचना एवं गुण विकास के अनुकूल न होना** (Unfavourable quantum, Composition and Quality of Population for Growth)—अल्प-विकसित देशों में जनसंख्या की वृद्धि की गति तेज रहती है और जन-साधारण का जीवनकाल छोटा होता है। जिससे उत्पादक श्रम शक्ति का जनसंख्या में अनुपात कम रहता है। परम्परागत जीवन, व्यापक अशिक्षा और सामाजिक रूढ़िवादिता (Conservatism) के कारण श्रम में कुशलता ग्रहण करने की क्षमता कम होती है जिससे उत्पादन की क्रियाएँ अवरुद्ध होती हैं।

TOUCH 'n' PASS

7. **राजनीतिक एवं आर्थिक अस्थिरता** (Political and Economic Unstability)—विकसित राष्ट्रों की तुलना में अल्प-विकसित राष्ट्रों में राजनीतिक उथल-पुथल अत्यधिक होती है। सुदृढ़ शासन की अनुपस्थिति में विकास के अनुकूल नीतियों का निर्धारण एवं कुशल संचालन सम्भव नहीं हो पाता है। इससे साधनों का अपव्यय (Wastage) होता है।

उपयुक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि क्षेत्रीय असन्तुलित (Imbalance) विकास के कुछ कारण विभिन्न देशों की आन्तरिक प्रतिकूल परिस्थितियों से उदय होते हैं और बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। वास्तव में, विकसित राष्ट्र यह नहीं चाहते हैं। कि अल्पविकसित राष्ट्र में विकास की गति इतनी तीव्र हो कि वे विकसित राष्ट्रों के आश्रय से मुक्त हो जाए। जो भी सहायता विकसित राष्ट्रों एवं विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा विकासशील राष्ट्रों को प्रदान की जाती है, उनका अन्तिम लक्ष्य विकसित राष्ट्रों पर विकासशील राष्ट्रों की निर्भरता को बनाए रखना होता है। यही कारण है कि विभिन्न राष्ट्रों में विकास की गति में इतना अन्तर पाया जाता है।

एक ही राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों का सन्तुलित विकास
(Balanced Regional Development of A Country)

अल्प-विकसित राष्ट्रों की प्रक्रिया में अन्तर्क्षेत्रीय असन्तुलित विकास एक समस्या का रूप ग्रहण करता है। विकास विनियोजन की वृद्धि के साथ-साथ आमतौर पर असन्तुलित विकास की गहनता में वृद्धि होती जाती है और निर्धन क्षेत्रों और वर्गों को विकास का लाभ सम्पन्न क्षेत्रों एवं सम्पन्न वर्गों की तुलना में कम ही प्राप्त होता है। जिससे तुलनात्मक दृष्टिकोण से सम्पन्नता एवं विषमता का अन्तर और अधिक हो जाता है। सन्तुलित विकास का निम्न तीन अर्थों में प्रयोग किया जाता है—

1. क्षेत्रीय सन्तुलन
2. खण्डीय सन्तुलन
3. आय वितरण सन्तुलन

1. **क्षेत्रीय सन्तुलन** (Regional Balance)—क्षेत्रीय सन्तुलन से आशय किसी देश में विभिन्न भौगोलिक (Geographical Developed) एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान विकास से है अर्थात् विकास प्रक्रिया का संचालन इस तरह किया जाए कि विभिन्न क्षेत्रों के विकास को गतिशील रखने के साथ-साथ पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास की गति को अधिक तेज रखा जाए जिससे पिछड़े क्षेत्र विकसित क्षेत्रों के समान विकास का स्तर प्राप्त कर सकें। इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि विकास प्रक्रिया में विकसित क्षेत्रों के और विकास को उस समय तक गतिहीन रखा जाए जब तक कि अन्य क्षेत्र इनके समान विकास स्तर प्राप्त न कर ले। विकसित (Developed) क्षेत्रों के विकास की गति को तीव्र रखकर इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। वर्तमान युग में लगभग सभी विकासशील राष्ट्र असन्तुलित (Imbalance) क्षेत्रीय विकास के दोष से पीड़ित हैं, और इन देशों की विकास प्रक्रिया (Process) का संचालन इस तरह किया गया है कि क्षेत्रीय असन्तुलन में कमी होने के स्थान पर वृद्धि होती जा रही है। क्षेत्रीय असन्तुलित विकास के उदय होने के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं—
   (i) उपरिढाँचे की सुविधाओं की उपलब्धता में विषमता होती है।
   (ii) पिछड़े क्षेत्रों में जन-मानस की विकासपरक अभिव्यक्ति आमतौर पर गौण रहती है।
   (iii) पिछड़े क्षेत्रों की गरीबी आर्थिक क्रियाएँ आरम्भ करने में बाधक होती हैं।
   (iv) पिछड़े क्षेत्रों में निजी निवेश (Investment) की प्रेरणा नहीं होती।
   (v) पिछड़े (Backward) क्षेत्र कृषि प्रधान होते हैं और नगरीय क्षेत्रों की सुविधाओं से वंचित होते हैं।
2. **खण्डीय सन्तुलन** (Sectoral Balance)—खण्डीय सन्तुलन के तहत अर्थव्यवस्था के विभिन्न खण्डों (कृषि, खनिज, उद्योग, यातायात, संचार, शिक्षा, प्रशिक्षण, आदि) में सन्तुलन स्थापित किया जाता है। विभिन्न उद्योगों एवं व्यवसायों में पारस्परिक सन्तुलन स्थापित किए बिना विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान नहीं की जा सकती है। एक उद्योग अथवा व्यवसाय के उत्पादों अथवा सेवाओं का उपयोग अन्य उद्योग एवं व्यवसायों में आदाओं (Inputs) के रूप में किया जाता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के समस्त खण्ड एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं और एक खण्ड का प्रभाव दूसरे खण्ड पर पड़ता है। इसलिए जब तक अर्थव्यवस्था के सभी खण्ड़ों का विकास सन्तुलित रूप से नहीं किया जाता है, एक खण्ड की क्रियाएँ दूसरे खण्ड की क्रियाओं को या तो अवरुद्ध करती हैं अथवा दोहराती हैं जिससे साधनों

का अपव्यय होता है। अधिकतर विकासशील (Developing) राष्ट्रों में विकास की गति धीमी होने के कारणों में मुख्य है खण्ड़ीय सन्तुलन।

3. **आय वितरण सन्तुलन** (Income Distribution Balance)—विकास नियोजन के फलस्वरूप राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में तो वृद्धि हो जाती है लेकिन आय के पुनर्वितरण द्वारा समानता उदय नहीं हो पाती है। आय एवं अवसर की समानता उत्पन्न किए बिना विकास की प्रक्रिया का लाभ सम्पन्न वर्गों को ही अधिक मिलता है। जिससे विषमताओं में और वृद्धि होती है। आय के विषय वितरण से समाज में सम्पन्न एवं विपन्न जनसमुदाय के वर्ग (Class) स्थापित होते हैं और सामाजिक असन्तुलन का उदय होता है। विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक प्रगति के साथ-साथ विषमताएँ एवं सामाजिक असन्तुलन भी बढ़ता जाता है और व्यापक निर्धनता (Poverty) निरन्तर बनी रहती है।

प्र.6. मिर्डल के चक्रीय कार्यकरण के मॉडल की विवेचना कीजिए।
Discuss the Myrdal's model of circular causation.

उत्तर

मिर्डल का चक्रीय कार्यकरण का मॉडल
(Myrdal's Model of Circular Causation)

प्रो० मिर्डल (Myrdal) का मत है कि आर्थिक विकास का परिणाम चक्रीय कार्यकरण प्रक्रिया है। इससे धनिक को अधिक लाभ प्राप्त होता है और जो लोग पिछड़ जाते हैं, उनके प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। प्रो० गुन्नार मिर्डल ने विकासात्मक समस्याओं का अवलोकन विभिन्न देशों में पाई जाने वाली क्षेत्रीय असमानताओं (Regional Disparity) और अन्तर्राष्ट्रीय असमानताओं के सन्दर्भ में किया है। अर्द्ध-विकसित देश के अन्दर ही विभिन्न क्षेत्रों में आय, कच्चे माल की उपलब्धि की प्रवृत्ति सामान्यत: पाई जाती हैं। कुछ देशों में साम्राज्यवाद के कारण भी इसमें वृद्धि हुई है।

प्रो० गुन्नार मिर्डल ने 'प्रसरण प्रभाव' एवं 'अति निर्यात प्रभाव' में अन्तर प्रस्तुत किया है। पहला प्रभाव विस्तार और समृद्धि के बढ़ने से सम्बन्धित है और दूसरा आय और अन्य आर्थिक लाभों के क्षेत्र में विभिन्नताओं के बढ़ने को दर्शाता है। जब भी एक क्षेत्र विशेष में विकास होता है तब दूसरे क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव 'प्रसार' या 'अति निर्यात प्रभावों' पर दोनों ही प्रकार का पड़ता है। परन्तु 'प्रसरण प्रभाव' अधिक व्यापक और प्रभावशाली होते हैं। यही कारण है कि प्रो० मिर्डल ने साधनों के मूल्यों की समानता द्वारा आर्थिक एकीकरण को विकास की प्राथमिक आवश्यकता बताया है। यदि श्रम उद्योग-धन्धों में कृषि की अपेक्षा अधिक आय प्राप्त कर सकता है तो साधनों का दोबारा वितरण आवश्यक हो जाता है। जिस प्रकार घरेलू अर्थव्यवस्था में अनेक असन्तुलन उत्पन्न करने वाली शक्तियाँ पाई जाती हैं। उसी तरह विश्व अर्थव्यवस्था में भी अनेक असन्तुलन उत्पन्न करने वाली शक्तियाँ पाइ जाती हैं। इन क्षेत्रीय असमानताओं, इत्यादि का क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर निवारण जरूरी है।

मिर्डल मॉडल
(Myrdal Model)

मिर्डल ने विकास का मॉडल राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समतलों पर प्रादेशिक असमानताओं के आधार पर बनाया है। इस मॉडल में उसने अतिनिर्यात एवं प्रसरण प्रभावों की धारणा का प्रयोग किया है। मिर्डल के अनुसार, "प्रादेशिक असमानताओं का मुख्य कारण अल्पविकसित देशों में प्रबल अतिनिर्यात प्रभाव एवं दुर्बल प्रसरण प्रभाव माने जाते हैं।" मिर्डल के मॉडल की निम्नांकित विशेषताएँ हैं—

1. प्रो० गुन्नार मिर्डर ने अपने चक्राकार सिद्धान्त तथा संचयी कारण एवं परिणाम के आधार पर बताया कि असमानताओं के विाय में प्राचीन सैद्धान्तिक मान्यताएँ पूर्ण रूप से गलत हैं। इस विषय में प्राचीन सैद्धान्तिक विचार सन्तुलन की मान्यता इस बात पर आधारित है कि जब भी सन्तुलन कुछ क्रिया विशेषों अथवा कारण विशेषों के कारण भंग होता है तो तुरन्त कुछ ऐसी प्रक्रियाओं का भी जन्म होता है, जो इस सन्तुलन की पुन: प्राप्ति की व्यवस्था करती हैं। हम बड़ी आसानी से यह कह सकते हैं कि इस विषय में प्राचीन मान्यता इस बात पर आधारित है। कि अर्थव्यवस्था में निरन्तर एक सन्तुलन स्थापित रहता है और यदि यह किन्ही कारणों अथवा शक्तियों द्वारा भंग भी हो जाता है। तो इसकी पुन: स्थापना की प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं।

   प्रो० गुन्नार मिर्डल ने यह भी बताया कि प्राचीन मान्यताओं में एक अवास्तविक मान्यता यह भी है कि प्राचीन विश्लेषण में गैर-आर्थिक तत्त्वों को कोई विशेष महत्त्व नहीं दिया गया था। वास्तविकता यह है कि विभिन्न सामाजिक तत्त्वों का भी

TOUCH 'n PASS

अर्थव्यवस्था में आर्थिक तत्त्वों के समान ही महत्त्व है, क्योंकि आर्थिक तत्त्वों की भाँति इनमें भी लगातार परिवर्तन होते रहते हैं।

2. **प्रादेशिक असमानताएँ**—देश में प्रादेशिक असमानता का कारण आर्थिक भिन्नता है। यह पूँजीवादी अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित रहती है तथा लाभ के उद्देश्य से चलाई जाती हैं, वे क्षेत्र विकसित हो जाते हैं, जो कि लाभ के उद्देश्य से चलाए जाते हैं तथा अन्य क्षेत्र-विकसित रह जाते हैं। बाजार शक्तियों की स्वतन्त्र शक्ति प्रादेशिक असमानताओं को बढ़ाती है। यह प्रादेशिक असमानताएँ उस समय उभर आती हैं, जबकि कुछ स्थानों पर कीमत में वृद्धि हो जाती है। और वे प्रदेश गतिहीन बने रहते हैं। प्रो. मिर्डल का कहना है कि "यदि बात बाजार शक्तियों पर ही छोड़ दी जाए और उन्हें किन्ही नीति हस्तक्षेपों से अवरुद्ध न किया जाए तो समस्त आर्थिक सक्रियताएँ विकासशील अर्थव्यवस्था को औसत से अधिक प्रतिफल प्रदान करेंगी। इसके विपरीत विज्ञान, कला, साहित्य, शिक्षा व संस्कृति कुछ स्थानों पर एकत्रित हो जाएगी और देश के दूसरे भाग को न्यूनाधिक पश्चग-जल (backwater) मे छोड़ देंगी। इस प्रकार प्रादेशिक असमानताएँ तब उभरती हैं, जब कुछ स्थान अन्य प्रदेशों की कीमत पर वृद्धि करते हैं और वे प्रदेश गतिहीन रहते हैं।

   पूँजी से भी प्रादेशिक असमानताएँ बढ़ जाती हैं विकसित प्रदेश में बढ़ी हुई माँग विनियोग को प्रेरित करती है जिससे माँग में और वृद्धि होकर विनियोग में वृद्धि हो जाती है। यदि बैंकिंग व्यवस्था को नियमित नहीं किया गया तो दरिद्र क्षेत्रों से बचतों को निकाल कर धनी एवं प्रगतिशील प्रदेशों में पहुँचाने का साधन बन जाती है जिससे पूँजी के प्रतिफल ऊँचे तथा सुरक्षित हो जाते हैं।

   मिर्डल पिछड़े हुए प्रदेशों पर देशान्तर, पूँजीगतियों व व्यापार के अतिनिर्यात प्रभावों का विश्लेषण करते हैं। उन्होंने अपनी थीसिस में यह बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार श्रम का देशान्तर, पूँजीगतियों व व्यापार के अतिनिर्यात प्रभाव पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास में बाधा डालते हैं। साथ ही समस्त अर्थव्यवस्था के विकास को धीमा करते हैं। जब एक क्षेत्र का विकास अन्य पिछड़े हुए क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होने लगता है तो विकसित क्षेत्र में संचयी प्रसार की शृंखला चालू होने से अन्य क्षेत्रों पर अतिनिर्यात प्रभाव कार्यशील हो जाते हैं जिससे विकास अन्तर शुरू होते हैं।

3. **अन्तर्राष्ट्रीय असमानताएँ**—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से अल्प-विकसित देशों में प्रबल अतिनिर्यात प्रभाव हो सकते हैं। मिर्डल का मत है कि "व्यापार धनी तथा प्रगतिशील प्रदेशों के पक्ष में आधारभूत पक्षपात लेकर तथा कम विकसित देशों के प्रतिकूल परिचालन करता है।" यदि दो देशों में से एक औद्योगिक हो और दूसरा अल्प-विकसित हो और औद्योगिक एवं अल्प-विकसित देशों के मध्य अबाधित व्यापार हो, तो वह औद्योगिक देश को बल देगा तथा अल्प-विकसित देश को गरीब बना देगा। अमीर देश उत्पादों को सस्ती दर पर लाकर अल्प-विकसित देशों के लघु उद्योगों को पीछे धकेल देता है। जिससे पिछड़े देश प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादक मात्र बनकर रह जाते हैं। चूँकि निर्यात व्यापार में प्राथमिक वस्तुओं की माँग लोच रहित होती है अत: उन्हें मूल्यों में काफी उतार-चढ़ाव के कारण हानि सहनी पड़ती है तथा निर्यातों से अधिक लाभ अर्जित नहीं कर पाते हैं। इसमें भुगतान शेष की कठिनाइयाँ भी आती हैं। पूँजी प्राप्तियाँ भी अन्तर्राष्ट्रीय असमानताओं की रोकथाम करने में असफल रही हैं। अत: जो अबाधित व्यापार उन्नत देशों में पगति लाते हैं, उन्हीं ने अल्प-विकसित देशों में प्रबल अतिनिर्यात प्रभाव उत्पन्न किए हैं। अत: अल्प-विकसित देशों के बीच जो दुर्बल प्रसरण प्रभाव विद्यमान हैं; वे इन देशों के अपने ही भीतर के उन दुर्बल प्रसरण प्रभावों की झलक मात्र हैं। जो इनके विकास के निम्न स्तर के कारण उत्पन्न हुए रहते हैं।

   पूँजी-गतियाँ भी अन्तर्राष्ट्रीय असमानताओं की रोकथाम करने में असफल रही हैं, क्योंकि विकसित देश स्वयं ही निवेशकर्ताओं को वस्तुएँ, लाभ तथा सुरक्षा करते हैं। जिससे पूँजी अल्प-विकसित देशों से दूर रहती हैं।

समीक्षात्मक मूल्यांकन
(Critical Appraisal)

मिर्डल के मॉडल ने बहुत सुन्दर ढँग से उन राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों को मिला दिया है जो विश्व के अल्प-विकसित देशों को उस संचयी प्रक्रिया में रखने का प्रयास करती हैं, जहाँ दरिद्रता स्वयं अपना कारण बन जाती है। यह सत्य है कि अल्प-विकसित देशों में प्रबल अतिनिर्यात प्रभाव प्रसरण प्रभावों को मन्द कर देते हैं। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियाँ उन्हें रोकने का प्रयास करती हैं तथा प्रादेशिक व विश्व असमानताओं को प्रेरित करती हैं। बाजार व्यवस्था में नियन्त्रण की कमी के कारण

TOUCH 'n' PASS

अल्प-विकसित देशों के निर्यात नहीं बढ़े हैं। इससे विकसित देशों के आयातों एवं निर्यातों में बड़ा अन्तर आ गया है, जिसने उनके आर्थिक, विकास को महँगा तथा लम्बा बना दिया है। अनुभव ने भी मिर्डल के मॉडल की पुष्टि की है।

प्र.7. निर्भरता सिद्धान्त के विभिन्न संस्करणों का वर्णन कीजिए।

Describe the different versions of dependency theory.

उत्तर 1950 के दशक के दौरान लैटिन अमेरिका में निर्भरता का सिद्धान्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के उदारवादी सिद्धान्तों के आलोचक के रूप में उभरा। बाहरी प्रभाव के कारण राष्ट्र-राज्य के आर्थिक पिछड़ेपन की व्याख्या के रूप में निर्भरता सिद्धान्त को परिभाषित किया जा सकता है। थियोटोनियों डॉस सैंटोस (1936-2018) , निर्भरता सिद्धान्त के प्रमुख समर्थकों में से एक थे। वे इसे एक ऐतिहासिक स्थिति के रूप में परिभाषित करते हैं। जो कुछ देशों के पक्ष में विश्व अर्थव्यवस्था की संरचना को आकार देता है। जिससे दूसरों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। निर्भरता एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार से अनुकूलित होती है। निर्भरता सिद्धान्त वैश्विक दक्षिण में देशों में लगातार पिछड़ेपन और अविकसितता के कारणों को समझने और समझाने का प्रयास करता है और इस समस्या को हल करने के लिए सुझाव देता है।

निर्भरता सिद्धान्त के विभिन्न संस्करण
(Different Versions of Dependency Theory)

निर्भरता एकल एकीकृत सिद्धान्त नहीं है बल्कि यह कुछ देशों/क्षेत्रों में जारी आर्थिक निर्भरता और अविकसितता का अध्ययन करने के लिए सिद्धान्तों या रूपरेखाओं का एक समूह है और इसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और विदेश पर प्रभाव की समझ है। निर्भरता सिद्धान्त के विद्वानों को कई शिविरों में विभाजित किया गया है। इसमें राउल प्रीबिश द्वारा मध्यम संस्करण का प्रतिनिधित्व किया गया है। अतिवादी (रेडिकल) या मार्क्सवादी-लेनिनवादी संस्करण आन्द्रे गौंडर फ्रैंक द्वारा प्रचारित है, और एक अधिक व्यापक विश्व सिस्टम सिद्धान्त इमामुएल वालरस्टीन द्वारा निर्धारित किया गया है।

मध्यम संस्करण (Medium Versions)

राउल प्रीबिश (1901-1986) के कार्यों ने निर्भरता सिद्धान्त को उत्पन्न करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। राउल प्रीबिशि अर्जेंटीना के अर्थशास्त्री थे और अपने कैरियर के दौरान उन्होंने अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया, अर्जेंटीना सेन्ट्रल बैंक के महानिदेशक, लैटिन अमेरिका के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के प्रमुख, और व्यापार और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन विकास के सचिव के कार्यकारी सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, प्रेस्बिश ने एक जमीनी अध्ययन किया, जिसका शीर्षक था, द इकोनॉमिक डेवलपमेण्ट ऑफ लैटिन अमेरिका एण्ड इट्स प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स (1950) जो लैटिन अमेरिकी देशों के आर्थिक पिछड़ेपन की जाँच थी।

प्रीबिश के अनुसार, यह विकसित देशों के साथ व्यापार की प्रतिकूल शर्तें (TOT) हैं। जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से लैटिन अमेरिकी देशों की आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया है। टीओटी किसी देश की निर्यात कीमतों और उसकी आयात कीमतों के बीच का अनुपात है। जबकि लैटिन अमेरिकी देश प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादक हैं। वे इसे औद्योगिक रूप से उन्नत देशों को निर्यात करते हैं। इन प्राथमिक वस्तुओं को संसाधित और औद्योगिक रूप से उन्नत देशों में तैयार उत्पादों में बदल दिया जाता है। ये तैयार उत्पाद लैटिन अमेरिकी क्षेत्र सहित विकासशील देशों को निर्यात किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, देश अपने प्राथमिक वस्तुओं को सस्ते दामों पर निर्यात करते हैं और तैयार उत्पादों को उच्च कीमतों पर आयात करते हैं और इससे उनकी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हंस वोल्फगैंग सिंगर (1910-2006) के साथ किए गए अपने अनुभवजन्य अध्ययन के आधार पर, प्रीबिश ने प्रीबिश-सिंगर की शर्तों के व्यापार थीसिस (PST) को निर्धारित किया। पीएसटी का सुझाव है कि तैयार उत्पादों के उत्पादकों के साथ बढ़ते व्यापार घाटे के कारण प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादकों की अर्थव्यवस्था दिन-प्रतिदिन गिर रही है। दूसरे शब्दों में, प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादकों और तैयार उत्पादों के बीच आर्थिक अन्तर उनके बढ़ते आर्थिक सम्बन्धों के साथ मिलकर बढ़ता है। इस प्रकार, प्रीबिश-सिंगर की शर्त-व्यापार थीसिस (पीएसटी) ने निर्भरता सिद्धान्त के लिए नींव रखी।

प्रीबिश ने तुलनात्मक लाभ के सिद्धान्त और उदार अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण को चुनौती दी कि विकासशील देशों को मुक्त व्यापार से लाभ उठाने के लिए प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञ होना चाहिए। प्रीबिश ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए एक संरचनात्मक दृष्टिकोण पेश किया, जो विकास/अविकसितता और कोर/परिधि के द्वि-आधारी विरोधों पर आधारित था। दूसरे शब्दों में, उनका अध्ययन विकसित और विकासशील देशों के बीच स्वाभाविक रूप से असममित सम्बन्ध पर केन्द्रित

था। उदार सिद्धान्तों के विपरीत, प्रीबिस्क का दृष्टिकोण वैश्विक दक्षिण में देशों के अनुभव से विकास और अविकसितता के विषय की जाँच कर रहा था। लैटिन अमेरिका में आर्थिक पिछड़ेपन के कारणों को निर्धारित करने के बाद, प्रीबिस्क ने इसके बाद राज्य के हस्तक्षेप, लैटिन अमेरिका के आर्थिक एकीकरण, विषमताओं को दूर करने में भूमि सुधार और आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकीकरण (आईएसआई) जैसी कई सिफारिशें कीं। आयात प्रतिस्थापन औद्योगीकरण एक व्यापार नीति है। जो घरेलू स्तर पर उद्योगों को बढ़ावा देकर आयात को कम करना चाहती है। आईएसआई का प्रमुख उद्देश्य आयात में कमी है, जिससे व्यापार घाटे की समस्या का समाधान होता है, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। जिससे औद्योगिक आत्मनिर्भरता प्राप्त होती है और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है। हालाँकि, इन सिफारिशों के सफल कार्यान्वयन में कुछ बाधाएँ थीं। पहले लैटिन अमेरिकी देशों में तुलनात्मक रूप से छोटे बाजार पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करने और कीमतों को कम रखने के लिए पर्याप्त नहीं थे। दूसरा मुद्दा लैटिन अमेरिका को कृषि अर्थव्यवस्थाओं से औद्योगिक देशों में बदलने में कठिनाइयों से सम्बन्धित था। तीसरी समस्या यह थी कि आईएसआई ने पूँजी के आयात पर अधिक निर्भरता और औद्योगीकरण के लिए आवश्यक भारी मशीनरी का कारण बना।

अतिवादी सिद्धान्त (Extremist Theory)

अतिवादी निर्भरता सिद्धान्त मार्क्सवाद और लेनिन की साम्राज्यवाद की समझ पर बनाया गया है। आन्द्रे गौंडर फ्रैंक, जैम्स कॉक्रॉफ्ट और डेल जॉनसन को अतिवादी निर्भरता सिद्धान्तवादी माना जाता है। अतिवादी निर्भरता सिद्धान्तकारों का तर्क है कि निर्भरता सम्बन्ध के पीछे मकसद वैश्विक पूँजीवाद है। विकसित देश विकासशील देशों में अपने तैयार उत्पादों के लिए बाजार तलाशते हैं। इसके अलावा, विकसित देश भी विकासशील देशों को निवेश के लिए गंतव्य मानते हैं। जब विकासशील देश विकसित देशों से पूँजी उधार लेते हैं। तो ऋण चुकाने से उनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। अतिवादी निर्भरता सिद्धान्तकारों का मानना है कि वैश्विक दक्षिण में देशों के 'अविकसितता' एक ऐतिहासिक उत्पाद हैं। यहाँ 'अविकसितता' अविकसित अवस्था से भिन्न होती है। अविकसित विकास की कमी की स्थिति है, और अविकसितता दूसरे देश द्वारा शोषण की परिणति है। साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा उपनिवेशवाद, शोषण, और सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक पुनर्गठन की कालोनियों के केन्द्रों ने पूर्व कालोनियों को परिधीय और उनके पूर्व स्वामी (वर्तमान में विकसित देशों) को केन्द्र या कोर में बदल दिया है। नतीजतन, परिधि में देशों को पूँजी, प्रौद्योगिकी और तैयार माल के लिए मूल (विकसित देशों) पर निर्भर होना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, उपनिवेशवाद की सदियों (शताब्दियों) ने विकासशील देशों को प्राथमिक वस्तुओं, सस्ते श्रम और पूँजी, प्रौद्योगिकियों, और तैयार माल के भण्डार में बदल दिया है।

अतिवादी निर्भरता सिद्धान्तकारों का मानना है कि पूँजीवादी व्यवस्था द्वारा लागू श्रम का कठोर अन्तर्राष्ट्रीय विभाजन दुनिया के कुछ हिस्सों में अविकसितता के लिए जिम्मेदार है। यहाँ परिधि राज्यों को प्राथमिक वस्तुओं की आपूर्ति का काम सौंपा जाता है। सबसे चौकाने वाली बात यह है कि परिधि राज्यों को क्या आपूर्ति करनी है और उन्हें पूँजी और प्रौद्योगिकी के रूप में क्या प्राप्त करना है, इसका निर्धारण कोर के आर्थिक हितों से होता है। यहाँ, परिधि राज्यों के पास उनके विकास से सम्बन्धित मामलों पर कोई कथन या नियन्त्रण नहीं है। ऐसी हालत में, कोर और परिधि राज्यों में सरकारें पूँजीपतियों के हितों को सन्तुष्ट करने की कोशिश करती हैं। कोर और परिधि पर पूँजीपति वर्ग का यह नियन्त्रण पूँजीवाद या साम्राज्यवाद के उच्चतम चरण की विशेषता है इस प्रक्रिया में, परिधि वाले देश भी सम्प्रभुता के नुकसान का अनुभव करते हैं। क्योंकि निर्णय लेने की शक्ति कोर के पास है। कच्चे माल के निर्माता कोर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक संलग्न बन जाते हैं। लैटिन अमेरिका में वास्तविक राष्ट्रीय पूँजीवाद नहीं है। बल्कि यह एक पूँजीवाद है। जो निर्भर है यह निर्भर पूँजीवाद मुख्य अर्थव्यवस्थाओं में की गई प्रक्रियाओं और निर्णयों का परिणाम है।

अतिवादी निर्भरता सिद्धान्तकारों का तर्क है कि वैश्विक दक्षिण में देश विकास के लिए पश्चिमी मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकते हैं। उपनिवेशवाद के लम्बे इतिहास और उपनिवेशों में सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं के पुनर्गठन ने कोर और परिधि राज्यों के बीच सम्बन्धों का एक विषम ढाँचा तैयार किया। इसने तैयार उत्पादों के उत्पादकों और परिधि राज्यों को प्राथमिक वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता के रूप में मूल बना दिया है। इसके अलावा, व्यापार की शर्तें परिधि की कीमत पर कोर के दक्ष में हैं। जो कोर और परिधि राज्यों के बीच असमानताओं को और अधिक चौड़ा करता है। कट्टरपंथी निर्भरता सिद्धान्तकारों का मानना है कि प्राथमिक वस्तुओं और तैयार उत्पादों के बीच अदान-प्रदान के रूप में सरासर शोषण केवल विकासशील देशों की कमजोर स्थिति को खराब करेगा। दूसरे शब्दों में, यह असमान विनिमय अविकसितता के विकास को आगे बढ़ाता है। फ्रैंक जैसे अतिवादी निर्भरता

TOUCH 'n' PASS

सिद्धान्तकारों के अनुसार अविकसितता अविकसित से अधिक विकसित देशों के शोषण द्वारा बनाई गई स्थिति है। इसलिए एक समाजवादी क्रान्ति इस शोषणकारी और आश्रित रिश्ते से अलग होने का एकमात्र तरीका है।

विश्व व्यवस्था सिद्धान्त (World System Theory)

इम्मानुएल वालरस्टीन द्वारा प्रस्तावित विश्व व्यवस्था सिद्धान्त, निर्भरता सिद्धान्त का व्यापक संस्करण है। उदारवादी और अतिवादी निर्भरता सिद्धान्तकारों के विपरीत, जो कोर और परिधि के बीच आर्थिक सम्बन्धों के लिए अपने अध्ययन को सीमित करते हैं, विश्व व्यवस्था सिद्धान्त एक व्यापक भौगोलिक ढाँचे पर केन्द्रित हैं। साम्राज्यवाद की लेनिन की समझ द्वारा विश्व व्यवस्था सिद्धान्त यह मानता है कि आज के रूप में दुनिया को केवल वैश्विक पूँजीवाद के विकास के सन्दर्भ में समझा जा सकता है। क्योंकि, आज केवल एक विश्व व्यवस्था है, जो कि एक पूँजीवादी विश्व-अर्थव्यवस्था है, यूरोप में लम्बी सोलहवीं शताब्दी (1450-1640) के दौरान उभरा। वालरस्टीन के अनुसार, इस पूँजीवादी विश्व-अर्थव्यवस्था को अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए बाजार के लिए उत्पादन, और कोर और परिधीय राज्यों के बीच असमान विनिमय सम्बन्धों की विशेषता है। इसके अलावा इस वैश्विक पूँजी ने एक पदानुक्रमित संरचना उत्पन्न की है, जो इस विश्व, अर्थव्यवस्था के भीतर प्रत्येक राज्य की स्थिति निर्धारित करती है। इस श्रेणीबद्ध संरचना और बाजार तन्त्र के माध्यम से, कोर परिधि का शोषण करता है।

वालरस्टीन ने अर्ध-परिधि को 'परिधि' और 'कोर' के बीच तीसरी श्रेणी के रूप में पेश किया। अर्ध-परिधीय राज्य भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएँ हैं, जो आधुनिक उद्योगों, शहरों और बड़े किसानों जैसी विशेषताओं के कारण हैं। विश्व व्यवस्था सिद्धान्तकारों के अनुसार, कोर/अर्ध-परिधि/परिधि पदानुक्रम में स्थिति बदलने की सम्भावना बहुत कम हैं। इसलिए मुख्य परिधि और अर्ध-परिधि पूँजीवादी विश्व-अर्थव्यवस्था की स्थायी विशेषताओं के रूप में बनी हुई हैं। इसलिए, विश्व व्यवस्था सिद्धान्त सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक विकास के उदारवादी और आधुनिकीकरण सिद्धान्तों का आलोचक है। विश्व व्यवस्था सिद्धान्त, आगे कहता है कि अर्ध-परिधि राज्यों को परिधि में विभाजित करती है और यह कोर के खिलाफ एक एकीकृत विरोध को एक कठिन कार्य बनाती है। अर्ध-परिधि-परिधि शिविरों के भीतर विभाजन के कारण कोर अपना आधिपत्य बनाए रखता है। हालाँकि, विश्व व्यवस्था सिद्धान्त का तर्क है कि पूँजीवादी वैश्विक अर्थव्यवस्था के भीतर विरोधाभास पूँजीवाद की गिरावट और समाजवाद द्वारा इसके प्रतिस्थापन की ओर ले जाएगा।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. यदि किसी देश में बेरोजगारी लम्बे समय तक बनी रहती है, तो इसे ..... बेरोजगारी कहते हैं।

(क) अनौपचारिक (ख) तकनीकी
(ग) घर्षणात्मक (घ) दीर्घकालिक

उत्तर (घ) दीर्घकालिक

प्र.2. भारत को आत्मनिर्भर और स्व-उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का है?

(क) पहली पंचवर्षीय योजना (ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना
(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना (घ) चौथी पंचवर्षीय योजना

उत्तर (ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना

प्र.3. अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है जो—

(क) वृद्धि स्तर पर हो (ख) प्रारम्भिक स्तर पर हो
(ग) दोनों (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (ख) प्रारम्भिक स्तर पर हो

प्र.4. हम किस देश को विकसित तथा किसको अल्पविकसित कहें, यह इस बात पर निर्भर है कि हम विकास मापने के लिए किस मापदण्ड का प्रयोग करें?

(क) प्रो० हरबर्ट फ्रेन्कल (ख) हिगिन्स (ग) ए०आर० हर्शमैन (घ) कोई नहीं

उत्तर (क) प्रो० हरबर्ट फ्रेन्कल

TOUCH 'n' STUDY

प्र.5. अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के घरेलू उपाय है?
(क) परिवहन (ख) संचार (ग) शक्ति, सिंचाई (घ) आवास
(ङ) ये सभी
उत्तर (ङ) ये सभी

प्र.6. पूँजी निर्माण दर—
(क) कमी की जाए (ख) वृद्धि की जाए (ग) स्थिर रहे (घ) कोई नहीं
उत्तर (ख) वृद्धि की जाए

प्र.7. विकसित अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन-सा क्षेत्र अधिकतम रोजगार प्रदान करता है?
(क) उद्योग क्षेत्र (ख) सेवा क्षेत्र
(ग) कृषि एवं सहायक क्रिया (घ) विदेशी क्षेत्र
उत्तर (ग) कृषि एवं सहायक क्रिया

प्र.8. आर्थिक विकास—
(क) एक स्थैतिक विचार है (ख) एक गत्यात्मक विचार है
(ग) आर्थिक सन्तुलन का विचार है (घ) परम्परागत विचार है
उत्तर (ख) एक गत्यात्मक विचार है

प्र.9. एक देश की विकास दर निर्धारित होती है—
(क) सीमान्त बचत प्रवृत्ति द्वारा (ख) पूँजी संचय की दर द्वारा
(ग) तुलनात्मक लागत नियम द्वारा (घ) सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति द्वारा
उत्तर (ख) पूँजी संचय की दर द्वारा

प्र.10. विकास मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है यह कथन किस अर्थशास्त्री ने दिया?
(क) एडम स्मिथ (ख) शुम्पीटर
(ग) लेविस (घ) कोलीन क्लार्क
उत्तर (ग) लेविस

प्र.11. विकास की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है?
(क) अविकसित (ख) विकासशील (ग) विकसित (घ) ये सभी
उत्तर (ख) विकासशील

प्र.12. अल्पविकसित देशों के लिए निर्धन राष्ट्र शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री है—
(क) सेमुअल्सन (ख) उर्सुला हिक्स
(ग) मायर एवं बाल्डविन (घ) ये सभी
उत्तर (ग) मायर एवं बाल्डविन

प्र.13. U.N.O. ने अल्पविकसित देश को परिभाषित करने के लिए किन मानदण्ड को अपनाया है?
(क) प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय (ख) प्रति व्यक्ति वास्तविक आय
(ग) राष्ट्रीय मौद्रिक आय (घ) राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय
उत्तर (ख) प्रति व्यक्ति वास्तविक आय

प्र.14. द्वैत अर्थव्यवस्था का मॉडल दिया—
(क) आर०एफ० हैरोड ने (ख) आर०एम० सोलो ने
(ग) ए०के० सेने ने (घ) डब्ल्यू०ए० लेविस ने
उत्तर (घ) डब्ल्यू०ए० लेविस ने

TOUCH 'n PASS

प्र.15. सरकार भारत में गरीबी कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा दृष्टिकोण अपना रही हैं?

1. विशिष्ट गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
2. विकासोन्मुखी विकास
3. गरीबों की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना।
4. नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए।

(क) केवल 1 और 3 (ख) केवल 1 और 2 (ग) केवल 2 और 3 (घ) ये सभी

उत्तर (घ) ये सभी

प्र.16. निम्नलिखित में से कौन-सा गरीब के माँग पक्ष के दुष्चक्र के लिए सही है—

(क) कम आय → कम माँग → कम निवेश → पूँजी की कमी → कम उत्पादकता
(ख) कम उत्पादकता → कम आय → कम बचत → कम निवेश → पूँजी की कमी
(ग) कम आय → कम निवेश → कम माँग → पूँजी की कमी
(घ) कम माँग → कम बचत → कम उत्पादकता → कम निवेश → पूँजी की कमी

उत्तर (क) कम आय → कम माँग → कम निवेश → पूँजी की कमी → कम उत्पादकता

प्र.17. गरीबी का दुश्चक्र—

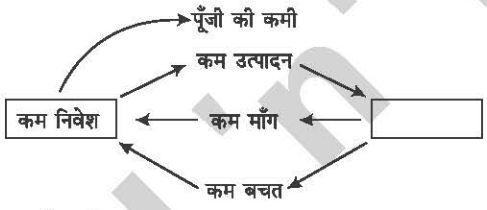

इसमें खाली स्थान पर क्या आयेगा?

(क) कम मेहनत (ख) कम लाभ (ग) कम आय (घ) कम पूँजी

उत्तर

प्र.18. ब्रके ने द्वितीय समाज का आर्थिक सिद्धान्त दिया हैं जिसको वे ..... कहते हैं—

(क) पूर्वी अर्थशास्त्र (ख) द्वितीय अर्थशास्त्र (ग) दोनों (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (ग) दोनों

प्र.19. सामाजिक द्वैतवाद का सिद्धान्त किस तरह की अर्थव्यवस्था पर लागू होता है?

(क) अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्था (ख) अल्प-विकसित अर्थव्यवस्था
(ग) विकसित अर्थव्यवस्था (घ) 'क' और 'ख' दोनों

उत्तर (क) अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्था

प्र.20. फाई रेनिस मॉडल की मान्यताएँ—

1. जनसंख्या वृद्धि एवं बर्हिजात तत्त्व है।
2. भूमि की पूर्ति स्थिर है।
3. कृषि क्षेत्र का उत्पादन केवल भूमि तथा श्रम का फलन है।
4. इसके मॉडल में इकहरी अर्थव्यवस्था की कल्पना कि गई है।

(क) 1, 2, 3 (ख) 2, 3, 4 (ग) 2, 3, 1 (घ) 1, 2, 4

उत्तर (क) 1, 2, 3

TOUCH 'n' PASS

UNIT-VI

प्रौद्योगिकीय विकास
Technical Progress

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. सन्निहित और असम्बद्ध में क्या अन्तर है?

What is the difference between embodied and disenbodied?

उत्तर सन्निहित स्मृति आवंटन में, प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए स्मृति का एकमात्र सन्निहित खण्ड निर्दिष्ट किया जाता है। गैर-सन्निहित मैमोरी आवंटन में, प्रक्रिया को मैमोरी में कई मैमोरी स्थानों पर विभिन्न मैमोरी सेक्शन की अनुमति दी जाती है।

प्र.2. तकनीकी प्रगति के तीन प्रकार क्या हैं?

What are the three types of technological progress?

उत्तर (i) उत्पादन की तकनीकी कुशलता (ii) उत्पादन क्रिया का विस्तार (iii) साधन गहनता में परिवर्तन।

प्र.3. तकनीक के चयन से आप का क्या अभिप्राय है?

What do you mean by selection of technology?

उत्तर संरचना, प्रोत्साहनमूलक मूल्यतन्त्र, समतावादी सामाजिक संरचना, उचित वितरण प्रणाली, जनसहयोग आदि महत्त्वपूर्ण पहलू हैं जो तकनीक चयन पर निर्भर करते हैं। मुख्य रूप से तकनीक को निम्न दो भागों में बाँटा जाता है—(i) श्रम-प्रधान तकनीक एवं पूँजी-प्रधान तकनीक।

प्र.4. आर्थिक संवृद्धि क्या हैं?

What is economic growth?

उत्तर आर्थिक संवृद्धि की परिभाषा—आर्थिक संवृद्धि से मतलब किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि से है। सामान्य रूप से यदि किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो कहा जाता है कि उस देश में आर्थिक संवृद्धि हो रही है।

प्र.5. व्यष्टि और समष्टि में क्या अन्तर हैं?

What is the difference between micro and macro?

उत्तर व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है; जैसे—एक उपभोक्ता, एक फर्म (उत्पादक) इत्यादि। समष्टि अर्थशास्त्र में सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर बड़े आर्थिक समूहों का अध्ययन व अन्तर्सम्बन्धों का विश्लेषण किया जाता है; जैसे—समग्र माँग, समग्र पूर्ति, राष्ट्रीय आय इत्यादि।

प्र.6. तकनीकी प्रगति विकास को कैसे प्रभावित करती है?

How does technological progress affect development?

उत्तर तकनीकी प्रगति मानव संसाधनों की दक्षता बढ़ाने में मदद करती है। उत्पादन की तकनीकों के उपयोग के लिए श्रम को प्रशिक्षण दिया जाता है। यह उनकी दक्षता में सुधार करता है। श्रमिकों की दक्षता में वृद्धि, उत्पादन के अधिक नवीन विचारों को सुविधाजनक बनाती है।

TOUCH n PASS

प्र.7. तटस्थ प्रक्रियाएँ क्या हैं?

What are neutral processes?

उत्तर तटस्थ प्रक्रियाएँ भविष्यवाणी करती हैं कि सभी प्रजातियाँ अपनी जनसांख्यिकीय दरों (जन्म, मृत्यु, फैलाव और जाति उद्‌भवन दर) में समान है और बहिष्करण प्रक्रियाएँ पूरी तरह यादृच्छि के हैं।

प्र.8. तटस्थता कितने प्रकार की होती है?

How many types are of neutrality?

उत्तर तटस्थता तीन प्रकार की होती है—1. वर्गों के बीच तटस्थता (2) सांस्कृतिक गुटों के बीच तटस्थता (3) राजनीतिक पार्टियों के बीच तटस्थता।

प्र.9. तटस्थता के उदाहरण क्या हैं?

What are the examples of neutrality?

उत्तर तटस्थता पदार्थ जो सबसे प्रसिद्ध हैं वे हैं—पानी, टेबल, नमक, चीनी का घोल और खाना पकाने का तेल। खाना पकाने का तेल एक तटस्थ पदार्थ है।

प्र.10. तटस्थता की विशेषताएँ क्या हैं?

What are the characteristics of neutrality?

उत्तर तटस्थता वक्र की यह विशेषता इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता यदि एक वस्तु की अधिक मात्रा का उपयोग करता है तो वह दूसरी वस्तु की कम मात्रा का उपयोग करेगा, तभी वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से मिलने वाली सन्तुष्टि समान होगी।

प्र.11. प्रक्रिया मॉडलिंग से आप क्या समझते हैं?

What do you understand by process modelling?

उत्तर प्रक्रिया मॉडलिंग व्यापक मात्रात्मक गतिविधि आरेख और फ्लोचार्ट उत्पन्न करती है जिसमें निम्नलिखित सहित किसी दी गई प्रक्रिया के कामकाज में महत्त्वपूर्ण अन्तर्दृष्टि होती है।

प्र.12. प्रक्रिया मॉडल के उपयोग का प्राथमिक उद्‌देश्य क्या है?

Write the problem of selection of technology

उत्तर प्रक्रिया मॉडल मौजूदा या नियोजित प्रक्रियाओं का चित्रमय प्रतिनिधित्व है और यह समझने के लिए उत्कृष्ट संसाधन है कि कौन-से कार्य किए जाते हैं और वे कैसे कार्य करते हैं। प्रोसेस मॉडल का एक प्राथमिक उद्‌देश्य उद्‌यम के भीतर सूचना की जरूरतों की खोज को सुगम बनाना है।

प्र.13. प्रक्रिया मॉडलिंग के दो मुख्य उद्‌देश्य क्या हैं?

What are the two main objectives of process modelling?

उत्तर 1. प्रक्रियाएँ कैसे काम करती हैं, इसकी स्पष्ट समझ प्रदान करें। 2. निरन्तरता बनाएँ और प्रक्रियाओं को मानकीकृत और नियन्त्रित करने का एक तरीका बनाएँ।

प्र.14. काल्डोर वृद्धि मॉडल की कोई पाँच आलोचनाएँ लिखिए।

Write any five criticisms of Kaldor growth model?

उत्तर इस मॉडल की प्रमुख पाँच आलोचनाएँ निम्नवत् हैं—

1. आय वितरण की समुचित व्याख्या नहीं करता है।
2. काल्डोर मॉडल की मान्यताएँ दृढ़ एवं जटिल हैं।
3. काल्डोर मॉडल व्यक्तिगत बचतों की उपेक्षा करता है।
4. यह मॉडल निरपेक्ष मॉडल है; क्योंकि यह अनुत्पादक व्यय की उपेक्षा करता है।
5. यह मॉडल पूँजी पर आय के पुनर्वितरण प्रभाव की उपेक्षा करता है।

TOUCH 'n PASS

प्र.15. तकनीक के चुनाव की समस्या लिखिए।
Write the problem of selection of technology.

उत्तर तकनीक के चुनाव की समस्या से आशय किसी विशिष्ट परियोजना के लिए उत्पादन के साधनों के संयोग के प्रकार के चुनाव से है।

प्र.16. तकनीकी से क्या आशय है?
What is the meant by technology?

उत्तर तकनीकी से आशय उत्पादन के तरीके से है अथवा किसी उत्पादन कार्य के लिए विभिन्न साधनों को किस ढँग से लगाया जाये, इसकी मात्रात्मक अभिव्यक्ति है।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. तकनीकी प्रगति से क्या अभिप्राय हैं?
What is the meaning of Technological Progress?

उत्तर

तकनीकी प्रगति से अभिप्राय
(Meaning of Technological Progress)

तकनीकी प्रगति तीव्र आर्थिक विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है। आज के विकसित राष्ट्र उच्च तकनीक के आधार पर ही विकास के इस स्तर तक पहुँच सके हैं; जबकि अल्प-विकसित देशों में वैज्ञानिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक की न केवल कमी है, बल्कि तकनीकी प्रगति करने की उत्कण्ठा, तकनीकी परिवर्तन लाने की पहल और उसके लिए संस्थागत ढाँचे का अभाव भी है। यद्यपि अल्प-विकसित देशों का वर्तमान विकृत सामाजिक ढाँचा गतिशील तकनीकी परिवर्तन को अंगीकार करने में सक्षम नहीं है फिर भी यह कहा जाता हैं कि तकनीकी प्रगति के अभाव में ये देश अपना तीव्र आर्थिक विकास करने में सफल नहीं हो सकेंगे। अत: आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों के लिए यह आवश्यक है कि वे तकनीकी प्रगति हेतु हर सम्भव प्रयास करें। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु देश के अन्दर नवीन तकनीकों का विकास और विकसित देशों से उन्नत तकनीक का आयात किया जाना चाहिए।

तकनीकी प्रगति एक अत्यन्त व्यापक शब्द है जिसमें प्रौद्योगिक ज्ञान के विकास के अतिरिक्त तकनीकी परिवर्तन, नवप्रवर्तन और उद्यमशीलता का भी समावेश होता हैं। **प्रो० कुजनेट्स** ने तकनीकी प्रगति के अन्तर्गत पाँच तत्त्वों का समावेश किया हैं—

(i) **वैज्ञानिक खोज** (Scientific Discovery)—अर्थात् तकनीकी ज्ञान में वृद्धि करना
(ii) **आविष्कार** (Inventions) अर्थात् विद्यमान ज्ञान का सर्वोत्तम ढंग से प्रयोग करना
(iii) **नव-प्रवर्तन** अर्थात उत्पादन क्रियाओं में आविष्कारों को लागू करना
(iv) **सुधार** (Improvement) अर्थात् आविष्कारों की उपादेयता में वृद्धि करना तथा
(v) **तकनीकी-सामाजिक परिवर्तन (Techno-social change)** अर्थात् संस्थागत ढाँचे को तकनीकी प्रगति के अनुकूल बनाना।

तकनीकी परिवर्तन से तात्पर्य 'उत्पादन फलन' (Production Function) को इस प्रकार परिवर्तित करना है ताकि उसमें सभी ज्ञात तकनीकों का समावेश हो सके। **किण्डलबर्जर** के अनुसार, तकनीकी परिवर्तन किसी उद्यम के वास्तविक उत्पादन फलन को इस तरह परिवर्तित कर देता है कि उन्हीं साधनों से अधिक उत्पादन या फिर कम साधनों से उत्पादन की उतनी ही मात्रा प्राप्त करना सम्भव होता है। तकनीकी परिवर्तन का परिणाम उत्पादन की अधिक मात्रा के अतिरिक्त अधिक उपयोगी नई वस्तुओं के उत्पादन के रूप में भी होता है। आर्थिक विकास के सम्बन्ध में तकनीकी प्रगति से तात्पर्य उत्पादन की प्रविधि में परिवर्तन से है और इस दृष्टि से नव-प्रवर्तन का पर्यायवाची कहा जा सकता हैं।

आधुनिक अर्थशास्त्री तकनीकी प्रगति को विस्तृत अर्थों में प्रयोग करते हैं। उनकी धारणा है कि तकनीकी प्रगति से आशय मात्र तकनीकी ज्ञान में सुधार ही नहीं है बल्कि उन सामाजिक अथवा संस्थागत परिवर्तनों से भी है जो तकनीकी प्रगति से पूर्व होते हैं और उसके लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। **हर्बर्ट फ्रैकेल** (Herbert Frankel) के अनुसार, "तकनीकी परिवर्तन केवल तकनीकी ज्ञान में सुधार नहीं हैं बल्कि उससे अधिक है। तकनीकी परिवर्तन से पहले सामाजिक परिवर्तन होने चाहिए और समुदाय में अपनी सामाजिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संस्थाओं को बदलने की तीव्र इच्छा एवं तत्परता होनी चाहिए ताकि इन संस्थाओं को नई उत्पादन तकनीकों और आर्थिक क्रियाओं में तीव्र प्रगति के अनुरूप बनाया जा सके।"

TOUCH 'n PASS

प्र.2. सोलो मॉडल की मान्यताएँ लिखिए।
Write the assumptions of Solow model.

उत्तर

सोलो मॉडल
(Solow Model)

नव-प्रतिष्ठित मॉडलों में **रॉबर्ट एम० सोलो** का मॉडल अग्रणी है। प्रो० सोलो ने अपने आर्थिक संवृद्धि मॉडल की रचना हैरड-डोमर मॉडल के विकल्प के रूप में प्रस्तुत की। हैरड-डोमर मॉडल की कमी यह रही कि इसमें लचीलेपन का अभाव है अर्थात् यह उत्पादक संसाधनों की सापेक्ष स्थिति में होने वाले परिवर्तनों के प्रति तटस्थ रहता है। हैरड-डोमर मॉडल स्थिर पूँजी श्रम अनुपात की मान्यता पर आधारित है। सोलों ने हैरड-डोमर मॉडल की 'स्थिर अनुपातों' (स्थिर पूँजी-उत्पाद अनुपात तथा स्थिर पूँजी श्रम अनुपात) की मान्यता को नकारते हुए स्पष्ट किया कि इस मान्यता को हटाने से हैरड के सतत विकास के मार्ग में अन्तर्निहित अस्थिरता को दूर करने के साथ-साथ सन्तुलित विकास की स्थिति को कायम रखा जा सकता है। उनके अनुसार, दीर्घकाल में उत्पादन के दोनों साधनों पूँजी तथा श्रम को एक-दूसरे से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। साथ ही इन दोनों के अनुपात में भी परिवर्तन हो सकता है। एक विशुद्ध पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में इन साधनों के उपलब्ध ढेर सारे अनुपातों में से उस अनुपात का चयन किया जाता है जो स्थिर विकास का आश्वासन देता है, जो वृद्धि की इच्छित दर तथा प्राकृतिक दर को सम्भव बनाता है। सोलो ने अपने मॉडल में व्यक्तियों के पूर्व ज्ञान, वस्तु, श्रम तथा पूँजी बाजार में सहजता से समायोजन आदि आधारभूत मान्यताओं को अंगीकार किया है।

सोलो मॉडल की मान्यताएँ (Assumptions of Solow Model)

सोलो ने अपने मॉडल का निर्माण निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर किया है—

1. उत्पादन केवल दो साधनों पूँजी (K) तथा श्रम (L) का प्रतिफल है तथा इन दोनों साधनों को परस्पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
2. अर्थव्यवस्था में एक सम्मिश्र वस्तु का उत्पादन होता है।
3. अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है।
4. कीमतें तथा मजदूरी लोचशील होती हैं।
5. तकनीकी प्रगति तटस्थ रहती है।
6. बचतें उत्पादन-स्तर का एक निश्चित अनुपात है अर्थात् समाज में बचत प्रवृत्ति स्थिर है। अन्य शब्दों में, बचत (S) कुल उत्पादन (Y) के निश्चित भाग (s) के बराबर होती है अर्थात्
$$S = sY \ (s = \text{बचत की दर})$$
7. पूँजी का मूल्य ह्रास नहीं होता जिसके फलस्वरूप निवेश = बचतें और यह पूँजीकोष में होने वाले परिवर्तन $\left(\frac{dK}{dt} = K\right)$ के बराबर होती है अर्थात्
$$I = sY = K$$
8. श्रम शक्ति की वृद्धि-दर बहिर्जात (Exogoneous) तत्त्वों द्वारा निर्धारित होती है और निश्चित आनुपातिक दर (n) के हिसाब से बढ़ती है।
9. पैमाने के स्थिर प्रतिफल लागू होते हैं। अन्य शब्दों में, उत्पादन फलन प्रथम कोटि का समरूप होता है। अर्थात्
$$Y = f(KL) \ (\text{जहाँ } Y = \text{उत्पादन}, F = \text{फलन})$$

उपर्युक्त मान्यताओं के आधार पर सोलो अपने मॉडल में यह स्पष्ट करते हैं कि यदि तकनीकी गुणांक परिवर्तनशील हों तो पूँजी-श्रम अनुपात काल पर्यन्त सन्तुलन अनुपात की दिशा में समायोजित होने की प्रवृत्ति रखता है। यदि श्रम से पूँजी का प्रारम्भिक अनुपात अधिक होगा तो श्रम शक्ति की तुलना में पूँजी तथा उत्पादन की वृद्धि अधिक धीरे होगी और विलोमशः भी। सोलों का विश्लेषण सन्तुलन पथ (स्थिर अवस्था) की ओर केन्द्रित है चाहे वह किसी भी पूँजी श्रम अनुपात से क्यों न प्रारम्भ हुआ हो।

TOUCH n PASS

प्र.3. सोलो मॉडल की हैरड-डोमर से तुलना कीजिए।
Compare the Solow Model with the Harrod-Domar Model.

उत्तर

सोलो मॉडल की हैरड-डोमर मॉडल से तुलना
(Comparison of Solow Model with Harrod-Domar Model)

सोलो मॉडल की हैरड-डोमर मॉडल की तुलना निम्नलिखित हैं—

1. सोलों का दीर्घकालीन वृद्धि मॉडल हैरड-डोमर मॉडल पर एक सुधार है तथा इसे हैरड-डोमर मॉडल के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें नव-प्रतिष्ठित उत्पादन फलन का प्रयोग किया गया है।
2. सोलो मॉडल में हैरड-डोमर मॉडल की 'स्थिर अनुपातों' वाली मान्यता को छोड़कर शेष सभी मान्यताओं को स्वीकार किया गया है।
3. हैरड-डोमर मॉडल में अर्थव्यवस्था अधिक से अधिक छुरी-धार (Knife-edge) सन्तुलन ही प्राप्त करती है और वह भी तब जबकि इसके प्रमुख प्राचलों—बचत अनुपात, पूँजी-उत्पाद अनुपात तथा श्रम-शक्ति की वृद्धि दर में कोई अन्तर न आए। इन प्राचलों में यदि तनिक भी विचलन उत्पन्न होता है तो इसका परिणाम यह होगा कि या तो बेरोजगारी में वृद्धि हो जाएगी या फिर दीर्घकालीन स्फीति आ जाएगी। इसलिए सोलो ने स्थिर अनुपातों की मान्यता के बिना एक दीर्घकालीन वृद्धि मॉडल प्रस्तुत किया है जो सतत वृद्धि अवस्था को दर्शाता है।
4. हैरड के विपरीत, सोलो की मान्यता है कि पूँजी और श्रम के बीच प्रतिस्थापन की सम्भावना के कारण विकास-प्रक्रिया में समायोजनशीलता बढ़ जाती है। साथ ही, उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप उत्पादन की कम या अधिक पूँजी-श्रम अनुपात वाली तकनीक का चयन करना सम्भव हो जाता है।
5. सोलो मॉडल में, सन्तुलित विकास दर (हैरड-मॉडल के अनुसार Gw) पूँजी-श्रम अनुपात में आवश्यक परिवर्तनों की सहायता से श्रम-शक्ति की वृद्धि दर (हैरड मॉडल के अनुसार Gn) के अनुरूप सदैव समायोजन कर लेती है; जबकि हैरड मॉडल में ऐसा होना सम्भव नहीं है।
6. दीर्घकालीन वृद्धि दर मुख्यत: श्रमशक्ति की वृद्धि दर और तकनीकी प्रगति द्वारा निर्धारित होती है; जबकि हैरड मॉडल में इन दोनों को स्थिर मान लिया गया है। सोलो मॉडल में इन्हें स्थिर नहीं माना गया है बल्कि इन कठोरताओं एवं रुकावटों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया हैं जिससे यह मॉडल अधिक वास्तविक एवं व्यावहारिक हो गया है।

प्र.4. सोलो मॉडल की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
Critically explain the solow model.

उत्तर

सोलो मॉडल की आलोचना
(Criticism of Solow's Model)

सोलो मॉडल की प्रमुख आलोचनाएँ निम्नवत् हैं—

1. **अवास्तविक मान्यताएँ**—सोलो का मॉडल पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। इसके अतिरिक्त इस मॉडल में यह भी मान लिया गया है कि निवेश बचत पर निर्भर करता है।
2. **वास्तविक वृद्धि दर (G) तथा आवश्यक वृद्धि दर (Gw) के मध्य सन्तुलन की उपेक्षा**—सोलो का मॉडल हैरड के आवश्यक वृद्धि दर (Gw) तथा प्राकृतिक वृद्धि-दर (Gn) के बीच सन्तुलन की व्याख्या करता है, परन्तु यह वास्तविक वृद्धि दर (G) तथा आवश्यक वृद्धि दर (Gw) के मध्य सन्तुलन की समस्या पर ध्यान नहीं देता है। इससे यह मॉडल अपूर्ण हो जाता है।
3. **निवेश-फलन की अनुपस्थिति**—सोलो मॉडल में निवेश फलन को सम्मिलित नहीं किया गया है। यदि इसे सम्मिलित कर लिया जाए तो इसमें भी अस्थिरता की हैरड समस्या पुन: उत्पन्न हो जाती है।
4. **पूँजी की समरूपता एवं लोचशीलता पर आधारित**—सोलो मॉडल पूँजी की समरूपता एवं लोचशीलता की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। वास्तव में, पूँजीगत पदार्थों में पर्याप्त भिन्नता विद्यमान रहती है। जिससे समूहीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पूँजीगत पदार्थों में भिन्नता के फलस्वरूप सतत वृद्धि के पथ पर अग्रसर होना सहज नहीं होता है।

TOUCH 'n PASS

5. **श्रम एवं पूँजी का प्रतिस्थापन**—सोलो ने श्रम एवं पूँजी के बीच प्रतिस्थापन की सम्भावना को स्वीकार करके आर्थिक विकास के एक सरल एवं सपाट मॉडल का निर्माण किया है। यद्यपि दीर्घकाल में श्रम एवं पूँजी को कुछ सीमा तक परस्पर घटा-बढ़ा कर प्रतिस्थापित किया जा सकता है, परन्तु प्रतिस्थापन की सम्भावना सदैव विद्यमान रहती है, इसे मान लेना उचित नहीं होगा।

प्र.5. कालडोर के आर्थिक वृद्धि मॉडल की मान्यताएँ लिखिए।
Write assumptions of Kaldor's Model of Economic Growth.

उत्तर

कालडोर के आर्थिक वृद्धि माडल की मान्यताएँ
(Assumptions of Kaldor's of Economic Growth)

कालडोर का वृद्धि मॉडल निम्नलिखित पूर्व धारणाओं पर आधारित है—

1. एक विकासशील अर्थव्यवस्था में उत्पादन के एक स्तर को प्राप्त करने हेतु संसाधनों की मात्रा सीमित होती है।
2. उत्पादन के दो साधन हैं—पूँजी तथा श्रम। इस दृष्टि से आय को भी दो भागों में बाँटा जा सकता है—लाभ और मजदूरी। लाभ की सकल मात्रा बचा ली जाती है तथा मजदूरी की सकल मात्रा उपभोग कर ली जाती है।
3. इस मॉडल में मौद्रिक नीति एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा मौद्रिक मजदूरी स्थिर रहती है।
4. सकल बचतें मजदूरियों में से की गई बचतों तथा लाभों में से की गई बचतों का योग होती हैं।
5. तकनीकी प्रगति पूँजी संचय की दर पर निर्भर करती है।
6. आय मजदूरियों तथा लाभों का योग है। मजदूरियों में शारीरिक श्रम का प्रतिफल तथा वेतन सम्मिलित है तथा लाभों में साहसियों तथा सम्पत्ति के स्वामियों की आय सम्मिलित है।
7. यह मान लिया गया है कि पूँजी संचय तथा पूँजीगत वस्तु बनाने वाले उद्योगों, में तकनीकी प्रगति के कारण प्राविधिक चयन (Choice of technique) में परिवर्तन होता है।
8. उत्पादन फलन कालपर्यन्त अपरिवर्तित रहता है तथा उत्पादन में स्केलगत स्थिर प्रतिफल का नियम लागू होता है। पूँजी तथा श्रम एक-दूसरे के पूरक होते हैं।
9. श्रमिकों की सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति पूँजीपतियों की सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति की अपेक्षा अधिक होती है। अर्थात, $sp < sw$।
10. यह कीन्स की पूर्णरोजगार परिकल्पना पर आधारित है जिसमें अल्पकाल में वस्तुओं एवं सेवाओं की समग्र पूर्ति बेलोच होती है।
11. मॉडल में प्रयुक्त समस्त समष्टि आर्थिक अवधारणाएँ—आय, मजदूरियाँ एवं लाभ, पूँजी, बचत तथा निवेश स्थिर मूल्यों में व्यक्त की गई हैं।
12. यह मजदूरी वस्तु (Wage goods) के रूप में स्थिर मजदूरी पर असीमित श्रम पूर्ति की मान्यता पर आधारित है।
13. निवेश की दर या निवेश का कुल आय से अनुपात को एक स्वतन्त्र चर राशि माना गया है। अर्थात् बचत करने की प्रवृत्ति (sp या sw) में परिवर्तन होने पर निवेश में परिवर्तन नहीं होते।

प्र.6. कालडोर मॉडल की हैरड-डोमर मॉडल से तुलना कीजिए।
Compare of Kaldor Model with Harrod-Domar Model.

उत्तर

कालडोर मॉडल की हैरड-डोमर मॉडल से तुलना
(Comparison of Kaldor Model with Harrod-Domar Model)

कालडोर की धारणा के अनुसार निवेश को पूँजी स्टॉक में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि निवेश का राष्ट्रीय आय से अनुपात है।

$$\frac{1}{Y} = s = \frac{\Delta K}{Y}$$

उपर्युक्त समीकरण में ΔY से गुणा तथा ΔY से भाग देने पर,

$$\frac{1}{Y} = s = \frac{\Delta K}{\Delta Y}\frac{\Delta Y}{Y}$$

TOUCH 'n' PASS

समीकरण में $\frac{\Delta Y}{Y}$ हैरड की अभीष्ट वृद्धि दर (Gw) को व्यक्त करता है जिसे काल्डोर G के रूप में वर्णन करता है और $\frac{\Delta K}{\Delta Y}$ को पूँजी-उत्पाद अनुपात v के रुप में।

अत: $$\frac{1}{Y} = s.G.v$$

हैरड के अभीष्ट वृद्धि दर के समीकरण को प्रदर्शित करने के लिए जैसा कि हम जानते हैं, काल्डोर का समीकरण है।

$$\frac{P}{Y} = \frac{1}{(sp - sw)} \cdot \frac{1}{Y} - \frac{sw}{(sp - sw)}$$

या $$\frac{P}{Y} = \frac{1}{sp} \cdot \frac{1}{Y} \qquad (\because \quad sw = 0)$$

$$\frac{1}{Y} = G.v = Gw.Cr$$

$$\frac{P}{Y} = \frac{1}{sp} Gw.Cr$$

अपने मॉडल में काल्डोर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि "अभीष्ट और प्राकृतिक वृद्धि दरें एक-दूसरे से स्वतन्त्र नहीं हैं। यदि लाभ की सीमाएँ लोचदार हों तो $\frac{P}{Y}$ में परिणामी परिवर्तन द्वारा पहली, दूसरे के साथ अपने आपको समायोजित करेंगी।"

प्र.7. काल्डोर मॉडल एवं अल्प-विकसित देश पर टिप्पणी कीजिए।
Comment on Kaldor model and Under developed country.

उत्तर

काल्डोर मॉडल एवं अल्प-विकसित देश
(Kaldor Model and UDCs)

काल्डोर के वृद्धि मॉडल पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट होता है कि यह विकसित देशों के साथ-साथ विकासशील देशों के लिए भी काफी उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण है। यह मॉडल आर्थिक वृद्धि की केवल प्रावैगिक यान्त्रिकी पर ही ध्यान नहीं देता वरन् यह विकास प्रक्रिया की विशिष्टताओं का भी उल्लेख करता है। यह मॉडल स्थिर जनसंख्या तथा वृद्धिशील जनसंख्या के बीच भेद करता है। पुन: यह मॉडल सामान्य उत्पादन फलन के स्थान पर तकनीकी प्रगति फलन का प्रयोग करता है। यह मॉडल यह भी स्पष्ट करता है कि जब जनसंख्या वृद्धि की दर आर्थिक वृद्धि दर के बराबर अथवा उससे अधिक होती है तब तकनीकी प्रगति फलन विपरित ढंग से प्रभावित होता है तथा अर्थव्यवस्था पूर्व-परिपक्व ह्रास (Premature stagnation) की ओर मुड़ जाती है। उल्लेखनीय है कि अल्प-विकसित देश जनसंख्या की ऊँची वृद्धि दर की समस्या से ग्रस्त रहते हैं। काल्डोर का मॉडल इस समस्या के समाधान हेतु उपाय सुझाने में अग्रणी भूमिका निभाता है। इस समस्या का समाधान तकनीकी प्रगति फलन में निहित है जो उत्पादकता वृद्धि तथा पूँजी संचय से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में काल्डोर ने प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि तथा निवेश वृद्धि दर में एक मजबूत सम्बन्ध की विवेचना की है। अन्य शब्दों में, काल्डोर ने तकनीकी प्रगति फलन के पर्याप्त ऊँचे मूल्य पर बल प्रदान किया है। यदि यह देश तकनीकी प्रगति के स्तर को ऊँचा उठाते हैं तब वृद्धिशील जनसंख्या के साथ भी सन्तुलित विकास प्राप्त कर सकते हैं अन्यथा जनसंख्या नियन्त्रण का एक अन्य विकल्प खुला रहेगा।

इस तरह, काल्डोर द्वारा व्यक्त दोनों विकल्प तकनीकी प्रगति के स्तर को बढ़ाना अथवा जनसंख्या नियन्त्रण विशेषकर अल्प-विकसित देशों में आर्थिक वृद्धि की ऊँची दर को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परन्तु अल्प-विकसित देशों में इन दोनों विकल्पों को मूर्त रूप देना एक कठिन कार्य हैं। इसके लिए प्रचुर मात्रा में पूँजी, बचत एवं निवेश का होना आवश्यक होता है जिसकी अल्प-विकसित देशों में प्राय: कमी व्याप्त रहती है। भारत जैसे विकासशील देशों में काफी प्रयास के बावजूद जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण नहीं किया जा सका है साथ ही यहाँ पूँजी का अभाव भी है। इन देशों में पूँजी की कमी, पूँजी संचय को तो कुप्रभावित करती ही है साथ ही निर्धनता के दुश्चक्र को भी बढ़ावा देती है। जिससे बाद में तोड़ना कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त, अल्प-विकसित देशों में तकनीकी प्रगति की ऊँची दर को प्राप्त करना भी एक दुष्कर कार्य है। विकास के अन्तिम चरण में तकनीकी प्रगति गुणांक के मूल्य में वृद्धि करना सम्भव है, परन्तु आरम्भिक चरण में बचत एवं निवेश की नीची प्रवृत्ति के

TOUCH 'n PASS

कारण ऐसा सम्भव नहीं हो पाता है। सम्पूर्ण रूप में, उपर्युक्त कठिनाइयों के बावजूद अल्प-विकसित देशों की समस्याओं के समाधान में काल्डोर के मॉडल की भूमिका अहम एवं काफी महत्त्वपूर्ण है।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. आर्थिक विकास में तटस्थ और गैर-तटस्थ तकनीकी प्रगति का वर्णन कीजिए।
Describe the neutral and Non-Neutral Technical Progress.

उत्तर

तटस्थ और गैर-तटस्थ तकनीकी प्रगति
(Neutral and Non-Neutral Technical Progress)

एक तकनीकी प्रगति तटस्थ तब कही जाती है; जबकि वह न तो पूँजी-बचत और न ही श्रम-बचत करने वाली होती है अर्थात् इनके प्रभाव इस अर्थ में तटस्थ होते हैं कि इन दोनों साधनों में से कोई किसी सीमा पर अधिक अथवा कम महत्त्वपूर्ण नहीं हो पाता है। इसके विपरीत जब प्रगति अथवा परिवर्तन पूँजी बचतकारी अथवा श्रम बचतकारी हो तो इसे गैर-तटस्थ तकनीकी प्रगति कहते हैं। तटस्थता के सम्बन्ध में दो परिभाषाएँ महत्त्वपूर्ण हैं, एक का प्रतिपादन **प्रो० हिक्स** द्वारा किया गया है; जबकि दूसरी का प्रतिपादन **प्रो० हैरड** ने किया है।

(1) तटस्थरता के सम्बन्ध में हिक्स की धारणा (Hicks View bbout Neutrality)

प्रो० हिक्स के अनुसार, एक आविष्कार तब तटस्थ कहा जाता है जब वह श्रम तथा पूँजी की सीमान्त उत्पादकता की समान अनुपात में वृद्धि करता है। अन्य शब्दों में, एक तकनीकी प्रगति अथवा परिवर्तन तटस्थ तब रहता है जब एक स्थिर पूँजी-श्रम अनुपात पर श्रम के साथ पूँजी के सीमान्त उत्पादन का अनुपात अपरिवर्तित रहता है। एक तकनीकी परिवर्तन श्रम बचतकारी तब कहा जाता है जब यह एक स्थिर पूँजी-श्रम अनुपात पर श्रम की अपेक्षा पूँजी के सीमान्त उत्पादन को बढ़ा देता है।

हिक्स के तटस्थ तकनीकी परिवर्तन को चित्र 1 में दो भिन्न उत्पादन फलनों की तुलना करते हुए प्रदर्शित किया गया है। चित्र में अनुलम्ब अक्ष पर प्रति व्यक्ति उत्पादन (q) को प्रदर्शित किया गया है। ($q = \frac{Q}{L}$, जहाँ Q उत्पादन तथा L श्रम आगत है) तथा क्षैतिज-अक्ष पर पूँजी-श्रम अनुपात K को दर्शाया गया है। ($k = \frac{K}{L}$, जहाँ K तथा L भौतिक इकाइयों में पूँजी तथा श्रम आगत है) चित्र में OQ श्रम और पूँजी के सीमान्त उत्पाद को मापता है। OP तकनीकी परिवर्तन से पूर्व का उत्पादन फलन तथा OP_1 तकनीकी परिवर्तन के पश्चात का उत्पादन फलन है।

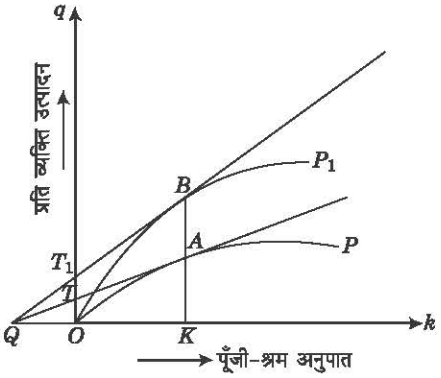

चित्र 1

यदि उत्पादन फलन OP हैं तब स्पर्श रेखा QTA का ढाल पूँजी के सीमान्त उत्पादन को तथा OT श्रम के सीमान्त उत्पादन को मापता है। यह सिद्ध करने के लिए कि श्रम तथा पूँजी के सीमान्त उत्पादन के बीच के अनुपात OQ मापता है। हम त्रिभुज OTQ को लेते हैं, चूँकि QT का ढाल पूँजी के सीमान्त उत्पादन को प्रदर्शित करता है जिसे यदि u द्वारा व्यक्त करें तब,

$$u = \frac{OT}{OQ} \text{ या } OQ = \frac{OT}{u}$$

इस प्रकार OQ सीमान्त श्रम उत्पादन (OT) तथा सीमान्त पूँजी उत्पादन (u) के बीच अनुपात को मापता है। हिक्स का तटस्थ तकनीकी प्रगति परिवर्तन यह बताता है कि यदि तकनीकी परिवर्तन उत्पादन फलन को ऊपर की ओर OP से OP_1 की ओर खिसका देता हैं तो दोनों सीमान्त उत्पादनों का अनुपात अवश्य ही क्षैतिज अक्ष से किसी भी अनुलम्ब रेखा पर ठीक वही होना चाहिए जैसे कि KB, जहाँ यह बिन्दु A तथा B पर क्रमशः उत्पादन फलनों के बिन्दुओं से होकर गुजरता है। इसके अतिरिक्त, हिक्स-तटस्थ तकनीकी प्रगति में यह भी शर्त है कि स्पर्श रेखा QB जो कि उच्चतर उत्पादन फलन OP_1 पर है। अवश्य ही बिन्दु Q से जो कि O से बाईं ओर है, निकलनी चाहिए जैसा कि स्पर्श रेखा QA तकनीकी परिवर्तन से पूर्व थी। चित्र 5 में उत्पादन फलन

TOUCH 'n' PASS

OP_1 पर स्पर्श रेखा QB बिन्दु Q से निकलती है। जब दोनों स्पर्श रेखाएँ QA तथा QB बिन्दु Q से निकलकर उत्पादन फलनों OP तथा OP_1 पर स्पर्श करती हैं, केवल तभी सीमान्त श्रम उत्पादन तथा सीमान्त पूँजी उत्पादन के अनुपात समान होंगे। यथा सीमान्त श्रम उत्पादन तथा सीमान्त पूँजी उत्पादन तकनीकी परिवर्तन के बाद $\frac{OT_1}{u_1} = \frac{OT}{u}$ सीमान्त श्रम उत्पादन तथा सीमान्त पूँजी उत्पादन तकनीकी परिवर्तन से पूर्व। अत: सीमान्त श्रम तथा पूँजी उत्पादनों के बीच अनुपात बिन्दु A तथा B पर अनुलम्ब रेखा KB पर समान है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि हिक्स तटस्थ तकनीकी प्रगति से प्रति व्यक्ति उत्पादन AB के बराबर बढ़ जाता है। जबकि पूँजी श्रम अनुपात OK पर स्थिर रहता है। इस प्रकार हिक्स-तटस्थ तकनीकी परिवर्तन समस्त उत्पादन फलन में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। इस स्थिति को निम्नवत् व्यक्त किया जा सकता है—

$$Q = A(t)\, f(K, L)$$

जहाँ K तथा L क्रमश: श्रम तथा पूँजी को तथा Q कुल उत्पादन को प्रकट करते हैं। $A(t)$ तकनीकी प्रगति का सूचक है जो दीर्घकाल में परिवर्तन के संचयी प्रभाव को मापता है तथा t का बढ़ता हुआ फलन है।

हिक्स-तटस्थता की उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर हम श्रम बचतकारी तथा बचतकारी तकनीकी परिवर्तनों को परिभाषित कर सकते हैं। जिसे **जॉन रॉबिन्सन** ने पक्षपाती तकनीकी प्रगति (Biased Technical Progress) कहा है।

आलोचना (Criticism)—हिक्स तटस्थता की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि यह एक कठोर तरह की परिभाषा है, जबकि इसमें बड़ी संख्या में साधनों का समावेश है। दूसरे, हिक्स तटस्थता की माँग लोचों तथा प्रतिस्थापन लोचों पर निर्भरता इसे विश्लेषण का एक जटिल उपकरण बना देती है। तीसरे, हैरड ने हिक्स तटस्थता की इस आधार पर आलोचना की है कि 'यह अपने आप में नव प्रवर्तन की वास्तविक स्थिति में बारे में असम्बन्धित हैं; जैसे कि वस्तुओं तथा साधनों के लिए माँग की लोच। अन्त में, हिक्स की तटस्थता स्थैतिक आर्थिक विश्लेषण के ढाँचे में निर्मित है।

(2) हैरड़ का तटस्थ तकनीकी प्रगति (Harrod's Neutral Technical Progress)

सर रॉय हैरड ने अपनी पुस्तक 'Towards a Dynamic Economics' में तटस्थ तकनीकी प्रगति की एक वैकल्पिक परिभाषा प्रस्तुत की है। उनकी परिभाषा पूँजी उत्पाद अनुपात पर आधारित है। उनके अनुसार, तकनीकी प्रगति तब तटस्थ होती है जब लाभ की एक स्थिर दर (अथवा ब्याज दर) पर पूँजी-उत्पाद अनुपात भी स्थिर हो। इस तरह हैरड की तटस्थ तकनीकी प्रगति के लिए लाभ की दर (r) तथा पूँजी-उत्पाद अनुपात (K/Y) दोनों की नियतता वांछनीय होती है। यदि लाभ की दर तकनीकी प्रगति के पश्चात यथावत रहती है; जबकि पूँजी उत्पाद अनुपात बढ़ जाता है तब तकनीकी प्रगति श्रम बचतकारी होती है। दूसरी ओर, यदि एक स्थिर लाभ दर पर तकनीकी प्रगति के कारण पूँजी उत्पाद अनुपात घट जाता है तब तकनीकी प्रगति पूँजी बतचकारी होती हैं। हैरड की तटस्थ तकनीकी प्रगति को चित्र 2 की सहायता से भी समझाया जा सकता है। चित्र में प्रति व्यक्ति पूँजी (K) को समानान्तर अक्ष पर तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन (q) को अनुलम्ब अक्ष पर प्रदर्शित किया गया है। OP तकनीकी परिवर्तन से पूर्व का उत्पादन फलन है जबकि OP तकनीकी परिवर्तन के पश्चात का उत्पादन फलन है।

उत्पादन फलन OP के बिन्दु A पर पूँजी उत्पाद अनुपात OK_1 / OY_1 हैं तथा उत्पादन फलन OP' के बिन्दु B पर OK_2 / OY_2 हैं। चूँकि रेखा OL दोनों बिन्दुओं A तथा B में से गुजरती हैं। इसलिए पूँजी-उत्पाद अनुपात इन बिन्दुओं पर समान हैं, अर्थात् $OK_1 / OY_1 = OK_2 / OY_2$।

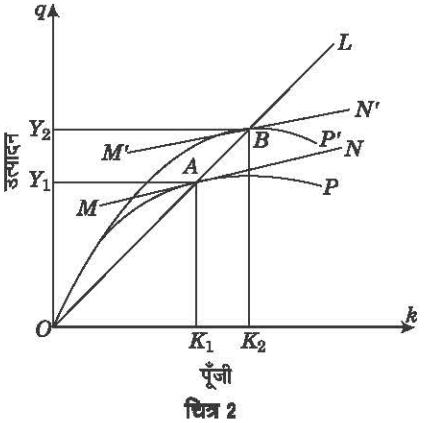

चित्र 2

हैरड की तटस्थता के अनुसार तकनीकी प्रगति के पश्चात लाभ की दर एक स्थिर पूँजी-उत्पाद अनुपात के साथ-साथ निश्चित रूप में स्थिर बनी रहनी चाहिए। इसका तात्पर्य है कि पूँजी की सीमान्त उत्पादकता (या लाभ की दर) उत्पादन फलन OP तथा OP' के बिन्दु A तथा B पर समान होनी चाहिए। पुन: हैरड की तटस्थता यह चाहती है कि उत्पादन फलन OP के बिन्दु A तथा उत्पादनफलन OP' के बिन्दु B के ढलान बिल्कुल बराबर हों। दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ है कि बिन्दु A तथा B पर स्पर्श रेखाएँ निश्चित ही एक-दूसरे के समानान्तर हों। चित्र में A बिन्दु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा MN तथा बिन्दु B से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा $M'N'$ समानान्तर इस प्रकार हैरड-तटस्थ तकनीकी परिवर्तन जैसा कि उत्पादन फलन OP को ऊपर की ओर OP'

पर सरकता हुआ दर्शाया गया हैं, क्रमश: बिन्दु A तथा B पर पूँजी उत्पादन को रेखा OL के माध्यम से समान दर्शाता है तथा स्पर्श रेखा A तथा B की ढलानों की समानता द्वारा स्थिर लाभ दर को दर्शाता है।

इस तरह, हैरड की तटस्थ तकनीकी प्रगति की परिभाषा हिक्स की परिभाषा से अधिक उत्तम है; क्योंकि यह गत्यात्मक स्थिति पर लागू होती है न कि स्थैतिक स्थिति पर। इस प्रकार, यह आर्थिक वृद्धि सिद्धान्त का एक महत्त्वपूर्ण भाग है; क्योंकि इसमें पूँजी उत्पादन अनुपात सिद्धान्त का प्रयोग किया गया है जो कि आधुनिक वृद्धि विश्लेषण का अनिवार्य अंग है। पैमाने के स्थिर प्रतिफल मानते हुए, पूँजी उत्पादन अनुपातों में परिवर्तन तकनीकी परिवर्तनों के माध्यम से ही हो सकते हैं।

प्र.2. विकास लेखांकन पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए।

Comment in detail on development accounting.

उत्तर

विकास लेखाकन
(Development Accounting)

कुल कारक उत्पादकता (TFP) या संक्षेप में उत्पादकता किसी भी राष्ट्र विशेष रूप से विकासशील देश के आर्थिक विकास के सन्दर्भ में एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा होती हैं। उत्पादकता औद्योगिक विकास और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता में योगदान करती है। यह उस दर को इंगित करती है जिस पर नियोजित संसाधनों से रोजगार उत्पन्न होता है। उत्पादकता में वृद्धि से संसाधनों का बेहतर उपयोग होता हैं और औद्योगिक उत्पादों की लागत एवं कीमतों में कमी आती है, जिससे घरेलू व अन्तर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में माँग तेजी से बढ़ने लगती है। जब से रॉबर्ट सोलो ने उत्पादन वृद्धि का आदान वृद्धि के योगदान और अवशिष्ट उत्पादकता के पद से विघटित किया है तब से इस अवधारणा ने लोकप्रियता हासिल की है और इसे फर्मों या देशों के श्रेणीक्रम में मानदण्ड़ के रूप में उपयोग किया जा रहा हैं। एक बार उत्पादकता के रोजगार वृद्धि, निर्यात प्रस्थिति या प्रौद्योगिकी अंगीकरण आदि सफलता के अन्य संकेतकों के साथ सहसम्बद्ध हो जाने के बाद इस प्रकार के श्रेणीकरण को विश्वसनीयता प्राप्त हो जाती है। कम उत्पादकता जैसी अवधारणा को भी किसी अर्थव्यवस्था में फर्मों के विकास का पूर्वानुमान करने के लिए उपयोगी पाया जाता है, जो कि अन्तिम निष्पादन मानक होता है। नीतिगत हस्तक्षेपों अथवा फर्मों के निर्णयों के मूल्यांकन के मानदण्ड के रूप में इसके द्वारा आकर्षित किए जाने वाले ध्यान से भी इसके महत्त्व का अनुमान लगाया जा सकता है। अर्थशास्त्र की विभिन्न शाखाओं में इस अवधारणा की प्रासंगिकता और अर्थ भिन्न-भिन्न हैं। औद्योगिक अर्थशास्त्र में, उदाहरण के लिए एक वृहद ग्रन्थ-समूह उत्पादकता पर अनुसन्धान एवं विकास के प्रभाव और उद्योग संरचना पर उसके परिणामी प्रभाव की विवेचना करता है। अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में व्यापार उदारीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने का प्रयास मूल्य-लागत अन्तर में परिवर्तन का आकलन करने से लेकर उत्पादकता में परिवर्तन तक होते हैं। मूलरूप में उत्पादकता मापन का उद्देश्य उत्पादन में उन परिवर्तनों की पहचान करना होता है जिन्हें आगत में परिवर्तन से नहीं समझाया जा सकता है।

इस अवधारणा के पीछे प्राय: यह बोध होता है कि उत्पादन श्रम और पूँजी के पारम्परिक कारकों के अलावा कुछ और है जो उत्पादन में वृद्धि की ओर ले जाता है। आमतौर पर यह अज्ञात वस्तु तकनीकी प्रगति से जुड़ी होती है। परवर्ती अवधारणा की व्याख्या स्वयं विभिन्न तरीकों से की जा सकती है, परन्तु अन्तत: इसका अर्थ सदैव यह होता है कि श्रम शक्ति, मशीनों, मानव ज्ञान और कौशल का संयोजन कुल आय में ऐसे परिवर्तनों की ओर ले जाता है जिनकी अपेक्षा अलग से पूँजी या श्रम में परिवर्तनों से नहीं होती है।

किसी भी अर्थव्यवस्था की संवृद्धि (GDP में वृद्धि) को आमतौर पर उन कारकों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है जिन्हें दो व्यापक शीर्षकों के अन्तर्गत रखा जा सकता है, यथा पूँजी और श्रम। किन्तु जब हम इसका परिकलन करते हैं तो पाते हैं कि पूँजी और श्रम समग्र वृद्धि का हिसाब नहीं दे सकते हैं तथा असल में एक अवशिष्ट कारक होता है जो अमल में आता है और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। इस कारक को ही कुल कारक उत्पादकता (TFP) के रूप में जाना जाता है। आइए, इसे एक समीकरण के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं—

$$Y = Af(K, L) \qquad \ldots(1)$$

जहाँ Y उत्पादन (GDP) है, K निवेश की गई भौतिक पूँजी का स्टॉक है और L श्रम (काम के घण्टे) हैं। चर A का अर्थ है—कुल कारक उत्पादकता।

एक अवधारणा के रूप में कुल कारक उत्पादकता (TFP) न केवल प्रति व्यक्ति विकास और उत्पादकता के पदों में किसी देश की उपलब्धि के व्यापक आर्थिक कुल संस्तर के सन्दर्भ में महत्त्वपूर्ण है, बल्कि उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता के निर्धारक

तत्त्वों को मापने में भी समान महत्त्व रखती है। अब तक का अत्यधिक लोकप्रिय मापदण्ड–श्रम उत्पादकता अथवा प्रति इकाई श्रम में वर्धित मूल्य—इस कमी से ग्रस्त है कि वह यह नहीं बताता कि उत्पादकता क्यों बढ़ी या फिर इसका विपरीत सत्य है। क्या यह पूँजी के वर्धित निवेश के कारण है या फिर कोई अन्य कारण हैं?

उपलब्धि का विश्लेषण करते समय उक्त उपागम (TFP) उत्पादकता में परिवर्तन के कारण में जाने का प्रयास करता है और इस प्रकार अन्तर्निहित कारणों और विकास की संधारणीयता सम्बन्धी गहन परिज्ञान देता है। उत्पादन जारी रहने पर उत्पादकता बदलती रहती है। प्रौद्योगिकीय उन्नयन, दक्षता में सुधार, श्रमिकों की शिक्षा में वृद्धि, प्रशिक्षण के कारण श्रम की गुणवत्ता में सुधार आदि ही वे परिवर्तन हैं जो उच्च उत्पादकता की ओर ले जाते हैं। आज उक्त उपागम (TFP) को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और विभिन्न दक्षता–वर्धक संस्तर में तेजी से प्रगति के कारण विश्व भर में उत्पादन वृद्धि का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत माना जाता है।

ऊपर दिए गए समीकरण (1) में A के उच्च मान का अर्थ है कि वही आदान अधिक उत्पादन की ओर ले जाते हैं और इसका विपरीत भी सत्य है। यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था के हितों को आगे बढ़ाने के लिए उस निवेश का कितनी कुशलता से प्रयोग किया जा रहा है और यही पूँजी व श्रम निवेश की उत्पादकता है। कुल कारक उत्पादकता को अर्थव्यवस्था के विकास में वास्तविक निर्धारण कारक माना जाता है; क्योंकि पूँजी व श्रम दोनों को अनिश्चित काल तक निवेश नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पूँजी व श्रम पर निर्भर होती है तो जैसे ही इन आदानों में इस निवेश को कम किया जाता है, उसकी संवृद्धि घटती है और इसका विपरीत भी सत्य है। तदनुसार यह कोई स्थिर वृद्धि नहीं होती। अतएव वर्धित कुल कारक उत्पादकता ही एकमात्र तरीका है जिससे कोई अर्थव्यवस्था स्थिर संवृद्धि कायम रख सकती है। साथ ही, ह्रासमान सीमान्त प्रतिफल का नियम (Law of Diminishing Marginal Returns) हमें बताता है कि श्रम व पूँजी के निरन्तर अन्तर्वाह से दीर्घकालिक विकास प्राप्त नहीं होगा; क्योंकि आदानों का मान उच्चतम सीमा तक बढ़ जाता है। वे समय के साथ कम लाभ देने लगते हैं। इस प्रकार विकास को सुनिश्चित और अनवरत रखने का एकमात्र तरीका इन आदानों की दक्षता को अधिकतम करना है और समान मात्रा में ही आदानों के लिए लाभ की गुणवत्ता एवं मात्रा में सुधार करने की दिशा में काम करना ही है, यथा कुल कारक उत्पादकता में वृद्धि करना है।

उत्पादकता ही आर्थिक विकास का प्रमुख कारण होता है कुछ देश दूसरों की तुलना में मुख्यत: इसलिए बेहतर स्थिति में हैं कि वे अधिक उत्पादनशील हैं। साथ ही, कोई देश जितना अधिक उत्पादनशील होगा, वह विश्व बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में उतना ही अधिक सक्षम होगा; क्योंकि वह किसी भी उत्कृष्ट उत्पाद का उत्पादन करते हुए लागत कम रख सकता है। उत्पादकता का एक उच्च स्तर उस देश में लोगों के जीवन स्तर को भी ऊँचा उठाता है; क्योंकि उन्हें उन्हीं आदानों से बेहतर उत्पादन मिलता है, यथा वे कम कीमतों पर बेहतर गुणवत्ता उत्पाद पाते हैं। इस तरह का विश्लेषण करने के लिए अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास के स्रोतों पर एक अलग परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने के लिए विकास लेखांकन नामक एक प्राधार तैयार किया है।

हम इस पर चर्चा बाद में करेंगे कि कैसे घटक संवृद्धि अनिवार्यत: एक विकास लेखांकन प्रयोग ही है। अभी हम एक ऐसे उत्पादन फलन से चर्चा आरम्भ करते हैं जो हमें बताता है कि किसी समय विशेष (t) पर उत्पादन (Y_t) क्या होगा। यह अर्थव्यवस्था के पूँजी स्टॉक (K_t), उसकी श्रम शक्ति (L_t) और उसकी कुल कारक उत्पादकता (A_t) का फलन है। यदि उत्पादन में परिवर्तन होता है तो यह केवल अर्थव्यवस्था के पूँजीगत स्टॉक, उसकी श्रम शक्ति अथवा उसके कुल कारक उत्पादकता के स्तर में परिवर्तन के कारण ही होगा। यहाँ हम उत्पादन फलन के **कॉब-डगलस** रूप की बात कर रहे हैं, जो कि निम्नवत् होता है—

$$Y_t = A_t f(K_t^a, L_t^{1-a})$$

इस समीकरण में हम देख सकते हैं कि हमें तीन कारणों से उच्च उत्पादन प्राप्त होता है, यदि अधिक संख्या में काम के घण्टे (उच्चतर L) लगाए जाते हों, यदि लोगों के पास काम करने के लिए अधिक उपकरण आदि (उच्चतर K) हों अथवा यदि पूँजी व श्रम का अधिक उत्पादनशीलता से उपयोग (उच्चतर A) किया जाता है।

समीकरण (2) से ज्ञात होता है कि यह पूर्ण प्रतिस्पर्धा और निरन्तर अनुमापी प्रतिफल की कल्पना करके चलता है, जैसा कि चर K व L के गुणांक दर्शाते हैं। यदि हम संवृद्धि में वृद्धि का 1/ 3 भाग पूँजी को और 2/ 3 भाग श्रम को (जो कि सर्वाधिक विकसित देशों में देखा जाता है।) आवंटित कर उत्पादन वृद्धि को उक्त तीन तत्त्वों में से प्रत्येक में अपघटित कर दें तो समीकरण निम्नवत् बन जाता है।

$$Y_t = A_t K_t^{1/3} L_t^{2/3} \qquad \ldots(3)$$

लघुगणक लेकर उत्पादन (Y) में वृद्धि निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाई जाती है—

$$\ln Y = \ln A + 0.33 \ln k + 0.67 \ln L \qquad \ldots(4)$$

जहाँ In Y उत्पादन में वृद्धि है, In k पूँजी में वृद्धि है, In L श्रम में वृद्धि हैं। और In A कुल कारक उत्पादकता में वृद्धि है। (ये सब एक समयावधि विशेष के लिए ही हैं।)

हम इस समीकरण का प्रयोग प्रति कर्मचारी उत्पादन वृद्धि की गणना करने के लिए भी कर सकते हैं, यथा श्रम उत्पादकता (Y/L) है। इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है—

$$Y/L = A(K/L)^{1/3} \quad ...(5)$$

जब हम इस समीकरण में उत्पादन में वृद्धि का सूत्र लागू करते हैं तो निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होता है—

$$\text{In } Y/L = \text{In } A + 0.33 \text{ In } K/L \quad ...(6)$$

जहाँ In Y/L प्रति श्रमिक उत्पादन में वृद्धि है, $\delta(K/L)/(K/L)$ प्रति श्रमिक पूँजी की मात्रा में वृद्धि है और $\delta A/A$ कुल कारक उत्पादकता में वृद्धि है।

इस प्रकार समीकरण (6) से ज्ञात होता है कि प्रति श्रमिक उत्पादन दो कारणों से बढ़ सकता है—कुल कारक उत्पादकता में वृद्धि और प्रति श्रमिक पूँजी की मात्रा में वृद्धि। अत: यदि हम किसी ऐसी यथार्थ—जगत परिस्थिति पर विचार करें जिसमें तीनों कारक—पूँजीगत स्टॉक, श्रम और कुल कारक उत्पादकता बदल रहे हों तो उत्पादन की आनुपातिक वृद्धि दर समीकरण (4) में उल्लिखित वृद्धि के अनुसार ही होगी, जोकि प्रमुख है।

यदि हमें उत्पादन की आनुपातिक वृद्धि दरें, पूँजी स्टॉक और श्रम बल ज्ञात हो और हम उत्पादन फलन में ह्रासमान अनुमापी प्रतिफल प्राचल α भी जानते हों तो हम इस विकास-लेखांकन समीकरण का प्रयोग कुल कारक उत्पादकता A की वृद्धि दर (प्रत्यक्षत: प्रेक्षित नहीं) परिकलित करने के लिए कर सकते हैं और कुल उत्पादन Y की वृद्धि निम्नवत् अपघटित करने के लिए कर सकते हैं—(i) वर्धमान पूँजी स्टॉक K से योगदान में, (ii) वर्धमान श्रम बल L से योगदान और (iii) उच्च कुल कारक उत्पादकता A से योगदान।

चूँकि समीकरण (4) में विकास लेखांकन हमें संवृद्धि उन घटकों में विभाजित करने की अनुमति देता है, जिन्हें पूँजीगत स्टॉक की ओर श्रम बल की संवृद्धि के प्रेक्षणीय कारकों और किसी अवशिष्ट कारक के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है—वस्तुत: जिसे प्राय: सोलो अवशिष्ट या अज्ञानता की माप कहा जाता है। यह विकास का वही हिस्सा है जिसे उत्पादन के मानक कारकों में वृद्धि द्वारा अस्पष्टीकरण छोड़ दिया जाता है। सोलो अवशिष्ट या कुल कारक उत्पादकता में परिवर्तन ऊपर बताए गए अनेक कारणों से हो सकते हैं। अर्थशास्त्री प्राय: कुल कारक उत्पादकता को "प्रौद्योगिकी" के रूप में इंगित करते हैं, परन्तु यदि यह प्रौद्योगिकी है तो यह व्यापकतम सम्भव अर्थ में प्रौद्योगिकी ही है। न केवल भवन-निर्माण के लिए नए तरीके, नए-आविष्कृत मशीनें और बिजली के नए स्रोत ही कुल कारक उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, बल्कि कार्य संघटन में सरकारी विनियमन की दक्षता में, अर्थव्यवस्था में, एकाधिकार की कोटि में, कार्यबल की साक्षरता एवं कौशल में तथा कई अन्य कारकों में परिवर्तन भी कुल कारक उत्पादकता को प्रभावित करते हैं।

कुल कारक उत्पादकता के मापन में जहाँ जिस उपागम का प्रयोग किया गया है, वही तथाकथित विकास लेखांकन है, जो कि परिकलन तकनीक के लिहाज से सरल होने के बावजूद पर्याप्त रूप से ज्ञानवर्धक परिणाम देता है।

प्र.3. प्रौद्योगिकी और विकास के सन्दर्भ में हैरोड-डोमर और सोलो मॉडल का विवरण दीजिए।

Describe harrod Domar and Solow models in the context of technology and development.

उत्तर प्रौद्योगिकी और विकास के सन्दर्भ में हैरोड-डोमर और सोलो मॉडल

(Harrod-Domar and Solo Model in the Context of Technology and Development)

विकास मॉडल, विशेषत: हैरोड-डोमर और सोलो मॉडल, इस सन्दर्भ में चर्चा करते हैं कि आगत प्रयोग के स्तर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पादन कैसे बदल जाता है। चूँकि यहाँ श्रम व पूँजी का अधिक प्रयोग किया गया, उत्पादन में बदलाव आया। हमने बचत और निवेश की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर भी चर्चा की। तथापि, उत्पादन की परिस्थितियाँ सदा समान नहीं रहती हैं। जब प्रौद्योगिकी का उन्नयन होता है तो तकनीकी प्रगति होने पर आगतों को अधिक कुशलता से एकत्र किया जा सकता है।

तकनीकी परिवर्तन का उत्पादन प्रक्रिया में सुधार से कुछ लेना-देना अवश्य हैं और वास्तव में ऐसा ही है। हम उत्पादन फलन को देखकर ही तकनीकी स्तर में परिवर्तन को दर्शाते हैं। चलिए, सरलता के लिए मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में एक ही सजातीय वस्तु है। यह वस्तु पूँजी व श्रम के प्रयोग से उत्पन्न होती है। तकनीकी प्रगति की संकल्पना करने का सबसे सरल तरीका यह

TOUCH 'n' PASS

समझना है कि तकनीकी प्रगति का अर्थ आदान की पहले जितनी मात्रा का उपयोग करके पहले से अधिक उत्पादन किया जाना ही होता है। यदि आप किसी उत्पादन फलन की कल्पना करें तो देख सकेंगे कि तकनीकी प्रगति होने पर उत्पादन फलन समय के साथ ऊपर की ओर खिसक रहा है। तकनीकी परिवर्तन (सुधार) को देखने का एक अन्य तरीका यह कहना है कि उत्पादन फलन की प्रकृति एक बेहतर रूप में बदल गई है या फिर यह कहना कि या एक से अधिक कारकों का पहले की तुलना में कम उपयोग करके उत्पादन की पहले जितनी मात्रा का उत्पादन किया जा सकता है।

उत्पादन फलन में परिवर्तनों के रूप में तकनीकी परिवर्तन को निरूपित करने के लिए हमने जिस सामान्य विधि का प्रयोग किया है (इसे प्रत्येक समोत्पाद की स्थिति में परिवर्तनों के रूप में भी दर्शाया जा सकता है) उसे उत्पादन फलन में समय शामिल कर स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सकता है। यह उत्पादन फलन अब निम्नवत् दिखाई देता है—

$$Y = F(K, L, t) \quad \ldots(1)$$

जहाँ कोणांक t एक उत्पादन फलन शिफ्टर है।

यद्यपि उपर्युक्त समीकरण (1) तकनीकी प्रगति दर्शाने का सर्वाधिक सामान्य तरीका है, तकनीकी परिवर्तन दर्शाने का एक और तरीका है, जिसमें तकनीकी प्रगति उत्पादन फलन में परिवर्तनों के माध्यम से होती है, भले ही प्रयोग की गई आगतों में वृद्धि न हुई हो। यह ऐसा है मानों उत्पादन के कारणों को किसी तरह बढ़ाया गया हो और वे पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करने में सक्षम हो गए हों।

तकनीकी परिवर्तन को समझने के लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि तकनीकी परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं। उनका मुख्य रूप से पूँजी-श्रम की गहनता के साथ और निहितार्थक रूप से कुल उत्पाद में पूँजी व श्रम के सापेक्ष अंशों पर होता है। इसका पूँजी व श्रम के प्रतिफल पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, यथा वेतन दर और पूँजी के किराये पर। यदि पूँजी-श्रम अनुपात पूँजी गहनता बढ़ जाती हैं तो इसे पूँजी सघनीकरण कहा जाता है।

चलिए, अब हम तकनीकी परिवर्तन के वर्गीकरण का अध्ययन आरम्भ करते हैं। ऐसा करने से पहले, आइए, कारक-वर्धित तकनीकी प्रगति सम्बन्धी अपनी चर्चा को याद करें। हम यहाँ एक सम्बन्धित अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। तकनीकी परिवर्तन सन्निहित या असम्बद्ध हो सकता है। सन्निहित तकनीकी परिवर्तन का अर्थ है कि तकनीकी परिवर्तन उत्पादन उपादान के प्रकार, आमतौर पर पूँजी में परिवर्तन के रूप में होता हैं। दूसरे शब्दों में, सन्निहित तकनीकी परिवर्तन नए प्रकार की मशीनों (किसी नई प्रक्रिया या नई प्रौद्योगिकी) के रूप में समाविष्ट होता है।

दूसरी ओर, असम्बद्ध तकनीकी प्रगति का अर्थ है कि नई या पुरानी मशीनों के प्रकार की परवाह किए बिना, समान मात्रा में उपादान अधिक मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं या फिर कम मात्रा में आगतों का उपयोग करके समान मात्रा में उत्पादन किया जा सकता हैं। दूसरे शब्दों में, समोत्पाद अन्दर की ओर खिसकता हैं।

तकनीकी परिवर्तन के सम्बन्ध में एक अन्य अवधारणा तटस्थता है। मोटे तौर पर तटस्थता का अर्थ है कि तकनीकी परिवर्तन न तो श्रम की बचत होता है और न ही पूँजी की बचत। **सर जॉन हिक्स** ने तकनीकी प्रगति को पूँजी के सीमान्त उत्पाद और श्रम सीमान्त उत्पाद के अनुपात पर तकनीकी परिवर्तन के प्रभाव के रूप में देखा। यदि तकनीकी परिवर्तन के बाद यह अनुपात बढ़ता है तो हिक्स की शब्दावली में इसे श्रम की बचत कहा जाता है। यदि यह अनुपात समान रहता है तो यह तटस्थ होता है और यदि अनुपात गिरता है तो इसे पूँजी की बचत कहा जाता है। अब हम तकनीकी प्रगति के **हिक्सियन** वर्गीकरण को इन शब्दों में बता सकते हैं, कोई भी तकनीकी प्रगति प्रति-श्रमिक उत्पादन फलन को ऊपर की ओर खिसका देगी। यदि पूँजी-श्रम अनुपात के किसी भी दिए गए मान पर पूँजी के सीमान्त उत्पाद और श्रम के सीमान्त उत्पाद के अनुपात में वृद्धि होती है। तो इस तकनीकी प्रगति को श्रम बचतकारी कहा जाता है। दूसरी ओर, यदि पूँजी-श्रम अनुपात के किसी दिए गए मान के लिए यह अनुपात घटता है तो तकनीकी प्रगति को पूँजी बचतकारी कहा जाता है, और यदि अनुपात वही रहता है तो यह हिक्स तटस्थ कहलाता है।

सर रॉय हैरोड ने तकनीकी प्रगति का एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया जो कि हिक्स के वर्गीकरण से भिन्न था। उन्होंने तटस्थ को एक ऐसे तकनीकी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जिसमें पूँजी गुणांक (पूँजी-उत्पादन अनुपात) किसी नियत ब्याज दर की विद्यमानता में नहीं बदलता है। मोटे तौर पर, उन्होंने कहा कि ब्याज दर नियत होने पर यदि पूँजी व श्रम के बीच कुल राष्ट्रीय उत्पाद का वितरण स्थिर रहता है तो यह तटस्थ तकनीकी प्रगति कहलाती है। यदि हम पूर्ण प्रतिस्पर्धा पर विचार करते हुए ब्याज दर को पूँजी के किराये के बराबर एवं तदनुसार पूँजी के सीमान्त उत्पाद के बराबर लेते हैं तो यह हैरोड-तटस्थ तकनीकी प्रगति पूँजी उत्पादन अनुपात और पूँजी के सीमान्त उत्पाद के बीच सम्बन्ध दर्शाती समुक्ति होती है।

तकनीकी प्रगति सम्बन्धी रॉबर्ट सोलो का वर्गीकरण एक मामले को छोड़कर हैरोड और हिक्स के वर्गीकरण के समान ही है। हिक्स का वर्गीकरण नियत पूँजी श्रम अनुपात के बिन्दुओं पर विभिन्न प्रति-श्रमिक उत्पादन वक्रों पर बिन्दुओं की तुलना करता है और हैरोड की वर्गीकरण पद्धति नियत पूँजी उत्पादन अनुपात के बिन्दुओं पर विभिन्न प्रति श्रमिक उत्पादन वक्रों पर बिन्दुओं की तुलना करती हैं। सोलो का वर्गीकरण पुराने और नए प्रति श्रमिक उत्पादन के बिन्दुओं की तुलना उन बिन्दुओं पर करता है जिन पर श्रम उत्पादन अनुपात स्थिर रहता है। इस प्रकार सोलो तटस्थता तब होती है जब वह उन बिन्दुओं पर जहाँ स्थिर हो, यथा पूँजी व श्रम के सापेक्ष अंश स्थिर रहते हों। यह दर्शाया जा सकता है कि कोई भी सोलो तटस्थ तकनीकी प्रगति पूँजी वर्धक होती है।

प्र.4. संस्थाएँ क्या हैं? ऐसे कुछ तरीकों पर चर्चा करें जिनसे संस्थाएँ आर्थिक विकास को निर्धारित करती हैं।
What are institutions? Discuss some of the ways in which institutions determine economic development.

उत्तर

विकास के अन्य निर्धारक तत्त्व
(Other Determinants of Development)

कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा उत्पादन के उपादान, संचय, प्रौद्योगिकी, उत्पादकता वृद्धि, इत्यादि विकास के अधिकांश आर्थिक निर्धारक तत्त्वों को संसक्त कारणों के रूप में लिया गया है। तथापि ये आर्थिक निर्धारक तत्त्व स्वयं अन्तर्निहित मूल कारणों से प्रेरित व प्रभावित हो सकते हैं। जिनमें कुछ गैर-आर्थिक भी हो सकते हैं।

संस्थाएँ
(Institutions)

हाल के दिनों में संस्थागत अर्थशास्त्र ने विकासशील देशों के विश्लेषण में यथेष्ट महत्त्व अर्जित किया है। कुछ ही समय पूर्व व्यष्टि अर्थशास्त्र के उपकरणों का प्रयोग कर विनिमय के विश्लेषण की अनुपूर्ति संस्थागत विश्लेषण द्वारा किए जाने की माँग की गई है। फिलहाल आर्थिक विकास के अध्ययन में भी संस्थानों के अध्ययन को महत्त्व दिया गया है।

राष्ट्रों के बीच उत्पादन एवं निधि सम्बन्धी भिन्नताएँ हो सकती हैं और यह राष्ट्रों के आर्थिक विकास में अन्तर की व्याख्या करने वाला माना जाता है। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार वे कारक जो आर्थिक विकास लाने वाले माने जाते हैं जो कि अन्तर्जात होते हैं, वे स्वयं विकास के मूल कारण अथवा विकास की व्याख्याएँ नहीं होते। वे वास्तव में विकास के अभिलक्षण या वैशिष्ट्य होते हैं। विकास निष्पादन में भिन्नताएँ का मुख्य कारण विभिन्न देशों में संस्थाओं की संरचना में अन्तर होता है। संस्थाएँ व उनमें भिन्नताएँ देशों के कार्य-निष्पादन में व्यापक अन्तर के लिए उत्तरदायी हो सकती हैं।

ये संस्थाएँ क्या होती है? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता डगलस नॉर्थ संस्थाओं को किसी समाज में खेल के नियम अथवा अधिक यथाविधि मानवीय अन्तर्क्रिया को रूपायित करने वाले मानवीय रूप से तैयार किए गए व्यवरोध बताते हुए परिभाषित करते हैं। उनका कहना है कि संस्थाएँ लोगों के बीच अन्योन्यक्रिया में निग्रह विशेष तरीके से अभिव्यक्त करती हैं। ये अन्योन्य क्रियाएँ आर्थिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक हो सकती है।

सम्पत्ति के अधिकार और बाजारों के पूर्णता स्तर जैसी आर्थिक संस्थाएँ समाज में आर्थिक प्रोत्साहनों की संरचना को प्रभावित करती हैं। आर्थिक संस्थाएँ यह भी निर्धारित करती हैं कि समाज में आवंटन कितनी कुशलता से नियत किया जाएगा। तदनुसार, न केवल यह बोध आवश्यक है कि संस्थाएँ महत्त्वपूर्ण होती हैं, बल्कि यह भी कि संस्थाएँ अन्तर्जात होती हैं। आर्थिक विवेचन में एक नया पहलू सम्पत्ति के अधिकारों में परिवर्तनों और आर्थिक विकास पर अत्यधिक प्रभाव डालने वाली लेन-देन लागतों पर विचार करता है। इस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण रोनाल्ड कोसे और डगलस नॉर्थ के कार्यों से मिलता है। उनके एक अन्य पहलू ने सूचना अर्थशास्त्र में विषम सूचना, अपूर्ण जानकारी, नैतिक हानिभय, प्रतिकूल चयन, संकेतन एवं संवीक्षा आदि हाल के विकास घटनाचक्र का उपयोग करने की माँग की है ताकि यह समझा जा सके कि संस्थाएँ विकास को कैसे प्रभावित करती हैं। वे संस्थाओं को लुप्त और अपूर्ण बाजारों, जोखिम की व्याप्ति और सूचना की विषमता द्वारा अर्थव्यवस्था में उत्पन्न अन्तरालों को पाटे जाने के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने इसका उपयोग इन पद्धतियों पर कृषि संस्थानों को गठित करने के लिए किया है। इसका उल्लेख जॉर्ज एकरलोफ और जोसेफ स्टिग्लिट्ज जैसे अर्थशास्त्रियों की पुस्तकों में आता है। रोचक बात यह है कि उपर्युक्त चारों अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार मिला है।

सौदा लागत या लेन-देन लागत के अनुयायी वर्ग का तर्क है कि जैसे ही लेन-देन लागतों में बदलाव होता है, संस्थाएँ इन लागतों को कम करने के लिए उभरती हैं। यही विकास का आधार है। लेन-देन लागतों में शामिल होती हैं—अनुवीक्षण लागत, समन्वयन

लागत और अनुबन्ध प्रवर्तन लागत। जब लेन-देन की लागत अधिक होती है तो सम्पत्ति के अधिकारों का नियतन महत्त्वपूर्ण हो जाता है साथ ही, लेन-देन की लागत अधिक होने पर अनुबन्ध सम्पत्ति के सम्बन्धों से निर्धारित किए जाते हैं। विकास प्रक्रिया में आकारिक मितव्ययिता और लेन-देन लागतों के बीच कोई समझौताकारी समन्वयन उभर सकता है। साधारण आमने-सामने की बातचीत में लेन-देन की लागत कम हो सकती है। परन्तु उत्पादन लागत बढ़ जाती है क्योंकि विशेषज्ञता और श्रम विभाजन सीमित होता है। लेन-देन लागत अनुयायी वर्ग यह भी मानता है कि सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन से संस्थागत परिवर्तन होते हैं।
सूचना अर्थशास्त्र अनुयायी वर्ग ने अपने सिद्धान्तों को अधिक कठोर शब्दों में प्रस्तुत किया और स्पष्ट रूप से साम्यावस्था की धारणाओं को सामने लाया। इसके अलावा, संस्थागत गुणवत्ता, असमानता के मध्यस्थता प्रभाव के माध्यम से शिक्षा एवं स्वास्थ्य में निवेश की मात्रा एवं गुणवत्ता को प्रभावित करती है। उच्च स्तर की शिक्षा वाले देशों में संभ्रान्त वर्ग पर अधिक व्यवरोध के साथ संस्थाएँ अपेक्षाकृत अधिक लोकतान्त्रिक हुआ करती हैं। शिक्षा और संस्थानों के बीच कारण-कार्य सम्बन्ध किसी भी दिशा में जा सकता है या फिर ये दोनों अन्य कारकों के कारण संयुक्त रूप से उत्पन्न हो सकते हैं।

भूगोल (Geography)

प्रथम दृष्टिया ऐसा लगता है कि भूगोल का विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। यह सम्भवत: संयोग मात्र नहीं है कि अनेक गरीब राष्ट्र भूमध्य रेखा के आसपास और उसके निकट ही स्थित हैं। अति उष्ण जलवायु कार्य करने की ऊर्जा को सीख लेती है, इसलिए श्रमिकों की उत्पादकता प्रभावित होती है। कम उत्पादकता से कम आय होती है और कम उत्पादकता वाले बहुत से श्रमिक शायद पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन का खर्च उठाने में सक्षम न हों। निम्न पोषण स्तर उत्पादकता को और कम कर सकता है। इसके अलावा, भूगोल अवस्थापन कारक के माध्यम से आर्थिक विकास को भी प्रभावित करता है। भौगोलिक कारक उद्योगों एवं कारखानों को लाभकारी क्षेत्रों में स्थित होने या न होने के लिए अग्रसर कर सकते हैं। इसी प्रकार कृषि, शहरीकरण तथा अर्थव्यवस्था के कुछ अन्य पहलू भी भौगोलिक स्थिति से प्रभावित हो सकते हैं।
अर्थशास्त्रियों ने भौगोलिक कारकों पर पहले से अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया है। सर्वप्रथम, अन्ततोगत्वा बहुत कम अर्थशास्त्रियों को ही यह संशय हैं कि जलवायु सहित भौतिक भूगोल का आर्थिक इतिहास पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। भूगोल कभी वास्तव में बहिर्जात था, भले ही अब मानवीय कार्यकलाप इसे बेहतर या बदतर बनाने के लिए फेरबदल सकते हैं। किन्तु भूगोल द्वारा निभाई गई आर्थिक भूमिका, जैसे उष्णकटिबन्धीय जलवायु, आज कम स्पष्ट है।
कुछ शोध बताते है कि जब अन्य कारकों, विशेष रूप से असमानता एवं संस्थाओं को ध्यान में रखा जाता है तो भौतिक भूगोल वर्तमान विकास स्तरों संबंधी हमारे बोध में बहुत कम वृद्धि करता है। तथापि कुछ साक्ष्य मिलावटी हैं। उदाहरण के लिए, मलेरिया के स्वतन्त्र प्रभाव के कुछ प्रमाण हैं और संकेत हैं कि कुछ परिस्थितियों में भूमिबद्ध प्रस्थिति आर्थिक विकास के लिए बाधा हो सकती है। वस्तुत: भूगोल से विकास के परिणामों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रमाणित है।

संस्कृति (Culture)

सांस्कृतिक कारक भी शिक्षा, उत्तर-औपनिवेशिक संस्थागत गुणवत्ता एवं नागरिक समाज की प्रभावशीलता पर जोर देने के स्तर को प्रभावित करने में महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं। हालाँकि आर्थिक कारकों के सम्बन्ध में संस्कृति की सटीक भूमिका स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं होती।
यह अवधारणा कि संस्कृति राष्ट्रीय समृद्धि का निर्धारक तत्त्व है। समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने तर्क दिया था कि अथक परिश्रम व धनोपार्जन का गुणगान करने वाले एक "प्रोटेस्टेंट का उदय ही 16वीं शताब्दी में उत्तरी यूरोप में आरम्भ आर्थिक विकास को अचानक वृद्धि की ओर ले गया। हाल ही में अर्थशास्त्रियों ने इस बात पर विचार किया है कि क्या ताइवान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की तीव्र वृद्धि को उनके "एशियाई मूल्यों" के पालन से समझाया जा सकता है, जो कि वर्ष 1980 में द इकोनॉमिस्ट पत्रिका द्वारा गढ़ा गया एक पदबन्ध है। इन उदाहरणों के बावजूद बहरहाल, अर्थशास्त्रियों ने आमतौर पर मानवविज्ञानियों, समाजशास्त्रियों व इतिहासकारों के विपरीत संस्कृति को विकास के किसी निर्धारक तत्त्व के रूप में नहीं देखा है। अर्थशास्त्री संस्कृति का विश्लेषण नहीं करना चाहते क्योंकि इसकी मात्रा निर्धारित करना कठिन होता है।
यदि हमे यह दर्शाना हो कि आर्थिक विकास के लिए संस्कृति महत्त्वपूर्ण है तो हमें पहले यह दिखाना होगा कि संस्कृति के कुछ सम्भावित महत्त्वपूर्ण पहलू होते हैं जो भिन्न—भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न दिखाई देते हैं और दूसरा यह कि संस्कृति के ये पहलू

आर्थिक देशों में भिन्न-भिन्न दिखाई देते हैं। परिणामों को सार्थक रूप से प्रभावित करते हैं। इन दोनों ही पहलुओं को दर्शाना मुश्किल होता है क्योंकि संस्कृति को मापना मुश्किल होता है। न केवल संस्कृति के विभिन्न आयाम होते हैं, बल्कि जब हम स्वयं को संस्कृति के किसी एक पहलू तक सीमित रखते हैं तब भी हमारे पास प्राय: किसी वस्तुनिष्ठ (बहुत कम मात्रात्मक) मापदण्ड़ का अभाव होता है और पर्यवेक्षकों के व्यक्तिपरक आकलन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसी प्रकार, कुछ मामलों में संस्कृति के आर्थिक प्रभावों का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, जबकि अन्य मामलों में ऐसे प्रभावों का केवल अनुमान भर लगाया जा सकता है।

हम मोटे तौर पर संस्कृति के कुछ पहलुओं का और उनके द्वारा आर्थिक विकास को प्रभावित किए जाने के तरीके का उल्लेख मात्र कर सकते हैं। संस्कृति के कुछ व्यष्टिगत पहलू हैं—नए विचारों के प्रति उदारता, अथक परिश्रम के मूल्य में विश्वास, भविष्य के लिए बचत और वह जिस सीमा जहाँ तक लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। संस्कृति के कुछ वृहत्तर अभिलक्षण सामाजिक पूँजी, परम्पराएँ आदि हो सकते हैं।

नए विचारों के प्रति उदारता (Openness to New Ideas)—आर्थिक विकास की ऐतिहासिक प्रक्रिया की जाँच करने वाले विद्वानों ने प्राय: विदेशों से नए विचारों को आयात करने के लिए समाज के खुलेपन के महत्त्व पर जोर दिया है। किसी देश विशेष में उपयोग की जाने वाली अनेक तकनीकों का आविष्कार अन्य देशों में ही किया गया था, इसलिए वह देश जो विदेशों से प्राप्य प्रौद्योगिकियों को तत्परता से अपनाएगा, प्रौद्योगिकीय रूप से अधिक उन्नति करेगा।

अथक परिश्रम (Hard Work)—पूरे मानव इतिहास में हर संस्कृति में लगभग सभी वयस्कों को जीवित रहने के लिए काम करना पड़ा है। फिर भी संस्कृतियाँ उस कार्य के विषय में अपने-अपने भिन्न दृष्टिकोण रखती हैं—किसी आवश्यक बुराई के रूप में अथवा किसी अन्तर्भूत मूल्य वाली गतिविधि के रूप में।

बचत दर (Saving Rate)—किसी देश का आर्थिक विकास उसकी बचत दर से अत्यधिक प्रभावित होता है। हमने यह भी देखा कि देशों के बीच बचत दरों में काफी अन्तर होता है। यदि देशों के बीच सांस्कृतिक भिन्नताएँ उनकी बचत दरों को प्रभावित करती हैं तो ये भिन्नताएँ आर्थिक विकास के स्तर को प्रभावित कर सकती हैं।

विश्वास (Belief)—आर्थिक अन्तर्क्रियाओं में प्राय: किसी व्यक्ति पर अपनी बात रखने के लिए निर्भरता शामिल होती है। विश्वास के बिना आर्थिक गतिविधि एक कच्चे स्तर तक कम हो जाएगी और यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग अपने वायदों को पूरा करें, विपुल संसाधनों को झोंकना होगा। समाज जटिल संगठन बनाने से प्राप्त लाभों से वंचित हो जाएगा। उदाहरण के लिए, लोगों को विशिष्ट कार्यों में विशेषज्ञता प्राप्त करने अथवा व्यापार से लाभ का दोहन करने की अनुमति देना। स्पष्टत: जिस समाज में हम अपनी प्रतिबद्धताओं को निभाने के लिए दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकते, वह गरीब ही होगा।

प्र.5. केनेथ एरो द्वारा प्रस्तुत करके सीखना मॉडल को विस्तार से स्पष्ट करें।

Explain in detail the learning model presented by Kenneth Arrow.

उत्तर

अन्तर्जात विकास मॉडल
(Endogenous Development Model)

एरो का करके-सीखना सिद्धान्त (Arrow's Learning)

करके-सीखना (Learning-by-doing) आर्थिक सिद्धान्त में एक ऐसी संकल्पना है जिसमें उत्पादकता अभ्यास, आत्म-पूर्णता और अल्प नवाचार के जरिए हासिल की जाती है। अमेरिकी अर्थशास्त्री केनेथ एरो ने इस संकल्पना का प्रयोग नवाचार एवं प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के प्रभाव स्पष्ट करने के लिए अन्तर्जात विकास सिद्धान्त संबंधी अपने अभिकल्प में किया। एरो के कालजयी दस्तावेज दि इकॉनामिक इम्पलिकेशन्स ऑफ लर्निंग बाई डूइंग (1962) ने दर्शाया कि किस प्रकार यह विचार आधुनिक आर्थिक विकास सिद्धान्त के एकदम अनुकूल है और इसे शानदार ताजा घटनाचक्र के निर्णायक प्रतिफल हेतु एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में प्रयोग किया। एरो ने आय प्रति व्यक्ति में ऐसी वृद्धि से परिचय कराया जिन्हें महज किसी पूँजी श्रम अनुपात में वृद्धि से स्पष्ट किया जा सकता। आर्थिक विकास में प्रौद्योगिकीय परिवर्तन की भूमिका को पहचान कर और ज्ञान की संकल्पना सम्बन्धी एक ऐसी व्याख्या प्रस्तुत कर जो किसी उत्पादन में निहित होती है, एरो ने समझा कि ज्ञान कैसे अर्जित किया जाता है। इसलिए उसने ज्ञान में परिवर्तन सम्बन्धी एक ऐसा अन्तर्जात सिद्धान्त प्रतिपादित किया जो उत्पादन फलनों में अन्तर्कालिक और अन्तर्राष्ट्रीय बदलावों में निहित होता है।

ज्ञानार्जन या विद्या प्राप्ति अर्थात् "सीखना" अनेक तरीकों से स्पष्ट किया जा सकता है, फिर भी सभी सिद्धान्त यह स्वीकार करते हैं कि विद्या प्राप्ति अनुभव का प्रतिफल होती है। किसी समस्या को हल करने के प्रयास में ही आप कुछ सीखते हैं और इसलिए

विद्या प्राप्ति किसी क्रिया-कलाप के दौरान ही सम्भव हो पाती है। एरो ने अनेक प्राचीन विद्या-प्राप्ति अनुभवों का परिणाम यह निकाला कि अनिवार्यतः एक ही समस्या की पुनरावृत्ति से जुड़ी विद्या ह्रासमान लाभ ही देती है। किसी भी ज्ञात प्रोत्साहन के लिए एक साम्य अनुक्रिया प्रतिमान होता है, जिसकी दिशा में सीखने वाले का व्यवहार बार-बार मुड़ता है तब निरन्तर वर्धमान उपलब्धि में निहित होगा कि प्रोत्साहक दशाएँ स्वयं निरन्तर उद्विकासी हों, न कि महज दोहराई जाने वाली।

एरो ने वर्धमान उत्पादकता में अनुभव की भूमिका पर बल दिया, जिसे आर्थिक सिद्धान्त के मुख्य संग्रह में आत्मसात किया जाना अभी शेष है। तदनुसार उसने इस परिकल्पना को आगे बढ़ाया कि अधिकतर प्रौद्योगिकीय परिवर्तन का श्रेय अनुभव को दिया जा सकता है, जो कि उस उत्पादन प्रक्रिया का ही हिस्सा होता है। जो ऐसे सवालों को जन्म देती है जिनके लिए माकूल जवाब कालान्तर में चुने जाएँगे। अतः करके सीखना उत्पादन प्रक्रिया से ज्ञान संचय करने का ही एक उदाहरण है। जब लोग माल का उत्पादन करते हैं तो उत्पादन प्रक्रियाओं को सुधारने के तरीके अपरिहार्य रूप से निकल आते हैं। उत्पादकता में सुधार सामान्य उत्पादन क्रिया के प्रतिफल स्वरूप ही सामने आता हैं न कि जानबूझकर किए गए प्रयासों के फलस्वरूप। जब करके सीखना ही प्रौद्योगिकीय प्रगति का स्रोत हो तो ज्ञानवर्धन/ज्ञानार्जन की दर R&D को समर्पित सकल घरेलु उत्पाद के अंश पर निर्भर नहीं रहती बल्कि इस बात से बढ़ती है कि परम्परागत उत्पादन फलन से कितनी नयी जानकारी उत्पन्न होती हैं। इस उत्पादन फलन को निम्नवत् लिखा जा सकता है—

$$Y(t) = K(t)^{\alpha} [A(t)L(t)]^{1-\alpha} \quad ...(1)$$

जहाँ K = पूँजी, L = श्रम, Y = उत्पादन, A = ज्ञान भण्डार और $\alpha = a$ प्राचल जो 0 और 1 के बीच अवस्थित है।

सामान्यतया करके सीखने का सरलतम उदाहरण उन परिस्थितियों में देखा जाता है जहाँ विद्या प्राप्ति नयी पूँजी उत्पादन के पार्श्व प्रभाव स्वरूप होती है। चूँकि यहाँ ज्ञानवर्धन पूँजीवर्धन का फलन होता है। ज्ञान भण्ड़ार पूँजी भण्ड़ार का फलन होता है। यहाँ केवल एक ही भण्ड़ार चर है जिसका व्यवहार अन्तर्जात है, यथा—

$$A(t) = BVK(t)^{\beta} \quad ...(2)$$

जहाँ B और β दोनों ही O से अधिक हैं।

यदि हम इसे समीकरण (1) में रखें तो प्रापत होगा—

$$Y(t) = K(t)^{\alpha} B^{1-\alpha} K(t)^{\beta(1-\alpha)} L(t)^{1-\alpha} \quad ...(3)$$

आप देखेंगे कि विद्या की विद्यमानता में पूँजी का योगदान उसके परम्परागत योगदान से कहीं अधिक होता है—वर्धित पूँजी न केवल अपने प्रत्यक्ष योगदान से उत्पादन में वृद्धि करती है [पद $K(t)^{\alpha}$] बल्कि वह परोक्ष रूप से नये विचारों के विकास में भी योगदान देती है और शेष समस्त पूँजी को पहले से अधिक उत्पादनशील $K(t)^{\beta(1-\alpha)}$ बना देती है।

अपने सरलीकृत रूप में इस मॉडल को निम्नवत् निरूपित किया जा सकता है—

$$Y_i = A(K)F(K_i, L_i)$$

जहाँ एक फर्म i के लिए Y_i उत्पादन है, K_i कुल पूँजी भण्डार है और L_i श्रम का भण्ड़ार हैं, जबकि A तकनीकी उत्पादन है और K कुल शेयर पूँजी को निरूपित करता हैं।

लेव्हरी-सैसिंस्की मॉडल (Levary-Sansiski Model)

उक्त एरो मॉडल को दो अर्थशास्त्रियों डेविड लेव्हरी और आइटन सैसिंस्की द्वारा व्यापक और विस्तृत बना दिया गया है। ये ज्ञान के स्रोत के रूप में वर्धित ज्ञान के अधिप्लावन प्रभाव पर बल देते हैं। इनका मानना है कि ज्ञान का स्रोत अथवा करके सीखना हर फर्म का निवेश है। किसी भी फर्म के निवेश में वृद्धि उसके ज्ञान के स्तर में एक समानान्तर वृद्धि की ओर अग्रसर करती है।

इस मॉडल के अनुसार, किसी फर्म का ज्ञान एक लोकहित वस्तु होता है, जिसका लाभ अन्य फर्में शून्य लागत पर उठा सकती हैं। तदनुसार ज्ञान अपने लक्षण में गैर-प्रतिद्वन्द्वी होता है, जो कि अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों पर अपनी छलकन दर्शाता है। ऐसा तब होता है जब प्रत्येक फर्म नियत अनुमापी प्रतिफल के तहत काम करती है और सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था वर्धमान अनुमापी प्रतिफल के तहत काम कर रही होती है।

यह मॉडल अन्तर्जात प्रौद्योगिकीय प्रगति को ज्ञान अथवा करके सीखना के पदों में स्पष्ट करता है, जो कि प्रतिस्पर्धात्मक साम्यावस्था के संगत होने साथ कुल वर्धमान लाभ के प्रसंग में उत्पादन फलन और आर्थिक विकास की ऊर्ध्वमुखी वृद्धि में प्रकट होता है।

TOUCH n PASS

किंग-रॉब्सन मॉडल (King-Robson Model)

मर्वलिन किंग और मार्क रॉब्सन नामक दो अर्थशास्त्रियों ने अपने प्रौद्योगिकीय प्रगति फलन में "देखकर सीखना" पर जोर दिया है। किसी फर्म द्वारा निवेश किया जाना उसके द्वारा अपने सामने खड़ी समस्याओं को हल करने हेतु नवाचार अपनाया जाना दर्शाता है। यदि वह सफल रहता है तो अन्य फर्में भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह नवाचार अपना लेंगी। तदनुसार, देखकर सीखना से परिणत बाह्यताएँ आर्थिक विकास की कुँजी सिद्ध होती हैं।

उक्त अध्ययन दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र में नवाचार अन्य क्षेत्रों की उत्पादकता पर संक्रामक अथवा प्रदर्शन प्रभाव दर्शाता है जिससे आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। एकाधिक स्थिरावस्था विकास पथ मौजूद है यहाँ तक कि एक समान आरम्भिक अक्षय निधि वाली अर्थव्यवस्थाएँ भी और निवेश बढ़ाने वाली नीतियाँ अपनाई जानी चाहिए।

रोमर मॉडल (Romar Model)

वर्ष 1986 में अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल रोमर ने अन्तर्जात विकास विषयक अपने प्रथम दस्तावेज में ऐरो के मॉडल का एक भिन्न रूप प्रस्तुत किया, जिसे "निवेश कर सीखना" कहा गया। उसने ज्ञान सृजन की कल्पना निवेश के एक सह-उत्पाद के रूप में की। रोमर ने ज्ञान को उत्पादन फलन में आदान के रूप में लिया, जो कि निम्नवत था—

$$Y = A(R)\, F(R_i, K_i, L_i) \qquad \ldots(5)$$

जहाँ Y = कुल उत्पादन, $A(R) = R \,\&\, D$ से ज्ञान का सार्वजनिक भण्डार, R_i = फर्म i द्वारा $R\&D$ पर व्यय से प्राप्त परिणामों का भण्ड़ार, K_i = फर्म i की शेयर पूँजी तथा L_i = फर्म i का श्रम आदान।

रोमन फलन F को अपने सभी आदानों R_i, K_i, L_i, आदि में डिग्री 1 का सजातीय मानते हैं और R_i को एक प्रतिद्वन्द्वी वस्तु के रूप में लेते हैं। उसके मॉडल में तीन मुख्य तत्त्व रहे—बाह्यताएँ, उत्पादन की प्रस्तुति में वर्धमान लाभ और नये ज्ञान के उत्पादन में ह्रासमान लाभ।

किसी फर्म द्वारा किए गए अनुसन्धान प्रयासों की छलकन ही अन्य फर्मों द्वारा नये ज्ञान का सृजन किए जाने की ओर प्रवृत्त करती है। किसी फर्म द्वारा प्रयुक्त नयी अनुसंधान प्रौद्योगिकी तत्काल छलक कर समग्र अर्थव्यवस्था में फैल जाती है। इस मॉडल में नया ज्ञान ही उस दीर्घावधि विकास का अनन्य निर्धारक तत्त्व होता है जो अनुसंधान प्रौद्योगिकी में निवेश से तय होता है। अनुसंधान प्रौद्योगिकी ह्रासमान लाभ दर्शाती हैं। जिसका अर्थ होता है कि अनुसंधान प्रौद्योगिकी में निवेश ज्ञान को दोगुना नहीं करेगा। साथ ही, अनुसंधान प्रौद्योगिकी में निवेश कर रही फर्म को ज्ञान में वृद्धि से लाभ अन्य रूप से नहीं मिलेगा। एकस्व अधिकार संरक्षण की अनुविता के कारण नये ज्ञान से अन्य फर्में भी लाभान्वित होंगी। अत: वर्धित ज्ञान से माल उत्पादन वर्धमान लाभ दर्शाता है और प्रतिस्पर्धात्मक साम्यावस्था बाह्यताओं की वजह से वर्धमान कुल लाभ से संगति दर्शाने लगती है। युक्तियुक्त लाभ अधिकतम करतीं फर्मों द्वारा नये ज्ञानार्जन के लिहाज से रोमर ने अनुसंधान प्रौद्योगिकी में निवेश को अन्तर्जात माना।

लुकास मॉडल (Lucas Model)

अमेरिकी अर्थशास्त्री रॉबर्ट लुकास ने मानव पूँजी में निवेश पर आधारित एक अन्तर्जात विकास मॉडल का प्रयोग किया, जो कि जापानी अर्थशास्त्री हिरोफुमी उजावा ने विकसित किया था। लुकास का मानना था कि शिक्षा पर निवेश मानव पूँजी को उत्पादन की ओर ले जाता है, जो कि विकास प्रक्रिया में अति महत्त्वपूर्ण निर्धारक तत्तव होता है। लुकास ने मानव पूँजी के प्रभावों पर आधारित दो वर्ग बनाए—(i) आन्तरिक प्रभाव, जहाँ प्रशिक्षण ले रहा कोई श्रमिक पहले से अधिक उत्पादनशील हो जाता है तथा (ii) बाहरी प्रभाव, जो कि छलकन दर्शाते हैं और पूँजी के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में अन्य श्रमिकों की उत्पादकता भी बढ़ा देते हैं। भौतिक पूँजी की बजाय मानव पूँजी में निवेश ही ऐसे अधिप्लावन प्रभाव दर्शाता है जो प्रौद्योगिकी के स्तर को ऊपर ले जाते हैं। इस प्रकार, फर्म i का उत्पादन निम्नवत् दिखाई देगा—

$$Y_i = A(K_i).(H_i)H^e \qquad \ldots(6)$$

जहाँ A तकनीकी गुणांक है, K_i और H_i उत्पादन Y_i प्रस्तुत करने के लिए फर्म i द्वारा प्रयुक्त भौतिक और मानव पूँजी इंगित करते हैं। H अर्थव्यवस्था की कुल मानव पूँजी का औसत स्तर है तथा e वह प्राचल लुकास मॉडल में हर फर्म के सामने नियम अनुमापी प्रतिफल होता है, जबकि समग्र अर्थव्यवस्था के लिए वर्धमान अनुमापी प्रतिफल होता है। करके सीखना अथवा काम पर रखकर प्रशिक्षण तथा अधिप्लावन प्रभावों में मानव पूँजी निहित होती है। प्रत्येक फर्म मानव पूँजी के कुल योग से लाभान्वित होती

TOUCH 'n PASS

है। इस प्रकार, आर्थिक संवृद्धि के लिए अर्थव्यवस्था में अन्य फर्मों का संचित ज्ञान अथवा अनुभव नहीं बल्कि औसत कौशल और ज्ञान अधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं।

रोमर का प्रौद्योगिकीय परिवर्तन सम्बन्धी मॉडल (Romer's Model of Technological Change)

वर्ष 1990 में पॉल रोमर ने विचारों के उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त एक अनुसन्धान क्षेत्र को मान्यता देने वाले अन्तर्जात प्रौद्योगिकीय परिवर्तन सम्बन्धी मॉडल प्रस्तुत किया। यह क्षेत्र विचार अथवा नया ज्ञान उत्पन्न करने के लिए वर्तमान ज्ञान भण्ड़ार के साथ-साथ मानव पूँजी का भी आह्वान करता है। संसाधनों से अधिक विचारों का महत्त्व ही उसके विश्लेषण का आधार है, जहाँ वह जापान का उदाहरण देते हैं, यथा एक ऐसा देश जिसके पास अल्प प्राकृतिक संसाधन हैं मगर उसने नये पाश्चात्य विचारों और प्रौद्योगिकी का सदैव स्वागत किया है।

इस मॉडल के अनुसार नया ज्ञान उत्पादन प्रक्रिया में तीन तरीकों से प्रवेश पाता है—

1. मध्यवर्ती माल क्षेत्र में—जहाँ किसी नये मध्यवर्ती आदान के उत्पादन के लिए कोई नया डिजाइन प्रयोग किया जाता है।
2. तैयार माल क्षेत्र में—जहाँ श्रम, मानव पूँजी और उपलब्ध टिकाऊ उत्पादक वस्तुएँ तैयार माल प्रस्तुत करते हैं।
3. अनुसंधान के क्षेत्र में—जहाँ कोई नया डिजाइन कुल ज्ञान भण्ड़ार बढ़ा देता है, जिससे इस क्षेत्र में लगी मानव पूँजी की उत्पादकता बढ़ जाती है।

अन्तर्जात प्रौद्योगिकीय परिवर्तन सम्बन्धी यह मॉडल निम्नलिखित अवधारणाओं पर आधारित है—

→ आर्थिक संवृद्धि प्रौद्योगिकीय परिवर्तन से आती है।

→ प्रौद्योगिकीय परिवर्तन अंतर्जातीय होता है।

→ बाजार प्रोत्साहन अर्थव्यवस्था में प्रौद्योगिकीय परिवर्तन उपलब्ध कराने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

→ किसी नये डिजाइन के आविष्कार में मानव पूँजी की कोई विशिष्ट मात्रा अपेक्षित होती है।

→ मानव पूँजी की कुल आपूर्ति नियत होती है।

→ आविष्कार करने वाली फर्म द्वारा ज्ञान अथवा किसी नये डिजाइन को आंशिक रूप से छूट देने और अपने पास ही रखने योग्य माना जाता है। (एकस्व अधिकार प्राप्त डिजाइन जो कि आविष्कारक की सहमति के बिना बनाया और बेचा नहीं जा सकता)

परन्तु $R\&D$ में निवेश अन्य फर्मों द्वारा किया जा सकता है और उसके लाभ प्रोद्भूत किए जा सकते हैं।

→ प्रौद्योगिकी एक गैर प्रतिद्वन्द्वी आदान है।

→ नया डिजाइन फर्मों द्वारा भिन्न-भिन्न समयावधियों में बिना किसी अतिरिक्त लागत के और बिना आदान का मूल्य घटाए प्रयोग किया जा सकता है।

→ किसी विद्यमान डिजाइन को प्रयोग करने की निम्न लागत नये डिजाइन तैयार करने की लागत घटा देती है।

→ जब फर्में $R\&D$ में निवेश कर कोई नया डिजाइन तैयार कर लेती है तो बाह्यताएँ उत्पन्न होती हैं जो कि निजी अनुबन्धों से आंतरिक बना ली जाती हैं।

इस मॉडल में प्रौद्योगिकी उत्पादन फलन निम्नवत् दर्शाया जाता है—

$$\Delta A = F(K_A, H_A, A) \qquad \ldots(7)$$

जहाँ ΔA प्रौद्योगिकी के लिए प्रौद्योगिकी उत्पादन फलन है, K_A डिजाइन प्रस्तुत करने अथवा प्रौद्योगिकी में निवेशित पूँजी की राशि है। H_A $R\&D$ में नियोजित मानव पूँजी (श्रमिक) की मात्रा है तथा A डिजाइनों को विद्यमान प्रौद्योगिकी है।

यह उत्पादन फलन दर्शाता है कि प्रौद्योगिकी अन्तर्जात होती है। जब $R\&D$ हेतु पहले से अधिक मानव पूँजी नियोजित की जाती है तो प्रौद्योगिकी कुछ अधिक मात्रा में बढ़ती है यथा A का मान पहले से अधिक हो जाता है। चूँकि यह माना जाता है कि प्रौद्योगिकी एक गैर-प्रतिद्वन्द्वी आदान हैं और अंशत: छूट देने योग्य है, प्रौद्योगिकी के सकारात्मक अधिप्लावन प्रभाव देखे जाएँगे, जिन्हें अन्य फर्मों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। तदनुसार, नयी प्रौद्योगिकी (ज्ञान अथवा विचारों) का उत्पादन भौतिक पूँजी, मानव पूँजी और विद्यमान प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर बढ़ाया जा सकता है।

TOUCH 'n PASS

प्र.6. काल्डोर-हिक्स क्षतिपूर्ति सिद्धान्त का वर्णन कीजिए।
Kaldor-Hicks Compensation Criterion.

उत्तर

काल्डोर-हिक्स क्षतिपूर्ति सिद्धान्त
(Kaldor-Hicks Compensation Criterion)

पैरेटल मानदण्ड यह व्यक्त करने में असमर्थ है कि जब अनुबन्ध वक्र पर किसी भी दिशा में किया गया आन्दोलन सामाजिक कल्याण को बढ़ाने वाला है या नहीं। केवल यह व्यक्त किया जाता है कि एक व्यक्ति की उपयोगिता में कमी करके ही सम्भव है। परन्तु इस प्रकार के परिवर्तन से समाज कल्याण बढ़ता है या घटता है, इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त नहीं होती। ऐसा इस कारण से है; क्योंकि पैरेटो मानदण्ड उपयोगिता की अन्तर-व्यक्तिगत तुलना नहीं करता इसलिए पैरेटो इष्टतमता द्वारा प्रस्तुत कल्याण सम्बन्धी विश्लेषण अनिर्धारणीय है क्योंकि अनुबन्ध वक्र पर बहुत से पैरेटो इष्टतम बिन्दु हैं। काल्डोर सिटोस्की जैसे अर्थशास्त्रियों ने किसी आर्थिक पुनर्गठन से जो कुछ लोगों को हानि प्राप्त होती है और कुछ लोगों को लाभ प्राप्त होता है, परिणाम स्वरूप सामाजिक कल्याण में परिवर्तन होता है। इन अर्थशास्त्रियों ने पैरेटो इष्टतमता विश्लेषण में अनिर्धारणीयता को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने एक मानदण्ड प्रस्तुत किया जिसको क्षतिपूर्ति सिद्धान्त के माध्यम से जाना जाता है। इस मानदण्ड के आधार पर अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन या पुनर्गठन जो कुछ लोगों को हानि पहुँचाता है और कुछ लोगों को लाभ पहुँचाता है, के मूल्यांकन करने का दावा किया।

मान्यता (Assumption)—इस सिद्धान्त की पूर्वकल्पनाएँ निम्न प्रकार से हैं—

1. एक व्यक्ति की सन्तुष्टि दूसरे व्यक्ति की सन्तुष्टि से स्वतन्त्र है और एक व्यक्ति अपने कल्याण का सबसे श्रेष्ठ निर्णय स्वयं ले सकता है।
2. उत्पादन और उपयेाग में किसी प्रकार की बाह्य बचतें नहीं होती है।
3. उपभोक्ताओं की रुचि स्थिर रहती है।
4. उत्पादन व विनिमय की समस्या वितरण की समस्या से अलग की जा सकती है। क्षतिपूर्ति सिद्धान्त इस बात को स्वीकार करता है कि सामाजिक कल्याण स्तर उत्पादन स्तर का फलन है।
5. तुष्टिगुण को कर्मवाचक पद्धति से मापा जा सकता है। अन्तर व्यक्तिगत तुलना सम्भव है। एक व्यक्ति के तुष्टिगुण की दूसरे व्यक्ति के तुष्टिगुण से तुलना की जा सकती है।

काल्डोर-हिक्स कल्याण मानदण्ड : क्षतिपूर्ति सिद्धान्त
(Kaldor-Hicks welfare criterion : Compensation Principle)

काल्डोर पहला अर्थशास्त्री था जिसने क्षतिपूर्ति भुगतान के आधार पर कल्याण मानदण्ड प्रस्तुत किया। इस मानदण्ड की सहायता से काल्डोर वक्र किसी भी दिशा में गति से जो कल्याण व अकल्याण उत्पन्न होता है, को मापा जा सकता है। इस मानदण्ड के अनुसार कोई आर्थिक परिवर्तन या पुनर्गठन या किसी नीति में परिवर्तन में कुछ लोगो को लाभ होता है और दूसरों को हानि होती है तो यह परिवर्तन समाज कल्याण को बढ़ा देगा, लाभ प्राप्त करने वाले लोग हानि उठाने वाले लोगों की क्षतिपूर्ति कर देते हैं और फिर भी पहले की अपेक्षा बेहतर स्थिति में होते हैं। बाउमल के शब्दों में, "कोई परिवर्तन समाज कल्याण बढ़ाने वाला है, यदि लाभ उठाने वाले व्यक्ति हानि उठाने वाले व्यक्तियों से अपने लाभ को हानि की अपेक्षा उच्च जाँचते हैं तो "स्पष्ट है कि यदि किसी नीति परिवर्तन से समाज के किसी वर्ग को जो लाभ होता है वह उस हानि से अधिक हैं जो समाज के दूसरे वर्ग को उठानी पड़ती है तब यह परिवर्तन समाज कल्याण को बढ़ाने वाला कहा जाएगा।

मुआवजा मानदण्ड को उपयोगिता सम्भावना वक्र की सहायता से निम्न चित्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। उपभोक्ता A की उपयोगिता को X-अक्ष पर और उपभोक्ता B की उपयोगिता को Y-अक्ष पर मापा गया है DE चित्र में उपयोगिता सम्भावना वक्र है जो इन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिन्हें A और B प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट है कि ज्यों हम वक्र के निचले भाग पर चलते हैं तो A की उपयोगिता बढ़ती जाती है और B की कम होती जाती है।

कल्पना कीजिए कि वर्तमान उत्पादन या आप के वितरण के आधार पर A और B का जो उपयोगिताएँ प्राप्त हैं वे Q बिन्दु द्वारा दर्शाई गई हैं। परन्तु जब कोई आर्थिक परिवर्तन किया जाता है तो दोनों व्यक्ति Q बिन्दु से T बिन्दु पर पहुँच जाते हैं। इससे B की उपयोगिता बढ़ जाती है और A की उपयोगता कम हो जाती है। इसलिए यह परिवर्तन पैरेटो मानदण्ड के आधार पर मूल्यांकित नहीं

TOUCH 'n PASS

किया जा सकता। यद्यपि R, G, S आदि बिन्दु Q की अपेक्षा सामाजिक रूप से बेहतर हैं। जो पैरेटो मानदण्ड के आधार पर व्यक्त नहीं की जा सकती। परन्तु काल्डोर-हिक्स द्वारा प्रस्तुत किया गया क्षतिपूर्ति सिद्धान्त हमें इस योग्य बनाती है कि Q से T बिन्दु पर पहुँचने से समाज कल्याण बढ़ा है या नहीं। इस मानदण्ड के अनुसार यह देखना होता है कि B को जो लाभ हुआ है क्या वह A को होने वाली हानि को पूरा करके भी पहले से अच्छी स्थिति में हो सकता है। चित्र में देखा जा सकता है कि आपके पुनर्वितरण से यदि B A को कुछ आय देता है ताकि A समाप्त हो जाये तब वे R बिन्दु पर पहुँच सकते हैं। चित्र से स्पष्ट है कि A उपभोक्ता R बिन्दु पर उसी स्थिति में है जैसा कि वह Q बिन्दु पर था। इसका अर्थ यह हुआ कि नीति परिवर्तन के परिणामस्वरूप Q से R तक पहुँचने में उपभोक्ता A की क्षतिपूर्ति कर देता है और फिर भी Q की अपेक्षा बेहतर स्थिति में हैं इसलिए इस मानदण्ड के अनुसार Q से T तक पहुँचना समाज कल्याण को बढ़ाने वाला होगा जैसा कि वे आय के पुनर्वितरण से R, G, S आदि बिन्दुओं को प्राप्त कर सकते हैं।

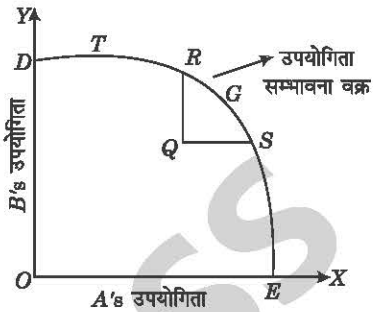

चित्र 1

उपयोगिता सम्भावना वक्र के T बिन्दु से R पहुँचने के लिए B को A की हानि को क्षतिपूर्ति करना पड़ता है। परन्तु यह क्षतिपूर्ति B उपभोक्ता A को प्रत्यक्ष नहीं करता बल्कि सरकार आय के पुनर्वितरण द्वारा R या G बिन्दु को प्राप्त करती हैं जिसके परिणामस्वरूप A की क्षतिपूर्ति हो जाती है और समाज कल्याण में वृद्धि होती है। अब यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह पुनर्वितरण कितनी सुगमता और शीघ्रता से कर पाती है। यदि पुनर्वितरण से G बिन्दु प्राप्त किया जाता हैं तो Q बिन्दु की अपेक्षा A और B दोनों बेहतर स्थिति में होंगे।

यदि किसी आर्थिक नीति में परिवर्तन के परिणामस्वरूप उपयोगिता सम्भावना वक्र ऊपर की तरफ सरक जाए तो समाज कल्याण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

चित्र में प्रारम्भिक उपयोगिता सम्भावना वक्र UV द्वारा दर्शाया गया है। कल्पना की गई है कि दोनों व्यक्ति A और बिन्दु Q पर स्थापित है। किसी आर्थिक नीति परिवर्तन के कारण उपयोगिता सम्भावना वक्र ऊपर की तरप सरककर U^1V^1 बन गई है जिस पर दोनों उपभोक्ता, R बिन्दु को प्राप्त होते हैं। Q से R तक पहुँचने पर A की उपयोगिता बढ़ी है और B की कम हो गई है। परन्तु R की स्थिति क्षतिपूर्ति मानदण्ड के अनुसार Q की तुलना में अधिक सामाजिक कल्याण प्रदान करने वाली है; क्योंकि केवल आप के पुनर्वितरण द्वारा U^1V^1 उपयोगिता सम्भावना वक्र पर R से S स्थिति प्राप्त की जा सकती है जिस पर दोनों A और B उपभोक्ता बिन्दु Q की अपेक्षा बेहतर स्थिति में होंगे। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कोई भी आर्थिक परिवर्तन जो अर्थव्यवस्था को ऊँची उपयोगिता वक्र पर पहुँचता हैं, अधिक सामाजिक कल्याण प्रदान करने वाला होता है।

सूक्ष्म मूल्यांकन (Critical Evaluation)—क्षतिपूर्ति सिद्धान्त को निम्न आधारों पर आलोचित या मूल्यांकित किया जा सकता है—

1. इस सिद्धान्त में यह कल्पना की गई है कि व्यक्तियों की रुचि या पसन्द स्थिर रहती है, परन्तु यह कल्पना गलत है। वास्तव में व्यक्तियों की रुचि वस्तुओं के लिए बदलती रहती है।
2. सिद्धान्त की यह मान्यता है कि उपभोक्ता और उत्पादन में बाह्य बचतें नहीं होती हैं, अव्यावहारिक है।
3. सिद्धान्त की कल्पना है कि आदर्श अपने कल्याण का निर्णय स्वयं करता है, सही नहीं है; क्योंकि एक व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में अपने कल्याण का सही-सही मूल्यांकन नहीं कर सकता और उसके कल्याण पर बाहरी शक्तियों (सरकार) का प्रभाव पड़ता है।
4. इस सिद्धान्त की यह मान्यता है कि उपयोगिता को कर्मवाचक ढँग से मापा जा सकता है और इस आधार पर एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई उपयोगिता की तुलना दूसरे व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई उपयोगिता से की जा सकती है। परन्तु अधिकतर व्यक्ति अपनी उपयोगिता व्यक्त करने में असमर्थ रहते हैं, इसलिए अन्तर व्यक्तिगत तुलना सम्भव नहीं है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. "गुणक एवं त्वरक सिद्धान्तों के मध्य सम्बन्ध है।" किसका शब्द है?

(क) डोमर (ख) हैरड (ग) हैबरलर (घ) मेहता

उत्तर (ख) हैरड

TOUCH 'n PASS

प्र.2. हैरड द्वारा प्रयुक्त मॉडल में तीन प्रकार की वृद्धि दरों का उल्लेख किया है। वे दर—
(क) वास्तविक वृद्धि दर, अभीष्ट अथवा आवश्यक वृद्धि दर, प्राकृतिक वृद्धि दर
(ख) स्वधारणीय वृद्धि, अनावश्यक वृद्धि दर, दीर्घकालीन वृद्धि
(ग) सन्तुलित वृद्धि, छुरी-धार वृद्धि, सतत वृद्धि
(घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर (क) वास्तविक वृद्धि दर, अभीष्ट अथवा आवश्यक वृद्धि दर, प्राकृतिक वृद्धि दर

प्र.3. यह विकास की वह दर है जो जनसंख्या में वृद्धि एवं तकनीकी सुधारों के बावजूद होती है—
(क) प्राकृतिक (ख) अभीष्ट
(ग) सन्तुलित (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (क) प्राकृतिक

प्र.4. वह दर जिस पर देश वास्तव में विकास कर रहा है। यह दर बचत-अनुपात तथा पूँजी-उत्पाद अनुपात (COR) द्वारा निर्धारित होती है—
(क) सन्तुलित (ख) वास्तविक (ग) प्राकृतिक (घ) अभीष्ट
उत्तर (ख) वास्तविक

प्र.5. प्राकृतिक वृद्धि दर (Natural rate of growth) का सूत्र है—
(क) $GC = S$ (ख) $G_w = \frac{S}{C_6}$
(ग) $G_n, C_r = S$ (घ) $G_w, C_r = S$
उत्तर (ग) $G_n, C_r = S$

प्र.6. विकास की तीनों दरें समान होने पर कौन-सी अवस्था होती है?
(क) दीर्घकालीन मंदी (ख) दीर्घकालीन स्फीति
(ग) विकास की स्वर्णिम अवस्था (घ) ये सभी
उत्तर (ग) विकास की स्वर्णिम अवस्था

प्र.7. हैरड के अनुसार—
(क) आय में वृद्धि $= \frac{\text{बचत प्रवृत्ति}}{\text{पूँजी उत्पाद अनुपात}}$
(ख) आय में वृद्धि $= \frac{\text{सीमान्त बचत प्रवृत्ति}}{\text{पूँजी उत्पाद अनुपात}}$
(ग) आय में वृद्धि $= \frac{\text{औसत प्रवृत्ति}}{\text{पूँजी उत्पाद अनुपात}}$
(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर (ख) आय में वृद्धि $= \frac{\text{सीमान्त बचत प्रवृत्ति}}{\text{पूँजी उत्पाद अनुपात}}$

प्र.8. यदि G अधिक है G_w से $(G > G_w)$ तो—
(क) दीर्घकालीन मन्दी (ख) दीर्घकालीन स्फीति
(ग) दीर्घकालीन वृद्धि (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (ख) दीर्घकालीन स्फीति

TOUCH 'n' PASS

प्र.9. यदि G_w कम है G_n ($G_w < G_n$) से तो—

(क) दीर्घकालीन गतिहीनता (ख) दीर्घकालीन मंदी

(ग) छुरी-धार सन्तुलन (घ) ये सभी

उत्तर (क) दीर्घकालीन गतिहीनता

प्र.10. हैरड-डोमर मॉडल की सीमाएँ कौन-सी हैं?

(क) बचत प्रवृत्ति और पूँजी-उत्पाद अनुपात स्थिर नहीं रहते

(ख) श्रम एवं पूँजी का निश्चित अनुपात में प्रयोग नहीं

(ग) ब्याज दर में परिवर्तन न होने की मान्यता अनुचित

(घ) उपर्युक्त सभी

उत्तर (घ) उपर्युक्त सभी

प्र.11. सोलो ने अपने मॉडल में व्यक्तियों के पूर्व ज्ञान, वस्तु, श्रम तथा ..... में सहजता से समायोजन आदि आधारभूत मान्यताओं को अंगीकार किया है।

(क) उत्पादन (ख) संसाधनों

(ग) पूँजी बाजार (घ) श्रम शक्ति

उत्तर (ग) पूँजी बाजार

प्र.12. सोलो मॉडल में K तथा L दो साधन हैं, K और L क्या हैं?

(क) वस्तु, श्रम (ख) पूँजी, श्रम

(ग) पूँजी, वस्तु (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (ख) पूँजी, श्रम

प्र.13. सोलो मॉडल की मान्यता है—

(क) तकनीकी प्रगति तटस्थ रहती है

(ख) अर्थव्यवस्था में कम रोजगार की स्थिति विद्यमान है

(ग) पूँजी की बचत होती है

(घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर (क) तकनीकी प्रगति तटस्थ रहती है

प्र.14. यदि किसी समय पूँजी श्रम (r) अनुपात आरम्भिक पूँजी (r^-) से कम या अधिक हो जाता है तब अर्थव्यवस्था सन्तुलित विकास पथ से ..... हट है।

(क) पास (ख) दूर

(ग) स्थिर (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (ख) दूर

प्र.15. प्रो० कुजनेट्स ने तकनीकी प्रगति के अन्तर्गत कितने तत्त्वों का समावेश किया है?

(क) दो (ख) चार (ग) पाँच (घ) तीन

उत्तर (ग) पाँच

प्र.16. तकनीकी प्रगति के तत्त्व हैं—

(क) आविष्कार, वैज्ञानिक खोज (ख) सुधार

(ग) नव-प्रवर्तन, तकनीकी सामाजिक परिवर्तन (घ) ये सभी

उत्तर (घ) ये सभी

TOUCH 'n PASS

प्र.17. हर्बर्ट फ्रैंकेल के अनुसार—

(क) तकनीकी परिवर्तन केवल उत्पादन में सुधार है।

(ख) तकनीकी परिवर्तन व्यापार में सुधार है।

(ग) तकनीकी परिवर्तन केवल तकनीकी ज्ञान में सुधार नहीं बल्कि उससे अधिक है।

(घ) उपर्युक्त सभी।

उत्तर (ग) तकनीकी परिवर्तन केवल तकनीकी ज्ञान में सुधार नहीं बल्कि उससे अधिक है।

प्र.18. ''विकसित देशों में वास्तविक आय में होने वाली वृद्धि दर अकेले पूँजी निर्माण का परिणाम नहीं है, बल्कि बहुत हद तक उत्पादकता में वृद्धि का परिणाम है जो स्वयं तकनीकी प्रगति के फलस्वरूप होती है'' कथन है—

(क) रैगनर नर्क्स (ख) आस्कर लंगे

(ग) किण्डलबर्जर (घ) बाल्डिवन

उत्तर (ग) किण्डलबर्जर

प्र.19. "Towards a dynamic Economics" किसकी पुस्तक है?

(क) प्रो० हिक्स (ख) रॉबर्ट सोलो

(ग) किण्डलबर्जर (घ) सर रॉय हैरड

उत्तर (घ) सर रॉय हैरड

प्र.20. श्रम बचतकारी होती है—

(क) यदि लाभ की दर तकनीकी प्रगति के पश्चात यथावत रहती है जबकि पूँजी उत्पाद बढ़ जाता है।

(ख) यदि लाभ की दर तकनीकी प्रगति के पश्चात विचलन होती है जबकि पूँजी उत्पाद घट जाता है।

(ग) यदि लाभ की दर तकनीकी प्रगति के पश्चात घटता है तो पूँजी उत्पाद बढ़ जाता है।

(घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

उत्तर (क) यदि लाभ की दर तकनीकी प्रगति के पश्चात यथावत रहती है जबकि पूँजी उत्पाद बढ़ जाता है।

प्र.21. काल्डोर मॉडल की समीकरण में किन आधारों को रखा गया है?

(क) राष्ट्रीय आय (γ) (ख) सकल मजदूरी (w)

(ग) सकल लाभ (P) (घ) ये सभी

उत्तर (घ) ये सभी

प्र.22. $I = S$ हमें बताता है कि—

(क) इच्छित बचतों को इच्छित विनियोग के बराबर होना

(ख) पूर्ण रोजगार की स्थिति

(ग) दोनों

(घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (ग) दोनों

TOUCH 'n PASS

UNIT-VII

आर्थिक विकास में शिक्षा एवं शोध की भूमिका
Role of Education and Research in Economic Growth

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. अन्तर्जात विकास से क्या अभिप्राय है?
What is meant by endogenous development?

उत्तर अन्तर्जात विकास वह विकास है जो मुख्य रूप से स्थानीय रणनीतियों, ज्ञान, संस्थानों और संसाधनों पर आधारित है, हालाँकि विशेष रूप से नहीं। इसमें स्थानीय समुदाय के भीतर से शुरू होने वाले अनुकूलन और नवाचार की एक सतत् प्रक्रिया शामिल है।

प्र.2. अन्तर्जात विकास क्यों होता है?
Why does endogenous development happen?

उत्तर स्थानीय उत्पादक प्रणालियों में बाह्यताओं के उपयोग के परिणामस्वरूप अन्तर्जात विकास प्रक्रियाएँ होती हैं, जो बढ़ते-रिटर्न और आर्थिक विकास के लिए अनुकूल हैं।

प्र.3. नया अन्तर्जात विकास सिद्धान्त क्या है?
What is new endogenous development?

उत्तर अन्तर्जात विकास सिद्धान्त के अनुसार आर्थिक विकास मुख्य रूप से बाहरी शक्तियों के बजाय आन्तरिक शक्तियों का परिणाम है। यह तर्क देता है कि उत्पादकता में सुधार को सीधे तेजी से नवाचार और सरकारों एवं निजी क्षेत्र के संस्थानों से मानव पूँजी में अधिक निवेश से जोड़ा जा सकता है।

प्र.4. अन्तर्जात वृद्धि सिद्धान्त उत्पादकता वृद्धि के कौन-से दो स्रोत प्रस्तुत करता है?
What two sources of productivity growth are present by the endogenous growth theory?

उत्तर अन्तर्जात वृद्धि सिद्धान्त कहता है कि उत्पादकता वृद्धि के दो स्रोत हैं; मानव पूँजी और अनुसंधान एवं विकास।

प्र.5. बौद्धिक पूँजी किसे माना जाता हैं?
What is considered intellectual capital?

उत्तर बौद्धिक पूँजी में मानव पूँजी, सूचना पूँजी, ब्राण्ड जागरूकता और निर्देशात्मक पूँजी शामिल है। व्यवसाय बेहतर कर्मचारियों की भर्ती, कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके और नए पेटेंट विकसित करके बौद्धिक पूँजी बढ़ा सकते हैं।

प्र.6. बौद्धिक पूँजी में कितने तत्त्व होते हैं?
How many elements are there in intellectual capital?

उत्तर बौद्धिक पूँजी में तीन तत्त्व होते हैं—मानव पूँजी, संरचनात्मक पूँजी (या संगठनात्मक पूँजी) तथा सम्बन्धपरक (ग्राहक) पूँजी।

TOUCH 'n PASS

प्र.7. कार्यशील पूँजी का क्या अर्थ है?
What is meant by worbing capital?

उत्तर कार्यशील पूँजी फर्म के पास उपलब्ध वह राशि होती है जिसका इस्तेमाल वर्तमान दायित्वों (जो एक वर्ष से कम समय से बकाया हैं) को पूरा करने एवं परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु किया जाता है।

प्र.8. शिक्षा में अनुसन्धान की भूमिका क्या हैं?
What is the role of research in education?

उत्तर शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्र में ज्ञान में वृद्धि करना, उसमें सुधार करना तथा प्रसार करना है। शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना, छात्रों के अधिगम में विकास करना। शिक्षण की प्रभावशाली प्रविधियों का विकास करना। शिक्षा प्रशासन तथा शिक्षा प्रणाली में अनुसन्धान प्रक्रिया द्वारा सुधार तथा विकास करना।

प्र.9. सीखने में अनुसंधान क्या है?
What is research in learning?

उत्तर शोध-आधारित सीखने के दृष्टिकोण में, महत्त्वपूर्ण, प्रासंगिक और दिलचस्प प्रश्नों और चुनौतियों का पता लगाने के लिए छात्र सक्रिय रूप से खोज करते हैं और फिर कई संसाधनों और ग्रन्थों का उपयोग करते हैं। वे पढ़ने के कौशल और शब्दावली का निर्माण करते समय जानकारी और विचारों को ढूँढ़ते हैं। संसाधित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. बौद्धिक पूँजी निर्माण एवं मानव संसाधन विकास के महत्त्व बताइए।
State the importance of intellectual capital formation and human resource development.

उत्तर

बौद्धिक पूँजी निर्माण एवं मानव संसाधन विकास का महत्त्व
(Importance of Intellectual Capital Formation and Human Resource Development)

किसी देश का आर्थिक विकास उस देश में उपलब्ध मानव पूँजी के स्टॉक तथा संचय की दर पर निर्भर करता है। विकासशील देशों में नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया में मानव के विकास पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता। यही कारण है कि इन देशों में विकास के वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाते हैं तथा वहाँ विकास की दर निम्न रहती है। अत: विकास की प्रक्रिया में पूँजीगत साधनों-प्लाण्ट तथा मशीनरी पर व्यय करने के साथ-साथ मानव पूँजी के विकास पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आज अधिकांश विकासवादी अर्थशास्त्री इस बात के पक्षधर हैं कि मानव-पूँजी में अधिक-से-अधिक विनियोग किया जाना चाहिए ताकि आर्थिक विकास के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटक मानव संसाधन का समुचित विकास किया जा सके।

मानव संसाधन विकास आर्थिक विकास का एक प्रभावकारी एवं सकारात्मक अवयव है। किसी देश के सर्वांगीण विकास के लिए वहाँ के मनुष्यों का निपुण, ज्ञानी और बुद्धिमान होना आवश्यक होता है। अल्प-विकसित देशों के आर्थिक विकास में अविकसित मानव संसाधन की उपस्थिति सबसे प्रमुख बाधा है। इन देशों में क्रान्तिक कौशल, निर्णायक चातुर्य एवं निपुणता की कमी रहती है, अत: भौतिक पूँजी चाहे वह स्वदेशी हो अथवा आयातित हो उसका उत्पादन में समुचित कुशलता के साथ प्रयोग नहीं हो पाता है। अत: इन देशों में मात्र भौतिक पदार्थों पर व्यय करके ही आर्थिक विकास की समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता है। मानव संसाधन के विकास पर ध्यान न देकर भौतिक साधनों पर ही ध्यान केन्द्रित करना ऐसा होगा जैसे बिना योग्य इन्जीनियर के इन्जन तथा बिना मैकेनिक के मशीनरी। मशीन के साथ-साथ योग्य मनुष्य का भी होना जरूरी होता है जो उसे चलाता है, व्यवस्थित रखता है तथा उसकी मरम्मत करता है। अत: मनुष्य में निवेश करना उतना ही महत्त्वपूर्ण होता है जितना कि भौतिक पूँजी में।

TOUCH n PASS

प्र.2. मानव संसाधन विकास अथवा बौद्धिक पूँजी निर्माण के स्रोतों का उल्लेख कीजिए।
Explain the sources of human resource development or intellectual capital formation.

उत्तर

मानव संसाधन विकास अथवा बौद्धिक पूँजी निर्माण के स्रोत
(Sources of Human Resource Development or Intellectual Capital Foration)

अल्प-विकसित देशों के विकास की प्रारम्भिक अवस्था में मानव विकास के दो मुख्य स्रोत माने जाते हैं—(1) आन्तरिक स्रोत तथा (2) बाह्य स्रोत

1. **आन्तरिक स्रोत** (Internal Source)—मानव संसाधन विकास कौशल निर्माण के आन्तरिक साधनों के दो रूप हो सकते हैं—(क) विशिष्ट तकनीकी संस्थानों की स्थापना करना तथा उनमें शिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराना तथा (ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना कर उनमें प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करना। वर्तमान समय में लगभग सभी विकासशील देशों में प्राविधिक संस्थाओं एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जा रही है। भारत में भी इस तरह की अनेक संस्थाओं की स्थापना की गई है। जहाँ तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
2. **बाह्य स्रोत** (External Source)—बाह्य स्रोत से तात्पर्य है—विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता लेना अथवा घरेलू श्रम शक्ति को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी तकनीकी संस्थाओं एवं विशेषज्ञों का ज्ञान का उपयोग करना। अल्प-विकसित देशों में जिस तरह आर्थिक विकास के लिए विदेशी पूँजी का आयात किया जाता है उसी तरह उच्चस्तरीय विदेशी कौशल अर्थात् उच्चस्तरीय तकनीकी ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों, तकनीशियनों एवं प्रबन्धकों की सेवाएँ प्राप्त की जाती हैं। विदेशी कौशल के आयात के मुख्य रूप से चार स्वरूप हो सकते हैं—(i) विदेशी तकनीशियनों को स्थायी अथवा अस्थायी रूप से देश में नियुक्त करना। (ii) घरेलू श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के लिए कुछ समय के लिए विदेशी विशेषज्ञों को आमन्त्रित करना। (iii) देश के श्रमिकों को तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु विदेशों में भेजना। (iv) तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त विदेशी श्रमिकों को देश में प्रवास हेतु प्रोत्साहित करना आदि।

प्र.3. आर्थिक विकास में मानव पूँजी निर्माण के उपाय बताइए।
Give the measures human capital formation in economic development.

उत्तर

मानव पूँजी निर्माण के उपाय
(Measures for Human Capital Formation)

मानव पूँजी निर्माण अथवा मानव संसाधन विकास हेतु निम्न उपायों को प्रयोग में लाया जा सकता है—

1. **अनिवार्य शिक्षा** (Compulsory Education)—शिक्षा व्यक्ति को युक्तिपरक बनाकर उसकी कुशलता एवं कार्यक्षमता में वृद्धि करती हैं। शिक्षित व्यक्ति देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अधिक सकारात्मक भूमिका निभा सकता है।
2. **तकनीकी शिक्षा पर अधिक बल** (More Emphasis on Technical Education)—अल्पविकसित देशों में विभिन्न व्यवसायों में शिक्षित एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों के रूप में मानव पूँजी की आवश्यकता इसलिए अधिक होती है क्योंकि वे जटिल विधियों एवं उपकरणों का प्रयोग करते हैं। अत: उनके यहाँ सामान्य स्नातकों की अपेक्षा क्रान्तिक कुशलताओं (Critical Skills) वाले व्यक्तियों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए, इन देशों में उद्यमियों, व्यापार प्रबन्धकों, प्रशासकों, वैज्ञानिकों तकनीशियनों, इन्जीनियरों, डॉक्टरों आदि की अधिक आवश्यकता पड़ती है।
3. **शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन** (Change in Educational System)—मानव पूँजी निर्माण हेतु शिक्षा प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन एवं सुधार आवश्यक है। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सामान्य स्नातक स्तर तक शिक्षा प्रदान करने मात्र से मानव पूँजी निर्माण नहीं होता, इससे शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है जिससे सामाजिक असन्तोष में वृद्धि होती है तथा उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

TOUCH 'n PASS

4. **समुचित प्रेरणा** (Proper Motivation)—हार्बिन्सन का मत है कि तीव्र आर्थिक विकास के लिए शिक्षा में निवेश को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए पुरुषों तथा स्त्रियों को इस बात की समुचित प्रेरणा दी जाए कि वे ऐसी उत्पादक क्रियाओं की ओर उन्मुख हों, जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। व्यक्तियों को प्रशिक्षित किए जाने की जिम्मेदारी प्रमुख नियोजक संस्थाओं पर डाली जानी चाहिए तथा इन संस्थाओं का समुचित पथ-प्रदर्शन किया जाना चाहिए ताकि वे आधुनिक रोजगार कार्यक्रमों का विकास कर सकें।

प्र.4. मानव पूँजी में विनियोग की सीमाएँ लिखिए।
Write the limitations of investment in human capital.

उत्तर

मानव पूँजी में विनियोग की सीमाएँ
(Limitations of Investment in Human Capital)

मानव पूँजी में विनियोग के औचित्य व महत्त्व को आज निर्विवाद रूप में स्वीकृत किया जा चुका है। परन्तु अल्पविकसित देशों में व्याप्त गरीबी एवं पूँजी की कमी से मानव पूँजी के विकास में समुचित विनियोग नहीं हो पाता, इसके फलस्वरूप इन देशों में कौशल निर्माण की गति धीमी रहती हैं।

अल्पविकसित देशों में निम्न कारणों से मानव पूँजी में निवेश की गति धीमी रहती हैं—

1. इन देशों में मानव संसाधनों के विकास हेतु विनियोजित की जाने वाली पूँजी का अभाव होता है।
2. अल्पविकसित देशों को कौशल निर्माण के लिए विदेशी तकनीकी ज्ञान का आयात करना पड़ता है। जिसके लिए विदेशी विनिमय कोषों की आवश्यकता होती है, परन्तु इन देशों में विदेशी विनिमय का सर्वथा अभाव पाया जाता है।
3. अधिकांश अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएँ कृषि प्रधान होती हैं और कृषि के अन्तर्गत नव-प्रवर्तन और कौशल निर्माण की सम्भावनाएँ कम रहती है।
4. इन देशों के सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संगठनों तथा रूढ़िवादी विचारों के कारण भी प्राविधिक ज्ञान को अपनाने व लागू करने में कठिनाई बनी रहती है।
5. इन देशों में लोग विकास, ज्ञान तथा कौशल के प्रति उदासीनता प्रदर्शित करते हैं। इससे मानव पूँजी में विनियोग को प्रोत्साहन नहीं मिलता।
6. अल्पविकसित देशों में वित्तीय साधनों का अभाव पाया जाता है, अत: ऐसी दशा में यदि उपलब्ध साधनों का अधिकांश भाग मानवीय साधनों के विकास पर व्यय कर दिया जाए तो भौतिक विकास के लिए साधनों का अभाव बना रहेगा, जो त्वरित आर्थिक विकास की दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता।
7. कौशल निर्माण एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। मानव संसाधनों के विकास की यह एक प्रक्रिया है जो निरन्तर किए जाने वाले प्रयासों के फलस्वरूप दीर्घकाल में ही फलीभूत हो पाती है क्योंकि कौशल निर्माण के प्रमुख तीन तत्त्वों-शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुभव को साकार रूप प्रदान करने के लिए एक लम्बे समय तक विनियोग करना पड़ता है। अत: राष्ट्रीय स्तर पर कौशल निर्माण के लिए पर्याप्त एवं लगातार विनियोग, असीमित धैर्य तथा पूर्ण सतर्कता की आवश्यकता पड़ती है।

प्र.5. 'करके सीखने' पर टिप्पणी कीजिए।
Write a note on 'Learning by doing'.

उत्तर

करके सीखना
(Learning By Doing)

यह सर्वज्ञात तथ्य है कि जानकारी और कौशल अर्जन कार्य अनुभव से प्राप्त होता है। किसी वस्तु विशेष के उत्पादन से सम्बन्धित कार्य के करने से प्राप्त जानकारी एवं अनुभव के आधार पर उस वस्तु के उत्पादन को दक्षता तथा उत्पादकता के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। श्रमिक, प्रबन्धक, उद्यमी, व्यवसायी एवं पूँजी के स्वामी अनुभव एवं कौशल अर्जन के फलस्वरूप अपने उत्पादन की लागत घटाकर उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर अधिकतम लाभ प्राप्ति में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। अपने 'श्रम विभाजन' के विचार की विवेचना करते समय एडम स्मिथ ने जानकारी एवं कौशल अर्जन की प्रक्रिया के महत्त्व को स्पष्ट किया है। जानकारी एवं कार्य अनुभव के आधार पर ही श्रमिक विशिष्टता एवं निपुणता अर्जित करता है। प्रबन्धक भी अनुभव के आधार पर अपनी दक्षता में वृद्धि करता है।

TOUCH 'n PASS

असमावेशित तकनीकी प्रगति में अनुभव से प्राप्त ज्ञान एवं बाह्यजात तन्त्र है। असमावेशित तकनीकी प्रगति विशुद्ध रूप से संगठनात्मक होती है जिसमें आगतों में परिवर्तन किए बिना तथा बिना किसी नवीन निवेश के अधिक उत्पादन किया जाता है यह सब अनुभव से प्राप्त कौशल के आधार पर ही होता है।

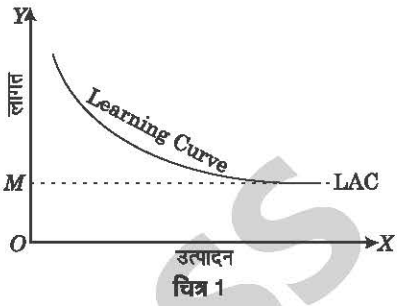

चित्र 1

जानकारी अनुभव से प्राप्त होती है। यदि इस सम्बन्ध में अनुभव को उत्पादित वस्तु की मात्रा से मापा जाता है तो जितना अधिक उत्पादन होगा, प्रति इकाई लागत उतनी ही कम होगी। जानकारी के परिणाम बढ़ते हुए प्रतिफल की तरह होते हैं। जानकारी होने से उत्पादकता की दर बढ़ जाती है जब फर्में नई वस्तुएँ उत्पादित करना प्रारम्भ करती हैं, तो 'करके सीखने' को अंगीकार करती हैं। जब वे पहली इकाई उत्पादित कर लेती हैं तो अनुभव एवं जानकारी के आधार पर समय एवं लागतों को कम करने का प्रयास करती हैं। वस्तु बनाने के साथ-साथ बढ़ रहे अनुभव से लागतें गिरती जाती हैं जब इसकी अधिक-से-अधिक मात्रा उत्पादित की जाती है। जब फर्म जानकारी की सभी सम्भावनाओं का उपयोग कर लेती है, तो लागतें न्यूनतम स्तर M पर पहुँच जाती हैं जैसा कि उपर्युक्त चित्र में दिखाया गया है। इस तरह करके सीखने के आधार पर दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का अनुमान लगाया जा सकता है।

प्र.6. विदेशी पूँजी की सीमाएँ लिखिए।
Write the limitations of foreign capital.

उत्तर

विदेशी पूँजी की सीमाएँ
(Limitations of Foreign Capital)

विदेशी पूँजी की सीमाएँ निम्न प्रकार हैं—

1. **विदेशी सहायता विकास के लिए आवश्यक शर्त नहीं—प्रो० बौर** (Bauer) के अनुसार, अल्पविकसित देशों के विकास के लिए विदेशी सहायता अनिवार्य नहीं है। उसके शब्दों में, "विदेशी सहायता गरीबी से ऊपर उठने के लिए स्पष्टतया न तो सामान्यत: आवश्यक और न ही पर्याप्त शर्त है।" यह आर्थिक विकास के लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि बहुत-से नये विकसित देश प्रारम्भ में अल्पविकसित थे तथा बिना विदेशी सहायता के विकसित हुए।
2. **ऋण-भार में उत्तरोत्तर वृद्धि**—विदेशी ऋणों का भार आन्तरिक ऋणों की तुलना में अधिक होता है। इसका कारण यह है कि विदेशी ऋणों का भुगतान केवल विदेशी करेंसी अथवा विदेशी विनिमय के रूप में ही करना पड़ता है। चूँकि अल्पविकसित देशों का विदेशी विनिमय-कोष पहले ही काफी क होता है और फिर, ये देश ऋण सेवा भार (ब्याज) को वहन करने की स्थिति में भी नहीं होते। फलस्वरूप ऋण परिशोधन का बढ़ता हुआ भार इन देशों को और अधिक ऋण लेने के लिए विवश कर देता है जिससे यह देश उत्तरोत्तर ऋणग्रस्तता के विषम चक्र में फँसते चले जाते हैं।
3. **विदेशी सहायता आय-अर्जन क्षमता को नहीं सुधारती**—विदेशी सहायता अल्पविकसित देशों की आय-अर्जन क्षमता को सुधारने में विफल रही है और वे विशाल वाह्य सार्वजनिक ऋणों से अब दबे हुए हैं।
4. **विदेशी विनिमय संकटपूर्ण**—सहज रूप में प्राप्त होने वाली विदेशी पूँजी से देश का भुगतान सन्तुलन प्रतिकूल हो जाता है। अल्पविकसित देशों का भुगतान सन्तुलन एक तो पहले ही प्रतिकूल होता है, दूसरे, उस पर ऋण सेवा भार (ब्याज) और ऋण परिशोधन भार इस भुगतान सन्तुलन पर और अधिक दबाव डालता है। परिणामस्वरूप ऋणी देश का विदेशी विनिमय संकट और भी गहरा हो जाता है।
5. **आर्थिक शोषण**—भूतकाल में विदेशी पूँजी पिछड़े हुए राष्ट्रों के आर्थिक शोषण का एक प्रमुख साधन रही है। इसका जीता-जागता उदाहरण उपनिवेशवाद का वह घिनौना इतिहास है जिसके अन्तर्गत उपनिवेशीय देशों का खुलकर आर्थिक शोषण किया गया। यद्यपि पिछले दो-तीन दशकों से विदेशी पूँजी का स्वरूप काफी बदल चुका है और उसके द्वारा अब शोषण की सम्भावना भी बहुत कम है परन्तु प्रतिकूल परिस्थिति कभी भी आ सकती है।
6. **विकास के प्रारूप का विकृत होना**—आज अधिकांश अल्पविकसित देश अपने तीव्र आर्थिक विकास के लिए नियोजन पद्धति को अपनाए हुए हैं। विदेशी पूँजी का स्वतन्त्र आगमन विकास की प्राथमिकताओं के क्रम को अस्त-व्यस्त कर देता है। इसका कारण यह है कि विदेशी पूँजी प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों में न जाकर, लाभ-पूर्ण क्षेत्रों में जाने की अधिक प्रवृत्ति रखती है। इस प्रकार विदेशी पूँजी ऋणी देश के विकास में सहायक कम, बाधक अधिक सिद्ध होती है।

TOUCH 'n' PASS

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. अन्तर्जात संवृद्धि सिद्धान्त की विवेचना कीजिए।
Discuss the endogenous growth thoery.

उत्तर

अन्तर्जात संवृद्धि
(Endogenous Growth Theory)

विगत कुछ वर्षों से विशेषकर 1980 के दशक से व्यावहारिक अर्थशास्त्र के अन्तर्गत विश्व के विभिन्न देशों के मध्य उत्पादन वृद्धि दरों में व्याप्त विषमता के अध्ययन एवं विश्लेषण का प्रचलन बढ़ा है। इस सम्बन्ध में ढेर सारे शोधकार्य किए गए हैं तथा सम्बन्धित साहित्य का प्रकाशन किया गया है। इस अन्तर्जात संवृद्धि के प्रति उत्तरदायी विभिन्न कारकों की भूमिका की विवेचना जिस सिद्धान्त पर आधारित है उसे 'विकास का नवीन सिद्धान्त' अथवा अन्तर्जात संवृद्धि सिद्धान्त (Endogenous Growth Theory) के नाम से जाना जाता है।

इस सिद्धान्त की व्याख्या में निम्नलिखित तत्त्वों का ज्ञान सकारात्मक भूमिका निभाता है—

1. विश्व के निर्धनतम देशों के निष्पादन पश्चात (Post performance) की स्थिति तथा विभिन्न देशों के बीच विकास दरों में बढ़ती भिन्नता।
2. आँकड़ों की उपलब्धता में बढ़ोतरी जो विश्वसनीयता अर्थमितीय कार्य को सम्भव बनाते हैं।
3. पथ-भंग अध्ययन (Path breaking studies) जो इस परिकल्पना का खण्डन करता है कि कालपर्यन्त विकासशील एवं विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय अभिमुख हो जाएगी। इस परिकल्पना की भविष्यवाणी नव-क्लासिकी वृद्धि सिद्धान्त पर आधारित है जो पूँजी ह्रासमान के प्रतिफल की मान्यता को अंगीकार करता है, जिसके दिए होने पर समान अधिमान एवं प्रौद्योगिकी वाले देशों के बीच गरीब देशों के विकास की गति धनी देशों की अपेक्षा अधिक होगी।

सोलो के उत्पादन-फलन उपागम में वर्णित सोलो अवशेष (Solow's residual) अधिक विकास के एक बड़े अंश की व्याख्या करने में सफल नहीं रहा। इस सम्बन्ध में अब्रामोविट्ज (Abramovitz) ने इंगित किया है कि यह (सोलो अवशेष) संवृद्धि के कारणों की समुचित व्याख्या करने में असफल रहा है। अन्तर्जात संवृद्धि सिद्धान्त, आर्थिक विकास की प्रक्रिया का अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है क्योंकि यह पूँजी संचय पर जोर देता है, तकनीकी परिवर्तन की अन्तर्जात विधियों पर विचार करता है, मानव पूँजी की भूमिका को महत्त्व प्रदान करता है तथा शोध एवं विकास के महत्त्व पर बल प्रदान करता है। इस सिद्धान्त की सहायता से विभिन्न देशों के बीच राष्ट्रीय आय की वृद्धि-दर के बढ़ते अन्तरों का आकलन किया जा सकता है। सोलो का मॉडल केन्द्राभिमुख (Convergence) होने की भविष्यवाणी करता है क्योंकि यह एक देश की विकास दर तथा इसके आरम्भिक आय स्तर के बीच विपरीत सम्बन्ध निरूपित करता है।

पॉल रोमर (Paul Romar) अन्तर्जात सिद्धान्त के प्रमुख विवेचकों में से एक हैं, जिनका कथन है कि नवीन सिद्धान्त मात्र केन्द्राभिमुख विषय से ही सम्बन्धित नहीं है बल्कि साथ ही अन्य बहुत-सी बातों से भी सम्बन्धित है। उनका तर्क है कि नवीन सिद्धान्त इस वास्तविकता से सम्बद्ध है कि तकनीकी परिवर्तन लोगों की क्रियाओं से निकलकर आता है तथा बहुत से व्यक्तियों तथा फर्मों के पास बाजार शक्ति होती है और वे कीमत ग्रहण करने वाली (Price Taker) नहीं होती जैसा कि पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। अत: आविष्कार विस्तार और प्रौद्योगिकीय प्रगति में वृद्धि संवर्धक की प्रक्रिया को समझने के लिए अपूर्ण प्रतियोगिता के मॉडलों को आर्थिक वृद्धि के सिद्धान्त में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह उपागम परम्परावादी पूर्ण प्रतियोगी नव-क्लासिकी मॉडलों की विपरीत विचारधारा पर आधारित है जहाँ सरकारी हस्तक्षेप विकास की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव डालने में सक्षम नहीं होता। अन्तर्जात वृद्धि सिद्धान्त तकनीकी प्रगति के स्रोतों को पहचानने का प्रयास करता है तथा परिणामी सरकारी नीतियों के निहितार्थ की विवेचना करता है। सोलो का विकास सूत्र समग्र विकास-दर के निर्धारण में पूँजी आगत की लघु भूमिका को निरूपित करता है। उत्पादकता की वृद्धि निश्चित रूप से निवेश क्रिया की दर पर निर्भर करती है। इसका तात्पर्य यह है कि निवेश की क्रियाओं में ही तकनीकी प्रगति निहित है। अन्तर्जात सिद्धान्त इस तथ्य की जाँच करने का कार्य करता है।

अन्तर्जात सिद्धान्त एक ऐसे स्पष्ट सिद्धान्त की विवेचना करता है जो प्रौद्योगिकी साधन (A) के व्यवहार का निर्धारण करता है। जिसे सोलो के मॉडल में एक बहिर्जात तत्त्व माना गया है। अन्य शब्दों में, इस सिद्धान्त प्रौद्योगिकी एक अन्तर्जात तत्त्व हैं।

चूँकि विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकीय सुधार विविधताओं से भरे होते हैं। अत: एक एकाकी सरल मॉडल में ऐसे प्रत्येक परिवर्तनों को सम्मिलित करना एक जटिल एवं कठिन कार्य है। इस समस्या के निराकरण हेतु **रोमर** ने सुझाव दिया कि यह मान लिया जाना

TOUCH 'n' PASS

चाहिए कि जो विचार अथवा आविष्कार प्रौद्योगिकी का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे अन्य वस्तुओं के समान ही पूँजी तथा श्रम की सहायता से उत्पादित किए जा सकते हैं। अन्य शब्दों में, उन्होंने 'इन्वेन्शन फैक्ट्रीज' (Invention factories) के अस्तित्व की कल्पना की है। ये इन्वेन्शन फैक्ट्रीज और कुछ नहीं बल्कि शोध प्रयोगशालाएँ हैं। जो विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकी के अन्वेषण एवं आविष्कार तथा उनमें सुधार के प्रयासों में संलग्न हैं।

इस दृष्टि से एक नए उत्पादन फलन प्रौद्योगिकी का निर्माण करना सम्भव हो जाता है। यह उत्पादन फलन निम्नवत् स्वरूप ग्रहण कर सकता है—

$$\Delta A = T(N_A, K_A, A)$$

जहाँ, ΔA = तकनीकी प्रगति

A = वर्तमान अथवा पहले से ही अस्तित्व में रहने वाली प्रौद्योगिकी

N_A = प्रौद्योगिकी के उत्पादन कार्य में संलग्न श्रमिकों की संख्या

K_A = प्रौद्योगिकी के उत्पादन कार्य में प्रयुक्त पूँजी की मात्रा

T = प्रौद्योगिकी हेतु उत्पादन फलन

यहाँ N_A तथा K_A क्रमशः अर्थव्यवस्था में नियुक्त कुल श्रम (N) तथा पूँजी (K) के एक अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं (अर्थात् $N_A < N$ तथा $K_A > K$)। समीकरण स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित करता है कि प्रौद्योगिकी एक अन्तर्जात तत्त्व है। श्रम तथा पूँजी को अधिक मात्रा में प्रयोग करके प्रौद्योगिकी की प्रगति की ऊँची दर प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान प्रौद्योगिकी (A) भी प्रयोग करने पर प्रौद्योगिकी के सुधार में सहायक हो सकती है। एक शोध प्रयोगशाला में उत्पन्न विचार (Idea) अन्य प्रयोगशाला में भी प्रयुक्त हो सकता है। आविष्कार का पैटेन्ट हो सकता है, परन्तु उससे सम्बन्धित विचारों का प्रयोग अन्यों द्वारा किया जा सकता है। इस दृष्टि से प्रौद्योगिकी एक गैर-अपवर्जी अर्थात् सार्वजनिक वस्तु है।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रौद्योगिकी की वृद्धि-दर तथा परिणामी उत्पादन की वृद्धि दर स्थायी रूप से बढ़ाई जा सकती है। प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में ऐसा होना सम्भव है। पूर्व में वर्णित प्रौद्योगिकी उत्पादन फलन के आधार पर एक नवीन उत्पादन फलन की रचना निम्नवत की जा सकती है। जो प्रौद्योगिकी उत्पादन में प्रयुक्त श्रमिकों की मात्रा तक ही सीमित है—

$$\Delta A = CN_A . A \qquad \text{(जहाँ } C \text{ एक स्थिरांक है।)}$$

या, $$\frac{\Delta A}{A} = CN_A$$

उपर्युक्त समीकरण यह व्यक्त करता है कि प्रौद्योगिकी की वृद्धि-दर दीर्घकाल में इन्वेन्शन फैक्ट्रीज में प्रयुक्त श्रमिकों की मात्रा का फलन है अर्थात् ऐसे श्रमिकों की मात्रा में वृद्धि होते रहने पर प्रौद्योगिकी की वृद्धि-दर $\left(\frac{\Delta A}{A}\right)$ भी बढ़ती जाती है।

$\frac{\Delta A}{A}$ सोलो की वृद्धि आकलन सूत्र (Growth accounting formula) का अंग है। इसका तात्पर्य यह है कि $\frac{\Delta A}{A}$ में होने वाली वृद्धि विकास दर में स्थायी वृद्धि कर देगी।

प्र.2. आर्थिक विकास में बौद्धिक पूँजी (ज्ञान, शिक्षा एवं शोध) की भूमिका लिखिए।

Write the role of intellectual capital (learning, education and research) in economic development.

उत्तर

शिक्षा, शोध एवं ज्ञान की भूमिका
(Role of Education, Research and Knowledge)

किसी देश का आर्थिक विकास उसकी कार्यकुशल, शिक्षित एवं प्रशिक्षित श्रम शक्ति पर निर्भर करता है। आर्थिक विकास एक यान्त्रिक क्रियामात्र ही नहीं वरन् अन्तिम रूप से यह एक मानवीय उपक्रम है। अन्य मानवीय उपक्रमों की भाँति इसका परिणाम सही अर्थों में इसको संचालित करने वाले जन समुदायों की कुशलता, गुणों एवं प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। यदि किसी देश की जनसंख्या उसके आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप है और उसके निवासी विवेकशील, परिश्रमी, शिक्षित व कार्यदक्ष है तो निःसन्देह अन्य बातों के समान रहने पर उस देश का आर्थिक विकास अधिक होगा।

आर्थिक विकास की दृष्टि से 'भौतिक पूँजी' की अपेक्षा 'मानवीय पूँजी' को अधिक महत्त्वपूर्ण समझा जाता है क्योंकि मानवीय साधनों की कुशलता एवं दक्षता पर ही आर्थिक विकास का ढाँचा खड़ा किया जा सकता है। यदि किसी देश के पास पर्याप्त व

TOUCH 'n PASS

श्रेष्ठतम मानव पूँजी उपलब्ध है तो उस देश की भौतिक पूँजी और भी अधिक उत्पादक बन जाती है। इसके विपरीत यदि मानव पूँजी का अभाव है तब भौतिक पूँजी का लाभपूर्ण उपयोग नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी हालत में चलती हुई मशीनें रुकने लगती हैं, उपकरण समय से पूर्व घिसने लगते हैं, उपज की किस्म व उत्पादकता का स्तर गिर जाता है।

वैबलन के अनुसार, प्रौद्योगिकीय ज्ञान तथा कुशलता समाज की 'अभौतिक उपकरण तथा अमूर्त सम्पत्ति' है जिसके बिना भौतिक पूँजी उत्पादकतापूर्वक प्रयोग में नहीं लायी जा सकती। अल्प-विकसित देशों में धीमी वृद्धि के लिए उत्तरदायी मानव पूँजी में निवेश की कमी है। यदि ऐसी अर्थव्यवस्थाएँ शिक्षा तथा तकनीकी ज्ञान का प्रसार नहीं करती और लोगों की कुशलता का स्तर नहीं बढ़ाती तो भौतिक पूँजी की उत्पादकता घट जाती है।

आर्थिक पिछड़ापन दूर करने और प्रगति, क्षमताएँ व प्रोत्साहन उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि लोगों के ज्ञान व कुशलता में वृद्धि की जाए। वास्तव में मानव साधन के गुण में सुधार किए बिना अल्प-विकसित देशों में कोई प्रगति सम्भव नहीं।

अजितदास गुप्त के अनुसार, "शिक्षा को आवंटित किए गए साधन उत्पादकीय क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं, अत: शिक्षा तथा अन्य आधार-संरचना निवेश सिद्धान्त के आवश्यक अंग हैं।"

शिक्षा के बिना आर्थिक विकास सम्भव नहीं है। जैसा कि **प्रो० मिर्डल** ने कहा है कि, "बहुत बड़ी जनसंख्या को निरक्षर छोड़कर राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम शुरू करने की बात मुझे निरर्थक मालूम पड़ती है।"

प्रो० सिंगर का मत है कि शिक्षा में किया गया विनियोग केवल उत्पादक ही नहीं होता, बल्कि यह बढ़ता हुआ प्रतिफल देता है। यही कारण है कि विकसित देशों द्वारा अपने आर्थिक विकास की प्रक्रिया के दौरान शिक्षा, अनुसन्धान पर अधिक महत्त्व प्रदान किया गया है। यहाँ तक कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीकी नव प्रवर्तनों का लगभग दो-तिहाई योगदान माना जाता है।

इस तरह, आर्थिक रूप से उन्नत देशों ने अपना आर्थिक विकास अपने योग्य एवं प्रशिक्षित श्रमिकों तथा तकनीशियनों के बल पर किया है। अमेरिकी अर्थशास्त्रियों; जैसे—शुल्ज, हार्बिन्सन, डैनिसन, कैण्ड्रिक व कुजनेट्स आदि द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की तीव्र वृद्धि के लिए मुख्य रूप से शिक्षा पर किया गया विनियोग ही उत्तरदायी है। इन लोगों का कथन है कि शिक्षा पर खर्च किया गया एक डॉलर, राष्ट्रीय आय में उसकी अपेक्षा अधिक वृद्धि करता है जितना आर्थिक संरचना (बैंध, सड़कें आदि) व पूँजीगत वस्तुओं पर एक डॉलर लगाने से प्राप्त होता है।

इस तरह, विकास की प्रक्रिया में शिक्षा का महत्त्व एक गैर-विवादित सत्य है। अत: आज विश्व के देशों में मानव पूँजी में निवेश हेतु उच्च प्राथमिकता दी जाती है। मानव पूँजी में निवेश से तात्पर्य संकुचित अर्थों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर व्यय करना है, जबकि व्यापक अर्थों में, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सभी सामाजिक सेवाओं पर व्यय करने से लगाया जाता है।

शिक्षा सम्बन्धी विनियोग मुख्यत: निम्न तीन क्षेत्रों में किए जा सकते हैं—

1. कृषि विस्तार सेवाओं की व्यवस्था करने,
2. औद्योगिक कौशल को उन्नत करने, तथा
3. प्रशासकीय एवं प्रबन्धकीय क्षमता में वृद्धि करने हेतु।

निष्कर्ष रूप में, मानव पूँजी में विनियोग के औचित्य व महत्त्व को आज निर्विवाद रूप में स्वीकार किया जा चुका है, परन्तु अल्पविकसित देशों में मानवीय विनियोग की अपनी कुछ सीमाएँ हैं जिनके कारण इन देशों में वांछित दर से कौशल निर्माण नहीं हो पाता।

शोध एवं विकास
(Research and Development)

आर्थिक प्रगति के सतत् सुधार में तकनीकी अथवा प्राविधिक परिवर्तन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तकनीकी प्रगति वस्तुत: शोध, अन्वेषण तथा नव-प्रवर्तन के संयोग का परिणाम है। शोध तथा अन्वेषण वे क्रियाएँ हैं जो ज्ञान का सृजन करती हैं तथा विकास व नव-प्रवर्तन वे क्रियाएँ हैं जो नए ज्ञान का उत्पादन कार्य में प्रयोग करती हैं। इस तरह शोध एवं अन्वेषण ही प्राविधिक परिवर्तन का आधार होते हैं। **प्रो० किण्डल बर्जर** के अनुसार, "प्राविधिक प्रगति का अर्थ किसी व्यवसाय में प्रयुक्त, ज्ञान और वास्तविक उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन हैं। इसके द्वारा उसी मात्रा में साधनों के प्रयोग से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है अथवा उसी मात्रा में उत्पादन प्राप्त करने के लिए साधनों की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। इसका प्रभाव पुराने उत्पादन की अधिक मात्रा के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाले नए उत्पादनों के रूप में भी हो सकता है।" **प्रो० शुम्पीटर** के अनुसार, "प्राविधिक प्रगति से आशय अर्थव्यवस्था में उत्पादन साधनों के ऐसे संयोग का प्रवेश है जो पहले सम्भव नहीं था अथवा प्रयुक्त नहीं किया

TOUCH 'n PASS

गया था। यह एक ऐसी वस्तु है जिसे आन्तरिक साधन के रूप में प्रवेश दिया जाता है और जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर आर्थिक संक्रान्ति की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होती है।''

तकनीकी प्रगति में योगदान देने वाले विभिन्न तत्त्वों के सापेक्ष महत्त्व और स्वयं प्रगति की रफ्तार भी विभिन्न देशों में उनकी विकास अवस्थाओं तथा सामाजिक, आर्थिक शक्ति के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिक प्रगति के अनेक स्रोत एक-दूसरे से पृथक भी नहीं होते, बल्कि वे परस्पर अन्तर्सम्बन्धित होते हैं। फिर भी तकनीकी प्रगति के चार मुख्य स्रोत निम्नांकित हैं—

1. देश की जनता की अन्वेषणकारी तथा नव-प्रवर्तनकारी क्रियाएँ।
2. विदेशी व्यापार, विदेशी सहायता अथवा सम्पर्क आदि विभिन्न माध्यमों से विदेशों से सुधारी हुई तकनीकों का आयात।
3. 'करके सीखना' (Learning by doing) अर्थात् देश के श्रमिकों, प्रबन्धकों मालिकों का उत्पादन कार्यों में व्यावहारिक अनुभव और सीख।
4. मानवीय पूँजी में निवेश अर्थात् देश की जनता तथा श्रमिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा निपुणता में सुधार।

प्रो० शुम्पीटर ने विकास की प्रक्रिया में साहसी तथा नव-प्रवर्तन के योगदान पर विशेष बल दिया है। शुम्पीटर के विचार में प्रगति रचनात्मक विनाश की प्रक्रिया का परिणाम है। यदि देश में तकनीक का विकास नहीं हो रहा हो तो विदेशी तकनीकों को आत्मसात किया जा सकता है। विदेशों की प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने की क्रिया को 'सांस्कृतिक विकरण प्रक्रिया' कहा जाता है। अन्वेषण तथा नव-प्रवर्तन जनता के सांस्कृतिक गुणों पर निर्भर होते हैं।

तकनीकी प्रगति आज के विकसित समाज की एक प्रमुख विशेषता है, परन्तु तकनीकी प्रगति एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत नयी तकनीकें, नयी मशीनें, परिवर्धित कार्य कुशलता तथा उत्पादकता आदि सम्मिलित हैं। तकनीकी विकास के लिए किसी भी समाज को लम्बी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। **प्रो० साइमन कुजनेट्स** ने तकनीकी विकास के विभिन्न सोपानों का निर्धारण निम्न प्रकार किया है—

1. वैज्ञानिक खोज अथवा तकनीकी ज्ञान में वृद्धि,
2. आविष्कार अर्थात् उपयोगी उद्देश्य हेतु उपलब्ध ज्ञान का उपयोग,
3. आविष्कार का आर्थिक उत्पादन में प्रयोग अर्थात् नव-प्रवर्तन,
4. नव-प्रवर्तन का आधिकाधिक प्रसार एवं उसमें सुधार।

इस प्रकार तकनीकी प्रगति एक धीमी, लम्बी एवं बहुमुखी प्रक्रिया है जिसका प्रारम्भ मौलिक खोजों से भी हो सकता है और उत्पादन प्रक्रिया में सूक्ष्म सुधार से भी।

आधुनिक विकसित अर्थव्यवस्थाओं में तकनीकी खोजों पर नियमित रूप से भारी मात्रा में धन व्यय किया जाता है तथा निरन्तर सुधार की चेष्टा की जाती है। तकनीकी प्रगति के आधार पर ही पश्चिमी देशों में पूँजी प्रधान उत्पादन व्यवस्था का विकास हो सका है। इस प्रकार आधुनिक पूँजी प्रधान उत्पादन तकनीकी विकास का परिणाम है और तकनीकी विकास वैज्ञानिक विकास का परिणाम है। अन्य शब्दों में, शोध एवं अन्वेषण आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का आधार है और आधुनिक तकनीक आर्थिक प्रगति का आधार है।''

बौद्धिक पूँजी निर्माण
(Intellectual Capital Formation)

किसी देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गतिशील बनाने तथा उपलब्ध संसाधनों का युक्तिपरक विदोहन करने में उस देश की विवेकशील जनसंख्या की भूमिका अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होती हैं। जिस देश की जनसंख्या अधिक शिक्षित, प्रशिक्षित तथा तकनीकी ज्ञान से युक्त होती है वह देश उतनी ही तेजी से विकास करता है। वास्तव में, देश के पास बौद्धिक सम्पदा के रूप में इन्जीनियर, तकनीकी प्रशिक्षक, प्रबन्धकीय और प्रशासकीय वर्ग, वैज्ञानिक, चिकित्सक व कृषि विशेषज्ञ होने पर भौतिक पूँजी अधिक उत्पादक बन जाती है। यही कारण है कि वर्तमान में समस्त देश अपने उपलब्ध संसाधनों की सहायता से बौद्धिक पूँजी निर्माण की प्रक्रिया में संलग्न हैं। बौद्धिक पूँजी निर्माता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत देश के नागरिकों के ज्ञान, कुशलता एवं क्षमताओं में वृद्धि हेतु मुद्रा का निवेश किया जाता हैं।

वैबलन के अनुसार, प्रौद्योगिकीय ज्ञान तथा कुशलता समाज के अभौतिक उपकरण एवं अमूर्त सम्पत्ति है जिसके बिना भौतिक पूँजी उत्पादकतापूर्वक प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है। इस तरह स्पष्ट है कि अल्पविकसित देशों में धीमी प्रगति के लिए उत्तरदायी मानव पूँजी अथवा बौद्धिक सम्पदा के विकास हेतु पर्याप्त मात्रा में निवेश न किया जाना है।

TOUCH 'n PASS

प्र.3. भौतिक आगत पर टिप्पणी कीजिए।
Write a long note on physical input.

उत्तर

भौतिक आगत
(Physical Input)

पश्चिमी देशों में सांख्यिकी अनुसंधान दिखाते हैं कि भौतिक आगत की अपेक्षा उत्पादन में ऊँची दर से वृद्धि हुई हैं। इसका कारण है कि मानव की योग्यता, उत्पादन साधनों के लिए लगातार बढ़ रही है। क्योंकि शिक्षा और कुशल, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धि इत्यादि में सुधार हुआ है। इसलिए भौतिक विकास के साथ मानव विकास भी होना चाहिए।

एडम स्मिथ एसे अर्थशास्त्री हैं अर्थशास्त्री जिन्होंने मानव की निपुणता व मानव को उत्पादन साधन माना है। **प्रो० मार्शल** ने इस विचार को नकार दिया है और कहा है कि मानव बाजार के लिए नहीं है। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि शिक्षा में निवेश प्रतिफल के लिए लेना चाहिए और इसे मानव व पूँजी में निवेश समझना चाहिए जो मानव पूँजी निर्माण को बढ़ाता है।

शिक्षा और आर्थिक वृद्धि
(Education and Economic Growth)

शिक्षा में निवेश से आर्थिक वृद्धि होती है। वास्तव में, भौतिक पूँजी का प्रयोग मानव संसाधन पर निर्भर करता है। पश्चिम देशों में किए गए अध्ययन ने आर्थिक वृद्धि में शिक्षा के योगदान को दिखाया (मापा) हैं। **प्रो० एडवर्ड एफ० डेन्सन** ने बताया है कि शिक्षा में निवेश ने कुल राष्ट्रीय आय में 23 प्रतिशत की वृद्धि और अमेरिका में रोजगार प्राप्त लोगों ने वास्तविक राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति 42 प्रतिशत का आर्थिक वृद्धि में योगदान किया। यह आँकड़े 1929-57 के बीच लिए गए हैं।

प्रो० टोडारो के अनुसार शिक्षा विकसित तथा अल्पविकसित देशों में योगदान देती है जो निम्न प्रकार है—

1. यह ज्यादा (बड़ी मात्रा) में उत्पादक श्रम शक्ति जुटाने में मदद करती है तथा साथ में ज्ञान व कुशलता में वृद्धि भी होती है।
2. यह अधिक मात्रा में शिक्षक, स्कूल तथा दूसरे क्षेत्रों में श्रमिक, कापी व पेपर को छापने स्कूल यूनिफॉर्म बनाने वाले इत्यादि को रोजगार प्रदान करती है।
3. यह शिक्षक नेताओं की क्लास (वर्ग) बनाने में सहायता करती है। जैसे—सरकारी सेवाएँ, सार्वजनिक कॉरपोरेशन, निजी व्यवसाय आदि।
4. यह जनसंख्या को निपुणता तथा आधुनिक धार अपनाने में मदद करती है।

शिक्षा से आय असमानता में कमी, ज्ञान में वृद्धि तथा खोज करने में सहायता मिलती है। इससे मानव विकास में भी वृद्धि होती है। शिक्षा में विकास पंचवर्षीय योजनाओं से शुरू हुआ। भारत में शिक्षा में खर्च का नाम तथा दूसरे (पश्चिमी देशों) में इसे शिक्षा में निवेश का नाम दिया है। भारत में शिक्षा खर्च को मानव संसाधन में निवेश का नाम नहीं दिया है इसलिए आर्थिक वृद्धि के नाम से अथवा उसके बढ़ाने के नाम से शिक्षा को जगह मिली है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में नियोजन कमीशन ने ₹ 21,217 करोड़ शिक्षा पर खर्च किए। यह इस योजना के सार्वजनिक क्षेत्र का 4.9 प्रतिशत था। यद्यपि शिक्षा पर खर्च वर्तमान समय में भी पूर्ण नहीं हैं। 160 देशों में से सम्बन्धित आँकड़े बताते है कि भारत का रैंक (सार्वजनिक खर्च शिक्षा पर तथा GNP पर में योगदान) 82 है जो काफी नीचे है। वर्तमान समय में भारत में शिक्षा में कुछ सुधार हुआ है न कि साक्षरता बल्कि स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई हैं। लेकिन फिर भी भारत में ऊँची तथा तकनीकी शिक्षा की सुविधाएँ कम है क्योंकि यदि ज्ञान तथा शोध के बारे में बात की जाए तो यह तभी सम्भव है जब तकनीकी शिक्षा में वृद्धि हो।

शिक्षा, ज्ञान व शोध के क्षेत्र में अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में बहुत कम परिवर्तन हुए हैं शिक्षा के स्तर में अथवा सुधार में भारत में केवल इसकी बनावट बदली है। इसके अलावा अधिक परिवर्तन नहीं हो पाए। इन अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में थोड़े-थोड़े परिवर्तन किए गए हैं जो पहल कोलानियल देश; जैसे—फ्रांस, इंग्लैण्ड, स्पेन, बेल्जियम, पुर्तगाल और संयुक्त राज्य के अधिकतर बराबर दिखाई देते हैं। अल्पविकसित देशों की प्रकृति कृषि साधन की प्रवृत्ति है और जो विदेशों से तकनीक का हस्तान्तरण हुआ है उसके लिए शिक्षा स्तर की भी आवश्यकता है।

इसके साथ अमीर देशों ने भौतिक तथा मानवीय तकनीक के हस्तान्तरण से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार पर अपना दबदबा बना रखा है। इस वजह से इन देशों के बीच आय में बहुत ज्यादा असमानता उत्पन्न हुई। अन्तर्राष्ट्रीय माइगरेशन में अधिक अवसर प्राप्त होने की वजह से अल्पविकसित देशों से इंजीनियर, डॉक्टर अथवा दूसरे कार्य में निपुण व्यक्ति विकसित देशों में चले जाते हैं जिससे

TOUCH 'n' PASS

"Brain drain" की समस्या उत्पन्न हुई है। विकसित देशों में इस तरह का "Brain drain" उनकी केवल अच्छी नीति से नहीं, न ही अल्पविकसित देशों की आर्थिक नीति से, बल्कि अल्पविकसित देशों में शिक्षा नीति का सही नहीं होना है। यह 'ब्रेन ड्रेन' न कि अल्पविकसित देशों की पूर्ति को प्रभावित करता है बल्कि देश में उत्पन्न होने वाली समस्याओं (घरेलू समस्याओं) की तरफ से भी ध्यान को हटाता है। यह रुकना तभी सम्भव है जब रहने की लागत कम हो, हॉस्पिटल, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएँ तथा इस तरह की तकनीकी प्रयोग की जाए ताकि शिक्षित युवक व युवती को अवसर प्राप्त हो।

यदि हमारे देश के अन्दर उचित शिक्षा, ज्ञान तथा अन्वेषण किए जाएँ तो इससे उत्पादन लागत में कमी होगी। रोजगार के ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे तथा लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होगी और जो डॉक्टर, इन्जीनियर अथवा दूसरे intellectuals विदेश में चले जाते हैं उनका योगदान हमारे देश में होगा। अल्पविकसित देशों को अपनी शिक्षा नीति में modification न कर बल्कि इसको परिवर्तित करना होगा। क्योंकि हम केवल विदेशी नकल कर उनके अनुसार अपने उद्देश्य को निर्धारित कर लेते हैं लेकिन वे कैसे प्रभावी होंगे। इस बारे में अन्वेषण नहीं करते। अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं को शिक्षा नीति में आवश्यक परिवर्तन करने चाहिए। शिक्षा में बढ़ोतरी के लिए खर्च का नाम न देकर बल्कि उसमें निवेश कर इसको उद्योग का दर्जा देना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति बुश से पूछा गया अपने देश के प्रति आपका क्या उद्देश्य या लक्ष्य है? उनका जवाब था शिक्षा। शिक्षा नीति को कल्याण सिद्धान्त का नाम न देकर यह आर्थिक वृद्धि में कितना योगदान कर सकती हैं इसके बारे में ध्यान देना चाहिए तभी हम अपने देश को विकास की प्रकृति व इसकी प्रवृत्ति को बढ़ा सकते हैं।

प्र.4. अन्तर्जात विकास सिद्धान्त की समालोचना एवं विकासशील और विकसित देशों के लिए अन्तर्जात विकास के नीतिगत निहितार्थ स्पष्ट कीजिए।

Criticize the theory of endogenous growth and explain the policy implications of endogenous growth for developing and developed countries.

उत्तर

अन्तर्जात विकास मॉडलों की समालोचना
(Criticisum of Endogenous Development Model)

अनेक अर्थशास्त्रियों ने अपने-अपने विचार से नए विकास सिद्धान्त की आलोचना की है, जिनमें कुछ इस सामान्य प्रस्ताव पर आधारित है कि अन्तर्जात विकास सिद्धान्त नयी तरह का नहीं है जो कि निम्न प्रकार है—

1. स्कॉट एवं अवर्बैंक का मानना है कि नव विकास सिद्धान्त को एडम स्मिथ के दर्शन में और वर्धमान लाभ को मार्क्स के विश्लेषण में देखा जा सकता है।
2. श्रीनिवासन को नव-विकास सिद्धान्त में कुछ भी नया नहीं लगता क्योंकि वर्धमान लाभ और चरों की अन्तर्मुखता विकास के नवशास्त्रीय और कैल्डर मॉडलों से लिए गए हैं।
3. फिशर इसकी आलोचना यह कहकर करते हैं कि यह केवल उत्पादन फलन और स्थिर अवस्था पर निर्भर करता है।
4. ओल्सन को लगता है कि यह मानव पूँजी की भूमिका पर बहुत अधिक जोर देता है और संस्थाओं की भूमिका को नकारता है।
5. नव-विकास सिद्धान्तों के विभिन्न मॉडलों में भौतिक और मानव पूँजी के बीच अन्तर स्पष्ट नहीं है।
6. अन्तर्जात विकास सिद्धान्त आनुभाविक साक्ष्य से पुष्ट किया जाना असम्भव हैं।
7. इसे ऐसी अवधारणाओं पर आधारित बताया जाता है जिनको सही-सही आँका नहीं जा सकता।
8. ये सभी सिद्धान्त आनुभाविक साक्ष्य में प्रस्तुत सशर्त सम्मिलन को स्पष्ट नहीं करने में विफल रहते हैं।
9. नव-विकास सिद्धान्त की एक बड़ी कमी यह है कि परम्परागत नवशास्त्रीय सिद्धान्त की अनेक अवधारणाओं पर निर्भर है, जोकि प्राय: विकासशील और अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए अनुपयुक्त होते हैं।
10. विकासशील देशों में आर्थिक संवृद्धि प्राय: निकृष्ट अवसंरचना, अपर्याप्त संस्थाओं तथा अपूर्ण पूँजी और माल बाजारों के कारण उत्पन्न अक्षमता से अवरुद्ध रहती है। अन्तर्जात विकास सिद्धान्त इन कारकों का समावेश करने में विफल रहता है।
11. यह सिद्धान्त विशेष रूप से दीर्घावधि विकास पर ही दृष्टि डालता है और अल्पावधि एवं मध्यावधि विकास को अनदेखा करता है।

TOUCH 'n PASS

विकसित और विकासशील देशों के लिए नीतिगत निहितार्थ
(Plicy Implication of Endogenous Growth for Developing and Developed Countries)

अन्तर्जात विकास सिद्धान्त के अनुसार, विकासशील और विकसित देशों की प्रति व्यक्ति विकास दरों का अभिसरण कभी होगा, यह सम्भव ही नहीं। भौतिक और मानव पूँजी दोनों पर वर्धमान लाभ का अर्थ है कि निवेश पर लाभ दर विकासशील देशों के सापेक्ष विकसित देशों में नहीं गिरेगी। अतएव, पूँजी प्रवाह विकसित से विकासशील देशों की ओर मोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, जबकि वास्तव में इसका विपरीत ही हो सकता है।

भौतिक और मानव पूँजी दोनों का संवृद्धि में मापित योगदान सोलो मॉडल द्वारा सुझाए गए योगदान से कही अधिक होगा। शिक्षा अथवा R&D में निवेश स्वयं फर्म पर सकारात्मक प्रभाव ही नहीं बल्कि अन्य फर्मों और समग्र अर्थव्यवस्था पर अधिप्लावन प्रभाव भी दर्शाता है। इसके अनुसार, सोलो विकास लेखांकन में प्रौद्योगिकीय परवर्तन की वजह से दिखने वाली बचत दरअसल पहले से भी कम नजर आ सकती है। हाल के विकास लेखा प्रयोग दर्शाते हैं कि 'अस्पष्ट बचत' की वजह से होने वाली संवृद्धि की प्रतिशतता अल्प उन्नत अर्थव्यवस्था के लिए काफी कम होती है। यह दरअसल, बस इन देशों में पूँजी को ही दर्शाता है। विकल्पत: यह विकास सिद्धान्त से आमतौर पर हटा दिए गए ऐसे अन्य सरोकारों को दर्शा सकता है जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए विशेष प्रासंगिकता रखते हों। उदाहरण के लिए, तीसरी दुनिया के देशों की विकास प्रक्रिया में मुख्य तत्त्वों के रूप में प्रबन्धन, संगठन, अवसंरचना और क्षेत्रीय हस्तान्तरण के महत्त्व पर जोर देते हैं।

यह आवश्यक नहीं कि वर्धमान अनुमापी प्रतिफल प्राप्त अर्थव्यवस्थाएँ आय वृद्धि के स्थिरावस्था स्तर पर पहुँचे ही, जैसा कि सोलो-स्वॉन मॉडल कहता है। इसके अलावा, शोध व विकास की सकारात्मक बाह्यताओं के साथ, आय वृद्धि धीमी नहीं पड़ती और अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में नहीं पहुँचती। दूसरी ओर, बचत दर में वृद्धि अर्थव्यवस्था की विकास दर में किसी स्थायी वृद्धि की ओर प्रवृत्त कर सकती है।

मानव पूँजी के वृहत्तर भण्डार रखने वाले और शोध व विकास में अधिक निवेश करने वाले देश आर्थिक विकास की तीव्र दर का लाभ उठाएँगे। यह अनेक विकासशील देशों के धीमे विकास का कारण हो सकता है।

इससे सम्भवत: अपना सर्वाधिक लाभ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लेने की पक्षधर कोई भी अल्पविकसित अर्थव्यवस्था पहले से अधिक स्वतन्त्र महसूस करने लगती है क्योंकि ऐसा करके ही वह विश्व ज्ञान भण्ड़ार तक अपनी पहुँच बना सकती है। परन्तु अमीर देशों से गरीब देशों को प्रौद्योगिकी का प्रवाह स्वत: कदापि नहीं होता। इससे सवाल खड़ा होता है कि यहाँ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की क्या भूमिका रहती है और वे प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण हेतु प्रोत्साहनों का प्रत्युत्तर किस प्रकार देती है। यह स्वाभाविक रूप से शासकीय नीति का प्रश्न सामने रखता है।

अन्तर्जात विकास के आधुनिक प्रकथनों का सार यह है कि तकनीकी प्रगति बचत के लिए उत्तरदायी भी अन्तर्जात मानव पूँजी-निर्माण ही होता है। परन्तु यदि परवर्ती को सरकारी नीति से प्रभावित किया जा सकता हो तो वैश्विक विकास को भी तदनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि शोध व विकास कार्यों में आपेक्षिक लाभ प्राप्त कोई देश अनुसन्धान को आर्थिक सहायता देना चाहता हो तो वैश्विक विकास में वृद्धि होगी।

इसी प्रकार, नयी खोज करने के बजाय विनिर्माण में अपेक्षाकृत अधिक दक्ष किसी अर्थव्यवस्था द्वारा प्रस्तावित इसी तरह की आर्थिक मदद वैश्विक विकास को पतन की ओर भी ले जा सकती है। विनिर्माण क्षेत्र को संरक्षण प्रदान करने वाली व्यापार नीतियाँ भी कुशल श्रमिकों को अनुसन्धान कार्य छोड़ विनिर्माण क्षेत्र में जाने को उकसा सकती हैं जिससे नवाचार पिछड़ जाएगा। अन्य बातें पूर्ववत रहने पर व्यापार नीति एक ओर नीति-सक्रिय देशों में अनुसंधान से विनिर्माण में संसाधनों के हस्तान्तरण को प्रभावित करेगी तो दूसरी ओर नीति-निष्क्रिय देशों में संसाधनों के हस्तान्तरण की दिशा बदल जाएगी।

अन्तर्जात विकास सिद्धान्त के नीतिगत निहितार्थ अन्तर्राष्ट्रीय उत्पाद चक्र से भी उद्भूत होते हैं। परम्परागत रूप से, किसी भी उन्नत अर्थव्यवस्था में आविष्कार और नये उत्पाद वहाँ दिखाई पड़ते हैं जहाँ शोध व विकास कार्य सुविकसित होता है। तदन्तर, नकल करके अथवा प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण द्वारा इन उत्पादों को अल्पविकसित देशों में उतारा जाता है और फिर अन्त में इन वस्तुओं का उत्पादन कम मजदूरी वाले देशों में पहुँच जाता है। तदनुसार, विनिर्मित उत्पादों में व्यापार केवल किसी उन्नत अर्थव्यवस्था में उत्पादित नवीनतम अभिनव वस्तुओं और प्रमुखत: किसी अल्प उन्नत अर्थव्यवस्था द्वारा वर्तमान में उत्पादित कहीं अधिक परम्परागत वस्तुओं के बीच विनिमय के आधार पर होता है। उत्पाद चक्र किसी ऐसी उन्नत अर्थव्यवस्था वाले अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सदा-उद्विकासी प्रतिमान के लिए उत्तरदायी होता है जो अपनी उन्हीं वस्तुओं का आयात कर रहा हो जिनका वह आरम्भ में निर्यात करता था। उत्पाद चक्र मॉडल के सन्दर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सदैव उन्नत और अल्प विकसित दोनों अर्थव्यवस्थाओं

TOUCH 'n' PASS

में एक तीव्रतर आर्थिक विकास के सहयोगी के रूप में उभरता है। पूर्ववर्ती में, उन्नत से अल्प उन्नत अर्थव्यवस्था को उत्पादन का स्थानान्तरण संवृद्धि-प्रवर्धक उत्पाद-विकास कार्य में प्रयोगार्थ संसाधनों को खोल देता है। साथ ही, अल्प उन्नत अर्थव्यवस्था में संवृद्धि तेजी से होने लगती है क्योंकि उन्नत अर्थव्यवस्था से आयातित तकनीकें सीखने और अपनाने के लिए आवश्यक संसाधन स्वायत्त नवोत्पाद विकास हेतु आवश्यक संसाधनों के मुकाबले बहुत कम होते हैं दोनों ही स्थितियों में विद्या-प्राप्त गतिविधियों (उन्नत अर्थव्यवस्था में नवाचार, अल्प उन्नत अर्थव्यवस्था में नकल) को आर्थिक सहायता से दीर्घावधि विकास दरें बढ़ाने की आशा की जा सकती है।

अन्तत यह स्पष्ट ही लगता है कि व्यापार नीति में विश्व अर्थव्यवस्था हेतु दीर्घावधि विकास पथ प्रभावित करने की क्षमता होती है। तथापि, इसमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना होता है। ज्ञान के क्षेत्रों को प्रभावित करती संवृद्धि की पहचान अपने आप में एक बड़ी समस्या है, पहले नहीं तो बाद में। दूसरे, यह तथ्य कि मॉडल विश्लेषण से अवकलित निष्कर्ष विश्लेषण में निहित शर्तों अथवा अवकल्पनाओं में फेरबदल कर आसानी से पलटे जा सकते हैं—जोकि अधिकांशत आनुभाविक रूप से हल किए जाना असम्भव है—विकास निर्धारण में आपका विश्वास डिगाता है। इसके अलावा, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और विश्व अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में स्वयं नीति मापदण्डों के परिणाम और प्रभाव दूसरों की नीतिगत कार्यवाहियों के साथ परस्पर निर्भरता दर्शाते हैं। यह तथ्य राष्ट्रीय नीति के समन्वयन अथवा कम से कम द्वितीय-सर्वोत्तम परिणामों पर विचार किए जाने की आवश्यकता को इंगित कर सकता है।

कुल मिलकर, अन्तर्जात विकास सिद्धान्त का एक निहितार्थ यह है कि खुलापन, प्रतिस्पर्धा, परिवर्तन और नवाचार अपनाने वाली नीतियाँ संवृद्धि को बढ़ावा देती है। इसके विपरीत, किसी विशिष्ट विद्यमान उद्योग अथवा फर्म को संरक्षण देकर अथवा उसका पक्ष लेकर परिवर्तन को बाधित अथवा मन्द करने वाली नीतियाँ कालान्तर में विकास धीमा कर देती हैं जिससे समाज को हानि ही पहुँचती है।

प्र.5. विदेशी पूँजी का भारत जैसे अल्पविकसित देशों के विकास में योगदान लिखिए।
Write the Contribution of foreign capital in the development of less developed countries like India.

उत्तर

विदेशी पूँजी का भारत जैसे अल्पविकसित देशों के विकास में योगदान
(Contribution of Foreign Capital in the Development of Less Developed Countries Like India)

विदेशी पूँजी के प्रकार (Types of Foreign Capital)

(A) व्यक्तिगत विदेशी विनियोग
- (i) प्रत्यक्ष व्यक्तिगत विनियोग
- (ii) पोर्टफोलियों विनियोग
- (iii) साधारण अंशों में विनियोग

(B) सार्वजनिक विदेशी विनियोग
- (i) ऋण व अनुदान
- (ii) तकनीकी सहायता
- (iii) खाद्यान्न आधिक्य का निर्यात

(C) अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों का ऋण

विदेशी पूँजी का भारत के विकास में निम्न प्रकार से योगदान है—

1. **विदेशी राष्ट्रों से वास्तविक साधनों की प्राप्ति** (Procurement of real resources from foreign countries)—विकास के कार्यों में जहाँ घरेलू एवं बाहर साधन अपर्याप्त होते हैं उन्हें विदेशी सहायता से पूर्ण किया जा सकता है। कर, ऋण या मुद्रा प्रसार से बचत तो प्राप्त होती है परन्तु इससे वास्तविक साधनों के उपयोग से वंचित रहना पड़ता है। अत: राष्ट्र अतिरिक्त विनिमय द्वारा वित्तीय साधन जुटाकर वस्तुओं को प्राप्त करके उपभोग कर सकता है।
2. **बाह्य मितव्ययिताओं का सृजन** (Creation of external economies)—आमतौर पर तो बाह्य मितव्ययिताओं के होने पर ही विदेशी पूँजी का आगमन होता है, परन्तु कभी-कभी स्वयं विदेशी पूँजी भी देश की बाह्य मितव्ययिताओं के सृजन करने में सहायता प्रदान करती है तथा विदेशी विनियोगों को आकर्षित करती है।

3. **विनियोग कमी को पूर्ण करने हेतु** (To meet investment requirement)—जिन देशों में आय का सृजन निम्न होता है, वहाँ घरेलू बचत भी कम होती है। ऐसे में करो एवं आन्तरिक ऋणों से जो राशि प्राप्त होती है वह विनियोग की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए अपर्याप्त होती है। ऐसी स्थिति में बाह्य साधनों से सहायता लेना श्रेयस्कर होता है।
4. **लाभ अर्जित करना** (To earn profits)—विदेशी विनियोजक अपने साथ कुशल विशेषज्ञ लाते हैं जिससे अविकसित एवं अर्द्धविकसित देशों को लाभ प्राप्त होते हैं। इन कुशल विशेषज्ञों से प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान होती हैं कालान्तर में यही विकसित देश अपने देश में विकास की योजनाएँ बनाकर आर्थिक विकास करते हैं।
5. **आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना** (Accelerating the pace of economic progress)—अर्द्धविकसित देश जो बिना बाह्य व्यापारी के पर्याप्त मात्रा में विदेशी विनिमय अर्जित नहीं कर सकता, विदेशी पूँजी के माध्यम से विदेशी विनिमय उपलब्ध कराके नवीन योजनाओं के प्रारम्भ को प्रोत्साहित करती है।
6. **स्वस्थ परम्परा का निर्माण** (Formation of healthy tradition)—विदेशी पूँजी के विनियोजन से देश में स्वस्थ परम्परा का निर्माण होता है। उसके आगमन से उद्योग प्रोत्साहित होते है और लाभ प्राप्त करते हैं जिससे विदेशी विनियोजन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है।
7. **सरकारी आय में वृद्धि** (Increase in public revenue)—विदेशी विनियोजन से प्राप्त होने वाले लाभ पर सरकार अन्य कर प्राप्त करती हैं जिससे सरकार की आय में वृद्धि होती है इससे सरकारी आय में वृद्धि होती है जिसे देश के आर्थिक विकास में लगाया जा सकता है।
8. **घरेलू अर्थव्यवस्था पर भार में कमी** (Reduction in the strain of the domestic economy)—जब विदेशी पूँजी का प्रवेश नहीं हुआ होता है तो राष्ट्र की आय कम होने से विकास की प्रारम्भिक अवस्था में विनियोग के साधन को जुटाने के लिए आन्तरिक उपयोग करना पड़ता है जिसका जनता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। परन्तु विदेशी पूँजी की सहायता से उपभोग को उच्चतम स्तर पर रखा जा सकता है। उपभोग ऊँचा होने से उत्पादन में वृद्धि होती है।
9. **विदेशी उपभोगी वस्तुएँ उपलब्ध होना** (Availability of essential foreign goods)—विदेशी विनियोजन से जनता को विदेशी उपभोग वस्तुएँ सस्ते मूल्य पर सुविधापूर्वक उपलब्ध हो जाती है।
10. **जीवन स्तर में वृद्धि करने हेतु** (Increase in the standard of living)—विकसित एवं अर्द्धविकसित देशों के मनुष्यों के जीवन स्तर में काफी अन्तर होता है जो विश्वशान्ति के लिए एक खतरा है। अत: अर्द्धविकसित देशों का तीव्र विकास होना आवश्यक है। बचत की दर कम न कर विदेशी पूँजी की सहायता से जीवन स्तर में वृद्धि की जा सकती है।
11. **भुगतान सन्तुलन की कमी को दूर करने हेतु** (To remove the disequilibrium in the balance of payment)—अर्द्धविकसित देशों में तीव्र विकास से भुगतान सन्तुलन की कमी को उत्पन्न करता है। आर्थिक विकास व प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालने के अतिरिक्त निम्नांकित ढंगों से प्रत्यक्ष प्रभाव भी डालता है—
    - विकास कार्यक्रमों को पूर्ण करने के लिए भारी मात्रा में सामग्री की आयात किया जाता है
    - बहुत से कच्चे पदार्थ, जो पहले निर्यात किये जाते थे, अब उनका उपयोग देश में होने लगा है जिससे निर्यात में कमी व भुगतान सन्तुलित हो जाते हैं।
12. **स्फीति रहित विकास** (Development without inflation)—विदेशी पूँजी सहायता से देश का मुद्रा स्फीति रहित विकास किया जा सकता है। विदेशी विनियोजन से विनियोग की कमी को पूर्ण किया जा सकता है तथा स्फीतिक परिस्थितियों से बचा जा सकता है।
13. **प्राविधिक ज्ञान, प्रबन्धकीय योग्यता आदि की कमी को पूर्ण करना** (To fulfil the deficiency of technical and managerial abiliy)—विदेशी पूँजी आमत्रंण करने से प्राविधिक ज्ञान आदि की उपलब्धता भी हो जाती है। तकनीकि ज्ञान प्राप्त होने से औद्योगिक उन्नतिसम्भव हो जाती है।
14. **जोखिम उठाना** (Risk taking)—विदेशी पूँजीपति जोखिम उठाकर नई उद्योग की स्थापना करते हैं। असफल होने पर यहीूँजी हानि सहन करने का साहस करता है। सफल होने पर घरेलु पूँजीपति भी उसी व्यवसाय को आरमी करके लाभ उठाते हैं।
15. **अन्य लाभ** (Other merits)—अन्य लाभ; जैसे—रोजगार प्राप्त होना, उपभोग व बचत में वृद्धि होना, उत्पादन एवं लाभ को बढ़ाना आदि भी विदेशी पूँजी के आने से मिलता है।

TOUCH 'n' PASS

प्र.6. विदेशी पूँजी से होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए।
Describe the disadvantages of foreign capital.

उत्तर

विदेश पूँजी से होने वाली हानियाँ
(Disadvantages of Foreign Capital)

विदेशी पूँजी से होने वाली हानियाँ निम्न हैं—

1. **सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की विदेशी विनियोजकों पर निर्भरता** (Dependency of the entire economy on the foreign investors)—देशवासी अपने निर्वाह के लिए विदेशियों की पूँजी पर निर्भर हो जाती हैं पूँजी उधार देने वाले राष्ट्र के व्यापार चक्र का प्रभाव ऋण लेने वाले राष्ट्र पर भी पड़ता है।
2. **घरेलू नियोक्ताओं को बाहर करने का भय** (Danger of expelling the internal investors)—अनियन्त्रित स्वतन्त्र देने पर डर बना रहता है कि विदेशी विनियोक्ता घरेलू विनियोक्ताओं को क्षेत्र से बाहर न कर दे क्योंकि घरेलू ऐतिहासिक कारणों से अधिक होती हैं, परन्तु यदि समान सुविधाएँ दी जाती है। "विनियोक्ता विदेशी पूँजीपति से कम कुशल होते हैं। विदेशी विनियोक्ता की कार्यकुशलता तो घरेलू विनियोक्ता भी विदेशी विनियोक्ताओं के समकक्ष हो सकते हैं।
3. **विदेशी पूँजी राष्ट्र का शोषण करना** (Exploitation of the country through foreign capital)—भूतकाल में विदेशी पूँजी ने देश का शोषण किया और प्राप्त लाभों को विनियोग करने वाले देशों को दे दिया गया। प्राय: यह देखा गया है कि विदेशी पूँजी का विनियोग अर्द्धविकसित देशों में ऐसे उद्योगों में प्रयोग किया जाता जिससे कच्चे माल का उत्पादन अधिक बढ़ सके जिसे विदेशी देशों के उद्योगों के लिए निर्यात किया जा सके। विदेशी पूँजी द्वारा राष्ट्र का शोषण किया गया जिसमें उनके महज स्वार्थ की भावना ही दिखाई दी। अविकसित देशों का विकास पिछड़ा ही रह गया। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में प्राय: दोहरी आर्थिक संरचना की कठिनाइयाँ उपस्थित करती है, एक ओर निर्यात के लिए उत्पादन किये जाने वाले बाजार में उत्पादन के लिए निम्न उत्पादकता वाला क्षेत्र है।
4. **विदेशी विनियोग का खातों आदि में विकेन्द्रीकरण** (Concentration of foreign investment in mines, etc)—विदेशी पूँजी प्राय: खानों जैसे व्यवसायों में ही केन्द्रित रही क्योंकि इसके उत्पादन निर्यात किये जाते हैं जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है और इनमें प्राप्त लाभ विदेशी पूँजी का विनियोग ऐसे उद्योग में किया जाये जिसका माल घरेलू बाजार में बिकता हो तो आयात पर निर्भरता कम हो जायेगी और विदेशी विनिमय की बचत होगी। विदेशी पूँजी को निर्यात उद्योगों में केन्द्रित करने से एक तरफा विकास सम्भव हो सकेगा।
5. **विदेशी पूँजी का निर्यात उद्योगों में विनियोग** (Investment of foreign capital in export industries)—विदेशी शासक का यह स्वार्थ होता है कि वे निर्यात उद्योगों में ही विदेशी पूँजी लगाये क्योंकि परिवहन साधनों का विकास बन्दरगाह और मुख्य व्यापारिक केन्द्रों पर उनका ध्यान आकृष्ट रहता है न कि देश के आन्तरिक भाग में परिवहन के साधनों पर। रेल का विकास, भारत में इस बात की पुष्टि करता है कि अंग्रेजों को कच्चा माल ले जाने तथा निर्मित माल का आयात करना अति सुविधाजनक हो गया। इससे ब्रिटिश उद्योगों के विकास को पर्याप्त प्रोत्साहन मिलता रहा हैं।
6. **विदेशी पूँजी का बुरा अनुभव** (Bad experience of foreign capital)—भूतकाल में विदेशी पूँजी का खराब अनुभव रहा है जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। यह राष्ट्रीय सरकार विदेशी पूँजी को विनियोजित एवं नियन्त्रित ढँग से आमन्त्रित करे तो बुरे प्रभावों से बचा जा सकता है, परन्तु इसके साथ ही इस बात पर भी ध्यान देना है कि देश में ऐसे नियम न बना दिया जाये जिससे विदेशी पूँजी के आगमन पर एकदम रोक लग जाये और देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़े।
7. **देश की राजनीति में हस्तक्षेप** (Interference in the politics of country)—यदि विदेशी पूँजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो इससे देश की राजनीति पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा। राजनीति दलों को चन्दा देकर भी राष्ट्रों को गुट में मिलाने का प्रयास किया जाता है।
8. **घरेलू विनियोजको के क्षेत्र में ह्रास** (Decline in the domestic investors)—विदेशी पूँजी को देश के सर्वाधिक लाभदायक कार्यों में विनियोग किया जाता है। जिससे घरेलू विनियोजकों को पूँजी के विनियोग करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। इससे देश में उद्योगों के विकास को पूर्ण अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं और देश पिछड़ जाता है।

TOUCH 'n' PASS

9. **भेदभावपूर्ण व्यवहार** (Discriminatory treatment)—विदेशी पूँजीगति देश के श्रमिकों एवं योग्य व्यक्तियों को अपने राष्ट्र के लाभार्थ उपयोग करते हैं। इससे देश के उद्योगों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता और वे पिछड़ जाते हैं।
10. **घरेलू मांग सम्बन्धी माल का उत्पादन न करना** (Non-production of goods for domestic demand)—विदेशी पूँजी का उपयोग प्राय: घरेलू माँग सम्बन्धी माल की पूर्ति हेतु नहीं किया जाता है, जबकि इन उद्योगों को लघु पैमाने व छोटी मात्रा की पूँजी से ही प्रारम्भ किया जा सकता। विदेशी पूँजीपति इन उद्योगों में पूँजी लगाने की नहीं सोचता। यह राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए हानिकारक हो सकती है। इसका मुख्य कारण स्थानीय बाजार का अभाव था।
11. **लाभ की ऊँची दर** (High Rate of Profit)—विदेशी पूँजी जिन उद्योगों में विनियोजित की जाती है उनकी लाभ की दर काफी ऊँची होती है। जबकि अन्य उद्योगों में लाभ की दर इतनी अधिक नहीं होती। लाभ की ऊँची दर रखने से वस्तुओं के उत्पादन की लागत बढ़ जाती है और इसके परिणामस्वरूप वस्तुओं के मुल्य बढ़ जाते हैं और देशवासियों को हानि उठानी पड़ती है।

इस प्रकार "विदेशी व्यापारिक उपक्रम देश के विकास में किस सीमा तक सहायता करता है, यह इस बात पर निर्भर नहीं होता कि यह कार्य निर्यात के लिए है या घरेलू उपयोग के लिए। यह इस बात पर अधिक निर्भर करता है कि यह श्रमिक व अन्य स्थानीय साधनों की कितनी माँग बढ़ाता है, अपने लाभों को कितना पुनींविनियोग करता तथा अन्य घटकों का इस प्रभाव पड़ता है।"

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. किसी भी देश का आर्थिक विकास किन तत्त्वों पर आधारित हैं?
(क) शिक्षित व प्रशिक्षित श्रम शक्ति (ख) कार्यकुशलता
(ग) दोनों (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (ग) दोनों

प्र.2. "बहुत बड़ी जनसंख्या को निरक्षर छोड़कर राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम शुरू करने की बात मुझे निरर्थक मालूम पड़ती हैं" किसने कहा?
(क) प्रो० सिंगर (ख) वैबलन (ग) प्रो० मिर्डल (घ) अजित दास गुप्त

उत्तर

प्र.3. बौद्धिक पूँजी क्या है?
(क) ज्ञान (ख) कुशलता (ग) क्षमताओं में वृद्धि (घ) ये सभी

उत्तर (घ) ये सभी

प्र.4. प्रो० साइमन कुजनेट्स ने तकनीकी विकास के लिए सोपानों का निर्धारण किया है जो है–
(क) वैज्ञानिक खोज (ख) आविष्कार (ग) नव-प्रवर्तन (घ) ये सभी

उत्तर (घ) ये सभी

प्र.5. मानव पूँजी निर्माण के उपाय
(क) अनिवार्य शिक्षा (ख) तकनीकी शिक्षा पर अधिक बल
(ग) शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन (घ) ये सभी

उत्तर (घ) ये सभी

प्र.6. मानव संसाधन के विकास में आन्तरिक स्रोत (Internal Source) है/हैं—
(क) विदेशी तकनीशियनों को स्थायी अथवा अस्थायी रूप से देश में नियुक्त करना।
(ख) विशिष्ट तकनीकी संस्थानों की स्थापना करना तथा उन्हें शिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
(ग) देश के श्रमिकों को प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजना।
(घ) उपरोक्त सभी

उत्तर (ख) विशिष्ट तकनीकी संस्थानों की स्थापना करना तथा उन्हें शिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

TOUCH 'n PASS

प्र.7. कौशल निर्माण है—
(क) अल्पकालीन (ख) दीर्घकालीन (ग) निरन्तर (घ) ये सभी
उत्तर (ख) दीर्घकालीन

प्र.8. कौशल निर्माण के प्रमुख तीन तत्त्व हैं—
(क) शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुभव (ख) श्रम, पूँजी व निवेश
(ग) ज्ञान, साधन एवं उपयोग (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (क) शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुभव

प्र.9. अपने श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के लिए विदेश भेजना किस प्रकार का उदाहरण हैं?
(क) आन्तरिक (ख) बाह्य (ग) राजकीय (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (ख) बाह्य

प्र.10. अन्तर्जात संवृद्धि सिद्धान्त को ओर किस नाम से जाना जाता है?
(क) विकास का गतिशील सिद्धान्त (ख) विकास का सतत् सिद्धान्त
(ग) विकास का नवीन सिद्धान्त (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (ग) विकास का नवीन सिद्धान्त

प्र.11. अन्तर्जात संवृद्धि सिद्धान्त की सहायता से विभिन्न देशों के बीच राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर के ..... अन्तरों का आकलन किया जा सकता है।
(क) घटते (ख) बढ़ते (ग) स्थिर (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (ख) बढ़ते

प्र.12. आर्थिक विकास की दृष्टि से ''भौतिक पूँजी'' की अपेक्षा 'मानवीय पूँजी' को ..... महत्त्वपूर्ण समझा जाता है?
(क) कम (ख) अधिक (ग) बराबर (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (ख) अधिक

प्र.13. ''प्राविधिक प्रगति का अर्थ किसी व्यवसाय में प्रयुक्त ज्ञान और वास्तविक उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन है। इसके द्वारा उसी मात्रा में साधनों के प्रयोग से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है अथवा उसी मात्रा में उत्पादन प्राप्त करने के लिए साधनों की कम मात्रा की आवश्यकता होती है।'' यह परिभाषा किसने दी?
(क) प्रो० शुम्पीटर (ख) प्रो० किण्डल बर्जर
(ग) प्रो० साइमन कुजनेट्स (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर

प्र.14. बौद्धिक सम्पदा में किसे सम्मिलित किया जाता है?
(क) इन्जीनियर (ख) वैज्ञानिक चिकित्सक (ग) प्रबन्धकीय (घ) ये सभी
उत्तर

प्र.15. भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया है?
(क) 2000 (ख) 2015 (ग) 2008 (घ) 2002
उत्तर (क) 2000

❑

TOUCH 'n' PASS

UNIT-VIII

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार
International Trade

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है?
What is teh purpose of international trade?

उत्तर अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय उन आवश्यक और दुर्लभ वस्तुओं और सेवाओं के आयात और उपलब्धता की सुविधा प्रदान करता है जिनका उत्पादन घरेलू अर्थव्यवस्था में नहीं किया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक महत्त्वपूर्ण साधन है। विकासशील देशों के लिए विकासशील व्यवसाय करने का अवसर है।

प्र.2. भारत का अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय क्या है?
What is the india's international business?

उत्तर वर्ष 1950-51 में भारत का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 1,214 करोड़ रुपए की थी जो वर्ष 2016-17 में यह बढ़कर 44.30 लाख करोड़ रुपए हो गया। 1970 के दशक से पहले, भारत में बहुत सारे कृषि उत्पादों का आयात किया जाता था। 1970 के दशक के बाद, हरित क्रान्ति की सफलता के बाद, कृषि और सम्बद्ध वस्तुओं के आयात में गिरावट आई है।

प्र.3. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषताएँ क्या हैं?
What are the characteristics of international trad?

उत्तर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की एक ओर उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का उपयोग शामिल है। इसलिए विनिमय दरों और विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में प्रत्येक देश की अपनी नीति है। संक्षिप्तता के लिए, चार्ट 1 में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषताओं का उल्लेख किया गया।

प्र.4. एफडीआई क्या है? एफडीआई के फायदे और नुकसान बताएँ।
What is FDI? Explain the advantages and disadvantages of FDI.

उत्तर एफडीआई देश के वित्त और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को बढ़ाता है। यह उस देश को प्रदान करता है जिसमें निवेश कई उपकरणों के साथ होता है, जिसका लाभ वे उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब FDI होता है, प्राप्तकर्ता व्यवसायों को वित्त, प्रौद्योगिकी और परिचालन कार्यप्रणाली में नवीनतम उपकरणों तक पहुँच प्रदान की जाती है।

प्र.5. एफडीआई की जरूरत क्यों है?
Why is FDI needed?

उत्तर एफडीआई नए रोजगार और अधिक अवसर पैदा करता है; क्योंकि निवेशक विदेशों में नई कम्पनियों का निर्माण करते हैं। इससे स्थानीय लोगों की आय और अधिक क्रय शक्ति में वृद्धि हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप लक्षित अर्थव्यवस्थाओं में समग्र वृद्धि होती है।

प्र.6. क्या एफआईआई एफडीआई में निवेश कर सकता है?
Can FII invest in FDI?

उत्तर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए निवेश का एक हिस्सा है। हालाँकि प्रत्येक एफआईआई उस देश में एफडीआई नहीं करेगा जिसमें वह निवेश कर रहा है। एफआईआई सीधे देश के स्टॉक/प्रतिभूति बाजार, इसकी विनिमय दर और मुद्रास्फीति को प्रभावित करते हैं।

TOUCH 'n' PASS

प्र.7. विदेशी निवेश संस्थान क्या है?

What is foreign investment institute?

उत्तर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) किसी देश के एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश है। FDI किसी निवेशक को एक बाहरी देश में प्रत्यक्ष व्यावसायिक खरीद की सुविधा प्रदान करता है।

प्र.8. संस्थागत निवेश से आप क्या समझते हैं?

What do you understand by institutional investment?

उत्तर संगठनों या संस्थानों; जैसे—बैंकों, बीमा कम्पनियों, म्युचुअल फण्ड हाउस आदि द्वारा किसी देश की वास्तविक या वित्तीय सम्पत्तियों में किए जाने वाले निवेश को संस्थागत निवेशकों के रूप में जाना जाता है।

प्र.9. भारत में विदेशी निवेश कितना है?

How much is foreign investment in India?

उत्तर भारत में वित्त वर्ष 2021-22 में 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) हासिल किया जो अब तक किसी भी वित्त वर्ष में सबसे अधिक है। वर्ष 2014-15 में भारत में केवल 45.15 अरब अमेरिकी डॉलर का एफडीआई आया था; जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर का एफडीआई अब तक का सर्वाधिक सालाना एफडीआई है।

प्र.10. विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में क्या अन्तर है?

What is the difference between foreign trade and foreign investment?

उत्तर विदेशी व्यापार का तात्पर्य दुनिया के दो देशों के बीच माल, सेवाओं और पूँजी के व्यापार से है। विदेशी निवेश से तात्पर्य देश के बाहर स्रोत से किसी कम्पनी में किए गए निवेश से है।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. व्यापार और आर्थिक विकास पर टिप्पणी कीजिए।

Write a note on Trade and Economic Development.

उत्तर

व्यापार और आर्थिक विकास
(Trade and Economic Development)

उन्नीसवीं शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से कुछ क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि हुई। यह क्षेत्र, आमतौर पर संयुक्त राज्य, यूरोप से काफी मात्रा में श्रम व पूँजी का आगमन हुआ, लेकिन आधारभूत विकास तो पश्चिमी यूरोप की खाने की वस्तुओं व कच्चे माल की माँग जिसे ये उत्पादित करने में सक्षम थे, उनसे वृद्धि हुई। यद्यपि **प्रो० नर्कसे** का कहना है नए देशों के लिए व्यापार वृद्धि का इन्जन है, लेकिन अल्पविकसित देशों के लिए यह कहानी बिल्कुल विपरीत है। अल्पविकसित देशों में प्राथमिक उत्पादन निर्यात की अदायगी करने के लिए किया गया लेकिन घरेलू अर्थव्यवस्था कम विकसित हुई। इसलिए विदेशी व्यापार दोहरी अर्थव्यवस्था के रूप में साबित हुआ। यद्यपि थोड़े से क्षेत्र में वृद्धि हुई। यह क्षेत्र शक्तिशाली लोगों और उनके राजनीतिक नियन्त्रण के नीचे थे और इन अर्थव्यवस्थाओं ने दूसरे देशों की कीमत पर अपने को विकसित करने में रूचि रखी। इन शक्तिशाली देशों ने औद्योगिकरण को बढ़ाने के लिए अल्पविकसित देशों से कच्चे माल का आयात करने में रूचि रखी जिसकी कम कीमत अदा करनी पड़ती थी। आधुनिक तकनीक के राज्य कुछ पूँजीवादी संस्थान बनाए जो सारा धन (निर्यात से प्राप्त धन) विदेशों में विदेशी पूँजी के लाभ के रूप में हस्तान्तरित करते थे। इसलिए विदेशी व्यापारी ने मेट्रोपॉलिटन देशों में आर्थिक वृद्धि की न कि घरेलू अर्थव्यवस्था में।

प्रो० सिगर ने कहा है, व्यापार के औपनिवेशिक शासन में औद्योगिक देश दोनों तरफ विशिष्ट हैं—दोनों प्राथमिक वस्तुओं के उपभोक्ता तथा उत्पादित वस्तुओं के उत्पादक; जबकि अल्पविकसित देश दोनों तरफ बुरे (Worst) हैं। मशीन से बने उत्पादन की कीमत अधिक है। ये मेट्रोपॉलिटन देश अपने निर्यात की कीमत अल्पविकसित देशों के निर्यात की कीमत से कई गुना ज्यादा लेते हैं जो निम्न प्रकार हैं 1. मशीनीकरण का निर्यात बढ़ाने की सम्भावना तथा अपनी जनसंख्या को निम्न उत्पादकता वाले व्यवसाय से अधिक उत्पादकता वाले व्यवसाय में हस्तान्तरण 2. अपनी अर्थव्यवस्था के विस्तृत मशीनीकरण उद्योग का आनन्द 3. प्राथमिक

TOUCH 'n' PASS

वस्तुओं का उपभोक्ता होने से प्राथमिक उद्योग। इसलिए केवल विकसित देश ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अधिक फायदा उठा सकते हैं।

प्र.2. व्यापार और कम विकसित देश पर संक्षिप्त लेख लिखिए।
Write a brief note on Trade and Less Developed Countries.

उत्तर

व्यापार और कम विकसित देश
(Trade and Less Developed Countries)

पिछले चार दशकों से व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई है। यद्यपि वर्ष 1965 से 1995 के बीच विकसित देशों के निर्यात में 7 प्रतिशत की वृद्धि प्रति वृर्षि वर्ष हुई है। लेकिन अल्पविकसित देशों में निर्यात में वृद्धि कम दर से 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष हुई। कीमत के स्तर पर अथवा निर्यात की कीमत रखी जाए तो अल्पविकसित देशों का विश्व व्यापार में हिस्सा वर्ष 1965 में 30 प्रतिशत था जो गिरकर वर्ष 1995 में 20 प्रतिशत गया। अधिकतर कम आय वाले अल्पविकसित देश अपनी निर्यात का 75 प्रतिशत हिस्सा प्राथमिक वस्तुओं से कमाते हैं। दूसरी तरफ विकसित देश का निर्यात का 90 प्रतिशत हिस्सा निर्मित वस्तुओं से कमाते हैं। अल्पविकसित देशों की अधिकतर संख्या प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात पर करती है। इसलिए इनके निर्यात में तेजी नहीं आई है; क्योंकि यह आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रों पर निर्भर हैं।

बाहरी क्षेत्र में विद्यमान तत्त्वों के बाद और भी कई कारण हैं जिससे आर्थिक उन्नति होने पर निर्यात योग्य वस्तुओं के उपभोग में वृद्धि अथवा कच्चा माल इत्यादि को अपने उद्योगों में करना। वर्ष 1952 में भारत ने तेल का निर्यात प्रतिबन्धित किया था; क्योंकि तेल की घरेलू क्षेत्र के लिए माँग पूरी नहीं हो पाई। स्फीतिकारी प्रभावों को रोकने के लिए सरकार इस तरह के कदम उठाती हैं।

निर्मित वस्तुओं का निर्यात
(Manufactured Export)

अल्पविकसित देशों में निर्यात में वृद्धि वो भी निर्मित वस्तुओं में कम होती है। **पेबरिस** ने कहा है यह भुगतान सन्तुलन की वजह से है। पहले भी बता चुके हैं यह माँग की आय लोच के कम होने की वजह से है। प्राथमिक वस्तुओं की माँग की लोच कम हैं इस वजह से भुगतान सन्तुलन की समस्या उत्पन्न होती है। निर्मित क्षेत्र में निर्यात कम होने का कारण उत्पादन समस्या तथा गलत घरेलू नीति है। अल्पविकसित देशों में उत्पादन के साथ टैरिफ समस्या भी उत्पन्न हो जाती हैं। इस टैरिफ की वजह से निर्यात प्रभावित होते हैं।

अल्पविकसित देशों में निर्मित उद्योगों में उत्पादन की समस्या बाजार में सिर्फ लागत का ही अन्तर नहीं बल्कि कीमत करने पर हो सकता है बिक्री न हो। यद्यपि बहुत-सा अल्पविकसित देशों के गरीब प्रतियोगी है। अल्पविकसित देशों के उपभोक्ता भी विदेशों में बनी वस्तुओं कर उपयोग करने को लालयित रहते हैं। इसलिए सरकार इसको नियन्त्रित करने के लिए आयात कर लगाती है।

इन सब बातों के साथ हम कह सकते हैं कि विदेशी व्यापार का यदि वास्तविकता की दृष्टि से आकलन किया जाए तो यह सही रूप से लाभदायक नहीं है; क्योंकि अल्पविकसित तथा विकसित देशों में निर्यात वस्तुओं की प्रवृत्ति में काफी अन्तर है। लेकिन फिर भी यदि औद्योगिकरण को बढ़ावा देना है तो हमे तकनीकी लाभ भी प्राप्त होते हैं, जो आयात से सम्भव है।

प्र.3. भारत में ऊर्जा संकट के कारण एवं उनके समाधान हेतु सुझाव बताइए।

उत्तर

भारत में ऊर्जा संकट के कारण
(Causes of Energy Crisis in India)

ऊर्जा संकट का अर्थ है ऊर्जा के साधनों का अभाव। देश के आर्थिक विकास में ऊर्जा एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यह संकट मात्र भारत तक ही सीमित नहीं हैं वरन् विश्वव्यापी है। हालाँकि भारत में वर्ष 1950-51 से लेकर वर्तमान तक की अवधि में विद्युत कोयला एवं कच्चे तेल के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। फिर भी यह संकट विद्यमान है। बढ़ती हुई ऊर्जा की माँग हर क्षेत्र में बनी हुई है, चाहे वह क्षेत्र औद्योगिक हो या कृषि। संक्षेप में ऊर्जा संकट के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं—

1. तीव्र गति से होता हुआ औद्योगिक विकास।
2. गाँवों के विद्युतीकरण एवं कृषि का बढ़ता हुआ यन्त्रीकरण।

TOUCH 'n PASS

3. कोयले का समय पर भारी मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण रेलों आदि में तेल का उपयोग बढ़ गया है। देश में इसका उत्पादन 335 लाख टन वार्षिक हैं; जबकि उसकी खपत 1000 लाख टन वार्षिक पहुँच गई हैं। यह आयात द्वारा पूरा किया जाता है।
4. कोयले का बढ़ता हुआ अभाव जिससे ताप विद्युत गृहों को समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है।
5. जल विद्युत उत्पादन में कमी के कारण जल विद्युत योजनाओं को कार्यरूप में परिणत होने में देर हो जाती है और उनके निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाते हैं।

भारत में ऊर्जा संकट के समाधान
(Solutions to energy crisis in India)

भारत में ऊर्जा संकट के समाधान निम्नलिखित हैं—

1. पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन बढ़ाना एवं आन्तरिक उपभोग को कम करना।
2. गैस का उत्पादन बढ़ाना एवं नवीन स्थानों की खोज करना जहाँ इसकी मिलने की सम्भावना हो।
3. विद्युत उत्पादन के चार साधन—कोयला, तेल, पानी व परमाणु शक्ति। परमाणु शक्ति का विकास होने में समय लग सकता है। कोयले एवं तेल की भारी मात्रा में माँग के कारण इसकी उपलब्धता कम होती जा रही है। ऐसे में मात्र जल विद्युत का उपयोग ही सम्भव है जो वर्षा के पानी को रोककर नदियों का पानी प्रयोग कर बनायी जा सकती है।
4. विद्युत गृहों की पूर्ण क्षमता के उपयेाग को बढ़ाने की आवश्यकता है।
5. विद्युत की बरबादी एवं चोरी में कमी से 1/3 उत्पादन का भी समुचित प्रयोग किया जा सकता है।

प्र.4. बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विदेशी निवेश के वैकल्पिक तरीके लिखिए।
Write alternative methods of Foreign investment by multinational companies.

उत्तर

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विदेशी निवेश
(Foreign Investment by Multinational Companies)

अपनी लाभप्रदता बढ़ाने के लिए कई विशाल फर्मों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर एकीकरण के लिए देश के बाहर जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए वे अपने देश के बाहर अपने उत्पादन या वितरण इकाइयों को स्थापित करना लाभदायक पाते हैं। विदेशी निवेश के तीन मुख्य तरीके हैं—

1. **MNCs उत्पादों की बिक्री के लिए स्थानीय फर्मों के साथ समझौता**—एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी अपने देश में बिक्री के लिए अपने देश में उत्पादित के निर्यात के लिए स्थानीय कम्पनियों के साथ एक समझौता कर सकती है। इस मामले में, एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी विदेशी कम्पनियों को विदेशी बाजारों में अपने उत्पाद को बेचने और बिक्री कार्यों के सभी पहलुओं को नियन्त्रित करने की अनुमति देती है।
2. **सहायक कम्पनियों की स्थापना**—एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी द्वारा विदेश में निवेश के लिए दूसरा मोड़ विदेशी देश में संचालित करने के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी स्थापित करना है। इस मामले में एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी के पास अपने उत्पाद या सेवा के उत्पादन से लेकर उसके अन्तिम उपयोग या उपभोक्ताओं को बेचने तक के व्यवसाय संचालन पर पूरा नियन्त्रण होता है।
   किसी विशेष देश में एक बहुराष्ट्रीय निगम की एक सहायक कम्पनी उस देश की कम्पनी अधिनियम के तहत स्थापित की जाती है। ऐसी सहायक फर्म प्रबन्धकीय कौशल, वित्तीय संसाधनों और अपनी मूल कम्पनी की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से लाभान्वित होती है। हालाँकि, यह मूल कम्पनी से कुछ स्वतन्त्रता प्राप्त हैं।
3. **बहुराष्ट्रीय निगम की शाखाएँ**—अपनी सहायक कम्पनियों की स्थापना के बजाय, बहुराष्ट्रीय निगम अन्य देशों में अपनी शाखाएँ स्थापित कर सकता है। शाखाएँ होने के कारण वे कानूनी रूप से स्वतन्त्र व्यावसायिक इकाई नहीं हैं, लेकिन उनकी मूल कम्पनी के साथ जुड़ी हुई है।

TOUCH 'n PASS

प्र.5. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विनियमन पर टिप्पणी कीजिए।
Comment on international trade regulation.

उत्तर

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विनियमन
(International Trade Regulation)

परम्परागत रूप से दो देशों के बीच व्यापार द्विपक्षीय सन्धियों के माध्यम से विनियमित किया जाता था। कई सदियों तक वणिकवाद में विश्वास के तहत अधिकांश देशों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर सीमा शुल्क उच्च था और कई प्रतिबन्ध थे। 19वीं सदी में, विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम में, मुक्त व्यापार में विश्वास सर्वोपरि बन गया। उसके बाद से यह धारणा पश्चिमी देशों के बीच प्रभावी सोच बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में, विवादास्पद बहुपक्षीय सन्धियों जैसे जनरल एग्रीमेण्ट ऑन टैरिफ एण्ड ट्रेड (GATT) और विश्व व्यापार संगठन ने वैश्विक स्तर पर विनियमित व्यापार ढाँचे को निर्मित करते हुए मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयास किया। इन व्यापार समझौतों ने, अनुचित व्यापार के दावों के साथ जो विकासशील देशों के लिए लाभदायक नहीं हैं, अक्सर विरोध और असन्तोष को जन्म दिया है।

मुक्त व्यापार का आम तौर पर, आर्थिक रूप से सर्वाधिक मजबूत देशों द्वारा सबसे अधिक समर्थन किया जाता है, हालाँकि वे अक्सर उन उद्योगों के लिए चयनात्मक संरक्षणवाद में संलग्न होते हैं जो रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण हैं; जैसे—अमेरिका और यूरोप द्वारा कृषि पर लगाया जाने वाला सुरक्षात्मक प्रशुल्क। नीदरलैण्ड और यूनाइटेड किंगडम उस वक्त मुक्त व्यापार के कट्टर पैरोकार थे जब वे आर्थिक रूप से प्रभावकारी थे। आज संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड़ किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसके सबसे बड़े समर्थक हैं। हालाँकि, कई अन्य देश (देश, भारत, चीन और रूस) तेजी से मुक्त व्यापार के हिमायती बनते जा रहे हैं; क्योंकि वे आर्थिक रूप से खुद अधिक शक्तिशाली बन रहे हैं। जैसे—जैसे प्रशुल्क स्तर में गिरावट आ रही है गैर-प्रशुल्क उपायों पर चर्चा करने की इच्छा भी बढ़ रही है, जिसमें शामिल है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वसूली और व्यापार सरलीकरण। व्यापार सरलीकरण में सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और व्यापार को पूरा करने में सम्बन्धित लेनदेन लागत पर ध्यान दिया जाता है।

परम्परागत रूप से कृषि हित, आम तौर पर मुक्त व्यापार के पक्ष में है; जबकि विनिर्माण क्षेत्र अक्सर संरक्षणवाद का समर्थन करते हैं। हालाँकि, हाल के वर्षों में इसमें कुछ हद तक बदलाव आया है। वास्तव में, कृषि से जुड़े गुट, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और जापान में, प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सन्धियों में खास नियमों के लिए मुख्यत: जिम्मेदार है जो अधिकांश अन्य वस्तुओं और सेवाओं की अपेक्षा कृषि में अधिक संरक्षणवादी उपायों की अनुमति देते हैं।

मंदी के दौरान, घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए प्रशुल्क बढ़ाने का अक्सर अत्यधिक घरेलू दबाव होता है। महान मन्दी के दौरान यह दुनिया भर में हुआ है। कई अर्थशास्त्रियों ने विश्व व्यापार में पतन के लिए प्रशुल्क को अंदरूनी कारण के रूप में रेखांकित करने का प्रयास किया है जिसके लिए कई लोगों का मानना है कि इसने मन्दी को अधिक विकट कर दिया।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन, विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक स्तर पर किया जाता है और कई अन्य क्षेत्रीय व्यवस्था के माध्यम से; जैसे—दक्षिण अमेरिका में MERCOSUR , अमेरिका, कनाड़ा और मैक्सिकों के बीच नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (NAFTA) आर 27 स्वतन्त्र देशों के बीच यूरोपीय संघ, फ्री ट्रेड एरिया ऑफ द अमेरिका (FTAA) की योजनाबद्ध स्थापना पर 2005 ब्यूनस आयर्स वार्ता, मुख्य रूप से लैटिन अमेरिकी देशों की आबादी के विरोध में विफल हो गई। ऐसे ही अन्य समान समझौते जैसे कि मल्टीलेटरल एग्रीमेण्ट ऑन इन्वेस्टमेंट (MAI) भी हाल के वर्षों में विफल हो गए।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. व्यापार सिद्धान्त एवं व्यापार के लाभों का वर्णन कीजिए।
Describe the Trade Theory and Benefit from Trade.

उत्तर

व्यापार सिद्धान्त
(Trade Theory)

परम्परावादी व्यापार सिद्धान्त को 1817 में **प्रो० डेविज रिकार्डो** ने अपनी पुस्तक Principle of Political Economy में प्रतिपादित किया तथा अधिकतर परम्परावादी अर्थशास्त्रियों ने इसको सराहा है। इस सिद्धान्त की महत्त्वपूर्ण बात यह है कि व्यापार मुक्त होना चाहिए। यही सबसे उत्तम है। अधिकतर अल्प विकसित देश प्राथमिक वस्तुओं को निर्यात तथा विकसित देश उत्पादित (मशीनों से निर्मित पदार्थ) वस्तुओं का निर्यात करते थे। अल्पविकसित देशों से की गई दखल अंदाजी से (मशीनों से बने उत्पाद

पर प्रतिबन्ध और इनको अपने देश में उद्योग स्थापित करना) यद्यपि वर्तमान शताब्दी के पचास व साठ के दशक में व्यापारी के विपरीत कई आवाजें उठी और परम्परावादी अर्थशास्त्रियों को भी आलोचना की गई। सबसे ज्यादा आलोचना करने वालों में Rau Prebisch, Hans Singor और Gunnar Myrdal थे। उनका कहना है कि अल्प-विकसित देशों के सन्दर्भ में यह मान्यता गलत है कि परम्परावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार प्रत्येक देश को व्यापार से लाभ है। वास्तव में विकसित तथा अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के बीच व्यापार सम्बन्ध से विकसित देशों को ही लाभ पहुँचाता है। ब्रिटिश समय में इन देशों के उद्योग धन्धे नष्ट हो गए और ये सिर्फ कच्चा माल निर्यात करने वाले देश बन कर रह गए। इसलिए व्यापार ने सिर्फ इन देशों का शोषण किया। आजादी के बाद इन देशों ने बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के कार्यक्रम चलाए और इस उद्देश्य के लिए व्यापार पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबन्ध लगाए।

व्यापार से लाभ
(Benefits from Trade)

व्यापार से लाभ को सबसे पहले रिकार्डों ने अपनी तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के द्वारा आगे बढ़ाया जो परम्परावादी अर्थशास्त्रियों की अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नीति की रीढ़ की हड्डी बना। इस सिद्धान्त को दो देशों में वस्तुएँ मॉडल की सहायता से बता सकते हैं। मान लो दो देश दो वस्तुओं में (जूट व कौटन) व्यापार करते हैं इसमें दो सँभावनाएँ हैं पहली स्थिति में देश A गर्म कपड़ों का उत्पादन तथा B जूट के उत्पादन में भरपूर लाभ कमा रहा है। दूसरे संदर्भ में A को जूट उत्पादन में तुलनात्मक लाभ तथा B को गर्म कपड़ों के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ हैं

A देश अपने उत्पादन (गर्म कपड़ों) में विशिष्ट होने पर लाभ कमाता है। इसी प्रकार B अपने जूट उत्पादन में विशिष्ट होने पर लाभ कमाता है। यदि ये दोनों आपस में व्यापार करते हैं तो दोनों ही लाभ कमाएँगे क्योंकि यदि ये व्यापार न करके अपने देश में उत्पादन करते हैं तो उत्पादन अपने देश में करेगा। तो उत्पादन लागत अधिक होगी। गर्म कपड़ा उद्योग यदि जूट का उत्पादन अपने देश में करेगा तो उसकी लागत अधिक होगी क्योंकि यह इस उत्पादन में विशिष्ट नहीं है। यदि ये दोनों इन वस्तुओं का व्यापार के द्वारा आदान-प्रदान करते हैं तो लाभ होगा।

यदि हम तुलनात्मक लाभ को देखें तो A देश दोनों के उत्पादन में निपुण है लेकिन तुलनात्मक लाभ जूट को उत्पादन करने में है। यद्यपि B भी दोनों के उत्पादन में निपुण है लेकिन गर्म कपड़ों के उत्पादन को उत्पादित करने में तुलनात्मक लाभ कम है। तुलनात्मक व्यापार सिद्धान्त बताता है कि यदि दोनों देश व्यापार करेंगे तो इन्हें लाभ प्राप्त होंगे। क्योंकि यदि किसी भी देश को उत्पादन करने में विशिष्टता हासिल है वह अपने विशिष्टता हासिल उत्पादन का निर्यात कर सकता है तथा दूसरे देश जो अपने उत्पादन में विशिष्ट हैं उससे आयात कर सकता है। इस प्रकार दोनों देश अपने उत्पादन को निर्यात कर एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं। लेकिन यह सिद्धान्त अथवा यह एकल मॉडल कई मान्यताओं पर आधारित है। ये मान्यताएँ निम्नलिखित हैं—

1. सिर्फ श्रम ही अकेला उत्पादक साधन है।
2. हर देश में एक घण्टे श्रम की कीमत बराबर है।
3. तकनीक स्थिर है।
4. प्रतिफल का पैमाना स्थिर है।
5. यातायात लागत नहीं है।
6. उत्पादन के साधन पूर्ण रूप से गतिशील (आन्तरिक व्यापार) और पूर्ण रूप से प्रगतिशील (अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारा में) है।
7. खुजा बाजार कोई प्रतिबन्ध नहीं है।
8. प्रत्येक वस्तु के लिए वस्तु की श्रेष्ठता एक जैसी है तथा एक देश से दूसरे देश में कोई अन्तर नहीं है।

इसके साथ अल्पविकसित देशों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं—

1. खुला (मुक्त) व्यापार से देश में उत्पादन की अधिकता। अल्पविकसित देशों के सन्दर्भ में व्यापार उन्हें विकसित देशों से मशीनरी, शक्ति उत्पन्न करने के साधन, सड़क बनाने की मशीन, दवाइयाँ, कैमिकल आदि का आयात कर तकनीकी उन्नति से लाभान्वित करता है।
2. व्यापार से अल्पविकसित देशों की उपभोग क्षमता में वृद्धि करता है। और साधनों की कमी पूरा करना तथा उत्पादनों के लिए विश्वस्तर पर बाजार जिसको अल्पविकसित देश पैदा करने में कठिनाई महसूस करती है।

TOUCH 'n' PASS

3. कुछ समय के पश्चात साधन लागत, सभी देशों में जो व्यापार में शामिल होते हैं, कम होती है अथवा बराबर होती है। अल्पविकसित देशों में पूँजी की कीमत कम तथा श्रम की कीमत बढ़ेगी और विकसित देशों में इसके विपरित स्थिति होगी। इस वजह से शामिल होने वाले सभी देशों में साधन लागत बराबर होगी।
4. दूसरे लाभों की अपेक्षा अल्पविकसित देश तकनीक ज्ञान तथा उद्यमी, प्रबन्धकीय कुशलता आयात से लाभ अर्जित करता है। **प्रो० हेबरलर** का कहना है देर से प्रवेश करने वाले (विकास और औद्योगिक प्रक्रिया में) ज्यादा फायदा उठा सकते हैं; क्योंकि उद्यमियों के अनुभवों से सफलता तथा असफलता से जानकारी ले सकते हैं। आज के अल्पविकसित देश विकसित देशों से ली गई तकनीक में तथा उसको जानने में प्रगति कर रहे हैं।
5. **प्रो० हेबर्रलर** के अनुसार व्यापार पूँजी के लिए एक नया विकल्प बनता है। व्यापार का स्तर अधिक होने से अल्पविकसित देशों की ब्याज तथा मूलधन देने की क्षमता बढ़ेगी। इसलिए यह विदेशी पूँजी का अधिक आयात करेगी। इसलिए यह (विदेशी पूँजी) निर्यात उद्योग स्थापित करना, आयात प्रतिस्थापन्न उद्योग, सामाजिक संस्थान का आरम्भ इत्यादि के विकास से आर्थिक विकास प्रक्रिया को बढ़ाने में मदद करेगी। विदेशी व्यापार की अनुपस्थिति में विदेशी पूँजी को आयात करने की सम्भावना कम होगी। इसलिए देश इस पूँजी के लाभ से वंचित होगा।
6. विदेशी व्यापार साफ सुथरी प्रतियोगिता रखता है तथा गलत एकाधिकारी पर नजर रखता है। हेबरल का कहना है अमरीकी अर्थव्यवस्था ज्यादा प्रतियोगी, विशिष्ट है दूसरों की अपेक्षा; क्योंकि यह अपने अन्दर भी प्रतियोगिता रखता है तथा इनका आन्तरिक व्यापार मुक्त है। इस सन्दर्भ में, अल्पविकसित देशों के भी बाजार का आकार छोटा होने पर भी प्रतियोगिता बढ़ानी चाहिए।

ऊपर वर्णित बातों से जो व्यापार के बारे में कही गई इससे लगता है कि अल्पविकसित देशों के लिए यह एक जरूरी साधन है। ये देश विदेशी पूँजी और विदेशी विचार कहते हैं। जब तक ये निर्यात नहीं बढ़ाएँगे इनके लिए कैसे भुगतान कर सकते हैं।

प्र.2. क्या भारत एक अल्पविकसित देश है? इस कथन की विवेचना कीजिए।
Is India an under developed country? Ciscuss this statement.
***अथवा* अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं?**
What do you understand by underdeveloped economy?

उत्तर

क्या भारत एक अल्प-विकसित देश है?
(Is India An Under-Developed Country)

भारत-एक विकासशील अर्थव्यवस्था (India-A Developing Economy)

अर्द्ध-विकसित देशों की विभिन्न विशेषताओं को देखते हुए तथा बाह्य दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था पर दृष्टिपात करने पर निःसन्देह यही कहा जायेगा कि भारत एक अर्द्ध-विकसित राष्ट्र है जिसके प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं— (1) कृषि की प्रधानता (2) प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, (3) पूँजी निर्माण का निम्न स्तर, (4) बेरोजगारी, (5) ऊँची जन्म वृ मृत्यु-दरें (6) निम्न प्रत्याशित आयु, (7) जनसंख्या का घनत्व, (8) पुरानी उत्पादन विधि, (9) निम्न साक्षरता, (10) पिछड़ा आर्थिक व सामाजिक ढाँचा, (11) निम्न जीवन स्तर आदि ऐसी कसौटियाँ हैं जो भारत को पिछड़ेपन के धरातल पर लाकर खड़ा कर देती है। परन्तु पिछले कुछ वर्षों से भारत विकास की स्थैतिक अवस्था से निकलकर प्रावैगिक अवस्था में प्रवेश कर चुका है जैसा कि निम्न विवरण से स्पष्ट है—

1. **नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था** (Planned Mixed Economy)—1 अप्रैल, 1951 से भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजित अर्थव्यवस्था के रूप में कार्यशील है। यहाँ आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएँ बनाई जाती है। इसे मिश्रित इसलिए कहा जाता है कि यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र दोनों को काम करने का समान अवसर दिया गया है। एक तरफ सरकारी उपक्रम है तो दूसरी तरफ निजी उपक्रम है।
   जुलाई, 1991 से देश में आर्थिक सुधारों का नया कार्यक्रम अपनाया गया है जिसके अन्तर्गत आर्थिक उदारीकरण का मार्ग अपनाया गया है। सरकार निजीकरण, बाजारीकरण व अन्तर्राष्ट्रीयकरण पर बल देने लगी है।

TOUCH 'n PASS

2. **प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि** (Increase in Per Capita Income and National Income)—भारत में प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में निरन्तर वृद्धि हो रही हैं। प्रति व्यक्ति वार्षिक आय जो वर्ष 1950-51 में (वर्ष 1993-94 की कीमतों के आधार पर) ₹ 3,687 थी, वह वर्ष 2000-2001 में बढ़कर ₹ 10,254 हो गई है।
3. **बचत व विनियोग दरों में वृद्धि** (Increase in Saving and Investment Rates)—योजना अवधि में बचत व विनियोग दर में भी उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। चालू मूल्यों के आधार पर GDP से सकल बचत का अनुपात जो 1950-51 में 8.9 प्रतिशत था, वह 2000-2001 में बढ़कर 23.0 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार सकल घरेलू पूँजी निर्माण की दर जो वर्ष 1950-51 में 8.9 प्रतिशत थी, वह 2000-2001 में बढ़कर 24.0 प्रतिशत हो गयी।
4. **तीनों क्षेत्रों का सापेक्षिक महत्त्व** (Relative Significance of Three Sectors)—पिछले 52 वर्षों में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि के योगदान में कमी आयी है और उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का सापेक्षिक महत्त्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है। ये परिवर्तन अर्थव्यवस्था के विकास के परिचायक हैं।
5. **कृषि क्षेत्र का विकास** (Development of Agriculture)—कुछ समय पूर्व तक भारत में कृषि अत्यन्त ही पिछड़ी हुई तथा अविकसित स्थिति में थी परन्तु अब खेती में उपकरणों, रासायनिक खाद, अधिक उपज देने वाले बीजों व अन्य कृषि आदान (Agricultural inputs) का प्रयोग धीरे-धीरे जोर पकड़ रहा है और खेती का व्यापारीकरण भी बढ़ रहा है। "हरित क्रान्ति" के कारण अब पहले की अपेक्षा कृषि उत्पादन की मात्रा काफी तेजी से बढ़ने लगी है।
6. **औद्योगिक विकास** (Industrial Development)—औद्योगिक क्षेत्र में तो परिवर्तन तेज गति से हो रहे हैं। अब देश में अनेक प्रकार के आधुनिक उद्योग, मूल व भारी उद्योग; जैसे—मशीन उद्योग, लोहा व इस्पात उद्योग, इन्जीनियरिंग उद्योग आदि स्थापित किये जा चुके हैं। पहले केवल दस्तकारी या कुटीर उद्योगों का ही बोलबाला था। औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में इधर कुछ वर्षों से भारी वृद्धि हुई है। औद्योगिक विकास के फलस्वरूप देश में निर्मित वस्तुओं का आयात काफी बढ़ गया है और निर्यात व्यापार में निर्मित वस्तुओं का भाग काफी तेजी से बढ़ रहा है। राष्ट्रीय आय तथा रोजगार में उद्योग क्षेत्र का योगदान धीरे-धीरे बढ़ रहा है।
7. **सार्वजनिक क्षेत्र का विकास** (Development of Public Sector)—यहाँ सार्वजनिक उद्योगों में बराबर वृद्धि हो रही है। वर्ष 1950-51 में भारत में 5 सार्वजनिक उद्योग थे जिनमें 29 करोड़ रुपये की पूँजी लगी थी। वर्तमान में इनकी संख्या 235 व विनियोजित पूँजी बढ़कर 2,73,700 करोड़ रुपये हो गई। इन उद्योगों में लोहा एवं इस्पात उद्योग, सीमेण्ट, उद्योग, रसायन उद्योग, इन्जीनियरिंग उद्योग, कोयला उद्योग व अनेक उपभोक्ता व औद्योगिक उद्योग शामिल हैं।
8. **बाजार-तन्त्र द्वारा आर्थिक क्रियाओं का निर्देशन** (Direction to Economic Activities by Market Machanism)—भारतीय अर्थव्यवस्था में बाजार-तन्त्र बहुत प्रभावशाली है। यहाँ वस्तुओं के अलावा उत्पादन के साधनों; जैसे—श्रम और पूँजी के पर्याप्त रूप से संगठित बाजार हैं। वस्तु बाजारों में अधिकांश चीजों की कीमतें माँग और पूर्ति की शक्तियों के बीच सन्तुलन द्वारा निर्धारित होती हैं। बाजार-तन्त्र द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों को नियन्त्रित करने के लिए लाइसेन्स प्रणाली के अलावा आयात नियन्त्रण, अनिवार्य वस्तुओं के अभाव के समय उनका उचित मूल्य दुकानों (Fair Price Shops) के द्वारा वितरण द्वारा किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि उत्पादों की समर्थन कीमतों (Support Prices) पर सरकार द्वारा खरीद की व्यवस्था की गई है।
9. **निर्धनता दूर करने के विशिष्ट कार्यक्रम** (Specific programmes For Eradicating Poverty)—छठी योजना में गरीबी दूर करने के विशिष्ट कार्यक्रम; जैसे—समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम व रोजगार सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम अपनाने से निर्धनता अनुपात घटा हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में योजना आयोग व लकड़वाला विशेषज्ञ समूह के आँकड़ों में भारी अन्तर पाया जाता है।
10. **यातायात एवं संचार** (Transport and Communication)—रेलों, सड़कों जहाजरानी तथा संचार के साधनों में भी पर्याप्त विकास हुआ है। भातीय रेल प्रणाली विश्व की बड़ी रेल प्रणालियों में अपना अग्रणी स्थान रखती है। जहाजरानी में भारत का विश्व की बड़ी 16 जहाजरानी प्रणालियों में महत्त्वपूर्ण स्थान है। संचार व्यवस्था में भी नये कीर्तिमान स्थापित किये गये हैं। उपग्रह के माध्यम से दूरसंचार व्यवस्था का विकास हुआ है।
11. **मुद्रा और साख व्यवस्था** (Money and Credit System)—बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में भी प्रगति उत्साहवर्द्धक रही है। बैंकों एवं बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण से बैंक जमाओं और बीमा व्यवसाय में अत्यधिक वृद्धि हुई है। वित्तीय

TOUCH 'n PASS

साधनों की उपलब्धि से कृषि, निर्यात उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योगों, फुटकर एवं छोटे व्यापार, स्व-नियुक्त रोजगार, शिक्षा आदि क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है।

12. **सामाजिक सेवाओं का विस्तार** (Expansion of Social Services)—शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सामाजिक सेवाओं के विस्तार में भी पर्याप्त प्रगति हुई है। स्कूली एवं विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा और शोध के क्षेत्रों में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। साक्षरता का स्तर बढ़ा है। अब देश में प्रशिक्षित, श्रमिकों, तकनीकी विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, अनुसन्धानकर्ताओं, प्रशासकों व प्रबन्धकों आदि की कमी नहीं है।
13. **सामाजिक परिवर्तन** (Social Change)—भारतीय समाज में शिक्षा के प्रसार व विकास के साथ-साथ परिवर्तन हुआ है। रूढ़िवादिता, बाल-विवाह, पर्दा-प्रथा, छुआछूत आदि बुराइयाँ धीरे-धीरे कम हुई हैं और देशवासियों ने विकास के अनुरूप अपने को ढालने की चेष्टा की है जो एक प्रगति के पक्ष पर अग्रसर राष्ट्र के लिए आवश्यक है।

निष्कर्ष (Conclusion)—उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था यद्यपि पिछड़ी है लेकिन अब वह गरीबी के दुष्चक्र से बाहर है। योजनाकाल में हमने तीव्र गति से आर्थिक विकास किया है। जिसके कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था में संस्थात्मक एवं संरचनात्मक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आज हमारा औद्योगिक ढाँचा पहले से अधिक मजबूत है। कृषि क्षेत्र में विविध संस्थागत और तकनीकी सुधार हुए हैं। आधारभूत आर्थिक संरचना ज्यादा विकसित है। वित्तीय ढाँचा अधिक सशक्त और फैला हुआ है। आर्थिक उदारीकरण की नीति के तहत निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। बाजार संयन्त्र का अधिक उपयोग किया जा रहा है तथा देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास चल रहा है। हर्ष की बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्रयशक्ति की समता की दृष्टि से विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं।

प्र.3. स्वतन्त्रता के पश्चात आधार संरचना का विकास एवं ऊर्जा संसाधन का वर्णन कीजिए।
Describe the development of infrastructure and energy resources after independence.

उत्तर

स्वतन्त्रता के पश्चात आधार संरचना का विकास
(Development of Infrastructure after Independence)

इस कथन से कदापि इंकार नहीं किया जा सकता कि अधोसंरचना के विकास के अभाव में देश का विकास सम्भव नहीं है। इसी कारण भारत की आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया में अधोसंरचना के विकास पर बल दिया गया। 62 वर्षों की नियोजन प्रक्रिया में आधार संरचना का अच्छा विकास हुआ। 11 पंचवर्षीय योजनाएँ, तीन वार्षिक योजनाएँ व तीन वर्ष का अन्तरकाल का नियोजन इस बात की पुष्टि भी करता है।

भारत में अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में योजना व्यय का लगभग 50 प्रतिशत आधारभूत संरचना पर व्यय किया है। परिणामस्वरूप भारत का आधारभूत संरचना उपलब्ध हो सका। यह एक विडम्बना ही है कि आधारभूत संरचना की उपलब्धता मात्र शहरों एवं नगरों में ही उपलब्ध है और गाँवों में इनका विकास तुलनात्मक दृष्टि से नहीं हो सका। इसी कारण जनसंख्या का पलायन गाँवों से शहरों की ओर हो रहा है और परिणामस्वरूप शहरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही हैं।

निम्नलिखित तालिका से यह स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता पश्चात भी भारत में आधारभूत संरचना का काफी विकास हुआ है—

विवरण	इकाई	वर्ष 1950-51	वर्ष 2008-09
1. ऊर्जा या शक्ति			
(i) 1. कोयले का उत्पादन	लाख टन में	322	
(ii) 2. विद्युत का उत्पादन	विलियन kwh में	5	4933
(iii) 3. कच्चे तेल का उत्पादन	लाख टन में	3	746.6
2. परिवहन			
(i) 1. रेलों की लम्बाई	1000 km में	53.6	335
(ii) 2. सड़कों की लम्बाई	लाख km में	4	63.3
(iii) 3. जहाजों की क्षमता	लाख GRT में	3.7	33.4

TOUCH 'n PASS

3. संचार			
(i) 1. डाकखाने	हजार में	3.6	115.3
(ii) 2. टेलीफोन	करोड़	0.017	30.05
4. बैंक एवं वित्त			
(i) 1. बैंक	कार्यालय	2600	76885

अब हम एक करके सभी मदों का विस्तार से उल्लेख करेंगे।

ऊर्जा संसाधन
(Energy Resources)

जिस देश में सस्ते व पर्याप्त माँग में शक्ति संसाधन उपलब्ध होते हैं वह देश अपना विकास आसानी से व तीव्र गति से कर सकता है। इसका कारण है कि सभी क्षेत्रों; जैसे—कृषि, उद्योग, परिवहन आदि में शक्ति साधनों की आवश्यकता पड़ती है। इसके विपरीत जिस देश में शक्ति संसाधन अपर्याप्त होते हैं या अविकसित होते हैं। वह देश अन्य सभी आवश्यक सुविधाओं के होते हुए भी विकास मन्द गति से कर पाता है। यही कारण है कि प्रत्येक देश अपनी आर्थिक योजनाएँ बनाते समय शक्ति संसाधनों के विकास पर विशेष जोर देता है।

यह माना जाता है कि जिस देश में शक्ति संसाधन की प्रति व्यक्ति खपत जितनी अधिक होगी उस देश में प्रति व्यक्ति आय भी उतनी ही अधिक होगी। इस दृष्टि से देखा जाय तो भारत दोनों में ही पीछे है। यहाँ प्रति व्यक्ति शक्ति संसाधनों की खपत भी कम है और प्रति व्यक्ति आय भी कम है।

भारत में विश्व की 16 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, लेकिन यहाँ पर कुल विश्व खपत की 1.5 प्रतिशत शक्ति ही खर्च होती हैं। आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2008-09 के अनुसार यहाँ प्रति व्यक्ति खपत लगभग 90.4 KWH वार्षिक है जो बहुत कम है।

भारत में शक्ति संसाधन कई है; जैसे—मनुष्य, पक्षी, लकड़ी, कोयला, वायु, जल, परमाणु, खनिज तेल आदि संसाधनों को दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है—

1. **परम्परागत साधन**
   (i) कोयला (ii) विद्युत (iii) खनिज तेल या पेट्रोलियम
2. **गैर परम्परागत साधन**
   (i) परमाणु शक्ति (ii) वायु शक्ति (iii) सूर्य शक्ति
   (iv) गैस भाप विद्युत गृह आदि

1. परम्परागत साधन (Traditional Means)

(i) **कोयला**—कोयला को ईंधन का बादशाह माना जाता है। औद्योगिक क्रान्ति की शक्ति का माध्यम कोयला को ही माना जाता है। चाहे मानव सभ्यता का विषय हो या किसी देश के आर्थिक विकास का प्रथम चरण कोयला का स्थान सर्वोपरि है। इसी कारण से काला सोना (Black Gold) या काला हीरा (Black Diamond) का नाम दिया गया है।

कोयले के उपयोग में न मात्र शक्ति उत्पादन बल्कि ईंधन का रूप भी उतना ही महत्त्व रखता है। इससे निकले कई रासायनिक पदार्थ; जैसे—तेल, बेजोल, नेफ्था का प्रयोग रासायनिक उद्योगों में होता है। बिजली उपकरणों के निर्माण में भी कोयले का प्रयोग किया जाता है। कोलतार भी बनाया जाता है; जिससे सड़क का निर्माण होता है। इससे डायल भी बनाया जा सकता है जिससे अमोनिया द्रव निकलता है जो खाद बनाने वाले कारखानों के काम आता है।

भारत में कोयले के कुल 264.54 करोड़ टन के भण्ड़ार है। यह विश्व के कुल कोयला भण्ड़ार का 8 प्रतिशत ही है। तीसरे स्थान की श्रेणी में भारत के पास मात्र 2 प्रतिशत ही बढ़िया किस्म का कोयला है; जबकि 7 प्रतिशत मध्यम किस्म और 91 प्रतिशत कोकिंग (Non Coking) किस्म का है।

भारत में मात्र तीन क्षेत्र ही है जो कोयला उत्पादन क्षेत्र में आते हैं—पश्चिम बंगाल एवं झारखण्ड एवं अन्य छुटपुट क्षेत्र। पश्चिम बंगाल एवं झारखण्ड कुल मिलाकर 61 प्रतिशत कोयल का उत्पादन करते हैं। आज भारत में 22 प्रतिशत कोकिंग कोयला व 78 प्रतिशत गैर कोकिंग कोयला का उत्पादन हो रहा है।

TOUCH n PASS

(ii) **विद्युत**—किसी भी देश का आर्थिक विकास विद्युत शक्ति के बिना सम्भव नहीं हैं। चाहे गाँव हो या शहर, उद्योग हो या खेत, शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ विद्युत की आवश्यकता न हो। एक आवश्यक इनपुट के रूप में विद्युत का उपयोग पीने के पानी के लिए, परिवहन साधनों को चलाने के लिए, संचार सुविधाओं के लिए घरों व सड़कों पर रोशनी के लिए किया जाता है। विकसित देशों की तीव्र विकास के पीछे विद्युत का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान है। विद्युत का उत्पादन पानी, कोयला, डीजल, परमाणु शक्ति से होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से विद्युत का उत्पादन भारत में वर्ष 1900 से प्रारम्भ हुआ। पहला पन बिजलीघर कर्नाटक राज्य में शिवसमुद्रम में बनाया गया हालाँकि इसके पश्चात अनेक पन बिजलीघर बनाये गये परन्तु यह शहरी क्षेत्र तक ही सीमित थे।

1950-51 में विद्युत की कुल उत्पादन क्षमता 22 लाख टन थी जबकि 2008-09 में बढ़कर 1750 लाभ kW हो गई। वहीं 1950-51 में इसकी कुल वास्तविक उत्पादन 7 विलियन kWh थी जो 2008-09 में बढ़कर 842 विलियन kWh हो गई।

विकसित देशों की तुलना में भारत में विद्युत का प्रति व्यक्ति उत्पादन 55 KW वार्षिक ही है। जबकि अमेनिरका में 7998 kW हैं। यहाँ तक कि इटली में 2186 kW है।

विद्युत शक्ति के उत्पादन का 37.6 प्रतिशत भाग उद्योगों द्वारा खपत किया जाता है; जबकि 21.7 प्रतिशत भाग कृषि द्वारा खपत किया जाता है। विद्युत शक्ति का विकास सम्पूर्ण भारत में समुचित रूप से हुआ है। हिमालय प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल व मेघालय मुख्य रूप से जल विद्युत पर निर्भर हैं। दिल्ली, बिहार व पश्चिम बंगाल कोयले द्वारा उत्पादित बिजली पर निर्भर है तो वहीं आन्ध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु व उत्तर प्रदेश को जल विद्युत व कोयला से उत्पादित विद्युत दोनों ही मिलती है। अब तक भारत के गाँवों का लगभग 84 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है।

(iii) **खनिज तेल या पेट्रोलियम**—यह मात्र शक्ति साधन के रूप में ही नहीं वरन् बहुत से उद्योगों के लिए आधार भी है। पेट्रोलियम दो शब्दों से मिलकर बना है— पेट्रो + ओलियम । पेट्रो का अर्थ हैं—चट्टान एवं ओलियम शब्द का अर्थ है—तेल। अर्थात् चट्टान का तेल। भूरे या पीले या हरे रंग का यह पदार्थ तरल रूप में होता है एवं गहरे कुएँ से निकले अशोधित तेल को Crude Oil कहते हैं।

भारत में खनिज तेल भण्डार 35 करोड़ टन का है। यह भण्ड़ार असम, गुजरात, नाहरकटिया, रवम्भात, अंकलेश्वर, डिगबोई, सूरमाघाटी, कच्छ की खाड़ी, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, बंगाल की खाड़ी, बाम्बे हाई आदि में पाये जाते हैं।

भारत में तेल के स्रोत सर्वप्रथम 1866 में देखे गये थे और 1867 में सर्वप्रथम असम में तेल निकाला गया। डिगबोई क्षेत्र की स्थापना के साथ ही 1895 में असम ऑयल कम्पनी ने इसका कार्य भार सम्भाल लिया। 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई। तत्पश्चात निजी क्षेत्र के लिए भी यह क्षेत्र खोल दिया गया। जिसके फलस्वरूप Reliance व Easer Group इस ओर अग्रसर हुए। जहाँ वर्ष 1950-51 में भारत का खनिज तेल का उत्पादन 3 लाख टन था। वहीं वर्ष 2008-09 में 335 लाख टन रहा। इस समय देश में 13 करोड़ 25 लाख टन तेल शोधन क्षमता के 18 तेलशोधक कारखाने हैं। इनमें मात्र 1 निजी क्षेत्र में हैं जो कि Refiners Reliance Industries Limited, Jamnagar में स्थित है।

2. गैर-परम्परागत साधन (Non-Traditional Means)

(i) **परमाणु शक्ति**—होमी जहाँगीर भाभा को भारत में परमाणु शक्ति का विकास करने का श्रेय जाता है। इन्होंने वर्ष 1945 में TIFR (Tata Institute of Fundamental Research) टाटा आधारभूत अनुसन्धान संस्थान की स्थापना की। वर्ष 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। वर्ष 1954 में केन्द्र सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग स्थापित किया गया जिसका नाम डॉ० भाभा की मृत्यु के पश्चात "भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र" पर रखा गया। इस केन्द्र में चार अनुसन्धान रिऐक्टर हैं।

(a) अप्सरा (b) साइकस (c) जरलीना (d) ध्रुव
(d) कामिनी

TOUCH 'n PASS

आज देश में परमाणु विद्युत केन्द्र तारापुर परमाणु केन्द्र (महाराष्ट्र), रावतभाटा परमाणु शक्ति केन्द्र (राजस्थान) कलपक्कम परमाणु केन्द्र (तमिलनाडु), नरौरा परमाणु शक्ति केन्द्र (उत्तर प्रदेश), काकरापार शक्ति केन्द्र (गुजरात) तथा कैगा परमाणु शक्ति केन्द्र (कर्नाटक) में स्थित है।

भारत में परमाणु शक्ति का विकास—भारत में इस समय 2225 मेगावाट परमाणु शक्ति की उत्पादन क्षमता के परमाणु विद्युत गृह है जो अपनी पूरी क्षमता पर उत्पादन कर रहे हैं। परमाणु शक्ति के विकास की परम आवश्यकता है; क्योंकि देश के आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में सस्ती शक्ति की जरूरत होती है। जहाँ पर जल शक्ति अपर्याप्त है वहाँ परमाणु शक्ति इस कमी को पूरा करने में समर्थ है। कोयले के विकल्प के रूप में परमाणु शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है; क्योंकि कोयले के भण्ड़ार सीमित है। भाखड़ा नांगल, चम्बल आदि योजनाओं से भारी जल की आवश्यकता पूरी करके परमाणु शक्ति को उत्पन्न किया जा सकता है।

(ii) **वायु शक्ति**—इस शक्ति का भी प्रयोग देश के विकास के लिए किया जा सकता है। नीदरलैण्ड जैसे देशों ने इसका उपयोग पवन चक्कियाँ लगाकर किया है। हालाँकि भारत के गाँवों में किसानों द्वारा अनाज को भूसे से अलग करने के लिए इस शक्ति का प्रयोग किया जाता है। परन्तु अभी तक वृहत रूप से इसका उपयोग नहीं किया गया है। राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसन्धानशाला बंगलौर के अनुसार भारत में भी वायुशक्ति का उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। भारत अपनी 45000 मेगावाट वायु शक्ति की क्षमता का महज 13000 मेगावाट का ही उपयोग कर पा रहा है। विश्व में इसका स्थान पाँचवाँ है—जर्मनी, अमेरिका, डेनमार्क व स्पेन।

(iii) **सूर्य शक्ति**—सूर्य से प्राप्त शक्ति, शक्ति का एक ऐसा साधन होगा जो कभी समाप्त नहीं होगा। भारत का प्रथम सौर ऊर्जा बिजलीघर लद्दाख के छोंग्लेश्वर नामक गाँव में स्थापित किया गया जो विश्व में इस प्रकार की बिजली का दूसरा गाँव है। भारत में BHEL कम्पनी की हरिद्वार स्थित कैन्टीन में सूर्य शक्ति का प्रयोग धोने के लिए गर्म पानी के लिए किया जाता हैं। भावनगर (गुजरात) में पीने का पानी इसी शक्ति से साफ किया जाता है। दिल्ली के सुपर बाजार व उत्तर प्रदेश में भी सूर्य शक्ति के हीटर बेचे जा रहे हैं।

(iv) **गैस भाप विद्युत गृह**—भारत का पहला गैस भाप विद्युत गृह राजस्थान में कोटा के पास अन्त में बनाया गया है। जिसमें गैस से विद्युत बनना प्रारम्भ हो गया है। भारत का इस सम्बन्ध में यह पहला परीक्षण है।

प्र.4. आर्थिक विकास में भारत में रेल परिवहन व जल परिवहन का वर्णन कीजिए।
Describe the role of rail transport and water transport in economic development in India.

उत्तर

भारत में परिवहन साधन
(Means of Transport in India)

परिवहन को परिभाषित करते हुए अमेरिकी विद्वान **फेयर** एवं **विलियम्स** (Fair & Williams) के अनुसार, "परिवहन का अर्थ मनुष्यों अथवा सम्पत्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमनागमन (Movement) से है।"

परिवहन मनुष्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने की सुविधा प्रदान करती है। सस्ते और शीघ्रगामी साधन को आधुनिक परिवहन की संज्ञा दी जाती है जिसके अन्तर्गत रेल, मोटर, पानी के जहाज, हवाई जहाज आदि आते हैं।

परिवहन का देश के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। इससे कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि, विविधकरण एवं विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलता है। इससे व्यापार का ही विस्तार नहीं होता बल्कि मूल्यों में भी स्थिरता आती है। देश की सुरक्षा एवं रक्षा को बढ़ावा मिलता है एवं सरकारी आय भी बढ़ती है।

आर्थिक विकास में परिवहन का महत्त्व
(Importance of Transportation in Economic Development)

आर्थिक विकास में परिवहन का महत्त्व निम्नलिखित है—

1. **कृषि क्षेत्र में**—परिवहन के माध्यम से किसान अपने उत्पादन को शहरों में बेचने के लिए जा सकते हैं। ऐसे कई उत्पाद; जैसे—तरकारी, फल, डेरी उत्पाद, मछली आदि को शहर में बेचने के लिए परिवहन की सुविधा लाभप्रद होती है। इन

साधनों के विकास से कृषि उत्पादन बढ़ता है; क्योंकि शहरों से अच्छे बीज रासायनिक खादें व कृषि यन्त्र प्राप्त किये जा सकते हैं।

2. **औद्योगिक क्षेत्र में**—परिवहन साधनों का विकास होने से उन स्थानों पर नये-नये कारखाने स्थापित हो पाते हैं जो सड़कों, रेलों, बन्दरगाहों आदि से जुड़ जाते हैं। इसी के कारण खान उद्योग व वन उद्योग का विकास हुआ है। ये साधन श्रम में गतिशीलता ला देते हैं। इससे उद्योगों की श्रमिक उचित मात्रा में मिल जाते हैं।
3. **व्यापारिक क्षेत्र में**—परिवहन साधन के विकास से व्यापारिक क्रियाओं में वृद्धि होती है, साथ ही साथ विदेशी व्यापार में भी वृद्धि होती है। मूल्यों के उतार चढ़ावों में कमी हो जाती है।
4. **सामाजिक क्षेत्र में**—परिवहन साधन की सुविधा से विभिन्न क्षेत्र के लोग एक-दूसरे के सम्पर्क में आते हैं जिससे संस्कृतियों के सम्बन्ध में ज्ञान की वृद्धि होती है। इससे अन्धविश्वास व रूढ़िवादिता को कम करने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है एवं भाईचारें की भावना पनपती है।
5. **राजनीतिक क्षेत्र में**—देश में शान्ति व सुरक्षा के लिए द्रुतगामी परिवहन साधनों की आवश्यकता होती है। सीमा क्षेत्र व विदेशों से रक्षा के लिए भी परिवहन साधन चाहिए।

भारत में रेल परिवहन
(Rail transport in India)

पहली रेल सेवा भारत में वर्ष 1853 में बम्बई से थाना तक 21 मील मार्ग का सफर तय किया था। 1 अप्रैल 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना से अब तक रेल के क्षेत्र में भी काफी विकास हो गया है। तब से अब तक यात्रियों की संख्या 128 करोड़ प्रतिवर्ष से 572 करोड़ प्रतिवर्ष के ऊपर चली गई। मालगाड़ी द्वारा ढोये जाने वाले की मात्रा 9.3 करोड़ टन से 74.5 करोड़ टन हो गई हैं। लगभग 58145 करोड़ रुपये से अधिक की पूँजी की मात्रा भी लगाई जा चुकी है। विद्युत रेलमार्ग 388 किमी० से बढ़कर 17,786 कि०मी० हो गया। रेलवे विकास के सन्दर्भ में कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं—

1. **विद्युतीकरण**—वर्तमान में विद्युत रेलमार्ग की दृष्टि से भारत का एशिया में दूसरा व विश्व में ग्यारहवाँ स्थान है। कुछ ही वर्षों में देश के प्रमुख सात मुख्य भागों पर विद्युतीकरण का कार्य भी पूरा हो जायेगा।
2. **इंजन**—वर्तमान में रेलवे के पास 44 भाप इंजन, 4793 डीजल इंजन व 3188 बिजली के इंजन हैं।
3. **सन्देशवाहन व्यवस्था**—रेलवे ने Super high frequency and Channeling System पर आधारित सूक्ष्म तरंग पद्धति लागू की है। जो वर्तमान में 16,000 कि०मी० रेलमार्ग पर अपनायी जा रही है।
4. **सिग्नल व्यवस्था में सुधार**—पहले के यन्त्रीकृत सिग्नल की अपेक्षा अब बिजली सिग्नलों के प्रयोग में लाया जा रहा है जो अधिक विश्वसनीय है।
5. **रेलों की गति में वृद्धि**—सुपर एक्सप्रेस राजधानी एक्सप्रेस जैसे सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के चलाने से रेलों को गति मिल गई है। अब कई हजार किलोमीटर की यात्रा भी चन्द घण्टों में पूरी की जा सकती है। 20 रेलगाड़ियाँ शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से चलायी जा रही है। 16 इण्टरसिटी जन शताब्दी एक्सप्रेस 1 जुलाई 2002 से चलाई गई हैं।
6. **रेल निर्माणक इकाइयाँ**—रेल परिवहन के उपकरण, इन्जनों व डिब्बों के बनाने के लिए भारत में निम्न चार प्रमुख कारखाने हैं जिनकी स्थापना स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात ही हुई हैं—
   (i) **चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, कोलकाता**—वर्ष 1950 में स्थापित इस कारखाने में भाप के इंजन बनाये जाते थे। परन्तु अब बिजली व डीजल इन्जन बनने लगे हैं। वर्तमान में इसकी लगभग 170 बिजली इंजन व 81 डीजल इन्जन वार्षिक है।
   (ii) **इण्टीग्रल कोच फैक्टरी, पैराम्बूर (तमिलनाडु)**—डब्बा बनाने से लेकर सजाने तक का काम भी इस कारखाने के सुपुर्त है। पहला डिब्बा वर्ष 1955 में तथा पहला सुसज्जित डिब्बा वर्ष 1975 में बनकर निकला। वर्तमान में इसकी क्षमता 1600 डिब्बे प्रतिवर्ष हैं।
   (iii) इण्टीग्रल कोच फैक्ट्री कपूरथला।
   (iv) डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी।

TOUCH 'n' PASS

7. **माल-परिवहन व्यवस्था में उन्नति**—इसका भी विकास क्रमश: होता गया। शीघ्रता से माल पहुँचाने के लिए प्रमुख शहरों के मध्य सीधी "सुपर एक्सप्रेस मालगाड़ियों" लायी जा रही है। वर्ष 1969 "फ्रेट फारवर्ड स्कीम" लागू की गई है जिसके अन्तर्गत ये छोटे-छोटे सामान को एकत्रित कर रेलवे को वैगन माल के रूप में देता हैं।

रेल परिवहन का आर्थिक महत्त्व (Economic Importance of Rail Transport)

रेल परिवहन का आर्थिक महत्त्व निम्नलिखित है—

1. **कृषि का विकास**—रेल परिवहन के विकास से अब किसान अपनी आवश्यकता के फसल के अतिरिक्त उन उत्पादों का भी उपज करता है जिसका वह निर्यात कर सकता है; जैसे—चाय, तम्बाकू, कपास आदि।
2. **नाशवान वस्तुओं की बिक्री**—ऐसी वस्तुओं; जैसे—फल, तरकारी, दूध, मक्खन, घी, गन्ना, मछलियाँ आदि जो नाशवान प्रकृति की होती है, रेल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना आसान हो गया है जिससे इनके उत्पादन एवं बिक्री में भी वृद्धि हुई है।
3. **अकालों पर नियन्त्रण**—रेल विकास ने इस प्राकृतिक आपदा पर नियन्त्रण का कार्य किया है। रेलों द्वारा खाद्यान्न एक स्थान से दूसरे स्थान पर अति शीघ्र भेजना सम्भव हो गया है।
4. **मूल्यों में स्थिरता**—मूल्यों की विषमता को रेल का विकास ने बहुत हद तक सीमित कर दिया है। आसानी से सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने से मूल्यों की अस्थिरता पर नियन्त्रण लग गया है।
5. **उद्योगों का विकास**—आज रेलें कोयला, लोह-इस्पात, सीमेण्ट, जूट, सूती वस्त्र आदि उद्योगों के विकास में योगदान दे रही है। कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने से उद्योगों के विकास में सहायता मिली है।
6. **नगरों में वृद्धि**—रेलों की स्थापना एवं इनके विकास से सैकड़ों गाँव व कस्बे नगरों में परिणत हो गये हैं। समुद्री बन्दरगाहों का विकास हुआ है। एक ज्वलन्त उदाहरण के रूप में कानपुर का नाम लिया जा सकता है। जो एक छोसा-सा कस्बा था। परन्तु जिसकी आबादी 27.17 लाख तक पहुँच गई। यह रेलों के विकास के कारण ही सम्भव हो सका।
7. **डाक सेवा**—डाक सेवा का विकास रेल विकास पर निर्भर करता है। सन्देशवाहन एवं संचार व्यवस्था में वृद्धि भी रेलों द्वारा सम्भव हो सका है।
8. **निर्यात संवर्द्धन**—रेलों के द्वारा निर्यात होने वाली वस्तुएँ बन्दरगाहों के स्टेशनों तक आसानी से पहुँच जाता है।
9. **पर्यटन को प्रोत्साहन**—रेलवे द्वारा सरकुलर टुअर टिकट बेचे जाते हैं। जो अधिकाधिक 90 माह की अवधि के होते हैं। इससे रमणीक, धार्मिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थानों का भी विकास हुआ है।
10. **श्रम की गतिशीलता**—रेलों के विकास से श्रमों की गतिशीलता भी प्रभावित हुई हैं। जिससे उनके जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ा है।

जल परिवहन
(Water Transport)

जल परिवहन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का उस समय एक महत्त्वपूर्ण साधन था जब रेलों का जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय वायु परिवहन का कहीं नाम भी नहीं था और सड़क परिवहन अपनी प्रारम्भिक अवस्था में था।

जल परिवहन का आर्थिक महत्त्व (Economic Importance of Water transport)

जल परिवहन का आर्थिक महत्त्व निम्नलिखित है—

1. **परिवहन का सस्ता साधन**—यह सस्ता साधन इस कारण है; क्योंकि न इसमें सड़क बनानी पड़ती है न ही रेल की पटरी और न ही इन्हें कार्यशील बनाने के लिए कोई व्यय करना पड़ता है न पहियों की आवश्यकता होती है।
2. **कम पूँजीगत व्यय**—रेल मार्ग और सड़क मार्ग बनाने में लाखों का खर्च आता है, जबकि जल परिवहन के लिए कोई मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं होती है।
3. **अधिक क्षमता**—जलयान की भार खींचने की क्षमता रेल या सड़क परिवहन साधनों से अधिक होती है।
4. **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की जननी**—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास का सर्वप्रथम माध्यम जल परिवहन ही बना; क्योंकि अन्य साधनों से लागत तुलनात्मक रूप से अधिक आती है।

TOUCH 'n' PASS

5. **राष्ट्रीय सुरक्षा**—शत्रु के देश द्वारा पुलों, रेलमार्गों व सड़क मार्गों को नष्ट किया जा सकता है लेकिन जल मार्गों को नष्ट नहीं किया जा सकता है।
6. **एकमात्र साधन**—पहाड़ी, ढालों, घने वनों आदि स्थानों पर जल परिवहन के अतिरिक्त कोई और साधन नहीं है जिससे माल एवं यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके।
7. **थोक ढुलाई के लिए उपयुक्त**—सस्ता एवं सुविधाजनक होने के कारण वह थोक ढुलाई के लिए अति उपयुक्त है इससे समय की बचत भी हो जाती है।
8. **तटीय व्यापार की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण**—तटीय जल परिवहन का विकास इस बात से पुष्ट होता है कि भारत का समुद्रतटीय क्षेत्र काफी विशाल है।
9. **आर्थिक विकास**—देश से माल बाहर भेजा जा सकता है जिससे देश का आर्थिक विकास सम्भव हो जाता है।

जल परिवहन के प्रकार (Types Water transport)

1. **आन्तरिक जल परिवहन** (Inland water ways)—आन्तरिक जल परिवहन का विकास स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात सम्भव हो सका है। वर्तमान समय में भारत 3700 कि० मी० के लगभग आन्तरिक जल मार्ग का उपयोग करता है। यह सस्ता साधन होने के साथ-साथ कम शक्ति का प्रयोग भी करता है। भारी माल को कम व्यय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जा सकता है। भारी माल के साथ सामग्री भी आसानी से पहुँचाया जा सकता है। बाढ़ जैसी आपदा में यह कारगर बना रहता है। भारतीय नदियाँ चौड़ी होने के कारण बड़ी-बड़ी नावें चलाई जा सकती है। यहाँ की भूमि समतल होने के कारण नदियाँ भी समतल है।
2. **सामुद्रिक या जहाजरानी परिवहन** (Shipping)—जहाजरानी परिवहन देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। देश का लगभग 90% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। जहाँ पहली पंचवर्षीय योजना में देश की जहाजरानी की क्षमता 3.7 लाख GRT थी वहीं आज वर्तमान में यह 82.9 लाख हो गई। जहाजों की संख्या भी 94 से बढ़कर 707 हो गई।

प्र.5. भारत के आर्थिक विकास में वायु परिवहन व संचार का योगदान बताइए।
Explain the contribution of air transport and comunication in the economic development of India.

उत्तर

वायु परिवहन
(Air Transport)

भारत के लिए वायु परिवहन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सभी दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण एवं लाभकारी है। आधुनिक युग नवीनतम एवं क्रान्तिकारी भेंट है। जिससे भौगोलिक कठिन परिस्थितियों में भी कई हजारों किलोमीटर का सफर कुछ ही घण्टों में तय किया जा सकता है। वायु परिवहन का आर्थिक विकास से घनिष्ठ सम्बन्ध है। वायु परिवहन का आर्थिक विकास में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण योगदान है—

1. **भौगोलिक बाधाओं से मुक्ति**—चाहे समुन्द्र हो या रेगिस्तान, बर्फीला देश हो या नदी नाले, आज भी हजारों फुट की ऊँचाई पर भारतीय सेना अपने देश के प्रहरी का कार्य कर रही है।
2. **कृषि के विकास में सहायक**—वायु परिवहन के माध्यम से खेतों में कीटनाशक दवाइयों को छिड़ककर टिड्डियों व अन्य कीटाणुओं का नाश करता है। वर्ष 1954 से भारत इस सेवा का उपयोग कर रहा है।
3. **सुरक्षा एवं शान्ति**—देश की सुरक्षा के लिए वायु परिवहन एक अचूक अस्त्र की तरह है। इससे विदेशी आक्रमण रोकने के साथ-साथ दुश्मन देश को सबक भी सिखाया जा सकता है। भारत पाक युद्ध में इस परिवहन ने अपना कौशल दिखा दिया है।
4. **वाणिज्य का विस्तार**—बहुत ही अल्प समय में मूल्यवान नाशवान था कलात्मक वस्तुओं को देश से विदेशों में भेजना आसान हो गया है। इससे व्यावसायिक दृष्टि से लाभ प्राप्त होता है।
5. **स्वास्थ्य में सुधार**—विमान परिवहन की सहायता से दवाईयों का छिड़काव व जनसाधारण के स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकता है।

TOUCH 'n PASS

6. **वनों की रक्षा**—जब कभी वनों में भयंकर आग लग जाए, जिसे किसी भी माध्यम से रोकना कठिन है। ऐसे में वायु परिवहन से बचाव सम्भव हो जाता है।
7. **पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन**—इससे सरकार को रुपये में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अत: वायु परिवहन पर्यटन के माध्यम से भी आर्थिक विकास करने में सहायक है।

फेयर और विलियम्स के अनुसार, "मनुष्य को उपलब्ध विभिन्न साधनों में वायु परिवहन सबसे नवीनतम सबसे अधिक विकासशील, सबसे अधिक चुनौती देने वाला और हमारे आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन में सबसे अधिक क्रान्ति उत्पन्न करने वाला है।"

भारत में वायु परिवहन का विकास (Development of air transport in India)

भारत प्रयोगात्मक उड़ाने वर्ष 1919 में प्रारम्भ हुई थी, लेकिन आधुनिक विमान परिवहन का वास्तविक शुभारम्भ वर्ष 1927 में हुआ; जबकि भारत सरकार ने नागरिक उड्डयन की स्थापना की। वर्ष 1929 में ब्रिटेन, हॉलैण्ड एवं फ्रांस में प्रथम बार साम्राज्य वायुसेवा (Empire Air Services) के वायुयान भारत में उतरे। इसी समय इम्पीरियल एयरवेज नामक ब्रिटिश कम्पनी ने कराची व दिल्ली के बीच नियमित हवाई सेवा प्रारम्भ की।

1932–स्वदेशी सेवा, कराची व मद्रास के बीच टाटा बन्धुओं द्वारा शुरू की गई।

1933—इण्डियन नेशनल ऐयरवेज लिमिटेड नामक एक भारतीय संस्था बनी जिसने कराची व लाहौर तक विमान सेवा प्रारम्भ की

1935—टाटा ने बम्बई-त्रिवेन्द्रम की हवाई सेवा शुरू की।

1936—एयर सर्विसेज ऑफ इण्डिया लिमिटेड नामक एक तीसरी संस्था भारत में बनी जो 1939 में बन्द हो गयी । द्वितीय युद्ध के पश्चात वर्ष 1946 में कम्पनियों को अपनी उड़ान भारत में करने के लिए अनुज्ञापन (Licence) लेना अनिवार्य हो गया। वायु परिवहन लाइसेंस बोर्ड की स्थापना की गई।

1947—वायुमान सेवा की 27 कम्पनियाँ थी।

1948—विमान चालक प्रशिक्षण केन्द्र इलाहाबाद में स्थापित किया गया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात वायु सेवा के राष्ट्रीयकरण पर विचार किया जाने लगा। परिणामस्वरूप वर्ष 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। दो निगमों की स्थापना हुई—भारतीय विमान निगम (Indian Airlines Corporation) तथा अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय विमान निगम (Air India Intellectual Corporation) 26 जनवरी, 1981 से एक तीसरी सेवा वायुदूत के नाम से प्रारम्भ की गई।

वर्तमान में वायु सेवा की स्थिति—आज इस क्षेत्र में सार्वजनिक एवं निजी कम्पनियाँ दोनों ही हैं—

1. **सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियाँ**—इण्डियन एयरलाइन्स, एयर इण्डिया के विलय से "दि नेशनल एविऐशन कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड" बनी। मुख्यालय दिल्ली तथा निगमित कार्यालय मुम्बई में है। एयर इण्ड़िया का शुभंकर "महाराजा' ही इस विलय कम्पनी का शुभंकर है। इस क्षेत्र की अन्य कम्पनियाँ है—अयर इण्डिया चाटर्स लिमिटेड (AICL) तथा एलायन्स एयर।
2. **निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ**—जेट एयरवेज, सहारा एयर लाइंस, कम एवियेशन, स्पाइसजेट, गो एयरवेज, किंग फिशर, एयर लाइंस, पैरामाउण्ड एयरवेज तथा इण्टर ग्लोब एवियेशन (इण्डिगो) आदि। 60 प्रतिशत से अधिक ट्रैफिक अब इनके हाथ में है।

उड़ान क्लब एवं ग्लाइडिंग क्लब—इनकी संख्या 25 है जो अनियमित विमान सेवाएँ उपलब्ध कराती है।

भारतीय विमान पतन प्राधिकरण (AAI)—इसका गठन 1 अप्रैल, 1995 को राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण (ANI) एवं अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण (IAA) के विलय द्वारा हुआ। हवाई अड्डों के रखरखाव एवं संचालन की जिम्मेदारी इस प्राधिकरण की ही है।

पंचहंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड—देश के दुर्गम क्षेत्रों तथा ओ० एन० जी० सी० की सागर तटीय सेवाओं, राज्य सरकारों की सेवाओं तथा विशेष रूप से उत्तर पूर्व क्षेत्र में नियमित विमान सेवाएँ उपलब्ध कराता है।

हवाई अड्डे—देश में 127 हवाई अड्डे हैं। 15 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं।

TOUCH 'n' PASS

विमान निर्माण—वर्ष 1940 में भारत में बालचन्द हरिचन्द ने हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के नाम से एक विमान निर्माण करने का कारखाने खोला जिसे बाद में भारत सरकार व कर्नाटक सरकार ने मिलकर ले लिया। अब हवाई जहाज की यही एक कम्पनी है जो वायु सेना एवं नागरिक उड्डयन विभाग के लिए वायुयानों का निर्माण कर रही है।

वायु परिवहन की समस्याएँ एवं सुझाव—अधिक संचालन व्यय एवं पूर्णक्षमता का प्रयोग न होने के कारण वायु परिवहन का किराया अधिक होता है। कर्मचारियों एवं प्रबन्धकों के बीच समय-समय पर संघर्ष होने से हड़ताल होती है। नये विमान विदेशों से क्रय करने पर विदेशी मुद्रा कोष पर दबाव पड़ता है। भारत में अन्वेषण एवं प्रशिक्षण हेतु सुविधाएँ भी सीमित है।

सुझाव के रूप में वायुयान अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करे और मितव्ययिता को अपनाये, दुर्घटनाएँ कम करने का प्रयास करे एवं अन्वेषण और प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान दे, साथ ही साथ वायुयान निर्माण कार्य में तेजी भी लाये।

संचार
(Communication)

भारत में पहली संचार सेवा वर्ष 1837 में प्रारम्भ हुई। वर्ष 1854 में यहाँ 700 डाकखाने थे। इस समय 1,55035 डाकखाने हैं। संचार सेवा के प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं—

1. **डाकखाना**—आज जनता के लिए डाकखाना सेवा एक आधारशिला है। पोस्टकार्ड लिफाफा, अर्न्तदेशीय रजिस्टर्ड पत्र आदि इसके माध्यम हैं। प्रतिवर्ष डाकखाने से 1578 करोड़ पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाता है। इसके अलावा स्पीड़ पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक भी होते है। डाकखाना पत्र पत्रिकाओं आदि को हवाई जहाज, रेल, व रोडवेज की बसों के माध्यम से एक-दूसरे से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाता है। सुविधा व तुरन्त कार्यवाही के लिए, बड़े शहरों के लिए विशेष सुविधा देने के उद्देश्य से डाक को निम्न प्रकार में बाँटा गया हैं—
   (i) राजधानी चैनल (ii) मेट्रो चैनल
   (iii) ग्रीन चैनल (iv) व्यापारिक चैनल
   (v) बल्क मेल चैनल (Bulk Mail Channel)
   (vi) पीरिओडीकल चैनल (Periodical Channel)

   डाकखाने के माध्यम से अपने पत्र व छोटे-छोटे माल व नमूने के पैकिट भी शीघ्रता से भेजे जा सकते हैं। जिसके लिए डाकखाना सामान्य दर से कहीं अधिक दर वसूल करता है। लेकिन साथ ही यह वायदा करता है कि पत्र मात्र 48 घण्टे या निर्धारित समय सीमा में पहुँचा दिया जायेगा। जिसके लिए निम्न सेवाएँ प्रदान की है—
   (i) स्पीड पोस्ट
   (ii) एक्सप्रेस सेवा
   (iii) ई-पोस्ट एवं ई-बिल पोस्ट
2. **तार**—भारतीय तार विभाग विश्व की सबसे पुरानी सरकारी सार्वजनिक उपयोगिता है। भारत में तारघरों की संख्या जो वर्ष 1951 में 8500 थी बढ़कर 30,000 हो गई है। फोनोग्राम सेवा टेलेक्स सेवा प्रत्यक्ष ट्रंक डायलिंग जैसे सुविधाएँ अब सामान्य जनता को उपलब्ध है।
3. **दूरसंचार**—वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा के लिए दूरसंचार अब तक महत्त्वपूर्ण आदान हैं और इससे ही भारत अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसके द्वारा देश के कोने में संचार के लाभ पहुँचाए जा सकते हैं और यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में भी लाभदायक हो सकती है।
4. **टेली संचार नीति**—टेली संचार आधार संरचना को उपलब्ध कराने और उसके प्रबन्ध के बारे में काफी अस्पष्टता थी। टेली संचार सेवा विभाग और टेली संचार क्रियाओं का विभाग दो सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले विभाग थे। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) और भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) जो दिल्ली और मुम्बई में बुनियादी टेलीफोन सेवाएँ उपलब्ध कराती थी। MTNL और शेष देश में BSNL यह सेवा उपलब्ध कराती है।
   BSNL दूर संचार क्षेत्र के सेवा प्रदान करने वाले दो विभाग का निगमीकरण कर दिया गया है।
5. **फैक्स**—यह एक प्रकार से लिखित सन्देश प्राप्त करने या भेजने का साधन है। इसके लिए एक फैक्स मशीन की आवश्यकता होती है। जिसे टेलीफोन नम्बर से जोड़ देते हैं। यह मशीन सन्देश को कागज पर प्राप्त कर छाप देती है। साथ ही भेजने वाले का टेलीफोन नम्बर, नाम, पता व समय भी लिख देती है। इसमें टेलीफोन का व्यय लिया जाता है।

TOUCH 'n' PASS

6. **ई-मेल**—कम्प्यूटर युग में ई-मेल के द्वारा सन्देश को विश्व में कहीं भी भेजा जा सकता है। इसके लिए इन्टरनेट की सुविधा होनी चाहिए। संचार का यह साधन वर्तमान में अति लोकप्रिय साधन है।
7. **इण्टरनेट**—इण्टरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम इण्टरनेट देश-विदेश के लोगों के बीच सम्पर्क स्थापित कर सकता है। विश्व में होने वाली कोई भी घटना को देखा जा सकता है। इण्टरनेट द्वारा विश्वभर के कम्प्यूटर सूचना केन्द्रों से प्राप्त सूचनाओं व आँकड़ों को अपनी भाषा में बड़ी सरलता से प्राप्त किया जा सकता हैं। इस विधि को इण्टरनेट प्रोटोकॉल (Internet Protocol) कहा जाता है।

प्र.6. भारत में नियोजन तकनीकी का वर्णन विस्तार से कीजिए।
Describe in detail the planning technique in India.

उत्तर

भारत में नियोजन तकनीकी
(Planning Techniques in India)

भारत के आर्थिक विकास के लिए 1 अप्रैल, 1951 से नियोजन प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। प्रारम्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नियोजन तकनीकी के निर्धारण की समस्या अर्थव्यवस्था को धक्का देने के लिए अत्यन्त आवश्यक थी। लेकिन अब भारत की अर्थव्यवस्था की समस्याएँ तथा नियन्त्रण व्यवस्था के लिए नियोजन की तकनीकी में परिवर्तन करना भी जरूरी हो गया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति का आकलन करते हुए उपलब्ध संसाधनों का अनुमान लगाया जाता रहा है तथा संसाधनों के कुशलतम प्रयोग अधिकतम उत्पादन करने के लिए किया गया। इसके साथ सामाजिक तथा आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वित्तीय तथा भौतिक दृष्टिकोण पर ध्यान दिया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिए नियोजन की तकनीकी को यथासम्भव परिवर्तन भी किया गया है। भारत में केन्द्र सरकार की योजना नीति के साथ-साथ राज्य स्तर पर भी नियोजन की प्रक्रिया को जारी रखा गया है। नियोजित अर्थव्यवस्था से खुली तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने पर नियोजन की तकनीकी में आवश्यक सुधार भी किया गया है। आप आगे के बिन्दुओं के अध्ययन से नियोजन की तकनीकी को आसानी से समझ सकते हैं।

ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों तथा शासन पद्धति के कारण नियोजन के प्रारम्भ में उन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ा जो नियोजन से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था गरीबी तथा बेरोजगारी का सामना कर रही थी। नियोजन के प्रारम्भ में कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए संस्थागत परिवर्तनों वाली नियोजन की तकनीकी अपनायी गई जिसका कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ बेरोजगारी तथा गरीबी से छुटकारा पाने में सहायता मिल सकी। कृषि उत्पादन के लिए सामान्यत: श्रम का अधिक प्रयोग करने वाली तकनीकी के साथ कृषि की उत्पादकता तथा गुणवत्ता में सुधार करना भी नियोजन की तकनीकी के लिए आधार बनाया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था को तीव्र गतिशील बनाने के लिए और कृषि को अधिक श्रम का प्रयोग करने के योग्य बनाया गया। वही नवीन तकनीकी का प्रयोग करके देश में उद्योगों का विकास करना भी नियोजन की प्रक्रिया में शामिल किया गया तथा कृषि तथा उद्योग की आत्मनिर्भरता के द्वारा देश का आर्थिक विकास तेज गति से हो सके।

भारतीय अर्थव्यवस्था की मिश्रित प्रकृति होने के कारण सरकार द्वारा निजी तथा सार्वजनिक यन्त्र की विनियोग प्रवृत्ति को भी पूर्ण रूप से नियन्त्रित नहीं कर सकी। परिणामस्वरूप देश के विनियोजन की तकनीकी में परिवर्तन आना अत्यन्त आवश्यक था। बेरोजगारी तथा गरीबी दूर करने के लक्ष्य के साथ निजी क्षेत्र श्रम प्रधान तकनीकी का प्रयोग करने के समर्थ नहीं हो सकता। वही विदेशी व्यापार में सुधार के लिए भी सार्वजनिक क्षेत्र में नियोजन की प्रकृति में बदलाव लाना अत्यन्त आवश्यक रहा।

औद्योगिक आधार कायम करने के लिए विकास की प्रक्रिया चालू करने और औद्योगिक राष्ट्रों पर हमारी निर्भरता कम करने के लिए यह उचित ही पाया गया कि सरकार स्वयं पूँजी वस्तु क्षेत्र के लिए नियोजन में स्थान दिया जाये ताकि उपेक्षित क्षेत्रों का भी विकास हो सके। लोहा-इस्पात, भारी रसायन, भारी इन्जीनियरिंग परमाणु संयन्त्र, उर्वरक, जहाज निर्माण, मशीन, उपकरण, वायुयान निर्माण आदि के क्षेत्रों का विकास करने के लिए नियोजन की तकनीकी में भी परिवर्तन लाया गया। सामाजिक तथा अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में भी सार्वजनिक क्षेत्र की सहभागिता को नकारा नहीं जा सकता। इन भारी उद्योग तथा विदेशी व्यापार के विकास एवं विस्तार के लिए भी निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नियोजन में बदलाव लाया गया।

नियोजन तकनीकी की आवश्यकता (Requirement of Planning Technique)—भारत की नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत एक उपयुक्त नियोजन तकनीकी की आवश्यकता समय-समय पर महसूस की गई है जिसे निम्नवत रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। आपको ज्ञात होना आवश्यक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक विषमताओं की विसंगतियों का सामना करती रही

है। यह विषमता सम्बन्धी विसंगतियाँ सरकार की उपर्युक्त नियोजन तकनीकी को अपनाकर ही दूर की जा सकती हैं। इस आर्थिक विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया जाना अत्यन्त आवश्यक होगा। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था में एक ओर संसाधनों का शोषणात्मक प्रयोग हो रहा है तो दूसरी ओर उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण कुशलता के साथ प्रयोग किया जाना अभी बाकी है। जिसे आर्थिक नियोजन की उपयुक्त तकनीकी द्वारा ही सम्भव बनाया जा सकता है। आर्थिक नियोजन के एक लम्बे समय के बाद भी भारत में गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक, आर्थिक न्याय की कमी, अशिक्षा, श्रमिकों में अकुशलता जैसी अनेक समस्याएँ विद्यमान है। जिसके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि एक समन्वयकारी नियोजन की तकनीकी अपनायी जाये जो भारतीय अर्थव्यवस्था में व्याप्त उक्त समस्याओं का यथाशीघ्र निराकरण किया जा सके।

नियोजन तकनीकी की उपलब्धि—प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से अब तक दस पंचवर्षीय योजनाएँ पूर्ण हो चुकी है तथा ग्यारहवीं योजना पूर्ण होने के कगार पर है। भारत में अपनायी गयी नियोजन की तकनीकी के माध्यम से जो उपलब्धियाँ अर्जित की गई उनका विश्लेषण निम्नवत किया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय देश खाद्यान्न तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के लिए आत्मनिर्भर नहीं था, आर्थिक नियोजन को अपनाकर वर्तमान में देश खाद्यान्न तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है। कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि से सम्बन्धित उद्योगों का भी तीव्र विकास सम्भव हुआ है। आपको यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि भारत में बढ़ती जनसंख्या के बाद भी प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय में लगातार तीव्र गति से वृद्धि हुई है। योजनाकाल में देश के औद्योगीकरण का तीव्र प्रसार हुआ है। आधारभूत उद्योगों की स्थापना के साथ-साथ औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादकता होने में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई तथा भारत की औद्योगिक आत्मनिर्भरता से काफी वृद्धि हुई है। देश में कोयला, इस्पात, कागज, सीमेण्ट, साइकिल, नाइट्रोजन खाद, मशीन तथा औजारों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई तथा इन अंगों में आत्म निर्भरता की दिशा में सार्थक प्रयास किये गये हैं।

योजनाकाल में भारत में शिक्षा तथा गुणवत्ता एवं विस्तार के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा के विकास एवं विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया तथा उल्लेखनीय सफलताएँ प्राप्त की गई। आर्थिक सुधारों के समय तक देश में सार्वजनिक अंग का विस्तार किया गया जिसमें विनियोजित पूँजी में भी अत्यधिक वृद्धि की गई। वर्ष 1991 के बाद से निजी अंग के विस्तार एवं विकास की दिशा में अत्यधिक कार्य किया गया। देश में आर्थिक स्थिरता के साथ विकास किया गया। विदेशी व्यापार तथा ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य किये गये हैं। कल्याणकारी योजनाओं के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ अर्जित की गई है। देश में सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं का विस्तार किया गया है।

प्र.7. बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था में नियोजन की विवेचना कीजिए।
Discuss planning in a market-oriented economy.

उत्तर

बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था में नियोजन
(Planning in a Market-oriented Economy)

आपको यह मालूम होगा कि भारत में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग कुशलतम तरीके से आवश्यक है जो बाजार व्यवस्था के माध्यम से सम्भव है लेकिन बाजारोन्मुख भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नियोजन समस्या भी अपना अगला महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आर्थिक सुधारों के प्रारम्भिक समय में प्रारम्भ होने वाली आठवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार "यद्यपि बाजार व्यवस्था माँग (क्रयशक्ति द्वारा समर्पित) और पूर्ति के बीच सन्तुलन लाने में समर्थ है परन्तु यह आवश्यकता और पूर्ति के बीच सन्तुलन लाने में असमर्थ हैं। इस लिए इस क्षेत्र में आयोजन का महत्त्व बना रहेगा।

बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था की प्रकृति (Nature of market-oriented economy)—बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्द्धात्मक शक्ति बढ़ाने के लिए नियोजन की प्रक्रिया में परिवर्तन लाना अत्यन्त आवश्यक समझा गया। औद्योगीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करते हुए तकनीकी का चुनाव इस प्रकार से किया गया कि उत्पादकता घटाये बिना श्रम का प्रयोग अधिक से अधिक किया गया तथा अर्थव्यवस्था को रोजगार सृजित करने वाली बनाया गया।

योजना आयोग के अनुसार—'उच्च विकास दर का होना आवश्यक तो है परन्तु रोजगार वृद्धि के लिए यह आवश्यक नहीं है। अधिक रोजगार क्षमता वाले क्षेत्रों के योगदान से प्राप्त विकास ढाँचा और श्रम का अधिक प्रयोग करने वाली उत्पादन तकनीकी से रोजगार पैदा करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। यद्यपि दक्षता, उत्पादकता स्तर और प्रतिस्पर्द्धा कम किये बिना, तकनीकों को बदलने का कार्य सरल नहीं हैं। तथापि यह स्वीकार करना होगा अर्थव्यवस्था के बडे भाग कृषि क्षेत्र, असंगठित विनिर्माण क्षेत्र सहित सभी उत्पादन क्षेत्रों में उत्पादकता-स्तर में सुधार लाने की आवश्यकता है।"

बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को बनाये रखने के लिए नियोजन की प्रक्रिया में काफी उदारता बरती गयी। अर्थव्यवस्था से राज्य की नियन्त्रणकारी शक्तियों को काफी ढीला किया गया तथा नियोजन की प्रक्रिया में निजी क्षेत्रों की सहभागिता को शामिल किया गया। नियोजन प्रक्रिया में घरेलू संसाधनों का अनुकूलतम निजी क्षेत्र द्वारा करने पर जोर दिया गया। बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था में नियोजन की प्रक्रिया के लक्ष्य अल्पकालीन न होकर दीर्घकालीन निर्धारित किये गये तथा उसी प्रकार वित्तीय तथा भौतिक संसाधनों का आवंटन इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के आधार पर किया गया है। खुली अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय आयोजन को महत्त्वपूर्ण बनाया गया है। राज्य द्वारा सामाजिक सेवाओं का विस्तार करने वाली नियोजन को अपनाया गया है। वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था को रोजगार सृजित करने के लिए श्रम की गुणवत्ता को विकसित करने वाली नीतियों को आधार बनाया गया है।

यहाँ पर यह स्पष्ट करना अत्यन्त आवश्यक होगा बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका में कमी करके तथा बाजार तन्त्र व्यवस्था की कुशलता के साथ नियोजन द्वारा समानता के साथ विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत आयोजन का महत्त्व उन क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया है। जहाँ पर निजी क्षेत्र के अन्तर्गत आयोजन लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता। अर्थव्यवस्था में आर्थिक कुशलता बढ़ाने तथा प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता बढ़ाई गई है। लेकिन भारत में गरीबी, बेरोजगारी तथा स्वास्थ्य तथा शिक्षा सम्बन्धी अनेक समस्याओं को देखते हुए नियोजन की तकनीकी तथा आयोजन की प्रकृति को केवल निजी क्षेत्र के हित में ही नहीं देखा जहा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ निजी क्षेत्र के सन्दर्भ में आयोजन पूर्णरूप से कारगार सिद्ध नहीं हो सकता है। बाजार व्यवस्था पर्यावरण वन, पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए कभी भी महत्त्वपूर्ण सिद्ध नहीं हो सकती; जबकि यह क्षेत्र भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए अत्यन्त ही महत्त्व का माना गया है। मानव विकास रिपोर्ट 1991 में भी निजीकरण को अर्थव्यवस्था की समस्याओं का समाधान मानने से इंकार किया है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था एवं नियोजन (Mixed economy and planning)—भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसे बिना नियोजित व्यवस्था के संचालित करने की कल्पना नहीं की जा सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक क्षेत्र लाभ-हानि की संकल्पना से दूर सामाजिक हित पर आधारित है तो दूसरा क्षेत्र लाभ-हानि की संकल्पना से बिल्कुल दूर नहीं रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सहअस्तित्व वाला विकास नियोजन की एक उपयुक्त तकनीकी के अभाव में सम्भव नहीं हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र तीन रूपों में कार्यरत पाये गये हैं, पहला क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में कार्यशील है। पूर्ण स्वामित्व एवं नियन्त्रण राज्य के हाथ में है, इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र का हस्तक्षेप किसी भी सीमा तक स्वीकार नहीं है, दूसरा क्षेत्र पूर्णत: निजी क्षेत्र के स्वामित्व के अधीन है। लेकिन इस पर राज्य का सामान्य नियन्त्रण क्रियाशील रहता है तीसरा क्षेत्र निजी तथा सार्वजनिक रूप में सहअस्तित्व के रूप में कार्य करता है।

अर्थव्यवस्था के इन तीनों क्षेत्रों के नियन्त्रण एवं विकास के लिए एक व्यवस्थित सुसंगठित नियोजन की तकनीकी अपनाया जाना अत्यन्त ही आवश्यक समझा गया है। आपको यहाँ पर यह स्पष्ट करना अत्यन्त आवश्यक होगा कि निजी अंग को सरकार के नियन्त्रण से बाहर नहीं छोड़ा जा सकता है; क्योंकि ऐसा करने से सामाजिक हितों को सुरक्षित रख पाना अत्यन्त ही मुश्किल होगा जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लाभों से दूर ही रखा जा सकता है, जो आर्थिक विकास के लिए उपर्युक्त नहीं कहा जा सकता है।

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था के मिश्रण को समान रूप से संचालित करना एक कोई सरल कार्य नहीं है। भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था में एक उपयुक्त नियोजन की तकनीकी को अपनाने से पूर्व निम्न तथ्यों पर ध्यान देना अत्यन्त ही आवश्यक समझा जा सकता है—

1. सरकार द्वारा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों द्वारा किस सीमा तक सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्रियाशील कर सकती है ताकि दोनों क्षेत्रों में उचित समन्वय बना रहे तथा आर्थिक विरोधाभास की स्थिति नहीं बन सके।
2. सरकार द्वारा आर्थिक विकास को तीव्र करने तथा विनियोग सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय किस प्रकार लिये जाये ताकि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का हित भी सुरक्षित रह सके।
3. किसी भी एक क्षेत्र के विकास को दूसरे क्षेत्र की हित हानि के आधार पर न करने के लिए बाध्य किया जाये।

मिश्रित अर्थव्यवस्था में वित्तीय संस्थाओं पर राज्य सरकार का प्रभावी नियन्त्रण है ताकि वित्तीय व्यवस्था का किसी एक विशेष क्षेत्र के हित में नहीं हो सके। वित्तीय व्यवस्था किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास का आधार होती है। सरकार द्वारा एकाधिकार विकास पर रोक लगाने के लिए अर्थव्यवस्था को प्रतियोगात्मक बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास किया गया है। ताकि पूँजीपतियों

द्वारा जनता का किसी भी सीमा तक शोषण नहीं हो सके। लेकिन यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि पूँजीवादी ताकतों का विस्तार लाभ ही उच्च दर पर निर्भर है जो जनता के शोषण का ही परिणाम कहा जा सकता है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था के निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र को सुरक्षा के लिए उचित मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियों का निर्धारण सरकार द्वारा किया गया है जो आर्थिक अस्थिरता को रोकने का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपकरण कहे जाते हैं, जिसका अन्तर्विरोधी अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान निर्धारित किया गया है। सार्वजनिक विनियोग का एक बड़ा भाग ऐसे क्षेत्र में किया गया है जहाँ पर निजी क्षेत्र द्वारा विनियोग किया जाना सक्षमता से बाहर है। कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए उचित तथा सस्ते मूल्य पर सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, इसके साथ जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा नियोजन की तकनीकी से अर्न्तसम्बन्धित हैं। श्रम के विकास के लिए शिक्षा एवं तकनीकी प्राविधि को विकसित करने के लिए महत्त्वपूर्ण उपाय किये गये हैं जो सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही अंगों के विकास के लिए अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण हैं। श्रम की गुणवत्ता का विकास एवं विस्तार के लिए सार्वजनिक संस्थाओं के साथ-साथ निजी अंग की संस्थाओं की भी सहयोगिता सुनिश्चित की गई है ताकि नियोजन की बदलती तकनीकी के साथ पूर्ण रूप से समन्वय स्थापित किया जा सके। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संस्थाओं के आधार पर यह भी सुनिश्चित किया गया है कि आवश्यक कला वाले क्षेत्रों में नियोजन की श्रम प्रधान या पूँजी प्रधान तकनीकी को अपनाया जाये ताकि अर्थव्यवस्था की समस्याओं का समाधान किया जा सके।

जान ड्रेज और **अमत्यसेन** ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया है कि "जबकि व्यापार के प्रयोग के मार्ग में अवरोधकों को हटाने से कई प्रकार के अवसरों के विस्तार में महत्त्वपूर्ण लाभ होगा, इन अवसरों के व्यवहारिक प्रयोग के लिए कुछ प्रकार की मूल योग्यताएँ जरूरी हैं। जिनमें साक्षरता और शिक्षा, मूल स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा लिंग रूपी समानता, भू-अधिकार और स्थानीय लोकतन्त्र शामिल हैं। इन योग्यताओं का तीव्र विस्तार महत्त्वपूर्ण रूप में ऐसे सार्वजनिक कार्य पर निर्भर करता है, जिसकी भारत में अत्यधिक उपेक्षा की गई है और यह परिस्थिति हाल के सुधारों से पूर्व और बाद के काल में बनी हुई है। वास्तविक मुद्दा शेर को पिंजरे से बाहर निकालने का है और इसके बाद उदारीकरण की हदें पार करने की आवश्यकता है।

आपको उक्त विश्लेषण से यह भली भाँति स्पष्ट हो गया होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की निर्धनता, अशिक्षित, निम्न स्वास्थ्य, सामाजिक अन्याय, आर्थिक विषमता, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से बाहर निकालने के लिए बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था पर पूर्ण निर्भरता के साथ आयोजन को बदलना होगा।

प्र.8. भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका विस्तार से बताइए।

Explain in detail the role of multinational corporations in the indian economy.

उत्तर

भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका
(Role of Multinational Corporations in Indian Economy)

वर्ष 1991 से पहले बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में ज्यादा भूमिका नहीं निभाई थी। सुधार से पहले की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था सार्वजनिक उद्यमों पर हावी थी। आर्थिक शक्ति औद्योगिक नीति की एकाग्रता को रोकने के लिए वर्ष 1956 ने निजी कम्पनियों को एक बिन्दु से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। परिभाषा के अनुसार बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ बहुत बड़ी थी और कई देशों में काम करती थी; जबकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में विकास और व्यापार को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में ज्यादा भूमिका नहीं निभाई थी। जहाँ आयात-प्रतिस्थापन विकास रणनीति का पालन किया गया था। वर्ष 1991 के बाद से निजी विदेशी पूँजी के उदारीकरण और निजीकरण की औद्योगिक नीति को अपनाने के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के लिए महत्त्वपूर्ण माना गया है।

चूँकि विदेशी पूँजी और निवेश का बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय निगम है, इसलिए उन्हें कुछ विनियमों के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था में काम करने की अनुमति दी गई है। सुधार के बाद की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रति नीति में बदलाव के महत्त्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं—

1. **विदेशी निवेश को बढ़ावा देना**—हाल के वर्षों में, विकासशील देशों को बाहरी सहायता में कमी आई है। ऐसा इसलिए है। क्योंकि दाता विकसित देश विकासशील देशों की सहायता के रूप में अपने सकल घरेलू उत्पाद के बड़े अनुपात के साथ भाग लेने के लए तैयार नहीं हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ भारत में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए विदेशी पूँजी की आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाट सकते हैं।

वर्ष 1991 के बाद से उदारीकृत विदेशी निवेश, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को विभिन्न उद्योगों या परियोजनाओं के लिए तय अलग-अलग छत के अधीन भारत में निवेश करने की अनुमति देता है। हालाँकि, कुछ उद्योगों में 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयाँ (EOUs) लगाई जा सकती है। यह ध्यान दिया जा सकता है, घरेलू निवेश की तरह विदेशी निवेश की भी देश में आय और रोजगार पर कई गुना प्रभाव पड़ता है।

उदाहरण के लिए, मारुति उद्योग निर्माण कारों में सुजुकी फर्म के निवेश का प्रभाव मारुति उद्योग के श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए आय और रोजगार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे आगे भी जाता है। कई श्रमिक डीलर फर्मों में कार्यरत है जो मारुति कारों को बेचते हैं।

इसके अलावा, कई मध्यवर्ती सामान भारतीय आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मारुति उद्योग को आपूर्ति किए जाते हैं और इसके लिए कई श्रमिकों को उनके द्वारा मारुति कारों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न भागों और घटकों का निर्माण करने के लिए नियोजित किया जाता है। इस प्रकार उनकी आय भारत में मारुति उद्योग लिमिटेड में एक जापानी बहुराष्ट्रीय कम्पनी द्वारा निवेश से बढ़ जाती है।

2. **गैर-ऋण सृजन पूँजी प्रवाह**—भारत में पूर्व-सुधार की अवधि में जब बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को हतोत्साहित किया गया था, हम बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) पर बहुत अधिक निर्भर थे। जो ऋण सृजन पूँजी प्रवाह था। इससे बाहरी ऋण का बोझ बढ़ा और ऋण सेवा भुगतान हमारे चालू खाता प्राप्तियों के 35 प्रतिशत के खतरनाक आँकड़े तक पहुँच गया।

इसने हमारे ऋण दायित्वों को पूरा करने की हमारी क्षमता के बारे में सन्देह पैदा किया और भारत से पूँजी की एक उड़ान आई और इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1991 में भुगतान संकट का सन्तुलन बना रहा। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश गैर-ऋण सृजन पूँजी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है जिससे हम दायित्व से बच सकते हैं इसके अलावा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा निवेश का लाभ इस तथ्य में निहित है कि गैर-ऋण पूँजी की सर्विसिंग तभी शुरू होती है जब एमएनसी फर्म प्रत्यावर्तन के लिए कमाने के चरण तक पहुँचती है। इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ तनाव के दबाव को कम करने और भारत के सन्तुलन पर एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

3. **प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण**—बहुराष्ट्रीय निगमों की एक अन्य महत्त्वपूर्ण भूमिका यह है कि वे उच्च परिष्कृत प्रौद्योगिकी को विकासशील देशों को हस्तान्तरित करते हैं जो श्रमिक वर्ग की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक है और हमें उच्च प्रौद्योगिकी की आवश्यकता वाले नए उत्पादक उपक्रम शुरू करने में सक्षम बनाते हैं। जब भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपनी सहायक उत्पादन इकाइयाँ या संयुक्त उद्यम इकाइयाँ स्थापित करती हैं वे न केवल नई तकनीक और मशीनरी का उपयोग करके नई तकनीक का आयात करती है। बल्कि नए उपकरणों और मशीनरी का उपयोग करने के लिए कौशल और तकनीकी जानकारी भी प्राप्त करती है।

नतीजतन, भारतीय श्रमिकों और इंजीनियरों को नई बेहतर तकनीक और इसे इस्तेमाल करने का तरीका पता चला। भारत में, कॉर्पोरेट क्षेत्र अनुसन्धान और विकास पर केवल कुछ ही संसाधन खर्च करता है। यह विशाल बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट फर्म (MNC) है जो नई तकनीकों के विकास पर बहुत अधिक खर्च करते हैं और विकासशील देशों को उनके द्वारा विकसित नई तकनीक को स्थानान्तरित करके बहुत लाभान्वित कर सकते हैं। इसलिए, बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ भारतीय अर्थव्यवस्था के तकनीकी उन्नयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

4. **निर्यात को बढ़ावा देना**—पूरी दुनिया में व्यापक लिंक और कुशलता से उत्पादों का उत्पादन और इसलिए कम लागत के साथ बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ उस देश के निर्यात को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है जिसमें वे निवेश करते हैं। उदाहरण के लिए, हाल के वर्षों में चीन के निर्यात में तेजी से विस्तार चीनी उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा किए गए बड़े निवेश के कारण है।

ऐतिहासिक रूप से भारत में, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने बड़े पैमाने पर निवेश किया, जिनके उत्पादों का उन्होंने निर्यात किया। हाल के वर्षों में, जापानी ऑटोमोबाइल कम्पनी सुजुकी ने भारत सरकार के साथ संयुक्त सहयोग से मारुति उद्योग में एक बड़ा निवेश किया। मारुति कारों को न केवल भारतीय घरेलू बाजार में बेचा जा रहा है। बल्कि विदेशों में बड़ी संख्या में निर्यात किया जाता है।

TOUCH 'n' PASS

हाल ही में जब तक, भारत में निवेश के लिए एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी को अनुमति देते समय, सरकार ने इस शर्त के अधीन अनुमति दी थी कि सम्बन्धित बहुराष्ट्रीय कम्पनी भारत के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए उत्पाद का निर्यात करेगी।

हालाँकि पेप्सी के मामले में एक प्रसिद्ध कोल्डड्रिंक मल्टीनेशनल कम्पनी है; जबकि वर्ष 1961 में भारत में पेप्सी कोला का उत्पादन करने के लिए उत्पाद लाइसेंस प्राप्त करने के लिए यह अपने उत्पाद का एक निश्चित अनुपात निर्यात करने के लिए सहमत हो गया था। लेकिन बाद में इसने ऐसा करने में असमर्थता व्यक्त की। इसके बजाय, यह अन्ततः चीजों का निर्यात करने के लिए सहमत हो गया, जैसे कि यह चाय का उत्पादन करता था।

5. **अवसंरचना में निवेश**—वित्तीय संसाधनों पर एक बड़ी कमान विश्व स्तर पर और भारत के अन्दर संसाधनों को बढ़ाने की उनकी बेहतर क्षमता के साथ, यह कहा जाता है कि बहुराष्ट्रीय निगम बिजली परियोजनाओं, हवाई अड्डों और पदों के आधुनिकीकरण, दूरसंचार जैसे बुनियादी ढाँचे में निवेश कर सकते हैं।

बुनियादी ढाँचे में निवेश से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और भारत की अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा बुनियादी ढाँचे में निवेश से उत्पन्न बाहरी अर्थव्यवस्थाएँ स्वदेशी निजी क्षेत्र द्वारा निवेश में भीड़ बढ़ाएगी और इसलिए आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगी।

उपरोक्त के मद्देनजर, वर्तमान यूपीए सरकार का सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम भी प्रदान करता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को प्रोत्साहित किया जाएगा और सक्रिय रूप से माँग की जाएगी, विशेष रूप से (i) बुनियादी ढाँचे, (ii) उच्च प्रौद्योगिकी और (iii) निर्यात के क्षेत्रों में और (iv) जहाँ घरेलू सम्पत्ति और रोजगार एक महत्त्वपूर्ण पैमाने पर बनाए जाते हैं।

बहुराष्ट्रीय निगमों का आलोचना (Criticism of Multinational Corporations)

हाल के वर्षों में बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत और अन्य विकासशील देशों में काफी बढ़ा है। हाल के वर्षों में बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा निवेश में यह भारी वृद्धि कारकों (1) से प्रेरित हैं, औद्योगिक नीति के उदारीकरण ने निजी क्षेत्र को अधिक भूमिका प्रदान की, (2) अर्थव्यवस्था को खोलने और विदेशी व्यापार और पूँजी प्रवाह के उदारीकरण। इस आर्थिक माहौल में बहुराष्ट्रीय निगम जो वैश्विक मुनाफे की तलाश में हैं, उन्हें विकासशील देशों में निवेश करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देशों को कई लाभ पहुँचाता है लेकिन आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से कई सम्भावित खतरे और नुकसान हैं। इसलिए भारत और अन्य विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका की कई आधारों पर आलोचना की गई है। हम बहुराष्ट्रीय निगमों के खिलाफ लगाए गए कुछ आलोचनाओं के बारे में नीचे चर्चा करते हैं—

बाजार पर कब्जा—1. सबसे पहले, यह आरोप लगाया जाता है कि बहुराष्ट्रीय निगम अपनी पूँजी का निवेश करते हैं और अपने उत्पादों को बेचने और उन देशों के घरेलू बाजारों पर कब्जा करने और संचालित करने के लिए स्थानीय कम्पनियों के साथ मिलकर अपनी विनिर्माण इकाइयों का पता लगाते हैं। अपने विशाल संसाधनों और प्रतिस्पर्धा ताकत के साथ, वे अपनी प्रतिस्पर्धी कम्पनियों को मात दे सकते हैं।

उदाहरण के लिए, अगर भारत में कॉरपोरेट मल्टीनेशनल फर्मों को वर्तमान में छोटे और मंझोले उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों को बेचने या उत्पादन करने की अनुमति है तो उत्तरार्द्ध प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होंगे और इसलिए उन्हें व्यापार से बाहर कर दिया जाएगा। इससे देश में रोजगार के अवसरों में कमी आएगी।

2. **पूँजी-गहन तकनीकों का उपयोग**—यह देखा गया है कि आधुनिक विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ती पूँजी की तीव्रता भारत के औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की धीमी वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। इन पूँजी-गहन तकनीकों को बड़ी घरेलू कम्पनियों द्वारा आयात किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में इनका उपयोग बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया जा रहा है जो भारत में निवेश करने पर अपनी तकनीक लाते हैं। इस कारक पर जोर देते हुए, **थिरवाल** सही कहते हैं, "इस मामले में प्रौद्योगिकी अनुपयुक्त हो सकती है; क्योंकि प्रौद्योगिकी का कोई स्पेक्ट्रम नहीं है या अनुमति चयन नहीं किया गया है, लेकिन क्योंकि उपलब्ध प्रौद्योगिकी वैश्विक निवेश कम्पनियों द्वारा निवेश कर रही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उद्देश्यों को अधिकतम कर रही है कम विकसित देश चिंतित हैं।

3. **प्रोत्साहन उपभोग के लिए प्रोत्साहन**—बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के निवेश से भारत में निवेश में समग्र वृद्धि होती है लेकिन यह आरोप लगाया जाता है कि वे अर्थव्यवस्था में विशिष्ट खपत को प्रोत्साहित करते हैं। ये कम्पनियाँ पहले से ही अच्छे लोगों की इच्छा को पूरा करती है। उदाहरण के लिए, भारत में बहुत महंगी कारें (जैसे सिटी होंडा, हुंडई की एक्सेंट, मर्सिडीज, ओपल इस्ट्रा इत्यादि) एयर कण्डीशनर महंगे लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, महंगे फ्रिज और प्लाज्मा टीवी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा निर्मित या बेचे जा रहे हैं।
भारत जैसे गरीब देश के लिए इस तरह के सामान काफी अनुचित है। इसके अलावा, उनकी खपत का दूसरों की खपत पर एक प्रदर्शन प्रभाव पड़ता है। यह उपभोग करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है और देश की बचत में वृद्धि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।
4. **अप्रचलित प्रौद्योगिक का आयात**—बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की एक और आलोचना इस आधार पर है कि अप्रचलित मशीनों और प्रौद्योगिकी का आयात करते हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कुछ आयातित प्रौद्योगिकियाँ भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थितियों के लिए अनुपयुक्त हैं। यह आरोप लगाया जाता है कि भारत को अप्रचलित प्रौद्योगिकी के लिए डंपिंग ग्राउण्ड बनाया गया है। इसके अलावा, बहुराष्ट्रीय निगम भारतीय कारक-बन्दोबस्ती की स्थिति के अनुकूल स्थानीय तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए भारत में अनुसन्धान और विकास (आर एन्ड डी) का कार्य नहीं करते हैं। इसके बजाय, वे आर एण्ड डी गतिविधि को अपने मुख्यालय में केन्द्रित करते हैं।
5. यह पाया गया है कि भारत जैसे विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा निवेश आमतौर पर निर्यात प्रोत्साहन के बजाय घरेलू बाजारों पर कब्जा करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, अपने देश में सख्त पर्यावरण नियन्त्रण उपायों से बचने के लिए उन्होंने भारत में प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण भोपाल में स्थापित एक अत्यधिक प्रदूषणकारी रासायनिक संयन्त्र है, जिसके परिणामस्वरूप गैस त्रासदी हुई जब हजारों लोग या तो मारे गए या गम्भीर बीमारियों के कारण विकलांग हो गए। "ऐसे देशों में पर्यावरणीय उपायों को मजबूत करने के साथ, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बीच गरीब देशों में प्रदूषणकारी उद्योगों का पता लगाने की प्रवृत्ति है, जहाँ पर्यावरण कानून गैर-मौजूद है या इसे ठीक से लागू नहीं किया गया है, जैसा कि भोपाल गैस त्रासदी में मिसाल है।"
6. **विनिमय दर में अस्थिरता**—बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा उदारीकृत विदेशी निवेश का एक और प्रमुख परिणाम मेजबान देश की विदेशी विनिमय दर पर इसका प्रभाव है। विदेशी पूँजी प्रवाह भारतीय रुपये की विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करता है। विदेशी निवेश के माध्यम से एक बड़ी पूँजी प्रवाह अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि लाता है। विदेशी मुद्रा की माँग के साथ, विदेशी मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि से रुपये की विनिमय दर की सराहना होगी। भारतीय रुपये की यह प्रशंसा निर्यात को हतोत्साहित करेगी और व्यापार सन्तुलन में कमी के कारण आयात को प्रोत्साहित करेगी। उदाहरण के लिए, भारत में वित्त वर्ष 2004-05 और 2005-06 में, भारतीय अर्थव्यवस्था में एफआईआई (विशाल वित्तीय बहुराष्ट्रीय कम्पनियों) द्वारा बड़ी पूँजी प्रवाह किया गया था, ताकि यहाँ उच्च ब्याज दरों का लाभ उठाया जा सके और भारतीय पूँजी बाजार में भी उछाल आए। दूसरी ओर, जब इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मूल देशों में ब्याज दरें बढ़ती हैं या पूँजी बाजार से वापसी की दर बढ़ती है या जब मेजबान देश में अपने ऋण के भुगतान की क्षमता के बारे में विश्वास की हानि होती है, जैसा कि इस मामले में हुआ है। नब्बे के दशक के उत्तरार्ध में दक्षिण-पूर्व एशिया में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा पूँजी का बड़ा बहिर्वाह हुआ है। जिसके परिणामस्वरूप संकट और उनके विनिमय दर में भारी गिरावट आई है। इस प्रकार, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा पूँजी प्रवाह और बहिर्वाह विनिमय दर की बड़ी अस्थिरता के लिए जिम्मेदार रहे हैं। फिर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा मुनाफे के प्रत्यावर्तन का सवाल है। हालाँकि मेजबान देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा लाभ का एक हिस्सा पुनर्निवेशित किया जाता है, लेकिन मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा अपने मूल देशों को भेजा जाता है। यह विकासशील देशों के लिए एक सम्भावित नुकसान है। खासकर जब वे विदेशी मुद्रा समस्या का सामना कर रहे हैं। इस पर टिप्पणी करते हुए **थिरवाल** लिखते हैं "लोन फाइनस के साथ तुलना करने पर भी एफडीआई के सम्भावित नुकसान हैं, कि मुनाफे का बहिर्वाह हो सकता है जो बहुत लम्बे समय तक रहता है।"

स्थानीय कर के मूल्य निर्धारण और चोरी हस्तान्तरण—बहुराष्ट्रीय निगम आमतौर पर लम्बवत् एकीकृत होते हैं। बहुराष्ट्रीय फर्म द्वारा एक कमोडिटी के उत्पादन में इसके चरणों में विभिन्न चरण शामिल होते हैं। अन्तिम कमोडिटी के उत्पादन में उपयोग

TOUCH 'n PASS

किए जाने वाले घटक अपने मूल देश में या अन्य देशों में अपने सहयोगियों में उत्पादित किए जा सकते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग से तात्पर्य भारत में कहे जाने वाले अन्तिम घटक के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले इसके घटकों या भागों के लिए खड़ी एकीकृत बहुराष्ट्रीय फर्म की कीमतों से हैं। घटकों या भागों ये कीमतें वास्तविक मूल्य नहीं हैं, जैसा कि उनके लिए मांग और आपूर्ति से निर्धारित होता है। वे कम्पनियों द्वारा मनमाने ढँग से तय किए जाते हैं ताकि उन्हें भारत में कम करों का भुगतान करना पड़े। वे कृत्रिम रूप से अपने मूल देश में उत्पादित मध्यवर्ती उत्पादों (यानी, घटक) के लिए सथानान्तरण मूल्य बढ़ाते हैं या भारत में अर्जित कम मुनाफा दिखाते हैं। नतीजतन, वे कॉर्पोरेट आयकर को विकसित करने में सफल होते हैं।

निष्कर्ष—हमने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विदेशी निवेश पर गहनता से चिंतन किया है इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। इसलिए, उन्हें नियमन की आवश्यकता है और उन्हें चयनित क्षेत्रों में अनुमति दी जानी चाहिए और विशेष क्षेत्रों में उनके निवेश पर विशेष निगरानी और राष्ट्रीय हितों के अनुकूल होना चाहिए। यदि स्थिरता और सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास का उद्देश्य प्राप्त करना है तो उनके लिए खुली नीति नहीं होनी चाहिए।

यह सच है कि बहुराष्ट्रीय निगम भारत में निवेश करने में जोखिम लेते हैं, वे पूँजी और विदेशी मुद्रा लाते हैं जो गैर-ऋण पैदा कर रहे हैं, वे आम तौर पर प्रौद्योगिकी को बढावा देते हैं और निर्यात बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन उन्हें विनियमित किया जाना चाहिए ताकि वे इन लक्ष्यों को पूरा करें। उन्हें बुनियादी ढाँचे उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों और उन उद्योगों में निवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए जिनके उत्पाद एवं निर्यात कर सकते हैं और यदि वे शुद्ध रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करते हैं। हम **कॉलमैन** और **निक्सन** से सहमत हैं जो लिखते हैं। "कम विकास वाले देशों के भीतर विकास की कमी (या दिशा विकास हो रहा है) के लिए सीधे तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय निगमों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उनका मुख्य उद्देश्य वैश्विक लाभ अधिकतमकरण और उनके कार्यों का उद्देश्य उस उद्देश्य को प्राप्त करना है, न कि मेजबान कम विकसित देश विकसित करना। यदि वे प्रौद्योगिकी और उत्पाद जो वे पेश करते हैं अनुचित है, यदि उनके कार्य क्षेत्रीय और सामाजिक असमानताओं को बढ़ाते हैं। यदि वे भुगतान की स्थिति के सन्तुलन को कमजोर करते हैं। तो अन्तिम उपाय में यह नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए कम विकसित देश की सरकार पर निर्भर है जो समाप्त हो जाएगा।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विकासशील देशों को किसके सम्पर्क में लाता हैं?
(क) विकसित राष्ट्र (ख) अल्प-विकविसत राष्ट्र
(ग) कम विकसित राष्ट्र (घ) ये सभी

उत्तर (ग) कम विकसित राष्ट्र

प्र.2. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में पारस्परिक माँग का सिद्धान्त किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था?
(क) मिल (ख) हॉबलर्र (ग) मार्शल (घ) रिकार्गे

उत्तर (क) मिल

प्र.3. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर नीति तैयार करने के लिए नोड़ल विभाग हैं—
(क) भारतीय रिजर्व बैंक (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक
(घ) उद्योग संवर्धन और आन्तरिक व्यापार विभाग (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

उत्तर (घ) उद्योग संवर्धन और आन्तरिक व्यापार विभाग

प्र.4. निम्नलिखित में से कौन-सी भारत में विदेशी पूँजी के प्रवाह की विधि है?
(क) FDI (ख) FII (ग) NRI खाते (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (ग) NRI खाते

प्र.5. FDI का पूर्ण रूप क्या है?
(क) संघीय निवेश विभाग (ख) वन विकास सूचकांक
(घ) संघीय जाँच विभाग (घ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

उत्तर (घ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

TOUCH 'n' PASS

प्र.6. बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा किए गए निवेश को ..... कहा जाता है।
(क) विदेशी निवेश (ख) घाटा लेखा (घ) म्यूचुअल फण्ड (घ) कॉर्पोरेट फण्ड
उत्तर (क) विदेशी निवेश

प्र.7. एक देश में एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यवसायिक हितों में किया गया निवेश है—
(क) FDI (ख) Forex (ग) CRR (घ) SEZ
उत्तर (क) FDI

प्र.8. भारत में निजी सुरक्षा एजेन्सियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा क्या है?
(क) 51% (ख) 100% (ग) 49% (घ) 74%
उत्तर (घ) 74%

प्र.9. दोनों विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) और विदेशी संस्थागत निवेश (FII) किसी देश में निवेश से सम्बन्धित हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन दोनों के बीच एक महत्त्वपूर्ण अन्तर का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है—
(क) FII बेहतर प्रबन्धन कौशल और प्रौद्योगिकी लाने में मदद करता है; जबकि FDI केवल पूँजी में लाता है।
(ख) FII सामान्य रूप से पूँजी की उपलब्धता बढ़ाने में मदद करता है; जबकि FDI केवल विशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित करता है।
(ग) FII को FDI की तुलना में अधिक स्थिर माना जाता है।
(घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (ख) FII सामान्य रूप से पूँजी की उपलब्धता बढ़ाने में मदद करता है; जबकि FDI केवल विशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित करता है।

प्र.10. एक देश में दूसरे देश की वस्तु की माँग जितनी अधिक बेलोचदार होगी पहले देश के लिए व्यापार की शर्त—
(क) अनुकूल होगी (ख) प्रतिकूल होगी (ग) अप्रभावित होगी (घ) ये सभी
उत्तर (ख) प्रतिकूल होगी

प्र.11. व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाला घटक हैं—
(क) माँग व पूर्ति की लोच (ख) स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता
(ग) प्रशुल्क नीति (घ) ये सभी
उत्तर (घ) ये सभी

प्र.12. एक देश का देय वक्र बताता है कि देश क्या है?
(क) कर सकता है (ख) कर रहा है (ग) करने पर इच्छुक है (घ) ये सभी
उत्तर (ग) करने पर इच्छुक है

प्र.13. देश की आयात क्षमता को सूचित करने वाली कौन-सी व्यापार शर्त है?
(क) शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्त (ख) सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त
(ग) आय व्यापार शर्त (घ) एक घटीय व्यापार शर्त
उत्तर (ग) आय व्यापार शर्त

प्र.14. व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाला घटक हैं?
(क) माँग एवं पूर्ति लोच (ख) स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता
(ग) प्रशुल्क नीति (घ) ये सभी
उत्तर (घ) ये सभी

प्र.15. 'व्यापार के वास्तविक लाभों का निर्धारण करने के लिए कौन-सा व्यापार शर्त का प्रयोग होता है—
(क) एक घटकीय व्यापार शर्त (ख) द्विघटकीय व्यापार शर्त
(ग) वास्तविक लागत व्यापार शर्त (घ) वास्तविक लाभ व्यापार शर्त
उत्तर (ग) वास्तविक लागत व्यापार शर्त

TOUCH 'n PASS

प्र.16. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से एक देश में—

(क) राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है (ख) उपभोग स्तर बढ़ता है

(ग) लाभ सम्भावनाएँ बढ़ती है (घ) ये सभी बातें अनुकूल बनाती है।

उत्तर (घ) ये सभी बातें अनुकूल बनाती है।

प्र.17. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से—

(क) विशिष्टीकरण को जन्म मिलता है (ख) उत्पादन प्रविधि में सुधार आता है

(ग) स्पर्द्धा से मूल्यों में कमी आती है (घ) सभी कथन उपर्युक्त है।

उत्तर (ख) उत्पादन प्रविधि में सुधार आता है

प्र.18. व्यापार सिद्धान्त में गत्यात्मक तत्त्वों से अभिप्राय किस परिवर्तन से है?

(क) साधन उपलब्धता (ख) तकनीक (ग) रूचियाँ (घ) ये सभी

उत्तर (घ) ये सभी

प्र.19. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रभावों के सन्दर्भ में असंगत कथन अंकित करें।

(क) आर्थिक सहयोग बढ़ाता है। (ख) सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाता है

(ग) राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ाता है। (घ) विदेशों पर निर्भरता बढ़ती है।

उत्तर (ग) राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ाता है।

प्र.20. किसी भी देश की व्यापार शर्तें बराबर है—

(क) निर्यात वस्तु की कीमत/आयात वस्तु की कीमत

(ख) आयात वस्तु की कीमत/निर्यात वस्तु की कीमत

(ग) आयात वस्तु की कीमत × निर्यात वस्तु की कीमत

(घ) निर्यात वस्तु की कीमत + आयात वस्तु की कीमत

उत्तर (क) निर्यात वस्तु की कीमत/आयात वस्तु की कीमत

प्र.21. व्यापार की दिशा को निर्धारण करने वाला तत्त्व है—

(क) तुलनात्मक लाभ (ख) निरपेक्ष मान (ग) उपर्युक्त दोनों (घ) विनिमय दर

उत्तर (क) तुलनात्मक लाभ

❑

TOUCH n PASS

- यद्यपि इस पुस्तक को यथासम्भव शुद्ध एवं त्रुटिरहित प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास किया गया है, तथापि इसमें कोई कमी अथवा त्रुटि अनिच्छाकृत ढंग से रह गई हो तो उससे कारित क्षति अथवा सन्ताप के लिए लेखक, प्रकाशक तथा मुद्रक का कोई दायित्व नहीं होगा। सभी विवादित मामलों का न्यायक्षेत्र मेरठ न्यायालय के अधीन होगा।
- इस पुस्तक में समाहित सम्पूर्ण पाठ्य-सामग्री (रेखा व छायाचित्रों सहित) के सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन हैं। अतः कोई भी व्यक्ति इस पुस्तक का नाम, टाइटिल-डिजाइन तथा पाठ्य-सामग्री आदि को आंशिक या पूर्ण रूप से तोड़-मरोड़कर प्रकाशित करने का प्रयास न करें, अन्यथा कानूनी तौर पर हर्जे-खर्चे व हानि के जिम्मेदार होंगे।
- इस पुस्तक में रह गई तथ्यात्मक त्रुटियों तथा अन्य किसी भी कमी के लिए विद्वत् पाठकगण से भूल-सुधार/सुझाव एवं टिप्पणियाँ सादर आमन्त्रित हैं। प्राप्त सुझावों अथवा त्रुटियों का समायोजन आगामी संस्करण में कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार के भूल-सुधार/सुझाव आप info@vidyauniversitypress.com पर भी ई-मेल कर सकते हैं।